मानव विकास रिपोर्ट 2013

दक्षिण का उदयः

विविधतापूर्ण विश्व में मानव प्रगति

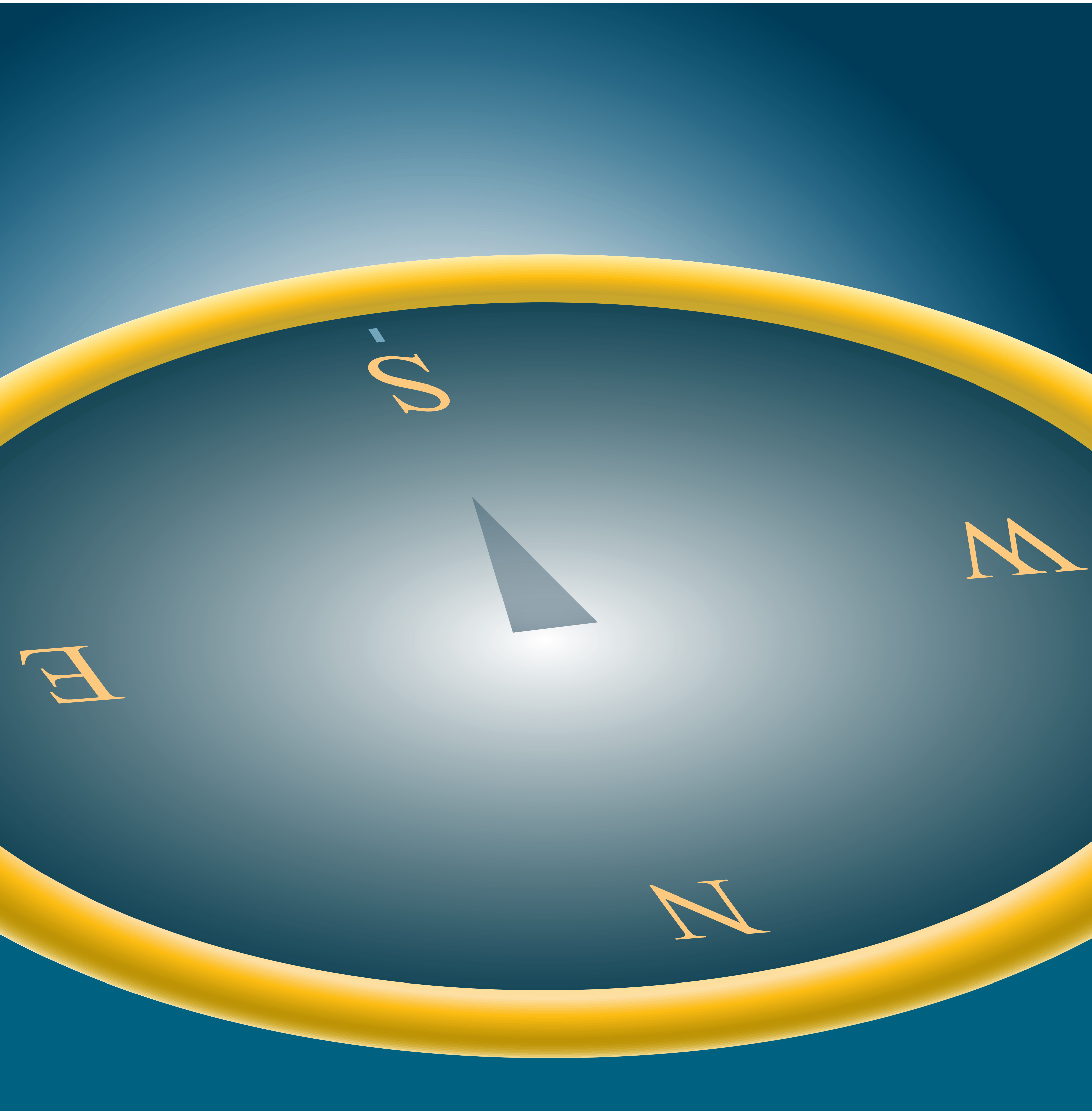

वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट यू.नए.डी.पी. द्वारा 1990 से विकास के प्रमुख मुद्दों, रुझानों और नीतियों के स्वतंत्र, अनुभव आधारित विश्लेषणों के रूप में प्रकाशित वैश्विक मानव विकास रिपोर्टों की श्रृंखला में नवीनतम है।

वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित अतिरिक्त संसाधनों को ऑनलाईन http://hdr.undp.org पर देखा जा सकता है, जिनमें 20 से अधिक भाषाओं में रिपोर्ट के संपूर्ण संस्करण या सारांश, 2013 की रिपोर्ट के लिए अधिकृत मानव विकास शोध पत्रों का संग्रह, संवादात्मक मानचित्र और राष्ट्रीय मानव विकास संकेतकों के आँकड़े, रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांकों में प्रयुक्त स्रोतों और कार्यविधियों की पूर्ण व्याख्या, कंट्री प्रोफ़ाइल और अन्य पृष्ठभूमि सामग्री के साथ ही पिछली वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टें शामिल हैं।

मानव विकास रिपोर्ट 2013

दक्षिण का उदय :
विविधतापूर्ण विश्व में मानव प्रगति

संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम
(यू.एन.डी.पी.)
के लिए
प्रकाशित

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

मानव विकास रिपोर्टें 1990-2013

1990 मानव विकास की अवधारणा एवं मापन
1991 मानव विकास का वित्तीयन
1992 मानव विकास के वैश्विक आयाम
1993 जन भागीदारी
1994 मानव सुरक्षा के नए आयाम
1995 लैंगिकता एवं मानव विकास
1996 आर्थिक प्रगति एवं मानव विकास
1997 ग़रीबी उन्मूलन के लिए मानव विकास
1998 मानव विकास के लिए उपभोग
1999 मानवीयतापूर्ण वैश्वीकरण
2000 मानवाधिकार एवं मानव विकास
2001 नई प्रौद्योगिकियों को मानव विकास में सहायक बनाना
2002 विभाजित विश्व में लोकतंत्र को गहराना
2003 सहस्राब्दि विकास लक्ष्यः ग़रीबी मिटाने के लिए राष्ट्रों के बीच समझौता
2004 आज के वैविध्यपूर्ण विश्व में सांस्कृतिक आज़ादी
2005 अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दुविधाएँः एक असमान विश्व में सहायता व्यापार एवं सुरक्षा
2006 अभावों के पारः ऊर्जा, ग़रीबी और वैश्विक जल संकट
2007/2008 जलवायु परिवर्तन से मुकाबलाः एक विभाजित विश्व में मानव-एकजुटता
2009 बाधाओं पर विजयः मानव गतिशीलता एवं विकास
2010 देशों की वास्तविक संपदाः मानव विकास के पथ
2011 संवहनीयता और समताः सबके लिए एक बेहतर भविष्य
2013 दक्षिण का उदयः विविधतापूर्ण विश्व में मानव विकास

क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्टें: पिछले दो दशकों में यू.एन.डी.पी. के क्षेत्रीय ऑफ़िसों के सहयोग से विकासशील विश्व के सभी प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रीय फ़ोकस वाली मा.वि.रि. प्रकाशित हुई हैं। विचारोत्तेजत विश्लेषणों और दो टूक नीतिगत सुझावों वाली इन क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्टों ने अरब देशों में राजनीतिक सशक्तीकरण, अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा, एशिया में जलवायु परिवर्तन, मध्य यूरोप में जातीय अल्पसंख्यकों से होने वाले बर्ताव और लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई क्षेत्र में असमता व नागरिक सुरक्षा जैसे बेहद अहम मुद्दों की पड़ताल की है।

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टें: सन् 1992 में पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से यू.एन.डी.पी. के सहयोग और स्थानीय संपादकीय टीमों के प्रयासों से 140 देशों में राष्ट्रीय मा.वि.रि. प्रकाशित हो चुकी हैं। अब तक 700 से भी अधिक संख्या में प्रकाशित हो चुकी इन रिपोर्टों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परिसंवादों और शोध के द्वारा राष्ट्रीय नीति के सरोकारों में मानव विकास के दृष्टिकोण को पिरोने का काम हुआ है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टों ने जलवायु परिवर्तन से लेकर युवाओं की बेरोज़गारी और जातीयता अथवा जेंडर आधारित असमानता सरीखे अहम विकास-मुद्दों को अपने विमर्श के दायरे में शामिल किया है।

कॉपीराइट © 2013
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा

1 यू.एन. प्लाज़ा, न्यू यॉर्क, एन.वाई. 10017 संयुक्त राज्य अमेरिका

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी अंश पूर्वानुमति के बिना न तो पुनर्प्रकाशित किया जा सकता है, न ही किसी रिट्रीवल सिस्टम में संरक्षित किया जा सकता है अथवा किसी भी रूप में और किसी भी विधि से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फ़ोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग अथवा अन्य किसी तरह से प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

भारत में ब्राइट सर्विसेज़ प्रा. लि. द्वारा मुद्रित

मानव विकास रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद सम्यक् कम्युनिकेशन्स द्वारा

संपादन एवं प्रोडक्शनः कम्युनिकेशन्स डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेटेड, वाशिंगटन डी.सी.

डिज़ाइनः मेलेनी डोहर्टी डिज़ाइन, सैन फ्रांसिस्को, सी.ए.

प्रकाशन के बाद भी पाठ में रह गई ग़ल्तियों एवं कमियों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें **http://hdr.undp.org**

मानव विकास रिपोर्ट 2013 की टीम

निदेशक एवं प्रमुख लेखक
ख़ालिद मलिक

शोध एवं सांख्यिकी
मॉरिस कुगलर (शोध के प्रमुख), मिलोरैड कोवेसेविक (मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी), शुभ्रा भट्टाचार्जी, एस्ट्रा बोनीनी, सिसीलिया कैल्डेरॉन, एलेन फुक्स, एमी गाये, इएना कोनोवा, आर्थर मिन्सेट, शिवानी नय्यर, होज़े पिनेडा एवं स्वर्निम वाघले

संचार एवं प्रकाशन
विलियम ओर्मे (संचार के प्रमुख), बोटागोज़ अब्द्रेयेवा, कार्लोटा आएलो, एलियोनोर फ़ोर्नियर-टूम्बस, ज्याँ-ईव्ज़ हैमेल, स्कॉट लूविस एवं सामन्ता वौचोप

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टें
इवा जेस्पर्सन (उप निदेशक), क्रिस्टीना हैकमान, जोनाथन हॉल, मैरी एन मवांगी एवं पाओला पग्लियानी

परिचालन एवं प्रशासन
सरन्तूया मैंड (परिचालन प्रबंधक), इकेटेरीना बर्मन, डाएन बोउपडा, ममाये गेब्रेसादिक एवं फ़े हुएरेज़-शनाहन

आमुख

मानव विकास रिपोर्ट 2013, दक्षिण का उदयः एक विविधतापूर्ण संसार में मानव प्रगति हमारे समय की उभरती भू-राजनीति पर निगाह डालते हुए उभर रहे मुद्दों और प्रवृत्तियों का परीक्षण करती है, और उन नए तत्वों को चिन्हित करती है जो विकास परिदृश्य को गढ़ रहे हैं।

रिपोर्ट दलील देती है कि बड़ी संख्या में विकासशील देशों के गतिमान, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रूपान्तरित होने का और उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मानव विकास प्रगति पर उल्लेखनीय असर पड़ रहा है।

रिपोर्ट रेखांकित करती है कि पिछले दशक में सभी देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आयामों में, जैसे वे मानव विकास सूचकांक में मापे जाते हैं, अपनी उपलब्धियाँ तेज़ की हैं। जिन देशों के आँकड़े उपलब्ध थे, उनमें से 2012 में किसी का भी मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) 2000 के मान से नीचे नहीं था। चूँकि निम्नतर मा.वि.सू. वाले देशों में इस दौरान ज़्यादा तेज़ प्रगति दर्ज की गई, इसलिए मानव विकास सूचकांक मानों में विश्व भर में उल्लेखनीय अभिमुखता (convergence) थी, हालाँकि प्रगति, क्षेत्रों के बीच और भीतर भी, असमान थी।

खास तौर पर उन देशों को देखते हुए जिन्होंने 1990 और 2012 के बीच मानव विकास के आय और ग़ैर-आय आयामों में अपने मा.वि.सू. मान में बड़ी प्रगति प्राप्त की, यह रिपोर्ट उन रणनीतियों की पड़ताल करती है, जिन्होंने इन देशों के अच्छे प्रदर्शन को सम्भव बनाया। इस अर्थ में यह 2013 की रिपोर्ट विकास रूपान्तरण के विशिष्ट चालकों-तत्वों के वर्णन और इस प्रगति को बनाए रखने वाली मददगार भावी नीति-वरीयताओं को रेखांकित करके विकास से जुड़े विमर्श में अहम योगदान करती है।

इस रिपोर्ट के लिए विकसित अनुमानों के अनुसार, सन् 2020 तक, सिर्फ़ तीन प्रमुख विकासशील देशों– ब्राज़ील, चीन और भारत– का संयुक्त आर्थिक उत्पादन कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल उत्पादन से आगे निकल जाएगा। इस विस्तार का बहुतांश दक्षिण के भीतर ही नए व्यापार और तकनीकी भागीदारियों द्वारा प्रेरित है, जैसा यह रिपोर्ट भी दर्शाती है।

लेकिन इस और इससे पहले की मानव विकास रिपोर्टों का एक केन्द्रीय संदेश यह है कि अकेले आर्थिक वृद्धि से ही अपने आप मानव विकास प्रगति नहीं होती। ग़रीब-समर्थक नीतियाँ और लोगों की क्षमताओं में भरपूर निवेश– शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गारपरक दक्षताओं पर ध्यान दे कर– प्रतिष्ठापूर्ण काम तक पहुँच का विस्तार करती हैं और टिकाऊ प्रगति को संभव बनाती हैं।

विकास का संवेग टिकाऊ बनाए रखने के लिए 2013 की रिपोर्ट चार स्पष्ट क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करती है– समता में वृद्धि, लैंगिकता के आयामों को शामिल करते हुए; युवाओं सहित नागरिकों की मुखरतर आवाज़ और सहभागिता को बढ़ावा; पर्यावरणीय चुनौतियों का मुकाबला; और जनसांख्यिकीय परिवर्तन का प्रबंधन।

रिपोर्ट यह भी सुझाती है कि जैसे-जैसे वैश्विक विकास चुनौतियाँ ज़्यादा जटिल और अपनी प्रकृति में ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय होती जाती हैं, हमारे समय की सबसे ज़रूरी चुनौतियों, चाहे वह ग़रीबी उन्मूलन हो, जलवायु परिवर्तन हो या फिर शांति और सुरक्षा, उन पर समेकित-समन्वित कार्रवाई अनिवार्य है। चूँकि अब देश व्यापार, आप्रवास, और सूचना संचार तकनीकों द्वारा अधिकाधिक अंतरसंबद्ध हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक जगह के नीतिगत निर्णय दूसरी जगहों पर भी भरपूर असर डालते हैं। पिछले कुछ सालों के संकट– खाद्य, वित्तीय, जलवायु– जिन्होंने इतने लोगों की ज़िन्दगियों को नुकसान पहुँचाया, यही दिखाते हैं। साथ ही दिखाते हैं झटकों और आपदाओं के प्रति लोगों की अरक्षितताओं को कम करने के लिए काम करने की ज़रूरत को भी।

दक्षिण में मौजूद ज्ञान, दक्षताओं और विकास चिंतन का लाभ उठाने के लिए यह रिपोर्ट ऐसी नई संस्थाओं की माँग करती है जो क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सक्षम बना सकें। विकासशील दुनिया की उभरती शक्तियाँ पहले ही दूसरे विकासशील देशों के लिए नवाचारी सामाजिक और आर्थिक नीतियों की स्रोत हैं और उनके व्यापार, निवेश और बढ़ते विकास सहयोग की प्रमुख भागीदार भी हैं।

दक्षिण में बहुत से दूसरे देशों में तेज़ विकास हुआ है और उनके अनुभव तथा उनका दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकास नीति के लिए समान रूप से प्रेरक हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ज्ञान-मध्यस्थ की और साझीदारों– सरकारों, नागर समाज और बहुराष्ट्रीय कंपनियों– के संयोजक की उपयोगी भूमिका निभा पाता है ताकि अनुभव बाँटे जा सकें। अधिगम (ज्ञान-प्राप्ति) और क्षमता

वृद्धि को संभव बनाने में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह रिपोर्ट दक्षिण-दक्षिण सहयोग से जुड़े हमारे भावी कार्य के लिए बहुत उपयोगी अंतर्दृष्टियाँ देती है।

अंत में, यह रिपोर्ट एक ज़्यादा न्यायसंगत, समतापूर्ण संसार बनाने के लिए वैश्विक अधिशासन संस्थाओं पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डालने का आह्वान करती है। यह कालबाह्य ढाँचों को चिन्हित करती है जो नए आर्थिक और भू-राजनीतिक यथार्थ को प्रतिबिंबित नहीं करते, और भागीदारी के एक नए युग के लिए विकल्पों पर विचार करती है। यह बृहत्तर पारदर्शिता और जवाबदेही का आह्वान करती है, और इसके लिए वैश्विक नागर समाज की भूमिका को तो रेखांकित करती ही है, साथ में, वैश्विक बदलावों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वालों– जो अक्सर हमारे संसार के सबसे निर्धन और अरक्षित इन्सान होते हैं– के लिए अधिक निर्णयन शक्ति की बात पर भी ज़ोर देती है।

वर्ष 2015 के बाद के वैश्विक विकास एजेंडे पर चर्चा जारी है, और मैं आशा करती हूँ कि बहुत से लोग इस रिपोर्ट को पढ़ने का और तेज़ी से बदलते हमारे संसार के लिए इसके सबकों पर विचार करने का समय निकालेंगे। वैश्विक विकास की वर्तमान स्थिति की हमारी समझ को यह रिपोर्ट फिर ताज़ा करती है, और दिखाती है कि दक्षिण के इतने सारे देशों की विकास की तेज़ प्रगति के अनुभवों से कितना कुछ सीखा जा सकता है।

हेलेन क्लार्क
प्रशासक
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

आभार

यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.), मानव विकास रिपोर्ट ऑफ़िस (एच.डी.आर.ओ.) तथा अनेक मूल्यवान बाहरी सलाहकारों एवं सहकारियों के साझा प्रयासों का प्रतिफल है। हालाँकि, पिछली रिपोर्टों की ही तरह इस रिपोर्ट के निष्कर्ष, विश्लेषण और नीतिगत सुझाव केवल इसके लेखकों के ही हैं।

मार्च 2013 में इस रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ ही हम मानव विकास रिपोर्ट की पुरानी समय सारणी पर लौट रहे हैं– साल के पहले हिस्से में इसके वैश्विक लोकार्पण और वितरण के साथ। इस समय को चुनने से अद्यतन सांख्यिकीय सूचकों की रिपोर्ट के मिश्रित सूचकांकों को अपनी गणना में शामिल करने का मौका मिल जाता है और वर्ष भर रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों व संदेशों पर चर्चा करने के लिए काफ़ी अवसर मिल जाता है।

इस रिपोर्ट की तैयारी महबूब उल हक़ की पहली मानव विकास रिपोर्टों के सावधान पुनर्पाठ से निर्देशित थी। इस भावना के तहत रिपोर्ट की शुरुआत मौजूदा 'मानव विकास की स्थिति' की समीक्षा के साथ होती है, जिसमें दुनिया में आज की प्रमुख मानव विकास प्रवृत्तियों और मुद्दों की पड़ताल की गई है। अमर्त्य सेन और फ्रांसिस स्टुवर्ट की परिपक्व सलाह से भी यह रिपोर्ट काफ़ी लाभान्वित हुई। हक़ के करीबी साझीदार रहे इन दोनों महानुभावों ने खुले दिल से अहम सलाह भी दी और रिपोर्ट के लिए आलेख भी।

हमें खुशी है कि यह रिपोर्ट दूसरे लोगों के साथ ही न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग, जापानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के अध्यक्ष अकिहिको तनाका और तुर्की के विकास मंत्री केवडेट यिल्माज़ के हस्ताक्षरित लेखों से युक्त है। हम एच.डी.आर.ओ. द्वारा अधिकृत शोध पत्रों के लेखकों के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने उन मुद्दों पर हमारी समझ को काफ़ी समृद्ध बनाया, जिन्हें हमने चर्चा के लिए तय किया थाः फ्रेड ब्लॉक, नोदर फ़रगेनी, इलेने ग्रैबल, खलील हमदानी, पैट्रिक हैलर, बैरी ह्यूज़, इंगे कौल, पीटर क्रैजलुंड, शिव कुमार, वुल्फगैंग लुत्ज़, दीपक नैय्यर, लियैंसे दीकुमाना और नगायर वुड्स।

इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान हमें लगातार अपने प्रतिष्ठित मा.वि.रि.ऑ. सलाहकार पैनल से बहुमूल्य अंतर्दृष्टियाँ और मार्गदर्शन मिला, खासतौर से एडवर्ड एस. अयेन्सु, क्रिस्टोवाम बुआर्के, माइकल एलियट, जयंती घोष, पैट्रिक गिआमॉन्ट, नाना हविड्ट, रीमा खलफ़, नौरा लुस्टिग, सर जेम्स एलेक्ज़ेंडर मिर्लीस, राजेन्द्र के. पचौरी, समीर रदवान, रिज़ल रमली, गुस्ताव रानिस, फ्रांसिस स्टुवर्ट, मिगैल ज़केली और कान्देह के. युमकेला से।

हम एच.डी.आर.ओ. के सांख्यिकी पैनल को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांकों की गणना से संबंधित कार्यपद्धति और आँकड़ों के चयन के बारे में विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध करायीः एंटनी एटकिंसन, रशीद बेनमुख्तार बेनाब्देल्लाह, एनरिको जियोवनीनी, पीटर हार्पर, एंटनी के.एम. किलेले, बेन पॉल मुंग्येरेज़ा, हैन्ड्रिक वैन डर पॉल, मार्सिया क्विंसलर और एडुआर्डो सोहो गारज़ा अल्डापे।

रिपोर्ट के सभी सूचकांक और अन्य सांख्यिकीय संसाधन संबंधित क्षेत्र में उनके अग्रणी अंतरराष्ट्रीय आँकड़ा प्रदाताओं की दक्षता पर आधारित हैं, और मानव विकास रिपोर्ट के साथ उनके लगातार मित्रवत सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। सटीकता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट के सांख्यिकीय विश्लेषण को अकमल अब्दुराज़ाकोव, सबीना अल्कीरे, वर्जीनिया क्रुज़ेन, केनेथ हार्टगन और क्लाउडियो मोंटेनेग्रो द्वारा सांख्यिकी परिणामों की बाह्य समीक्षा से भी फ़ायदा मिला।

रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान आयोजित विचार-विमर्श कई संस्थानों और व्यक्तियों की उदार सहायता पर आधारित थे, जिनकी संख्या यहाँ उल्लेख करने के लिहाज़ से काफ़ी अधिक है। सितंबर 2011 और जून 2012 के बीच अदीस अबाबा, बॉन, ब्रासीलिया, कोलंबो, जिनेवा, न्यूयॉर्क, रबात, सैंटियागो और टोक्यो में विचार-विमर्श का आयोजन किया गया। यू.एन.डी.पी. के कंट्री और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित साझीदार संस्थानों द्वारा जो भी सहयोग मिला, जिनकी सूची http://hdr.undp.org/en/reports/hdr2013/consultations पर उपलब्ध है, उनका अत्यधिक कृतज्ञता के साथ आभार।

दुनिया भर में हमारे यू.एन.डी.पी. के कई साथियों ने– एच.डी.आर.ओ. पाठक वर्ग और कार्यकारी समूह के रूप में– रिपोर्ट की तैयारी और अंतिम प्रारूप तैयार करने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई। हम ख़ासतौर से आदेल अब्देललतीफ, पेद्रो कॉन्सियाव, रेबेका ग्रिन्स्पैन, ओलाफ़ कोरवेन, अजय छिब्बर, जॉर्ज रोनल्ड ग्रे मोलिना, हेराल्डो मुन्योज़, सलीम जहान, नतालिया लिनो, कमल मल्होत्रा, अबदुल्ले मार दिये, चार्ल्स मैकलीन, शांतनु मुखर्जी, मादी मूसा,

थंगवल पलानिवेल, अनुराधा राजीवन, तुरहान सालेह, हेदर सिम्पसन, बेन स्ले, मुनीर ताबे, एंतोनियो विजीलांते और कन्नी विग्नराजा को धन्यवाद देना चाहते हैं।

रिपोर्ट के तथ्यों की जाँच के लिए कई परिश्रमी, प्रतिभावान युवा साथियों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनमें फिलिप बैस्टियन, जोशुआ ग्रीनस्टाइन, नानी गू, डायना हिमेनेज़, वानशान ली, वेरोनिका पोस्टल और एलिसा व्लादिमीर शामिल हैं।

रिपोर्ट भाग्यवान है कि उसके पास कई ''एच.डी.आर.ओ.के मित्र'' हैं, जो इसे मज़बूती देने के लिए उम्मीद से आगे बढ़ गये। फ्रांसिस स्टुवर्ट और जोमो क्वामे सुंदरम द्वारा प्रारूप रिपोर्ट के समीक्षात्मक अध्ययन और खलील हमदानी, शिव कुमार, टेरी मेकिन्ले, पेद्रो कॉन्सियाव और पीटर स्टॉकर द्वारा व्यापक समीक्षा के अलावा हम कम्युनिकेशंस डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेटेड में ब्रूस रॉस-लार्सन की अगुवाई में मैटा दे कोकेरिमो, क्रिस्ट्रोफ़र ट्रॉट और एलेन विल्सन और डिज़ायनर मेलनी डोहर्टी के रूप में अपने संपादकों के श्रमसाध्य काम के प्रति भी आभारी हैं।

सबसे बढ़कर, मैं गर्वान्वित रूप से एच.डी.आर.ओ. दल के प्रति एक ऐसी रिपोर्ट को, जो विद्वता के उच्चतम मानकों को पूरा करती है, तैयार करने को लेकर उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए आभारी हूँ।

खालिद मलिक
निदेशक
मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय

अनुक्रम

आमुख	iv
आभार	vi
विहगावलोकन	1
प्रस्तावना	11

अध्याय 1

मानव विकास की स्थिति	**21**
देशों की प्रगति	23
सामाजिक एकीकरण	35
मानव सुरक्षा	38

अध्याय 2

अधिक वैश्विक होता दक्षिण	**43**
पुनर्संतुलनः अधिक वैश्विक विश्व और अधिक वैश्विक दक्षिण	43
मानव विकास से प्रोत्साहन	49
दक्षिण में नवाचार एवं उद्यमिता	55
सहकारिता के नए रूप	56
अनिश्चित दौर में प्रगति बरकरार रखने की चुनौती	60

अध्याय 3

विकासपरक रूपान्तरण के प्रचालक	**63**
प्रचालक 1- प्रसक्रिय विकासपरक राज्य	66
प्रचालक 2- वैश्विक बाज़ारों का दोहन	74
प्रचालक 3- सामाजिक नीति में संकल्पशील नवाचार	77

अध्याय 4

गति क़ायम रखने की चुनौती	**87**
विकासशील देशों के लिए नीतिगत प्राथमिकताएँ	87
जनसांख्यिकी और शिक्षा के परिदृश्य	
आबादी की आयु वृद्धि का प्रभाव	100
महत्वाकांक्षी नीतियों की आवश्यकता	101
सही वक्त पर क़दम उठाना	103

अध्याय 5

नए दौर के लिए अधिशासन एवं भागीदारियाँ	**105**
सार्वजनिक साधनों का एक नया वैश्विक दृष्टिकोण	106
दक्षिण के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व	109
वैश्विक नागर समाज	110
सुसंगत बहुलवाद की ओर	112
उत्तरदायी सम्प्रभुता	115
नई संस्थाएँ, नई कार्यविधियाँ	116
निष्कर्षः एक नए दौर के भागीदार	118

शब्दावली	123
नोट	125
संदर्भ	131

सांख्यिकीय परिशिष्ट

पाठकों के लिए मार्गदर्शिका		140
कुंजिकाः मा.वि.सू. देश व उनकी श्रेणी, 2012		143
सांख्यिकीय सारणियाँ		
1.	मानव विकास सूचकांक और इसके संघटक	144
2.	मानव विकास सूचकांक प्रवृत्तियाँ, 1980-2012	148
3.	असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक	152
4.	लैंगिक असमानता सूचकांक	156
5.	बहुआयामी निर्धनता सूचकांक	160
6.	संसाधनों पर नियंत्रण	162
7.	स्वास्थ्य	166
8.	शिक्षा	170
9.	सामाजिक एकीकरण	174
10.	वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह	178
11.	अंतरराष्ट्रीय पूँजी प्रवाह एवं प्रवास	182
12.	नवाचार और प्रौद्योगिकी	186
13.	पर्यावरण	190
14.	जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ	194
क्षेत्र		198
सांख्यिकीय संदर्भ		199
तकनीकी परिशिष्टः पूर्वानुमान क्रियाविधि पर व्याख्यात्मक टीप		200

बॉक्स

1.1	न्यायसंगतताः समष्टि अर्थशास्त्र और मानव विकास	22
1.2	अल्पकालीन कटौती के दीर्घकालीन परिणामःअफ्रीका में प्रजनन दर में बढ़ोतरी	22
1.3	एक मनुष्य होना क्या होना है?	24
1.4	खुशहाली के व्यक्तिनिष्ठ सूचकः दृष्टिकोण और नीति में बढ़ी हुई स्वीकृति	28
1.5	असमानता मानव विकास को रोकती है	31
1.6	शिक्षा गुणवत्ताः अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम पर उपलब्धि	33
1.7	सामाजिक कुशलताएँःव्यक्ति से परे मानव विकास	36
1.8	निर्धनता के संरचनात्मक आयाम	37
2.1	दक्षिण का वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण और मानव विकास	44
2.2	उत्तरी ब्रांडों का दक्षिण द्वारा अधिग्रहण	48
2.3	जोड़ने वाले सम्बन्धः उत्तर और दक्षिण की पारस्परिक निर्भरता	49
2.4	मोबाइल फ़ोन और पलापा रिंगः इण्डोनेशिया को जोड़ते हुए	51
2.5	प्रतियोगी दुनिया में सम्मानजनक रोज़गार	53
2.6	अंतिम संयोजन निचले स्तर की मजदूरी से कहीं अधिक है	54
2.7	ज़ाम्बिया में ब्राज़ील, चीन और भारत के कार्य	57
3.1	इतिहास और शुरुआती परिस्थितियों का महत्व है लेकिन वे नियति नहीं हैं	65
3.2	विकासपरक राज्य से क्या आशय? और क्या उसे सत्तावादी होना चाहिए?	67
3.3	जापान और त्रिकोणीय सहकार	68

3.4 कृषि में निवेश 69
3.5 पूर्वी यूरोप और मध्य एशियाः जहाँ उत्तर और दक्षिण का मिलन होता है 70
3.6 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रगतिशील निर्णय दिया हैः निजी स्कूलों में सुविधाहीन तबके के बच्चों के लिए सीटें अनिवार्य होंगी 79
3.7 बांग्लादेशः बाल जीवितता में नाटकीय प्रगति 81
3.8 तुर्की में सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण 83
3.9 सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम और मैक्सिको का अपॉर्च्युनिडेड्स 84
3.10 निर्धनता उन्मूलन नीति पर परामर्श के लिए न्यूयॉर्क शहर दक्षिण की ओर क्यों देखता है 85
4.1 कोरिया गणतंत्र और भारत में जनसंख्या की सम्भावनाओ में भिन्नता क्यों 88
4.2 चीन और घानाः जनसांख्यिकीय लाभांश से कौन लाभान्वित? 100
5.1 सार्वजनिक और निजी के बीच की बदलती रेखाः परिवहन 106
5.2 वैश्विक लोकतंत्र के लिए विश्व संसद 112
5.3 एशिया में क्षेत्रीय अर्थ प्रबंधनः चियांग माई इनीशियेटिव मल्टीलेटराइज़ेशन और एशियाई विकास बैंक 114
5.4 सी.ए.एफः लैटिन अमेरिका का एक विकास बैंक 115

रेखांकन

1. मा.वि.सू. पर त्वरित गति से प्रगति 12
2. दक्षिण के 40 से अधिक देशों ने 1990 और 2012 के बीच मा.वि.सू. में बेहतरीन प्रदर्शन करा, जो उनके पिछले प्रदर्शन से लगाए गए अनुमानों से ज़्यादा था 12
3. 2050 में चीन, भारत और ब्राज़ील का 1950 के 10% हिस्से से बढ़कर वैश्विक उत्पाद में 40% हिस्सा होगा 13
4. दक्षिण में मध्यम वर्ग के लगातार बढ़ने के अनुमान हैं 14
5. दक्षिण में इंटरनेट के इस्तेमाल में अभूतपूर्व बढ़त सबसे ज़्यादा पिछले दशक में हुई 15
6. कम से कम 15 विकासशील देशों के, 100 से अधिक देशों से ठोस व्यापारिक सम्बन्ध है, निर्यातक व आयातक, दोनों के रूप में 16
7. देश, समूह वार आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार 18
1.1 प्रति व्यक्ति आय सभी चार मा.वि.सू. समूहों में अलग-अलग मात्रा में बढ़ रही है 26
1.2 पिछले दशक में सब-सहारा अफ्रीका ने निरन्तर आय वृद्धि को हासिल किया 26
1.3 जितना नीचा मा.वि.सू., उतना बड़ा आय निर्धनता और बहुआयामी निर्धनता के बीच अंतराल 29
1.4 आय निर्धनता और बहुआयामी निर्धनता के अंतर को लेकर देशों के बीच खासी भिन्नताएँ हैं 30
1.5 मा.वि.सू. और उसके आयामों में असमानता के कारण हानि 31
1.6 अधिकतर क्षेत्र स्वास्थ्य व वैश्विक असमानता में गिरावट और आय असमानता में बढ़ोतरी दर्शाते हैं 32
1.7 कम ही देश उच्च मा.वि.सू., और जो टिकाऊ नीचा पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट मानव विकास के लिए ज़रूरी है, दोनो दिखाते हैं 35
1.8 विकास हमेशा सैन्य खर्च की वृद्धि के साथ नहीं होता 40
2.1 विश्व वस्तु व्यापार के हिस्से के रूप में दक्षिण-दक्षिण व्यापार 1980-2011 में तिगुने से ज़्यादा हो गया, जबकि उत्तर-उत्तर व्यापार घटा 46
2.2 दक्षिणी देशों से, और उनको किये जाने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 1990 के बाद से तेज़ी से बढ़ा है 47
2.3 2000 और 2010 के बीच 60 विकासशील देशों में इंटरनेट उपयोग की वार्षिक वृद्धि 30% से अधिक थी 50
2.4 प्रति व्यक्ति निर्यात आय और मानव विकास के बीच में उच्च सह-सम्बन्ध 52
2.5 वर्तमान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पिछले वर्षों के स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धियों से सकारात्मक सह-सम्बन्ध है 53
2.6 उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं ने 1995 के बाद भारी विदेशी मुद्रा एकत्र की है 58
3.1 कुछ देशों ने मा.वि.सू. के ग़ैर-आय और आय, दोनों आयामों पर बेहतर प्रदर्शन किया है 63
3.2 वर्तमान मा.वि.सू. मान और पूर्व में किए गए सार्वजनिक खर्चों में सकारात्मक सम्बन्ध है 71
3.3 उसी तरह बाल जीवितता की मौजूदा स्थिति और स्वास्थ्य पर किए गए पूर्ववर्ती सार्वजनिक खर्च भी सम्बन्धित हैं 71
4.1 तीव्र गति परिदृश्य के तहत शिक्षा के परिणाम बेहतर हो जाते हैं 92
4.2 अधिसंख्य देशों में रोज़गार के अवसर शैक्षिक उपलब्धता की गति के साथ नहीं बढ़ पाए 93
4.3 मानव विकास सूचकांक के प्रत्येक स्तर पर कुछ देशों की कार्बन उत्पादकता दूसरों से ज़्यादा है 94
4.4 विभिन्न पर्यावरणीय परिदृश्यों का चरम निर्धनता पर अलग-अलग प्रभाव होता है 96
4.5 शिक्षा नीतियाँ निर्भरता अनुपात को बदल सकती हैं 98
4.6 विकासशील देशों में आबादियाँ तेज़ी से बूढ़ी हो रही हैं 101
4.7 तीव्र गति परिदृश्य में 2050 के लिए मानव विकास सभावनाएँ बहुत अधिक हैं, विशेषतौर पर निम्न मा.वि.सू. देशों के लिए 101
4.8 वर्ष 2050 तक मानव विकास उपलब्धियों में सुधार तीव्र गति परिदृश्य में अधिक होगा 102
4.9 तीव्र गति परिदृश्य में 2050 तक के लिए प्रति व्यक्ति स.घ.उ. में बढ़त बहुत मज़बूत दिखती है 103
5.1 तीव्र गति परिदृश्य के तहत मानव विकास सूचकांक में सबसे बड़ा अनुमानित सुधार सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में होगा 118
5.2 जी-20 के नौ देशों के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक छोटे से अंश मात्र से सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया की अधोसंरचना के लिए काफ़ी मात्रा में अतिरिक्त सार्वजनिक संसाधनों की व्यवस्था हो सकेगी 118

मानचित्र

1.1 हत्या दर और मा.वि.सू. मान के बीच एक सूक्ष्म नकारात्मक सम्बन्ध है 39
1.2 थाइलैण्ड का निर्यात विस्तार, 1995-2011 45

सारणी

1.1 क्षेत्रवार और मा.वि.सू. समूह के अनुसार मा.वि.सू. और उसके आयाम, 2012 25
1.2 2012 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से बेहतर मा.वि.सू. पर प्रदर्शन करने वाले पाँच शीर्ष देश 27
1.3 असमानता और चयन की स्वतंत्रता और समुदाय के साथ संतुष्टि 38
2.1 2000-2001 और 2010-2011 में सबसे कम विकसित देशों का चीन से व्यापार (मिलियन डॉलर में, वर्तमान विनियम दरों पर) 46
2.2 विकास साझेदारियों के विभिन्न मॉडल 56
3.1 चुनिंदा विकासशील देश जिन्होंने मा.वि.सू. मान में कमी को बड़े पैमाने पर कम किया अथवा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (स.रा.आ.) में उच्च प्रगति दर दर्ज की, 1990-2012 64
3.2 मानव विकास में उच्च उपलब्धियों वाले देशों की वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी, 1985-1990 और 2005-2010 75
4.1 पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर, माँ के शैक्षिक स्तर के अनुसार 89
4.2 शिक्षा के परिदृश्य, 2010-2015, 2025-2030 तथा 2045-2050, के अनुसार पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित मृत्यु संख्या 90
4.3 पर्यावरणीय आपदा परिदृश्य में क्षेत्रानुसार चरम आय निर्धनता में जी रही आबादी, 2010-2050 96
4.4 चुनिंदा देशों में निर्भरता अनुपात की प्रवृत्तियाँ, 1970-2050 99
4.5 क्षेत्र और चुनिंदा देशों के अनुसार चरम निर्धनता में रह रहे लोग, आधारिक और तीव्र गति परिदृश्य, 2010-2050 103

‘‘जब हम सब जोख़िम से बचते हैं,
हम अपने लिए एक अत्यंत असुरिक्षत
दुनिया तैयार करते हैं।’’

डेग हर्मेरस्क्योल्ड

विहगावलोकन

हाल के वर्षों का सबसे सुखद घटनाक्रम रहा है अनेक देशों में मानव विकास की दिशा में हुई व्यापक प्रगति और उनका वैश्विक मंच पर उदयः 'दक्षिण का उदय'। आवाज़ों और शक्ति की यह बढ़ती विविधता उन सिद्धांतों को चुनौती दे रही है जिन्होंने द्वितीय विश्व-युद्धोत्तर काल में नीति-निर्माताओं के दिशानिर्देशक सिद्धांतों और प्रमुख संस्थाओं को दिशा दी। दक्षिण की सबलतर होती आवाज़ें अंतरराष्ट्रीय अधिशासन की और अधिक प्रतिनिधि रूपरेखा बनाने पर ज़ोर दे रही हैं, जिसमें लोकतंत्र और समता के सिद्धांत निहित हों।

इतनी ही महत्वपूर्ण यह बात है कि अनेक विकासशील देश इन विचारों को नई शक्ल दे रहे हैं कि मानव विकास का काम किस तरह किया जाए। दक्षिण का उदय केवल नीति-निर्देशों के किसी एक जमे-जमाए सूत्र के अनुपालन के कारण सम्भव नहीं हुआ है। बल्कि स्थानीय परिस्थितियों और अवसरों से दो-चार होने से जन्मी व्यावहारिक नीतियों के कारण हुआ है– इनमें राज्य की विकासपरक भूमिका के और गहरा होने, मानव विकास में सुधार के प्रति संकल्प (शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यों को समर्थन देते हुए) और कारोबार तथा नवाचार के प्रति खुलापन शामिल हैं। फिर भी, भविष्य की प्रगति के लिए ज़रूरी होगा कि नीति-निर्माता समता, अभिव्यक्ति और जवाबदेही, पर्यावरणीय जोखिमों और बदलती जनसांख्यिकी (demography) जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दें।

पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के देश मानव विकास के उच्चतर स्तर की ओर अभिमुख हो रहे हैं, जैसा कि मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) से प्रदर्शित होता है, जो तीन आयामों के तहत सूचकों का एक सम्मिश्रित मापक हैः जीवन प्रत्याशा (Life expectancy), शैक्षिक उपलब्धियाँ और सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए आवश्यक संसाधनों पर अधिकार। निम्न और मध्य मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) देशों में हुई तीव्र प्रगति के साथ ही, सभी समूहों और क्षेत्रों में मा.वि.सू. के घटकों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। इसके आधार पर दुनिया अब कम असमान हो रही है। फिर भी, ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय औसत मानव अनुभव के बड़े विभेद को छिपाते हैं। उत्तर और दक्षिण, दोनों ही क्षेत्रों के देशों में बड़ी असमानताएँ कायम हैं, और अनेक देशों के भीतर और उनके बीच आय की असमानता बढ़ती रही है।

हालाँकि अधिकतर विकासशील देशों ने अच्छा काम किया है, लेकिन एक बड़ी संख्या में देशों ने विशेष तौर पर अच्छा काम किया है– जिसे 'दक्षिण का उदय' कहा जा सकता है। कुछ सबसे बड़े देशों में तेज़ सुधार हुआ है, खास तौर से ब्राज़ील, चीन, भारत, इण्डोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में। छोटी अर्थव्यवस्थाओं, जैसे बांग्लादेश, चिली, घाना, मॉरिशस, रवाण्डा, और ट्यूनीशिया में भी काफ़ी प्रगति हुई है।

दक्षिण का उदय अभूतपूर्व गति और स्तर पर हुआ है। उदाहरण के लिए, एक-एक बिलियन से ज़्यादा आबादी वाले चीन और भारत का आर्थिक उत्थान, जिसके कारण बीस साल से कम समय में प्रति व्यक्ति निर्गत (output) दुगना हो गया– ऐसा आर्थिक बल जिसने औद्योगिक क्रांति से ज़्यादा बड़ी आबादी को प्रभावित किया।[1] सन् 2050 तक ब्राज़ील, चीन और भारत, तीनों मिलाकर क्रय शक्ति समता (purchasing power parity terms) के अर्थों में दुनिया के सकल निर्गत के 40% हिस्सेदार होंगे।

आज के अनिश्चय के दौर में दक्षिण के देश, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर, ग़रीबी को घटाकर और बड़े स्तर पर समृद्धि की रचना करके, सामूहिक रूप से वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ा रहे हैं। उनके सामने अब भी विकट चुनौतियाँ हैं और दुनिया के काफ़ी ग़रीब लोग इन देशों में रहते हैं। पर उन्होंने इस बात को स्थापित कर दिखाया है कि किस प्रकार वैश्वीकरण की मदद से, व्यावहारिक नीतियों और मानव विकास पर खास तौर से ज़ोर देने से उनकी अर्थव्यवस्थाओं में निहित अवसरों को सामने लाया जा सकता है।

बदलती दुनिया, एक अधिक वैश्विक दक्षिण

एक सामान्य पर्यवेक्षक के लिए सन् 2012 का घटनाक्रम दो अलग दुनियाओं की कहानी जैसा हैः पुनरुत्थानशील दक्षिण– जहाँ चीन और भारत जैसे सर्वाधिक चमकदार उदाहरण हैं, जहाँ मानव विकास के क्षेत्र में खासी प्रगति हुई है, विकास तेज़ है और ग़रीबी उन्मूलन का काम उत्साहवर्धक है– और एक संकटग्रस्त उत्तर, जहाँ मितव्ययिता (austerity) की नीतियाँ और आर्थिक विकास की अनुपस्थिति है, लाखों-करोड़ों बेरोज़गारों और सामाजिक सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए परेशानियाँ पैदा हो रहीं हैं। उत्तर और दक्षिण के लिए समान रूप से कुछ और

गहरी समस्याएँ भी हैंः विकसित और विकासशील, दोनों प्रकार के अनेक देशों में बढ़ती असमानता, जो वैश्विक संकट-मुक्ति और भावी प्रगति की संवहनीयता के लिए खतरा है, ग़रीबी उन्मूलन को सीमित कर रही है और पर्यावरण के लिए गम्भीर समस्या पैदा कर रही है।

दक्षिण के उदय और मानव विकास पर उसके प्रभावों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही यह रिपोर्ट दक्षिण के इस उदय के कारण बदलती दुनिया के बारे में भी है। इसमें हासिल की गई प्रगति, सामने आ खड़ी होती चुनौतियों (जिनमें से कुछ इसी सफलता का परिणाम हैं) और विश्व व क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि वैश्विक और क्षेत्रीय अधिशासन की उभरती सम्भावनाओं का आकलन किया गया है।

दक्षिण को उत्तर की ज़रूरत है और दूसरी ओर उत्तर को दक्षिण की ज़रूरत बढ़ती जा रही है।

पुनरुत्थानशील दक्षिण की, सबका ध्यान खींचने वाली यह कथा उत्साह जगाने वाली भी है और कुछ मायनों में ग़लतफ़हमी भी पैदा करती है। दक्षिण को उत्तर की ज़रूरत है और दूसरी ओर, उत्तर को दक्षिण की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। दुनिया अब ज़्यादा जुड़ती जा रही है। हाल के वर्षों में वैश्विक उत्पादन का विलक्षण पुनरभिविन्यास (reorientation) देखने में आया है। उसका रुख अब अंतरराष्ट्रीय कारोबार की ओर पहले से ज़्यादा है, जो सन् 2011 में वैश्विक निर्गत का 60% हो चुका था। सन् 1980 से 2010 के बीच विकासशील देशों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। वैश्विक वस्तु व्यापार में उनका हिस्सा 25% से बढ़कर 47% और निर्गत का हिस्सा 33% से बढ़कर 45% हो गया। विकासशील क्षेत्र एक-दूसरे के साथ अपने सम्बन्ध मज़बूत कर रहे हैं। सन् 1980 से 2010 के बीच दक्षिण-दक्षिण व्यापार, वैश्विक वस्तु व्यापार का 8% से कम था, जो बढ़कर 26% हो गया।

बहरहाल, अमेरिका मौद्रिक अर्थों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भविष्य में जहाँ तक देख पाते हैं, वह इसी स्थिति में रहेगा। यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वापसी (संकट-मुक्ति) में कमी रह जाती है या यूरोप अपनी वर्तमान आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को पार नहीं कर पाता है, तब विकासशील दुनिया को इसका गहरा धक्का लगेगा। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थिकीय दबाव के कारण देशों के बीच आपसी सहयोग की ज़रूरत आज पहले से कहीं ज़्यादा है। जहाँ दक्षिण का उदय अनेक महत्वपूर्ण मसलों में शक्ति-सम्बन्धों को नई शक्ल दे रहा है, वहीं यदि सहयोग विफल हुआ और कड़े फैसले टाले गए, तो कठिनाई से हासिल मानव विकास की उपलब्धियों को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा।

वास्तव में एक कदम आगे जाकर कहा जा सकता है कि उत्तर में एक 'दक्षिण' है और दक्षिण में एक 'उत्तर'। अभिजात वर्ग, चाहे वह उत्तर का हो या दक्षिण का, उत्तरोत्तर वैश्विक है और एक-दूसरे से जुड़ा है। पिछले दशक में पैदा हुई जबर्दस्त समृद्धि का लाभ, आंशिक रूप से वैश्वीकरण के कारण, सबसे ज़्यादा उन्हें मिला है। वे एक ही विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, उनकी जीवन शैली और शायद मूल्य भी एक जैसे हैं।

बदलती विश्व अर्थव्यवस्था मानव विकास की निरंतर प्रगति के सामने अभूतपूर्व चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ पैदा कर रही है। ऐसे दौर में जब दुनिया लगातार वित्तीय संकटों, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन और बढ़ते सामाजिक असंतोष का सामना कर रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संरचनाएँ एक भँवर में हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए साधनों को सुनिश्चित करने या समता और संवहनीयता की ज़्यादा बड़ी माँग को पूरा करने के लिए वैश्विक संस्थाएँ बदलते शक्ति-सम्बन्धों के अनुरूप ढलने में असमर्थ नज़र आती हैं।

यह परिघटना, दक्षिण के देशों द्वारा अपनाए गए अलग-अलग विकास-पथों के साथ मिलने का एक अवसर उपस्थित करती हैः आवाज़ों और शक्ति की बढ़ती विविधता को जगह देने और दीर्घकालीन सुस्थिर विकास के लिए, उन सिद्धांतों की पुनर्रचना की न भी सही, पुनर्समायोजन की ज़रूरत है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्धोत्तर संस्थाओं और नीति-निर्माताओं को दिशा दी। जो दिशा लोगों को आगे रखती है और संस्थाओं को निष्पक्ष और अधिक न्यायपूर्ण बनने को प्रेरित करती है, उसे पुष्ट करने के लिए इन सिद्धांतों पर पुनर्विचार और वैश्विक संस्थाओं में और लचीलापन लाने की ज़रूरत है। विकास-संरचनाओं में बढ़ती विविधता इस प्रकार के वैश्विक संवाद और पुनर्रचना के लिए अवसर और माँग पैदा कर रही है। इसलिए नवाचार, और लोकतंत्र, समता और संवहनीयता के सिद्धातों को साकार करने वाली वैश्विक और क्षेत्रीय अधिशासन संरचनाओं की सम्भावनाओं के दरवाज़े खुले हैं।

ब्राज़ील, चीन और भारत के विकास के रास्ते और बांग्लादेश, मॉरिशस और तुर्की की अपेक्षाकृत अनजानी सफलता-कथाएँ मानव विकास को हासिल करने के विचारों को नई शक्ल दे रहीं हैं। इन देशों की सफलता से 'सही' नीतियों की अवधारणा पर सवाल खड़े होते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि इन सफल देशों के अनुभवों से मूल्यवान सबक नहीं लिये जा सकते। इसके विपरीत, विकास की विविध राहों से, जिसमें राज्य की विकासपरक भूमिका, मानव विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति निष्ठा और व्यापार तथा नवाचार के प्रति खुलापन शामिल हैं, विकास के प्रमुख प्रचालक और सिद्धांत निकल कर आते हैं। और जहाँ यह रिपोर्ट दक्षिण के उदय के सकारात्मक पक्ष को स्वीकार करती है, इस बात को रेखांकित भी करती

है कि भविष्य की नीतियों और रणनीतिओं में समता और संवहनीयता के सरोकारों को पूरी तरह शामिल किया जाए। जैसा 2011 की *मानव विकास रिपोर्ट* में भी जोर दिया गया था, यदि असमानता और पर्यावरण-ध्वंस नीति-विमर्शों की पहली कतार में नहीं होंगे तो मानव विकास की निरंतर प्रगति सम्भव नहीं। विकास के मामले में 'सब चलता है' का नज़रिया और पर्यावरण संकट, दक्षिण में मानव विकास की दिशा में हासिल उपलब्धियों पर पानी फेर देंगे या यह प्रगति असंवहनीय हो जाएगी।

भविष्य को लेकर चिंताएँ उत्तर पर भी लागू होती हैं, जहाँ निम्न आर्थिक विकास, ऊँची बेरोज़गारी दर और मितव्ययिता उपायों ने मानव विकास के उच्च स्तरों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। उत्तर और दक्षिण दोनों जगह, देश और विदेश में, सामाजिक मीडिया-विस्फोट प्रवर्तित, नागरिकों, समुदायों और नागरिक संगठनों की निष्पक्षता और जवाबदेही की बढ़ती माँग को देखते हुए, सत्ताधारी अभिजात वर्ग सामाजिक समावेशन और कल्याण के सामने खड़े इन खतरों की अनदेखी नहीं कर सकते।

इन समकालीन और उदीयमान वैश्विक सच्चाइयों को संबोधित करने वाले नीति-निर्माण और शोध के लिए ऐसे कदमों और विश्लेषणों की आवश्यकता है जो मानव विकास की अवधारणा को और विस्तृत बना सकें। *मानव विकास रिपोर्ट* और मानव विकास संकेतकों के समूह को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं के आकलन से आगे जाकर सामाजिक स्तर की क्षमताओं, सरोकारों और अनुभूतियों को शामिल करना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की व्यक्तिगत उपलब्धियाँ और अनुभूतियाँ, यद्यपि अनिवार्य हैं, लेकिन मानव विकास में प्रगति की गारंटी नहीं देतीं अगर सामाजिक स्थितियाँ व्यक्तिगत उपलब्धियों को सीमित करती हों या प्रगति के बारे में बोध भिन्न हों। अरब देशों में जन-असंतोष यह बताता है कि लोग, खासकर युवा, जो पिछली पीढ़ी से ज़्यादा शिक्षित और स्वस्थ हैं, सार्थक रोज़गार, अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में आवाज़ उठाने और सम्मान के साथ पेश आने को महत्वपूर्ण मानते हैं।

इसके साथ ही, सामाजिक संघटन और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहन, जो ब्राज़ील जैसे देशों की विकास रणनीति का घोषित लक्ष्य है, एक एकीकृत समाज के सकारात्मक विकास-प्रभाव के प्रमाण पर आधारित है। किशोर-गर्भावस्थाओं से लेकर आत्महत्या की दरों तक, अधिक समतापूर्ण समाज मानव विकास के अधिकतर पैमानों पर, असमतापूर्ण समाजों से बेहतर साबित होते हैं। यह तथ्य विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में किए गए अध्ययनों से ज़ाहिर हुआ है। विकास के समाज-स्तरीय पक्षों पर अतीत की विकास-अवधारणाओं में कम ध्यान दिया गया है, पर वे अब विकास की दीर्घकालिक राह में अनिवार्य तत्व साबित हो रहे हैं।

दूसरे देशों को आगे आने में मदद करना

दक्षिण के उदय में सभी विकासशील देश अब भी पूरी तरह हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उदाहरण के लिए सबसे कम विकसित 49 देशों की सूची के अधिकांश देशों में बदलाव की गति धीमी है। खासतौर से उन देशों में जो स्थल-रुद्ध (landlocked) हैं या वैश्विक बाज़ारों से दूर हैं। फिर भी, इनमें से अनेक देशों को दक्षिण-दक्षिण व्यापार, निवेश, वित्त और तकीनीकी अंतरण का लाभ मिला है। मसलन, चीन की सकारात्मक संवृद्धि के छलकाव (spillovers) से दूसरे देशों, खासकर नज़दीकी व्यापार भागीदारों को लाभ मिला है। इससे विकसित देशों से घटी माँग के कारण पड़ा असर भी दूर हुआ है। अनुमान है कि यदि चीन और भारत में भी विकसित देशों की तरह विकास दर उसी गति से कम हुई होती तो 2007 से 2010 के निम्न-आय देशों की विकास दर 0.3 से 1.1% अंक कम होती।[2]

बहुत से देशों को इस छलकाव का लाभ महत्वपूर्ण मानव विकास क्षेत्रकों में मिला है, विशेषतः स्वास्थ्य में। उदाहरण के लिए, भारतीय फर्में किफ़ायती दवाओं, मेडिकल उपकरणों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं की सप्लाई अफ्रीका के देशों में कर रही हैं। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की कम्पनियाँ भी ऐसा ही असर डाल रही हैं।

बढ़ते प्रतिस्पर्धी दबाव

फिर भी, विशालतर देशों से आने वाले निर्यात के नुकसान भी हो सकते हैं। बड़े देश प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बनाते हैं, जो लघुतर देशों के आर्थिक विस्तार और औद्योगीकरण को कुंठित कर सकते हैं। पर ऐसे प्रतिस्पर्धी झटकों के बावजूद औद्योगिक पुनरुद्धार के उदाहरण भी हैं। आज की प्रतिस्पर्धी भूमिका भविष्य में आसानी से सहकारिता बन सकती है। पर यह, सहकारिता की ओर बढ़ना उन नीतियों पर निर्भर है जो स्थानीय एजेंटों को नई परिस्थितियों का लाभ दिलाती हैं।

दक्षिण के देशों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंजन उनका घरेलू बाज़ार है। मध्य वर्ग अपने आकार और माध्यिकामान आमदनी में बढ़ता जा रहा है। सन् 2025 तक उदीयमान बाज़ारों का सालाना उपभोग 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। तब तक दुनिया में 20,000 डॉलर सालाना आमदनी से ज़्यादा वाले 1 बिलियन परिवारों में से

स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की व्यक्तिगत उपलब्धियाँ यद्यपि अनिवार्य हैं, लेकिन मानव विकास में प्रगति की गारंटी नहीं देतीं, अगर सामाजिक स्थितियाँ व्यक्तिगत उपलब्धियों को सीमित करती हों या प्रगति के बारे में बोध भिन्न हों

तीन पंचमांश, यानी 60 फीसदी दक्षिण में होंगे। फिर भी, यह विस्तार वंचितताओं के बड़े द्वीपों से अवरुद्ध भी होगा। ये असमानताएँ न केवल अपने आप में अवांछनीय हैं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा करके प्रगति की संवहनीयता में भी बाधक बनती हैं।

ये रुझान एक अधिक संतुलित विश्व की ओर ले जा रहे हैं। केन्द्र में औद्योगिक देशों और परिधि में अनेक कम औद्योगिक देशों के बजाय अब एक ज़्यादा जटिल और गतिशील माहौल तैयार हो रहा है।

जहाँ वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर इस बात को लेकर काफ़ी जागरूकता है कि दुनिया रूपांतरित हो रही है, वहीं नेता, संस्थाएँ और विद्वान ऐसे सिद्धांतों, संस्थाओं और नीतियों को पेश करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, जो ज़्यादा न्यायसंगत और संवहनीय विश्व की रचना का अगला कदम साबित हों। शायद आंशिक रूप से ऐसा इसलिए है कि दुनिया इतनी तेज़ी से और इतने मोर्चों पर बदल रही है कि एक साझा आकलन मुश्किल और सामूहिक कदम उठाना पहुँच से बाहर लगता है। इस विमर्श में योगदान के रूप में यह रिपोर्ट समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य के विवेचनात्मक आकलन और उन सिद्धातों और अवधारणाओं को बढ़ाने की कोशिश है जो विविधता भरी दुनिया को उन मानव विकास रणनीतियों की ओर ले जाएँ जो 21 वीं सदी की नई चुनौतियों का मुकाबला करें, ग़रीबी को कम या पूरी तरह खत्म करें और सबकी प्रगति के द्वार खोलें।

नीतियाँ, भागीदारियाँ, सिद्धांत

दक्षिण के इतने देश मानव विकास सम्भावनाओं के रूपांतरण में किस प्रकार सफल हो पाए? अधिकतर, इन देशों में विकास के तीन उल्लेखनीय प्रचालक काम करते रहे हैं : एक प्रसक्रिय विकासात्मक राज्य; वैश्विक बाज़ारों का दोहन, और दृढ़संकल्पी सामाजिक नीति नवाचार। ये प्रचालक उन अमूर्त अवधारणाओं से नहीं निकले हैं कि विकास कैसे काम करे। बल्कि उनका प्रदर्शन अनेक देशों के विकास रूपांतरण अनुभवों से होता है। वस्तुतः वे पूर्वधारित और निर्देशात्मक उपागमों (approaches) को चुनौती देते हैं। एक ओर वे अनेक समूहात्मक, केन्द्र-प्रबंधित धारणाओं को रद्द करते हैं; दूसरी ओर वे वॉशिंगटन कंसेंसस द्वारा समर्थित निर्बाध उदारीकरण से भी दूर रहते हैं।

सफलता विश्व अर्थव्यवस्था के साथ धीरे-धीरे और क्रमिक रूप से जुड़ने और लोगों, संस्थाओं और अधोसंरचना पर निवेश करने पर मिलती है

प्रचालक 1 : एक प्रसक्रिय विकासपरक राज्य

एक मज़बूत, प्रसक्रिय और ज़िम्मेदार राज्य सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रकों के लिए नीतियाँ बनाता है– दूरगामी दृष्टि और नेतृत्व, साझा कायदों और मूल्यों तथा भरोसा और संघटन पैदा करने वाले नियमों और संस्थाओं के आधार पर। संवहनीय रूपांतरण को हासिल करने के लिए देशों को विकास की एक संतुलित पद्धति बनानी होगी। जो देश आमदनी और मानव विकास को हासिल करने और उसे बनाए रखने में कामयाब हुए हैं, किसी एक फॉर्मूले पर नहीं चले। अलग-अलग चुनौतियों के लिए उन्होंने बाज़ार नियमन, निर्यात प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास, और तकनीकी प्रगति की अलग-अलग नीतियों को अपनाया। प्राथमिकताएँ जनोन्मुखी होनी चाहिए, जो लोगों को जोखिमों से बचाते हुए अवसर तैयार करें। सरकारें ऐसे उद्योगों का पोषण कर सकती हैं जो अधूरे बाज़ारों के कारण अन्यथा उभर नहीं पाते। व्यापारियों द्वारा स्थितियों का अनुचित लाभ उठाने और सरकारी भाई-भतीजावाद (cronyism) के जोखिम के बावजूद दक्षिण के अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं के खुलने के बाद वहाँ के अनेक अकुशल उद्योग निर्यात सफलता के प्रचालक साबित हो गए।

बड़े और जटिल समाजों में किसी भी खास नीति का परिणाम अनिश्चित ही होता है। विकासपरक राज्य को इसलिए व्यावहारिक होना चाहिए और उसे विभिन्न पद्धतियों को परखना चाहिए। कुछ लक्षण अलग दिखाई पड़ते हैंः मसलन जनोन्मुखी विकासपरक राज्यों ने बुनियादी सामाजिक सेवाओं का विस्तार किया है। व्यक्तियों की क्षमताओं पर किया गया निवेश– स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के मार्फ़त–विकास प्रक्रिया का संलग्नक न होकर उसका अंतर्निहित हिस्सा है। अच्छे रोज़गारों में तेज़ विस्तार मानव विकास को बढ़ावा देने वाली वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है।

प्रचालक 2 : वैश्विक बाज़ारों का दोहन

प्रगति को बढ़ावा देने में वैश्विक बाज़ार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी नव औद्योगिक देश ''बाकी दुनिया जो जानती है, उसका आयात और जो वह चाहती है, उसका निर्यात'' की रणनीति पर चल रहे हैं। पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन बाज़ारों से 'जुड़ने की शर्तें'। लोगों पर निवेश किए बग़ैर वैश्विक बाज़ारों से प्रतिलाभ सीमित होता है। बाज़ारों के अचानक खुलने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ धीरे-धीरे और क्रमिक रूप से जुड़ने, राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप और लोगों, संस्थाओं और अधोसंरचना पर निवेश करने पर मिलती है। छोटी अर्थव्यवस्थाएँ विशिष्ट उत्पादों (niche products) पर ध्यान केन्द्रित करने में सफल रहीं हैं, उनकी सफलता विद्यमान या नई क्षमताओं के

निर्माण और लम्बे समय तक सरकारी समर्थन का परिणाम होती है।

प्रचालक 3 : संकल्पशील सामाजिक नीति नवाचार

कुछ ही देश हैं, जो सिर्फ अधोसंरचना पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर, प्रभावशाली सार्वजनिक निवेश के बग़ैर निरंतर तीव्र संवृद्धि पाने में सफल हुए हैं। एक ऐसे चक्र की रचना का लक्ष्य होना चाहिए, जहाँ संवृद्धि और सामाजिक नीति एक-दूसरे को मज़बूत करे। जिन देशों में आय में असमानता कम है, वहाँ की आर्थिक संवृद्धि ग़रीबी दूर करने में ज़्यादा सफल हुई है, मुकाबले उन देशों के जहाँ असमानता का स्तर ऊँचा है। विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रजातीय समूहों के बीच समानता को बढ़ावा देने से सामाजिक टकराव को कम करने में मदद मिलती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी सशक्तीकरण, और सामाजिक संगठन, सब ग़रीब लोगों को विकास में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करते हैं। क्षेत्रक संतुलन (sectoral balance)– खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देना– और रोज़गार विस्तार की गति और प्रकृति की यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि संवृद्धि किस सीमा तक आय को फैलाती है। पर बुनियादी नीति के ये उपकरण भी मताधिकार से वंचित समूहों को सशक्त नहीं बना सकते। समाज के हाशिए पर जा चुके ग़रीब अपनी समस्याओं को उठाने की कोशिश करते हैं, पर सरकारें हमेशा यह सुनिश्चित नहीं करतीं कि सेवाएँ सभी तक पहुँचें। सामाजिक नीति समावेश को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए– भेदभाव रहित और समान बर्ताव सुनिश्चित करना राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है– और इसे बुनियादी सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध करानी चाहिए जो स्वस्थ और शिक्षित श्रमशक्ति के उद्भव का समर्थन करके दीर्घकालीन आर्थिक विकास को रेखांकित करे। ज़रूरी नहीं कि ये सारी सेवाएँ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएँ। पर राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों की मानव विकास की बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच हो।

इस प्रकार विकास रूपांतरण का कार्य बहुमुखी है। इसके तहत बुनियादी सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर ग़रीब लोगों की परिसम्पत्ति बढ़ाई जाती है। राज्य और सामाजिक संस्थाओं के क्रिया-कलाप को इस प्रकार सुधारा जाता है जिससे संवृद्धि और समानता, दोनों को बढ़ावा मिले। आर्थिक क्रियाशीलता और सामाजिक गतिशीलता के सामने नौकरशाही और सामाजिक रुकावटों को दूर करने का काम भी यह करता है। बजट प्राथमिकताओं को तय करने में यह समुदाय को जोड़ता है और नेतृत्व को जवाबदेह बनाता है।

संवेग की संवहनीयता

दक्षिण के अनेक देशों ने काफ़ी सफलता का प्रदर्शन किया है। पर उच्चतर उपलब्धियों वाले देशों में भी भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं है। दक्षिण के देश किस प्रकार मानव विकास की अपनी प्रगति को जारी रखें और किस प्रकार यह प्रगति दूसरे देशों तक बढ़ाई जा सकेगी? यह रिपोर्ट इस काम को सुनिश्चित करने के लिए चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सुझाव देती है : समता बढ़ाना, आवाज़ और भागीदारी को संभव बनाना, पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना; और जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रबंधन। यह रिपोर्ट निष्क्रियता की भारी कीमत की ओर इशारा करती है और वृहत्तर नीतिगत महत्वाकांक्षा की पक्षकार है।

कुछ ही देश हैं जो सिर्फ अधोसंरचना पर ही नही, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर, प्रभावशाली सार्वजनिक निवेश के बग़ैर निरंतर तीव्र संवृद्धि पाने में सफल हुए हैं

समता बढ़ाना

स्त्रियों और पुरुषों तथा अन्य समूहों के बीच ज़्यादा समानता न सिर्फ अपने आप में ज़रूरी है, बल्कि मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए सबसे ताकतवर उपकरणों में से एक शिक्षा है, जो लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर रोज़गार पाने में मदद करती है, सार्वजनिक विमर्श से जोड़ती है और सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और अन्य हकदारियों को माँगती है।

शिक्षा का स्वास्थ्य और नैतिकता पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। इस रिपोर्ट के लिए किया गया शोध दर्शाता है कि बच्चे के जीवित रहने में घर की आय से ज़्यादा माता की शिक्षा के स्तर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शोध दिखाते हैं कि जिन देशों व क्षेत्रों में शिक्षा के शुरुआती परिणाम अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं, वहाँ नीतिगत हस्तक्षेपों का असर ज़्यादा होता है। इसके गहरे नीतिगत निहितार्थ हैं, जो परिवार की आय बढ़ाने के बजाय लड़की की शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं।

यह रिपोर्ट नीतिगत महत्वाकांक्षा का मज़बूती से समर्थन करती है। एक तीव्र गति परिदृश्य बताता है कि निम्न मानव विकास सूचकांक देश उच्च और अति उच्च मा.वि.सू. देशों के विकास स्तर की ओर अभिमुख हो सकते हैं। सन् 2050 तक सब-सहारा अफ्रीका में सकल मानव विकास सूचकांक 52% तक (0.402 से बढ़कर 0.612) और दक्षिण एशिया में 36% तक (0.527 से 0.714) बढ़ सकता है। ऐसे नीतिगत हस्तक्षेप ग़रीबी के खिलाफ़

लड़ाई में भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इसके विपरीत निष्क्रियता की कीमत बढ़ेगी, खासतौर से निम्न मानव सूचकांक वाले देशों में, जो ज़्यादा अरक्षित हैं। उदाहरण के लिए, महत्वाकांक्षी सार्वभौमिक शिक्षा नीतियों को लागू करने में विफलता भावी पीढ़ियों के विकास के अनेक आवश्यक स्तम्भों को प्रभावित करेगी।

अभिव्यक्ति और सहभागिता

जबतक लोग उन घटनाओं और प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होते जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, मानव विकास के रास्ते न तो वांछनीय होंगे और न संवहनीय

जबतक लोग उन घटनाओं और प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होते, जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, मानव विकास के रास्ते न तो वांछनीय होंगे और न संवहनीय। लोगों को नीति-निर्माण और परिणामों को प्रभावित करने लायक बनना चाहिए और युवा लोगों को खासतौर से वृहत्तर आर्थिक अवसर, राजनीतिक भागीदारी और जवाबदेही दिखने को मिलनी चाहिए।

उत्तर और दक्षिण, दोनों जगह असंतोष का स्तर ऊँचा होता जा रहा है, जनता अपनी चिंताओं को अभिव्यक्ति देने के ज़्यादा अवसर और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को प्रभावित करना चाहती है। आंशिक रूप से यह पढ़े-लिखे युवा वर्ग के लिए उपलब्ध सीमित रोज़गार अवसरों की प्रतिक्रिया है। ग़ैर-ज़िम्मेदार सरकारों के खिलाफ़ जन-विद्रोह की घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। ऐसी खलबली मानव विकास को पटरी से उतार सकती है– क्योंकि असंतोष से निवेश और संवृद्धि रुकती है– और निरंकुश सरकारें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए साधनों को उधर लगा देती हैं।

इस बात की भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि समाज किस वक्त असंतोष के अनिवर्ती बिन्दु (tipping point) पर पहुँचेगा। जन रोष, खासतौर से पढ़े-लिखे लोगों का गुस्सा, तब फूटता है, जब वे राजनीतिक प्रभाव के दायरे से खुद को बाहर पाते हैं और निराशाजनक आर्थिक सम्भावनाएँ ऐसे विरोध-प्रदर्शनों में शामिल होने की कीमत को घटा देती हैं। राजनीतिक भागीदारी के इस प्रयत्न-सघन स्वरूप का समन्वय जन-संचार के नए माध्यम आसानी से कर लेते हैं।

पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना

जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय खतरे, वनोन्मूलन, वायु और जल प्रदूषण, तथा प्राकृतिक आपदाएँ सबको प्रभावित करती हैं। पर वे ग़रीब देशों और ग़रीब समुदायों को ज़्यादा कष्ट पहुँचाती हैं। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए प्रकोप बनकर मँडरा रहा है, पारिस्थितिकीय तंत्र क्षतियाँ आजीविका अवसरों को प्रभावित कर रहीं हैं, खासतौर से ग़रीबों के।

हालाँकि निम्न मा.वि.सू. देश वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार हैं, पर वार्षिक वर्षा और इसमें होने वाले बदलाव से कृषि उत्पादों और जीवन पर पड़ने वाले असर के सबसे बड़े शिकार वही होते हैं। क्षति की यह तीव्रता अनुकूलन उपायों की अत्यावश्यकता को रेखांकित करती है।

निष्क्रियता की कीमत ऊँची होगी। जितनी लम्बी निष्क्रियता, उतनी ऊँची कीमत। संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को सुनिश्चित करने के लिए, नई नीतियों और संरचनात्मक बदलावों की ज़रूरत होगी, जो मानव विकास को निम्न-उत्सर्जन के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों, जलवायु प्रतिरोधी रणनीतियों और नवाचारी सार्वजनिक-निजी वित्त-पोषण व्यवस्थाओं के साथ जोड़े।

जनसांख्यिकीय बदलावों का प्रबंधन

वर्ष 1970 और 2011 के दौरान वैश्विक जनसंख्या 3.6 बिलियन से बढ़कर 7 बिलियन हो गई। वैश्विक आबादी के अधिक शिक्षित होने के साथ ही इसकी वृद्धि दर धीमी होगी। इसके अलावा, विकास की संभावनाएँ न केवल लोगों की कुल संख्या से, बल्कि आबादी की आयु संरचना से भी प्रभावित हुई हैं। एक बढ़ता हुआ गंभीर चिंता का विषय किसी देश का निर्भरता अनुपात है– यानी, कार्यशील आयु 15-64 की आबादी से विभाजित बच्चों और वृद्धों की संख्या।

कुछ ग़रीब क्षेत्रों को ''जनसांख्यिकी'' लाभांश से फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि कार्यशील-आयु वाली आबादी की हिस्सेदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा मज़बूत नीतिगत कार्रवाई की दशा में ही होगा।[3] संभावित जनसांख्यिकी लाभांश के लिए बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षित महिलाओं में कम, स्वस्थ और बेहतर शिक्षित बच्चों के प्रति रुझान होता है; कई देशों में, शिक्षित महिलाएँ अशिक्षित श्रमिकों के मुकाबले अधिक वेतन का आनंद भी लेती हैं।

इसके विपरीत, दक्षिण के धनी क्षेत्र एक काफ़ी अलग समस्या का सामना कर रहे हैं: जैस-जैसे उनकी जनसंख्या उम्रदराज़ होती है, कार्यशील-आयु वाली जनसंख्या की हिस्सेदारी घटती है। जनसंख्या आयुवृद्धि की दर महत्व रखती है क्योंकि यदि विकासशील देश ग़रीब ही बने रहते हैं तो उन्हें अपनी वृद्ध आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कई विकासशील देशों के पास जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए फ़िलहाल केवल थोड़े से ही अवसर उपलब्ध हैं।

जनसांख्यिकीय रुझान हालाँकि नियति नहीं हैं। खासतौर से उन्हें शिक्षा नीतियों के ज़रिये बदला जा सकता है। यह रिपोर्ट 2010-2050 के लिए दो परिदृश्य प्रस्तुत करती हैः एक है आधारिक परिदृश्य, जिसमें मौजूदा शैक्षिक रुझान जारी हैं, और दूसरा है तीव्र-गति परिदृश्य, जिसमें न्यूनतम शुरुआती स्तर वाले देश महत्वाकांक्षी शैक्षिक लक्ष्य तय करते हैं। निम्न मा.वि.सू. देशों के लिए तीव्र-गति परिदृश्य के तहत निर्भरता अनुपात में कमी, आधारिक परिदृश्य के तहत कमी के मुकाबले दोगुनी से अधिक होती है। महत्वाकांक्षी शैक्षिक नीतियाँ मध्यम और उच्च मा.वि. सू. देशों को उनके निर्भरता अनुपात में अनुमानित वृद्धि को काबू करने में सक्षम बना सकती हैं, इस तरह उम्रदराज़ आबादी की ओर जनसांख्यिकीय परिवर्तन सहज हो जाता है।

इन जनसांख्यिकीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए शिक्षा प्राप्ति के स्तर को बढ़ाने की ज़रूरत होगी जबकि बेरोज़गारी को घटाकर, श्रम उत्पादकता को बढ़ावा देकर और खासतौर से महिलाओं तथा उम्रदराज़ श्रमिकों की श्रम बल भागीदारी को बढ़ाकर उत्पादक रोज़गार के अवसरों का विस्तार करना होगा।

नए युग के लिए अधिशासन और साझेदारियाँ

दक्षिण का उदय हमारी तेजी से अंतर्संपृक्त होती दुनिया की दुर्जेय समस्याओं के लिए अवसर भी उपलब्ध कराता है और चुनौतियाँ भी। जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन, वैश्विक सामुदायिक संसाधनों का इस्तेमाल, और वाणिज्य, वित्त और प्रवास का नियमन जैसी चुनौतियों के सीमा पार प्रभाव हैं। वैश्विक सार्वजनिक सुविधाओं के कुछ घटक क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन प्रभावी प्रावधान के लिए आमतौर पर यथेष्ट बहुपक्षीय समन्वय और सहयोग की ज़रूरत होती है। न तो उत्तर और न ही नव प्रभावशाली दक्षिण क्षेत्रीय या वैश्विक वार्ताओं से अलग रह सकते हैं, जो इन विषयों पर सहमति कायम करने के लिए ज़रूरी है। दक्षिण के देश क्षेत्रीय और बहुपक्षीय प्रक्रियाओं को मज़बूत बनाने के लिए न सिर्फ वित्तीय संसाधनों का योगदान करने की स्थिति में हैं, बल्कि अपनी मानव विकास उपलब्धियों और इनमें से कई क्षेत्रों में व्यावहारिक नीतियों से मिले पर्याप्त अनुभवों को उपलब्ध करा सकते हैं।

दक्षिण ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों और वित्तीय प्रणालियों जैसे नये समझौतों और संस्थानों को बढ़ावा दिया है। परिणाम स्वरूप, आज अंतरराष्ट्रीय अधिशासन की व्यवस्था पुरानी संरचना और नये समझौतों का तानाबाना है। और वे कहीं अधिक विविधीकृत बन सकते हैंः अंतरराष्ट्रीय सहयोग में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रक्रियाओं की कहीं अधिक जटिल बनावट शामिल हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय अधिशासन के ज़्यादातर मौजूदा संस्थान और सिद्धान्त आज के मुकाबले एक काफ़ी अलग दुनिया के लिए तैयार किये गए थे। इसका एक परिणाम यह है कि उनमें दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम है। यदि उन्हें जीवित रहना है तो, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को अधिक प्रातिनिधिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनना होगा। वास्तव में दक्षिण की अधिक हिस्सेदारी से सभी अंतरसरकारी प्रक्रियाएँ मज़बूत होंगी, जो पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही दुनिया की गंभीर समस्याओं के लिए मूल्यवान समाधान मुहैया करा सकता है।

दक्षिण की अधिक हिस्सेदारी से सभी अंतरसरकारी प्रक्रियाएँ मज़बूत होंगी, जो पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही दुनिया की गंभीर समस्याओं के लिए मूल्यवान समाधान मुहैया करा सकता है

इस सब में, सरकारें, जाहिरन राष्ट्रीय संप्रभुता को बचाने के लिए चिंतित हैं। यद्यपि इस तरह का विचार कुछ मामलों में सही हो सकता है, लेकिन इससे किसी को फ़ायदा न मिलने वाले (zero-sum) विचार को बढ़ावा मिल सकता है। एक बेहतर रणनीति ''जिम्मेदार संप्रभुता'' होगी जिसके द्वारा राष्ट्र निष्पक्ष, नियम आधारित और जवाबदेह अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़ेंगे, सामूहिक उद्यमों में शामिल होंगे, जो वैश्विक कल्याण को बढ़ायें। ज़िम्मेदार संप्रभुता के लिए यह भी ज़रूरी है कि राज्य अपने नागरिकों के मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस दृष्टिकोण के अनुसार संप्रभुता को केवल एक अधिकार की तरह नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी की तरह भी देखा जाता है।

सार्वजनिक साधनों के प्रावधान के लिए मौजूदा संदर्भ के गहरे निहितार्थ हैं। जिन क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, वे वाणिज्य, प्रवास और जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित हैं। कुछ मामलों में सार्वजनिक साधनों को क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है, जो उन ध्रुवीकरणों से बचा सकता है जो कई बार बड़े, बहुपक्षीय मंचों में प्रगति को धीमा कर देते हैं। हालाँकि क्षेत्रीय सहकारिता के बढ़ने से नुकसान भी हैं– वो एक जटिल, बहु-स्तरीय और बिखरे हुए संस्थानों के तंत्र को और जटिल बना देता है। ऐसे में चुनौती ''सुसंगत बहुलवाद'' को सुनिश्चित करने की है ताकि सभी स्तरों पर संस्थान मोटे तौर पर समन्वित ढंग से काम कर सकें।

अंतरराष्ट्रीय अधिशासनिक संस्थानों को न केवल सदस्य राज्यों द्वारा बल्कि वैश्विक नागरिक समाज द्वारा भी ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। वैश्विक नागरिक संगठनों ने पहले ही अनुदान, ऋण, मानव अधिकारों, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर वैश्विक पारदर्शिता और शासन की स्थापना को प्रभावित किया है। नागर समाज का तंत्र नये मीडिया और नयी संचार तकनीक से बढ़त हासिल कर रहा है। यद्यपि नागर समाज के संगठनों को अपनी वैधता और जवाबदेही को लेकर सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है

और वे अवांछनीय रूप भी ले सकते हैं। फिर भी, भविष्य में अंतरराष्ट्रीय प्रशासन् की वैधता नागरिक तंत्रों और समुदायों के साथ साझेदारी करने की संस्थाओं की क्षमता पर निर्भर करेगी।

नए युग के लिए प्राथमिकताएँ

इस तरह मानव विकास का बुनियादी सिद्धान्त महत्वपूर्ण बना हुआ है। हमेशा की तरह, उद्देश्य सभी लोगों के लिए, चाहें वे कहीं भी रहते हों, विकल्पों और क्षमताओं का विस्तार करना है। दक्षिण के कई देशों ने पहले ही प्रदर्शित किया है कि क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी उन्होंने सफ़र का एक हिस्सा ही पूरा किया है। आने वाले वर्षों के लिए इस रिपोर्ट में पाँच व्यापक निष्कर्षों का सुझाव दिया गया है।

दक्षिण में बढ़ती आर्थिक शक्ति निश्चित रूप से मानव विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता से मेल खानी चाहिए

मानव विकास में निवेश को न केवल नैतिक आधार पर सही ठहराया जा सकता है, बल्कि इसलिए भी कि बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण एक अधिक प्रतिस्पर्धी और गतिशील वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफलता की कुंजी हैं। खासतौर से, इन निवेशों का लक्ष्य ग़रीब होने चाहिए– उन्हें बाज़ार से जोड़ना और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। ग़रीबी एक अन्याय है, निश्चित रूप से जिसे दृढ़ कार्रवाई के जरिये ठीक करना चाहिए।

अच्छी नीति निर्माण के लिए न सिर्फ़ व्यक्तिगत क्षमताओं बल्कि सामाजिक क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर देने की भी ज़रूरत है। व्यक्ति सामाजिक संस्थानों के अंतर्गत काम करते हैं, जो उनकी विकास संभावनाओं को सीमित कर सकता है या बढ़ा सकता है। ऐसी नीतियाँ जो मानव क्षमताओं को सीमित करने वाले सामाजिक रीति-रिवाज को बदलें, जैसे लिंग विभेद, बाल विवाह और दहेज प्रथा, जो व्यक्तियों को उनकी पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए अवसरों को खोलें।

कम विकसित देश दक्षिण की उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सफलता से सीख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं

मुद्रा भंडारों का अभूतपूर्व संचय व्यापक आधार वाली प्रगति को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है

उत्तर और दक्षिण, दोनों में मुद्रा कोषों और संप्रभु संपत्ति कोषों का अभूतपूर्व संचय व्यापक आधार वाली प्रगति को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। इन कोषों का एक छोटा सा हिस्सा मानव विकास और ग़रीबी उन्मूलन के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके साथ ही दक्षिण-दक्षिण व्यापार और निवेश प्रवाह नये ढंग से विदेशी बाज़ारों का फ़ायदा ले सकता है जो विकास के अवसरों को बढ़ाए, जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक वैल्यू-चेन में भाग लेना।

विशेषकर दक्षिण-दक्षिण व्यापार और निवेश बढ़ने से अन्य कम विकसित क्षेत्रों और देशों की ओर विनिर्माण क्षमताओं के अंतरित होने की बुनियाद तैयार हो सकती है। हाल में अफ्रीका में चीन और भारत के संयुक्त उद्यम और आरंभिक विनिर्माण निवेश एक विस्तृत कार्य बल बनाने में भूमिका अपना सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय उत्पादन तंत्र देशों को अधिक परिष्कृत उत्पादन केन्द्रों की ओर तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देकर तेज़ विकास के अवसर मुहैया कराता है।

नये संस्थान क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण-दक्षिण सम्बन्धों को आगे बढ़ा सकते हैं

नये संस्थानों और साझेदारियों के द्वारा देशों से ज्ञान, अनुभव और तकनीक साझा की जा सकती है। पूरे दक्षिण में व्यापार और निवेश को बढ़ावा और अनुभवों की साझेदारी को गति देने के लिए एक नये और सशक्त संस्थान के ज़रिए ऐसा हो सकता है। एक कदम नये दक्षिण आयोग की स्थापना हो सकता है, ताकि एक ताज़ी दृष्टि दी जा सके कि दक्षिण की विविधता किस प्रकार एकजुटता की वज़ह बन सकती है।

दक्षिण और नागर समाज के व्यापक प्रतिनिधित्व से प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर प्रगति में तेजी आ सकती है।

दक्षिण का उदय वैश्विक मंच पर अभिव्यक्ति की व्यापक विविधता को बढ़ावा दे रहा है। यह ऐसे अभिशासनिक संस्थानों के निर्माण के अवसर उपस्थित करता है जो सभी निर्वाचन क्षेत्रों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करता हो और जो वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए इस विविधता का उपयोगी ढंग से इस्तेमाल कर सके।

अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए नये निर्देशक सिद्धान्तों की ज़रूरत है, जो दक्षिण के अनुभव को शामिल करें। इस दिशा में समूह-20 का उदय एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन दक्षिण के देशों को ब्रेटेन वुड्स संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों में अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है।

सक्रिय नागरिक समाज और सामाजिक आन्दोलन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों, न्यायसंगत और निष्पक्ष अधिशासन् की अपनी माँग के प्रसार के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आन्दोलनों

के विस्तार और मुख्य संदेश तथा माँगों को बुलंद करने के लिए मंचों में वृद्धि के कारण अधिशासनिक संस्थानों के सामने अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी सिद्धान्तों को अपनाने की चुनौती है। आमतौर पर, एक निष्पक्ष और कम असमान दुनिया के लिए विचारों की विविधता और सार्वजनिक बहस की व्यवस्था ज़रूरी है।

दक्षिण का उदय सार्वजनिक साधनों की अधिक आपूर्ति करने के लिए नये अवसर उपस्थित करता है

एक संवहनीय विश्व के लिए वैश्विक सार्वजनिक साधनों की अधिक आपूर्ति ज़रूरी है। आज वैश्विक मसलों की संख्या और महत्व बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन में कमी, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय अस्थिरता से लेकर आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ाई और परमाणु प्रसार तक। इसके लिए वैश्विक प्रतिक्रिया ज़रूरी है। लेकिन कई क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग लगातार धीमा बना हुआ है और इस समय ख़तरनाक रूप से अनिश्चित है। दक्षिण का उदय वैश्विक सार्वजनिक साधनों के अधिक प्रभावी प्रावधानों और आज के कई वैश्विक मसलों पर जारी गतिरोधों को दूर करने के लिए नये अवसर उपस्थित करता है।

ज़्यादातर मामलों में सार्वजनिकता और निजता सार्वजनिक साधन के अंतर्जात गुण नहीं हैं, बल्कि सामाजिक निर्मितियाँ हैं और एक तरह से नीतिगत विकल्प हैं। राष्ट्रीय सरकारें उस स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर में कमी हो, लेकिन जब वैश्विक चुनौतियाँ उपस्थित होती हैं, अंतरराष्ट्रीय सहकार अनिवार्य हो जाता है, जो कई सरकारों की स्वैच्छिक कार्रवाई से ही हो सकता है। कई दबावपूर्ण चुनौतियों को देखते हुए, क्या सार्वजनिक है और क्या निजी है, इसका निर्धारण करने के लिए मज़बूत, प्रतिबद्ध व्यक्तिगत और सांस्थानिक नेतृत्व की ज़रूरत होगी।

* * *

यह रिपोर्ट समकालीन वैश्विक संदर्भ को प्रस्तुत करती है और नीति-निर्माताओं तथा नागरिकों के लिए एक मार्ग तैयार करती है, ताकि दुनिया की अंतर-संबद्धता को बढ़ाने और बढ़ती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन मिल सके। यह बताती है कि किस प्रकार दुनिया में शक्ति, विचार और संपत्ति की गतिशीलता बदल रही है– और 21वीं सदी की इन वास्तविकताओं का मुकाबले करने और व्यापक समता, संवहनीयता तथा सामाजिक एकीकरण के साथ मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नयी नीतियों और संस्थानों को चिन्हित करती है। मानव विकास में प्रगति के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई और संस्थानों की ज़रूरत है। वैश्विक स्तर पर वैश्विक सार्वजनिक साधनों को संरक्षित करने और उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत सुधार और नवाचार ज़रूरी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सामजिक न्याय के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय संदर्भों, संस्कृतियों और संस्थागत दशाओं की विविधता को देखते हुए ऐसी धारणा है कि सभी को एक चश्मे से देखने वाली टैक्नोक्रेटिक नीतियाँ न तो वास्तविक होंगी और न ही प्रभावी। फिर भी, सामाजिक संघटन जैसे अति महत्वपूर्ण सिद्धान्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण को लेकर राज्य की प्रतिबद्धता और व्यापार एकीकरण में खुलापन संवहनीय तथा न्यायसंगत मानव विकास की दिशा में बढ़ने के साधन बनकर उभरे हैं।

दक्षिण का उदय वैश्विक सार्वजनिक साधनों के अधिक प्रभावी प्रावधानों और आज के कई वैश्विक मसलों पर जारी गतिरोधों को दूर करने के लिए नये अवसर उपस्थित करता है

"दुनिया भर में, लोग एक साझा संघर्ष में एकजुट हो रहे हैं: उनके जीवन को गढ़ने वाली घटनाओं और प्रक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए।"

महबूब उल हक

प्रस्तावना

जब 2008-09 के वित्तीय संकट में विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने बढ़ना बंद कर दिया लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ती रहीं, तब दुनिया का ध्यान गया।[1] तब से दक्षिण के उदय पर, जिसे विकासशील दुनिया में एक बहुप्रतीक्षित वैश्विक पुनर्संतुलन के रूप में देखा जाता है, काफ़ी टिप्पणियाँ हुई हैं। परन्तु इन चर्चाओं का केन्द्र संकीर्ण रूप से कुछ बड़े देशों में सकल वृद्धि दर और व्यापार वृद्धि तक सीमित रहा है। लेकिन उनसे ज़्यादा व्यापक गतिकियाँ काम कर रही हैं–बहुत से और देशों को समेटते हुए, ज़्यादा गहरी प्रवृत्तियाँ, लोगों के जीवन पर दूरगामी प्रभावों, सामाजिक समता और वैश्विक व स्थानीय स्तरों पर लोकतांत्रिक अधिशासन की संभावनाओं से भरी। जैसा यह रिपोर्ट दिखाती है, दक्षिण का उदय मानव विकास में निरंतर निवेशों और उपलब्धियों का नतीजा है और पूरी दुनिया के लिए और भी व्यापक मानवीय प्रगति की संभावनाएँ पेश करता है। लेकिन उस प्रगति को एक सच्चाई बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी जानकार और प्रबुद्ध वैश्विक व राष्ट्रीय नीति-निर्माण की, इस रिपोर्ट में विश्लेषित नीति विकल्पों-सबकों से सीखते हुए।

दक्षिण का उदय अपनी गति और आकार में अभूतपूर्व है। इतिहास में कभी भी इतने अधिक लोगों की जीवन दशाओं और भविष्य की संभावनाओं में इतने नाटकीय ढंग से और इतनी तेज़ी से बदलाव नहीं हुआ। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने वाले 'ग्रेट ब्रिटेन' को प्रति व्यक्ति उत्पादन को दोगुना करने में 150 वर्ष लग गए। अमेरिका, जहाँ औद्योगीकरण बाद में हुआ, को 50 साल लगे।[2] औद्योगीकरण की शुरुआत के वक्त दोनों देशों की आबादी एक करोड़ से कम थी। दूसरी ओर चीन और भारत में मौजूदा आर्थिक उड़ान की शुरुआत तब हुई, जब उनकी आबादी लगभग एक बिलियन थी और दोनों देशों में प्रति व्यक्ति उत्पादन 20 वर्ष से भी कम में दोगुना हो गया– एक ऐसी आर्थिक शक्ति, जिसने औद्योगिक क्रांति के मुकाबले सौ गुना अधिक लोगों को प्रभावित करा।[3]

दक्षिण का उदय वैयक्तिक क्षमताओं के अभूतपूर्व विस्तार और उन देशों में संवहनीय मानव विकास की कहानी है जहाँ विश्व के अधिकतर लोग बसते हैं। जब दर्जनों देश और अरबों लोग विकास की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जैसा कि आज हो रहा है, तब इसका सीधा असर दुनिया के सभी देशों और क्षेत्रों में पूँजी निर्माण और व्यापक मानव प्रगति पर होगा। इसमें कम विकसित देशों के लिए बराबरी पर आने और सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए फ़ायदेमंद, रचनात्मक नीतिगत पहलों के लिए नए अवसर हैं।

जो विविध मार्ग सफल विकासशील देशों ने अपनाएँ हैं, उन पर करीबी नज़र डालने पर, समस्त देशों और क्षेत्रों के लिए उपलब्ध अनेक नीतिगत विकल्पों का पता चलता है। साथ ही यह मार्ग भावी विकासात्मक सहयोग और सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मक उपायों पर समझ बेहतर बनाने वाले मूल्यों और वैश्विक नज़रिए का ज्ञान देते हैं। लक्ष्य यही है कि जहाँ तक संभव हो सके, व्यापक आधार वाली प्रगति को बढ़ावा दिया जाय ताकि सभी देशों और समुदायों का जीवन-स्तर बेहतर हो और लोगों को उपलब्ध विकल्पों का विस्तार हो। इसमें मानव विकास के सभी प्रमुख आयाम, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीविका से लेकर अपने जीवन को सुधारने और नियंत्रित करने की व्यक्तिगत आज़ादी शामिल हैं।

दक्षिण के रूपांतरण के लिए उन नियमों को बदलने की ज़रूरत है जो वैश्विक सम्बन्धों का आधार हैं। अधिकतर बहुपक्षीय संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रतिबिंबित करते हुए बनाए गए थे। लेकिन आज इन संगठनों में 21वीं सदी के वैश्विक जनसांख्यिकी, संपत्ति और भू-राजनैतिक वर्चस्व की प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के दौरान नीति-निर्माण में दक्षिण के बढ़ते प्रभाव को देखा गया। अतीत में वित्तीय निर्णय केवल बड़ी औद्योगिक शक्तियों द्वारा ही लिए जाते थे, जैसा कि 1985 के प्लाजा समझौते में। लेकिन इस बार एक बड़े समूह, जी-20, जिसमें बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ शामिल थीं, ने प्रमुख भूमिका निभाई। पहले से स्थापित अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी दक्षिण के लोग अधिक संख्या में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं।[4]

ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बदलावों के महज कुछ शुरुआती संकेत भर हैं। इस बात की संभावना भी है कि दक्षिण के ये नए नायक बेहतर वैश्विक सार्वजनिक संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयासों को फिर से शुरू करेंगे। वास्तव में दक्षिण के उदय ने सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समक्ष उन तात्कालिक चुनौतियों को ला खड़ा किया है, जिनसे भविष्य में उन्हें जूझना पड़ सकता है। अवसरों में समता, अधिशासन में जन भागीदारी, पर्यावरणीय

रेखांकन 1

मा.वि.सू. पर त्वरित गति से प्रगति

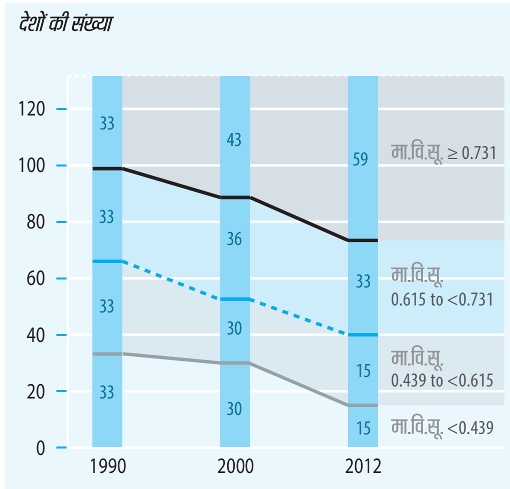

नोटः 1990 में 132 देशों के मा.वि.सू. के 25वें, 50वें और 75वें पर्सेन्टाइल के आधार पर अन्तराल बनाए गए हैं।
स्रोतः एच.डी.आर.ओ.।

रेखांकन 2

दक्षिण के 40 से अधिक देशों ने 1990 और 2012 के बीच मा.वि.सू. में बेहतरीन प्रदर्शन करा, जो उनके पिछले प्रदर्शन से लगाए गए अनुमानों से ज्यादा था

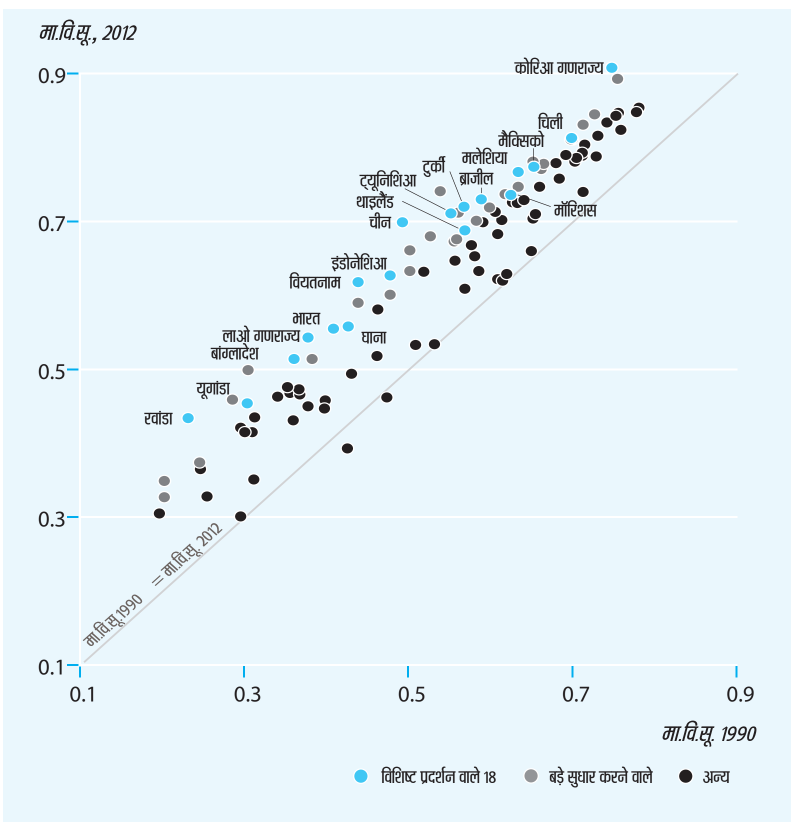

नोट : 45 अंश की रेखा के ऊपर वाले देशों का मा.वि.सू. मान, 1990 के मुकाबले 2012 में अधिक था। नीले व काले बिंदु दर्शाते हैं, वे देश जिनके मा.वि.सू. में 1990 से 2012 के बीच वृद्धि पूर्वानुमानों से कहीं अधिक रही। इन देशों की पहचान 2012 और 1990 के मा.वि.सू. के लॉग के 1990 के मा.वि.सू. लॉग पर आधारित परिवर्तन के समाश्रयण के अवशिष्टों के आधार पर की गई है। जिन देशों का नाम दिया गया है वे मा.वि.सू. में तीव्र प्रगति दर्ज करने वाले समूह में शामिल हैं, जिनपर अध्याय 3 में विस्तृत चर्चा की गई है।
स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणना।

संवहनीयता और जनसांख्यिकीय वृद्धि ऐसी कुछ चुनौतियाँ हैं। इस उदय की कुछ विशेषताओं को आगे विस्तारपूर्वक बताया गया है।

व्यापक स्तर पर प्रगति

21वीं सदी में दक्षिण का उदय सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, दूरसंचार और राष्ट्रीय अभिशासन में जन भागीदारी में बड़ी प्रगति के साथ-साथ हुआ है। इसके मानव विकास पर प्रभाव गहरे हैंः अत्यधिक ग़रीबी में गुज़र-बसर कर रहे लोगों का अनुपात 1990 के 43.1% के मुकाबले 2008 में घटकर 22.4% रह गया। अकेले चीन में ही 50 करोड़ से ज़्यादा लोग ग़रीबी से बाहर निकल पाए।[5]

मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में अपनी उपलब्धियों को पिछले दशक में, उससे पिछले दशक की तुलना में, अधिक उल्लेखनीय ढंग से बढ़ाया है। ऐसे देशों की संख्या, जिनका मा.वि.सू. (मानव विकास सूचकांक) मान 1990 में 25वें पर्सेन्टाइल से कम था, उनकी संख्या 1990 और 2000 के बीच 33 से घटकर 30 हो गई– और 2000 से 2012 के बीच आधी होकर 30 से 15 रह गई (रेखांकन 1)। ऊपर की ओर 75वें पर्सेन्टाइल से ऊपर के मा.वि.सू. वाले देशों की संख्या 1990 और 2000 में 33 से बढ़कर 43 हो गई जबकि यह आँकड़ा 2000-2012 में 43 से बढ़कर 59 हो गया। मा.वि.सू. के मध्यम चतुर्थकों (quartiles) में तस्वीर अधिक मिलीजुली है। कुल मिलाकर किसी भी देश के मा.वि.सू. मान में 2000 के मुकाबले 2012 में गिरावट नहीं आई। दूसरी ओर, इसके पूर्ववर्ती दशक में 1990 के मुकाबले 2000 में 18 देशों के मा.वि.सू. मान में गिरावट दर्ज की गई थी।

वर्ष 1990 और 2012 के बीच लगभग सभी देशों के मानव विकास सूचकांक में सुधार हुआ। उन 132 देशों, जिनकी पूरी आँकड़ा श्रृंखला उपलब्ध है, केवल 2 देशों– लेसोथो व ज़िम्बाब्वे– का मा.वि.सू. मान 1990 के मुकाबले 2012 में कम था। दक्षिण के 40 से अधिक देशों में प्रगति की रफ्तार खासतौर पर तेज़ रही। 1990 में समान मा.वि.सू. वाले देशों के लिए किए गए अनुमानों के मुकाबले इन देशों ने मा.वि.सू. में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया।[6] इनमें सब-सहारा अफ्रीका के घाना, रवाण्डा और युगाण्डा; दक्षिण एशिया के बांग्लादेश और भारत; अरब राज्यों से ट्यूनीशिया; पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में चीन, लाओ पी.डी.आर. और वियतनाम; और लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र के ब्राज़ील तथा चिली जैसे विविध देश शामिल हैं (रेखांकन 2)।

वैश्विक पुनर्संतुलन

पिछले 150 वर्षों में पहली बार विकासशील दुनिया

की केवल तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं– चीन, भारत और ब्राज़ील का सम्मिलित निर्गत उत्तर की पारंपरिक आर्थिक शक्तियोंः कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, युनाइटेड किंगडम और अमेरिका के संयुक्त स.घ.उ. के लगभग बराबर हो गया है।[7] इससे वैश्विक आर्थिक शक्ति में अप्रत्याशित पुनर्संतुलन हुआ है। वर्ष 1950 में चीन, भारत और ब्राज़ील कुल मिलाकर विश्व अर्थव्यवस्था का 10% हिस्सा थे, जबकि उत्तर के उक्त छह परंपरागत आर्थिक अगुवाकारों के पास करीब आधा हिस्सा था। और इस रिपोर्ट के अनुमानों के मुताबिक 2050 तक चीन, भारत और ब्राज़ील के पास वैश्विक निर्गत का 40% हिस्सा होगा (रेखांकन 3), जो आज के जी-7 ब्लॉक के कुल अनुमानित उत्पादन से काफ़ी अधिक होगा।[8]

आज कुल वैश्विक आर्थिक निर्गत में दक्षिण की हिस्सेदारी लगभग आधी है, जो 1990 के एक-तिहाई के मुकाबले काफ़ी अधिक है। आठ प्रमुख विकासशील देशों– अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, भारत, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की– का कुल स.घ.उ. अब अमेरिका के स.घ.उ. के बराबर हो चुका है, जो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है।[9] हाल में 2005 तक भी इन आठ देशों की कुल आर्थिक शक्ति अमेरिका के मुकाबले आधी थी।

आर्थिक निर्गत में इस ऐतिहासिक वृद्धि का मानव विकास के संदर्भ में बहुत अधिक अर्थ नहीं होता, यदि यह प्रगति वंचितता में अभूतपूर्व गिरावट और मानव क्षमताओं में विस्तार के साथ न हुई होती। 1.25 डॉलर प्रति दिन पर गुज़ारा करने वालों की संख्या को घटाकर आधा करने के प्रथम सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को तय समय से तीन साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। अत्यधिक आबादी वाले कुछ देशों को ग़रीबी उन्मूलन में मिली सफलता के कारण खासतौर से ऐसा संभव हो सकाः ब्राज़ील, चीन और भारत ने ग़रीबों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से कमी करी– ब्राज़ील में 1990 में जनसंख्या के 17.2% से 2009 में 6.1%, चीन में 1990 के 60.2% से 2008 में 13.1% और भारत में 1990 में 49.4% से 2010 में 32.7%।[10]

विकास की व्यापक चुनौतियाँ हालाँकि कम नहीं हुई हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस रिपोर्ट के लिए जिन 104 देशों का अध्ययन किया गया, उनके करीब 1.57 बिलियन लोग या 30% से अधिक आबादी बहुआयामी निर्धनता में रहती है।[11] बहुआयामी निर्धनता ऐसा मापक है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में ओवरलैप करते मानव अभावों की संख्या और तीव्रता को बताता है। दक्षिण के तेज़ी से बढ़ते कई देशों में बहुआयामी निर्धनता

आज कुल वैश्विक आर्थिक उत्पादन में दक्षिण की हिस्सेदारी लगभग आधी है, जो 1990 के एक-तिहाई के मुकाबले काफ़ी अधिक है

रेखांकन 3

2050 में चीन, भारत और ब्राज़ील का 1950 के 10% हिस्से से बढ़कर वैश्विक निर्गत में 40% हिस्सा होगा।

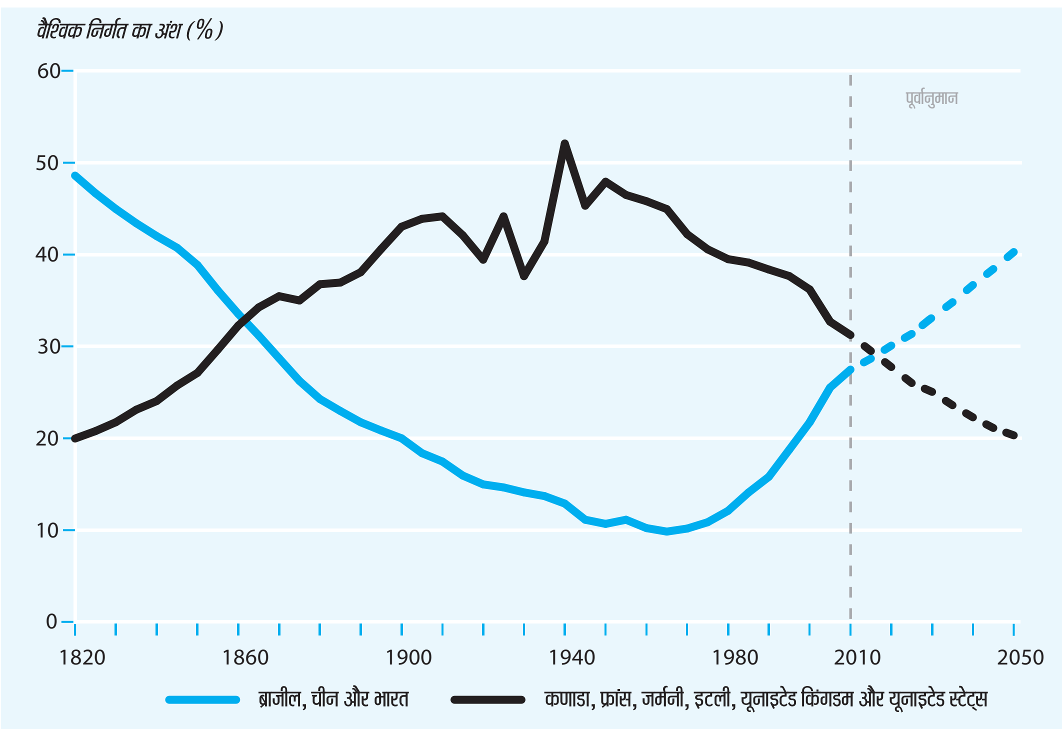

नोट 1 : निर्गत की गणना 1990 के डॉलर क्रयशक्ति समतुल्यता में की गई है।
स्रोतः मैडिसन (2010) के एच.डी.आर.ओ. द्वारा अंतर्वेशन (interpolation) के ऐतिहासिक आँकड़ों और पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स के अनुमानों पर आधारित

में रहने वालों की संख्या, आय निर्धनता का शिकार लोगों के मुकाबले अधिक है। कई देशों में आय असमानता बढ़ रही है। वर्ष 2012 में 132 देशों के असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक की गणना के आधार पर, असमानता के कारण मा.वि.सू. मान को लगभग एक चौथाई, यानी 23% की क्षति हुई है। वर्ष 1990 और 2005 के दौरान 66 देशों के असमानता-समायोजित मा.वि.सू. के रुझान बताते हैं कि कुल असमानता में केवल मामूली गिरावट ही हुई है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा-असमानता में गिरावट को बढ़ती आय-असमानता ने पाट दिया।[12] समस्त वैश्विक रुझानों के विपरीत लैटिन अमेरिका में 2000 से आय असमानता में लगातार गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अभी भी सभी क्षेत्रों में से यहाँ सबसे असमान वितरण है। सब-सहारा अफ्रीका में स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक असमानता है, जबकि दक्षिण एशिया में शिक्षा के क्षेत्र में।

समस्त वैश्विक रुझानों के विपरीत लैटिन अमेरिका में 2000 से आय असमानता में लगातार गिरावट दर्ज की गई

मध्यम वर्ग का व्यापक विस्तार

दक्षिण में मध्यम वर्ग आकार, आय और प्रत्याशाओं के लिहाज से तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्ष 1990 और 2010 के बीच वैश्विक मध्यम वर्ग आबादी में दक्षिण का हिस्सा 26% से बढ़कर 58% हो गया। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया का 80% से अधिक मध्य वर्ग दक्षिण में होगा और कुल उपभोग व्यय में उसकी हिस्सेदारी 70% होगी।[13] वर्ष 2030 तक दुनिया के दो-तिहाई मध्यमवर्गीय व्यक्ति एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रहेंगे, मध्य व दक्षिण अमेरिका में करीब 10% और सब-सहारा अफ्रीका में 2% (रेखांकन 4)। एशिया में करीब 75% मध्यम वर्ग के लोग भारत और चीन से होंगे और कुल उपभोग में उनकी हिस्सेदारी भी इतनी ही होगी। एक अन्य अनुमान के मुताबिक 2025 तक उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं का वार्षिक उपभोग 2010 के 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2030 में 30 ट्रिलियन डालर हो जाएगा। दक्षिण में विश्व के एक बिलियन परिवारों में से रह रहे पाँच में से तीन परिवारों की वार्षिक आमदनी 20,000 डॉलर से अधिक होगी।[14] निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के निरंतर विस्तार का गहरा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होगा।

रेखांकन 4

दक्षिण में मध्यम वर्ग के लगातार बढ़ने के अनुमान हैं

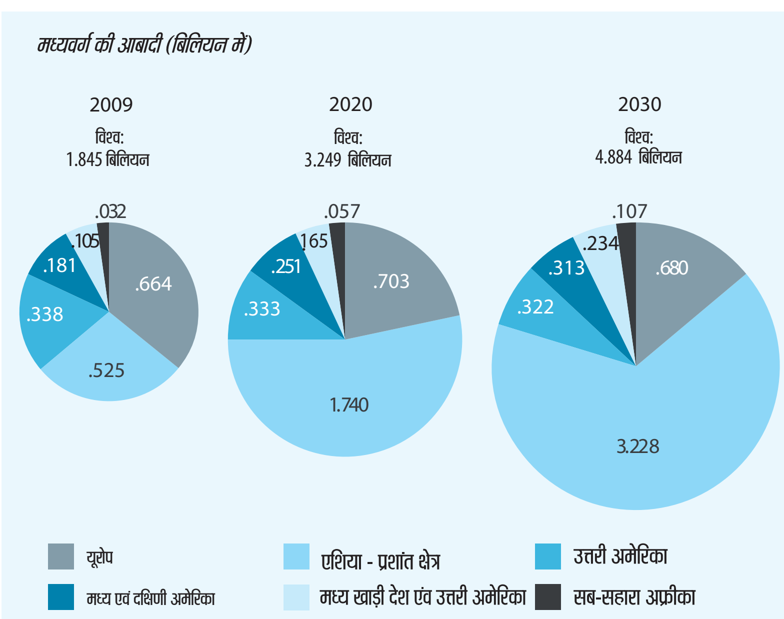

नोट : मध्य वर्ग में 10-100 डॉलर प्रति दिन कमाने या खर्चने वाले लोग शामिल है (2005 की क्रय शक्ति समता के अर्थों में)।
स्रोत: बुकिंग्स इन्स्टीट्यूशन्स 2012

दक्षिण में बड़ी संख्या में रहने वाले लोग, जिसमें अरबों उपभोक्ता और नागरिक शामिल हैं, सरकारों, कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दक्षिण में कार्यों के वैश्विक मानव विकास परिणामों को कई गुना बढ़ा देते हैं। उत्तर के साथ ही दक्षिण भी अब तकनीकी नवाचार और सृजनात्मक उद्यमशीलता के लिए उर्वरा ज़मीन का काम कर रहा है। उत्तर-दक्षिण के व्यापार में नई औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं ने विकसित देशों के बाज़ारों के लिए जटिल उत्पादों के कुशलतापूर्वक विनिर्माण की क्षमता हासिल कर ली है। लेकिन दक्षिण के आपसी सम्पर्क ने दक्षिण की कंपनियों को इस प्रकार सक्षम बनाया है कि वे स्थानीय ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने वाले उत्पादों और प्रक्रियाओं को तैयार कर सकें। इससे नए कारोबारी मॉडल तैयार हो रहे हैं क्योंकि कंपनियाँ ऐसे उत्पाद तैयार कर रहीं हैं जो निम्न आय वर्ग के ग्राहकों की पहुँच में हैं। दक्षिण का उदय प्रौद्योगिकी के विस्तार के नए मॉडल बना रहा है जहाँ व्यापक कार्यक्षेत्र में कम लाभांश के साथ कम आय वाले परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरत है। साथ ही, उन बड़ी संख्या के उपभोक्ताओं वाले बाज़ारों तक भी पहुँच बढ़ा रहा है जिनकी अधोसंरचना कमज़ोर है।

दुनिया अधिक शिक्षित भी हो रही है। स्कूलों में नामांकन दर में सतत बढ़ोतरी मानते हुए औपचारिक शिक्षा से वंचित, 15 वर्ष से अधिक के लोगों की संख्या 2050 की कुल वैश्विक आबादी के 12% से घटकर 3% रह जायेगी। माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त आबादी की हिस्सेदारी 2010 के 44% से बढ़कर 2050 में 64% पहुँच जायेगी। इसके साथ ही डिजिटल खाई तेज़ी से पट रही है। खासतौर से किफ़ायती दरों पर उपलब्ध मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो किसी भी क्षेत्र के लोगों तक ठीक-ठाक मात्रा में सूचना सुलभ करा रहा है।

दक्षिण में शिक्षित लोगों की आबादी में भारी बढ़ोतरी के कारण व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसरों को तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है। दक्षिण के जो देश भविष्य में निम्न निर्भरता दर दर्ज करते हैं,

वे 'जनसांख्यिकी लाभांश' तभी हासिल कर पायेंगे यदि श्रमिक बलों में वृद्धि के समान ही रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। यदि इस जनसांख्यिकीय माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त अच्छे रोज़गार न उपलब्ध हों तो नतीजतन नागरिक अशांति बढ़ सकती है। जैसा युवाओं की अगुवाई वाले अरब 'स्प्रिंग' विद्रोह में देखने को मिला।

अभूतपूर्व सम्बद्धता

दुनिया भर में व्यापार, यात्रा और दूरसंचार लेनदेन अभूतपूर्व गति से बढ़ रहे हैं। लोग लगातार पेशेवर कारोबारियों, पर्यटकों और प्रवासियों के रूप में एक से दूसरे देश के बीच इतनी बढ़ी संख्या में तेज़ी से आ-जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया। वर्ष 2010 में पहली पीढ़ी के प्रवासियों की कुल संख्या विश्व आबादी का लगभग 3% या लगभग 21.5 करोड़ थी जो 1960 के मुकाबले तीन गुना अधिक है।[15] दक्षिण के प्रवासियों द्वारा अपने घरों को भेजी जाने वाली कुल धनराशि का लगभग आधा हिस्सा अन्य विकसित देशों में रह रहे श्रमिकों द्वारा भेजा जाता है।

आज पहले के मुकाबले दक्षिण के देशों में अन्य विकासशील देशों से ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं। 2020 तक दुनिया भर में लगभग 1.6 बिलियन पर्यटकों की आवाजाही होगी जिसमें से लगभग 75% अंतरक्षेत्रीय होने का अनुमान है। पिछले तीन दशकों के दौरान कुल वैश्विक कारोबार में दक्षिण-दक्षिण कारोबार की हिस्सेदारी तीन गुना से अधिक बढ़कर 25% पहुँच गई। कम विकसित देशों में कुल बाह्य निवेश का 30% से 60% हिस्सा दक्षिण-दक्षिण विदेशी निवेश से आता है।[16]

दक्षिण में वर्ल्डवाइड नेटवर्क (इंटरनेट) का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यह उड़ान पिछले दशक के दौरान खासतौर से उल्लेखनीय रही है (रेखांकन 5)। वर्ष 2000 और 2010 के बीच 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले लगभग 60 विकासशील देशों में इंटरनेट का इस्तेमाल 30% वार्षिक की दर से अधिक बढ़ा। सितंबर 2012 में ऑनलाईन सोशल नेटवर्किंग साइट फ़ेसबुक के मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या एक बिलियन दर्ज की गई। 'मित्रों' के रूप में 140.3 बिलियन कनेक्शन थे। फ़ेसबुक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाले पाँच में से चार देश दक्षिण से हैं- ब्राज़ील, भारत, इण्डोनेशिया और मैक्सिको।[17]

वाणिज्य में परस्पर निर्भरता के कारण बड़ी संख्या में लोग वैश्विक बाज़ार में भाग ले रहे हैं– युगाण्डा में केला निर्यातकों से लेकर मेकांग नदी के झींगा किसानों तक। व्यापार एकीकरण के एक परंपरागत मापक– वैश्विक व्यापार का स.घ.उ. से अनुपात– 1913 में बढ़कर 22% हो गया, जो 1800 के 2% के मुकाबले अभूतपूर्व था।[18] आज यह अनुपात 56% से अधिक है।[19] कम से कम 15 विकासशील देशों के 100 से अधिक व्यापार भागीदारों के साथ ठोस कारोबारी सम्बन्ध हैं, निर्यातक और आयातक, दोनों के रूप में। यह आँकड़ा 1996 में 6 था (रेखांकन 6)। वैश्विक व्यापार प्रवाह में आज दक्षिण की हिस्सेदारी आधी है, जो 30 साल पहले मुश्किल से एक चौथाई थी। परंपरागत उत्तर-दक्षिण

दक्षिण में शिक्षित लोगों की आबादी में भारी बढ़ोतरी के कारण व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसरों को तैयार करने की तत्काल आवश्यकता

रेखांकन 5

दक्षिण में इंटरनेट के इस्तेमाल में अभूतपूर्व बढ़त सबसे ज़्यादा पिछले दशक में हुई

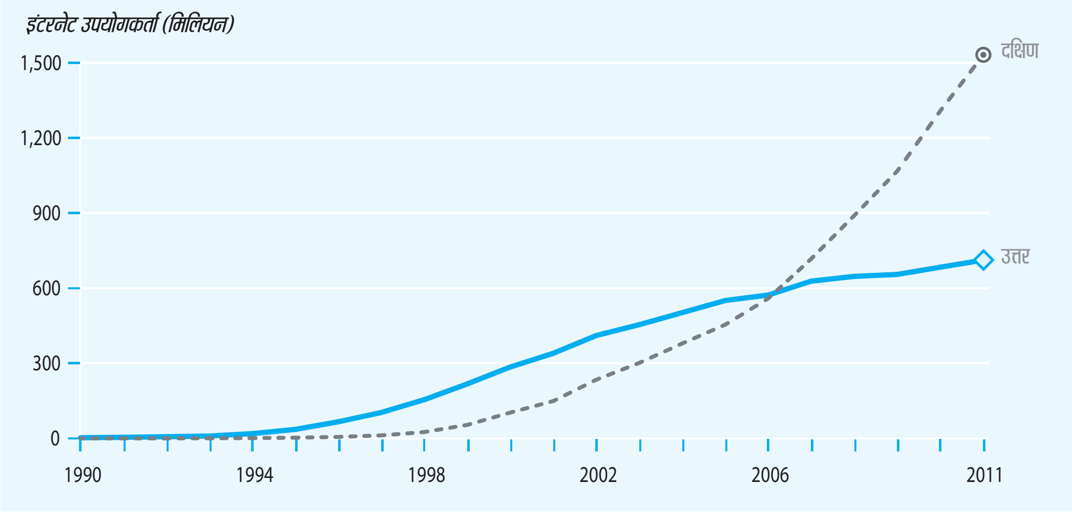

स्रोत: वर्ल्ड बैंक 2012a

के गठजोड़ के बजाय, दक्षिण-दक्षिण पर आधारित 'क्षैतिज' कारोबारी सम्बन्ध और गहरा रहे हैं।

दक्षिण के बीच आपसी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा आज भी उत्तर की माँग पर आधारित है, लेकिन इसका विपरीत भी सच हैः विकासशील देश उत्तर के लिए बड़े आयातक भी हैं। उदाहरण के लिए, 2007 से आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के स्थापित साझेदारों को अमेरिका का निर्यात 20% बढ़ा, जबकि इसी दौरान लैटिन अमेरिका व चीन को अमेरिकी से होने वाला निर्यात 50% से अधिक बढ़ा। दक्षिण को उत्तर की ज़रूरत है, लेकिन उत्तर के लिए भी दक्षिण की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है।

अब दक्षिण के देश भी प्रौद्योगिकियों और नए उत्पादों के विकास के स्वाभाविक केन्द्र के रूप में उभर रहे हैं। आज मानव विकास की संभावनाएँ कहीं अधिक हैं, जो दक्षिण से किए गए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कारण है।[20] परिस्थितियों में अंतर के कारण उत्तर से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को अपनाना महँगा पड़ता है, जबकि दक्षिण द्वारा किए गए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सीधे अपनाना कहीं आसान है। और दक्षिण द्वारा अपनायी जा रही प्रौद्योगिकियों ने विशेष किस्म के नवाचारों को बढ़ावा दिया है, जिसके मानव विकास को सीधे लाभ हैं। अफ़्रीकियों की आर्थिक पहुँच में आने वाले एशिया में बने मोबाइल फ़ोनों को ही लीजिएः एक परंपरागत बैंक खाता खोलने के बजाय सेल्युलर बैंकिंग सस्ती और आसान है। किसान मौसम की जानकारी और अनाज की कीमत पता कर सकते हैं और उद्यमी मोबाइल फ़ोन कियोस्क के जरिये कारोबारी सेवाएँ मुहैया करा सकते हैं। यह और इसके साथ ही दूसरे बदलावों ने उन संभावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया है जिन्हें इन्सान तकनीक के साथ साकार कर सकता हैः अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में

रेखांकन 6

कम से कम 15 विकासशील देशों के 100 से अधिक देशों से ठोस व्यापारिक सम्बन्ध हैं– निर्यातक व आयातक, दोनों के रूप में

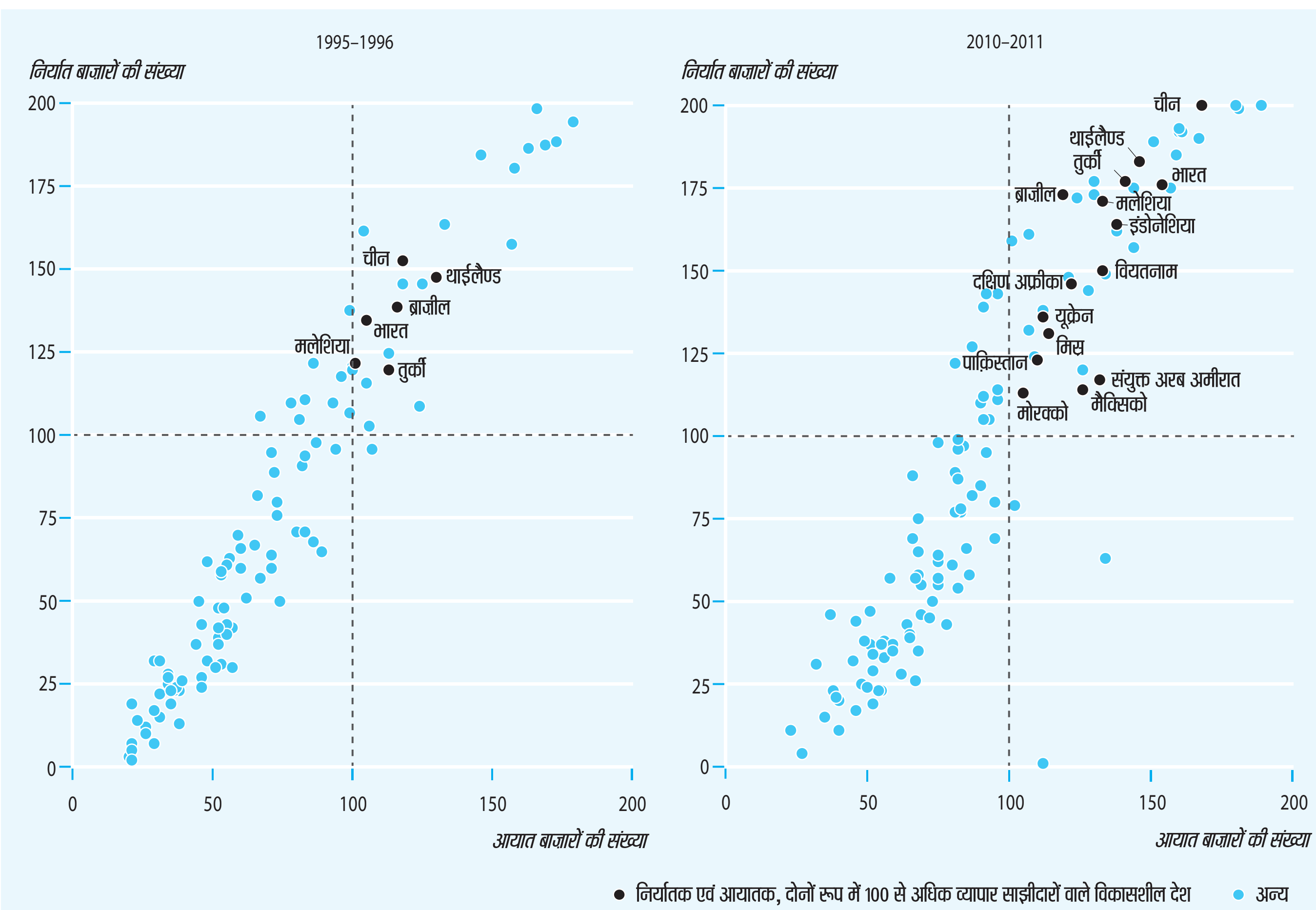

नोटः यह गणना 1995 और 1996 तथा 2010 और 2011 का औसत है। इसमें वही देश हैं जिनका द्विपक्षीय व्यापार 1995-1996 में 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2010-2011 में 2 मिलियन डॉलर से अधिक था।
स्रोतः यू.एन.एस.डी. (2012)।

भाग लेना; तेज़ी से और कम कीमत में सूचना पाना; सस्ती प्रजातीय (generic) दवाएँ बनाना; उन्नत बीज और नई किस्म की फसलें; और नए रोज़गार तथा निर्यात के अवसर तैयारा करना। ये नई प्रौद्योगिकियाँ अभी तक पृथक और हाशिये पर पड़े ग्रामीण समुदायों और शहरी ग़रीबों को जोड़ रही हैं। ये उन्हें मूल्यवान उपकरणों, संसाधन और सूचनाएँ सुलभ कराते हुए राष्ट्रीय तथा वैश्विक समाज में अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए सक्षम बना रही हैं।

व्यावहारिक विकास नीतियाँ

दक्षिणी देशों के उदय में विविधतापूर्ण अनुभवों के रंग बिखरे हैं, जो बताते हैं कि मानव विकास को हासिल करने और बनाये रखने के कई वैकल्पिक रास्ते हैं। देश अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नीतियों को अपनाने में व्यावहारिक रहे हैं। उदाहरण के लिए 1979 और 1989 के बीच चीन के कम से कम 40% राष्ट्रीय नियमन (regulations) प्रयोगात्मक समझे गए।[21] साथ ही व्यापक रूप से अपनाये जाने वाले साझा नज़रिये भी थे। दक्षिण के सर्वाधिक तेज़ी से प्रगति कर रहे देशों ने विदेशी व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकियों के लिए दरवाज़े खोल दिये। लेकिन केवल इस खुलेपन ने ही कामयाबी सुनिश्चित नहीं करी। उन्होंने अपनी खुद की मानव विकास क्षमताओं में भी निवेश किया, घरेलू संस्थाओं को मज़बूत बनाया और तुलनात्मक बढ़त के नए क्षेत्रों को तैयार किया। बाहरी खुलेपन के साथ आंतरिक तैयारी के महत्वपूर्ण तालमेल ने इन देशों को वैश्विक बाज़ार में संपन्न बनाया, जिससे उनकी बड़ी आबादी को सकारात्मक मानव विकास लाभ मिले।

आर्थिक प्रगति को तेज़ गति देने और सामाजिक टकराव को न्यूनतम करने के लिए सक्रिय राजनीतिक नेतृत्व महत्वपूर्ण था। आर्थिक वृद्धि ने स्वास्थ्य और शिक्षा में आवश्यक निवेश के लिए वित्त उपलब्ध कराया और आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के बीच तालमेल के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ब्राज़ील, भारत और मैक्सिको जैसे देशों के जाने-माने नवाचारी कार्यक्रमों– सशर्त नकदी हस्तांतरण व ग्रामीण रोज़गार गारंटी जैसे– से आर्थिक और सामाजिक अवसरों के कहीं अधिक समतापरक वितरण को बढ़ावा देने में मदद मिली। चीन ने भी 'समरस समाज' के अपने रणनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस तरह के नज़रिये को महत्व दिया है। दक्षिण के कई अन्य देशों में भी इन कार्यक्रमों के कारगर तत्वों को अपनाया गया है।

आमतौर पर इन सामाजिक पहलों का जोर समता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने पर रहा है। यह ऐसे पहलू हैं, जिन्हें पिछले विकास मॉडलों में कम तवज्जो मिली है, लेकिन जो मानव प्रगति की किसी भी स्थायी राह के महत्वपूर्ण घटक साबित हो रहे हैं। सत्ताधारी अभिजात वर्ग मान रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति का गहरा प्रभाव उनके अपने वजूद पर पड़ सकता है। सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक साधनों में निवेश से दीर्घावधि विकास के लिए इमारत तैयार होती है। इन अनुकरणीय पहलों– जिनमें समता, सशक्तीकरण और सहभागिता के व्यापक एजेंडा में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक नीतियाँ शामिल हैं– ने सहयोगात्मक सामाजिक न्याय के महत्व को रेखांकित किया है। न केवल नैतिक धरातल पर, बल्कि मानव विकास को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण उपाय के तौर पर भी।

विकास के नए भागीदार

दक्षिण अब ऐसी स्थिति में है जहाँ वह विकास के पुराने मॉडलों को अपने संसाधनों और अपने अनुभवों से संवर्धित करके प्रभावित कर सकता है और नया आकार दे सकता है। साथ ही, द्विपक्षीय सहयोग के अन्य पहलुओं पर नए प्रतिस्पर्धी दबाव बना सकता है। दक्षिण का उदय द्विपक्षीय साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग के नए तरीकों को बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण दक्षिण के भीतर ही रियायती वित्त, ढाँचागत निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कई विकल्प तैयार हुए हैं। दक्षिण से सहायता का बढ़ता स्रोत अक्सर बग़ैर आर्थिक नीतियों या अभिशासन को लेकर शर्त के होता है। उदाहरण के लिए, कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के घरेलू अनुभवों और उन्हें मिली सीखों ने विकास-विमर्श को बेहतर अधोसंरचना पर दोबारा ध्यान देने के उत्प्रेरक की भूमिका अदा की है। पिछले दशक के दौरान सब-सहारा अफ्रीका में लगभग आधा ढाँचागत वित्तीयन दक्षिण की ही दूसरी सरकारों और क्षेत्रीय कोषों द्वारा उपलब्ध कराया गया।[22]

इतना ही नहीं, दक्षिण की सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के पूँजी संचयन में हुई असाधारण बढ़ोतरी– जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि उल्लेखनीय है– विकासात्मक पूँजी का अनछुआ भंडार हैं। वर्ष 2000 और 2011 के बीच विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि का तीन-चौथाई दक्षिण के देशों द्वारा जमा किया गया है, आंशिक रूप से भविष्य में किसी वित्तीय घाटे या संकट से खुद को बचाने के लिए(रेखांकन 7)।

वर्ष 1995 में ही यू.एन.डी.पी. ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए महत्वपूर्ण 23 विकासशील देशों की पहचान कर ली थी। पिछले दशक के दौरान इन देशों ने अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ाया है।[23] ओ.ई.सी.डी. के बाहर ब्राज़ील, भारत और चीन, तीन सबसे बड़े दानदाता हैं।[24] क्षेत्रीय विकास में मलेशिया, थाइलैण्ड और तुर्की जैसे दूसरे

दक्षिण अब ऐसी स्थिति में है जहाँ वह विकास के पुराने मॉडलों को अपने संसाधनों और अपने अनुभवों से संवर्धित करके प्रभावित कर सकता है और नया आकार दे सकता है। साथ ही द्विपक्षीय सहयोग के अन्य पहलुओं पर नए प्रतिस्पर्धी दबाव बना सकता है

देशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पारस्परिक लाभ पर आधारित नई विकास साझेदारियाँ विकास के प्रयासों को और द्विपक्षीय व्यापार व निवेशों के आदान-प्रदान के अवसर बढ़ाती हैं, जिससे दक्षिण का उदय टिकाऊ हो। दक्षिण के उदय की इस प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय सत्ता की दिशा बदल रही है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ वैश्विक आर्थिक शक्ति में आये बदलाव के अनुरूप खुद को ढाल रही हैं।

पारस्परिक लाभ पर आधारित नई विकास साझेदारियाँ विकास के प्रयासों को और द्विपक्षीय व्यापार व निवेशों के आदान-प्रदान के अवसर बढ़ाती है, जिससे दक्षिण का उदय टिकाऊ हो

* * *

यह रिपोर्ट दक्षिण के उदय और मानव विकास पर उसके प्रभावों के कई पहलुओं का अत्यधिक विस्तार से परीक्षण करती है। अध्याय 1 में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मानव विकास के मौजूदा स्तर का जायज़ा लिया गया है। इसमें ग़रीबी, असमानता, सामाजिक एकीकरण और मानवीय सुरक्षा जैसे परस्पर सम्बन्धित क्षेत्रों के रुझानों, चुनौतियों और प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया है। अध्याय 2 बताता है कि किस तरह दक्षिण के देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। वे किस तरह अन्य विकासशील देशों में विकास के वाहक और बदलाव के लिए उत्प्रेरक बन रहे हैं और उनके सामने आ रही चुनौतियों को यह अध्याय पहचानता है। अध्याय 3 उन नीतियों और रणनीतियों का विश्लेषण करता है, जिन्होंने दक्षिण के सर्वाधिक सफल देशों में प्रगति को आधार दिया है। अध्याय 4 दो बुनियादी सवाल पूछता है: क्या यह प्रगति टिकाऊ होगी और मानव विकास को संवहनीय बनाने के लिए भविष्य में कैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं? अध्याय 5 वैश्विक तथा क्षेत्रीय अधिशासन के नए मसौदे के लिए ऐसी नीतियों और

रेखांकन 7

देश समूह वार आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार

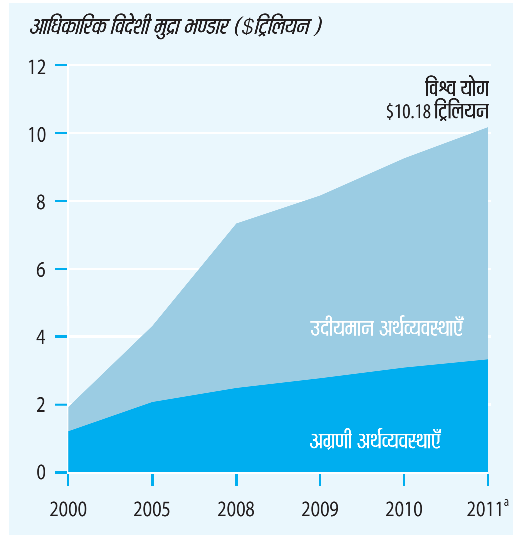

नोट: देशों के वर्गीकरण में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) की विधि का अनुसरण किया गया है। इसमें 34 उन्नत और 110 उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं, जो आई.एम.एफ. के करेंसी कम्पोज़िशन ऑफ ऑफीशिशल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व (सी.ओ.एफ.ई.आर.) को जानकारी देते हैं।
स्रोत: ग्राबेल 2013।

सिद्धान्तों की संभावनाओं पर विचार करता है जो पूरी तरह से दक्षिण के उदय को प्रतिबिंबित करता हो और उसके अनुकूल हो, और जो दक्षिण व उत्तर के दीर्घकालीन हित में हो। जैसा कि यह रिपोर्ट बताती है कि 21वीं सदीं की बढ़ती जटिल चुनौतियों के लिए नई भागीदारियों और नए नज़रियों की ज़रूरत है, जो तेज़ी से बदलती इस दुनिया की नई वास्तविकताओं को परिलक्षित करती हों।

“इन तीन चीज़ों को मिलाना
मानवता की राजनीतिक
समस्या है : आर्थिक दक्षता,
सामाजिक न्याय
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।”

जॉन मेयनार्ड कीन्स

1.

मानव विकास की स्थिति

ब्राज़ील से लेकर दक्षिण अफ्रीका, भारत से चीन तक, सबसे बड़े विकासशील देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख संचालक शक्ति बन गए हैं। लेकिन 2012 में दक्षिण की सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं तक ने उत्तर की वित्तीय समस्याओं से प्रभावित होना प्रारंभ कर दिया था। ऋण संकट और व्यापक बजट घाटों से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे अनेक विकसित देश कड़े मितव्ययिता कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, जो न केवल उनके नागरिकों के लिए कष्टप्रद साबित हो रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के लाखों अन्य लोगों के मानव विकास की संभावनाओं को भी कमज़ोर कर रहे हैं।

प्रथम *मानव विकास रिपोर्ट* ने 1990 में आर्थिक और सामाजिक प्रगति की एक अभिनव दृष्टि प्रस्तुत की, जो कि मूल रूप से लोगों के अपने विकल्पों और क्षमताओं में विस्तार करने के बारे में थी। तब से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अनेक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने विकास की तेज़ गति को जारी रखते हुए मानव विकास के मानकों को ऊँचा किया है। दक्षिण का उदय तेज़ी से बदल रहे विश्व की एक विशेषता है। आज दक्षिण विश्व के कुल निर्गत[1] और उपभोग[2] के लगभग एक-तिहाई हिस्से के लिए ज़िम्मेदार है। यदि चीन और भारत के नेतृत्व में इन अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़ वृद्धि नहीं हुई होती तो वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणाम अधिक गहरे होते।[3]

हालाँकि चिंताजनक यह रहा कि मंदी के चिन्हों से ये देश भी बच नहीं पाए। लेकिन एक अंतर्सम्पृक्त (interconnected) विश्व में उत्तर का संकट विकासशील देशों की प्रगति को धीमा कर सकता है। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर औद्योगिक देशों में सरकारें कठोर मितव्ययिता मापदंडों को लागू कर रही हैं जिससे सरकार की कल्याणकारी भूमिका में कमी और सरकारी व्ययों और लोक सेवाओं में कटौती जैसी प्रवृत्तियाँ दिखने लगी हैं।[4] इससे लोगों के लिए कठिनाइयाँ बढ़ी हैं और आर्थिक परिस्थितियाँ बदतर हुई हैं। विकसित विश्व के बहुत से व्यक्तियों का जीवन स्तर गिर रहा है। परिणामस्वरूप बहुत से देशों में सड़कों पर प्रदर्शन हुए हैं और लोगो का राजनीतिज्ञों और आर्थिक प्रबंधन से मोह भंग हुआ है।

दुनिया ऐसे संकट देख चुकी हैः 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में, 1980 के दशक में लैटिन अमेरिका में और 1990 के दशक में एशिया में। लेकिन इस बार 21 वीं शताब्दी के दूसरे दशक में संकट की उत्पत्ति पुनः यूरोप के हृदय क्षेत्र में हो रही है।

संप्रभु ऋण की संवहनीयता के विषय में एक वाजिब चिंता के कारण सरकारें मितव्ययिता कार्यक्रम लागू कर रही हैं। परंतु इसमें एक जोखिम यह है कि अल्प अवधि के ये उपाय मानव विकास और सामाजिक कल्याण की उस बुनियाद को कमज़ोर कर दीर्घ अवधि में हानिकारक सिद्ध होंगे, जो अर्थव्यवस्थाओं के प्रगति करने, लोकतंत्र के सफल होने और समाजों में असमता को कम करने और उन्हें आघातों को सहने योग्य बनाने के लिए अनिवार्य हैं।[5]

इस बात के भी प्रमाण उपलब्ध हैं कि कड़े मितव्ययिता कार्यक्रमों को शीघ्रता से लागू करने से मंदी अधिक गहरी और लंबी हो सकती है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (consolidation) के निजी घरेलू माँग और सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) पर संकुचनकारी प्रभाव[6] आर्थिक परिस्थितियों के कमज़ोर होने और बेरोज़गारी में वृद्धि के रूप में पहले ही देखे जा सकते हैं।[7] स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में कटौती से आने वाले कई वर्षों तक जनसंख्या के स्वास्थ्य, श्रमबल की गुणवत्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की स्थिति के कमज़ोर बने रहने की आशंका है (बॉक्स 1.1)। इससे कुछ समय के लिए मानव विकास की प्रगति का प्रक्षेप पथ (trajectory) नीचा रह सकता है (बॉक्स 1.2)। इसके अतिरिक्त आर्थिक गतिहीनता से कर राजस्व में कमी आएगी, जिसकी सरकार को सामाजिक सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वित्तीयन के लिए आवश्यकता होती है।

इस अधिकांश हानि से बचा जा सकता है। ऐतिहासिक साक्ष्य इशारा करते हैं कि घाटे में कटौती करने का सर्वाधिक उपयुक्त समय आर्थिक संवृद्धि में उछाल के बाद का होता है।[8] जैसा कि 75 वर्ष पूर्व जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने सारगर्भित ढंग से कहा था, ''मितव्ययिता के लिए उपयुक्त समय अर्थव्यवस्था के उछाल का होता है, न कि मंदी का।''[9]

सार्वजनिक व्यय की मात्रा के साथ उसके तत्वों पर और कैसे इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इस के उपायों पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार रोज़गार में वृद्धि और मानव विकास के उन्नयन के लिए संरचित, सरकारी राजस्वों और व्ययों के संघटन में एक वित्त-तटस्थ परिवर्तन, अगले एक से दो वर्षों में 33 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं

बॉक्स 1.1

न्यायसंगतता, समष्टि अर्थशास्त्र और मानव विकास

संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में आय में बढ़ती असमानता ने आय के वितरण और संवृद्धि के लाभार्थियों में न्यायसंगतता के मुद्दे को रेखांकित किया है। विकसित देशों में ये मुद्दे राजनीतिक विमर्श की मुख्य धारा में प्रवेश कर चुके हैं, हालाँकि अब तक नीतियों पर इसके सीमित प्रभाव ही दृष्टिगोचर हुए हैं। विकसित देशों में बेरोज़गारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है और विगत कुछ दशकों के दौरान श्रमबल के अधिकांश भाग के वास्तविक पारिश्रमिक में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, हालाँकि समृद्धतम दशमकों (deciles) में आय में संतोषजनक वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई असमानता के साथ सम्पन्नों का एक वर्ग सरकार के आकार में कमी और राजकोषीय संयम की माँग कर रहा हैः न केवल सम्पन्नों ने पहले की संवृद्धि से अनुपात से ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, बल्कि वे अपने फ़ायदों को बचाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध नजर आते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि नागर समाजों के भरपूर दबाव के होते हुए भी लोकतंत्रों में सरकारों के एजेंडों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के स्थान पर मितव्ययिता कार्यक्रमों का बाहुल्य है।

मितव्ययिता उपायों पर जोर देने की प्रवृत्ति मात्र यूरो क्षेत्र के देशों तक सीमित नहीं है। यूनाइटेड किंगडम ने वर्तमान मितव्ययिता कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक निवेश में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के लगभग 2% की कटौती की योजना बनाई है। मितव्ययिता के लिए यह आग्रह ऐसे समय पर उभरा है जबकि सार्वजनिक निवेश ऐतिहासिक निम्नतम स्तर पर पहुँच गया है। उदाहरणस्वरूप, यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2011/12 के लिए शुद्ध सार्वजनिक निवेश स.घ.उ. के 2% से भी कम रहा है। सरकार और सामाजिक व्ययों के आकार को घटाने के लिए निरंतर डाले जा रहे दबाव ने पुनर्प्राप्ति और संवृद्धि की संभावनाओं को कमजोर किया है।

समष्टि अर्थनीतियों के मानव विकास की दृष्टि से बड़े परिणाम निकल सकते हैं। सार्वजनिक ऋण में कमी लाने के लिए सामाजिक व्ययों में कटौती के दीर्घकालीन प्रभाव हो सकते हैं। यदि अर्थव्यवस्थाएँ सिकुड़ती रहीं तो ऋण कटौती के सतत दौर ऋण संवहनीयता को बढ़ाने में कम सहायक सिद्ध होंगे। व्ययों में कटौती से सकल माँग घटती है, जो उच्च आय असमानता से मिलकर अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों और लोगों को काम देने की संभावनाओं को कठिन बनाती है। पूर्ण रोज़गार की प्राप्ति के लिए घटी हुई सकल माँग की क्षतिपूर्ति होनी आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका (और अन्य औद्योगीकृत देशों) में नीची ब्याज दरों के माध्यम से इसे प्राप्त किया गया था। इसके और नए वित्तीय उपकरणों व शिथिल विनियमनों के परिणामस्वरूप एक ऐसा बुलबुला उत्पन्न हुआ जो अंततोगत्वा वर्तमान वित्तीय संकट का कारण बना। अपने नीति उपकरणों का उपयोग करने में काफ़ी अक्षम हो चुके यूरो क्षेत्र के देश संकट के समाधान के लिए अवमूल्यन (या स्फीति) की मौद्रिक नीतियों का प्रयोग नहीं कर सकते।

स्रोतः एटकिंसन 2011, 2012, ब्लॉक 2013, एच एम ट्रेजरी 2010, नैयर 2012, सेन 2012, स्टिग्लिट्ज़ 2012

बॉक्स 1.2

लघु-अवधि की कटौती के दीर्घकालीन परिणामः अफ्रीका में प्रजनन दर में बढ़ोतरी

हरेक दूसरे इलाके में गिरने के बावजूद कई सब-सहारा अफ्रीकी देशों में 1970 से 1980 के बीच प्रजनन दरों में बढ़ोतरी क्यों हुई? प्रजनन दर सामाजिक खर्च में कटौती, विशेषकर शिक्षा में, जो 1980 के दशक में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (structural adjustment programme) का हिस्सा बना, से जुड़ी हुई प्रतीत होती है।

शिक्षा में कटौती केवल मानव क्षमताओं को ही सीमित नहीं करती बल्कि बाद के वर्षों में जनसंख्या की आयु संरचना को भी प्रभावित करती है, क्योंकि इसका प्रभाव जन्म दर पर पड़ता है। निचले शिक्षा स्तर वाले देशों में, खासकर वे देश जहाँ बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती, ज़्यादा प्रजनन दर की प्रवृत्ति होती है। करीब सारी दुनिया में, उच्च शिक्षा स्तर वाली महिलाओं के कम बच्चे होते हैं। यह प्रभाव उन देशों में विशेषरूप से मज़बूत है जो अपने जनसांख्यिकीय संक्रमण के आरम्भिक दौर में हैं और उनकी कुल प्रजनन दर अभी ज़्यादा है। सूचनाओं को बढ़ा कर, व्यवहार की प्रेरणाओं को बदल कर और अपनी पसंद से जीने के लिए लोगों को सशक्त करके शिक्षा प्रजनन दर को कम करती है।

शिक्षा पर वास्तविक प्रति व्यक्ति खर्च में करीब 50% औसतन गिरावट के साथ, 1980 के दशक में सब-सहारा अफ्रीका ने जनसांख्यिकीय संक्रमण की ओर प्रगति में एक आंशिक उलटाव देखा। उस पूरे क्षेत्र में 1980 से 1986 के बीच प्राथमिक शिक्षा में नामांकन कुल मिला कर 79% से गिरकर 73% हो गए (16 देशों में गिरे और 17 में बढ़े)। घटे हुए शिक्षा खर्चों का महिला शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके कारण संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के पहले के काल की तुलना में बालिकाओं की प्राथमिक और माध्यमिक सामूहिक सकल नामांकन दर में ज़्यादा धीमी गति से बढ़ोतरी हुई।

स्रोत - लुट्ज और समीर 2012; रोज 1995।

में 18 से 21 लाख रोज़गार सृजित कर सकता है।[10]

हालाँकि विभिन्न देशों में अपनी व्यय प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने के लिए छूट का स्तर भिन्न-भिन्न होता है, पर कई में प्राथमिकताओं के पुनर्निधारण की गुंजाइश अधिक होती है। उदाहरण के लिए, 2010 में वैश्विक स्तर पर रक्षा व्यय 1.4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया। यह विश्व के 50 सर्वाधिक निर्धन देशों के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक है। जहाँ राजकोषीय सुदृढ़ीकरण आवश्यक हो, वहाँ भी कल्याणकारी सेवाओं में कटौती की आवश्यकता नहीं है। कुशलता में वृद्धि और जीवाश्म ईंधनों पर अनुदान में कमी लाते हुए सुदृढ़ीकरण का प्रयास सामाजिक व्यय को अपेक्षाकृत अ-प्रभावित छोड़ सकता है।[11]

मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने में दक्षिण के देशों ने बेहतर लोच का प्रदर्शन किया है। 2008 के संकट के पश्चात क्षणिक असफलताओं के बाद अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने मानव विकास और वृद्धि की अपनी ऊर्ध्वमुखी गति को फिर प्राप्त कर लिया है। यह अंशतः इसलिए है कि वे ज़्यादा व्यावहारिक हैं, विपरीत चक्रीय (countercyclical) उपाय कर रहे हैं और स्थिति बेहतर होने तक

अपने ऋण में कमी को स्थगित कर रहे हैं। दक्षिण से लगातार माँग ने भी कई विकासशील देशों का निर्यात बरकरार रखने में मदद की है, उत्तर में सुस्त आर्थिक गतिविधियों को प्रतिसंतुलित किया है।[12]

इसके साथ ही, कई विकासशील देशों ने लंबी अवधि के मानव विकास में निवेश जारी रखा है। उन्होंने मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) में प्रगति और सामाजिक व आधारभूत संरचना में पिछले सार्वजनिक निवेश के बीच एक स्पष्ट सकारात्मक पारस्परिक सम्बन्ध को स्वीकार किया है।[13] दक्षिण में सरकारों ने भी माना है कि संवहनीय विकास सामाजिक एकीकरण पर आधारित होना चाहिए। उदारहण के लिए, ब्राज़ील और भारत ने काम के अधिकार कार्यक्रम और नकद अंतरण योजनाएँ शुरू करके पूर्ववर्ती विकास मॉडलों में मानव विकास के कम आँके गए तत्वों का समर्थन किया है।

कुल मिलाकर, पिछले कुछ दशकों के दौरान दक्षिण के कई देशों ने केवल आर्थिक विकास को बढ़ाकर और ग़रीबी घटाकर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा में भी भारी सुधार करके मा.वि.सू. प्रदर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति की है (इस अध्याय में आगे इसपर विस्तृत चर्चा है)। यह व्यापक-आधारी उपलब्धि उल्लेखनीय है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आय में वृद्धि से मानव विकास के अन्य पक्षों में सुधार हो ही जाए। संवृद्धि स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश के लिए संसाधन उत्पन्न कर सकती है लेकिन यह सम्बन्ध अपने आप नहीं बनता। इसके अतिरिक्त सशक्तीकरण और सहभागिकता जैसी मानव विकास की दूसरी प्राथमिकताओं पर वृद्धि का प्रभाव मामूली भी हो सकता है।

पहले की अपेक्षा अब विकास की राहों की पर्यावरणीय संवहनीयता के साथ-साथ इन आयामों को प्रतिबिंबित करने के लिए संकेतकों की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है।

देशों की प्रगति

प्रत्येक *मानव विकास रिपोर्ट*, मुख्यतः मा.वि.सू. के ज़रिए, मानव प्रगति की पड़ताल करती रही है। यह एक मिश्रित पैमाना है जिसमें तीन आयामों में संकेतक शामिल हैः दीर्घायु, शैक्षिक उपलब्धि और एक अच्छी जिंदगी के लिए ज़रूरी संसाधनों पर नियन्त्रण। दूसरे संकेतक असमानता, ग़रीबी और लैंगिक कमियों को मापते हैं। सांख्यिकीय सारणी 1 में 2012 के लिए मा.वि.सू. मान दिए गए हैं।

2012 में मा.वि.सू. काफ़ी प्रगति दिखाता है। पिछले दशकों के दौरान विश्व भर के देश मानव विकास के उच्चतर स्तरों की ओर चलते रहे हैं। निम्न और मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देशों में मा.वि. सू. प्रगति की रफ्तार सबसे तेज़ रही है। यह अच्छी खबर है। लेकिन प्रगति के लिए मा.वि.सू. में औसत से ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। यह न वांछनीय होगा, न टिकाऊ, अगर मा.वि.सू. में वृद्धियाँ अपने साथ आय में बढ़ती असमानताएँ, उपभोग के असंवहनीय तौर तरीके, ऊंचे सैन्य खर्च और नीचे सामाजिक संघटन लाती हैं (बॉक्स 1.3)।

2012 में वैश्विक औसत मानव विकास सूचकांक 0.694 था। सब-सहारा अफ्रीका का सबसे नीचा था (0.475), उसके बाद दक्षिण एशिया (0.558) था। विकासशील भागों में पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के मा.वि.सू. सबसे ऊंचे थे (0.771), फिर लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के (0.741)।

मा.वि.सू. के तत्वों में जीवन प्रत्याशा, स्कूली वर्षों का माध्य और आय के संदर्भ में क्षेत्रों और मा.वि. सू. समूहों के बीच भारी अंतर है। अति उच्च मा.वि. सू. मान वाले देशों में औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निम्न मा.वि.सू. मान वाले देशों में औसत आय की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है (सारणी 1.1)। अति उच्च मा.वि.सू. देशों में जीवन प्रत्याशा निम्न मा.वि. सू. देशों की तुलना में तिहाई गुना ज़्यादा है, जबकि अति उच्च मा.वि.सू. देशों में 25 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों के औसत स्कूली वर्ष निम्न मा.वि.सू. वाले देशों की तुलना में तकरीबन तीन गुना ज़्यादा हैं। हालाँकि, स्कूली वर्षों की प्रत्याशा, जो विकासशील देशों में शैक्षिक संभावनाओं को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करती है, ज़्यादा आशावादी तस्वीर प्रस्तुत करती है। प्राथमिक स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों के औसत के अब 8.5 स्कूली वर्ष पूरे कर लेने की संभावना है जो उच्च मा.वि.सू. देशों (8.8 वर्ष) के आसपास ही है। कुल मिलाकर, निम्न मा.वि.सू. वाले ज़्यादातर देश प्राथमिक स्कूल स्तर पर पूर्ण नामांकन और माध्यमिक स्कूल के लिए 50% से ज़्यादा नामांकन हासिल कर चुके हैं या उनकी ओर बढ़ रहे हैं।

क्षेत्रों और मा.वि.सू. समूहों के बीच उपलब्धियों में व्यापक असमानताएँ है। देशों के समूहों के बीच असमानता का आकलन करने का एक तरीका समूह के विभिन्न देशों के बीच सबसे उच्च से सबसे निम्न मा.वि.सू. मानों के अनुपात की तुलना करना है। सब-सहारा अफ्रीका में यह अनुपात सबसे ज़्यादा है, इसके बाद अरब देशों, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों का स्थान है। सब-सहारा अफ्रीका में अधिकांश असमानता प्रति व्यक्ति आय (70.1 के अनुपात के साथ[14]) और स्कूली वर्षों के माध्य (7.8 के अनुपात के साथ) में भारी अंतरों की वजह से है। दक्षिण एशिया में भी असमानता मुख्यतः (10.7 के अनुपात के साथ) प्रति व्यक्ति आय और स्कूली वर्षों के माध्य में अंतर से (4.0 के अनुपात के साथ) आती है। अरब देशों में, और कुछ हद तक लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में मुख्य प्रचालक प्रति व्यक्ति आय में अंतर है ।

मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) में प्रगति और सामाजिक व आधारभूत संरचना में पिछले सार्वजनिक निवेश के बीच एक स्पष्ट सकारात्मक पारस्परिक सम्बन्ध है

बॉक्स 1.3

अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता

एक मनुष्य होना क्या होना है?

लगभग आधी सदी पहले, दार्शनिक टॉमस नागेल ने एक प्रसिद्ध लेख प्रकाशित किया, शीर्षक था 'एक चमगादड़ होना क्या होना है?' जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वह हैः एक मनुष्य होना क्या होना है? दरअसल, टॉम नागेल का दि फिलॉसॉफिकल रिव्यू में छपा अंतर्दृष्टिपूर्ण लेख भी मनुष्यों के बारे में ही था, और अंशतः ही चमगादड़ों के बारे में। दूसरे बिन्दुओं के अलावा, नागेल ने गहरी आलोचना व्यक्त की निरीक्षणवादी वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति एक चमगादड़ होने– या इसी तरह एक मनुष्य होने– के अनुभव की पहचान मस्तिष्क और शरीर में दूसरी जगहों पर होने वाली उन भौतिक परिघटनाओं से करने की आदत से, जिनका बाहरी निरीक्षण आसान है। एक चमगादड़ या एक मनुष्य होने का बोध सिर्फ मस्तिष्क और शरीर में चन्द चिहुँकनों के होने जैसा नहीं हो सकता। मस्तिष्क की जटिलता शरीर की सरलतर निरीक्षणीयता से नहीं सुलझाई जा सकती (भले ही ऐसा करने का प्रलोभन कितना हो)।

मानव विकास दृष्टिकोण की प्रगतिशीलता भी एक अंतर पर आधारित है– लेकिन नागेल की बुनियादी ज्ञानशास्त्रीय विपरीतता से अलग तरह के अंतर पर। वह दृष्टिकोण जो महबूबुल हक़ ने 1990 में शुरु हुई *मानव विकास रिपोर्ट* के माध्यम से आगे बढ़ाया था। इस दृष्टिकोण में जहाँ एक ओर मनुष्य जीवनों की समृद्धि का आकलन कठिन समस्या है, जिसमें शामिल हैं वे आज़ादियाँ जो मनुष्य के लिए मूल्यवान हैं, और दूसरी ओर वे सरल तरीके जिनसे आमदनियों और दूसरे बाहरी संसाधन– जो लोगों और देशों के पास होते हैं– की जानकारी रखी जा सकती है। सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) को देखना और नापना लोगों के मानवीय जीवन की गुणवत्ता को नापने से कहीं आसान है। लेकिन मानव कल्याण और स्वतंत्रता तथा उनके संसार की निष्पक्षता और न्याय से अंतर्संबंध को स.घ.उ. और उसकी वृद्धि दर तक सीमित नहीं किया जा सकता, जैसा बहुत से लोग करने को लालायित होते हैं।

मानव विकास की अंतर्निहित जटिलता को स्वीकारना ज़रूरी है, अंशतः तो इसलिए कि हमें उस प्रश्न को बदलने की ओर न सरका दिया जाए जो महबूबुल हक की साहसी पहल का केन्द्रीय बिन्दु था– स.घ.उ. का सम्पूरण (supplement) और किसी हद तक विस्थापन। लेकिन उसके साथ ही एक ज्यादा कठिन बिन्दु भी आया– जिसे हम मानव विकास दृष्टिकोण कहते हैं, जो उसका एक अभिन्न अंग है। सुविधा के लिए हम मानव विकास के कई आसान संकेतकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मा.वि.सू., जो केवल तीन परिवर्तों (variables) के प्रयोग और उन्हें आनुपातिक महत्व देने के एक बहुत आसान नियम पर आधारित है। किन्तु खोज वहाँ खत्म नहीं होती। हमें इन उपयोगी और कामचलाऊ तरीकों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए– स.घ.उ. की तुलना में मा.वि.सू. से मानव जीवन की गुणवत्ता के विषय में कहीं अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है– परंतु हमें एक सतत प्रयास वाले विश्व में इन कामचलाऊ रास्तों से मिलने वाले त्वरित लाभ से पूर्णतः संतुष्ट भी नहीं हो जाना चाहिए। जीवन की गुणवत्ता को मापना एक अत्यंत जटिल कार्य है– बनिस्पत मात्र एक नंबर के माध्यम से व्यक्त होने वाली उस वास्तविकता के, चाहे उसे मापने के लिए शामिल किए गए परिवर्तों को बहुत जाँच-परख के बाद तय किया गया हो और उन परिवर्तों को आनुपातिक महत्व देने की प्रक्रिया कितनी ही निष्पक्ष क्यों न हो।

इस जटिलता को स्वीकारने के अन्य महत्वपूर्ण निहितार्थ भी हैं। जटिलता को मान्यता देने के कारण ही, भले ही अंशतः, सार्वजनिक तर्क-विमर्श की महत्वपूर्ण भूमिका भी पनपती है– जिस पर वर्तमान मानव विकास रिपोर्ट विशेष जोर देती है। यह सही है कि जूता कहाँ काट रहा है, यह तो पहनने वाला ही बता सकता है, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि जूता काटने से बचाने वाली व्यवस्थाएँ तब तक प्रभावशाली नहीं बन सकतीं, जब तक लोगों को अपनी बात कहने और सार्वजनिक चर्चा करने के व्यापक अवसर नहीं दिए जाएँ। लोगों की खुशहाली और स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने वाले विभिन्न घटकों के महत्व की समझ तथा उसका आकलन केवल और केवल आबादी के साथ ऐसे सतत संवाद के माध्यम से सम्भव है, जिस संवाद का सार्वजनिक नीति-निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव हो। तथाकथित अरब क्रान्ति और विश्व के किसी भी जन आंदोलन के राजनीतिक महत्व की तुलना आम लोगों की उन अभिव्यक्तियों और पारस्परिक संवादों से की जा सकती है जिसमें वे अपने जीवन के कष्ट-अड़चनों को दूसरों से कहते हैं और यह भी कि कौन से अन्यायों को वे दूर करना चाहते हैं। विचार-विमर्श करने को बहुत कुछ है– एक-दूसरे के साथ और नीति निर्माण करने वाले लोक सेवकों के साथ भी।

जब शासन के विभिन्न स्तरों को वार्ता-संवाद की ज़िम्मेदारियों का ठीक से अहसास हो जाता है, तो इसमें ऐसे लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्यतया शामिल होना चाहिए जो स्वयं अपनी ज़रूरतों को अपनी आवाज़ में व्यक्त करने के लिए यहाँ अभी उपस्थित नहीं हैं। मानव विकास भावी पीढ़ी के सराकारों के प्रति केवल इसलिए उदासीन नहीं हो सकता कि वर्तमान में उसकी उपस्थिति नहीं है। पर मनुष्य में दूसरों के, उनके जीवन के बारे में सोचने की क्षमता होती है। और एक ज़िम्मेदार व जवाबदेह राजनीति से अपेक्षित है कि वह संकीर्ण, आत्मकेन्द्रित सरोकारों में उलझे संवादों से भिन्न, सामाजिक समझ को विस्तार देकर भविष्यत और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं और स्वतंत्रताओं को महत्व दे। यहाँ बात केवल इन समस्त सरोकारों को एक अकेले सूचक में समाहित करने की नहीं है– जैसे कि पहले से ही भारी-भरकम हो चुके मा.वि.सू. पर (जो, वैसे भी, केवल वर्तमान खुशहाली और आज़ादी का सूचक है) और बोझ लाद दिया जाए। असल मुद्दा है यह सुनिश्चित करना कि मानव विकास की चर्चाओं में उन दूसरे चिंता-सरोकारों को भी शामिल किया जाए। मानव विकास रिपोर्टें फलक विस्तार की इस प्रक्रिया में योगदान देने का सिलसिला जारी रख सकती हैं– व्याख्या-विश्लेषणों तथा प्रासंगिक जानकारियों की सारणियों के जरिए।

मानव विकास का दृष्टिकोण, मानव जीवन की सफलताओं और वंचितताओं को समझने की कठिन प्रक्रिया में हुई अहम प्रगति का परिचायक है, साथ ही यह परिचायक है गहन आत्मनिरीक्षण तथा संवाद की महत्ता का– और इसके माध्यम से दुनिया में निष्पक्षता और न्याय के उन्नयन का। हम एक बात में काफ़ी हद तक चमगादड़ों के समान हो सकते हैं कि उनकी ही तरह एक अधीर पर्यवेक्षण विज्ञानी की मापक छड़ की पकड़ से बचे रहें, लेकिन चमगादड़ों से बहुत आगे जाकर हममें यह क्षमता होती है कि हम अपने और दूसरों के बहु-आयामी जीवनों के वर्तमान और भविष्य के बारे में बात करें और सोच सकें। इसलिए इन्सान होना एक स्तर पर तो चमगादड़ जैसा होना है लेकिन उससे बहुत भिन्न होना भी है।

कुल मिलाकर, पिछले दशक में मा.वि.सू. मानों में काफ़ी समाभिरूपता (convergence) देखी गई है, कम मा.वि.सू. वाले देशों में मानव विकास में तेज़ी के साथ। निम्न और मध्यम मा.वि.सू. देशों में तीव्रतर प्रगति के साथ सभी मा.वि.सू. समूहों और क्षेत्रों में मा.वि.सू. के सभी आयामों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। पूर्वी एशिया व प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण एशिया में पहले के दशकों से चली आ रही प्रगति देखी गई, जबकि सब-सहारा अफ्रीका में पिछले दशक में बहुत तेज़ प्रगति हुई। मा.वि.सू. में समाभिरूपता पिछले दशक में अधिक स्पष्ट हुई है।

जीवन प्रत्याशा मा.वि.सू. के प्रमुख अंगों में से एक है। 2012 में औसत जीवन प्रत्याशा 70.1 साल रही, मा.वि.सू. समूहों के बीच भारी अंतरों के साथः निम्न मा.वि.सू. वाले देशों में यह 59.1 साल थी तो अति उच्च मा.वि.सू. वाले देशों में 80.1 साल। देशों के बीच तो अंतर और भी बड़े हैं, सिएरा लिओन में 48.1 साल की न्यूनतम और जापान में 83.6 साल की उच्चतम। एच.आई.वी. और एड्स महामारी के तेज़ी से फैलने के परिणामस्वरूप सब-सहारा अफ्रीका में 1990 और 2000 के बीच जीवन प्रत्याशा 49.5 साल पर स्थिर हो गई थी। परंतु 2000

सारणी 1.1

क्षेत्रवार और मा.वि.सू. समूह के अनुसार मा.वि.सू. और उसके आयाम, 2012

क्षेत्र और मा.वि.सू. समूह	मा.वि.सू.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष में)	स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष (वर्ष में)	स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष (वर्ष में)	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (2005 पी.पी.पी. $)
क्षेत्र					
अरब देश	0.652	71.0	6.0	10.6	8,317
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	0.683	72.7	7.2	11.8	6,874
यूरोप एवं मध्य एशिया	0.771	71.5	10.4	13.7	12,243
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	0.741	74.7	7.8	13.7	10,300
दक्षिण एशिया	0.558	66.2	4.7	10.2	3,343
सब-सहारा अफ्रीका	0.475	54.9	4.7	9.3	2,010
मा.वि.सू. समूह					
अति उच्च मानव विकास	0.905	80.1	11.5	16.3	33,391
उच्च मानव विकास	0.758	73.4	8.8	13.9	11,501
मध्यम मानव विकास	0.640	69.9	6.3	11.4	5,428
निम्न मानव विकास	0.466	59.1	4.2	8.5	1,633
विश्व	0.694	70.1	7.5	11.6	10,184

नोटः आँकड़े जनसंख्या द्वारा भारांकित हैं और 187 देशों के मा.वि.सू. मानों के आधार पर परिकलित किए गए हैं। पी.पी.पी. क्रय शक्ति समता है।
स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ। सांख्यिकीय सारणी 1 भी देखें।

से 2012 के बीच इसमें 5.5 साल की बढ़ोतरी हुई।

मा.वि.सू. पर एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव, और मानव जीवन के सबसे संवेदनशील संकेतकों में से एक है, बाल जीवितता। 2010 में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की वैश्विक मृत्यु दर 1000 जन्मे बच्चों पर 55 मौतों की थी, हालाँकि यह विभिन्न मा.वि.सू. समूहों में असमान रूप से बँटी हुई थी। निम्न मा.वि.सू. वाले देशों में यह दर सबसे ज़्यादा (1000 जन्म पर 110 मृत्यु)थी, उसके बाद मध्यम मा.वि.सू. देशों (42), उच्च मा.वि.सू. देशों (18) और अति उच्च मा.वि.सू. देशों में (6)। बच्चों का कमज़ोर स्वास्थ्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को नुकसान पहुँचा सकता है और बाद में वयस्क के रूप में उसकी श्रम उत्पादकता को प्रभावित करता है।

मा.वि.सू. की तुलनाएँ आम तौर पर उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच की जाती हैं, और इस आधार पर विश्व कम असमान हो रहा है। फिर भी, मानव अनुभव की व्यापक विभिन्नताओं को राष्ट्रीय औसत छिपा लेते हैं, तथा उत्तर और दक्षिण, दोनों के देशों में गहरी असमानताएँ बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का 2012 में मा.वि.सू. मान 0.94 था, जो रैंकिंग के मामले में विश्व में तीसरा था। लैटिन अमेरिकी मूल के नागरिकों का मा.वि.सू. मान 2010-11 में 0.75 के करीब था जबकि अफ्रीकी अमेरिकियों का 0.70 था।[15] लेकिन लूसियाना राज्य में एक अफ्रीकी-अमेरिकी का औसत मा.वि.सू. मान 0.47 था।[16] अति उच्च मा.वि.सू. देशों में मा.वि.सू. उपलब्धि में इसी तरह की जातीय विषमताएँ दक्षिणी यूरोप के *रोमा* लोगों में देखी जा सकती हैं।

कुछ विकासशील देशों में भी मानव विकास की रेंज बड़ी है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील में 2000 में, जिस अद्यतन वर्ष के उप-राष्ट्रीय स्तर के आँकड़े उपलब्ध हैं, सबसे उच्च मा.वि.सू. मान साओ पाओलो राज्य के साओ कैटानो डो सुल में (0.92) और सबसे कम परनंबुको राज्य के मानारी में (0.47) रहा। प्रांतीय भिन्नताओं के साथ चीन में भी ऐसी ही, हालाँकि कम तीखी, स्थिति है। वहाँ शंघाई में यह उच्चतम (0.91) तो तिब्बत में सबसे नीचे (0.63) है।[17]

मा.वि.सू. की तुलनाएँ आम तौर पर उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच की जाती हैं, और इस आधार पर विश्व कम असमान हो रहा है

आय और मानव विकास

मानव विकास और मा.वि.सू. का एक और अनिवार्य आयाम संसाधनों पर नियंत्रण है, जिसे प्रति व्यक्ति आय से नापा जाता है। 1990 और 2012 के बीच सभी चारों मा.वि.सू. समूहों में आय में वृद्धि हुई है, हालाँकि इसकी मात्रा में अंतर रहा है

रेखांकन 1.1

प्रति व्यक्ति आय सभी चार मा.वि.सू. समूहों में अलग अलग मात्रा में बढ़ रही है

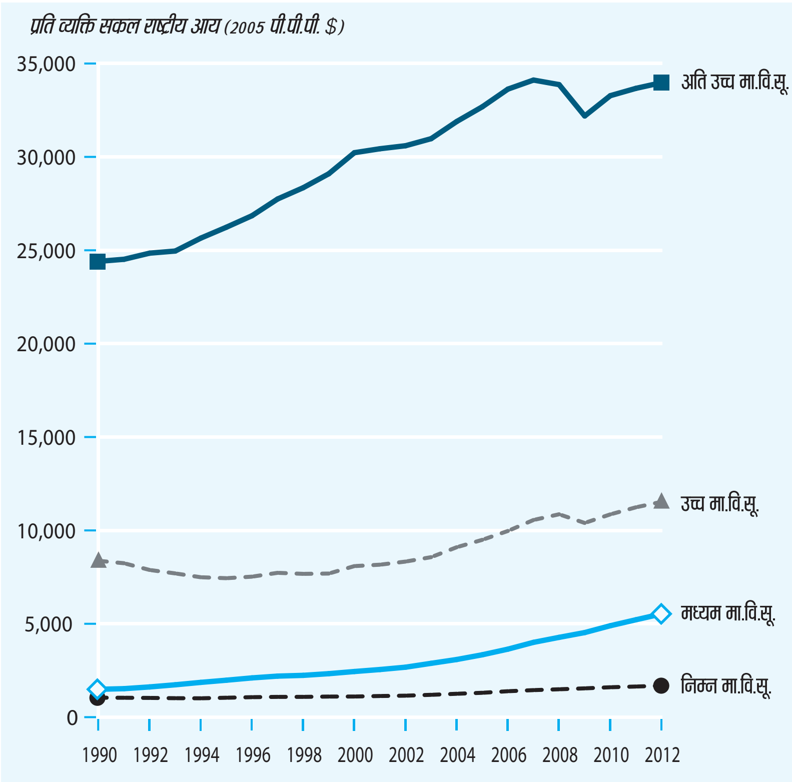

नोट- पी.पी.पी. का मतलब क्रय शक्ति समता है।
स्रोत - एच.डी.आर.ओ. की गणनाएँ, 161 देशों और क्षेत्रों के एक समान पैनल पर आधारित।

रेखांकन 1.2

पिछले दशक में सब-सहारा अफ्रीका ने निरन्तर आय वृद्धि को हासिल किया

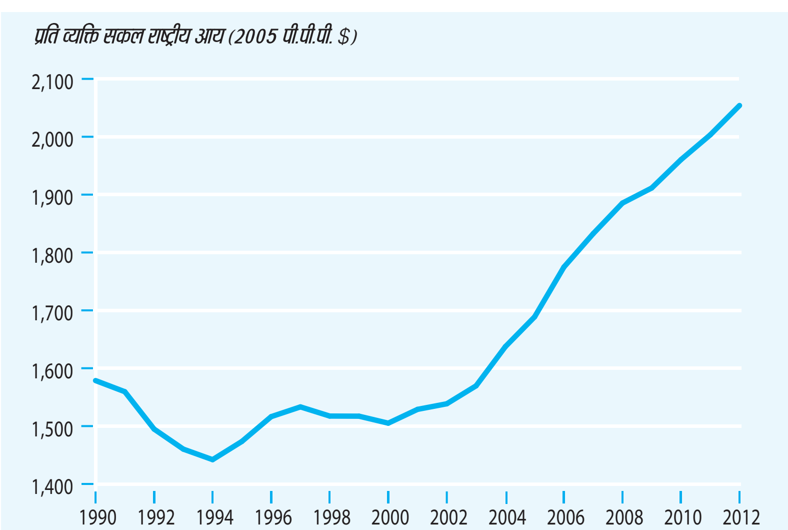

नोट- पी.पी.पी. का मतलब क्रय शक्ति समता है।
स्रोत - एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

(रेखांकन 1.1)। प्रति व्यक्ति आय में उच्चतम औसत वार्षिक वृद्धि चीन और इक्वेटोरियल गिनी में 9% पर दर्ज की गई। केवल 12 देशों ने 4% वृद्धि को पार किया, जबकि 19 देशों में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई।

सब-सहारा अफ्रीका में सबसे जोरदार उपलब्धियों में से एक देखी गई है। 2003 से 2008 तक– वैश्विक वित्तीय संकट से पहले के पाँच सालों में– इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय सालाना 5% की दर से बढ़ी, 1990 के दशक की दर से दो गुना (रेखांकन 1.2)।[18] इस ऊर्ध्वमुखी रुझान का नेतृत्व संसाधन-संपन्न देशों ने किया जिन्हें अफ्रीका के मुख्य जिन्स निर्यात में दाम बढ़ने का फ़ायदा मिला, चीन के नेतृत्व में दक्षिण से आने वाली मज़बूत माँग की वजह से। ये जिन्स हैं विशेषतः गैस, तेल, खनिज और कृषि उत्पाद।

लेकिन ज़्यादा विविध अर्थव्यवस्थाओं और कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में मज़बूत प्रदर्शन के साथ अन्य देशों में भी विकास का विस्तार हुआ है। जिन्स कीमतों में इजाफ़े के बावजूद, कुल जिन्स-आयातक कई देश, जैसे इथियोपिया, रवाण्डा और युगाण्डा, लगातार तेज़ी से विकास कर रहे हैं। सब-सहारा अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएँ ज़्यादा क्षेत्रीय एकीकरण के कारण वैश्विक झटकों से अंशतः बच सकीं, विशेषकर पूर्वी अफ्रीका में।

जैसा कि ज़्यादातर *मानव विकास रिपोर्टों* ने रेखांकित किया है, केवल आय का स्तर ही मायने नहीं रखता, बल्कि यह भी कि उस आय का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक समाज अपनी आय को शिक्षा पर खर्च कर सकता है या युद्ध के हथियारों पर। व्यक्ति अपनी आय को ज़रूरी खाद्य पदार्थों पर खर्च कर सकता है या नशीली वस्तुओं पर। समाज और व्यक्ति, दोनों के लिए अधिकतम धन कमाने की प्रक्रिया निर्णायक नहीं है, बल्कि यह है कि वे आय को मानव विकास में कैसे बदलते हैं। सारणी 1.2 मा.वि.सू. श्रेणी और सकल राष्ट्रीय आय (स.रा.आ.) प्रति व्यक्ति के बीच सबसे बड़े सकारात्मक अंतर के पैमाने पर देशों की सफलताओं को दिखाती है।[19] अति उच्च मानव विकास वाले देशों की सूची में न्यूज़ीलैंड और उच्च मानव विकास वाले देशों की सूची में क्यूबा शीर्ष पर है।

निर्धनता

विश्व की सर्वप्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है– निर्धनता और भूख का उन्मूलन। यह आठ सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में पहले स्थान पर है। इसके लिए 2015 तक 1.25 डॉलर प्रतिदिन से कम पर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों के अनुपात को आधा

करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अधिक जनसंख्या वाले कुछ देशों की सफलता के कारण यह लक्ष्य निर्धारित तिथि से तीन साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया। इन देशों में प्रमुख हैं– ब्राज़ील (जहाँ 1.25 डॉलर प्रतिदिन से कम पर गुज़ारा करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 17.2% से घटकर 6.1% पर पहुँच गया), चीन (60.2% से घटकर 13.1%) और भारत (49.4% से घटकर 32.7%)।[20] इसी का नतीजा है कि निर्धनों की संख्या में कमी आई है। अकेले चीन ने 1990 से 2008 के दौरान 51 करोड़ लोगों को निर्धनता से मुक्ति दिलाई।[21]

निर्धन लोग केवल आय की कमी से ही नहीं जूझते। ग़रीबी के विविध आयाम हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में कमियाँ। इसके अलावा, विश्व की लगभग 10% जनसंख्या किसी न किसी प्रकार की विकलांगता की शिकार है, जिससे आय से निरपेक्ष उनका जीवन स्तर सीमित होता है।[22]

बीसवीं शताब्दी की शुरुआत और मध्य में यूरोपीय देशों ने न केवल आय में बढ़ोतरी करके, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराके ग़रीबी घटाई।[23] सापेक्षिक निर्धनता के स्तर को देखते वक्त सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, इसके साथ कि क्या निर्धन ''बग़ैर शर्म के लोगों के बीच आ सकते हैं?''[24] आय को एक गरिमापूर्ण जीवन स्तर में बदलना अनेक परिसंपत्तियों और क्षमताओं पर निर्भर करता है। ये वे मुद्दे हैं जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक व निजी सुरक्षा उपलब्ध कराके राज्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है (बॉक्स 1.4)। आय को खुशहाली में रूपांतरित करना, खासतौर पर निर्धनों के, पर्यावरणीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।[25]

निर्धनता की अधिक विस्तृत माप बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (ब.नि.सू. यानी Multidimensional Poverty Index) के माध्यम से की जा सकती है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर में वंचितताओं पर दृष्टि डालता है। ब.नि.सू उत्पाद है बहुआयामी निर्धनता की कुल गणना (बहुआयामी तौर पर निर्धन लोगों के भाग) और प्रत्येक बहुआयामी तौर पर निर्धन परिवार द्वारा सहन की जाने वाली वंचितताओं की औसत संख्या (उनकी निर्धनता की तीव्रता) का। निर्धनता की तीव्रता पर ध्यान केंद्रित करने से ब.नि.सू. (MPI), एक देश या समुदाय के भीतर, केवल कुल संख्या की गिनती की तुलना में निर्धनता की एक अधिक संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाता है। ब.नि.सू. की परिधि में आने वाले 104 देशों के लगभग 1.56 बिलियन या उनकी जनसंख्या के 30% से अधिक लोग अनुमानतः बहुआयामी निर्धनता में जीते हैं।[26] यह इन देशों में 1.25 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीने वाले अनुमानित 1.14 बिलियन लोगों की संख्या से ज़्यादा है, हालाँकि यह उन लोगों के अनुपात से कम है जो 2 डॉलर प्रतिदिन से कम आय पर आजीविका चला रहे हैं।[27] यह प्रवृत्ति सभी चार मा.वि.सू. समूहों पर लागू होती है, हालाँकि मध्यम और उच्च मा.वि.सू. देशों की तुलना में निम्न मा.वि.सू. देशों में यह अंतर अधिक है (रेखांकन 1.3)। यह दक्षिण के तेज़ी से वृद्धि करते बहुत से देशों के लिए भी सच है (रेखांकन 1.4)।

ब.नि.सू.पर आधारित सर्वोच्च गणना प्रतिशत (headcount percentages) वाले देश अफ्रीका में हैं:

सारणी 1.2

2012 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से बेहतर मा.वि.सू. पर प्रदर्शन करने वाले पाँच शीर्ष देश

मा.वि.सू. समूह एवं देश	मा.वि.सू. मान	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (स.रा.आ.) (2005 पी.पी.पी. डॉलर)	स.रा.आ. श्रेणी से मा.वि.सू. श्रेणी का अंतर
अति उच्च मानव विकास			
न्यूज़ीलैंड	0.919	24,358	26
आयरलैंड	0.916	28,671	19
ऑस्ट्रेलिया	0.938	34,340	15
कोरिया गणराज्य	0.909	28,231	15
इस्राइल [a]	0.900	26,244	13
उच्च मानव विकास			
क्यूबा	0.780	5,539	44
जॉर्जिया	0.745	5,005	37
मॉन्टेनीग्रो	0.791	10,471	24
अल्बानिया	0.749	7,822	21
ग्रेनाडा	0.770	9,257	21
मध्यम मानव विकास			
समोआ	0.703	3,928	28
टोंगा	0.710	4,153	26
फ़िजी	0.702	4,087	24
किर्गिस्तान	0.622	2,009	24
घाना	0.558	1,684	22
निम्न मानव विकास			
मेडागास्कर	0.483	828	28
टोगो	0.459	928	16
केन्या	0.519	1,541	15
ज़िम्बाब्वे	0.397	424	14
नेपाल [b]	0.463	1,137	11

नोट - [a] सभी अति उच्च मा.वि.सू. वाले इन देशों, चिली, एस्टोनिया और यूनान के लिए भी स.रा.आ. और मा.वि.सू. रैंक का अंतर 13 है।
[b] निम्न मा.वि.सू. वाले देश लाइबेरिया के स.रा.आ. और मा.वि.सू. रैंक का अंतर भी 11 है।
स्रोत - एच.डी.आर.ओ. गणना। सांख्यिकीय सारणी 1 भी देखें

बॉक्स 1.4

खुशहाली के व्यक्तिनिष्ठ सूचक: दृष्टिकोण और नीति में बढ़ी हुई स्वीकृति

हाल के वर्षों में खुशहाली व मानवीय प्रगति को मापने और लोक नीति को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिनिष्ठ आँकड़ों के प्रयोग में रुचि बढ़ी है।[1] यूनाइटेड किंगडम में, सरकार ने स्टिग्लिट्ज, सेन और फितौसी (2009) द्वारा सुझाए गए खुशहाली के व्यक्तिनिष्ठ सूचकों के प्रयोग के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। भूटान ने अपने लोक नीति कदमों में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को निर्मित करने वाले उप-संकेतकों को समन्वित किया है। ये आँकड़े पूरक की भूमिका तो निभा सकते हैं, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ आँकड़ों का विकल्प नहीं हैं।

काह्नेमेन और क्रूगर (2006) व्यक्तिनिष्ठ खुशहाली के मापन के लिए विश्लेषणात्मक आधार इस तथ्य को बनाते हैं कि लोग अक्सर ''तार्किक आर्थिक एजेंट'' के मानकों से अलग व्यवहार करते हैं। असंगत निर्णय लेना, नवीन जानकारियों के आलोक में विश्वासों में सुधार न करना, लाभदायक विनिमयों से परहेज करना: ये सभी कारक तार्किकता की उस मान्यता का उल्लंघन करते हैं जो देखे गए व्यवहार को अर्थशास्त्र की प्रत्यक्ष वरीयताओं के सिद्धांत में बदलने का आधार है। यदि परीक्षित आँकड़ों और वास्तविक वरीयताओं में परिकल्पित सम्बन्ध कमज़ोर होगा तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ आँकड़ों पर निर्भर रहने की वजह कमज़ोर होती है, और व्यक्तिनिष्ठ आँकड़ों का प्रयोग करने की ज्यादा बड़ी वजह बन जाती है।

स्टिग्लिट्ज, सेन और फितूसी (2009) जीवन की गुणवत्ता को मापने के अपने तीन अवधारणात्मक उपागमो (approaches) में से एक व्यक्तिनिष्ठ खुशहाली को बनाते हैं। वे बताते हैं कि इस उपागम के उपयोगितावादी परंपरा से सशक्त सम्बन्ध हैं लेकिन इसमें उससे वृहत्तर आकर्षण है। लेकिन, जीवन की गुणवत्ता के व्यक्तिनिष्ठ मापदंडों के वस्तुनिष्ठ प्रतिरूप नहीं होते। उदाहरण के लिए खुशी को मापने का कोई परीक्षित मापदंड नहीं है, जबकि मुद्रास्फीति को वास्तविक या देखी गई मुद्रास्फीति के रूप में मापा जा सकता है। उनके अनुसार व्यक्तिनिष्ठ उपागम जीवन की गुणवत्ता के आयामों और उन्हें आकार देने वाले वस्तुनिष्ठ कारकों के बीच अंतर करना संभव बनाते हैं।

व्यक्तिनिष्ठ मापदंडों की भी अपनी समस्याएँ हैं। उनकी प्रकृति क्रमवार (ordinal) है और सामान्यतः इनके संदर्भ में देशों व संस्कृतियों के मध्य तुलना संभव नहीं हो पाती। समय के फलक पर ये विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए प्रसन्नता जैसे व्यक्तिनिष्ठ सूचकों का एकमात्र या प्रमुख नीति मापदंड के रूप में प्रयोग ग़लत निष्कर्षों की ओर ले जा सकता है। हालाँकि अगर इन सूचकों को उचित ढंग से मापा और सावधानी के साथ उपयोग किया जाए, तो ये विशेष तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर, नीति को प्रभावित करने में वस्तुनिष्ठ आँकड़ों के मूल्यवान परिपूरक की भूमिका निभा सकते हैं।

खुशहाली का एक महत्वपूर्ण व्यक्तिनिष्ठ सूचक समग्र जीवन संतुष्टि है। इसे सर्वेक्षणों से जाना जा सकता है। इसे 0-10 अंकों के स्केल से मापा जा सकता है। 149 देशों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर औसत जीवन संतुष्टि (Average Life Satisfaction) 5.3 है (सारणी देखें), सारणी में सबसे नीचे स्थान टोगो (2.8) का है और सबसे ऊपर डेनमार्क (7.8) का है (देखिए सांख्यिकीय सारणी 9)। यह देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उच्च मानव विकास वाले देशों में जीवन संतुष्टि भी ऊँची दिखती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ संतुष्टि और समग्र जीवन संतुष्टि

मा.वि.सू. समूह एवं क्षेत्र	समग्रता में जीवन से संतुष्टि, 2007-2011[a] (0, न्यूनतम संतुष्ट, 10, सर्वाधिक संतुष्ट)	स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्टि 2007-2009[a] (हाँ में जवाब देने वाले, % में)	शिक्षा की गुणवत्ता से संतुष्टि, 2011 (हाँ में जवाब देने वाले, % में)
मा.वि.सू. समूह			
अति उच्च मा.वि.सू	6.7	61.9	61.3
उच्च मा.वि.सू.	5.9	55.2[b]	58.0
मध्यम मा.वि.सू.	4.9	68.7[b]	69.2
निम्न मा.वि.सू.	4.5	50.0	56.5
क्षेत्र			
अरब देश	4.8	54.3[b]	50.0
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	5.1[b]	79.5[b]	68.2[b]
यूरोप एवं मध्य एशिया	5.3	44.8	51.8
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	6.5	56.7	61.4[b]
दक्षिण एशिया	4.7	64.8	73.3
सब-सहारा अफ्रीका	4.4	50.1[b]	52.0
विश्व	5.3	61.0[b]	64.2

a. आँकड़े बताई गई अवधि में अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए हैं।
b. मान सांख्यिकीय सारणियों में दर्शाए नहीं गए हैं क्योंकि आँकड़े आधे से अधिक देशों के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं, जो इस समूह के देशों की लगभग दो-तिहाई आबादी से ज्यादा हिस्सा है
स्रोत: गैलप (2012) के आधार पर की गई गणनाएँ।

स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता से संतोष मानवीय खुशहाली के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिनिष्ठ सूचक हैं। सर्वेक्षणों परिणाम प्रदर्शित करते हैं कि आय और मानव विकास स्तरों के एक व्यापक फलक में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ व शिक्षा दी जा सकती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से औसत वैश्विक संतुष्टि 61% थी। इसमें निम्नतम स्थान इथियोपिया (19%) का और उच्चतम स्थान लक्ज़मबर्ग (90%) का था (देखिए सांख्यिकीय सारणी 7)। शैक्षिक गुणवत्ता के साथ औसत वैश्विक संतुष्टि 64% थी। इसमें निम्नतम स्थान पर माली (35%) और उच्चतम स्थान पर कंबोडिया (94%) है (देखिए सांख्यिकीय सारणी 8)।

दक्षिण एशिया में 65% लोग स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के साथ संतुष्टि दर्शाते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका में यह प्रतिशत क्रमशः 41 और 83 है। श्रीलंका का आँकड़ा दिखाता है कि तुलनात्मक तौर पर आय के निम्न स्तरों के होते हुए भी समुदाय और राज्य के बारे में सामाजिक छवि को मज़बूत किया जा सकता है। विपरीततः यूरोप और मध्य एशिया में स्वास्थ्य सुविधा संतुष्टि (health care satisfaction) 45 प्रतिशत है।

स्रोत : काह्नेमेन एँड क्रुएगर (2006), स्टिगलिट्ज़, सेन एवं फितूसी (2009), डोलन, लायर्ड एवं मेटकाफ(2011), स्टीवर्ट (2013)

इथियोपिया (87%), लाइबेरिया (84%), मोज़ांबीक (79%) और सिएरा लिओन (77%; सांख्यिकीय सारणी 5 देखें)। निर्धनता की उच्चतम तीव्रता वाले देशों (भारित सूचकों के न्यूनतम 33% में वंचितताएँ) में इथियोपिया और मोज़ांबीक (2007-11 के दौरान प्रत्येक में लगभग 65%) आते हैं। उसके बाद क्रमशः बुर्किना फासो (64%), सेनेगल (59%) और लाइबेरिया (58%) आते हैं। लाइबेरिया की तुलना में बहुआयामी निर्धनों के कम अनुपात (कुल गणना अनुपात) के बावजूद मोज़ांबीक का ब.नि.सू. मान (0.512) उच्चतर है क्योंकि यहाँ उपलब्ध आँकड़े वाले देशों में निर्धनता की तीव्रता सबसे ज़्यादा है।

दक्षिण एशिया में सर्वाधिक ब.नि.सू. बांग्लादेश (2007 के आँकड़ों के अनुसार 0.292) का है और उसके बाद क्रमशः पाकिस्तान (2007 के आँकड़ों के अनुसार 0.264) और नेपाल (2011 के आँकड़ों के अनुसार 0.217) आते हैं। बहुआयामी निर्धनता में जीवन बिताने वाली जनसंख्या का अनुपात बांग्लादेश में 50%, पाकिस्तान में 53% और नेपाल में 49% है। बांग्लादेश में वंचितताओं की तीव्रता 50.4%, पाकिस्तान में 53.4% और नेपाल में 49% है। हालाँकि पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बहुआयामी निर्धनता में जीवन बिताता है, फिर भी पाकिस्तान में वंचितताओं की तीव्रता कहीं अधिक है। इसके अलावा, बांग्लादेश और नेपाल में स्वास्थ्य और शिक्षा आयामों की तुलना में जीवन स्तर आयाम का अधिक योगदान होता है, जबकि पाकिस्तान में स्वास्थ्य आयाम अन्य दोनों आयामों की तुलना में कहीं अधिक योगदान देता है।

समता और मानव विकास

मानव विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम समता है। हर व्यक्ति को अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार एक संतोषपूर्ण जीवन बिताने का अधिकार है। किसी को भी एक छोटे या तकलीफ़देह जीवन के लिए इस वजह से अभिशप्त नहीं होना चाहिए कि वह एक 'ग़लत' वर्ग या देश, 'ग़लत' जाति या नस्ल, या 'ग़लत' लिंग में पैदा हुआ/हुई है।

असमानता

असमानता मानव विकास की गति को धीमा करती है और कुछ मामलों में तो बिल्कुल रोक ही सकती है। यह शिक्षा और स्वास्थ्य की असमानता में सबसे अधिक दिखता है और आय असमानता में कम, जहाँ इसके प्रभाव उच्च और अति उच्च मा.वि.सू. देशों में ज़्यादा ठोस हैं। इस रिपोर्ट के लिए 132 विकसित और विकासशील देशों का विश्लेषण असमानता और

रेखांकन 1.3

जितना नीचा मा.वि.सू., उतना बड़ा आय निर्धनता और बहुआयामी निर्धनता के बीच अंतराल

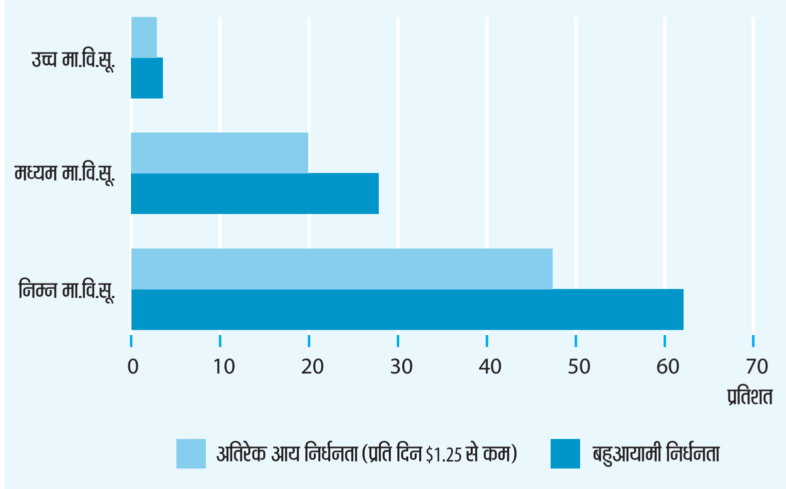

नोट: 2002-2011 के आँकड़े। जनसंख्या-भारित औसत उच्च मा.वि.सू. समूह के लिए 22 देशों और मध्यम व निम्न मा.वि.सू. समूहों में से प्रत्येक के लिए 36 देशों पर आधारित है।
स्रोत: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

मानव विकास (बॉक्स 1.5) में प्रतिलोम सम्बन्ध दिखाता है। विकसित देशों के अनेक अध्ययनों के निष्कर्ष भी यही बताते हैं।[28]

मानव विकास पर असमानता के प्रभावों का आकलन असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (अ.मा.वि.सू. यानी Inequality-adjusted Human Development Index- IHDI) से किया जा सकता है, जो मानव विकास के औसत स्तर और जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के स्तर और संसाधनों पर नियंत्रण के आयामों में इसके वितरण का परीक्षण करता है। जहाँ कोई असमानता नहीं है, वहाँ अ.मा. वि.सू.(IHDI), मा.वि.सू. के बराबर होता है। इन दोनों के मध्य अंतर ही असमानता को इंगित करता है। जितना अधिक अंतर होगा, असमानता का परिमाण भी उतना ही अधिक होगा।[29]

2012 में 132 देशों के लिए हुई अ.मा. वि.सू. गणनाओं के अनुसार कुल मा.वि.सू. मान के एक-चौथाई या 23% की हानि असमानता की वजह से हुई (देखिए सांख्यिकीय सारणी 3)। निम्न मा.वि. सू. वाले देश अनेक आयामों में व्यापक असमानता के चलते अधिक पीड़ित रहते हैं। निम्न मा.वि.सू देश एक-तिहाई मान मा.वि.सू. असमानता के कारण गँवा देते हैं जबकि अति उच्च मा.वि.सू देश मात्र 11% गँवाते हैं।

पिछले दो दशकों में दुनिया भर में, आय की तुलना में स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता ज़्यादा घटी है।[30] इसका आंशिक कारण जीवन प्रत्याशा और स्कूल जाने के माध्य वर्ष बढ़ाने जैसे उपायों की उच्चतर सीमाएँ हैं

किसी को भी एक छोटे या तकलीफ़देह जीवन के लिए इस वजह से अभिशप्त नहीं होना चाहिए कि वह एक 'ग़लत' वर्ग या देश, 'ग़लत' जाति या नस्ल, या 'ग़लत' लिंग में पैदा हुआ/हुई है

रेखांकन 1.4

आय निर्धनता और बहुआयामी निर्धनता के अंतर को लेकर देशों के बीच खासी भिन्नताएँ हैं

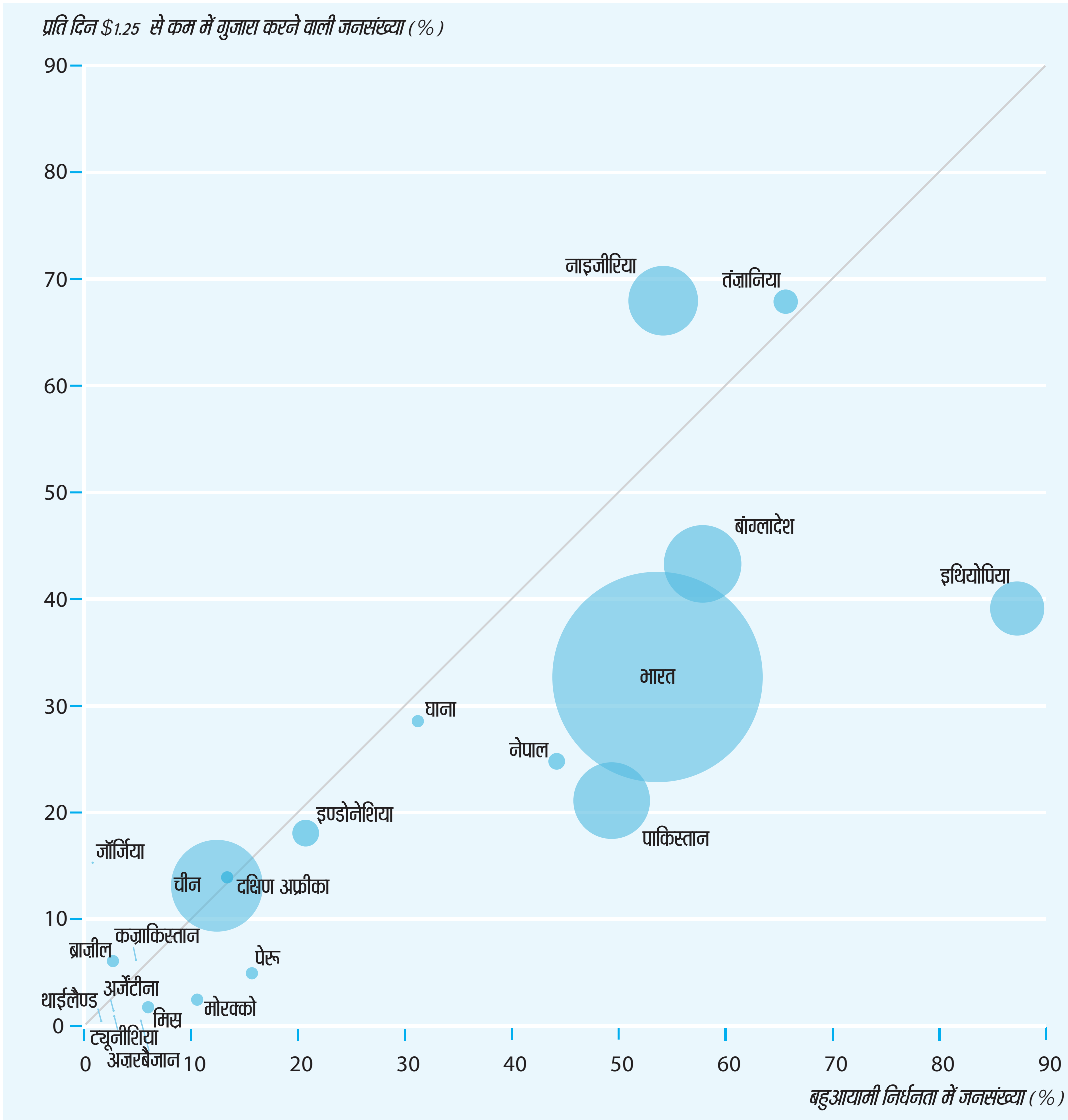

नोटः 2002-2011 के आँकड़े। वृत्ताकार आकृतियाँ बहुआयामी निर्धनता में रह रहे लोगों की संख्या को दर्शाती हैं। वृत्तों का आकार उनकी बहुआयामी निर्धन जनसंख्या के अनुपात में है विकर्ण रेखा इंगित करती है जहाँ 1.25 डॉलर प्रति दिन के नीचे रहने वाली जनसंख्या बहुआयामी निर्धन जनसंख्या के बराबर है।
स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

जिनकी ओर अंततः सभी देश अभिमुख होते हैं। दूसरी ओर, आय की कोई उच्चतर सीमा नहीं है। वस्तुतः सारे अध्ययन यह बताते हैं कि आय में वैश्विक असमानता का स्तर उच्च है, हालाँकि इसके ताजा रुझानों पर मतैक्य नहीं है।[31] एक अध्ययन ने 1970 से 2000 के दौरान 138 देशों के आय वितरण को एकीकृत किया और पाया कि माध्य प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के साथ असमानता में कोई बढ़त नहीं आई है।[32] दूसरे अध्ययन इसके विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।[33] वहीं, दूसरे अध्ययन भी हैं जिन्हें कोई बदलाव नहीं मिला है।[34]

1990 से 2005 के दौरान 66 देशों के लिए अ.मा.वि.सू. के रुझान बताते हैं कि स्वास्थ्य व शैक्षिक असमानता में हुई कमी को आय असमानता में हुई वृद्धि द्वारा घटा दिए जाने के कारण समग्र असमानता में मामूली ही कमी आई है (चित्र 1.5)। अधिकांश क्षेत्र आय असमानता को बढ़ते और स्वास्थ्य व शिक्षा में असमानता को घटते दिखाते हैं (चित्र 1.6)। लैटिन अमेरिका में सन् 2000 से आय की असमानता में कमी देखी जा रही है, लेकिन अभी भी यहाँ सभी क्षेत्रों

में से सर्वाधिक असमान वितरण व्याप्त है। सब-सहारा अफ्रीका में स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वाधिक असमानता है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक असमानता दक्षिण एशिया में है।

विश्व ने 1990 से 2010 के दौरान शिक्षा उपार्जन में असमानता कम करने में काफ़ी प्रगति की है। यह प्रगति स्कूली शिक्षा वर्षों की प्रत्याशा और नामांकन अनुपात, दोनों में दिखी है। यूरोप और मध्य एशिया (शिक्षा में असमानता के कारण होने वाले नुकसान में तकरीबन 68% की कमी आई), पूर्वी एशिया और प्रशांत (34%) और लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई देशों (32%) ने इस दिशा में विशेष तौर पर प्रगति दिखाई है। विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों में प्राथमिक शिक्षा के लिए औसत नामांकन का अनुपात तकरीबन 100% है। और ज़्यादा बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर रहे हैं।

हो सकता है, स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों में असमानता में आ रही कमी सामाजिक नीति में नवाचार और सम्बन्धित सरकारी प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करती हो। स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच भी एक सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए, महिलाओं की बेहतर शिक्षा से उनमें और अगली पीढ़ी में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं। इस तरह जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, साथ-साथ चल सकते हैं। आज शिक्षा में सबसे ज़्यादा असमानता गुणवत्ता में विषमताओं को प्रतिबिंबित करती हैः (बाक्स 1.6)। कई विकासशील देशों में दोहरी व्यवस्था है, संपन्न लोग अधिकांशतः निजी वित्तपोषित अच्छे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढते हैं, और ग़रीब अपर्याप्त साधनों वाले, सरकारी पैसे से चलने वाले संस्थानों में ।[35]

बढ़ती असमानता, खासकर समूहों के बीच, सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकती है, दीर्घावधि मानव विकास प्रक्रिया को कमजोर करते हुए। असमानताओं का बने रहना अक्सर अंतर-पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता का अभाव पैदा करता है और उससे भी सामाजिक असंतोष होता है।

आय असमानता में बढ़ोतरी कुछ सीमा तक राष्ट्रीय राजकोषीय और, खासकर, कर-प्रणाली की असफलता दिखाती है। इसे सामाजिक सुरक्षा द्वारा सन्तुलति या पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका में नकद अंतरण कार्यक्रमों (cash transfer programmes) के परिणामस्वरूप आय असमानता घटी है।

बॉक्स 1.5

असमानता मानव विकास को रोकती है

मानव विकास सूचकांक आँकड़ों का उपयोग करते हुए एच.डीआर.ओ. का शोध बताता है कि असमानता और इसके बाद के मानव विकास के सुधार में उलटा सम्बन्ध होता है, और इसका प्रमुख कारण आय असमानता से ज़्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता का होना है।

2012 के लिए 132 देशों के आँकड़ों का उपयोग करते हुए प्रतिगमन विश्लेषण (Regression Analysis) ने चार व्याख्यात्मक परिवर्तों (Explanatory Variable) जैसे मानव विकास में समग्र असमानता, जीवन प्रत्याशा में असमानता, शिक्षा प्राप्त करने में असमानता और प्रति व्यक्ति आय में असमानता के कारण मा.वि.सू. और इसके प्रत्येक घटक (स्वास्थ्य, शिक्षा और आय) पर बहुआयामी असमानता के प्रभाव को दिखाया। इस असमानता को मा.वि.सू.-सापेक्ष असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक में कमी के रूप में मापा गया। प्रत्येक व्याख्यात्मक परिवर्त के लिए एक भिन्न प्रतिगमन (Regression) प्रयुक्त किया गया और इन सभी परिवर्तों में मानव विकास के स्तरों (निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च) को नियंत्रित करने के लिए नकली (डमी) परिवर्त शामिल हैं। मानव विकास में समग्र असमानता, जीवन प्रत्याशा में असमानता और शिक्षा प्राप्त होने में असमानता सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण (1% स्तर पर) बहुत ऊँचा नकारात्मक सहसम्बन्ध हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में असमानता कोई सहसम्बन्ध नहीं दिखाती। अलग-अलग विनिर्देशों पर भी नतीजे ऐसे ही ठोस थे, तब भी, जब निम्न और मध्यम मानव विकास देशों को एक ओर और उच्च तथा अति उच्च मानव विकास देशों के समूहों को दूसरी ओर रखा गया।

स्रोत : एच.डी.आर.ओ.

रेखांकन1.5

मा.वि.सू. और उसके आयामों में असमानता के कारण हानि

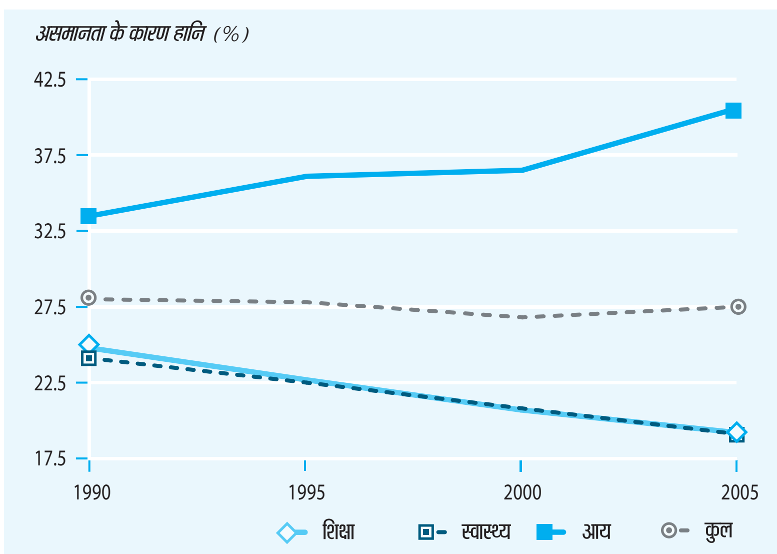

नोटः 66 देशों के जनसंख्या-भारित संतुलित पैनल पर आधारित
स्रोतःमिलानोविक (2010) के आँकड़ों के आधार पर एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

जेंडर और महिलाओं की स्थिति

लैंगिक समानता मानव विकास का एक प्रमुख सरोकार और एक अनिवार्य हिस्सा, दोनों है। अक्सर ही, महिलाओं के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम बाज़ार में भेदभाव किया जाता है। यह उनकी स्वतंत्रताओं को सीमित करता है। भेदभाव की सीमा को लैंगिक असमानता सूचकांक (लै.अ.सू.) के माध्यम से मापा जा सकता है जो तीन आयामों में लैंगिक असमानता के कारण उपलब्धि-हानि को मापता हैः प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम बाज़ार में भागीदारी। लै.अ.सू. का जितना ऊँचा मान, उतना ज़्यादा भेदभाव। 148

रेखांकन1.6

अधिकतर क्षेत्र स्वास्थ्य व वैश्विक असमानता में गिरावट और आय असमानता में बढ़ोतरी दर्शाते हैं

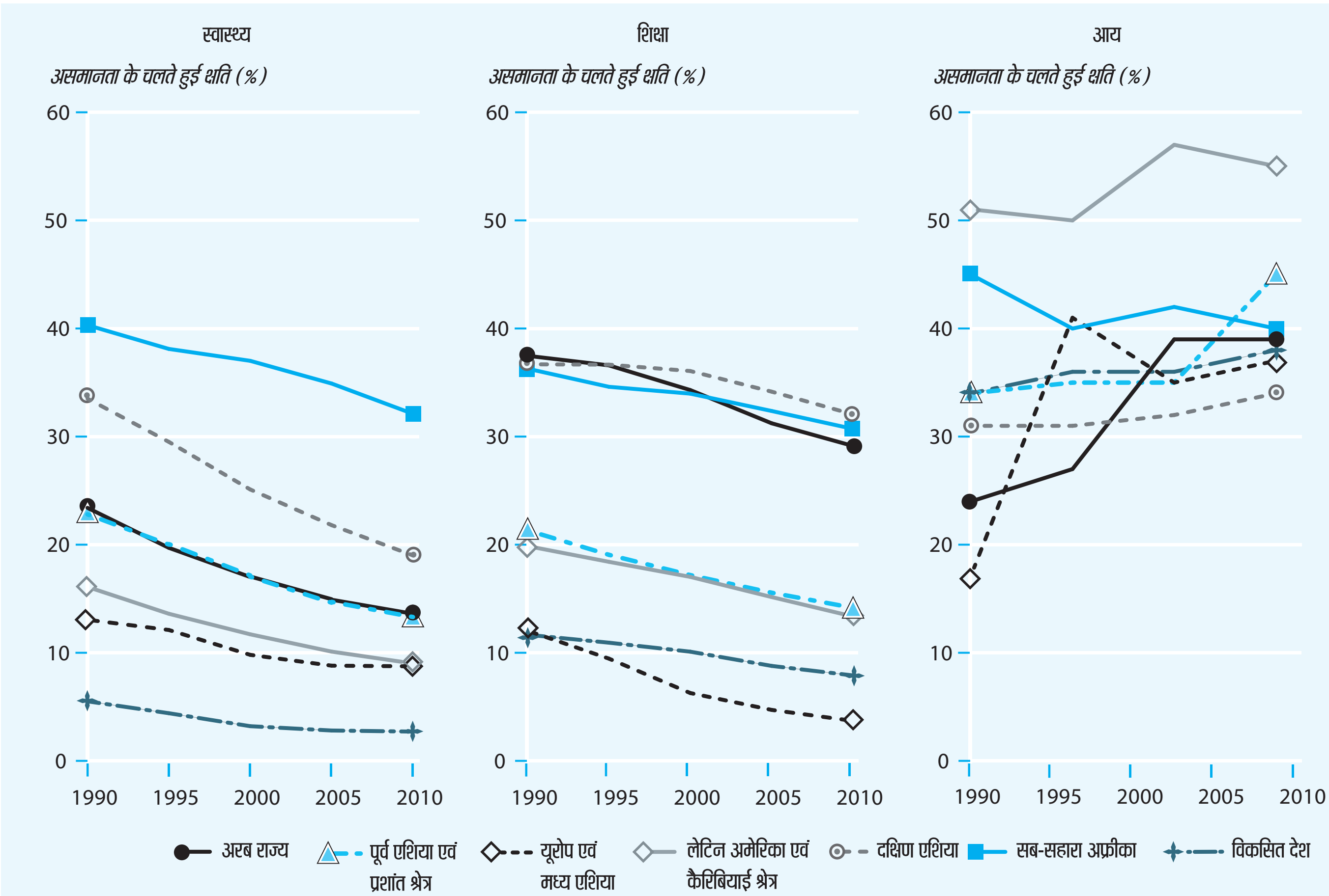

नोट : 182 देशों में स्वास्थ्य असमानता से होने वाली हानि के कारण जनसंख्या भारित संतुलित पैनल, 144 देशों में शैक्षिक असमानता के कारण हानि और 66 देशों में आय असमानता के कारण होने वाली हानि पर आधारित। मिलानोविक (2010) से आय असमानता के आँकड़े 2005 तक उपलब्ध हैं।
स्रोत : एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग की जीवन सारणियों से स्वास्थ्य आँकड़ों का, बारो और ली (2010) से शैक्षिक आँकड़ों का और मिलानोविक (2010) से आय असमानता आँकड़ों का उपयोग करते हुए।

देशों के 2012 के आँकड़ों पर आधारित लै.अ.सू. विभिन्न देशों के बीच व्यापक विभिन्नताएँ दर्शाता है। इसका फलक 0.045 (नीदरलैंड) से लेकर 0.747 (यमन) तक है, औसत 0.463 है (सांख्यिकीय सारणी 4 देखें)।

उच्च लैंगिक भेदभाव दक्षिण एशिया (0.568), सब-सहारा अफ्रीका (0.577) और अरब देशों (0.566) में बना हुआ है। दक्षिण एशिया में इसके तीन प्रमुख कारक हैं– संसद में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व (18.5%), शैक्षिक उपलब्धि में लैंगिक असंतुलन (50% पुरुषों की तुलना में केवल 28% महिलाएँ ही कम से कम माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाती हैं) और श्रम बल में कम भागीदारी (81% पुरुषों की तुलना में 31% महिलाएँ ही श्रम बल का हिस्सा हैं।

2000 से लेकर 2012 के बीच लै.अ.सू. की गिरावट की प्रगति वास्तव में सार्वभौमिक है, लेकिन असमान।[36] अति उच्च मानव विकास वाले समूह के देशों ने दूसरे मानव विकास समूहों के देशों से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और श्रम बाज़ार भागीदारी और शैक्षिक प्राप्ति के मामलों में स्त्रियों और पुरुषों के बीच ज़्यादा समानता का प्रदर्शन किया है। लेकिन इस समूह में भी कई देशों में संसदीय भागीदारी के मामले में विशाल लैंगिक असमानताएँ हैं। उदाहरण के लिए इटली ने महिलाओं की भागीदारी को 50% से अधिक बढ़ाया है लेकिन वे अब भी कुल सीटों के तकरीबन पाँचवें हिस्से (20.7%) पर ही काबिज हो सकी हैं। आयरलैंड में महिला संसदीय भागीदारी अभी 20% से कम है जबकि रवाण्डा में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा (48% की तुलना में 52%) है।

हालाँकि सब-सहारा अफ्रीका के कई देशों ने 2000 से 2012 के बीच लै.अ.सू. मानों में प्रगति

प्रदर्शित की है, लेकिन अब भी उनका प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों के देशों की तुलना में बहुत खराब है। इसका प्रमुख कारण उच्च मातृ मृत्यु दर, ऊँची किशोरी प्रजनन दरें व शैक्षिक उपार्जन में भारी अंतराल होना है।

सबसे ज़्यादा चिंताजनक रुझानों में एक है जन्म के समय का लिंगानुपात, जो कुछ तेज़ी से विकास कर रहे देशों में बिगड़ रहा है। 0 से 4 साल तक के बच्चों का प्राकृतिक अनुपात 1.05 (या 105 लड़कों पर 100 लड़कियाँ) है। लेकिन 175 देशों में, जहाँ के 2012 के आँकड़े उपलब्ध हैं, यह औसत 1.07 था, और 13 देशों में तो 1.08 से 1.18 के बीच था।[37]

कुछ देशों में लिंग-आधारित गर्भपात और शिशु हत्या जनसांख्यिकीय परिदृश्य को कृत्रिम रूप से बदल रहे हैं। इससे लड़कियों और महिलाओं की कमी हो रही है। यह केवल लैंगिक न्याय और समानता के लिए ही चिंता का कारण नहीं है, इसके लोकतंत्र के लिए बड़े निहितार्थ हैं और यह सामाजिक हिंसा पैदा कर सकता है।

जन्म के समय पुरुष लिंगानुपात का अधिक होना समाज में महिलाओं की स्थिति, बद्धमूल पितृसत्तात्मक रिवाजों और दुराग्रहों, जो गहरे जड़ जमाए सामाजिक-सांस्कृति विश्वासों का एक रूप हैं, शहरी व ग्रामीण समाजों की बदलती आकांक्षाएँ और कुछ देशों में दहेज प्रथा को प्रतिबिंबित करता है।[38] हाल के वर्षों में अल्ट्रासाउंड तकनीकों के प्रसार और दुरुपयोग के कारण यह समस्या गंभीर बन चुकी है क्योंकि ये तकनीकें माता-पिता की लड़कों को वरीयता देने की पुरानी पसंद को साकार करना संभव बनाती हैं। हालाँकि, इसका मुख्य प्रचालक पितृसत्तात्मक रिवाजों और दहेज प्रथा के कारण लड़कों की उच्चतर आर्थिक कीमत का मिश्रण है। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी देशों में केवल पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह, दहेज प्रथा के अभाव में, जन्म के समय उच्च पुरुष लिंगानुपात में नहीं बदलते दिखते।

इस असमानता को दूर करने के लिए कई सामाजिक मान्यताओं को बदलना होगा, उन्हें भी जो लड़कियों की जगह लड़कों के होने पर परिवार के आर्थिक प्रलोभनों को प्रभावित करती हैं। इसमें शामिल होगा इस शोषक दहेज प्रथा[39] को प्रभावी ढंग से समाप्त करना और महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक मौके उपलब्ध कराना, उनके अपनी जिंदगी पर ज़्यादा नियंत्रण पाने के लिए परिस्थितियाँ बनाना, उनकी राजनीतिक भागीदारी और परिवारों के भीतर निर्णय शक्ति बढ़ाना।

अक्सर यह तर्क दिया गया है कि महिलाओं के लिए शिक्षा में प्रगति उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तरों को बढ़ाने में मदद करती है और प्रजनन दरों को घटाती है।[40] इस तरह, महिलाओं के लिए विकल्पों

बॉक्स 1.6

शिक्षा गुणवत्ताः अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन के कार्यक्रम पर उपलब्धि

मानव विकास सूचकांक के शिक्षा अंग के दो मापक हैं: स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष और अपेक्षित स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष। लेकिन यहाँ स्कूली शिक्षा के वर्षों से ज्यादा शिक्षा की गुणवत्ता मानव क्षमताओं के प्रसार में एक प्रमुख कारक है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) का अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम (पीसा) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक उपार्जन पर संगत आँकड़े इकट्ठा करता है और औसत अध्ययन अंकों, निम्न-प्रदर्शन वाले स्कूलों का अनुपात और गुणवत्ता परिणामों की स्थिरता का विभिन देशों के बीच तुलना संभव बनाता है। उदाहरण के लिए, एक उच्च-शिक्षित श्रम बल का जो लाभ अब तक पारंपरिक रूप से अमेरिका जैसे देश उठाते रहे हैं, अब खिसकता लग रहा है, जैसे-जैसे दूसरे देशों के (जैसे आयरलैंड, जापान और कोरिया गणतंत्र) यही वर्ग अमेरिका में मिलने वाली योग्यताओं को हासिल भी कर रहे हैं और उनसे आगे भी निकल रहे हैं।

63 देशों और इलाकों में 2009 में किए गए सबसे ताजा पीसा मूल्यांकन में बहुत से देशों ने उपार्जन परिणामों की गुणवत्ता में प्रभावशाली प्रगति दिखाई है। शंघाई, चीन, के छात्रों ने पठन, गणित और विज्ञान दक्षताओं में 62 देशों के विद्यार्थियों से बेहतर प्रदर्शन किया। उनके बाद रहे पठन में कोरिया गणतंत्र, फिनलैंड, हांगकांग व चीन (एस.ए.आर.), गणित में सिंगापुर, हांगकांग व चीन (एस.ए.आर.) और कोरिया गणतंत्र और विज्ञान में फिनलैंड, हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.) व सिंगापुर के छात्र। गणित में अमेरिका का प्रदर्शन औसत से कम रहा है और वह पुर्तगाल और आयरलैंड के साथ 29वें स्थान पर रहा। हालाँकि विज्ञान में थोड़ा अधिक औसत के साथ उसने 21वाँ स्थान प्राप्त किया। अमेरिका ने पठन में औसत से अधिक प्रदर्शन करते हुए आइसलैंड और पोलैंड के साथ 15वाँ स्थान हासिल किया। बहुत निम्न स्तरीय प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए ब्राज़ील, चिली, इण्डोनेशिया और पेरू जैसे देशों ने प्रभावशाली प्रगति की है।

ज्यादा ज्ञान-चालित वैश्वीकृत दुनिया में शिक्षा की गुणवत्ता में निवेश करने वाले कुछ देश भविष्य में काफ़ी लाभ उठाएँगे।

अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आकलन कार्यक्रम (पीसा) के पठन अंकों का मानव विकास सूचकांक से सकारात्मक सह-सम्बन्ध है

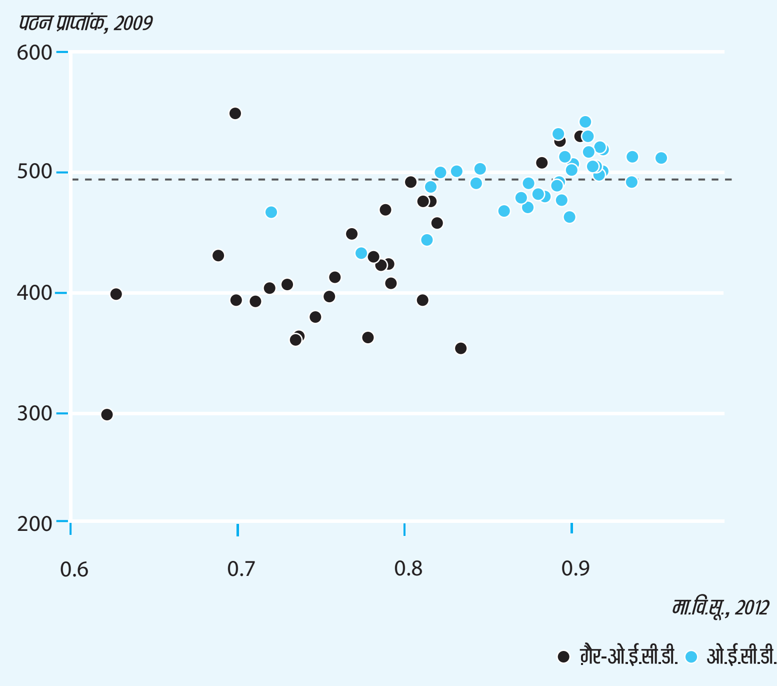

स्रोतः मा.वि.सू. मान, एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ; पीसा (अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आकलन कार्यक्रम) अंक, ओ.ई.सी.डी. (2010b)।

के विस्तार में इसके अन्तर्निहित मूल्य के अलावा शिक्षा की महिला और बच्चे के स्वास्थ्य और प्रजनन परिणामों को बढ़ाने में भी एक ठोस भूमिका है। इस संदर्भ में, निम्न और मध्यम मा.वि.सू. देशों को अभी काफ़ी रास्ता तय करना है। 1970-2000 में उच्च और अति उच्च मा.वि.सू. देशों में अशिक्षित आबादी के बीच एक लैंगिक असंतुलन भी था, हालाँकि इन देशों में तब स्कूल जाने की उम्र वाली बालिकाओं और युवतियों में हर शैक्षिक स्तर पर काफ़ी हद तक लैंगिक संतुलन था।

भविष्य की पीढ़ियों के हितों की कीमत पर पाए गए लाभों की तुलना में मानव विकास द्वारा उपलब्ध संवहनीयता श्रेष्ठतर होती है

महिलाओं के लिए शिक्षा और रोज़गार निर्माण महत्वपूर्ण तो बेशक हैं लेकिन पर्याप्त नहीं। महिलाओं की आय को बढ़ाने के लिए आम नीतियाँ परिवारों में लैंगिक भेदभाव, अवैतनिक कामों का महिलाओं पर उच्चतर बोझ होने और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण काम के लैंगिक विभाजन पर विचार नहीं कर पातीं। जब नीतियाँ ऐसे आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जो इन कारकों पर विचार नहीं करते, तो उनके स्त्रियों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, हालाँकि वे नीतियाँ आर्थिक संपन्नता पैदा करती हैं।[41] लैंगिक समानता को बढ़ाने की प्रमुख कुँजी राजनीतिक और सामाजिक सुधार हैं जो महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ाते हैं, जिनमें स्वतंत्रता, गरिमा, सहभागिता, स्वायत्तता और सामूहिक एजेंसी शामिल हैं।[42]

अंतर-पीढ़ी समता और संवहनीयता

जब एक के बाद एक संकट उत्पन्न हो रहे हों तो आज के कामों के महत्वपूर्ण दीर्घकालीन नतीजों का नजरअंदाज़ हो जाना आसान है। इसलिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि आज चुने गए विकल्पों का भविष्य में दशकों तक उपलब्ध विकल्पों पर बड़ा और निर्णायक प्रभाव हो सकता है। संवहनीय मानव विकास का मतलब है विभिन्न पीढ़ियों के तात्कालिक विकल्पों और वर्तमान व भावी पीढ़ियों को अधिकार प्रदान करने के सम्बन्धों को समझना।

जाहिर है, एक संतुलन चाहिए। लोगों, विशेषकर निर्धन और विविध वंचितताओं के साथ जी रहे लोगों की क्षमताओं को आज बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बुनियादी अधिकारों का मामला होने के साथ ही जीवन की सार्वभौमिकता के तकाजों का अंग है।[43] साथ ही, वर्तमान की निर्धनता और कष्ट भविष्य के लिए नकारात्मक परिणाम देते हैं। अतः उद्देश्य होना चाहिए आंतर-पीढ़ी और अंतर-पीढ़ी समता।

लोगों में आज निवेश करने के लिए ज़रूरत है आज चढ़ाए गए कर्जों और, वे भावी पीढ़ियों पर जो अदायगियाँ लादते हैं, उनके बीच एक समझदार संतुलन की। जैसा कि 1994 की *मानव विकास रिपोर्ट* रेखांकित करती है, ''सभी स्थगित ऋण, चाहे आर्थिक हों, सामाजिक या पारिस्थितिकीय, वे संवहनीयता को गिरवी रख देते हैं।''[44] हालिया वित्तीय संकट सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह के आर्थिक कर्ज के टिकाऊपन को सामने लाया है जब अर्थव्यवस्थाएँ नहीं बढ़ रही होती हैं। यह सामाजिक और पारिस्थितिकीय ऋणों के गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाता है। पर्यावरण के मोर्चे पर पहले ही वर्तमान और विगत पीढ़ियों के चुनावों से पारिस्थितिकी तंत्रों को गंभीर नुकसान पहुँचने के भरपूर प्रमाण मिल ही चुके हैं। निर्धन देश न तो धनी देशों के उत्पादन और उपभोग प्रवृत्ति का अनुसरण कर सकते हैं और न ही उन्हें करना चाहिए। और धनी देशों को अपने पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट में कमी लानी चाहिए क्योंकि एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उनका प्रति व्यक्ति उपभोग और उत्पादन संवहनीय नहीं हैं।

पर्यावरणीय बदलाव और नाजुक पारिस्थितिकियों की वैश्विक चुनौतियाँ आज विशेष चिंता का विषय हैं। एक प्रभावशाली अध्ययन का निष्कर्ष है कि ''मानवता पहले ही कम से कम तीन भूमंडलीय सीमाओं का अतिक्रमण कर चुकी है।''[45] वैश्विक संवहनीयता पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्च स्तरीय पैनल की 2012 की रिपोर्ट में भी इस बिंदु को दोहराया गया है।[46] कुछ देश आज एक पारिस्थितिकीय संवहनीय मार्ग अपना रहे हैं। इसने संवहनीय मानव विकास की ओर चलना सुगम बनाने के लिए तकनीकी नवाचार और उपभोग के तरीकों में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।[47]

रेखांकन 1.7, वर्ष 2012 में 151 देशों के मा.वि.सू. के सापेक्ष उनके उपभोग के पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट को दर्शाता है।[48] बहुत कम देश हैं जिनमें दोनों, अर्थात उच्च मा.वि.सू. मान हो और विश्व औसत से नीचे पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट हो। यह दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। समय के साथ हालात और खतरनाक हो रहे हैं। जहाँ कुछ उच्च मा.वि.सू. वाले देशों का प्रति व्यक्ति पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट वैश्विक औसत जैवक्षमता से कम है (1.79 वैश्विक हेक्टेयर प्रति व्यक्ति 2008 में), उनके फुटप्रिंट समय के साथ बढ़ते रहे हैं।

लोग सिर्फ अपने लिए मौजूद विकल्प की ही चिन्ता नहीं करते, बल्कि इसकी भी कि उन फैसलों को कैसे हासिल किया जा रहा है, कौन कर रहा है और किस कीमत पर। भविष्य की पीढ़ियों के हितों की कीमत पर पाए गए लाभों की तुलना में मानव विकास द्वारा उपलब्ध संवहनीयता श्रेष्ठतर होती है। वस्तुतः, संवहनीय मानव विकास के लिए एक बेहतर लेखा तंत्र, भावी मानव विकास और वर्तमान उपलब्धियों, दोनों को शामिल करेगा।

पर्यावरणीय संवहनीयता की निगरानी के बेहतर

रेखांकन 1.7

कम ही देश उच्च मा.वि.सू., और जो टिकाऊ नीचा पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट मानव विकास के लिए ज़रूरी है, दोनों दिखाते हैं

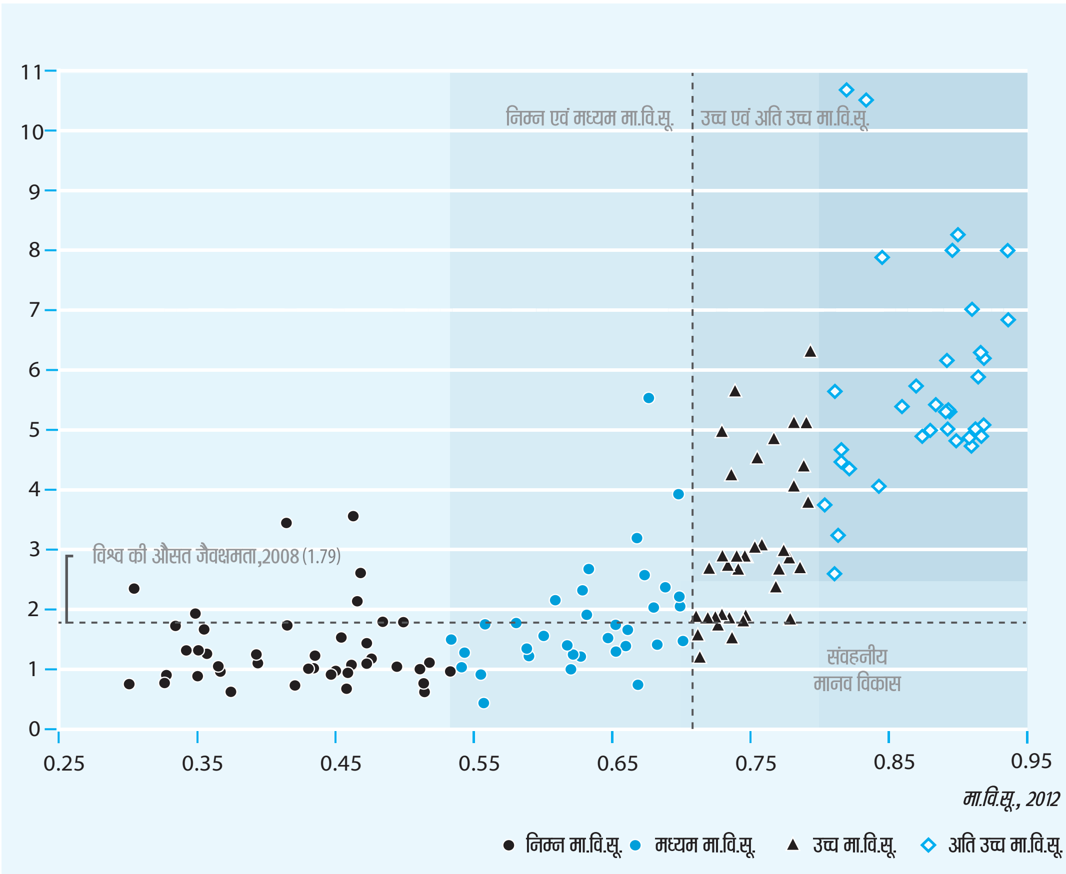

नोटः परिस्थितिकीय फुटप्रिट पृथ्वी की जैव क्षमता और जैव क्षमता की माँग बताने का एक मापक है। यह एक दिए हुए साल में जैविक रूप से उत्पादक भूमि और जल की औसत उत्पादकता पर निर्भर करता है।
स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ एवं वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क (2011)

तरीकों की भी ज़रूरत है। संवहनीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012 में उन उपायों का आह्वान किया गया, जो वर्तमान और भविष्य के विकल्प समूहों के सम्बन्धों को संबोधित कर सकें। इन उपायों को आर्थिक और पर्यावरणीय ऋण के संग्रह की निगरानी करनी चाहिए, इस आधार पर खड़े होकर, कि इस ग्रह के प्रत्येक नागरिक का, चाहे वह जीवित हो या अभी अजन्मा, समान अधिकार है एक सुविधापूर्ण, संतोषजनक जीवन जीने का। यह भी ज़रूरी है कि ये उपाय ग्रहीय सीमाओं या अनिवर्ती बिन्दुओं (tipping points) को भी ध्यान में लाएँ, यह स्वीकार करते हुए कि जलवायु परिवर्तन, उदाहरण के रूप में, पहले ही भारी कीमतें वसूल कर रहा है। इन कीमतों को सबसे ज़्यादा ग़रीब देशों और ग़रीब समुदायों को चुकाना पड़ता है।

सामाजिक एकीकरण

मानव विकास का अर्थ है व्यक्तिगत क्षमताओं का विस्तार। लेकिन व्यक्ति दूसरों के साथ भी जुड़े होते हैं। इसलिए, व्यक्ति एक-दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, यह संघटित और स्थायी समाजों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। विभिन्न समूहों का एकीकरण खुशहाली और सामाजिक स्थायित्व के लिए उतना ही अहम हो सकता है, जितनी आर्थिक सफलता। असमता और अपवर्जन (exclusion) ऐसे सामाजिक अन्याय हैं जो मानव स्वतंत्रताओं को बुनियादी रूप से कमजोर करते हैं।

एक एकीकृत समाज प्रभावी सामाजिक संस्थाओं पर निर्भर करता है जो लोगों को सामूहिक रूप से काम करने में सक्षम बनाती हैं, यूँ समूहों के बीच भरोसा और एकजुटता बढ़ाती हैं। इन संस्थाओं में औपचारिक

बॉक्स 1.7

सामाजिक कुशलताएँः व्यक्ति से परे मानव विकास

व्यक्ति अकेले नहीं पनप सकते, वास्तव में वे अकेले जी भी नहीं सकते। लेकिन, मानव विकास उपागम तत्वतः व्यक्तिवादी रहा है, यह मानते हुए कि विकास व्यक्ति की क्षमताओं या स्वतंत्रताओं का विस्तार है। किन्तु समाजों के कुछ पहलू हैं जो व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मापे नहीं जा सकते, क्योंकि वे सम्बन्धों पर आधारित हैं, जैसे परिवार या समुदाय कितने अच्छी तरह से रहते हैं। ये सामाजिक संघटन और सामाजिक समावेशन के विचारों में समग्र समाज के तत्वों के रूप में शामिल कर लिए जाते हैं। व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। सामाजिक संस्थाएँ व्यक्तियों की अस्मिताओं और चुनावों को प्रभावित करती हैं। एक स्वस्थ समाज का सदस्य होना एक उत्कर्षशील अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है।

इसलिए मानव विकास दृष्टिकोण का एक काम ऐसी सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति को समझना है, जो मानव के फलने-फूलने में मददगार हैं। तब विकास का मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत क्षमताओं पर अल्पकालीन प्रभाव पर ही नहीं बल्कि इस पर भी होगा कि क्या समाज ऐसे विकसित हो सकता है जो मनुष्य के उत्कर्ष में सहायक हो। सामाजिक स्थितियाँ एक समाज विशेष में केवल व्यक्तियों के परिणामों को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की उपलब्धियों को भी प्रभावित करती हैं।

सामाजिक संस्थाएँ वे सभी संस्थाएँ हैं जिनमें लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं (यानी उनमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं), लाभ कमाने वाली बाज़ार की संस्थाओं और राज्य के अलावा। इनमें सम्मिलित हैं औपचारिक ग़ैर-सरकारी संगठन, अनौपचारिक संघ, सहकारी समूह, उत्पादक संगठन, मोहल्ला संगठन, खेल क्लब, बचत संगठन और बहुत से दूसरे। उनमें मानव विकास परिणामों को प्रभावित करने वाले व्यवहार की मान्यताएँ और नियम भी होते हैं। उदाहरण के लिए, रोज़गार के प्रति रवैया भौतिक खुशहाली को प्रभावित करता है और वरीयता की मान्यताओं और भेदभाव से असमानता, भेदभाव, सशक्तीकरण और राजनीतिक स्वतंत्रता इत्यादि प्रभावित होते हैं। यह बताने के लिए कि ये संस्थाएँ क्या हो सकती हैं, क्या कर सकती हैं, और यह समझने के लिए कि वे व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती हैं, हम *सामाजिक कुशलताओं* शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।

मानव विकास परिप्रेक्ष्य के केन्द्र में यह बात है कि सामाजिक मान्यताएँ लोगों के चुनाव, फैसलों और दूसरों के साथ व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और यूँ संपूर्ण समुदाय के परिणामों पर असर डालती हैं। एक मानव विकास दृष्टिकोण से समुदाय की मान्यताएँ और व्यवहार हानिकारक तरीके से विकल्पों को सीमित कर सकते हैं– उदाहरण के लिए, सामाजिक बहिष्कार, या कुछ चरम मामलों में, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की हत्या। ग़रीबी में फँसे और बाल विवाह और दहेज की जरूरतों का समर्थन करने वाली अनौपचारिक मान्यताओं से घिरे परिवार ऐसी बद्धमूल सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तनों को अस्वीकार कर सकते हैं। सामाजिक संस्थाएँ लंबे काल में बदलती हैं और ये बदलाव अपने साथ सामाजिक तनाव भी ला सकते हैं, अगर वे कुछ समूहों के हितों को नुकसान पहुँचाएँ जबकि कुछ का पक्ष लें।

नीति परिवर्तन एक राजनीतिक संघर्ष का नतीजा होता है जिसमें विभिन्न समूह (और व्यक्ति) परिवर्तन विशेष का समर्थन या विरोध करते हैं। इस संघर्ष में असंगठित लोग आमतौर पर शक्तिहीन होते हैं लेकिन एक साथ इकट्ठा होकर वे सामूहिक रूप से शक्ति हासिल कर सकते हैं। मानव विकास बढ़ाने वाली सामाजिक क्रिया (जैसे शिक्षा के विस्तार, प्रगतिशील कर और न्यूनतम मजदूरी के लिए नीतियाँ) अचानक स्वतः स्फूर्त नहीं होती, बल्कि ऐसे समूहों के कारण जो परिवर्तन का समर्थन करने में प्रभावी हैं, जैसे उत्पादक समूह, श्रमिक संगठन, सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दल। ये संगठन निर्धनतर लोगों के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कोलकाता (भारत) में यौन कर्मियों के एक समूह और केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) में एक झुग्गी-झोपड़ी समुदाय की महिलाओं ने दिखाया। उन्होंने एकजुट होकर सामूहिक दबाव बनाकर अपनी स्थिति और आत्म सम्मान को ऊँचा उठाया।

संख्या, क्रियाकलापों, प्रभावशीलता और अपनी सामाजिक कुशलताओं के नतीजों में समाजों में व्यापक भिन्नताएँ हैं। संस्थाओं और मान्यताओं को मानव विकास-संवर्द्धक, मानव विकास-निरपेक्ष और मानव विकास-अपकर्षक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यक्तियों और संस्थाओं में बीच और आपस में मूल्यवान क्षमताओं और सम्बन्धों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं की पहचान और प्रोत्साहन बुनियादी महत्व का है। कुछ सामाजिक संस्थान (मान्यताएँ भी) कुछ मामलों में मानव विकास का समर्थन कर सकते हैं, कुछ में नहीं। उदाहरण के लिए, मज़बूत पारिवारिक रिश्ते व्यक्तियों को उथल-पुथल में सहारा दे सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत फैसलों और मौकों को सीमित कर सकते हैं।

मोटे तौर पर, सामाजिक संघटन और मानव विकास को बढ़ाने वाली संस्थाएँ समूहों (जैसे जातीय, धार्मिक या लैंगिक समूह) के बीच निम्न स्तर की विषमता और लोगों व समूहों के बीच और आपस में उच्च स्तर का विश्वास व अंतर्क्रिया प्रदर्शित करती हैं। इससे इनमें एकजुटता आती है और हिंसक संघर्ष नहीं होता है। यह संयोग नहीं है कि वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार 2012 में विश्व में 10 सबसे ज़्यादा शांत देशों में 5 देश सबसे ज़्यादा समतापूर्ण समाजों में भी शामिल हैं। इसे असमानता के कारण मानव विकास सूचकांक मान में होने वाली हानि द्वारा मापा गया है। उनकी यह विशिष्टता भी है कि उनमें भेदभाव अनुपस्थित है और हाशियाकरण का स्तर नीचा है। कुछ मामलों में, भेदभाव विरोधी उपाय हाशियाकरण के बोझ को हल्का कर सकते हैं और अपवर्जन के सबसे बुरे प्रभावों को आंशिक रूप से कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी कानून में इस प्रावधान ने कि लोगों की भुगतान क्षमता को देखे बग़ैर अस्पतालों के आपातकक्षों को सारे मरीजों को इलाज देना चाहिए, एक महँगी किन्तु सीमित कवरेज वाली स्वास्थ्य सेवा के असर को अंशतः घटाया है। कई देशों (मलेशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका सहित) में सकारात्मक कार्रवाई ने वंचित समूहों की परिस्थितियों में सुधार किया है और सामाजिक स्थायित्व में योगदान दिया है।

सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक कुशलताओं का अध्ययन मानव विकास उपागम का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए– समूहों के निर्माण, समूहों और व्यक्तियों के बीच अंतरक्रियाएँ, प्रलोभनों और सामूहिक कर्म पर बंधन, समूहों, राजनीति और नीति परिणामों के बीच सम्बन्ध, व्यवहारों को प्रभावित करने में मान्यताओं की भूमिका, और मान्यताएँ कैसी बनती और बदलती हैं, इसके सहित।

स्रोत - स्टीवर्ट 2012, इंस्टीट्यूट फ़ॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस 2013

ग़ैर-सरकारी संगठन, अनौपचारिक संघों और सहकारी समूहों के साथ-साथ व्यवहार के नियम और मान्यताएँ शामिल हैं। वे व्यक्तिगत मानव विकास परिणामों, सामाजिक संघटन और सामाजिक स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत क्षमताओं से इन्हें अलग रखने के लिए इन संस्थाओं के कामकाज और लोगों पर उनके प्रभाव को 'सामाजिक कुशलताएँ' कहा जा सकता है (बॉक्स 1.7)। किस हद तक सामाजिक कुशलताएँ ज़्यादा संघटित समाजों को बनाती हैं उसे सामाजिक समावेशन और सामाजिक स्थायित्व हासिलकरने में उनकी सफलता से नापा जा सकता है।

सामाजिक अपवर्जन को सुलझाने के लिए कुछ विकासशील देशों ने पुनर्वितरण के साथ विकास की रणनीति का परिष्कार करके संवृद्धि के लाभों को ज़्यादा समान तरीके से बाँटने की कोशिश की है। लेकिन समावेशी संवृद्धि की यह 'कमोडिटी-केंद्रित' दृष्टि ऐसे आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को मिटाने में ज़्यादा काम नहीं आती, जिसकी प्राचीन ऐतिहासिक

और सांस्कृतिक जड़ें हैं। इस तरह का भेदभाव उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में भी व्यापक हो सकता है। स्पष्टतः, अकेली आय वृद्धि सामाजिक संघटन हासिल नहीं कर सकती, सक्रिय नीतियाँ ज़रूरी हैं।

असमानता का प्रभाव पीढ़ियों तक चल सकता है। उदाहरण के लिए, आठ विकसित देशों के एक अध्ययन में पाया गया कि ज़्यादा असमान देशों में सामान्यतः कम सामाजिक गतिशीलता थी।[49] यूनाइटेड किंगडम में विशेषरूप से जब असमानता बढ़ी तो अंतरपीढ़ी गतिशीलता में गिरावट आई।

लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई मानव विकास रिपोर्ट 2010 ने सामाजिक गतिशीलता की कमी और सतत असमानता के बीच रिश्ते को रेखांकित किया।[50] ब्राज़ील में आमदनियों में असमानता का कम से कम एक चौथाई, परिवार की परिस्थितियों जैसे माता-पिता की शैक्षिक प्राप्ति, नस्ल या जातीयता, या जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है।[51]

आय वितरण की प्रवृत्तियों की पीढ़ियों-पार ऐसी निरंतरता चिली और मेक्सिको में भी दिखती है, हालाँकि मेक्सिको ने हाल के सालों में बढ़ी हुई अंतरपीढ़ी गतिशीलता देखी है।[52] लैटिन अमेरिका ग्रस्त है नीची सामाजिक गतिशीलता से, जो आय वितरण के निम्नतम पायदान पर खड़े ऐसे लोगों के लिए अवसरों को दबाती है, जिनके लिए समाज में सफल कार्यप्रदर्शन मुख्यतः पृष्ठभूमि के तत्वों से तय होता है, ऐसे तत्व जो उनके नियन्त्रण से परे हैं। विषमतापूर्ण समाजों में यह समस्या विशेष तौर पर असाध्य है, क्योंकि वंचित समूहों के सदस्य प्रगति करना खास तौर पर कठिन पाते हैं।

असमानता और अपवर्जन बने रहते हैं, जब अपवर्जित और वितरण के निचले हिस्सों के लोग इसके निवारण के लिए राजनीतिक अभिव्यक्ति से

असमानताओं की उपस्थिति सामाजिक मेलजोल को प्रभावित कर सकती है और विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता को भी अवरोधित कर सकती है

बॉक्स 1.8

निर्धनता के संरचनात्मक आयाम

निर्धनता में कमी लाने के परंपरागत एजेंडे इसके संरचनात्मक स्रोतों की पहचान तो करते हैं, परंतु इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। समावेशी संवृद्धि को बढ़ाने के लिए समकालीन हस्तक्षेपों का मुख्य ध्यान सामाजिक सुरक्षा तंत्र के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से मिलने वाले विकास के परिणामों पर है। हालाँकि ऐसी सार्वजनिक पहलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन ये केवल निर्धनता के लक्षणों पर ध्यान देती हैं, इसके स्रोतों पर नहीं।

ऐसे संकीर्ण हस्तक्षेपों के नतीजे आय निर्धनता के स्तर में अलग-अलग मात्रा में कमी और मानव विकास में कुछ सुधार के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन दक्षिण के ज़्यादातर हिस्सों में आय असमानताओं में वृद्धि हुई है, सामाजिक विषमताएँ फैली हैं और अन्याय सर्वव्यापी बना हुआ है, जबकि निर्धनता के संरचनात्मक स्रोत अब भी कायम हैं। निर्धनता की समाप्ति की किसी भी विश्वसनीय कार्यसूची को इसे बनाए रखने वाले संरचनात्मक अन्यायों को रोकना होगा।

परिसम्पत्तियों तक असमान पहुँच

धन और ज्ञान तक असमतापूर्ण पहुँच बाज़ार में अपवर्जितों की प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति को कमजोर करती है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण निर्धनता ग्रामीण समाज के कम अधिकारसंपन्न तबके की भूमि और जल तक अपर्याप्त पहुँच से उत्पन्न होती है। भू-स्वामित्व मात्र आर्थिक विशेषाधिकार का एक स्रोत नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक अधिकार का भी स्रोत रहा है। भू-स्वामित्व की प्रचलित संरचना एक सुसंचालित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शत्रुतापूर्ण बनी हुई है। इसी भाँति, पूँजी और संपत्ति तक पहुँच में कमी शहरी निर्धनता को बनाए रखती है।

बाज़ार में असमान सहभागिता

समाज की प्रचलित संपत्ति संरचनाओं के कारण संसाधन-विहीन लोग अधिक गतिशील बाज़ार क्षेत्रकों से बाहर रह जाते हैं। सामान्यतः उत्पादन के प्रमुख एजेंट शहरी अभिजात होते हैं जो ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाले आर्थिक क्षेत्रकों को गति देने वाले कार्पोरेट संपत्तियों के स्वामी होते हैं। दूसरी ओर, अपवर्जित वर्ग होता है, जो प्राथमिक उत्पादकों और श्रमिकों के रूप में उत्पादन और मार्केटिंग श्रृंखलाओं के सबसे निचले सिरे पर रह जाता है, जहाँ पर उसके पास अपने श्रम को मूल्यसंवर्धित करके बाज़ार अर्थव्यवस्था के अवसरों में हिस्सा पाने के बेहद कम मौके रह जाते हैं।

सूक्ष्म ऋण बाज़ार में डिफॉल्ट की निम्न दरों से अपनी ऋणपात्रता का प्रदर्शन करने के बावजूद पूँजी बाज़ार अपवर्जितों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने में असफल साबित हुए हैं। और औपचारिक पूँजी बाज़ार, अपवर्जितों की बचतों को आकर्षित करने के लिए और तीव्रतर वृद्धि वाले कार्पोरेट क्षेत्र में उनको निवेश परिसंपत्तियों में बदलने के लिए वित्तीय उपकरण उपलब्ध नहीं करा पाया है।

न्यायहीन अधिशासन

यह असमानतापूर्ण और न्यायहीन सामाजिक और आर्थिक संसार न्यायहीन अधिशासन द्वारा और सघन बनाया जा सकता है। अधिशासन के संस्थानों में अपवर्जित लोग अक्सर बे-आवाज़ रह जाते हैं, और यूँ सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा अल्पसेवित भी। लोकतंत्र की संस्थाएँ अपवर्जितों की ज़रूरतों के प्रति प्रतिसादहीन बनी रहती हैं, नीतिगत कार्यसूचियों में भी और चुनावी उमीदवारों के चयन में भी। प्रातिनिधिक संस्थाएँ इस तरह सम्पन्नों और सामाजिक शक्तिवानों के एकाधिकार में चली जाती हैं जो पदों का इस्तेमाल अपने धन को बढ़ाने और सत्ता पर अपनी पकड़ को बनाए रखने में करते हैं।

संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना

इन संरचनात्मक अन्यायों को सुधारने के लिए, अपवर्जितों की बाज़ार अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में अधिक न्यायसंगत शर्तों पर हिस्सा लेने की क्षमता को मज़बूत करके नीति एजेंडों को ज़्यादा समावेशी बनाना ज़रूरी है। ऐसे एजेंडों के माध्यम से अपवर्जितों को उत्पादन, वितरण और अधिशासन की प्रक्रियाओं के भीतर पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया को अपवर्जितों को इतना शिक्षित और समर्थ बनाना चाहिए कि वे अपने जीवन को मात्र श्रमिकों और किराए के किसानों के रूप में न बिता कर, उत्पादक संपत्तियों के स्वामी बन सकें। वितरण प्रक्रिया ऐसी हो जो उन्हें सामूहिक कर्म के माध्यम से अपने श्रम को मूल्य संवर्धित करते हुए अधिक अवसर प्रदान करके अपवर्जितों को बाज़ार में ऊपर उठने में समर्थ बनाते हुए प्राथमिक उत्पादकों के रूप में उनकी आनुवांशिक भूमिका से ऊपर उठने का अवसर दे सके। अपवर्जितों को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति और बाज़ारों तक पहुँच के साथ अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ और शिक्षा तक समतापूर्ण पहुँच पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अधिशासन प्रक्रिया को प्रातिनिधिक संस्थानों में अपवर्जितों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना चाहिए। यह शासन के संस्थानों तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने और निर्णय प्रक्रिया में उनकी आवाज को महत्व देने के लिए बेहद आवश्यक है।

स्रोतः सोभन 2010, निर्धनता के अन्याय को चुनौती

सारणी 1.3

असमानता और चयन की स्वतंत्रता और समुदाय के साथ संतुष्टि

मा.वि.सू. समूह व क्षेत्र	असमानता के कारण मा.वि.सू.मान में होने वाली कुल हानि 2012 (%)	विकल्प चुनने की स्वतंत्रता से संतुष्टि 2007-2011 [a] (% संतुष्टि)	समुदाय से संतुष्टि [b] 2007-2011 [a] (% हाँ में उत्तर)
मा.वि.सू. समूह			
अति उच्च मानव विकास	10.8	81.5	85.9
उच्च मानव विकास	20.6	66.3	76.4
मध्यम मानव विकास	24.2	77.8	79.9
निम्न मानव विकास	33.5	61.8	72.2
क्षेत्र			
अरब देश	25.4	54.6	67.6
पूर्व एशिया एवं प्रशांत	21.3	78.7[c]	80.1[c]
यूरोप एवं मध्य एशिया	12.9	58.5	76.5
लैटिन अमेरिका एवं कैरेबिया	25.7	77.9	79.0
दक्षिण एशिया	29.1	72.9	83.2
सब-सहारा अफ्रीका	35.0	69.1	65.2
विश्व	23.3	73.9	79.0

a.आँकड़े सबसे ताजा उपलब्ध वर्ष के हैं दिए गए कालखंड के अनुसार

b. गैलप सर्वेक्षण के शहर से कुल संतुष्टि के सवाल पर आधारित

c. क्षेत्रीय औसत क्षेत्र के उन सभी देशों के हैं जिनके आँकड़े उपलब्ध हैं। सांख्यिकीय सारणियाँ 7, 8 और 9 एक क्षेत्र के औसत तभी बताती हैं जब कम से कम आधे देशों के, कम से कम दो-तिहाई जनसंख्या को कवर करने वाले आँकड़े उपलब्ध हों।

स्रोतः असमानता के कारण मानव विकास सूचकांक में कुल हानि। एचडीआरओ गणनाएँ असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक पर आधारित, चयन की स्वतंत्रता और समुदाय से संतुष्टि, गैलप (2012) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

वंचित रहते हैं। ज़्यादा समान और न्यायसंगत समाज, जो संतोषजनक और समावेशी मानव विकास के लिए ज़रूरी हैं, ज़्यादा आवाज़ और राजनीतिक सहभागिता और ज़्यादा जवाबदेह सरकार चाहते हैं। (बॉक्स 1.8)।

यहाँ तक कि यूरोपीय संघ में, जहाँ जनसंख्या के एक बड़े हिस्से ने समृद्धि 'को बढ़ते हुए देखा है, कुछ समूह पीछे छूट गए हैं। उदाहरण के लिए *रोमा*, जो एक हज़ार से ज़्यादा वर्षों से यूरोपीय सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। तकरीबन 70 से 90 लाख जनसंख्या के रोमा यूरोप के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यक हैं। ये यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों में रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर यूरोपीय संघ के नागरिक हैं लेकिन लगातार भेदभाव और सामाजिक अपवर्जन के शिकार हैं।

जैसा कि दो क्षेत्रीय *मानव विकास रिपोर्टों* ने उद्घाटित किया है, रोमा सामाजिक अपवर्जन के एक दुष्चक्र में फँसे हुए हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता आ रहा है।[53]

असमानताओं की उपस्थिति सामाजिक मेलजोल को प्रभावित कर सकती है और विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता को भी अवरोधित कर सकती है। व्यक्ति-निष्ठ आँकड़े किसी देश या किसी समुदाय के भीतर सामाजिक एकीकरण की स्थिति के बारे में अच्छी समझ दे सकते हैं (बॉक्स 1.8)।

असमानताओं की उपस्थिति सामाजिक मेलजोल प्रभावित कर सकती है और चयन की स्वतन्त्रता को सीमित कर सकती है। व्यक्तिनिष्ठ आँकड़े एक देश या समुदाय के भीतर सामाजिक एकीकरण की स्थिति में एक अन्तर्दृष्टि दे सकते हैं। प्रमाण सुझाते हैं कि असमानता के कारण होने वाले नुकसान और विकल्प चयन की स्वतंत्रता और समुदाय से संतुष्टि के बीच में एक छोटा नकारात्मक सह-सम्बन्ध है। प्रमाण यह भी सुझाते हैं कि उच्च मा.वि.सू. वाले समाजों में लोग आमतौर पर समुदाय के साथ और अपने लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता के साथ ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। इन सम्बन्धों को समझने का प्रयास देशों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत सीखें दे सकता है (सारणी 1.3)।

मानव सुरक्षा

मानव विकास रिपोर्ट 1994 में कहा गया कि सुरक्षा की परिकल्पना को राज्य की सीमाओं की सैन्य सुरक्षा के सिद्धांत से हट कर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असुरक्षा (या मानव असुरक्षा) को घटाने में बदलना चाहिए।[54] प्रत्येक समाज में मानव सुरक्षा को विभिन्न तरह के खतरे कमज़ोर करते हैं, जिनमें भुखमरी, बीमारी, अपराध, बेरोज़गारी, मानवाधिकार उल्लंघन और पर्यावरणीय चुनौतियाँ शामिल हैं। इन खतरों की तीव्रता विश्व भर में अलग-अलग है लेकिन मानव सुरक्षा अभाव और डर से मुक्ति की एक सार्वभौमिक तलाश बनी हुई है।

ज़रा आर्थिक असुरक्षा पर विचार कीजिए। उत्तर के देशों में लाखों युवा अब काम नहीं ढूँढ पा रहे हैं। और दक्षिण में लाखों किसान एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने लायक नहीं कमा पाते और विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों के साथ, खासकर महिलाओं के लिए, पलायन के लिए बाध्य हो जाते हैं। आजीविका में असुरक्षा का, खाद्य व पोषण में असुरक्षा के साथ नज़दीकी सम्बन्ध है। विकासशील देशों में कई परिवार खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों के कारण रोजाना दो वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ रहते हैं जो बच्चों के पोषण की प्रगति को भी कम कर देती है। कई धनी और ग़रीब देशों में निर्धनता का दूसरा बड़ा कारण किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाओं की असमान उपलब्धता है। परिवार में खराब स्वास्थ्य, ख़ासकर परिवार के मुखिया का, पारिवारिक ग़रीबी के सबसे आम कारणों में से एक है। क्योंकि आय का नुकसान होता है और

मानचित्र 1.1

हत्या दर और मा.वि.सू. मान के बीच एक सूक्ष्म नकारात्मक सम्बन्ध है

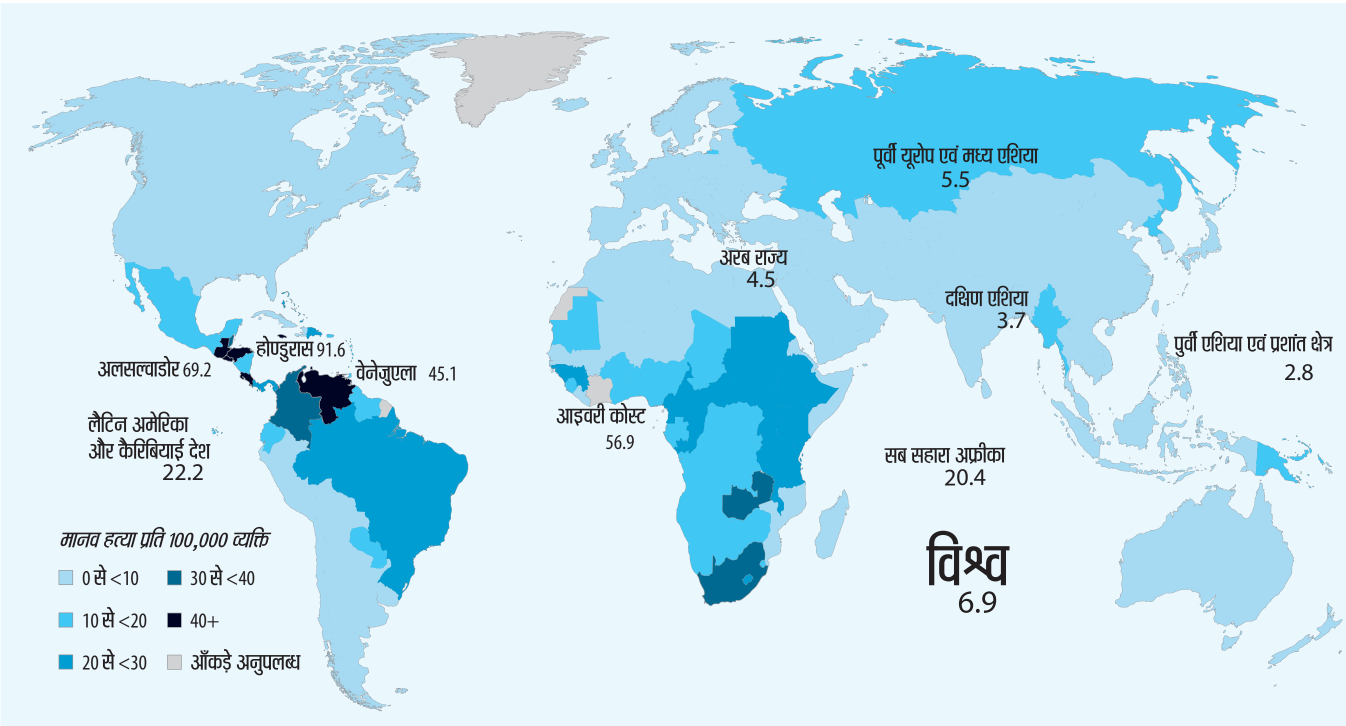

स्रोत: यू.एन.ओ.डी.सी.2012 पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

इलाज के खर्चे उठाने पड़ते हैं।

सुरक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणों को सैन्य मज़बूती पर अनावश्यक बल देने की जगह एक सुविचारित जन-केंद्रित सिद्धांत की ज़रूरत है। अपराध, विशेषकर हत्या, और सैन्य खर्च के आँकड़ों से इस दिशा-परिवर्तन की प्रगति के बारे में संकेत हासिल किए जा सकते हैं।

अपराध

डर से मुक्ति, अपराध दर में कमी, विशेषकर हत्याओं की दरों में कमी, के रूप में दिखनी चाहिए। कुछ अध्ययनों में तो हत्या दर का इस्तेमाल नागरिक संपर्क और विश्वास के मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए *कैरिबियाई मानव विकास रिपोर्ट* 2012 में कहा गया है कि हिंसक अपराध भविष्य के विकास की संभावनाओं को धीरे-धीरे नष्ट कर देते हैं। सुरक्षा लागत के भारी बोझ से सेवाओं और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कमी आती है। निवेश का माहौल भी नष्ट होने लगता है। इसके अलावा अपराध के कारण प्रभावित समुदाय या देश से प्रतिभा का पलायन बढ़ सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में निवेश के लिए उपलब्ध धन में कमी आने लगती है क्योंकि इसका इस्तेमाल अपराध नियंत्रण के लिए होने लगता है। इस तरह विकास रुक जाता है और सामाजिक एकीकरण कमजोर होने लगता है।[56]

189 देशों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में हत्या का वैश्विक औसत प्रति एक लाख लोगों पर 6.9 का था। मोनैको में यह सबसे कम शून्य जबकि होण्डुरास में यह सबसे ज़्यादा 91.6 है (सांख्यिकीय सारणी 9 देखें)। हत्या दर और मा.वि.सू. मान में एक सूक्ष्म नकारात्मक सम्बन्ध है। निम्न मा.वि.सू. वाले देशों में प्रति एक लाख लोगों पर हत्या की दर 14.6, उच्च मा.वि.सू. वाले देशों में 13.0 और अति उच्च मा.वि.सू. देशों में यह आँकड़ा 2.1 है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में हत्या दर सबसे ज़्यादा (प्रति एक लाख लोगों पर 22.2) है। इसके बाद सब-सहारा अफ्रीका (20.4), यूरोप व मध्य एशिया (5.5), अरब देश (4.5), दक्षिण एशिया (3.7) और पूर्वी एशिया व प्रशांत (2.8)

का स्थान है।

शहरों की हत्या दरों पर निगाह डालना उपयोगी हो सकता है। आम धारणा के विपरीत, अपराध आम तौर पर निर्धनतर शहरों में अपेक्षाकृत ज़्यादा नहीं होते। अमर्त्य सेन (2008) लिखते हैं कि कोलकाता 'भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे ग़रीब शहरों में से एक है लेकिन सभी भारतीय शहरों की तुलना में यहाँ हिंसक अपराध सबसे कम है।'[58] यही बात हत्या के मामले में भी सही है। कोलकाता में हत्या के मामलों का औसत प्रति एक लाख लोगों पर 0.3 है, जो कहीं ज़्यादा समृद्ध लंदन (2.4) और न्यूयार्क (5.0) से नीचा है।[59]

सेन का तर्क है कि मोहल्लों के बीच आय या जातीय अलगाव से रहित 'मिश्रित' शहर के रूप में इसके लंबे इतिहास का फायदा कोलकाता को मिला है। कई दशकों से शहर में आधारभूत सार्वजनिक सेवाओं की प्रणाली का प्रचलन रहा है, जिसमें सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और सस्ती सार्वजनिक यातायात प्रणाली शामिल हैं। इन्होंने आर्थिक और सामाजिक अपवर्जन के प्रभावों को कम किया है। शहर में चलने वाली ट्रेनों में ग़रीब फेरीवाले, मजदूर और अच्छी जगहों पर काम करने वाले, सभी साथ-साथ यात्रा करते हैं।

वहीं दूसरी तरफ जब लोगों को ऐसी सेवाएँ नहीं मिल पाती हैं तो अपराध की तरफ उन्मुख होने की उनकी आशंका बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, दोबारा मुजरिम बनने वालों पर ब्रिटेन के एक अध्ययन ने पाया कि बहुत से कैदी सामाजिक अपवर्जन के आजीवन शिकार रहे हैं[60] और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच से लगभग पूरी तरह अपवर्जित रहे हैं।[61]

सभी देशों के पास पूर्ण विसैन्यीकरण के लिए सहायक पूर्व परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन अधिकतर के साथ यह गुंजाइश ज़रूर है कि वे अपने सैन्य खर्च को काफ़ी हद तक धीमा करते जाएँ

रेखांकन 1.8

विकास हमेशा सैन्य खर्च में वृद्धि के साथ नहीं होता

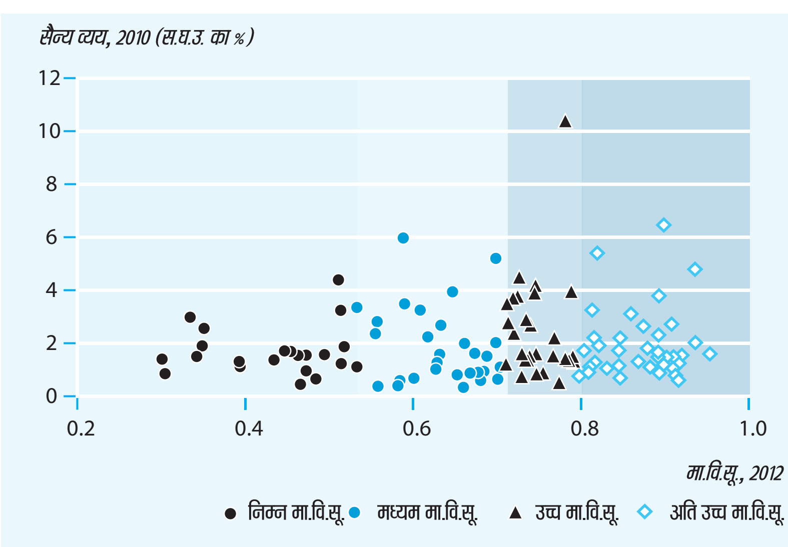

स्रोतः सैन्य खर्च पर आँकड़े, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मा.वि.सू., एचडीआरओ गणनाएं।

सैन्य खर्च

शीत युद्ध के अंत के बाद से स.घ.उ. के अनुपात में सैन्य खर्च मापने पर पता चलता है कि सैन्यीकरण में समग्र तीव्रता नहीं आई है। आंशिक रूप से यह राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों में बदलाव के कारण है। 1990 के दशक के शुरू से, जहाँ अंतर-राज्यीय विवादों में कमी दिखी है, आंतर-राज्यीय विवादों की संख्या में 20वीं सदी के मध्य से तेज़ी आई थी।

आज ज़्यादातर सुरक्षा खतरे दूसरे देशों से नहीं बल्कि उग्रवाद, आतंकवाद और अन्य नागरिक विवादों से है।[62] शीत युद्ध के बाद के काल में 50 लाख से ज़्यादा लोग संघर्षों के शिकार बने हैं, जिनमें 95% नागरिक हैं।[63]

उदाहरण के लिए दक्षिण एशिया में सभी नौ देश पिछले दो दशक से आंतरिक संघर्ष झेल रहे हैं और इसकी वजह से होने वाली मौतें अंतर-देशीय संघर्षों से होने वाली मौतों की तुलना में ज़्यादा हैं।[64] इसके अलावा, 2001 से इन देशों में ज़्यादा संघर्ष दूसरी जगहों की तुलना में निर्धनतर क्षेत्रों में हुए हैं।[65]

104 देशों के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 2010 में सैन्य खर्च 1.4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा या विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% था। ज़्यादातर खर्च अति उच्च मा.वि.सू. वाले देशों द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जैसे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ रही हैं, विशेषकर मध्यम मा.वि.सू. देशों में, उनका सैन्य खर्च भी बढ़ता रहा है। मध्यम मा.वि.सू. देशों में सैन्य खर्च 1990 से लेकर 2010 के बीच तीन गुना हो गया, निम्न मा.वि.सू. देशों में यह वृद्धि 50% के करीब है और अति उच्च मा.वि.सू. देशों में 22%। उच्च मा.वि. सू. देशों में इसमें तकरीबन 47% की गिरावट आई है। फिर भी इन तीनों मा.वि.सू. समूहों में, जहाँ कुल सैन्य खर्च बढ़ा है, यह स.घ.उ. की वृद्धि की तुलना में कम है। इन सकल आँकड़ों के भीतर काफ़ी विभिन्नताएँ छिपी हैं। यूरोप और मध्य एशिया में सैन्य खर्च में 1990 से 2010 के बीच 69% की गिरावट आई जबकि दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया व प्रशांत और अरब देशों में इसमें 43 से 338% की वृद्धि हुई।[66]

हालाँकि विकास के साथ अक्सर सैन्य खर्च में बढ़ोतरी होती है लेकिन यह हर मामले में सही नहीं होता (रेखांकन 1.8)। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में सैन्य खर्च की सबसे अधिक हिस्सेदारी अति उच्च और उच्च मा.वि.सू. देशों में है। लेकिन कुछ अति उच्च मा.वि.सू. देशों में इसका हिस्सा स.घ.उ. के 1% से कम है। इन देशों में शामिल हैं - ऑस्ट्रिया, आइसलैंड, आयरलैंड और लग्जमबर्ग।

दक्षिण के उभरते देशों के लिए इसका विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए, कोस्टा रीका के पास 1948 से कोई सेना नहीं है।[67] यह सेना पर कुछ भी खर्च नहीं करता। इस तरह यह सामाजिक कार्यक्रमों और

सामाजिक निवेशों के लिए ज़्यादा धन मुहैया कराने में सक्षम है।[68] कोस्टा रीका ने 2009 में अपने स.घ.उ. का 6.3% शिक्षा में और 7% स्वास्थ्य में निवेश किया। इस चुनाव ने मा.वि.सू. में उसकी प्रगति को 1980 के 0.621 से बढ़ाकर 2012 में 0.773 कर दिया। आज करीब 20 देशों के पास या तो सेना नहीं है या फिर बहुत छोटी है। उनके पास ज़्यादातर छोटे इलाके होते हैं और बहुत से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी शक्तियों पर निर्भर करते हैं। पूर्ण विसैन्यीकरण के लिए सभी देशों के पास सहायक पूर्व परिस्थितियाँ नहीं हैं। आंतरिक संघर्षों के संदर्भ में विशेषकर भारत ने दिखाया है कि जहाँ अल्पावधि में हिंसा से निपटने के लिए पुलिस का उपयोग ज़्यादा प्रभावी हो सकता है पर पुनर्वितरण और सर्वांगीण विकास मध्यावधि में नागरिक असंतोष से निपटने और बचाव के लिए बेहतर रणनीति है।[69]

* * *

मानव विकास की स्थिति का यह विश्लेषण सकारात्मक और आशाजनक है। लेकिन अभी काफ़ी कुछ करना शेष है। लगभग प्रत्येक देश के समक्ष चुनौतियाँ और प्रगति के अवसर विद्यमान हैं। लेकिन विशेष चिंता का विषय यह है कि कुछ विकसित देशों ने ऋण संकट की प्रतिक्रिया के तौर पर मितव्ययी नीतियों की शुरुआत की है, जो दक्षिण के लोगों के लिए भविष्य के चुनावों और विकल्पों को बंद या कम कर सकती है।

उच्चतर मानव विकास के लिए एकमात्र सुकर (viable) मार्ग है क्षमताओं और अवसरों की वृद्धि में सक्रिय निवेश किया जाए। जैसा कि 1991 की *मानव विकास रिपोर्ट* कहती है, ''जो व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, आत्म विश्वासी और कुशल हैं, वे तेज़ी से बदल रही परिस्थितियों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की तकनीकी और प्रतिस्पर्द्धी माँगों को पूरा करने में अधिक सक्षम होते हैं।''[70]

अगला अध्याय शब्दांकित करता है कि किस हद तक दक्षिण के अनेक देश इस मार्ग का अनुसरण करने में सफल रहे हैं, साथ ही उनके वैश्विक प्रभावों को भी दिखाता है। आगे के अध्यायों में इस पर विचार किया जाएगा कि उन्होंने यह कैसे किया है, और देखेंगे कि दक्षिण के उदय के अंतरराष्ट्रीय अधिशासन तथा वैश्विक शक्ति सम्बन्धों के पुनर्गठन के लिए क्या निहितार्थ हैं।

‘‘जब संगीत बदलता है,
तो नृत्य भी बदल ही जाता है।’’

एक अफ्रीकी कहावत

‘‘मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर दीवारों से घेरा जाय और मेरी खिड़कियाँ बंद कर दी जायें। मैं चाहता हूँ कि सारे भू-भागों की सांस्कृतिक बयार मुक्त रूप से मेरे घर में बहे। लेकिन मैं किसी भी हवा द्वारा पैर उखाड़ दिये जाने से इन्कार करता हूँ।’’

महात्मा गाँधी

2.

अधिक वैश्विक होता दक्षिण

हाल के कुछ वर्षों में दक्षिण के अनेक विकासशील देशों का ऐसी गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में रूपांतरण हुआ है जो आर्थिक संवृद्धि और व्यापार की दिशा में अच्छे प्रदर्शन के साथ मानव विकास में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। आज के अनिश्चितता भरे समय में ये अर्थव्यवस्थाएँ संयुक्त रूप से वैश्विक आर्थिक संवृद्धि को बढ़ा रही हैं, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उठा रही हैं और बड़े पैमाने पर ग़रीबी मिटाने तथा सम्पन्नता बढ़ाने का काम कर रही हैं। इन देशों के सामने अब भी विकट चुनौतियाँ हैं और अब भी वहाँ दुनिया के तमाम ग़रीब लोग रहते हैं।[1] लेकिन इन्होंने यह दिखाया है कि व्यावहारिक नीतियों तथा मानव विकास पर प्रबलता से केन्द्रित होकर तथा भूमंडलीकरण द्वारा उपलब्ध अवसरों के बल पर उनकी अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्निहित अवसरों को बाहर लाया जा सकता है।

दक्षिण का उदय अपनी विविधता के कारण उल्लेखनीय है। विकासशील देशों की इस जमात में शामिल देशों की काफ़ी अलहदा संपदाएँ, सामाजिक ढाँचे, भौगोलिक परिवेश तथा अपना अलग इतिहास है। उदाहरण के लिए अल्जीरिया व अर्जेन्टीना, ब्राज़ील व बांग्लादेश, चीन व चिली, घाना व गयाना, भारत व इण्डोनेशिया, और मलेशिया व मोज़म्बीक। ये देश प्रदर्शित करते हैं कि एक तीव्र जन-केन्द्रित विकास विस्तृत संदर्भों के दायरे में हो सकता है। और उनके अनुभव तथा ज्ञान उन सर्वश्रेष्ठ कार्यों के विस्तारशील स्रोत हैं जो अन्य विकासशील देशों को रफ्तार पकड़ने में सक्षम बना सकती हैं।

इन देशों के बीच तेज़ी से बढ़ता अंतर्सम्बन्ध भूमंडलीकरण को अधिक संतुलित रूप देता है। नए व्यापार पथ फल-फूल रहे हैं। मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैण्ड, तुर्की और वियतनाम जैसे विविध देशों के सौ से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के साथ ठोस आयात-निर्यात सम्बन्ध हैं।[2] स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाई गई नई और बेहतर तकनीकें लोगों की उत्पादकता को बढ़ा रही हैं और उत्पादन को देश के बाहर भेजने में मदद कर रही हैं।

और यह सब इसलिए हो रहा है कि आज दुनिया भर के लोग और महाद्वीप परस्पर उस स्तर पर जुड़े हुए हैं जो पहले अकृपनीय था। 2 बिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं; 1 बिलियन से अधिक लोग हर साल दूसरे देशों की यात्राएँ करते हैं।[3]

यह रूपांतरण क्षेत्रीय और भूमंडलीय सम्बन्धों की गतिकी को प्रभावित कर रहा है। दक्षिण के प्रमुख देशों ने 2008 के वित्तीय संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक सार्वजनिक साधनों—जैसे मौसमी बदलावों को रोकने, स्थिर वित्तीय बाज़ार के लिए नियम बनाने, बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को वित्त उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पादन के उपयुक्त आवंटन को लेकर बातचीत अधिक सघन हुई है। ऐसा लग सकता है कि भागीदारों की बढ़ती संख्या वैश्विक सर्व-सहमति तक पहुँचना और मुश्किल करेगी। लेकिन आज के दौर में जिन वैश्विक मुद्दों पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, दक्षिण का यह उदय उसे तोड़ने और भविष्य में अधिक विकासोन्मुख वैश्विक समझौतों की ओर उन्मुख कर सकता है।

पुनर्सन्तुलन : अधिक वैश्विक विश्व और अधिक वैश्विक दक्षिण

वैश्विक उत्पादन ऐसे पुनर्सन्तुलित हो रहा है जो पिछले 150 सालों से देखा नहीं गया। वस्तुओं, सेवाओं, लोगों तथा विचारों के अंतरराष्ट्रीय परिचालन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सन् 1800 में व्यापार, विश्व निर्गत का 2% था।[4] यह अनुपात द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरंत बाद भी काफ़ी कम था और 1960 तक यह 25% से कम रहा, जबकि 2011 में व्यापार वैश्विक निर्गत का 60% हो गया।[5] यह वृद्धि काफ़ी व्यापक पैमाने पर वितरित है, जिसमें कम से कम 89 विकासशील देश अपना व्यापार और निर्गत का अनुपात पिछले दो दशकों में बढ़ा रहे हैं (बाक्स 2.1)।[6]

आज, कम व्यापार अवरोधों तथा घटे परिवहन खर्चों के कारण विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन अनेक देशों की सीमाओं के बीच विभाजित है और इन देशों में आंशिक रूप से तैयार वस्तुओं का व्यापार होता है।[7] और सूचना प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों ने सेवाओं को और अधिक व्यापार-योग्य बनाया है। इसके परिणामस्वरूप आंतर-औद्योगिक तथा आंतर-कंपनी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

देशों ने, खासतौर पर एशिया के, इन तब्दीलियों का खूब फ़ायदा उठाया है। सन् 1980 और 2010 के बीच उन्होंने विश्व के वाणिज्यिक व्यापार में अपना हिस्सा 25% से 47%[8] तक बढ़ाया और विश्व उत्पादन में उनका हिस्सा 33% से 45% तक बढ़ गया है। आज विकासशील देश विनिर्माण वस्तुओं

बॉक्स 2.1

दक्षिण का वैश्विक-अर्थव्यवस्था से एकीकरण और मानव विकास

1990-2010 के बीच 107 चुने हुए विकासशील देशों में कोई 87% वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकृत माने जा सकते हैं : उन्होंने अपना व्यापार-उत्पादन अनुपात बढ़ाया है, उनकी कई ठोस व्यापारिक साझेदारियाँ हैं।[1] और उन्होंने समतुल्य आय स्तर वाले देशों की तुलना में उच्च व्यापार-उत्पादन अनुपात बनाए रखा है।[2] ये सभी विकासशील देश एक - दूसरे से और विश्व से अधिक जुड़े हुए हैं : इंटनेट का उपयोग बड़े पैमाने पर विस्तारित हुआ है, 2000 से 2010 के बीच उपयोगकर्ताओं की संख्या में माध्य वार्षिक वृद्धि 30% से अधिक रही है।

यद्यपि वैश्विक रूप से एकीकृत सभी विकासशील देशों ने मानव विकास सूचकांकों में तेज़ वृद्धि अर्जित नहीं की है, तथापि इसका विपर्यय (converse) सत्य है। लगभग वे सभी देश (इन चुनिंदा देशों में कम से कम 45) जिन्होंने मानव विकास सूचकांकों में 1990 से 2012 के बीच अपने अन्य समकक्षों की तुलना में सबसे अधिक सफलता हासिल की है, पिछले दो दशकों में विश्व अर्थव्यवस्था से सबसे अधिक एकीकृत हुए हैं। उनके व्यापार-उत्पादन अनुपात में विकासशील देशों के समूह से लगभग 13% अधिक वृद्धि हुई तथा उनका मानव विकास सूचकांकों पर अधिक बेहतर प्रदर्शन रहा है। यह उन पिछले निष्कर्षों के अनुरूप है कि जैसे-जैसे देश विकसित होते हैं वे अधिक खुलते जाते हैं।

मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) में महत्वपूर्ण सुधार के साथ तेज़ी से एकीकृत हो रहे देशों में केवल वे ही बड़े देश शामिल नहीं हैं जो सुर्ख़ियों में छाये रहते हैं, बल्कि इसमें दर्जनों छोटे और कम विकसित देश भी शामिल हैं। इस तरह वे अक्सर सुने जाने वाली शब्दावली ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूसी महासंघ, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका), आई.बी.एस.ए. (IBSA) (भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका), सी.आई.वी.ई.टी.एस. (कोलंबिया, इण्डोनेशिया, वियतनाम, मिस्र, तुर्की और दक्षिण अफ़्रीका) और मिस्ट (मेक्सिको, इण्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया [कोरिया गणराज्य] और तुर्की) जैसे संदर्भित किये जाने वाले समूहों जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक विविध और बड़ा समूह बनाते हैं।

नीचे दिया हुआ चित्र व्यापार-निर्गत अनुपात (जो वैश्विक बाज़ार में भागीदारी की गहनता का सूचक है) के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक के परिवर्तनों[4] को प्रदर्शित करता है। वर्ष 1990 से 2012 के बीच इन विकासशील देशों में से 80 देशों से अधिक ने अपना व्यापार-निर्गत अनुपात बढ़ाया। इस उपसमूह के उन अपवादों में, जिन्होंने अपना मानव विकास सूचकांक भी महत्वपूर्ण रूप से सुधारा है, तीन बड़े देश (इण्डोनेशिया, पाकिस्तान और वेनेज़ुएला) हैं जो विश्व बाज़ार में भूमंडलीय भागीदार माने जाते हैं और कम से कम 80 देशों से आयात-निर्यात करते हैं। दो छोटे देश, जिनका व्यापार-उत्पाद अनुपात घटा (मॉरिशस और पनामा) अब भी उन स्तरों से काफ़ी ऊँचे स्तर पर व्यापार कर रहे हैं जो उनके समतुल्य आय-स्तर वाले अन्य देशों से अपेक्षा की जाती है। ऐसे सभी देश जिन्होंने 1990 से 2012 के बीच मानव विकास सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार किया है और अपना व्यापार-निर्गत अनुपात बढ़ाया है, चित्र के ऊपर दायीं ओर के चतुर्थांश (quadrant) में चिन्हित किये गए हैं। नीचे दाईं ओर के चतुर्थांश में वे देश हैं जिन्होंने अपना व्यापार-निर्गत अनुपात तो बढ़ाया लेकिन मानव विकास सूचकांक में मामूली विकास किया, इनमें केन्या, फ़िलीपीन्स और दक्षिण अफ़्रीका शामिल हैं।

दक्षिण में व्यापार प्रसार और मानव प्रगति

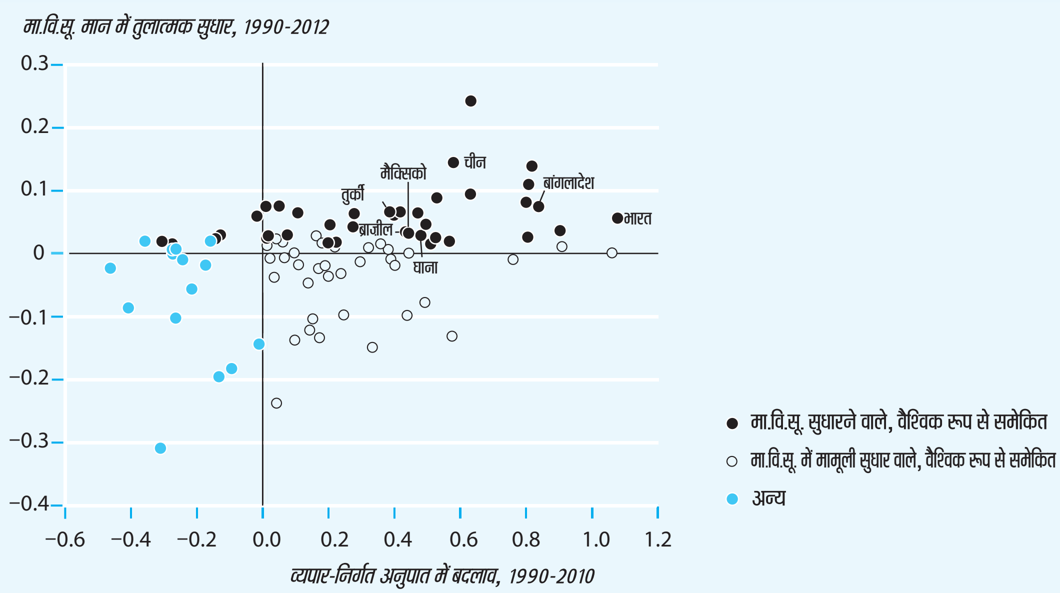

1. द्विपक्षीय व्यापार 2010-2011 में 2 मिलियन डॉलर को पार कर गया।
2. प्रति व्यक्ति आय पर व्यापार-स.घ.उ. अनुपात, जो भू-रुद्धता व जनसंख्या को नियंत्रित करता है, के लिए अंतर्देशीय समाश्रयण के परिणामों पर आधारित।
3. देखें रोड्रिक (2001)।
4. सापेक्षिक मा.वि.सू. की गणना 1990 से 2012 के बीच मा.वि.सू. के मानों के लघुगणकों (log) में परिवर्तन के 1990 के आरंभिक मा.वि.सू. पर समाश्रयण के अवशिष्ट से की जाती है। ऊपर के बाएँ चतुर्थांश में काले रंग से इंगित किए पाँच देश वे हैं जहाँ मा.वि.सू.मान में अहम सुधार हुए हैं, लेकिन उनके यहाँ 1990 से 2010 के बीच व्यापार-उत्पादन अनुपात घटा है, फिर भी उन्होंने या तो वैश्विक स्तर पर कई ठोस व्यापारिक सम्बन्ध बनाए या समतुल्य स्तर के प्रतिव्यक्ति आय वाले देशों से पूर्वानुमान से अधिक व्यापार किया। ऊपर दायें और नीचे दायें चतुर्थांश में खाली गोलों से इंगित किए गए देशों ने 1990 से 2012 के बीच सापेक्षिक मानव विकास सूचकांक मान में ठीक-ठीक काम किया है, लेकिन या तो व्यापार-निर्गत औसत को बढ़ाया है या फिर बड़ी संख्या में ठोस व्यापारिक सम्बन्ध बनाए रखे हैं।

स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ, व्यापार-उत्पादन अनुपात के आँकड़े विश्व बैंक से (2012[a])।

के विश्व उत्पादन के मूल्य-वर्धन (value addition) का एक तिहाई स्वयं निर्मित करते हैं।[9] सन् 1990 और 2010 के बीच जी-20 के आठ विकासशील देशों का वाणिज्यिक निर्यात पंद्रह गुना बढ़कर 200

नक्शा 2.1

थाइलैण्ड का निर्यात विस्तार, 1995-2011

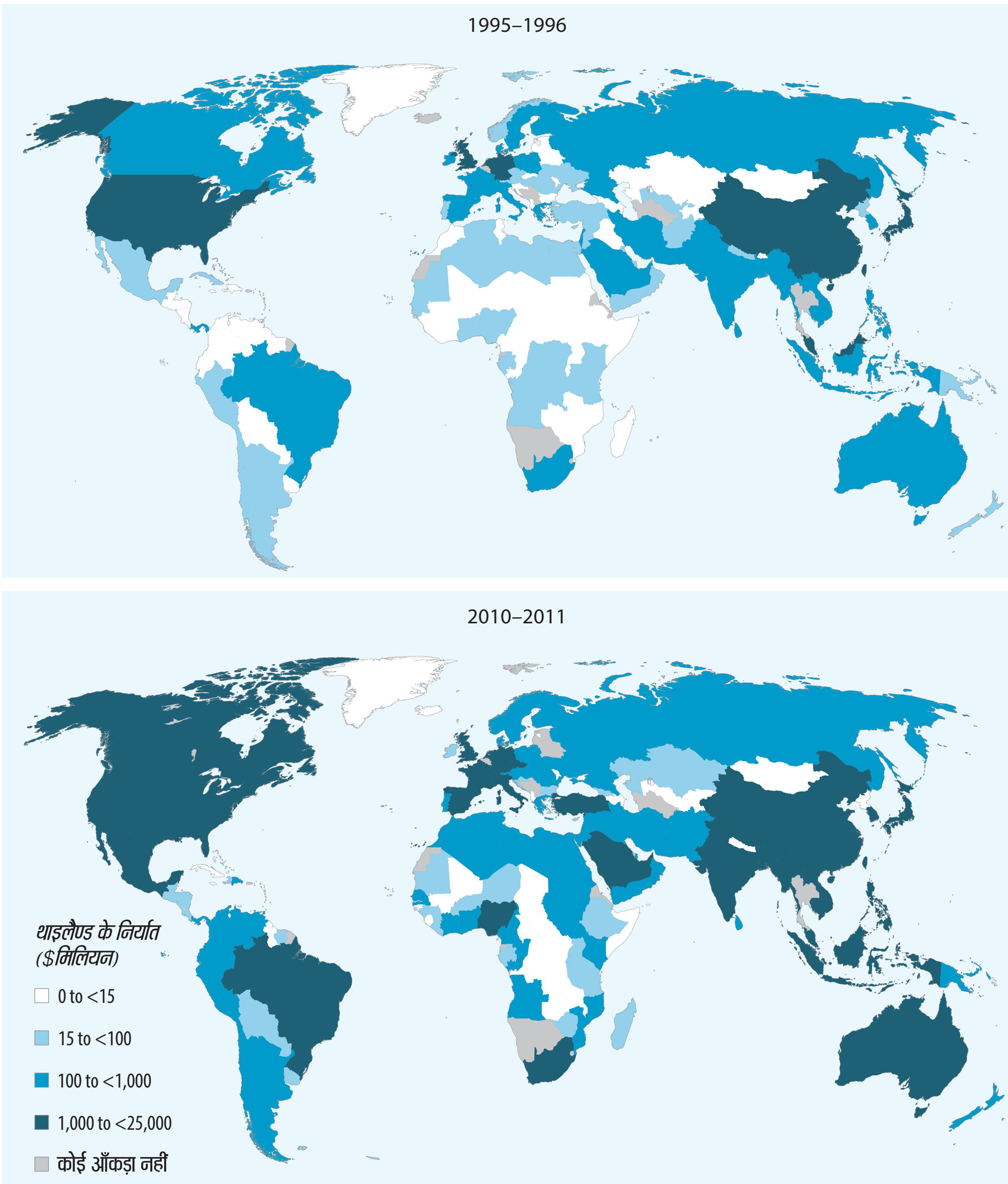

नोट आँकड़े 1995 व 1996 और 2010 व 2011 के औसत मान है।
स्रोत : यू.एन.एस.डी. 2012

बिलियन डालर से 3 ट्रिलियन डालर हो गया है।[10] लेकिन कई अन्य देशों का भी व्यापार बढ़ गया है। सन् 2010 में सब-सहारा अफ्रीकी देशों का प्रति व्यक्ति वाणिज्यिक निर्यात भारत के दो गुने से अधिक था।[11] 1995-1996 में थाइलैण्ड के लगभग 10 व्यापारिक भागीदार थे जिनमें से प्रत्येक को वह 1 बिलियन डॉलर से अधिक की वस्तुएँ निर्यात करता था; केवल 15 वर्षों बाद इसके पास तीन गुना से अधिक भागीदार हैं जो पूरी दुनिया में फैले हैं (नक्शा 2.1)।[12]

वैश्विक पुनर्सन्तुलन विकासशील देशों के अभूतपूर्व पारस्परिक जुड़ाव के साथ ही हुआ है। सन् 1980 और 2011 के बीच विश्व वाणिज्यिक व्यापार के हिस्से के रूप में दक्षिण के देशों का आपसी व्यापार 8.1% से बढ़कर 26.7% हो गया, इसमें वर्ष 2000 के दशक में संवृद्धि खासतौर पर उल्लेखनीय रही (रेखांकन 2.1)। इसी समयांतराल में उत्तर के

रेखांकन 2.1

विश्व वस्तु व्यापार के हिस्से के रूप में दक्षिण-दक्षिण व्यापार 1980-2011 में तिगुने से ज़्यादा हो गया, जबकि उत्तर-उत्तर व्यापार घटा

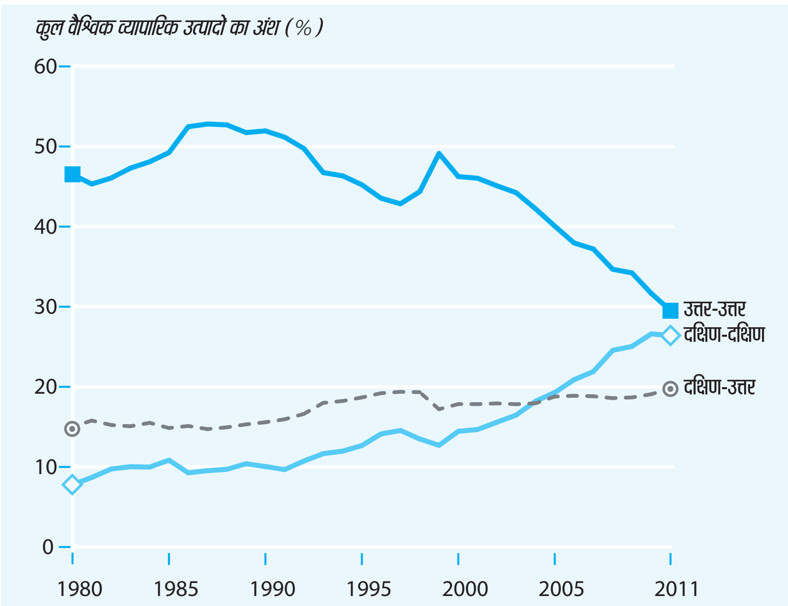

नोट: 1980 में उत्तर के तहत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, और पश्चिमी यूरोप शामिल है।
स्रोत: यू.एन.एस.डी. (2012) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

सारणी 2.1

2000-2001 और 2010-2011 में सबसे कम विकसित देशों का चीन से व्यापार (मिलियन डॉलर में, वर्तमान विनिमय दरों पर)

	चीन से आयात		चीन को निर्यात	
क्षेत्र	2000–2001	2010–2011	2000–2001	2010–2011
कृषि के कच्चे माल	16	105	243	1,965
खाद्य और पेय पदार्थ	164	1,089	378	841
ईंधन, अयस्क और धातु	42	323	3,126	44,244
रसायन	232	2,178	1	93
कपड़ा और चमड़ा	1,323	8,974	14	138
लौह-इस्पात	61	1,642	0	1
अन्य सामग्री आधारित उत्पाद	236	3,132	44	540
औद्योगिक उपकरण	400	4,415	1	1
इलेक्ट्रानिक्स	382	3,806	3	7
वाहन तथा उपकरण	266	6,691	0	1
वस्त्र और जूते	266	2,577	4	129
व्यावसायिक उपकरण और वस्तुएँ	147	2,291	1	34

नोट : चीन द्वारा बताये गए निर्यात मूल्य 2000 एवं 2001 के लिए और 2010 एवं 2011 के लिए औसत गणना और निकटम पूर्ण संख्या पर अधिमानित किया गये ; आयात मूल्यों में लागत, बीमा और मालभाड़ा शामिल है।
स्रोत : यू.एन.एस.डी. (2012) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

देशों के बीच आपसी व्यापार 46% से घटकर 30% से कम रह गया। यह प्रवृत्ति तब भी दिखाई देती है जब प्राकृतिक संसाधनों के आयात और निर्यात को शामिल नहीं किया जाता है।[13] दक्षिणी देशों का आपसी व्यापार हालिया आर्थिक मंदी के दौर में आर्थिक संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक रहा। दक्षिण के देश एक-दूसरे को उत्तर के देशों की अपेक्षा अधिक वाणिज्यिक वस्तुएँ (और औद्योगिक उत्पादन भी) निर्यात कर रहे हैं, और ये निर्यात अधिक कौशल तथा तकनीक सघन हैं।[14]

सब-सहारा अफ्रीका दक्षिणी देशों के बीच व्यापार का महतवपूर्ण स्रोत और गंतव्य बन गया है। सन् 1992 और 2011 के बीच, सब-सहारा देशों से चीन का व्यापार 1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 140 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया, भारतीय कंपनियाँ अफ्रीकी देशों में अधोसंरचना से लेकर होटल व्यवसाय और दूरसंचार क्षेत्र में निवेश कर रही हैं, जबकि ब्राज़ील की कंपनियाँ अंगोला में सबसे अधिक रोज़गार देने वालों में से हैं।[15]

पूँजीगत वस्तुओं तथा सेवाओं में व्यापार

दक्षिण-दक्षिण व्यापार विकासशील देशों को उचित मूल्यों पर पूँजीगत वस्तुएँ उपलब्ध कराता है, जो उनके लिए अधिक अनुकूल होती हैं, बजाय धनी देशों की पूँजीगत वस्तुओं के, जिनके खरीदे, अपनाये जाने और नकल की अधिक संभावना होती है।[16] इससे भारत को भी लाभ हुआ है। सन् 2010 में पूँजीगत वस्तु, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, नाभिकीय रिएक्टर और ब्वायलर चीन से भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा थे (60%) और उनकी कीमत, धनी देशों की तुलना में लगभग 30% कम थी।[17] लेकिन यह भी पूरी तरह से इस आदान-प्रदान की गतिशीलता को प्रतिबिंबित नहीं करता। उदाहरण के लिए, चीन के चौथे सबसे बड़े टर्बाइन उत्पादक, मिन्यांग ने, हाल ही में भारत की कंपनी ग्लोबल विंड पावर का 55% हिस्सा भारत में 2.5 गीगावाट की क्षमता वाली पवनचक्की और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से हासिल करा।[18]

सन् 2010–2011 में, उत्पादन क्षमता तथा आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण लागत (inputs)– वाहन और उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, व्यावसायिक मशीनरी और वस्तुएँ, रसायन तथा लोहा व स्टील– न्यूनतम विकसित देशों के चीन से किये गए आयात का लगभग आधा हिस्सा थे (सारणी 2.1)। आयात के क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग और चमड़े का था। इसमें धागे तथा कपड़े शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल कम विकसित देशों द्वारा उत्तर के देशों के बाज़ारों में निर्यात होने

वाले तैयार वस्त्रों को बनाने में होता है। उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, तैयार कपड़े और जूते कम विकसित देशों द्वारा चीन से किये गए आयात के 20% से भी कम था।

विकासशील देशों ने सेवा क्षेत्र में व्यापार के अवसरों का भी फ़ायदा उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी में नई बढ़त ने विभिन्न कौशल स्तरों पर व्यापार को सुलभ करा है : निम्न कौशल क्षमता के कार्य, जैसे काल सेंटर और डेटा इंट्री के; मध्यम कौशल के काम, जैसे दफ्तरों के लेखा के, प्रोग्रामिंग के, टिकट व बिल बनाने के; और उच्च-कौशल के कार्य जैसे वास्तुकला डिज़ाइन में, डिजिटल एनीमेशन, चिकित्सकीय परीक्षण और साफ्टवेयर डेवलपमेंट। उम्मीद है कि जैसे-जैसे विकासशील देश अपने खुद के बढ़ते हुए उपभोक्ता बाज़ार के लिए सेवाएँ उपलब्ध करायेंगे, सेवाओं के बढ़े आकार का फ़ायदा उठाकर यह प्रवृति और घनीभूत होंगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक कारोबार पर्यटन सम्बन्धी सेवाओं का है, जो वाणिज्यिक सेवाओं के विश्व निर्यात का लगभग 30% है।[19] वर्ष 2010 में पर्यटकों ने लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया; चीन सबसे लोकप्रिय ठिकानों में से था (5.7 करोड़ से अधिक लोग यहाँ आये), मिस्र, मलेशिया, मैक्सिको, थाइलैण्ड और तुर्की के साथ। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुमान से 2020 तक 1.5 बिलियन से अधिक पर्यटकों में से तीन-चौथाई का आगमन उनके भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर ही होगा।

रेखांकन 2.2

दक्षिणी देशों से और उनको किये जाने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 1990 के बाद से तेज़ी से बढ़ा है

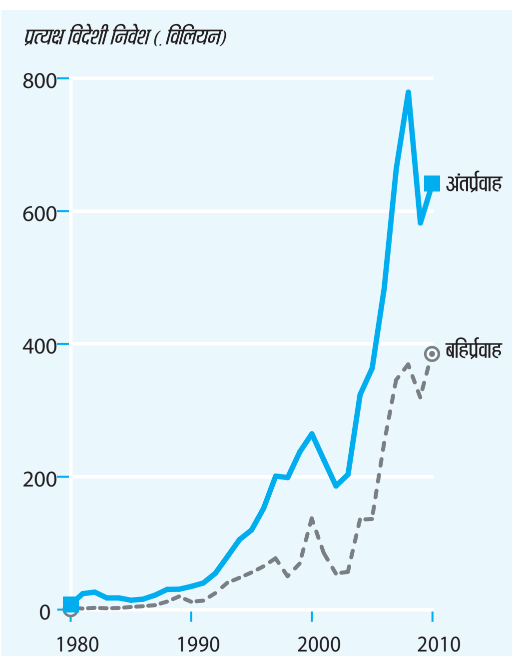

नोट : आँकड़े विकासशील और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा परिभाषित है। आँकड़े वर्तमान विनिमय दरों पर अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करके दिखाए गए हैं।
स्रोत : अंकटाड (2011a) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

कई विकासशील देशों में उत्पादन और व्यापार में बढ़ोतरी उनके यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बड़ी मात्रा में आगमन से ही हुई है : 1980 और 2010 के बीच दक्षिण के देशों ने वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अपनी हिस्सेदारी 20% से बढ़ाकर 50% कर ली।[20] विकासशील देशों से बाहर जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आने से हुई। 1990 के दशक में और 2000 के दशक के मध्य तक दक्षिण के देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगमन और वहाँ से बहिर्गमन की संवृद्धि दर तेज़ी से बढ़ी है (रेखांकन 2.2)। वर्ष 1996–2009 के बीच दक्षिण के देशों से अन्य दक्षिणी देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 20% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ा।[21] कई कम विकसित देशों में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक बड़ा हिस्सा अब दूसरे विकासशील देशों से आ रहा है, खासतौर पर दक्षिण में ठिकाना बनाए तेज़ी से बढ़ रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से।

इन निवेशों में आमतौर पर स्थानीय फर्मों के साथ जुड़ाव कर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल होता है जो श्रम का तथा स्थानीय सामग्री का गहन उपयोग करती हैं। कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो दक्षिणी देशों के बीच आपसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एक गहरे क्षेत्रवादी आयाम को दर्शाते हैं, जिसके तहत अधिकतम निवेश उसी क्षेत्र के देशों के बीच होता है– उसमें भी अक्सर पड़ोसी देशों तथा सामान भाषाएँ बोलने वाले देशों के बीच।[22] दक्षिण का सबसे बड़ा बाहरी निवेशक चीन है, जिसका निवेश स्टाक 1.2 ट्रिलियन डॉलर है।[23]

दुनिया की सबसे बड़ी फार्चून-500 कंपनियों के श्रेणी क्रम में 1990 में दक्षिण की केवल 4% कंपनियाँ थीं; 2011 आते-आते उनकी हिस्सेदारी 22% थी। आज, हर चार बहुराष्ट्रीय निगमों में से एक का मुख्यालय दक्षिण में है। हालाँकि उद्यम छोटे हो सकते हैं, लेकिन वे संख्या में बहुत अधिक हैं : आज जापानी बहुराष्ट्रीय निगमों से कोरियाई बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या अधिक है, और चीनी बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगमों से अधिक है। दक्षिण के उद्यम समान विकास चरण में, विकसित देशों द्वारा लिए गए समय से कम समय में वैश्विक हुए हैं।[24] वे रणनीतिक परिसंपत्तियों, जैसे ब्रांड, तकनीक और

बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य द्वारा व्यापार और निवेश में वृद्धि की एक तीसरी औद्योगिक क्रान्ति के रूप में तुलना की जा सकती है।

बॉक्स 2.2

उत्तरी ब्रांडों का दक्षिण द्वारा अधिग्रहण

वर्ष 2011 में फार्चून 500 की सूची में दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से 61 चीन के, 8 भारतीय और 7 ब्राज़ील के थे। केवल पाँच साल पहले चीन के 16, भारत के 5 और ब्राज़ील के 3 निगम इस सूची में थे। विलय और अधिग्रहण का उपयोग करके बाहर निवेश कर दक्षिण वैश्विक हो रहा है। उत्तर के सम्मानित ब्रांडों का अल्प या मध्य-आय वाले देशों द्वारा अधिग्रहण दक्षिण के उदय की पूर्वसूचना है। वर्ष 2005 में चीन की कंपनी लेनेवो ने आई.बी.एम. का लैपटाप संभाग 1.25 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, और इसकी 50 लाख डॉलर की देनदारी अपने जिम्मे ले ली। इसी तरह 2010 में, झेझियांग गीली ने स्वीडन की कार कंपनी वॉल्वो खरीद ली। अकेले 2011 में ही चीनी फ़र्मों ने उद्धारक होकर दो सौ से अधिक अधिग्रहणों में 42.9 बिलियन डॉलर खर्च किए। सेनी हेवी इंडस्ट्रीज़ कंपनी ने पुट्ज़मस्टर का अधिग्रहण किया, जो जर्मनी की सबसे बड़ी कंक्रीट पम्प बनाने वाली कंपनी है, लियोगांग मशीनरी कंपनी लिमिटेड ने पोलैंड के निर्माण यंत्र बनाने वाली कंपनी हुता स्तालाओ वोला को खरीद लिया तथा शैन्डांग हैवी इंडस्ट्री ग्रुप लिमिटेड ने इटली की *लक्ज़री याच* बनाने वाली कंपनी फेरेट्टी ग्रुप की 75% हिस्सेदारी खरीद ली।

भारत के टाटा समूह ने 2007 में 13.3 बिलियन डॉलर में एग्लो-डच स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया और 2008 में जगुआर लैंड रोवर को 2.6 बिलियन डॉलर में। आदित्य बिड़ला समूह ने 2007 में एक अमेरिकी एलुमिनियम कंपनी नोवेलिस का अधिग्रहण किया और 2011 में कोलम्बियन केमिकल्स का। महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने दीवालिया हो चुकी कोरियाई कार कंपनी सैंग्यांग का अधिग्रहण किया। ब्राज़ील की खाद्य निर्माता कपनियाँ भी सक्रिय रही हैं : 2007 में, जे.बी.एस. फ्रिबोई ने अपने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी स्विफ्ट को अमेरिकी बाज़ार में अपनी पहुँच आसान बनाने के लिए खरीद लिया। वर्ष 2011 में, तुर्की की कंपनियों ने लगभग 3 बिलियन डॉलर के 25 सौदे किए। तुर्की के सबसे प्रसिद्ध अधिग्रहणों में से एक बेल्जियम की चॉकलेट बनाने वाली कंपनी गोडिवा का था जिसे यिडलीज़ होल्डिंग ने 85 लाख डॉलर में ख़रीदा। दक्षिण-पूर्वी एशिया और अरब देशों द्वारा उत्तर की कम जाने जानी वाले ब्रांडों के दर्जनों अधिग्रहण किए गये हैं जो खास चर्चा में नहीं आए। (कई बड़ी खरीदें दक्षिण के देशों के बीच भी हुईं)। वर्ष 2010 में भारत की भारती एयरटेल ने जेन के अफ्रीकी कारोबार का 10.7 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया और चीन ने ब्राज़ील, भारत, रूसी महासंघ और दक्षिण आफ्रीका से 27 सौदों में 9.8 बिलियन डॉलर ख़र्च किए।

दक्षिण-उत्तर के बीच के अधिग्रहणों को अक्सर देशभक्ति के सन्दर्भ में व्याख्यायित किया जाता है। इन सौदों ने कारोबार में अल्प-काल में लाभ निर्माण तथा मूल्य-निर्माण किया है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। हालाँकि, दीर्घ-कालिक दृष्टि से देखें तो रणनीतिक उद्देश्य (संसाधन क्षेत्रक से बाहर) यह प्रतीति देते हैं कि इससे वह उद्यम सम्बन्धी ज्ञान, कौशल तथा प्रतियोगितात्मकता प्राप्त होगी जो कंपनियों की देश के भीतर तथा बाहर प्रसार में मदद करेगी। एक स्थापित, हालाँकि मुश्किल में फँसे उत्तरी ब्रांड को हासिल करना दक्षिणी कंपनियों को परिपक्व बाज़ारों में पैर रखने की जगह देता है। अधिग्रहण करने वाली कंपनियाँ अपनी लागतों को सप्लाई चेन को विविधतापूर्ण तथा भूमंडलीय बनाकर कम कर लेती हैं और तकनीक तथा अन्तर्निहित जानकारियाँ (जैसे जोखिम प्रबंधन या वित्तीय संस्थाओं के सन्दर्भ में साख योग्यता निर्धारण) हासिल कर लेती हैं, जिनसे वे अपनी कार्यक्षमता बढ़ा लेती हैं।

स्रोत : एच.डी.आर.ओ.; चाइना डेली 2012; द इकानामिस्ट 2011ab, डेलायट 2012ab लुएडी 2008।

वितरण तंत्र हासिल करके अपनी प्रतियोगितात्मकता बढ़ा रहे हैं (बाक्स 2.2)।

उत्पादन नेटवर्क

बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य द्वारा व्यापार और निवेश में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय उत्पादन संजालों (networks) के प्रसार से, ख़ासतौर से एशिया से जुडी हुई है। एक तीसरी औद्योगिक क्रान्ति[25] के रूप में ये संजाल उत्पादन की प्रक्रिया को राष्ट्रीय सीमाओं के पार कई चरणों में विभक्त कर देते हैं। परिणामस्वरूप विकासशील देश अपने औद्योगिक ढाँचों को विविधतापूर्ण बनाने में और जटिल उत्पादन प्रक्रिया में हिस्सेदारी करने में सफल हुए हैं। आरंभ में विकासशील देश उत्पादन प्रक्रिया के श्रम-सघन हिस्सों में, विशिष्ट रूप से उत्पादन संयोजन में संलग्न होते हैं और फिर धीरे-धीरे संघटकों के निर्माण और यंत्र निर्माण में। इस बीच कम जटिल उत्पादन कम विकसित पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्स्थापित होता है।

इसके साथ ही ये विनिर्माण संयंत्र घरेलू फ़र्मों के समक्ष कच्चे माल और उत्पादक सेवाओं की माँग पैदा करते हैं। इस तरह, अंतरराष्ट्रीय उत्पादन में हिस्सेदारी के अवसर नए आगंतुकों के समक्ष खुलते हैं, जैसे 1970 के दशक में मलेशिया के लिए, 1980 के दशक में थाइलैण्ड के लिए, 1990 के दशक में चीन के लिए और आज वियतनाम के लिए।

उत्तर ने दक्षिण के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण उत्तर को आर्थिक मंदी से उबरने में मदद कर रहा है (बाक्स 2.3)। अंतरराष्ट्रीय उत्पादन तंत्र प्रमुखतः उत्तर की अंतिम रूप से आई माँग से ही प्रेरित होते रहे हैं। वर्ष 1995 और 2005 के बीच एशिया के भीतर एकीकृत उत्पादन तंत्रों के उभार के परिणामस्वरूप उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात में लगभग 320 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।[26]

व्यक्तिगत नेटवर्क

व्यापार और निवेश में कई अंतरराष्ट्रीय अवसर व्यक्तिगत सम्बन्ध-सूत्रों के आधार पर विकसित होते हैं। अक्सर ये अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों और उनके मूल देश के बीच होता है। वर्ष 2010 में, अनुमानित रूप से विश्व के 3% लोग (21.5 करोड़) प्रथम पीढ़ी के प्रवासी थे,[27] और उनमें से लगभग आधे विकासशील देशों में रह रहे थे।[28] दक्षिण से दक्षिण के देशों के बीच होने वाले प्रवास का लगभग 80% सीमावर्ती देशों के बीच होता है।[29]

बॉक्स 2.3

जोड़ने वाले सम्बन्ध : उत्तर और दक्षिण की पारस्परिक निर्भरता

दक्षिणी देशों के बीच व्यापार का एक बड़ा हिस्सा, खासतौर पर विनिर्माण, अवयव और संघटक, उत्तर की माँग से निर्धारित होता है। यह दक्षिण के देशों को उत्तर के देशों के झटकों के प्रति संवेदी बनाता है। 2008 के भूमंडलीय वित्तीय संकट के बाद दक्षिण-पूर्व एशिया से जापान, योरोपीय यूनियन और अमेरिका को निर्यात 2008 और 2009 के बीच लगभग 20% कम हो गया। इन अर्थव्यवस्थाओं को चीन द्वारा किये जाने वाले निर्यात में कमी भी दो अंकों में थी।

उत्तर भी अपने आप को फिर से पटरी पर लाने के लिए आजकल लगातार दक्षिण पर और निर्भर होता जा रहा है। सन् 2007 के बाद, अमेरिका का निर्यात चीन और लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई देशों को पारम्परिक उत्तरी बाजारों को निर्यात की तुलना में ढाई गुना गति से बढ़ा। कमजोर डॉलर का फ़ायदा उठाकर और दक्षिण में बढ़ती हुई क्रयशक्ति के चलते अमेरिकी निर्यात का विस्तार केवल एयरक्राफ्ट, साफ्टवेयर और हालीवुड की फ़िल्मों जैसे पारम्परिक क्षेत्रों को ही नहीं, बल्कि नई उच्च-मूल्य की सेवाओं जैसे स्थापत्य, इंजीनियरिंग और वित्त को भी शामिल करता है। स्थापत्य के क्षेत्र में शंघाई के आश्चर्यजनक विकास (जिसमें शंघाई टावर्स शामिल है, जो 2015 में देश की सबसे ऊँची इमारत होगी) के पीछे अमेरिकी डिज़ाइनर और ढाँचागत इंजीनियर हैं, जो भारत, चीन और ब्राज़ील को निर्यात की जाने वाली सेवाओं में लगातार बढ़ती हुई फ़ीस और रायल्टी में हिस्सा पा रहे हैं।

इसके अलावा एक बढ़ती हुई 'एप्लिकेशन अर्थव्यवस्था' जिसे एप्पल, फ़ेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों का सहयोग मिलता है, वह 300,000 लोगों को रोज़गार भी देती है, जिनके बनाए उत्पाद पूरी दुनिया में आसानी से निर्यात किए जाते हैं। ऑनलाइन खेल और मोबाइल एप्लिकेशन बनाने वाली एक कंपनी जाईन्गा ने 2011 में 1.1 बिलियन डॉलर की आय की, इसका एक तिहाई हिस्सा अमेरिका से बाहर के देशों से आया। दक्षिण में बढ़ते हुए उपभोक्ता वर्ग का असर न केवल सेवाओं में बल्कि विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। अमेरिकी निर्यात का एक तिहाई अब उन फ़र्मों से हो रहा है जिनमें पाँच सौ से कम लोग नौकरी करते हैं, नई तकनीकों, जैसे त्रि-आयामी प्रकाशन से उनमें से कई उन बाज़ारों पर फिर से कब्ज़ा कर रही हैं जो आयात द्वारा गँवा दिए गए थे। उभरते हुए बाज़ारों ने अमेरिका की एक उपभोक्ता वस्तु उत्पादक की भूमिका को भी पुनर्जीवित किया है (उदाहरण के लिए खाद्यान्न उत्पादक की)। ये बदलती हुई व्यापार प्रवृत्तियाँ बताती हैं कि दक्षिण में आई मंदी उत्तर से होने वाले नए गतिशील निर्यातों के विकास को भी क्षति पहुँचाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर की मंदी ने दक्षिण को नुक्सान पहुँचाया था।

स्रोत : एच.डी.आर.ओ.; द इकानामिस्ट, 2012b

प्रवासी जन विदेशी मुद्रा के एक बहुत बड़े स्रोत होते हैं। वर्ष 2005 में दक्षिण से दक्षिणी देशों को भेजी गई रकम पूरी दुनिया में भेजी गई रकम की 30%–45% अनुमानित की गई।[30] प्रवासी जन बाज़ार अवसरों के बारे में जानकारी के भी एक स्रोत होते हैं। प्रवासी जनों को बढ़े हुए द्विपक्षीय व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी जोड़ा जा सकता है।[31] उदाहरण के लिए, कुछ ख़ास देशों के कर्मचारियों की बड़ी हिस्सेदारी वाले अमेरिकी बहुराष्ट्रीय उद्योगों को उन देशों से संयुक्त उद्यमों के भागीदारों पर निर्भर रहने की ज़रूरत कम होती है, जिनके साथ उनके कर्मचारियों के सांस्कृतिक सम्बन्ध होते हैं।[32]

यह जुड़ाव तब भी और मज़बूत हो सकता है जब प्रवासी अपने मूल देशों को लौटते हैं। उदाहरण के लिए, कैलिफ़ोर्निया की सिलिकान वैली के सूचना तकनीक के कई पेशेवर जब अपने देश को लौटते हैं, तो अपने साथ अपने विचार, पूँजी और संजाल वापस ले कर आते हैं। और, लौटने वाले, नई आधारभूत संरचनाएँ, विश्वविद्यालय, अस्पताल और व्यापार निर्मित कर रहे हैं। लौटने वाले उद्यमी अपने भूतपूर्व सहकर्मियों के साथ संपर्क में रहते हैं, जिससे व्यापार सूचनाओं के विसरण (diffusion) में सहयोग मिलता है। सीमा-पारीय वैज्ञानिक सहयोग भी प्रवासी जन से संपर्क में रहने वाले वैज्ञानिकों को आम हालात से अधिक मिलता है।[33]

सूचना के अन्य प्रवाह, इंटरनेट की व्यापक होती घुसपैठ तथा नए सोशल मीडिया से संभव होते हैं। वर्ष 2000 और 2010 के बीच, लगभग 60 विकासशील देशों में इंटरनेट के उपयोग की औसत वार्षिक वृद्धि असामान्य रूप से अधिक थी (रेखांकन 2.3)।[34] लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइटों, जैसे फ़ेसबुक, का सबसे अधिक उपयोग करने वाले लोगों वाले 10 देशों में से 6 देश दक्षिण के हैं।[35] यद्यपि ये दरें कुछ हद तक वर्ष 2000 में न्यून आधार को प्रदर्शित करती हैं, नए संचार माध्यम के प्रसार और अंगीकरण ने विभिन्न देशों में कई क्षेत्रों को बदल के रख दिया है (बॉक्स 2.4)।

मेज़बान देशों को अपने लोगों की क्षमताओं में निवेश करने की आवश्यकता है ताकि विदेशी पूँजी और विचारों में अंतर्निहित ज्ञान की पहचान हो सके और उसका उपयोग किया जा सके

मानव विकास से प्रोत्साहन

व्यापार, निवेश तथा अंतरराष्ट्रीय उत्पादन में सफल प्रदर्शन मानव विकास के बढ़ते हुए स्तर पर भी निर्भर करता है, जैसा शिक्षा और स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति निर्यात की उच्च आय की उपलब्धियों के बीच के सह-सम्बन्ध द्वारा दिखाया गया है (रेखांकन 2.4)। इस चित्र के ऊपरी दायें चतुर्थांश में दिखाए गए अधिक सफल देशों में महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसरों की भी प्रवृत्ति है। बढ़ा हुआ व्यापार नए कामगारों को, खासतौर से महिलाओं को श्रम बाज़ार में ले आता है और इस तरह उनके विकल्पों का विस्तार करता है। ये नए कामगार हमेशा अच्छी कार्यस्थितियों से लाभान्वित नहीं होते; लागत को कम रखने के प्रयास मज़दूरी दर और कार्य-वातावरण पर दबाव बना सकते हैं। कुछ सरकारें,

रेखांकन 2.3

2000 और 2010 के बीच 60 विकासशील देशों में इंटरनेट उपयोग की वार्षिक वृद्धि 30% से अधिक थी

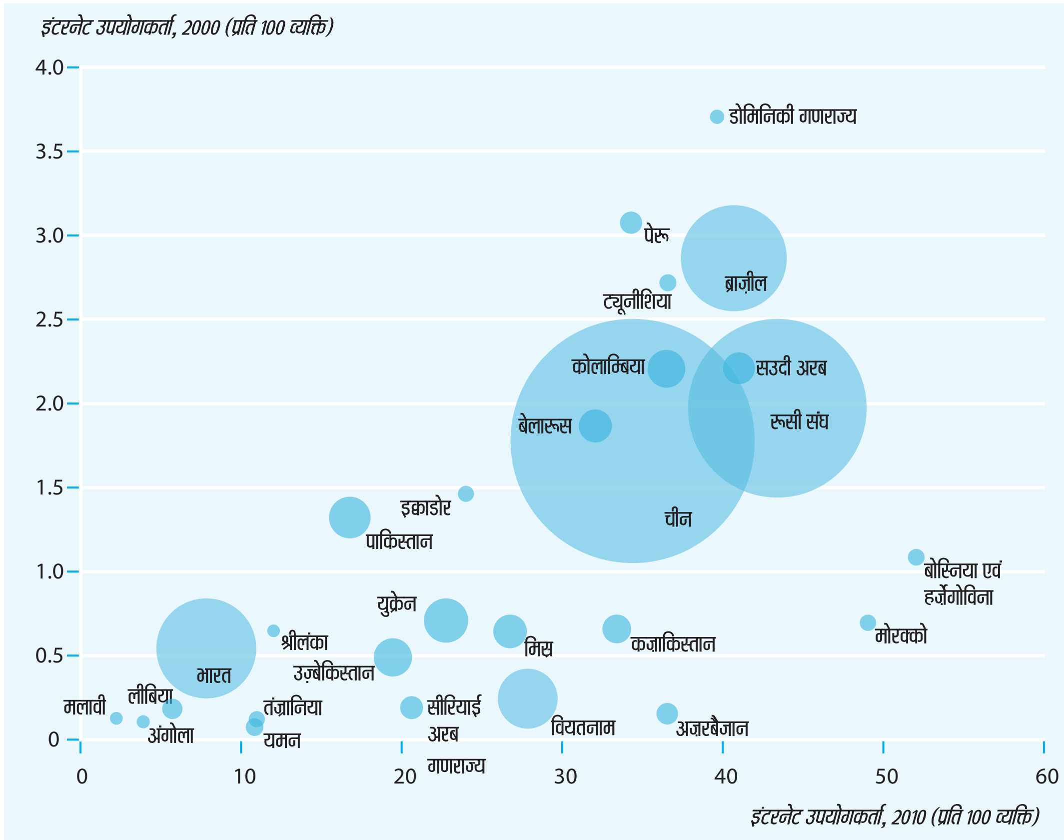

नोटः वृत्तों का आकार 2010 में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओ के समानुपाती है (संदर्भ के लिए, अंगोला में 320,000 और वियतनाम में 66 लाख)। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 75वें पर्सेंटाइल से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले विकासशील देशों को ही दर्शाया गया है।
स्रोतः आई.टी.यू. 2012; विश्व बैंक 2012a

अगर उन्हें यह विश्वास हो कि इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी तथा प्रतियोगात्मकता घटेगी, तो श्रमिक-अधिकारों के विस्तार के प्रति अनिच्छुक हो सकती हैं (बाक्स 2.5)।[36]

लोगों तथा संस्थाओं की क्षमताएँ भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से होने वाले लाभों को प्रभावित करती हैं। मेज़बान देशों को, विदेशी पूँजी और विचारों में अन्तर्निहित उपयोगी ज्ञान को पहचानने, आत्मसात करने और विकसित करने के लिए लोगों की क्षमताओं में निवेश करने की आवश्यकता होती है।[37] वास्तव में, एक शिक्षित तथा स्वस्थ श्रमशक्ति अक्सर विदेशी निवेशकों के इस निर्णय का मूलभूत कारक होती है कि कहाँ निवेश किया जाय। 137 देशों के प्रतिदर्श के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तः प्रवाह और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के बीच यह धनात्मक सह-सम्बन्ध देखा जा सकता है (रेखांकन 2.5)।[38]

मानव विकास वैश्विक वैल्यू चेन में हिस्सेदारी करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है; कम मज़दूरी और निम्न-कौशल वाले श्रमबल का आधिक्य अपने आप में पर्याप्त नहीं है

एक कौशलयुक्त आबादी तथा देश में आने वाले विदेशी निवेश के बीच का सम्बन्ध परस्पर प्रेरणादायी होता है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऐसे देशों में भी आ सकता है, जहाँ मानव विकास में कम उपलब्धियाँ हासिल की गई हों, लेकिन वहाँ प्रचुरता में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हों। उदाहरण के लिए, 2003 और 2009 के बीच जिन संसाधन-संपन्न अफ्रीकी देशों ने अपनी आर्थिक संवृद्धि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की महत्वपूर्ण भागीदारी का अनुभव किया है, वे ग़ैर-आय मा.वि.सू. के सबसे निचले संस्तरों पर हैं।[39] पर, इनका विकास पर असर सीमित होता है, अगर ये निवेश कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहे और शेष अर्थव्यवस्था से इनका जुड़ाव नहीं बना हो। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ बहुत व्यापक रूप में वितरित होने की संभावना नहीं है, अगर लोगों की क्षमताओं में संवहनीय निवेश नहीं होता। इस सन्दर्भ में, तुलनात्मक रूप से

बॉक्स 2.4

मोबाइल फ़ोन और पलापा रिंगः इण्डोनेशिया को जोड़ते हुए

इण्डोनेशिया ने अपने दूर-दराज़ स्थित द्वीपों के समूह को जोड़ने और अपने देश को बाहरी दुनिया के लिए खोलने में दूरसंचार टेक्नोलॉजी का इस तरह से उपयोग किया, जो एक पीढ़ी पहले अकृपनीय था। यह रूपांतरण स्वतः स्फूर्त नहीं था। इसके लिए व्यापक सार्वजनिक तथा निजी निवेश और राज्य संचालित सूचना और संचार निगम (DETIKANS) की भविष्यदर्शी नीति मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी। लगभग एक हज़ार बसे हुए द्वीपों के विशाल द्वीप समूह में फैली विविधतापूर्ण आबादी वाले इण्डोनेशिया ने डिजिटल युग में रूपांतरित होने में कठिन बाधाओं का सामना किया। लैंडलाइन फ़ोन बहुत कम थे जो सिर्फ़ प्रमुख शहरों में आम इण्डोनेशियाई को, वो भी ऊँचे दामों में उपलब्ध थे।

बहरहालए 2010 तक 24 करोड़ लोगों वाले देश में 22 करोड़ मोबाइल फ़ोन रजिस्टर किये जा चुके थे। राज्य द्वारा प्रोत्साहन और बाज़ार की प्रतियोगिता के कारण मोबाइल फ़ोनों तथा फ़ोन सेवाओं की कीमतों में कमी की वज़ह से बालिग़ लोगों में से लगभग 85% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे। इण्डोनेशियाई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। अभी 2008 तक जहाँ केवल 1.3 करोड़ लोगों को नियमित इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी, वहीं 2011 के उद्योग जगत के सर्वे के अनुसार 5.5 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट सुविधा थी। शहरी इण्डोनेशियाई लोगों, ख़ासकर युवाओं की बहुसंख्या के पास, मुख्यतः मोबाइल फ़ोनों के माध्यम से, और देश के 260,000 इंटरनेट कैफे के द्वारा भी, अब इंटरनेट सुविधा है।

डेटिकन्स (DETIKANS) के द्वारा सरकार ने पूरे द्वीप समूह में फ़ाइबर-ऑप्टिक केबल बिछाकर, जिन्हें वह 'पलापा रिंग' कहती है, इंटरनेट उपलब्धता को एक राष्ट्रीय वरीयता बना दिया है। यह दूरस्थ एक हज़ार ग्रामीण-स्कूलों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के अपने लक्ष्य के करीब है और इसने अपनी व्यापारिक सक्रियाओं के लिए ई-बजटिंग तथा ई-प्रोक्योरमेंट व्यवस्था शुरू की है। शायद सबसे आश्चर्यजनक है सोशल मीडिया का अचानक विस्तार। जुलाई 2012 में अकेले ग्रेटर जकार्ता में 74 लाख दर्ज फ़ेसबुक उपयोगकर्ता थे, जो बैंकाक के 87 लाख के बाद दुनिया के किसी एक शहर के लिए सबसे बड़ी संख्या है। कुल मिलाकर इण्डोनेशिया में 4.4 करोड़ फ़ेसबुक उपयोगकर्ता हैं– लगभग भारत के 4.9 करोड़ के बराबर। इण्डोनेशिया एक ऐसा देश बन गया है जहाँ कैबिनेट मंत्री अपने निर्वाचकों को रोज़ ट्वीट भेजते हैं। इसके पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी संख्या के ट्विटर उपयोगकर्ता हैं, और इसके पर्यावरणवादी ऑनलाइन आँकड़े तथा गूगल अर्थ के नक्शों का उपयोग निर्वनीकीकरण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं।

इण्डोनेशियाई विवेचक कहते हैं कि इस डिजिटल क्रान्ति के मानव-विकास के लिए लाभ स्पष्ट हैं, मोबाइल फ़ोन ग्रामीण समुदायों को लोक-स्वास्थ्य, बैंकिंग सेवा तथा कृषि-बाज़ार की सूचनाएँ उपलब्ध करते हैं। वर्ष 2010 से सूचना उपलब्धता के वृहद क़ानून ने ऑनलाइन लोक-सूचनाओं का सतत विस्तार कर लोक-भागीदारी को लाभ पहुँचाया है। अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुँचा है। दिसंबर 2011 में 'डेलायट एक्सेस इकोनॉमिक्स' ने यह गणना की है कि इंटरनेट अर्थव्यवस्था पहले ही इण्डोनेशिया के सकल घरेलू उत्पाद का 1.6% हो चुकी है, जो उसके प्राकृतिक गैस निर्यात से अधिक है और ब्राज़ील (1.5%) तथा रूसी महासंघ (1.6%) के समतुल्य है, हालाँकि यह अब भी चीन (2.6%) और भारत (3.2%)। से पीछे है। डेलायट अगले पाँच सालों में कम से कम इसके सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% हो जाने की भविष्यवाणी करता है, जो इण्डोनेशिया के सकल घरेलू उत्पाद में 2016 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की गई 6%-7% विकास दर की भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी करेगा।

स्रोत : करीमुद्दीन 2011; डेलायट 2011

संसाधन-दरिद्र इथियोपिया और तंज़ानिया ने 2000 और 2010 के बीच ग़ैर-आय मा.वि.सू. में बड़ी वृद्धि हासिल की तथा इसी अवधि में जो औसत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया, वह ध्यान देने योग्य है।

मानव विकास वैश्विक वैल्यू चेन में हिस्सेदारी करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रचलित धारणा के विपरीत कम-मज़दूरी और निम्न-कौशल वाले श्रम बल का आधिक्य अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि कहीं और बने अवययों को जोड़ना भी एक ऐसा जटिल काम हो सकता है जिसमें वैयक्तिक कौशल तथा बड़े स्तर पर संयोजन तथा संगठन के सामजिक सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती हो। लोग इस तरह का कौशल उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और नीतिगत समर्थन से हासिल कर सकते हैं। मूलभूत मानवीय क्षमताएँ भी बेहद महत्वपूर्ण हैं।[40] पूर्वी एशिया में चीन, मलेशिया, फिलीपींस और थाइलैण्ड, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई क्षेत्र में ब्राज़ील, कोस्टारिका और मैक्सिको तथा अरब देशों में मोरक्को और ट्यूनीशिया अवयवों तथा संघटकों में कुछ सबसे अधिक व्यापारिक हिस्सेदारी वाले देश हैं। व्यापक लाभ केवल तभी मिलते हैं जब गतिविधियों को बढ़ाया जाय (बाक्स 2.6)। बहरहाल, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अवयवों तथा संघटकों के व्यापार में किसी एक देश द्वारा किया गया मूल्य-संवर्धन अक्सर छोटा होता है। ऐसे देशों में, जहाँ उत्पादन लगभग पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाओं से जुड़े कुछ क्षेत्रों में ही होता है और जहाँ घरेलू अर्थव्यवस्था से इसका जुड़ाव बहुत सीमित होता है, वहाँ बाकी अर्थव्यवस्था को सीमित लाभ होते हैं।[41]

दूसरे देशों को गति पकड़ने में सहायता

दक्षिण के इस उदय में अब भी सभी विकासशील देश एक जैसे भागीदार नहीं हैं। उदाहरण के लिए 49 कम विकसित देशों में से अधिकतर में परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत धीमी है, खासतौर से उनमें, जो भू-रुद्ध हैं या दुनिया के बाज़ारों से दूर हैं। इसके बावजूद, इनमें से कई देशों ने दक्षिणी देशों से दक्षिण में होने वाले व्यापार, निवेश, वित्त और तकनीकी हस्तांतरण का लाभ लेना शुरू कर दिया है।

1988-2007 के बीच कि प्रवृत्तियों पर हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि चीनी संवृद्धि से छलके लाभ दूसरे विकासशील देशों, खासतौर से करीबी व्यापारिक भागीदारों तक पहुँचे हैं।[42] ये लाभ एक हद तक विकसित देशों से घटती हुई माँग के प्रभाव की क्षतिपूर्ति करते हैं। यदि चीन और भारत में

रेखांकन 2.4

प्रति व्यक्ति निर्यात आय और मानव विकास के बीच में उच्च सह-सम्बन्ध

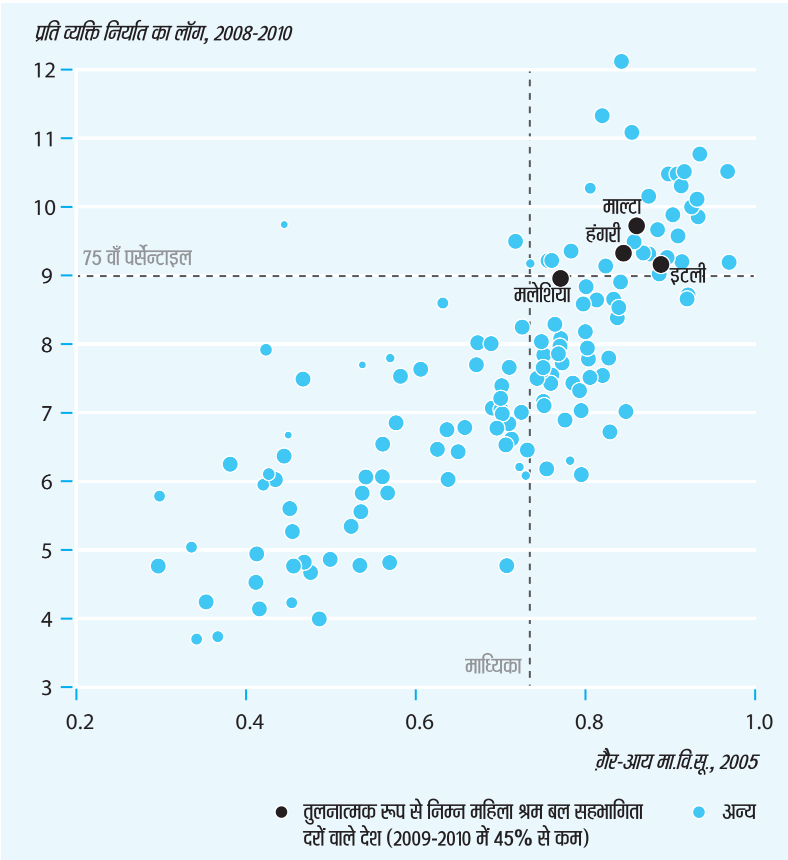

नोट : वृतों का आकार ग़ैर प्राथमिक क्षेत्रक के निर्यात केअंश के समानुपाती है।
स्रोत : एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ और विश्व बैंक (2012a).

संवृद्धि दर में 2007-2010 के दौरान विकसित देशों के जितनी ही कमी आई होती, तो एक अनुमान के मुताबिक निम्न आय वाले देशों में वृद्धि 0.3 से 1.1 प्रतिशत अंक तक कम हुई होती।[43] सिर्फ़ एक स्रोत देश, चीन, से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने कई अफ्रीकी देशों के संवृद्धि दर में महत्वपूर्ण योगदान करा, यहाँ तक कि 2008-2009 में भी जब संवृद्धि के अन्य प्रेरक क्षीण हो रहे थे। 2003 से 2009 के बीच चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संवृद्धि में आकलित योगदान दक्षिण अफ्रीका में 0.04 प्रतिशत बिंदु से लेकर जांबिया में 1.9 प्रतिशत बिंदु तक था। यह योगदान कांगो गणराज्य (1.0 प्रतिशत बिंदु), नाइजीरिया(0.9), मैडागास्कर(0.5), नाइजर(0.5) और सूडान(0.3) में भी ऊँचे स्तर का था।[44]

उदहारण के लिए सब-सहारा अफ्रीकी देशों तथा अन्य जगहों के माल उत्पादकों को पूर्वी तथा दक्षिण एशिया में माल की अचानक तेज़ी का लाभ हुआ है। सस्ते आयात कम आय वाले उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति में भी वृद्धि करते हैं और निर्यातोन्मुखी उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी। हालाँकि, कुछ अफ्रीकी देश उत्खनक उद्योगों की क्षेत्रीय प्रवृत्तियों के कारण, संभव है, नुक्सान उठा रहे हों, जो कि दक्षिणी देशों के आपस के व्यापार से संभाव्य लाभ को कम करती हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को *डच डिज़ीज़* (प्राकृतिक संसाधनों के तीव्र दोहन व निर्यात से बढ़ा राजस्व अतःप्रवाह जो मुद्रा को महँगा व घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को महँगा तथा ग़ैर प्रतियोगी बना जाता है।) के तीव्र जोखिम में डाल सकती है। इसके बावजूद प्राथमिक क्षेत्र मूल्य वर्धन के लिए बड़े बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज बना सकता है, जैसा कि ब्राज़ील, चिली, इण्डोनेशिया, मलेशिया और त्रिनिदाद तथा टोबैगो ने प्रदर्शित किया है। इन संभावनाओं में कृषि-उद्योग, सामरिक आधारभूत संरचनाएँ और साथ ही साथ, सेवाओं के लिए माँग (खाद्य प्रसंस्करण और वितरण, निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव के क्षेत्रकों में) भी शामिल है, सभी रोज़गार, प्रशिक्षण और आय पैदा करते हैं और उद्यमियों को नवाचार तथा निवेश के नए चक्र शुरू करने में समर्थ बना सकते हैं।

कई उत्साहवर्धक चिन्ह साफ़ दिखाई देते हैं। अफ्रीकी देशों के कमोडिटि क्षेत्रक में पूर्वी तथा दक्षिण एशियाई देशों के एकदम हालिया निवेश पहले से कम विदेशी अंतःक्षेत्र लक्षण (enclave characteristics) प्रदर्शित करते हैं। और दक्षिण की कई सरकारें अब अधिक व्यावहारिक हो रही हैं। जहाँ एक ओर वे मज़बूत आर्थिक नीतियाँ अपनाते हुए, संस्थाओं को मज़बूत कर और अधिक खुली हो रही हैं, वहीं सक्रियता से औद्योगिक नीति में भी मशक्कत कर रही हैं और उद्यमिता, शिक्षा, कौशल निर्माण तथा तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन दे रही हैं। जहाँ वे औद्योगिक समूहों तथा आर्थिक क्षेत्रों को समर्थन दे रही हैं और क्षेत्रीय व्यापार तथा निवेश को विस्तारित कर रही हैं, वहीं वे लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तथा ऋण सुलभ कर रही हैं। मज़बूत समष्टि आर्थिक नीतियाँ बड़े विदेशी मुद्रा के आगमन से जुड़े जोखिमों को प्रबंधित करती हैं जबकि स्फूर्त (smart) औद्योगिक नीति घरेलू कड़ियों को मज़बूत बनाती है और बाज़ार गुणकवर्धकों (multipliers) को बढ़ाती है।

कई देश मानव विकास में योगदान देने वाले क्षेत्रों में तकनीकी हस्तांरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी लाभान्वित हुए हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय कंपनियाँ किफ़ायती कीमतों पर दवाएँ, चिकित्सकीय यंत्र और सूचना व संचार तकनीक से जुड़े उत्पाद तथा सेवाएँ अफ्रीका के देशों को भेज रही हैं, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका की कंपनियाँ यही अपने क्षेत्रीय बाज़ारों में कर रही हैं। अफ्रीका में एशियाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने जनोपयोगी तथा दूरसंचार की अधोसंरचना क्षेत्र को भी विस्तारित किया है।

बॉक्स 2.5

प्रतियोगी दुनिया में सम्मानजनक रोज़गार

सम्मानजनक, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों की उपलब्धता, खासतौर पर औरतों को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाली है। फिर भी, आज के प्रतियोगी वैश्विक वातावरण के दबाव में कामगार कम मज़दूरी पाते हुए भी कम समय में अधिक काम करते हैं। मानव विकास और व्यापारिक, दोनों ही दृष्टिकोणों से सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगात्मकता श्रम-उत्पादकता को बढ़ाकर हासिल की जाती है। कम मज़दूरी और लम्बे काम के घंटों से निचोड़ी गई प्रतियोगात्मकता टिकाऊ नहीं होती। श्रम के लचीलेपन का मतलब सम्माननीय कार्य-परिस्थितियों से समझौता करने वाली कार्यवाहियों से नहीं लगाया जाना चाहिए। कम से कम 150 देशों ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की संधियों में संगठन बनाने की आज़ादी और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसे मूलभूत मसलों पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूनतम मज़दूरी, रोज़गार सुरक्षा, काम के घंटों, सामाजिक सुरक्षा और संविदा के रूपों पर श्रम क़ानूनों का उद्देश्य असमानता, असुरक्षा तथा सामाजिक प्रतिद्वंद्विता को घटाना है, वे व्यापार को नैतिक प्रबंधन रणनीति ज़ारी रखने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। यह दृष्टिकोण कि अधिक नियंत्रण हमेशा ही व्यापार के लिए बुरा होता है, अब खारिज कर दिया गया है। विश्व बैंक समूह का व्यापार करने का सूचक, जो श्रमिकों को काम पर रखने के बारे में है, और जो देशों को श्रमिकों को लेने व निकालने में नरमी के आधार पर क्रमांकित करता था, उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि वह ग़लत तरीके से यह संकेत देता था कि अपेक्षाकृत कम नियंत्रण हमेशा ही वरीय होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापारियों तथा बाहरी स्त्रोतों से माल व सेवाएँ लेने वाले अभिकर्ताओं पर यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि उन फ़र्मों में, जहाँ से वे अपना माल व सेवाएँ लेते हैं, वहाँ कार्य स्थितियाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुपालन में हों। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में शुमार एप्पल और इसके संविदाकार फ़ाक्स्कान का हालिया उदाहरण देखिए। फ़ाक्स्कान की फ़ैक्ट्रियों में भयावह श्रम-स्थितियों का भंडाफोड़ करने वाली मीडिया की रिपोर्टों के बाद एप्पल ने निरीक्षण करने वाले समूह, द फ़ेयर लेबर असोसिएशन को जाँच करने के लिए कहा। जब असोसिएशन ने कम तनख्वाह, लम्बे काम के घंटों और खतरनाक कार्य-स्थितियों को उजागर करने वाली अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की तो फ़ाक्स्कान व्यापक सुधार के लिए राज़ी हुआ और उसने तुरत ही चीनी क़ानून के अनुसार औसत साप्ताहिक काम के घंटों को 49 कर दिया। चीन के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के रोज़गार प्रदाता के रूप में फ़ाक्स्कान के पास प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों लोगों की श्रम स्थितियों को सुधारने की ताक़त है। इस मामले में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्तर के एक देश के जनमत (अमेरिकी मीडिया और हिमायती समूहों) ने उसी देश में स्थित एक कॉरपोरेशन पर दबाव बनाया कि वह अपने दक्षिण के देश के एक भागीदार पर उस दक्षिणी देश की श्रम नीतियों को लागू करने के लिए दबाव बनाए। यह परिणाम केवल एक ऐसे युग में संभव है, जहाँ व्यापार, वाणिज्यिक कार्यवाहियाँ और नैतिकता तथा मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता एक वैश्विक मानक में एकजुट हो रही हैं।

स्रोत : एच.डी.आर.ओ.; बर्ग एंड केजेज़ 2007; ड्यूहिग एंड ग्रीनहाउस 2012; हैलर 2013।

बढ़ता हुआ प्रतिस्पर्धात्मक दबाव

इसके बावजूद, बड़े देशों से निर्यात के नुक्सान भी हो सकते हैं। बड़े देश अपेक्षाकृत छोटे देशों में प्रतिस्पर्धात्मक दबाव पैदा करते हैं जो आर्थिक विविधता तथा औद्योगीकरण को बाधित कर सकते हैं। इसके उदहारण जांबिया के विद्युत उद्योग से, केन्या और सेनेगल के वस्त्र उद्योग तथा दक्षिण अफ्रीका के कपड़ा उद्योग तक विस्तृत हैं।[45] अफ्रीका से होने वाला वस्त्र निर्यात 'यू.एस. अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपार्चुनिटी एक्ट' तथा 'यूरोपियन यूनियन एवरीथिंग बट आर्म्स इनीशियटिव' के माध्यम से प्राप्त होने वाली व्यापार-वरीयता और उदार नियमों के बिना महत्वपूर्ण बाज़ारों में अपने व्यापार की हिस्सेदारी बड़ी मुश्किल से ही क़ायम रख सकता है।[46]

यहाँ तक कि बड़े देश भी प्रतिस्पर्धात्मक दबाव के प्रति प्रभावशून्य नहीं हैं। चीनी निर्यात सस्ते उत्पादों के आयात द्वारा तथा परोक्ष रूप से तीसरी दुनिया के बाज़ारों की प्रतियोगिता द्वारा ब्राज़ीली उत्पादन को प्रभावित करता है।[47] एक परोक्ष प्रतिक्रिया के रूप में, सितंबर 2011 में, ब्राज़ील ने विश्व व्यापार संगठन को औपचारिक रूप से आयात में अचानक तेज़ी लाने वाले मुद्रा उतार-चढ़ाव को रोकने वाले व्यापार उपायों की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया।[48] भारत लंबे समय से चीन में अपने आटोमोबाइल के लिए पारस्परिक बाज़ार उपलब्धता की माँग कर रहा है।

रेखांकन 2.5

वर्तमान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पिछले वर्षों के स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धियों से सकारात्मक सह-सम्बन्ध है

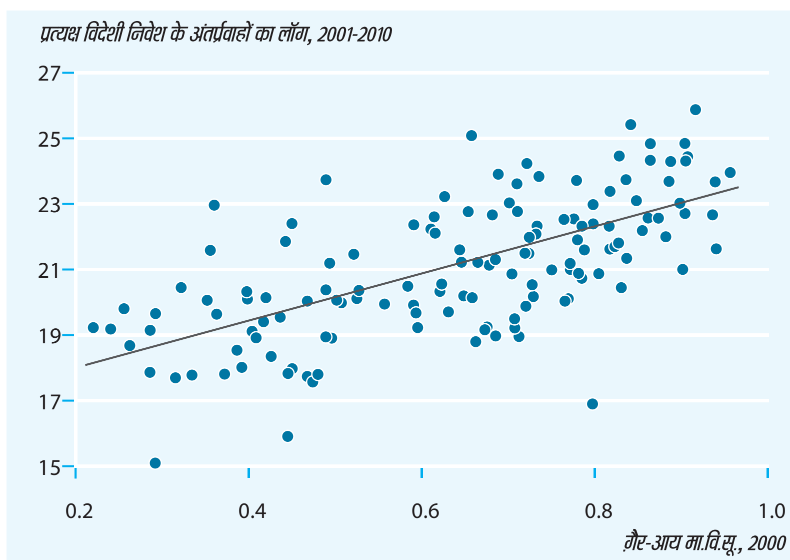

नोट : 2001 से 2010 के वर्षों में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का औसत किया गया मिलियन डॉलर में। नाइजीरिया का ग़ैर आय मानव विकास सूचकांक वर्ष 2005 का है
स्रोत : एच.डी.आर.ओ. की गणनाएँ तथा अंकटाड (2011a)।

अपने भागीदारों में से कुछ पर अपने बढ़ते हुए निर्यातों के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए, चीन

बॉक्स 2.6

अंतिम संयोजन निचले स्तर की मज़दूरी से कहीं अधिक है

दो लोकप्रिय तकनीकी उत्पाद, आई-फ़ोन और आई-पैड, चीन के शेन्जान की एक फ़र्म में संयोजित किए जाते हैं और पूरी दुनिया में सैकड़ों डॉलर में बेचे जाते हैं। चीन में किए गए श्रम का मूल्य, जो 10 डॉलर से कम है, एक आई-पैड की कीमत का 2% से भी कम होता है, जबकि आई-फ़ोन के थोक मूल्य का केवल 3.6% चीनी श्रमिक के हिस्से में जाता है। कीमत का बाकी हिस्सा संघटक तथा अवयव आपूर्ति करने वालों द्वारा अर्जित किया जाता है, जिनके मुख्यालय जर्मनी, जापान, कोरियाई गणराज्य और अमेरिका में हैं। कोरियाई फ़र्म एल.जी. और सैमसंग डिस्प्ले और मेमोरी चिप बनाते हैं, एप्पल अमेरिका में उत्पाद डिजाइन, साफ्टवेयर विकास तथा विपणन गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है और संयोजन करने वाली फ़र्म का मालिक चीन के ताईवान प्रदेश से है।

उत्पाद की कीमत का चीन के श्रमिकों को मिला कम हिस्सा यह धारणा पैदा कर सकता है कि संयोजन के लिए ज़्यादा परिष्कृत होने की आवश्यकता नहीं होती। यह भटकाने वाली बात है। जबकि एशिया ख़ासतौर पर मध्यम-कौशल वाले श्रमिकों के कम मज़दूरी दर के चलते आकर्षक है, टैक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण चुनौती उस वैश्विक पूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन है जिसमें सैकड़ों कंपनियों से संघटक और अवयव प्राप्त करना शामिल है। इसके लिए वैयक्तिक और सामूहिक, दोनों स्तरों पर औद्योगिक कौशल, लचीलेपन, गति तथा कर्मठता का एक दुर्लभ संयोजन चाहिए। उदाहरण के लिए एप्पल के एक एक्जीक्यूटिव ने न्यूयार्क टाइम्स से कहा कि ''अमेरिका ने ऐसे कुशलता वाले लोगों को बनाना बंद कर दिया है, जिनकी हमें ज़रुरत है।''

2007 के मध्य की इस घटना पर ध्यान दीजिए, जब एप्पल ने अपने आई-फ़ोन की स्क्रीन के ग्लास को अफ़रा-तफ़री में फिर से डिजाइन किया। मज़बूत किये गए, खरोंच-मुक्त काँच की पहली खेप फाक्सकान के एक प्लांट में आधी रात को पहुँची और तुरंत काम शुरू हो गया। तीन महीनों के भीतर एप्पल ने दस लाख आई-फ़ोन बेचे। 200,000 असेम्बली लाइन श्रमिकों के निरीक्षण के लिए 8,700 औद्योगिक अभियंताओं को काम पर रखने में 15 दिन लगे। एप्पल का आतंरिक अनुमान था कि इसी काम को अमेरिका में पूरा करने के लिए नौ महीने लगते।

स्रोत एच.आर.डी.ओ.; क्रेमर, लिंडन और देड्रिक 2011; जिंग और डेटर्ट 2010; डयूहिग और ब्रेडशर 2012

अधिमान्य (preferential) ऋण प्रदान कर रहा है और अफ़्रीकों देशों में बने-बनाये वस्त्र तथा कपड़ा निर्माण क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है।[49] चीन ने अपने परिपक्व उद्योगों, जैसे चमड़ा उद्योग को, अफ़्रीका की वैल्यू चेन के करीब जाने के लिए तथा दूरसंचार, दवा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण क्षेत्र के अपने आधुनिक उद्योगों को अफ़्रीका में संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।[50]

इसके अलावा, ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक झटकों ने औद्योगिक पुनरुत्थान किया है। उदाहरण के लिए, इथियोपिया का जूता उद्योग शुरुआत में पूर्वी एशिया के सस्ते आयातों से विस्थापित हो गया था, जिससे बड़े स्तर पर छँटनी हुई और व्यापार बंद हुए, खासतौर पर यह छोटे स्तर के बाज़ारों में हुआ जो पारंपरिक रूप से इथियोपियाई सूक्ष्म उद्यमों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। लेकिन यह उद्योग जल्दी ही उठ खड़ा हुआ, यहाँ तक कि इसने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भी जगह बनाई।[51] एक सर्वे में पाया गया कि 96 में से 78 ऐसे व्यवसायिक संघों ने, जिन्हें 2006 में आयातों से प्रतियोगिता में बहुत नुक्सान होना बताया गया था, अब खुद को समायोजित कर लिया है और कुछ ही वर्षों के भीतर वे प्रतिस्पर्धात्मक हो गए हैं। नाइजीरिया के प्लास्टिक उद्योग में भी ऐसा ही पुनरुत्थान हुआ।[52]

एक और चिंता का विषय यह है कि दक्षिण के अन्य देशों में माँग की वर्तमान प्रवृत्ति के कारण कई अफ़्रीकी अर्थव्यवस्थाओं पर प्राथमिक उत्पादों के क्षेत्र में विशेषता विकसित करने का दबाव बना है। कम विकसित देशों का अनुभव, जिनमें से 33 अफ़्रीका में हैं, इस चिंता की पुष्टि करता है, (देखें सारणी 2.1)। 2011 में कृषि सम्बन्धित कच्चा माल और ईंधन, धातु तथा अयस्क कम विकसित देशों से चीन को होने वाले निर्यात का 96% हिस्से से भी ज़्यादा है। कम विकसित देशों से चीन को निर्यात किए जाने वाला कुल तैयार माल 1 बिलियन डॉलर से भी कम था; जबकि चीन से तैयार माल का आयात 38 बिलियन डॉलर से अधिक था।

हालाँकि, दीर्घकाल में, प्राकृतिक संसाधन से जुड़े उद्योगों से बाहर कृषि और निर्माण के क्षेत्र में तथा साथ ही साथ वित्त तथा दूरसंचार जैसी सेवाओं में निवेशों को बढ़ावा देकर दक्षिणी देशों का आपसी सहयोग इस प्रवृति को बदल सकता है। अफ़्रीका में, सरकारों तथा पारंपरिक सहायता दाताओं के वर्षों की उपेक्षा के बाद, अब आधारभूत संरचना क्षेत्र, एक बार फिर प्राथमिकता बन गई है। नए विकास भागीदारों के अनुभवों तथा समर्थन के आधार पर कुछ देशों ने उपयोगी वस्तुओं की पूर्ति से बल पाकर आधारभूत संरचना के लिए धन जुटाने हेतु विशिष्ट ऋण प्रबंधों का भी सहारा लिया है।[53]

दक्षिणी देशों की आपसी अंतःक्रिया को समझाने के लिए न तो संपूरक और न ही प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण पर्याप्त हैं। ये वर्गीकरण सख्ती से लागू नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज की प्रतिस्पर्धात्मक भूमिका आसानी से कल एक संपूरक भूमिका में बदल सकती है। प्रतियोगिता से सहकार की ओर बढ़ना उन नीतियों पर आधारित लगता है जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाई जाती हैं। सब-सहारा अफ़्रीकी देशों को लेकर निराशावादी घोषणाओं, कि वहाँ औद्योगीकरण की कोई उम्मीद नहीं– इनको

ज़मीनी हक़ीकत ने नकार दिया है, जो परिस्थितियों की विषमता, प्रतिस्पर्धा के बावजूद तरक्की करने की क्षमता दिखाता है। इस सन्दर्भ में डांबिसा मोयो जैसे अफ्रीकी लेखक महाद्वीप के नए कर्ताओं की परस्पर लाभकारी भूमिकाओं के प्रति सकारात्मक हैं।[54]

पारंपरिक बाज़ारों से उभरते बाज़ारों में परिवर्तन देशों को उन तरीकों से भी प्रभावित करता है जिनके बारे में पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। अफ्रीका के इमारती लकड़ी उद्योग को ही लीजिए, जिसने प्रभावी तौर पर यूरोपीय बाज़ारों के लिए काम करने के बाद अब चीन पर नए तरीके से ध्यान देना शुरू किया है।[55] विशुद्ध रूप से मात्रा के लिहाज़ से चीन सबसे महत्वपूर्ण बाज़ार है, जो इस पर व्यापार को केन्द्रित करने के लिए अच्छा है। हालाँकि, चीन अपने निर्यातकों से जिस तरह के तकनीकी मानक अपेक्षित करता है, वह योरोपीय महासंघ द्वारा अपेक्षित मानकों से कम सख्त हैं। इन मानकों में, उत्पाद विनिर्देशों से लेकर एक तीसरे पक्ष द्वारा वन संवहनीयता और फार्मेल्डीहाइड गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के स्वास्थ्य नियमनों के सत्यापन शामिल हैं। अब तक इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि उभरते हुए बाज़ारों की तरफ़ जाने से अपेक्षित तकनीकी मानकों में कोई बढ़ोतरी होती है, जिसके लिए श्रमिकों की कुशलता और क्षमताओं में उन्नयन की आवश्यकता होगी।[56]

दक्षिण में नवाचार तथा उद्यमिता

उत्तरी और दक्षिणी देशों के आपसी व्यापार में, नई औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं ने विकसित देशों के बाज़ारों के लिए जटिल उत्पादों के दक्षतापूर्वक निर्माण हेतु क्षमताएँ विकसित की हैं। लेकिन दक्षिणी देशों की आपसी अंतःक्रिया ने दक्षिण की कंपनियों को ऐसे तरीकों को तथा ऐसे नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करा, जो विकासशील देशों के लिए अधिक उपयुक्त थे। इसमें नए व्यापार आदर्श शामिल हैं, जिनके द्वारा कंपनियों ने अल्प-आय वाले ग्राहकों के लिए, अक्सर कम लाभ के उत्पाद विकसित किए।

दक्षिण के देश स्वाभाविक रूप से मोबाइल की नयी तकनीकों और उत्पादों के संचार मानकों के लिए, जैसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जी.एस.एम.) पर आधारित संचार व्यवस्था के प्रयोगों की स्थली बने। 2005 में जी.एस.एम. इमेजिंग मार्केट इनिशियेटिव के तहत मोबाइल यंत्रों की कीमतें आधे से भी कम की गईं जिससे जी.एस.एम उपभोक्ताओं की संख्या प्रतिवर्ष 100 मिलियन कनेक्शन तक बढ़ी।

इसने आगे निवेश को प्रोत्साहित कियाः 2007 में दक्षिण अफ्रीका के एम. टी. एन. तथा कुवैत के ज़ेन सहित मोबाइल संचालकों ने सब-सहारा अफ्रीकी देशों में मोबाइल की पहुँच बढ़ाने और इसे 90% जनता तक पहुँचाने के लिए वहाँ अतिरिक्त 50 बिलियन के निवेश की पँचवर्षीय योजना की घोषणा की। वास्तव में, अफ्रीका में फ़ोन की कनेक्टिविटी में असाधारण वृद्धि लगभग पूरी तरह से भारत, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात में आधारित कंपनियों द्वारा ही संचालित हुई है।[57]

मोबाइल फ़ोन निर्माताओं ने भी उत्पादों को अल्प-आय उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के लिहाज़ से पुनर्निर्मित किया। उदाहरण के लिए, वर्ष 2004 में, बेंगलूरू स्थित टेक्सास उपकरणों के शोध तथा विकास केंद्र टी.आई. इण्डिया ने कम लागत तथा उच्च-गुणवत्ता वाले मोबाइल फ़ोनों के निर्माण में उपयोग के लिए एक एकल-चिप प्रोटोटाइप डिजाइन किया। 2005 में, टी.आई. के साथ मिलकर नोकिया ने, भारत में बने एकल चिप मोबाइल यंत्र भारत और अफ्रीका में बेचने शुरू किए, और 20 मिलियन से अधिक हैंडसेट बेचे गए। एकल-चिप डिवाइस दूसरे उपकरणों के लिए भी बने, जिनमें किफ़ायती मूल्य वाले डिजिटल डिस्प्ले मानीटर तथा चिकित्सकीय अल्ट्रासाउंड मशीन भी शामिल हैं। इंटेल ने ग्रामीण बैंकिंग के लिए हाथ में पकड़े जा सकने वाला यंत्र बनाया और विप्रो ने मूलभूत इंटरनेट संयोजकता के लिए कम ऊर्जा खर्च करने वाले डेस्कटाप कंप्यूटर बनाए। और 2008 में, टाटा ने अति-अल्प लागत वाली नैनो कार की घोषणा की, जो स्थानीय तकनीशियनों द्वारा संयोजित करे जाने के लिए किट में रखकर भेजी जा सकती है।

दक्षिणी देशों के बीच परस्पर हो रहे निवेश से होने वाले प्रौद्योगिकी विसरण से उद्यमियों का उत्साह, खासतौर पर अफ्रीका में, सामने आ रहा है। लोग अक्सर स्वयं-संगठित हो रहे हैं, ख़रीदार-विक्रेता सम्बन्ध बना रहे हैं और स्वतःस्फूर्त ढंग से उत्पन्न हो रहे बाज़ारों की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्यमी बन रहे हैं। यह एशिया में बने किफ़ायती मोबाइल फ़ोनों के उन उपयोगों से स्पष्ट है जो अफ्रीकी कर रहे हैंः उदाहरण के लिए बैंक अकाउंट खोलने की अपेक्षा सेल्यूलर बैंकिंग सस्ता और आसान है; किसान मौसम के सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर सकते हैं और उत्पाद की कीमत जाँच सकते हैं; और उद्यमी मोबाइल फ़ोन बूथों से व्यापारिक सेवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। नाइजर में मोबाइल फ़ोनों के प्रयोग ने खाद्यान्न बाज़ार का प्रदर्शन सुधारा है, और युगाण्डा के किसान अपने केलों का अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए मोबाइल फ़ोनों का उपयोग कर रहे हैं।

ये और अन्य रूपांतरण उन संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देते हैं, जो लोग तकनीक का प्रयोग करके कर सकते हैंः उन निर्णयों में भागीदारी जो

दक्षिण में अच्छा व्यापार कर रही कंपनियाँ दीर्घकालिक जोखिम लेने वाली प्रतीत होती हैं और स्थानीय खरीदारों के अनुकूल उत्पादों में नवाचार करने में स्फुर्ति दिखाती है।

उनके जीवन को प्रभावित करते हैं; शीघ्र और कम लागत पर ज्ञान को हासिल करना; सस्ती और अक्सर प्रजातिगत दवाओं का उत्पादन करना, बेहतर बीज और नयी फ़सल-किस्मों का उत्पादन; और नए रोज़गार तथा निर्यात अवसरों का निर्माण। ये संभावनाएँ हर आयवर्ग के लिए होती हैं और निचले स्तर पर जनसाधारण तक भी पहुँचती हैं।

औद्योगीकृत देशों के केंद्र के रूप में और परिधि पर अल्पविकसित देशों के होने के बजाए, अब एक अधिक जटिल और गतिशील वातावरण है

मध्य-वर्ग के उपभोक्ताओं की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दक्षिण में अच्छा व्यापार कर रही कंपनियाँ दीर्घकालिक जोखिम लेने वाली प्रतीत होती हैं और स्थानीय खरीदारों के अनुकूल उत्पादों में नवाचार भी कर रही हैं। दक्षिण के उपभोक्ता युवा हैं और अक्सर आधुनिक उपकरणों को पहली बार खरीदने वाले, जिनकी स्टोर के भीतर खरीदारी की विशिष्ट आदत है और जो आमतौर पर ब्रांडिग के प्रति अधिक ग्रहणशील हैं। उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में काम करने वाली कंपनियों को भिन्न प्रबंधन पद्धति के चलते लाभप्रद स्थिति हासिल हैः मेजॉरिटी शेयरधारकों के पास अपेक्षाकृत अधिक शक्ति होती है और वे उत्तर की कंपनियों की अपेक्षा संसाधनों को दूसरे काम में अधिक गति में लगा पाते हैं।[58]

इनमें से कुछ परिवर्धन शोध एवं विकास संस्थानों, व्यापारों और सामुदायिक साझेदारों के आपसी सम्वाद से हुए हैं। इन तरीकों से नवाचार और इसके लाभ तेज़ परिवर्तनों को जन्म देते हुए विस्तारित होते हैं। शोध और विकास को प्रेरित करने में अधिक भूमिका निभाने और निजी, विश्वविद्यालयीन और लोक शोध संस्थानों के सहयोग से उपज रही संगतियों को पोषित करने में राज्य की व्यापक भूमिका की स्वीकोरक्ति बढ़ी है। उदाहरण के लिए, कई अफ्रीकी देशों ने मॉरिशस की पूर्वी एशिया से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में शुरुआती सफलता का अनुकरण करते हुए निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन बनाए। मलेशिया की निवेश प्रोत्साहन नीतियों का भी बड़े पैमाने पर अनुसरण किया गया।

इधर, दक्षिण के देशों के लिए समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण चालक उनके अपने घरेलू बाज़ार हैं।। मध्यवर्ग आकार और आय में बड़ा हो रहा है। 2030 तक, विश्व के मध्यवर्ग के 80% लोग दक्षिणी देशों में होने का अनुमान है। दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया और प्रशांत महासागरीय देशों में ही मध्यवर्ग की जनसंख्या का 60% और कुल उपभोक्ता व्यय का 45% व्यय होगा।[59] एक और अनुमान के अनुसार 2025 तक, 20,000 डॉलर प्रतिवर्ष कमाने वाले 10 लाख परिवारों में से अधिकतर दक्षिण से होंगे।[60]

2008 से, चीनी, भारतीय तथा तुर्की के वस्त्र उद्योगों ने अपना उत्पादन सिकुड़ते हुए भूमंडलीय बाज़ारों से विकसित होते घरेलू बाज़ारों की तरफ़ स्थानांतरित किया है। घरेलू बाज़ारों पर अधिक भरोसा आतंरिक गतिशीलता को बल देगा और अधिक समावेशी संवृद्धि में योगदान करेगा। हालिया प्रवृति को देखते हुए, अफ्रीकी उपभोक्ता किफ़ायती कीमत वाले उत्पादों के बढ़ते हुए आयात से लाभान्वित होते रहेंगे। फलते-फूलते स्थानीय बाज़ारों के स्थानीय उद्यमियों को पैदा करने तथा उत्खनन जैसे उद्योगों, साथ-साथ आधारभूत संरचना, दूरसंचार, वित्त, पर्यटन और निर्माण उद्योगों में अधिक निवेश आकर्षित करने की संभावना है। खासतौर पर हल्के विनिर्माण उद्योगों में, जहाँ अफ्रीकी देशों के पास तुलनात्मक अप्रकट सापेक्ष लाभ (latent comparative advantage) हैं। इस परिदृश्य में, जो पहले से ही पिछले दशक में सक्रिय हो चुका है, घरेलू अर्थव्यवस्थाएँ ढाँचागत परिवर्तनों से गुजरी हैं और घरेलू उद्योगों ने आयातों और देश में आ रहे निवेश के प्रतियोगी दबाव का अपने उत्पादन को बेहतर बनाकर सामना किया है। लेकिन यह प्रक्रिया उन देशों के लिए मुश्किल साबित हो रही है जहाँ तकनीकी क्षमताएँ और अधोसंरचना कम विकसित है।

घरेलू बाज़ारों के इस तरह से विस्तार की राह में बड़े विकासशील देशों के भीतर अस्तित्वमान वंचितताओं वाले इलाकों और पिछड़े हुए क्षेत्रों से अवरोध पैदा होंगे। जैसे, उदाहरण के लिए, बावजूद इसके कि दक्षिण एशिया ने 1.25 डॉलर से कम में प्रतिदिन गुजारा करने वालों की संख्या में (2005 में क्रय शक्ति समानता के सन्दर्भ में) 1981 के 61% को 2008 में घटाकर 36% कर दिया, वहाँ 50 करोड़ से अधिक लोग अब भी अत्यंत ग़रीब हैं।[61]

ये असमानताएँ प्रगति की संवहनीयता को कमज़ोर कर देती हैं क्योंकि वे सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा करते हैं। भारत में, माओवादी विद्रोही देश के भीतर एक बड़े क्षेत्र में सक्रिय हैं; पड़ोस के देश नेपाल में माओवादी 12 वर्षों के भीतर एक साधनहीन जनसेना से उभर कर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरे हैं।

सारणी 2.2

विकास साझेदारियों के विभिन्न मॉडल

पेरिस घोषणापत्र के सिद्धांत	पारंपरिक दाता	विकास के नए सझीदार
स्वामित्व	राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ प्रदाताओं की प्राथमिकता निर्धारित करती हैं	राष्ट्रीय नेतृत्व विशिष्ट परियोजनाओं की ज़रुरत स्पष्ट करते हैं।
सामंजस्य निर्माण	प्राप्तकर्ता पर बोझ को न्यूनतम करने के लिए साझी व्यवस्था	प्राप्तकर्ता पर बोझ न्यूनतम करने के लिए कमतर नौकरशाही प्रावधान
सुपरिणामों के लिए प्रबंधन	प्राप्तकर्ता की अगुआई में प्रदर्शन आकलन की कार्यप्रणालियाँ	सहायता को शीघ्र तथा कम लागत पर उपलब्ध कराने पर जोर
पारस्परिक जवाबदेही	लक्ष्यों तथा सूचकों के माध्यम से अधिक जवाबदेही	संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, नीतिगत शर्तों का त्याग

स्रोत : पार्क (2011) से आहरित

सहकारिता के नए रूप

बहुत से विकासशील देश संपृक्तता और नए रिश्तों के प्रचालक और संवृद्धि ध्रुवों के रूप में उभर कर दक्षिण के अल्प-विकसित देशों के गति पकड़ने और एक अधिक संतुलित विश्व की ओर बढ़ने के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। औद्योगीकृत देशों के केंद्र के रूप में और परिधि पर अल्पविकसित देशों के होने के बजाए, अब एक अधिक जटिल और गतिशील वातावरण है। दक्षिण के देश व्यापार, वित्त और बौद्धिक संपदा के वैश्विक नियमों को फिर से गढ़ रहे हैं और नई व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ तथा भागीदारियाँ स्थापित कर रहे हैं।

विकास सहायता

दक्षिण का उदय द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक विकास सहयोग को प्रभावित कर रहा है। द्विपक्षीय स्तर पर देश, उन भागीदारियों द्वारा नवाचार कर रहे हैं जिसमें निवेश, व्यापार, तकनीक, रियायती वित्त और तकनीकी सहयोग शामिल है। क्षेत्रीय स्तर पर, व्यापार और मौद्रिक व्यवस्थाएँ सभी विकासशील क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में फूल-फल रही हैं और क्षेत्रीय सार्वजनिक साधन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। भूमंडलीय स्तर पर विकासशील देश बहुपक्षीय मंचों, जी-20, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं और अन्य, में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं और भूमंडलीय नियमों तथा कार्यप्रणालियों को आगे बढ़ा रहे हैं।

विकासशील देश बढ़ती हुई संख्या में द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विकास कोषों में सहायता प्रदान कर रहे हैं। अक्सर, इसमें पारंपरिक विकास सहयोग के साथ व्यापार, ऋण, तकनीक साझाकरण और प्रत्यक्ष निवेश घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं जो आर्थिक संवृद्धि को एक हद तक आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ावा देते हैं। दक्षिण के देश पारंपरिक दाताओं की तुलना में छोटे स्तर पर आर्थिक अनुदान देते हैं लेकिन दूसरे प्रकार की सहायता भी देते हैं, अक्सर ये अनुदान आर्थिक नीतियों या अधिशासन नज़रियों के बारे में दृष्टिकोण-सम्बन्धी स्पष्ट कड़ी शर्तों के बिना होते हैं।[62] परियोजना आधारित ऋणों में, संभव है कि हर बार वे बहुत पारदर्शी न हों, लेकिन वे प्राप्तकर्ता देशों द्वारा चिन्हित आवश्यकताओं को अधिक वरीयता देते हैं और इस तरह उच्च स्तर के राष्ट्रीय स्वामित्व को सुनिश्चित करते हैं।

ब्राज़ील, चीन और भारत विकास सहयोग के महत्वपूर्ण प्रदानकर्ता हैं जो सब-सहारा अफ्रीकी देशों में काफ़ी महत्वपूर्ण है।[63] ब्राज़ील ने अपने सफल विद्यालय सहायता कार्यक्रम तथा निरक्षरता से संघर्ष के लिए अपने कार्यक्रम को अमेरिकी भागीदारों के यहाँ प्रतिरोपित किया है। 2011 में, इसने 22 अफ्रीकी देशों से 53 द्विपक्षीय स्वास्थ्य समझौते किए थे।[64] चीन ने ठोस अधोसंरचना के लिए वित्त तथा तकनीकी सहायता से अपने निवेश प्रवाह और व्यापार समझौतों को संपूरित किया है ।

जुलाई 2012 में चीन ने अगले तीन वर्षों में अपने रियायती ऋणों को दोगुना करके 20 बिलियन तक पहुँचाने का निश्चय किया है।[65] भारत के आयात-निर्यात बैंक ने सब-सहारा अफ्रीका देशों को 2.9 बिलियन डॉलर ऋण के रूप में दिया है और अतिरिक्त 5 बिलियन डॉलर को अगले पाँच वर्षों में देने का निश्चय किया है।[66] 2001 से 2008 तक, दक्षिण के देशों और संस्थाओं ने सब-सहारा अफ्रीकी देशों की आधिकारिक अधोसंरचना के 47% का वित्तपोषण किया।[67]

दक्षिण से नए विकास सहयोगी, द्विपक्षीय सहयोग के अपने खुद के मॉडल पर काम करते हैं (बाक्स 2.7)। उनके वित्तीय सहयोग का स्तर और सहयोग-शर्तों को लेकर उनके दृष्टिकोण मिलकर अल्प-विकसित देशों में नीतिगत स्वायत्तता को बढ़ा सकते हैं।[68] अल्प-विकसित देश अब विकास सहयोग के लिए अधिक उभरते हुए साझीदारों की ओर देख सकते हैं।[69] चूँकि विदेशी ताकतें प्रभाव, स्थानीय उपभोक्ताओं तक पहुँच और लाभकारी निवेश शर्तों के लिए होड़ में हैं, यह उनके विकल्पों को विस्तारित करता है।

क्षेत्रीय विकास सहयोग संरचना क्षेत्रीय विकास बैंकों द्वारा भी विकसित हो रही है: अफ्रीकी विकास

बॉक्स 2.7

जाम्बिया में ब्राज़ील, चीन और भारत के कार्य

विकास के नए भागीदारों द्वारा अपनाए जा रहे द्विपक्षीय भागीदारी के माडल तेज़ी से बदल रहे हैं। अभी हाल तक जाम्बिया के कुल विकास-वित्त में इन नए भागीदारों का योगदान थोड़ा सा था। 2006 से 2009 के बीच जाम्बिया द्वारा प्राप्त किए गए कुल 3 बिलियन डॉलर के अनुदान और ऋणों में ब्राज़ील, चीन और भारत द्वारा दिया गया धन 3% से कम था।

नवबर 2009 में, चीन और जाम्बिया ने घोषणा की थी कि चीन जाम्बिया को 1 बिलियन डॉलर का रियायती ऋण छोटे तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए किस्तों में देगा। यह जाम्बिया के कुल विदेशी ऋण के 40% के बराबर था। 2010 में चीन के आयात-निर्यात बैंक ने 57.8 मिलियन डॉलर का ऋण नौ चालित अस्पताल खरीदने के लिए दिया। वर्ष 2010 में भारत ने भी 75 मिलियन डॉलर के ऋण और उसके बाद फिर 50 मिलियन डॉलर के ऋण (line of credit) की घोषणा एक जल-विद्युत परियोजना के वित्तपोषण के लिए की। ब्राज़ील ने जाम्बिया के उत्तर-पश्चिमी राज्य में भारतीय कंपनी द्वारा प्रबंधित कोन्कोला ताँबे की खदानों के खनन यंत्रों में भारी निवेश किया है। लगभग 400 मिलियन डॉलर के आरम्भिक निवेश के साथ ब्राज़ील की बड़ी खनन कंपनी वेल (Vale) दक्षिण अफ्रीकी कंपनी रेनबो के साथ जाम्बिया में ताँबे की तलाश और उत्खनन के लिए संयुक्त उपक्रम में हैं। ब्राज़ील और जाम्बिया ने पशुधन तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में तकनीकी सहायता के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्रोत : एच.डी.आर.ओ.; क्रेगलुण्ड 2013

परिवहन और आवाजाही प्रणालियों को युक्तिसंगत बनाने जैसे व्यावहारिक कदमों से क्षेत्रीय एकीकरण को और मजबूत बनाया जा सकता है।

रेखांकन 2.6

उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं ने 1995 के बाद भारी विदेशी मुद्रा एकत्र की है

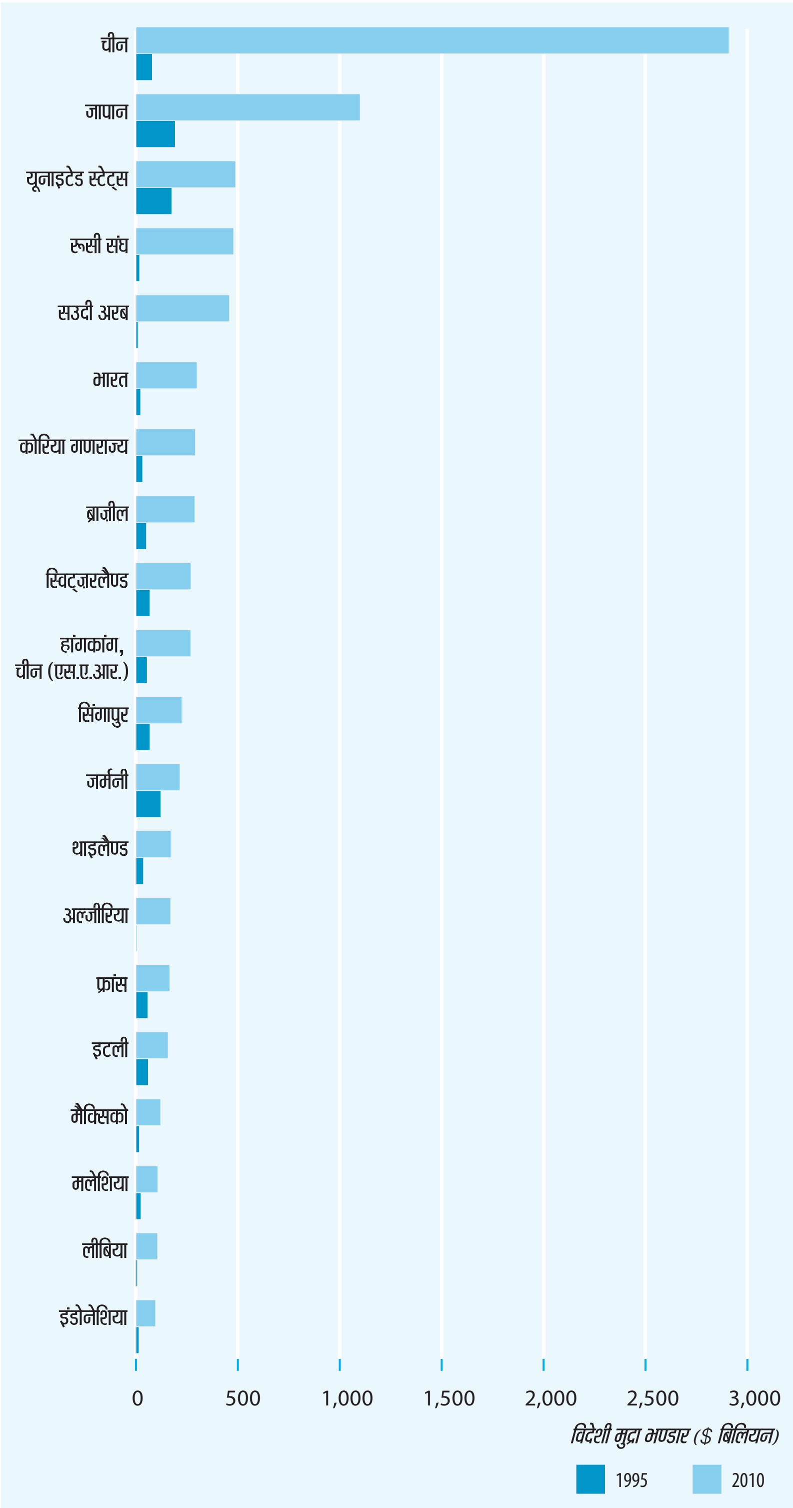

नोट : स्वर्ण रिज़र्व शामिल है
स्रोत : विश्व बैंक 2012a

बैंक (AFDB), एशियाई विकास बैंक (ADB) और अंतर-अमेरिकी विकास बैंक। 2009 में, एक प्रति-चक्रीय (countercyclical) भूमिका निभाते हुए क्षेत्रीय विकास बैंकों ने मिलकर सभी बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अनुदान का 18.4%(3.4 बिलियन डॉलर) उपलब्ध कराया जो 2005 की तुलना में 42% की वृद्धि है। अरब देशों से विकास सहायता ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया है और यह 2008 में 6 बिलियन डॉलर तक हो गई है।[70] 2001 और 2008 के बीच सब-सहारा अफ्रीका में अधोसंरचना के कुछ सबसे बड़े वित्तपोषकों में अरब राज्यों में स्थित क्षेत्रीय बैंक और निधियाँ थीं।[71] यदि अमीर देशों के नीति-निर्माताओं ने घरेलू आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण अपनी अनुदान प्रतिबद्धताओं में कटौती की, तो आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय विकास बैंकों से मिलने वाला विकास सहयोग अल्प-विकसित देशों के लिए और महत्वपूर्ण बन सकता है (दक्षिण-दक्षिण विकास सहयोग भी)।[72]

दक्षिण के विकास भागीदारों ने बहुपक्षीय विकास सहायता के नियमों से खुद को बाँधने या उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की है। लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से पारंपरिक दाताओं पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बनाया है और उन्हें विकासशील देशों की आवश्यकताओं और चिंताओं पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया है। कई पारंपरिक दाताओं के सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान के विपरीत नए भागीदारों ने सभी अल्प-आय वाले देशों में हालिया वर्षों में नई अधोसंरचनाओं में भारी मात्रा में निवेश किया है, जिसके परिणामस्वरूप, उदाहरण के लिए, विद्युत आपूर्ति में 35% का सुधार हुआ है, रेल क्षमताओं में 10% की वृद्धि हुई है और दूरसंचार सेवाओं की कीमतों में कमी आई है।[73]

व्यापार तथा वित्तीय समझौते

अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका ने व्यापार समझौतों में– द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय और क्षेत्रीय– प्रसार देखा है। दक्षिण एशिया में, इन क्षेत्रीय समझौतों ने राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़ दिया है। पूर्वी अफ्रीका में, बेहतर क्षेत्रीय समेकन ने अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक झटकों से बचाया है।[74] परिवहन, मालवाहन और आवाजाही प्रणालियों को युक्तिसंगत बनाकर और राष्ट्रीय नियामक योजनाओं को सुसंगत बनाकर क्षेत्रीय एकीकरण को और मज़बूत बनाया जा सकता है। दक्षिणी देशों के बीच अंतिम उत्पादों के व्यापार में प्रशुल्कों को कम किए जाने की भी गुंजाइश है, जो उत्तर-दक्षिण के व्यापार में लगने वाले प्रशुल्क से ज़्यादा है।[75]

1997 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद, दक्षिण के कई देशों ने नई मौद्रिक व्यवस्थाएँ विकसित

कीं, जो वित्तीय स्थापत्य को रूपांतरित कर रही हैं और उन देशों के लिए देश के भीतर निर्मित नीतियों के लिए जगह बना रही हैं। नए ऋण समझौते विचारधारा और शर्तों से ज़्यादा व्यावहारिकता पर बल देते हैं।

साथ में, उभरते हुए दक्षिण के विशाल वित्तीय आरक्षित भण्डारों से भूमंडलीय वित्तीय स्थापत्य का रूप भी गढ़ा जा रहा है। तमाम देशों ने, केवल ब्राज़ील, चीन और भारत ही नहीं, बल्कि इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, थाइलैण्ड और अन्य ने भी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा आरक्षित भण्डार भविष्य के वित्तीय मंदी और संकटों के प्रति आत्म-सुरक्षा के लिए एकत्र किए हुए हैं (रेखांकन 2.6)। 2000 और 2011 के तीसरे चतुर्थांश के बीच, वैश्विक विदेशी मुद्रा आरक्षित भण्डार 1.9 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 10.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जिसमें प्रभावी हिस्सेदारी उभरते हुए और विकासशील देशों की है। इनका कुल भण्डार 6.8 ट्रिलियन डॉलर है।[76] इनमें से कुछ देशों ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद संवृद्धि को गति देने के लिए इन आरक्षित भण्डारों का उपयोग किया। एक उल्टी हुई भूमिका में, अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इन कोषों की यूरोप के वित्तीय संकट में मदद के लिए माँग कर रहा है।

ऐसे बड़े मुद्रा भण्डारों वाले देश उनका एक हिस्सा आमतौर पर संप्रभु संपदा कोषों में अंतरित कर देते हैं। संप्रभु संपदा कोष संस्थान के आँकड़ों के अनुसार 2010 के अंत में इन कोषों में अनुमानित 4.3 ट्रिलियन डॉलर परिसंपत्तियाँ थीं, जिसमें 3.5 ट्रिलियन डॉलर विकासशील तथा उभरते हुए देशों के पास था और 800 बिलियन डॉलर अकेले पूर्वी एशिया में था।[77] मार्च 2011 में विकासशील और उभरते हुए देशों के पास 41 संप्रभु संपदा कोष थे, जिसमें से 10 के पास 100 से लेकर 627 बिलियन डॉलर की परिसंपत्ति थीं।

बड़े विदेशी मुद्रा भण्डार और संप्रभु संपदा कोष वित्तीय झटकों के ख़िलाफ़ सबसे कुशल सुरक्षा नहीं हैं। विदेशी मुद्रा के इस अभूतपूर्व संग्रहण की संग्रहणकर्ता देश तथा अन्य विकासशील देशों के लिए अवसर-लागतें हैं।[78] इन संसाधनों का उपयोग अधिक उत्पादक तरीकों से लोक-साधन उपलब्ध कराने में, उत्पादक क्षमता तथा आर्थिक एवं मानव विकास बढ़ाने वाली परियोजनाओं हेतु पूँजी उपलब्ध कराने में तथा क्षेत्रीय संस्थाओं के संसाधन कोषों को बढ़ाकर क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय वित्तीय स्थिरता बढ़ाने में किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, दक्षिण का उदय वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में संसाधन एकत्रण के नए तरीके विकसित कर रहा है और दक्षिण में एक सघनतर, बहुस्तरीय तथा अधिक विविधतापूर्ण वित्तीय स्थापत्य (architecture) बना रहा है। ये व्यवस्थाएँ कई बार ब्रेटन वुड्स संस्थाओं को प्रतिस्थापित करती हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में, उभरती संस्थाएँ और व्यवस्थाएँ वैश्विक वित्तीय स्थापत्य के पूरक के रूप में काम करती हैं। दक्षिण के बदलते हुए वित्तीय परिवेश में वित्तीय स्थिरता तथा लचीलेपन को बढ़ाने, दीर्घकालिक उत्पादक क्षमताओं के विकास को अवलंब देने, मानव विकास से सुसंगत लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय नीति वृत्त को फैलाने की क्षमता है। यही नहीं, उभरती हुई अर्थव्यस्थाओं में ब्रेटन वुड्स संस्थाओं पर अपने प्रतिनिधित्व, अधिशासन के सिद्धांतों और शर्तों के उपयोग के प्रति अपनी चिंताओं का जवाब देने के लिए दबाव बनाने के रूप में एक रूपान्तरकारी प्रभाव भी है।

जी-20 ने वित्तीय स्थिरता और वित्तीय अधिशासन बोर्ड जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानक तय करने वाली संस्थाओं में ज़्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह, सभी जी-20 देश अन्य कामों के अलावा अब बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बनी बेसेल कमिटी और सिक्योरिटी कमीशनों के अंतरराष्ट्रीय संगठन में प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण का अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी प्रभाव बढ़ रहा है, जहाँ चीन ने, नए बने उप प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया है, अब वह उसका तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनने वाला है।[79] विश्व बैंक में विकासशील और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं की मतदान क्षमता 2010 में 3.13 प्रतिशत बिंदु से बढ़ कर 47.19% पर पहुँच गई।[80]

प्रवास नीति

एसोशिएशन आफ़ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स, अफ्रीका यूनियन और कामन मार्केट आफ़ द साऊथ जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने प्रवास को अपने एजेंडे में जोड़ा है। इनमें से कुछ गतिविधियाँ क्षेत्रीय परामर्श से होती हैं, जो देशों के बीच साझा आधार पाने के लिए अनौपचारिक अबाध्यकारी प्रक्रियाएँ होती हैं। इनमें से कई प्रक्रियाएँ अंतरक्षेत्रीय हैं और क्षमता निर्माण, तकनीकी मानकीकरण और पुनर्प्रवेश जैसे मुद्दों पर समझौतों के लिए मूल तथा गंतव्य देशों के बीच फैली हुई हैं। उन्होंने संचार और सम्पर्क की बाधाओं को कम कर दिया है और देशों को साथ आने, एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने तथा साझा हलों की पहचान करने के लिए एक स्थान उपलब्ध कराया है।

इन वार्ताओं को प्रवास पर बाद के सफल प्रयासों का श्रेय दिया जा सकता है, सबसे महत्वकांक्षी प्रयास है 2001-2005 की बर्ने पहल, 2006 की संयुक्त राष्ट्र आमसभा द्वारा कराई गई प्रवास और विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता और उसके परिणामस्वरूप प्रवास और विकास पर वैश्विक मंच का गठन।[81] जैसा कि

जब जलवायु सम्बन्धी प्राकृतिक आपदाएँ और बढ़ते हुए समुद्र स्तर मानव विकास की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, तो देशों ने यह पहचान लिया है कि उनके पास अब जलवायु परिवर्तनों से अनुकूलन हेतु नीतियाँ बनाने और भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तनों की गंभीरता कम करने के अलावा कम ही विकल्प हैं

विकासशील देश उत्तर की तुलना में आपस में अधिक व्यापार कर रहे हैं और यह प्रचलन काफ़ी आगे जा सकता है

2009 की *मानव विकास रिपोर्ट* ने अनुशंसा की थी, ऐसे प्रयास लोगों द्वारा विदेशों में काम खोजने के रास्तों को उदार और सरल बनाकर, प्रवास से जुड़ी कार्यसंपादन की लागतें कम करके, आतंरिक गतिमानता (mobility) को लाभकारी बनाकर और गतिमानता को राष्ट्रीय विकास रणनीति का अविभाज्य हिस्सा बनाकर प्रवासी और गंतव्य स्थान के निवासियों के लिए परिणामों को बेहतर बना सकते हैं।[82]

पर्यावरणीय सुरक्षा

जिस तरह दक्षिण के देशों ने यह दिखाया कि वे किस तरह अपने संसाधनों के प्रबंधन के लिए साथ आ रहे हैं, रियो डी जेनेरियो में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मलेन ने क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की संभावना को प्रदर्शित किया। एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सरकारों द्वारा की गई एक पहल, जो मलेशिया और इण्डोनेशिया से सॉलोमन द्वीप तक फैली दुनिया की सबसे समृद्ध मूँगा चट्टानों (coral reef), 'मूँगा त्रिकोण' को सुरक्षा तो देगी ही, यह वर्तमान में 10 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन और रोज़गार देती है। कांगो नदी के बेसिन में, कई देश, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वर्षा-वन को बचाने के लिए ग़ैर-कानूनी लकड़ी व्यापार के खिलाफ़ मिलजुल कर काम कर रहे हैं।[83] रियो+20 में क्षेत्रीय विकास बैंकों के एक समूह ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन तथा साइकिल पथ को प्रोत्साहन देने के लिए 175 बिलियन डॉलर की घोषणा की है।[84]

दक्षिण का उदय जलवायु परिवर्तनों का सामना करने के लिए अनेक द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के रूप में भी प्रतिबिंबित होता है। जब जलवायु सम्बन्धी प्राकृतिक आपदाएँ और बढ़ते हुए समुद्र स्तर मानव विकास की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, तो देशों ने यह पहचान लिया है कि उनके पास अब जलवायु परिवर्तनों से अनुकूलन हेतु नीतियाँ बनाने और भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तनों की गंभीरता कम करने के अलावा कम ही विकल्प हैं। उदाहरण के लिए, अब देश तकनीकी विकास में सहयोग करने के लिए और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग कार्बन बाज़ार बनाने पर सहमत हो रहे हैं। चीन और युनाइटेड किंगडम के बीच एक साझेदारी अग्रवर्ती कोयला दहन तकनीकों को आज़माएगी, जबकि अमेरिका और भारत ने भारत में परमाणु ऊर्जा को विकसित करने के लिए साझेदारी की है।[85]

दक्षिण के देश जलवायु-अनुरूप तकनीकें विकसित कर रहे हैं और आपस में साझा कर रहे हैं। चीन 2008 में वायु-ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था, वह अब दुनिया में सोलर पैनलों और पवनचक्कियों का सबसे बड़ा उत्पादक है।[86] 2011 में भारत के नेशनल सोलर मिशन ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश में 62% वृद्धि होने में मदद की, जो 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और किसी भी बड़े नवीकरणीय बाज़ार में सबसे तेज़ निवेश प्रसार है। ब्राज़ील ने अक्षय ऊर्जा तकनीक में 8% की वृद्धि की है और वहाँ अब यह 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है।[87]

दक्षिण में जलवायु परिवर्तनों की गंभीरता कम करने तथा पर्यावरणीय संसाधनों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और राष्ट्रीय पहलें सकारात्मक क़दम हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण अपने मूल में ही वैश्विक विषय हैं, जिनके लिए बहुपक्षीय समझौतों द्वारा वैश्विक संकल्प आवश्यक हैं। समझौतों की सफलता के लिए उनमें दक्षिण की विकासमान अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग और भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय सहयोग और समझौते, जलवायु की चुनौतियों का सामना करने में ईमानदार रुचि को इंगित करते हुए इस दिशा में एक कदम हो सकते हैं।

अनिश्चितता के दौर में प्रगति बरकरार रखने की चुनौती

दक्षिण के उदय को व्यापार और निवेश के भूमंडलीय प्रसार से मदद मिली है। वर्ष 2007 में 100 से अधिक विकासशील देशों ने प्रति व्यक्ति आय में 3% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। हाल ही में, विकसित देशों की आर्थिक मंदी ने दक्षिण को क्षेत्रीय माँग की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है।[88] पहले से ही, विकासशील देश उत्तर की तुलना में आपस में अधिक व्यापार कर रहे हैं। यह प्रचलन आगे भी जारी रहेगा। दक्षिणी-दक्षिण व्यापार ब्लॉक ग़ैर सीमा शुल्क बाधाओं से भरे हुए हैं, जो उनकी व्यापार संभावनाओं को संकुचित करते हैं। दक्षिणी देशों के बीच निवेश के अधिक सुरक्षित और अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभकारी अवसर हैं, लेकिन विशाल विदेशी मुद्रा भंडार निरुद्योग पड़े हैं। यहाँ विकास साझेदारियों तथा क्षेत्रीय और अंतर्क्षेत्रीय सहयोग के प्रसार की संभावना है।

दक्षिण के उदय ने सब-सहारा अफ़्रीकी देशों की तीव्र आर्थिक संवृद्धि को सहारा दिया है और वहाँ मानव विकास की प्रगति के अवसरों में वृद्धि की है। इस सदी में सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से कई मानव विकास के पायदान पर नीचे हैं। उनमें से कुछ ने ग़ैर-आय सूचकों में प्रगति की है, तो दूसरों ने नहीं।

सरकारों को संवृद्धि संवेग के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और ऐसी नीतियों को अपनाना चाहिए जो बढ़ती हुई आय को मानव विकास में परिवर्तित कर सके। ऐसी नीतियाँ, जो मानव क्षमताओं तथा घरेलू उत्पादन क्षमता का निर्माण करें, वे देशों को

'कमोडिटी-जाल' में फँसने से बचाएँगी और आर्थिक गतिविधियों को विविधतापूर्ण बनाएँगी। दक्षिणी देशों का आपसी सहयोग व्यापार, निवेश और सभी उद्योगों, यहाँ तक कि कमोडिटी में भी, सीखने तथा विसरण की क्षमताओं को उभारने में मदद कर सकता है। दक्षिणी देशों की आपसी साझेदारियाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संयुक्त उपक्रमों, समकक्ष अध्ययन द्वारा प्रौद्योगिकी साझाकरण और वहनीय कीमतों पर उत्पादों को तथा ऐसे नवाचारी उपयोगों को उपलब्ध कराने में मदद कर सकती हैं, जो उभरते हुए उद्यमी वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करे, औद्योगिक विविधता को सुगम बनाए। यह साझेदारी पहले से ही हो रही है और आने वाले वर्षों में बड़ी मात्रा में और ज़्यादा बढ़ सकती है।

कुल मिलाकर खास बात यह है कि दक्षिण का उदय नाटकीय रहा है, और अभी यह उदय अपने शुरुआती दौर में है। आज विकासशील देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और उद्यमिता संपर्कों का विस्तार अभूतपूर्व है। रोज़ के अखबारों की सुर्ख़ियों में दुनिया की घटनाओं के बारे में निराशाजनक सन्देश हो सकते हैं, लेकिन इन निराशाजनक टिप्पणियों के बीच अनगिनत जगहों के मेहनती लोगों द्वारा उद्यमिता उपक्रमों तथा नई तकनीकों के सहज उपयोग की उत्साहजनक रिपोर्टों के टुकड़े अक्सर होते ही हैं।

हर किस्से को विकासशील देशों में रहने वाले लोगों की संख्या से गुणा कीजिए, तब अहसास होगा कि सभी क्षेत्रों में दक्षिण की प्रगति-संभावना विस्मयकारी रूप से प्रभावशाली है। अध्याय 3, उन कुछ महत्वपूर्ण प्रचालक तत्वों और क्षमताओं की पहचान करता है, जिन्होंने दक्षिण के अग्रणी देशों को तीव्र प्रगति के लिए सक्षम बनाया है और दूसरे देशों को भी अनुकरण की प्रेरणा दी है।

वैश्विक संभावनाएँ अनिश्चित हैं और उत्तर की आर्थिक गिरावट दक्षिण को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर रही है। लेकिन, सही सुधारों के साथ, जिसमें नीतिगत दिशाओं में बदलाव[89] शामिल हैं, दक्षिण के उदय से विश्व अर्थव्यवस्था के भीतर आए परिवर्तनों के फलस्वरूप टिकाऊ मानव प्रगति की संभावना अधिक मज़बूत दिखाई देती है।

‘‘हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि
सभी देश एक जैसी प्रणालियों को
अपनायेंगे, अनालोचक सहमति आज़ादी को कैद
करती है और विकास की शत्रु है।’’

जॉन एफ. कैनेडी

‘‘बुद्धिमानी न तो जड़ बने रहने में और
न ही बदलते रहने में है, बल्कि इन
दोनों के बीच की द्वंद्वात्मकता में है।’’

ओक्टेवियो पाज़

3.

विकासपरक रूपान्तरण के प्रचालक

दक्षिण के इतने सारे देशों ने आखिर अपनी मानव विकास संभावनाओं को कैसे रूपांतरित किया? उनकी सामाजिक और राजनीतिक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की उनकी विरोधाभासी पूँजी के मद्देनज़र प्रायः विकास का उनका पथ अलग-अलग रहा है। इसके बावजूद उनमें कुछ खास अंतर्निहित लक्षण एक निरंतरता के साथ बने रहे हैं। इस अध्याय में हम कुछ सर्वाधिक सफल देशों के अनुभवों और उनके तीन एकसमान प्रचालकों पर गौर करेंगेः उनके प्रसक्रिय विकासपरक राज्य, वैश्विक बाज़ार का दोहन करने की उनकी क्षमता और सामाजिक नीति निर्धारण नवाचार पर उनका विशेष ध्यान।

अनेक देशों ने पिछले दो दशकों के दौरान काफ़ी प्रगति की हैः दक्षिण के उदय का आधार काफ़ी हद तक व्यापक रहा है। उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले ऐसे देशों की पहचान की जा सकती है, जिन्होंने न केवल अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर्ज की, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों के लिहाज से औसत से अच्छा प्रदर्शन किया। उच्च स्तरीय उपलब्धता हासिल करने वालों की पहचान करने का एक तरीका यह है कि विकास के लगभग समान स्तरों पर रहे ऐसे देशों को देखा जाए जिन्होंने दूसरे देशों की तुलना में सकारात्मक आय वृद्धि दर्ज की है और स्वास्थ्य और शिक्षा के मापकों पर बेहतर प्रदर्शन किया। इन देशों में ब्राज़ील, चीन और भारत जैसे कुछ बड़े देश और बांग्लादेश, चिली, घाना, इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, मॉरिशस, थाइलैण्ड, ट्यूनीशिया, तुर्की, युगाण्डा और वियतनाम शामिल हैं (रेखांकन 3.1)।

यह अध्याय ऐसे देशों के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है जिन्होंने 1990 के बाद से आय वृद्धि और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मानव विकास के ग़ैर-आय मानकों के संदर्भ में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कुछ देश एक आयाम पर दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करते दिखते हैंः ब्राज़ील और तुर्की ने मा.वि.सू. के ग़ैर-आय घटकों में बेहतर प्रदर्शन किया, तो चीन के 1990-2010 के दौरान के प्रदर्शन में आय में वृद्धि हावी रही (ऐसा इसलिए क्योंकि 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सुधार की प्रकिया शुरू हुई, मगर चीन ने पहले ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय उपलब्धि हासिल कर ली थी)।[1] इसके अलावा, जैसा कि अध्याय 1 में दर्शाया गया है, ऐसे देशों का समूह, जिनका 1990 से 2012 के बीच मा.वि.सू. में सुधार के लिहाज से प्रदर्शन समकक्ष देशों से बेहतर था, उनमें लाओ पी.डी.आर., माली, मोज़ांबीक, रवाण्डा और युगाण्डा शामिल हैं।

उच्च स्तरीय उपलब्धि हासिल करने वाले देशों की पहचान करने का एक अन्य तरीका यह भी है कि ऐसे देशों को देखा जाए जो कि 'मानव विकास अंतर' (human development gap) को पाटने में अधिक सफल रहे, जिसे उनके मा.वि.सू. मानक से घटती दूरी (HDI shortfall) के रूप में देखा जा सकता है। (अधिकतम मा.वि.सू. मान से दूरी)।[2] सारणी 3.1 में उन 26 देशों की सूची है, जो या तो उन शीर्ष 15 विकासशील देशों में शामिल थे, जिन्होंने 1990-2012 के दौरान मा.वि.सू. कमी में उच्चतम कमी दर्ज की[3] या उन शीर्ष 15 देशों में शामिल थे, जिन्होंने इसी अवधि में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय के संदर्भ में सर्वोच्च दर की वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

ऊपर वर्णित पहले समूह के देशों ने तेज़ आर्थिक प्रगति के साथ-साथ समाज को, विशेषरूप से ग़रीबों को व्यापक रूप से लाभ पहुँचाने वाली सामाजिक नीतियों को अंज़ाम दिया। उदाहरण के लिए चीन ने कोरिया गणतंत्र और ईरान को छोड़कर अन्य देशों की तुलना में मा.वि.सू. कमी को सर्वाधिक घटाया।

रेखांकन 3.1

कुछ देशों ने मा.वि.सू. के ग़ैर-आय और आय, दोनों आयामों पर बेहतर प्रदर्शन किया है।

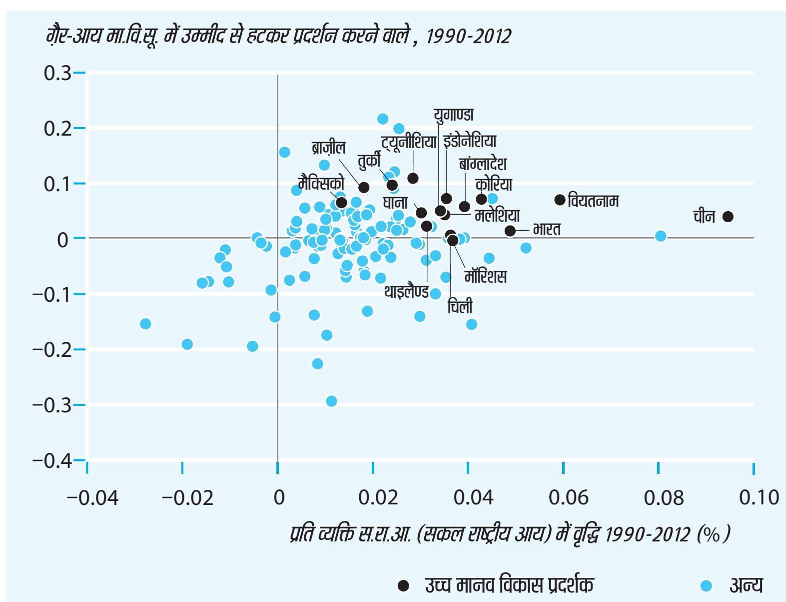

नोटः 96 देशों के संतुलित पैनल के आधार पर।
स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

सारणी 3.1

चुनिंदा विकासशील देश जिन्होंने मा.वि.सू. मान में कमी को बड़े पैमाने पर कम किया अथवा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (स.रा.आ.) में उच्च प्रगति दर दर्ज की,1990-2012

	मा.वि.सू. (मान)		मा.वि.सू. कमी में गिरावट[a]		प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में औसत सालाना वृद्धि	
			(%)	श्रेणी	(%)	श्रेणी
देश	1990	2012	1990-2012		1990-2012	
कोरिया गणराज्य	0.749	0.909	63.6	1	4.2	8
इस्लामिक गणराज्य ईरान	0.540	0.742	43.9	2	2.5	32
चीन	0.495	0.699	40.5	3	9.4	1
चिली	0.702	0.819	39.4	4	3.8	13
सऊदी अरब	0.653	0.782	37.3	5	0.4	77
अर्जेंटीना	0.701	0.811	36.9	6	3.5	18
मलेशिया	0.635	0.769	36.6	7	3.6	17
कतर	0.553	0.712	35.6	8	2.9	29
ट्यूनीशिया	0.569	0.722	35.5	9	2.5	33
तुर्की	0.743	0.834	35.3	10	3.2	22
मैक्सिको	0.654	0.775	35.0	11	1.3	58
अल्जीरिया	0.562	0.713	34.4	12	1.0	69
ब्राज़ील	0.666	0.780	34.3	13	3.9	11
पनामा	0.590	0.730	34.1	14	1.7	50
ब्रूनेई दारस्सलाम	0.782	0.855	33.4	15	–0.4	87
वियतनाम	0.439	0.617	31.8	21	5.9	3
मॉरिशस	0.626	0.737	29.8	25	3.6	14
डॉमिनीकी गणराज्य	0.584	0.702	28.3	28	3.9	12
म्यॉंमार	0.305	0.498	27.8	30	7.9	2
श्रीलंका	0.608	0.715	27.3	31	4.4	7
गयाना	0.502	0.636	26.7	36	5.3	4
लाओ पी.डी.आर.	0.379	0.543	26.5	39	4.4	6
भारत	0.410	0.554	24.5	45	4.7	5
बांग्लादेश	0.361	0.515	24.1	47	3.9	10
ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	0.685	0.760	23.9	49	3.6	15
मोज़ांबीक	0.202	0.327	15.6	72	4.1	9

a. अधिकतम मा.वि.सू. मान से दूरी में हुई घटत।।
नोटः 96 विकसशील देशों के संतुलित पैनल पर आधारित।
स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

चीन की तुलना में अपेक्षाकृत कम आर्थिक विकास के बावजूद कोरिया गणराज्य ने मा.वि.सू. के मामले में सर्वाधिक उपलब्धि हासिल की। वियतनाम भी मा.वि.सू. में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 20 देशों की सूची में शामिल है और आय वृद्धि के मामले में तीसरे नंबर पर था। वर्षों के आंतरिक विवाद के बावजूद श्रीलंका ने उच्च आय वृद्धि दर्ज की और मा.वि.सू. कमी में उल्लेखनीय घटाव हासिल किया।[4]

भारत का आर्थिक प्रदर्शन भी 1990-2012 के दौरान 5% की औसत सालाना आय वृद्धि दर के साथ प्रभावशाली बना रहा। यद्यपि भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय अब भी काफ़ी कम है और यह 2012 में 3400 डॉलर के आसपास थी; जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए उसे और विकास की ज़रूरत होगी, क्योंकि कम आय के साथ सिर्फ़ पुनर्वितरण के ज़रिए ग़रीबी में कमी करना बहुत कठिन है। बेहतर विकास प्रदर्शन की तुलना में मानव विकास को तेज़ करने में भारत का प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं है। वहीं, वास्तव में बांग्लादेश ने अपेक्षाकृत धीमे आर्थिक विकास और भारत की तुलना में आधी प्रति व्यक्ति सालाना आय के बावजूद मानव विकास के मुद्दे पर लगभग भारत जैसा ही और कुछ सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

मा.वि.सू. कमी को सर्वाधिक पाटने वाले शीर्ष 15 देशों में अल्जीरिया, ब्राज़ील और मैक्सिको जैसे देश शामिल थे, बावजूद इसके कि 1990-2012 के दौरान उनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय में 1%-2% के बीच औसत वृद्धि दर्ज की गई। उनके अनुभव दूसरी व्यापक रणनीति की ओर इशारा करते हैं, जिससे मानव विकास लाभांश प्राप्त हुआः लोगों की क्षमताएँ– खासतौर से उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सम्बन्धी क्षमताएँ– बढ़ाने के लिए राज्य का प्राथमिकता के आधार पर निवेश करना और अपने समाज को आर्थिक, पर्यावरणीय तथा अन्य खतरों व झटकों से जूझने वाले लोच-बल से सम्पन्न करना।

एक सबकः देश सिर्फ़ विकास पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसा कि 1993 और 1996 की *मानव विकास रिपोर्टों* ने भी तर्क दिया था, कि प्रगति और मानव विकास के बीच कोई स्वचालित रिश्ता हो, ऐसा नहीं है।[5] इसे ग़रीब-हितैषी नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसके लिए एक साथ स्वास्थ्य और शिक्षा में निरंतर निवेश करना होगा, सम्मानजनक नौकरियों का विस्तार करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रोकना होगा, लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करना होगा और आय का समतामूलक वितरण करने के साथ ही समुदायों के अनावश्यक विस्थापन को रोकना होगा।

कहने का आशय यह नहीं है कि आर्थिक प्रगति का कोई महत्व ही नहीं। ढेरों ग़रीब लोगों वाले ग़रीब देशों को उच्च आय की ज़रूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर तेज़ प्रगति से देशों को अपना और घाटा कम करने में मदद मिल सकती है और वे अतिरिक्त सार्वजनिक धन जुटा सकते हैं, जिससे बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं, खासतौर से, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश बढ़ाया जा सके। घरेलू आय में वृद्धि से बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिलती है, जीवन स्तर सुधरता है और ज़िंदगी गुणवत्तापूर्ण होती है।

इसके बावजूद यह आवश्यक नहीं कि उच्च आय अपने साथ-साथ इन्सान की खुशहाली (well being) में भी वैसी ही सकारात्मक वृद्धि कर दे। उदाहरण के लिए

बड़े शहरों की आबादी की प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, लेकिन वहाँ अपराध और प्रदूषण की दर भी उच्च होती है और वे ट्रैफ़िक की समस्या से भी जूझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर परिवारों की आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन गाँव में स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हो सकता है। प्रारंभिक परिस्थितियाँ देशों के वर्तमान और भविष्य के विकास की गति पर बहुत प्रभाव डालती हैं। फिर भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही चीज़ें ही महत्व की हैं (बॉक्स 3.1)।

वास्तव में आर्थिक प्रगति और मानव विकास के बीच के रिश्ते की डोर कई बार टूटी है। 1996 की *मानव विकास रिपोर्ट* ने प्रगति की छह अप्रिय किस्मों की पहचान की थीः रोज़गार विहीन प्रगति, जो रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ा सकती; निर्मम प्रगति, यह वृद्धिगत असमानता के साथ आती है; बे-आवाज़ प्रगति, जो सर्वाधिक अरक्षित समुदायों की भागीदारी को नकारती है; जड़ विहीन प्रगति, जो कहीं और से लिए गए अनुपयुक्त मॉडलों को अपने यहाँ थोपती है; और भविष्यहीन प्रगति, जो पर्यावरणीय संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर आधारित होती है।[6]

उच्च स्तरीय प्रगति का सृजन करना और उसको मानव विकास में रूपांतरित करने का क्या मतलब है? इन देशों के मानव विकास सम्बन्धी विभिन्न तरह के अनुभवों के सबक क्या हैं? वास्तव में रूपांतरण के प्रचालक (drivers) कौन से हैं? इस अध्याय में तीन प्रचालकों की पहचान की गई हैः

- प्रसक्रिय विकासशील राज्य
- वैश्विक बाज़ारों का दोहन
- दृढ़ सामाजिक नीति और नवाचार

ये प्रचालक किसी ऐसी अमूर्त अवधारणाओं से नहीं लिए गए हैं जो बताये कि विकास को किस तरह काम करना चाहिए; इसके बजाए ये दक्षिण के अनेक देशों के परिवर्तनकारी विकास अनुभवों से उपजे हैं। इतना ज़रूर है कि ये पूर्वधारित (preconceived) और निर्देशात्मक (prescriptive) दृष्टिकोणों को चुनौती देते हैंः एक ओर तो वे संग्रहवादी (collectivist), केंद्रीकृत तरीके से संचालित दृष्टिकोणों को दर किनार करते हैं, और दूसरी ओर वे वाशिंगटन सर्वानुमति (Washington Consensus) द्वारा स्वीकार किए गए बे़रोकटोक उदारीकरण से भी अलग राह पकड़ते हैं।

ये प्रचालक एक नए दृष्टिकोण वाले विकास की ओर इशारा करते हैं, जिसके मुताबिक राज्य एक अनिवार्य उत्प्रेरक है, जो व्यावहारिक रूप से नई वास्तविकताओं और वैश्विक बाज़ार की चुनौतियों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियों और कार्रवाइयों में तालमेल करता है। यह नया दृष्टिकोण इस बात को स्वीकारता है कि विकास स्वतः नहीं होता, और बदलाव को अकेले बाज़ार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बजाए, ज़रूरी यह है कि राज्य आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने वाली नीतियों और

इस अध्याय में तीन प्रचालकों की पहचान की गई हैः प्रसक्रिय विकासशील राज्य, वैश्विक बाज़ारों का दोहन और दृढ़ सामाजिक नीति और नवाचार

बॉक्स 3.1

इतिहास और शुरुआती परिस्थितियों का महत्व है, मगर वे नियति नहीं हैं

शुरुआती परिस्थितियों का गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ गुणधर्मों को न केवल बदलना मुश्किल होता है, बल्कि प्रायः संस्थाएँ और नीतियाँ भी उन्हें बनाए रखती हैं। जिन समाजों की शुरुआत उच्च स्तर की असमानता के साथ होती है, उनमें अभिजात वर्ग अपने प्रभाव वाला कानूनी ढाँचा स्थापित कर सकता है, जो उसके लाभ के लिए उच्च स्तर की असमानता क़ायम रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, उन कई अमेरिका को देखिए, जहाँ 17वीं सदी में मिट्टी की शुरुआती परिस्थितियों, मौसम और मूल बसावट के आधार पर तीन भिन्न तरह की बस्तियों (colonies) ने आकार लिया।

कैरिबियाई क्षेत्र में मिट्टी और मौसम ने बस्तियों को बड़े पैमाने पर आकर्षक जिन्सों के उत्पादन के अनुकूल बनाया। वहाँ सम्पत्ति और मानव पूँजी का वितरण अत्यंत असमान था जिसका लाभ अभिजात वर्ग को हुआ, जिसके कारण वे दासों की बड़ी कंपनियाँ खड़ी कर सके। खनिजों और मूल निवासियों से भरपूर स्पेनिश अमेरिका में प्राधिकारियों ने स्पेनिश उपनिवेशियों (Spanish Colonists) में भू-संसाधनों का वितरण किया। अभिजात वर्ग ने स्पेनिश राजा की सेवा की और स्वतंत्रता के बाद भी अपनी हैसियत को बरकरार रखा। आय की असमानता नस्लीय आधार पर कायम रही, जिसमें बड़े भू-भाग का मालिकाना हक होना नागरिकता हासिल करने की शर्त थी। पेरू सहित कई देशों में आज भी मूल आबादी और यूरोपीय वंशजों के बीच भयानक किस्म की क्षैतिज (horizontal) असमानता कायम है। अमेरिका के उत्तरी भाग में मूल आबादी बहुतायत में नहीं थी और मिट्टी और मौसम के हालात भी ऐसे नहीं थे कि उनके आधार पर कोई बड़ी आर्थिक रचना खड़ी हो सके। इसलिए वहाँ यूरोपीय मूल के श्रमिकों पर निर्भरता थी, जिसमें उच्च मानव पूँजी के साथ संपत्ति का कहीं अधिक समानता भरा वितरण था। प्रचुर मात्रा में ज़मीन होने और कमतर पूँजी की आवश्यकता के फलस्वरूप अधिकांश वयस्क पुरुष स्वतंत्र स्वामी की तरह काम करते थे।

हैती पश्चिमी गोलार्ध में आज सबसे ग़रीब देश है। 1790 में क्रांति की बेला में यह नए विश्व का संभवतः सबसे अमीर देश था। इसी तरह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सात वर्ष (1756-1763) चले युद्ध के उपरांत ब्रिटेन ने इस बात पर बहस की थी कि क्षतिपूर्ति के रूप में वह कैरिबियाई द्वीप गुआदेलोप (Caribbean island of Guadeloupe) स्वीकार करे या कनाडा को। यद्यपि कई शताब्दियों बाद गोलार्ध की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कनाडा कहीं अधिक सफल साबित हुआ।

इसके बावजूद, यह समझना जरूरी है कि इतिहास और शुरुआती परिस्थितियाँ ऐसी नही हैं जिनसे पार न पाया जा सके। बीते 30 वर्षों के दौरान मा.वि.सू. द्वारा मापी जाने वाली विकास सम्बन्धी आधे से अधिक प्रगति की 1980 के मा.वि.सू. मान के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। एक समान स्तर के साथ शुरुआत करने वाले भारत और पाकिस्तान, चिली और वेनेजुएला, मलेशिया और फिलीपींस या लाइबेरिया और सेनेगल ने विभिन्न परिणामों के साथ अपनी विकास यात्रा को अंजाम दिया है। जैसा कि 2010 की *मानव विकास रिपोर्ट* का तर्क रहा है कि यदि समान प्रस्थान बिंदु के बावजूद विभिन्न देश विकास के भिन्न रास्तों पर चलते हैं, और यदि इस दौरान औसत वैश्विक उपलब्धि में कोई परिवर्तन न रहा हो, तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास के नतीजों को राष्ट्रीय नीतियाँ, संस्थाएँ, सामाजिक संदर्भ और विशेष मानसिक प्रवृत्तियों से मिलने वाले बल-झटके ही संचालित करते हैं। यदि कोई देश दृढ़ता से ठान ले तो वह इतिहास का बंधक नहीं बना रह सकता।

स्रोतः एंगरमैन एंड सोकोलॉफ़ (2002); हॉफ़ (2003); थॉर्प एंड परेड्स (2011); यू.एन.डी.पी. 2010a

संस्थाओं के ज़रिए समाज को सक्षम बनाए। हालाँकि, यह कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है। इन तीनों तत्वों को जिस तरह से नीतियों में ढाला जाता है, वह संदर्भ विशेष पर और देश की प्रकृति, सरकार की क्षमताओं और शेष दुनिया से उसके सम्बन्धों पर निर्भर करता है।

प्रचालक 1ः एक प्रसक्रिय विकासपरक राज्य

विकास का आशय समाज को इस तरह बदलने से है ताकि सभी पीढ़ियों के लिए खुशहाली से जीने के अवसर बढ़ सकें– स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के मामले में उनके पास अधिक विकल्प हों, उनकी आज़ादी का विस्तार हो सके और समाज में सार्थक हिस्सेदारी के लिए उनके पास पहले से अधिक अवसर हों।

इस तरह के बदलावों को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले देशों में जो एक बात समान पाई जाती है, वह है, राज्य की प्रसक्रिय (proactive) भूमिका, जिसे एक विकासपरक राज्य (Developmental State) भी कहा जाता है। विकासपरक राज्य उन देशों को कहा जाता है जहाँ एक संवेदनशीलता के साथ सजग सरकार हो और जहाँ ग़ैर-राजनीतिक अभिजात वर्ग हो जिसके लिए तेज़ आर्थिक विकास बुनियादी लक्ष्य हो। कुछ देश एक कदम आगे जाकर इसमें एक और आयाम जोड़ते हैंः एक नौकरशाही जो नीतियाँ बनाने और प्रभावी तरीके से अमल करने के अधिकार से लैस हो। उच्च विकास दर और जीवन स्तर में सुधार होने से राज्य की व्यवस्था और अभिजात सत्तातंत्र को उसकी वैधता मिलती है।[7]

इस तरह के बदलावों को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले देशों में जो एक बात समान पायी जाती है, वह है, राज्य की प्रसक्रिय भूमिका–जिसे एक विकासपरक राज्य भी कहा जाता है।

कुछ उल्लेखनीय मामलों में देखा गया है कि विकासपरक प्रगति दीर्घकालीन दृष्टिकोण, साझा आदर्शों और मूल्यों, तथा ऐसे नियमों और संस्थाओं से निर्देशित होता है, जो विश्वास और संघटन बढ़ाते हैं। इसके साथ ही विकास को बदलाव के रूप में देख पाने की शर्त यह होती है कि इन अप्रत्यक्ष तत्वों पर ग़ौर किया जाए, यह भी समझा जाय कि ये समाज की सांगठनिक रचना को किस तरह से प्रभावित करते हैं, तथा किस तरह प्रत्येक नीति और सुधारों से संवाद करते हैं।

विकास की रणनीति, नौकरशाही की मज़बूत प्रशासनिक क्षमता और उचित नीतियाँ– ये सब मिलकर ही किसी देश के रूपांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले आवश्यक तत्व बनते हैं।[8] नीतियों के ऐसे लक्ष्य होने चाहिए कि वे बाधाओं की और स्थितियों को बदल सकने वाले शक्तिशाली उत्प्रेरकों की पहचान कर सकें। इस प्रक्रिया में संस्थाओं, समाजों और व्यक्तियों को अपने खुद के लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की रणनीतियों तथा नीतियों की पहचान करने की ज़रूरत होती है। हालाँकि हर जगह उन पर अमल भले ही न किया जाए, मगर लोगों की व्यापक भागीदारी और उनमें यह एहसास कि उनकी बात सुनी जा रही है और निर्णय़ लेने की प्रक्रिया में उनके दृष्टिकोणों पर ग़ौर किया जा रहा है और एजेंडा तय करने में उनकी अहम भूमिका है; यह दीर्घकालीन संवहनीय विकास के हित में है– वैसे ही जैसे एक सतत राजनीतिक नेतृत्व की ज़रूरत होती है, जिसके साथ टेक्नोक्रेटों की ऐसी मज़बूत टीम हो जो संस्थागत याद्दाश्त को दुरुस्त रख कर नीतियों में निरंतरता सुनिश्चित कर सके (बॉक्स 3.2)।[9]

मानव विकास और आर्थिक संवृद्धि को जोड़ने का या विकास को तेज़ करने का कोई आसान नुस्खा नहीं है।[10] वर्ष 1950-2005 के अंतर-देशीय आँकड़ों का एक अध्ययन बताता है कि विकास सम्बन्धी अधिकांश उपलब्धियाँ मज़बूत आर्थिक सुधारों के कारण हासिल नहीं हुईं और न ही सबसे मज़बूत आर्थिक सुधार विकास को गति दे सके।[11] सफल देशों ने नीतियों और सुधारों की लंबी सूची पर अमल करने के बजाए प्रगति की बाधाओं को धीरे-धीरे दूर कर तेज़ विकास किया है। इसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जो देश संवहनीय विकास को गति देने में सफल हुए, उन्हें विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने बाज़ार के नियमन (regulation), निर्यात को बढ़ावा देने, औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिकीय अनुकूलता तथा प्रगति के लिए विभिन्न तरह की नीतियाँ अपनायीं।[12] और जब कोई देश पहले ही तेज़ विकास कर रहा है, तब चुनौती भविष्य की बाधाओं को दूर करने या उनकी शिनाख्त करने की होती है, क्योंकि आगे चलकर यही वास्तविक या गंभीर बाधाएँ बन जाती हैं। व्यापार सम्बन्धी आघातों की सकारात्मक शर्तें, जैसा कि दक्षिण के उदय से हाल ही में उपभोक्ता सामानों में आया उछाल, विकास की तेज़ तो कर सकती हैं, मगर उसकी निरंतरता कायम नहीं रख सकतीं। हालाँकि, ध्यान देकर किए गए आर्थिक और संस्थागत सुधारों का सांख्यिकीय और मात्रात्मक रूप से संवहनीय विकास को तेज़ करने में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।[13]

उच्च प्रदर्शन करने वाले अनेक विकासशील देशों में राज्य की भूमिका पारंपरिक कल्याणकारी राज्य से अलग नज़र आती है, जिसका लक्ष्य बाज़ार की विफलताओं को दूर करना और बाज़ारोन्मुखी विकास को बढ़ावा देते हुए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना होता है। इसके विपरीत, विकासपरक राज्य प्रसक्रिय होते हैंः ये लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन की शुरुआत करते हैं और उसकी निगरानी करते हैं।[14] महज़ बाज़ारोन्मुखी होने के बजाए ऐसे राज्य विकासोन्मुखी रहे हैं। जिन राज्यों के पास मज़बूत नवाचारी सामाजिक कार्यक्रम हैं, वे अक्सर जनहितकारी भी साबित हुए हैं– प्रगति के बजाए मानव विकास पर ध्यान केंद्रित

बॉक्स 3.2

विकासपरक राज्य से क्या आशय? क्या उसका सत्तावादी होना जरूरी है?

विकासपरक राज्य पर हाल में विकसित हुआ साहित्य पूर्वी एशिया की "चमत्कारिक" अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों से उपजा हैः जिसका आधार दूसरे विश्व युद्ध से पहले का जापान और 20वीं सदी के उत्तरार्ध का हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.), कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और चीन का ताईवान प्रांत थे। हाल ही में चीन और वियतनाम (साथ ही कंबोडिया तथा लाओ पी.डी.आर. भी) को विकासपरक राज्यों के रूप में देखा जा सकता है। इनकी समान विशेषताओं में स्पष्ट रूप से कुछ खास क्षेत्रों को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना; योग्य नौकरशाही की सेवाएँ हासिल करना; विकास रणनीतियों के केन्द्र में ठोस एवं सक्षम सार्वजनिक संस्थाओं को रखना; स्पष्ट सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य रखना; और विकास के इनके मज़बूत रिकॉर्ड के आधार पर राजनीतिक वैधता अर्जित करना।

चूँकि पूर्वी एशिया के कुछ विकासपरक देश लोकतांत्रिक नहीं थे, इससे अनेक लोग यह भी सोचने को प्रेरित हुए कि विकासपरक राज्य का मॉडल सत्तावादी भी है। परंतु तानाशाही और विकास के अंतर्सम्बन्ध का साक्ष्य काफ़ी मिश्रित है। जापान और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों ने विकासपरक राज्यों की तरह काम किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने योजनाएँ तैयार करने के लिए योजना आयोग का गठन किया और अभिजातवर्गीय नौकरशाहों द्वारा तैयार क्षेत्रक (sectoral) औद्योगिक नीतियों से शुरुआत की और राज्य के नियंत्रण वाले उद्यमों का बढ़-चढ़ कर उपयोग किया। 1950 के दशक से स्कैंडेनेवियाई देशों ने भी विकासपरक देशों की तरह व्यवहार शुरू किया, जहाँ राजनीतिक वैधता तेज़ विकास के बजाए कल्याणकारी राज्य और पूर्ण रोज़गार के ज़रिए हासिल की गई। स्वीडन ने निजी-सार्वजनिक साझेदारी द्वारा रणनीतिक क्षेत्रकों (लौह और इस्पात, रेलवे, टेलीग्राफ़ और टेलीफ़ोन, और पनबिजली ऊर्जा) का विकास किया। उसने भारी उद्योगों को उभारने के लिए उन्हें लक्षित संरक्षण और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया। उसकी कल्याणकारी नीति ऐसी रणनीतियों के साथ एकीकृत थी जो उच्च उत्पादन वाले क्षेत्रकों को ढाँचागत बदलाव को बढ़ाने की तरफ ला सके।

अमेरिका का एक विकासपरक देश के रूप में लंबा इतिहास है और इसकी शुरुआत गणराज्य बनने के उसके शुरुआती दिनों से होती है। बहुत से लोग अमेरिका के पहले वित्त मंत्री एलेक्जेंडर हैमिल्टन को नए उद्योगों के संरक्षण (Infant industry Argument) का जनक मानते हैं। 1830 से 1945 के दौरान अमेरिका में दुनिया की सर्वाधिक व्यापार सम्बन्धी बाधाएँ थीं। इसी अवधि में उसने अधोसंरचना (पैसिफ़िक रेलवे, मध्य-पश्चिम की नहरों और कृषि सम्बन्धी अधोसंरचना), उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा विकास में भारी निवेश किया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी जब अमेरिका ने औद्योगिक रूप से प्रभुत्व कायम कर लिया था, बाज़ार के कट्टरवाद के उदय के बावजूद विकासपरक देश का अस्तित्व बना रहा।

ब्लॉक (2008) तर्क देते हैं कि राज्य ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान को व्यावसायिक उपयोग में रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया और यह संभव हुआ राज्य की एजेंसियों, उद्योगों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में बैठे उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के नेटवर्क के सहयोग से। विकासवाद अमेरिकी नीतियों की छाया में ही रहा, क्योंकि प्रौद्योगिकीय बदलावों को बढ़ावा देने में राज्य की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करने की उस दावे के साथ संगत नहीं बैठती, जो कहता है कि बाज़ार के संकेतों का जवाब देने के लिए निजी क्षेत्र को स्वंतत्र छोड़ देना चाहिए। हालाँकि अपने सीमित दायरे के बावजूद, जो वैधता के अभाव, अस्थिर वित्तीय और अन्य सीमितताएँ जो उसकी गोपनीयता की प्रकृति से जुड़ी हैं, अमेरिका का विकासशील राज्य अपेक्षाकृत सफल रहा है। अमेरिका ने अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक वित्तीयन के ज़रिए और रक्षा (कंप्यूटरों, हवाई जहाज़, इंटरनेट) और स्वास्थ्य (दवाओं, जेनेटिक इंजीनियरिंग) की खरीद के ज़रिए कई क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित की।

स्रोतः इवान्स (2010), चांग (2010). एदिधेजी (2010) ब्लॉक (2008)।

करने वाली पहल के तहत यह एक आवश्यक प्रगति है।

विकासपरक देशों की एक अन्य विशेषता औद्योगिक नीतियों के उनके उस अनुसरण (pursuit) से जुड़ी है जिसमें वे तुलनात्मक लाभ (Comparative advantage) का 'प्रबंधन' करते हुए समन्वय सम्बन्धी समस्याओं और बाह्य कारकों से निपटते हैं।[15] उदाहरण के लिए, तुलनात्मक लाभ की अन्तर्निहित क्षमता वाले उद्योगों को राज्य पोषित कर सकता है या फिर जिन उद्योगों की तुलनात्मक लाभ उठाने की गति धीमी हो गई है, राज्य उन्हें उबारने का प्रयास कर सकता है। नतीजतन, शुल्क संरक्षण से लाभ उठाने वाले अनेक उद्योग वैश्विक बाज़ारों में सफल साबित हुए हैं।[16] फिर भी, किसी उद्योग विशेष की सफलता या विफलता के लिए व्यापार सम्बन्धी विशेष नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराना कठिन होता है, क्योंकि सरकार के इन नीतिगत हस्तक्षेपों के पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं– राजस्व उगाही से लेकर विशेष हितों के संरक्षण तक।

तमाम उद्योगों के अध्ययन से मिलने वाला साक्ष्य उद्योग संरक्षण से मिलने वाले लाभ के बारे में अस्पष्ट हैं। हालाँकि, ढाँचागत सुधार और प्रौद्योगिकीय अनुकूलन अपनाने जैसी 'उदार' औद्योगिक नीतियों को अपनाने की चाह और प्रत्यक्ष कर तथा कुछ खास उद्योगों को अनुदान जैसे हस्तक्षेप की पक्षधरता 'कठोर' औद्योगिक नीतियों की वाछंनीयता में फ़र्क रहता है। इन नीतियों की उपयोगिता देश विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर होती है। इसके लिए कोई वैश्विक नुस्खा नहीं हो सकताः हालाँकि, पूर्व एशिया में जो उपयोगी साबित हुआ, ज़रूरी नहीं कि वह लैटिन अमेरिका में भी उपयोगी हो।

- *जापानः* जापान ने लंबे समय तक विकासपरक देश के रूप में काम किया है। 1870 वाले दशक के आते-आते वहाँ 'सुशिक्षित, राष्ट्रभक्त व्यवसायियों और व्यापारियों का एक समूह था और ऐसी सरकार अस्तित्व में आ चुकी थी जो आर्थिक आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही थी।'[17] इसके बाद किए गए अनेक सुधारों ने एक आधुनिक देश की अधोसंरचनात्मक बुनियाद रखी, जिसमें एक एकीकृत मुद्रा, रेल लाइन, सार्वजनिक शिक्षा और बैंकिंग कानूनों की स्थापना हो सकी। सरकार ने कपड़े से लेकर जहाज निर्माण पर केंद्रित राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों की स्थापना की, और उन्हें चलाया। इसने कई औद्योगिक उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर घरेलू उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया। दूसरे विश्व

विकासपरक देशों की एक अन्य विशेषता औद्योगिक नीतियों के उनके उस सन्धान से जुड़ी है जिसमें वे तुलनात्मक लाभ का 'प्रबंधन' करते हुए समन्वय संबंधी समस्याओं और बाह्य कारकों से निपटते हैं।

किसी भी विकासपरक राज्य के लिए कीमतों को दुरुस्त करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को दुरुस्त करना। ये लोक-केंद्रित, अवसरों को बढ़ावा देने वाली और नकारात्मक जोखिमों से बचाव करने वाली भी होनी चाहिए

युद्ध की समाप्ति के बाद से जापान सहायता स्वीकार करने वाले के बजाए एक दानदाता देश में रूपांतरित होता गया, जो एक मूलभूत बदलाव है (बॉक्स 3.3)।

- *कोरियाई गणराज्यः* 1960 से 1980 के दौरान कोरिया गणराज्य ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। 1961 के बाद सरकार ने सुधारों की एक श्रृंखला के ज़रिए व्यावसायिक वर्ग पर प्रभुत्व कायम किया। इनमें राज्य की संस्थागत एकजुटता को मज़बूत करने वाले उपाय शामिल थे, जैसे आर्थिक नियोजन बोर्ड का गठन किया गया, अलबत्ता वित्त पर नियंत्रण की नीति पर विशेष बल रहा। इसके अलावा उसने ध्यान रखा कि राज्य की नीतियाँ अनुदानों की बंधक न बनें। आगे चलकर वह आयात प्रतिस्थापन से हटकर निर्यात प्रोत्साहन के नीतिगत बदलाव का मार्गनिर्देशन कर सका।[18]

दक्षिण के अन्य उभरते देशों ने ऐसी ही नीतियों का अनुसरण किया। सरकारों ने सर्वाधिक संभावना वाले क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की और समष्टि अर्थव्यवस्था (Macroeconomics) का प्रभावी तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित किया और नवाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने नीति सम्बन्धी प्राथमिकताएँ तय करके, चुनिंदा उद्योगों को बढ़ावा देकर, राज्य और बाज़ार के बीच की पूरकता को पोषित करते हुए, दीर्घकालीन सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध होकर, मज़बूत राजनीतिक नेतृत्व विकसित कर, अनुभव से सीखकर और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देकर सामाजिक अवसरों का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया।

नीति प्राथमिकताओं को तय करना

किसी भी विकासपरक राज्य के लिए कीमतों को दुरुस्त करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को दुरुस्त करना। ये लोक-केंद्रित, अवसरों को बढ़ावा देने वाली और नकारात्मक जोखिमों (downside risks) से बचाव करने वाली भी होनी चाहिए। नीतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत से ही उभरता है एक और महत्वपूर्ण मुद्दा– नीति निर्माण की प्रक्रिया को दुरुस्त करना, अधिशासकीय संस्थान और नीतियाँ गहराई से परस्पर जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा सफल नहीं हो सकता। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतिगत प्रक्रियाओं का प्रबंधन प्रभावी और जवाबदेह सरकारी ढाँचों में कार्यरत प्रतिबद्ध लोगों द्वारा ही हो। विकास के विभिन्न चरणों पर नीतियाँ भी बदलती हैं। उदाहरण के लिए शुरुआती चरण में कई देशों की प्राथमिकता में रोज़गार बढ़ाना और ग़रीबी उन्मूलन शामिल होता है।

- *इण्डोनेशियाः* 1970 के दशक के मध्य से, नई तेल संपदा से प्राप्त होने वाले राजस्व के सहारे, इण्डोनेशिया ने ग्रामीण विकास और कृषि पर विशेष ध्यान देकर आयात-प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (import-substituting industrialization) का पूरक तैयार किया (कृषि में रणनीतिक निवेशों के परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए देखें बॉक्स 3.4)। संतुलित प्रगति की इस रणनीति ने श्रम की माँग को बढ़ाया, इस तरह बेरोज़गारी में कमी आई और वास्तविक मज़दूरी में इज़ाफ़ा हुआ।[19] इसके बाद 1980 के दशक के मध्य में, जब तेल से प्राप्त होने वाली आय में कमी आनी शुरू हुई, तो इण्डोनेशिया ने कृषि में लगे अतिरिक्त श्रम को ज़्यादा मज़दूरी देने वाले विनिर्माण के कार्य में

बॉक्स 3.3

अकिहिको तनाका, अध्यक्ष, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी

जापान और त्रिकोणीय सहकार

उदयीमान देशों के उल्लेखनीय आर्थिक प्रदर्शन से उत्साहित होकर दक्षिण-दक्षिण सहकार और त्रिकोणीय सहकार (triangular cooperation) पिछले वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। वे उत्तर-दक्षिण सहकार के पूरक की अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे निकल गए हैं और अब कई विकासशील देशों के लिए नवाचार और ज्ञान की साझेदारी के अनिवार्य स्रोत बन चुके हैं।

दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहकार के चार विशेष गुण और प्रवीणताएँ (merits) हैं : ज़्यादा प्रभावी समाधान प्राप्त करने के लिए समकक्षों के बीच ज्ञान और अनुभव की साझेदारी से अर्जित हुए लाभ, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और अनुभव की साझेदारी, जो उत्तर-दक्षिण सहयोग लक्ष्यों के साथ समेकित हो, वास्तविक स्वामित्व को सम्मान, जिसमें दक्षिण चालक की भूमिका में है; नए दानदाताओं के रूप में विकासशील देशों का तेजी से उभरना।

जापान ने 1975 में दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहकार के महत्व को पहचाना और एक बड़े स्तर पर त्रिकोणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। जापान विकास के उसी तरह के पथ से गुजरा है, जिससे आज कुछ उभरते देश गुज़र रहे हैं। पहले जापान केवल मदद प्राप्तकर्ता देश था, फिर वह प्राप्तकर्ता होने के साथ-साथ उदीयमान दानदाता की भूमिका में कई साल रहा, और अंततः मात्र दानदाता और ओ.ई.सी.डी. (आर्थिक सहकार एवं विकास संगठन) के 1964 में पहले एशियाई सदस्य के रूप में स्थापित हुआ।

विकास के इस रास्ते ने जापान को विश्वास दिलाया कि विकासशील देशों के बीच विकास अनुभव, ज्ञान और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की साझेदारी विकास सहयोग में एक बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकती है और इसके लिए दानदाताओं से मदद की ज़रूरत होती है।

ब्राज़ील, जापान और मोज़ाम्बीक के बीच सहयोग एक प्रमुख उदाहरण है। जापान ने ब्राज़ील को उसके उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र, जिसे सेराडो के रूप में जाना जाता है, विकसित करने के लिए सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप वह सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक बन सका। दोनों देशों ने अब मोज़ाम्बीक को वहाँ के विशाल सवाना विकसित करने के लिए साथ मिलकर सहायता देने का क्रम शुरू किया है।

विकास सहकार में एक केंद्रीय दृष्टिकोण के रूप में दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहकार को विस्तार देना अब एक उभरती हुई चुनौती है, जिसमें विकासकर्ताओं की बढ़ती संख्या के बीच सहायता के बिखराव को टालना भी एक चुनौती है।

बॉक्स 3.4

कृषि में निवेश

कृषि क्षेत्र में रणनीतिक निवेशों का परिवर्तनकारी प्रभाव हो सकता है। फसलों से उच्च उत्पादन हासिल होने से न केवल किसानों का जीवनस्तर ऊपर उठता है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में वस्तुओं और सेवाओं की माँग में भी वृद्धि होती है और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होते हैं। इससे खाद्यान्न की कीमतें भी घटने की गुंजाइश बनती है, जिससे भोजन पर होने वाला घरेलू खर्च कम होता है और अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रकों के लिए बाज़ार निर्मित होते हैं।

कृषि अनुसंधान एक सार्वजनिक साधन है और इसमें निजी क्षेत्र की सहायता अमूमन कम रहती है। इसलिए, सरकारें इस क्षेत्र में उपयोगी सहयोग कर सकती हैं। कुछ अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में हाल में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि में सार्वजनिक व्यय बढ़ाना प्रगति को प्रोत्साहित करने में विशेष रूप से सहायक होता है। कृषि सम्बन्धी खर्च को अनुसंधान और ग़ैर-अनुसंधान खर्चों में बाँटकर देखने से पता चलता है कि अनुसंधान सम्बन्धी खर्च विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। इसके अलावा, कृषि प्रसार सेवाएँ और सिंचाई व्यवस्था जैसे सार्वजनिक कार्य भी लाभकारी हैं।

चीन की कृषि सम्बन्धित अनुसंधान और विकास प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी है। चाइनीज़ एकेडेमी ऑफ़ एग्रीकृचरल साइंस, विभिन्न विश्वविद्यालयों और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ़ साइंस उसके अनुसंधान केंद्र हैं, इनके अधीन कुल मिलाकर 1100 अनुसंधान संस्थान हैं। आज चीन अफ्रीकी देशों के साथ दक्षिण-दक्षिण सहकार का अग्रणी बना हुआ है, इनमें से अनेक देश चीनी अनुसंधान से लाभ उठा रहे हैं।

कृषि सम्बन्धी प्रौद्योगिकी तो ब्राज़ील की भी एक ताकत है। वर्ष 2006 में लैटिन अमेरिका के कृषि अनुसंधान का तकरीबन 41% खर्च वहीं हुआ था। द सिस्टम फॉर एग्रीकृचरल रिसर्च एंड इनोवेशन (एस.आर.पी.ए.) ने प्रति कामगार कृषि-दक्षता में तकरीबन चार गुना वृद्धि दर्ज करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सरकारी उपक्रम द ब्राज़ील एग्रीकृचरल रिसर्च कॉर्पोरेशन कृषि सम्बन्धी रकबा बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। इसी तरह, ब्राज़ील के कृषि सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम संहवनीयता को ध्यान में रखकर विकसित किए गए। उदाहरण के लिए किसानों को उचित दाम और कर्ज सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए स्वयं को पात्र बनाने के लिए क्षेत्रीयता कानूनों (zoning laws) का सम्मान करना अनिवार्य है। एक अन्य कार्यक्रम मॉडेरैग्रो (Moderagro) किसानों को कर्ज़ के ज़रिए अपनी खेती को दुरुस्त करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। इसी तरह प्रोडूसा (Produsa) ऐसी खेतिहर ज़मीन में पौधा रोपण के लिए कर्ज उपलब्ध कराता है, जो परती (degraded) हो गई हों और प्रॉपलोरा (propflora) कर्ज़ के ज़रिए वनों में वृक्षारोपण (खासतौर से पॉम ऑयल) को बढ़ावा देता है।

स्रोत: ओ.ई.सी.डी. 2006, 2011a, फ़्रैन एवं सौरकार (2006); फ़्रैन नेस्टोरोवा एवं ओलोफिनबियी 2010; स्टैड्स एवं बीटेमा 2009; विश्व बैंक 2012a।

लगाकर, आयात प्रतिस्थापन से हटकर बाह्य-उन्मुख औद्योगीकरण की ओर रुख किया। 1990 के दशक की शुरुआत तक, जब इस अतिरिक्त श्रम की आपूर्ति पूरी तरह खप चुकी थी, प्राथमिक रूप से मज़दूरी दर में वृद्धि के ज़रिए ग़रीबी में कमी जारी रही। इस प्रकार, प्रत्येक चरण में एक लोक-केंद्रित दृष्टिकोण शामिल था, जिसमें बदलती स्थितियों के हिसाब से प्रगति की रणनीति में बदलाव किया गया।

सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा

परंपरागत आर्थिक एवं सामाजिक नीति चिंतन, जिसको 'वाशिंगटन सर्वानुमति' ने भी रेखांकित किया है, आर्थिक प्रगति के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में मूलभूत आर्थिक अधिकार प्राप्त करने पर बल देता रहा है। इसका तर्क है कि इसी के फलस्वरूप अन्य मानव विकास सुधार होते जाएँगे। वहीं, दूसरी ओर, मानव विकास दृष्टिकोण की माँग होती है कि ग़रीब लोगों के जीवन में सुधार को टाला नहीं जाना चाहिए। इसी लिए जनता-हितैषी विकासपरक राज्य वे हैं, जिन्होंने कई आधारभूत सामाजिक सेवाओं में विस्तार किया है (बॉक्स 3.5)।[20] इस दृष्टिकोण के तहत, लोगों की क्षमता वृद्धि में निवेश– स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य लोक सेवाओं के जरिए– विकास प्रक्रिया का कोई उपबंध (appendage) नहीं है, बल्कि इसका एक अनिवार्य हिस्सा है।

सार्वजनिक खर्चों के स्तर के अलावा इन्हें खर्च करने की प्रणाली और उनकी प्रभावशीलता व संरचना, सभी मिलकर क्षमता के विस्तार और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को प्रभावित करते हैं। विभिन्न देशों के बीच सार्वजनिक खर्च के होने वाले प्रभाव अलग-अलग हैं। एक वैश्विक अंतर-देशीय विश्लेषण स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रति व्यक्ति खर्च और वर्तमान मानव विकास उपलब्धियों के बीच एक सकारात्मक सम्बन्ध प्रदर्शित करता है (रेखांकन 3.2)। इसके अलावा, स्वास्थ्य पर पहले के समय किए गए प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च का बच्चों की बेहतर जीवितता और पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट से जुड़ाव है (रेखांकन 3.3)। स्वाभाविक रूप से ऐसे परिणाम किसी देश के विकास के स्तर और धन को खर्च करने के तरीके पर निर्भर करते हैं। अनावश्यक खर्चों और लापरवाहीपूर्वक उधार लेने की होड़ से बचाव के लिए देशों को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए।

इस बात को लेकर काफ़ी बहस हो चुकी है कि क्या सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश को बढ़ाता है या उसे घटाता है। दोनों तरह के परिणाम सम्भव हैं, और यह विकासशील देशों में सार्वजनिक पूँजी के उपयोग की विविधता पर निर्भर है। दक्षिण एशिया और सब-सहारा अफ्रीका में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विकास के मौजूदा कम स्तर से लेकर पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के उच्च प्रदर्शन वाले देशों तक, यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत है कि सार्वजनिक निवेश और उसकी बुनावट, दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- *बांग्लादेश:* समय के साथ सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के साथ-साथ राजकोषीय घाटे से बचकर, जिसने क्षेत्र के बाकी देशों को काफ़ी परेशान किया,

लोगों की क्षमता वृद्धि में निवेश– स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य लोक सेवाओं के जरिए–विकास प्रक्रिया का कोई उपबंध नहीं है, बल्कि इसका एक अनिवार्य हिस्सा है

बॉक्स 3.5

पूर्वी यूरोप और मध्य एशियाः जहाँ उत्तर और दक्षिण का मिलन होता है

उदीयमान दक्षिण को उत्तर से जोड़ने का काम कर रहा है रूपांतरित होता पूर्व। विश्व की कुल आबादी और निर्गत में पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया की हिस्सेदारी 5% है। केंद्रीय नियोजन वाली अर्थव्यवस्थाओं से बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं तक के तेज़ संक्रमण के प्रबन्ध का इनका अनुभव दूसरी जगहों पर विकासशील देशों के लिए उपयोगी नीति-सबकों से भरा हुआ है। रूपान्तरण का पहला चरण मानव विकास और जीवन स्तर में तीखी गिरावट के साथ शुरू हुआ। हालाँकि बाद में हर देश ने अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के तहत इससे उबरने में सफलता हासिल की, मोटे तौर पर समूचे अनुभव ने सामाजिक समावेशन के महत्व और राज्य की जवाबदेही भरी भूमिका को रेखांकित किया।

यूरोप और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल की *क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011*, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में सामाजिक बहिष्करण (social exclusion) के मापकों और मानव विकास सूचकांक मानों के बीच एक नकारात्मक सम्बन्ध को प्रदर्शित करती है। यह बताती है कि व्यक्तिगत बहिष्करण के हालात पैदा करने वाले जोखिमों में आर्थिक परिवर्तों (variables) की एक तिहाई से कम भूमिका होती है। श्रम अनौपचारिकता, भ्रष्टाचार और व्यापार शुरू करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया उच्च सामाजिक बहिष्करण के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके विपरीत, चूँकि रोज़गार समावेशन में सहायक होता है, श्रम बाज़ार की संस्थाएँ, जो कार्यशील और पहुँच के भीतर हैं, महत्वपूर्ण पाई गईं।

परिवर्तन के दो दशकों की सबसे प्रमुख सीख यह है कि राज्य की भूमिका समाजों और समावेशी विकास के लिए माहौल बनाने में अहम होती है। राज्य द्वारा अपनी जवाबदेही के क्षेत्रों को अचानक छोड़ देने या सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कंपनियों को बहुत तेज़ी से निजी क्षेत्र के हवाले करने पर ज़ोर देने का विचार लंबी अवधि में समाज के लिए बहुत महँगा साबित हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि इन ज़िम्मेदारियों को बरकरार रखने का मतलब पुराने ढाँचे को जस का तस बनाए रखना भी नहीं है। इसके विपरीत, अधिशासन की गुणवत्ता और सरकारों की कार्यकुशलता सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूती देने वाले सुधार तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को सीमित करने वाले सुधार आवश्यक हैं।

क्षेत्र के अनेक देश अब यूरोपीय संघ के सक्रिय सदस्य हैं। वे, और क्रोएशिया, कज़ाकिस्तान, रूसी संघ और तुर्की, साथ मिलकर उदीयमान दानदाता भी बन गए हैं। 2011 में उनकी सहायता राशि, 4 बिलियन डॉलर को पार कर गई थी। ये उदीयमान दानदाता समान विरासतों वाले, या उससे परे के, देशों के साथ द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय ज्ञान के आदान-प्रदान में सक्रिय हैं। हाल के वर्षों में रोमानिया ने मिस्र और ट्यूनीशिया के साथ चुनाव कराने का अनुभव साझा किया, पोलैण्ड ने लघु एवं मध्यम आकार के कारोबार के विकास के लिए इराक की मदद की है। चेक गणराज्य ने पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन पर अज़रबैजान के साथ सहयोग किया है और स्लोवाकिया ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में मोंटेनीग्रो और मॉल्दोवा को सहायता दी है।

स्रोत- एच.डी.आर.ओ., यू.एन.डी.पी. 2011b

बांग्लादेश ने निरंतर प्रगति की है।

- *भारतः* भारत ने सामाजिक सेवाओं और ग्रामीण विकास पर केंद्रीय सरकार के खर्च को 2006-2007 के 13.4% से बढ़ाकर 2011-2012 में 18.5% कर दिया।[21] और कुल खर्च के अनुपात में सामाजिक खर्च 2006-2007 के 21.6% की तुलना में 2009-2010 में बढ़ाकर 24.1% हुआ और 2011-12 में यह 25% तक पहुँच गया।

चुनिंदा उद्योगों को सम्पोषण

तुलनात्मक लाभ के गतिशील दृष्टिकोण को अपनाकर सरकारें बाज़ार-अनुशासित निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर सकती हैं, इस तरह उन क्षेत्रकों को सम्पोषित करते हुए, जो अधूरे बाज़ारों के कारण अन्यथा उभर नहीं पाते।[22] हालाँकि यह ज़रूर है कि इसमें रिश्तों का अनुचित लाभ उठाने (rent seeking) और चहेतों को फ़ायदा पहुँचाने सरीखे राजनीतिक खतरे जुड़े हैं। इसके बावजूद इसने दक्षिण के अनेक देशों को सक्षम बनाया कि वे अपने यहाँ के अक्षम और विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में असमर्थ करार दिए जा चुके उद्योगों में नई जान फूँककर उन्हें निर्यात सफल उद्योग बना दें। इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में खुलापन बढ़ने के बाद यह हो सका।

> तुलनात्मक लाभ के गतिशील दृष्टिकोण ने अनेक देशों को सक्षम बनाया कि वे अपने यहाँ के अक्षम और विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में असमर्थ उद्योगों में नई जान फूँककर उन्हें निर्यात सफल उद्योग बना दें। इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में खुलापन बढ़ने के बाद यह हो सका

- भारतः 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने दशकों तक राज्य की अगुआई वाली आयात-प्रतिस्थापक (support-substituting) औद्योगीकरण की एक रणनीति अपनाई। इसने निजी क्षेत्र से दूरी बनाए रखी जबकि टेक्नोक्रैटों को व्यापक शक्तियाँ दे दीं जिन्होंने व्यापार और निवेश को नियंत्रित किया और एक ऐसा तंत्र विकसित किया जो नौकरशाही की जटिलताओं से लदा हुआ था (लाइसेंस राज)।[23] हालाँकि इन वर्षों के दौरान मानव क्षमता को निर्मित करने और विश्व-स्तरीय उच्च शिक्षा में निवेश करने की सोची-समझी नीति तो जारी रही, लेकिन संभवतया प्राथमिक शिक्षा को नजरंदाज़ भी किया गया। 1990 के दशक के सुधारों के बाद इन निवेशों ने तब प्रतिफल दिया जब भारत उदीयमान सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम उद्योगों में कुशल कर्मियों की अपनी पूँजी के उपयोग में आश्चर्यजनक रूप से सक्षम हो गया। इसने 2011-12 तक 70 अरब डॉलर की निर्यात आय उत्पन्न की। इन वर्षों के दौरान जो एक और उद्योग विकसित हुआ, वह फार्मास्युटिक्स था। भारत ने उत्पादों को नहीं, बल्कि केवल प्रक्रिया को पेटेंट देने की नीति जारी रखी, जिसने कंपनियों को इंजीनियरों को वापस बुलाने के लिए प्रोत्साहित किया और भारत प्रजातीय दवाओं में विश्व का अगुआ बन गया।[24] क्षमता निर्माण की ऐसी ही कहानी भारत के आटोमोबाइल, रसायन और सेवा उद्योगों की है, जो अब तेज़ी से विश्व बाज़ार में अपनी पकड़ मज़बूत बना रहे हैं।
- *ब्राज़ीलः* लंबे समय तक ब्राज़ील ने अंतर्मुखी आर्थिक रणनीतियों (inward-oriented economic

strategies) के साथ प्रयोग किया। इस दौरान वे कंपनियाँ, जिन्हें बड़े घरेलू बाज़ार से फ़ायदा मिलता था, उन्हें निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, तो वे दशकों से विकसित अपनी क्षमता पर भरोसा करने में सक्षम हो गईं। उदाहरण के लिए एम्ब्रेयर आज 120 सीटों तक की क्षमता वाला जेट वाणिज्यिक विमान बनाने वाली विश्व की प्रमुख कंपनी है।[25] देश के इस्पात और जूता उद्योग ने भी घरेलू नवाचार की क्षमता को बढ़ाने वाले अनुसंधान और विकास की क्षमताओं के साथ सार्वजनिक स्वामित्व के तहत विकास किया।

रोज़गार निर्माण को प्राथमिकता

व्यावहारिक नीतियाँ, जिनका उद्देश्य सुरक्षित और लाभदायक नौकरियाँ पैदा करना हो, आर्थिक प्रगति और मानव विकास के बीच की कड़ी को मज़बूत कर सकती हैं। एशिया के साक्ष्य बताते हैं कि जिन देशों में उच्च प्रगति दर और ग़रीबी में कमी एक साथ होती है, वहाँ रोज़गार का भी विस्तार होने लगता है। यह बात 1970 के दशक में मलेशिया और थाईलैण्ड, 1980 के दशक में चीन और इण्डोनेशिया और 1990 के दशक में भारत और वियतनाम के लिए सही साबित हुई।[26] तेज़ विकास करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की पहली पीढ़ी– हाँगकांग, चीन (एस.ए.आर.), कोरिया गणतंत्र, सिंगापुर और चीन के ताइवान प्रांत– ने उत्पादकता और मजदूरी को बढ़ाते हुए 1990 के दशक से पहले रोज़गार को 2% से 6% की वार्षिक दर से बढ़ाया। विकास की इस पद्धति का नेतृत्व अक्सर छोटे स्तर की कृषि ने किया जैसे चीन के ताइवान प्रांत में हुआ। हाँगकांग, चीन (एस.ए.आर.), कोरिया गणराज्य और सिंगापुर में श्रम-सघन निर्यात-उन्मुख विनिर्माण से भी ऐसा ही किया गया।[27]

कुछ एशियाई देशों, जैसे कोरिया गणतंत्र और फिर बाद में थाइलैण्ड, की सफलता ने कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर सब-सहारा अफ्रीका के लिए सीख का काम किया क्योंकि उन्होंने विकास के समान स्तर पर रहते हुए रोज़गार सृजन की दर दो से तीन गुना ज़्यादा हासिल करके दिखाई थी। उदाहरण के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान अफ्रीका की श्रम शक्ति में तो 9.1 करोड़ लोग जुड़े हैं, जबकि मजदूरी देने वाले क्षेत्रकों में उसने केवल 3.7 करोड़ नौकरियाँ पैदा की हैं।[28] विनिर्माण और कृषि के श्रम-सघन उप क्षेत्रकों और इसी तरह रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और निर्माण के क्षेत्रों में प्रसक्रिय सरकारी नीतियों के साथ अफ्रीका में 2020 तक 7.2 करोड़ नौकरियाँ पैदा होने का अनुमान है। मौजूदा प्रगति स्तर से यह 1.8 करोड़ रोज़गार ज़्यादा होगा।[29] हालाँकि इन नीतियों को न केवल युवाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश की बल्कि आर्थिक विविधीकरण पर लक्षित आधारभूत

रेखांकन 3.2

वर्तमान मा.वि.सू. मान और पूर्व में किए गए सार्वजनिक खर्चों में सकारात्मक सम्बन्ध है

स्रोत : एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ एवं विश्व बैंक (2012a)

रेखांकन 3.3

..उसी तरह बाल जीवितता की मौजूदा स्थिति और स्वास्थ्य पर किए गए पूर्ववर्ती सार्वजनिक खर्च भी सम्बन्धित हैं

स्रोत : एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ विश्व बैंक (2012a) पर आधारित हैं।

संरचनाओं में निवेश और निजी कारोबार की बाधाओं, जैसे वित्त की कमी और परेशान करने वाले नियमों, को हटाने की भी ज़रूरत होगी।[30]

- *मॉरिशस:* श्रम-सघन प्रगति की संभावनाएँ तब ज़्यादा होती हैं, जब देशों में औद्योगीकरण अपेक्षाकृत निचले

स्तर का होता है। पिछले दो दशकों के दौरान मॉरिशस के प्रदर्शन के विश्लेषण पर आधारित एक अध्ययन में बताया गया कि पहले दशक(1982-1990) के दौरान नए रोज़गार और पूँजी संचयन द्वारा आर्थिक वार्षिक प्रगति का 80% हासिल किया गया।[31] नौकरियों में 5.2% सालाना वृद्धि के साथ बेरोज़गारी 20% से गिरकर 3% पर आ गई। हालाँकि अगले दशक (1991-1999) में हुई आर्थिक प्रगति पूँजी संचयन के ज़रिए कम और श्रमिकों की उत्पादकता वृद्धि द्वारा ज़्यादा प्रचालित थी– जो परिणाम था मानव क्षमताओं में वृद्धि के लिए किए गए निवेश का।[32]

- *बांग्लादेशः* 1980 के दशक की तुलना में 1990 के दशक में ग़रीबी में तेजी से गिरावट[33] आने का कारण, श्रम-सघन निर्यात (जैसे वस्त्र और मछली) और ग्रामीण इलाकों में ग़ैर-कृषि क्षेत्रों में रोज़गार में बढ़ोतरी (लघु एवं कुटीर उद्योग, निर्माण और अन्य ग़ैर-व्यापार योग्य सेवाओं में) दोनों ही थे। इस बेहतरी को बल देने में इस क्षेत्रक में हुए उत्पादकता-सुधार का हाथ तुलनात्मक रूप से कम था, और फसल उत्पादन की बढ़त, अदायगियों के अंतः प्रवाह की बढ़त और बढ़ते निर्यात से उपजी माँग का योगदान अधिक।[34]
- *रवाण्डा :* रोज़गारों में विस्तार का हमेशा निर्यात-मुखी विनिर्माण से प्रेरित होना ज़रूरी नहीं। रवाण्डा में पिछले दशक के दौरान पर्यटन सेवाओं में नौकरियों का विस्तार हुआ है। इस क्षेत्र की निर्यात आय, जो कॉफ़ी और चाय के निर्यात से होने वाली आय से अधिक है, तकरीबन 75000 लोगों को रोज़गार देती है।[35]
- *युगाण्डाः* रवाण्डा की तरह युगाण्डा में भी 1990 के दशक में हुई उच्च प्रगति बड़े पैमाने पर श्रम के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में आय में बढ़ोतरी से हुई,जो ग़रीबी को कम करने में मददगार साबित हुई। श्रम का यह इस्तेमाल नकदी फसलों वाले क्षेत्र के साथ विशेषकर हुआ क्योंकि वैश्विक मूल्य-वृद्धि और कृषि-व्यापार की शर्तों में हुए सुधार ने इस क्षेत्रक में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया था।[36]
- *थाइलैण्डः* कृषि योग्य भूमि से सम्पन्न विकासशील देशों में कृषि में लगातार स्थायी प्रकृति के रोज़गार पैदा होते रह सकते हैं, बावजूद इसके कि कुल निर्गत में इसका अंश समय के साथ घटता जाता है। थाइलैण्ड में ऐसा ही हुआ, जिसकी 1960 के दशक की रोज़गार पद्धति आज के कई सब-सहारा अफ्रीकी देशों जैसी थी। थाइलैण्ड तब से विनिर्माण का एक शक्तिशाली केंद्र बन चुका है। लाखों स्थायी नौकरियाँ ग़ैर-विनिर्माण क्षेत्रकों, जैसे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी व निर्माण और इसी तरह वाणिज्यिक खेती में भी पैदा होती रही हैं। कृषि में स्थायी नौकरियों की संख्या 1960 की 519,000 से बढ़कर 2008 में तकरीबन 30 लाख हो गई। 1990 के दशक में अकेले थाइलैण्ड ने स्थायी नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी में 11% अंकों का इज़ाफ़ा किया है (जैसा कि ब्राज़ील ने 1970 से 1988 के बीच किया)।[37]
- *इण्डोनेशियाः* 1997 के एशियाई वित्तीय संकट से पहले इण्डोनेशिया उच्च श्रम-सघन प्रगति के पथ पर सफलतापूर्वक चलने के कारण अलग ही दिखाई देता था। संकट से पहले दो दशकों तक वास्तविक मजदूरी में सालाना औसतन 5% की बढ़ोतरी हुई। अकेले 1990 से 1996 के बीच औपचारिक ग़ैर-कृषि रोज़गार 28.1% से 37.9% तक बढ़ा और कृषि में लगे कार्यबल की हिस्सेदारी कुल कार्यबल के 55.1% घटकर 43.5% हो गई।[38] संकट के बाद, जब विकास के लाभों की दिशा पलटी, तो कृषि श्रमिकों की ग़रीबी में आनुपातिक बढ़ोतरी सबसे कम थी।[39]

देशों को इस बात के लिए सजग होना होगा कि विकास की प्रकृति (और विकास के वाहक क्षेत्रकों में श्रम की तीव्रता का इस्तेमाल) आर्थिक बदलावों के साथ ही क्रमिक रूप से विकसित होती है और तब उन्हें लोगों के कौशल विकास के लिए भी समान निवेश की ज़रूरत होगी

जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण भी बताते हैं, दशक-दर-दशक प्रगति के प्रतिमान (pattern) अपवाद रूप में ही लगातार ग़रीब-हितैषी बने रह पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकासपरक बदलाव उत्पादन की संरचना में परिवर्तन का पर्याय है और नौकरियाँ पैदा करने के मामले में विभिन्न क्षेत्रकों की क्षमता भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, कुशल और अकुशल नौकरियों को भिन्न तरह के पूरक आगतों (inputs) की ज़रूरत होती है, जैसे औपचारिक शिक्षा और उद्योग-मुखी प्रशिक्षण। व्यापक मुद्दा यह है कि मानव विकास उन्मुख नीतियों के लिए संवृद्धि और संभावनाओं के समतापरक विस्तार, दोनों की ज़रूरत होती है। विकासपरक देशों को इस बात के लिए सजग होना होगा कि विकास की प्रकृति (और विकास के वाहक क्षेत्रकों में श्रम की तीव्रता का इस्तेमाल) आर्थिक बदलावों के साथ ही क्रमिक रूप से विकसित होती है और तब उन्हें लोगों के कौशल विकास के लिए भी समान निवेश की ज़रूरत होगी।

राज्य-बाज़ार पूरकताओं का पोषण

बाज़ार और सरकारें, दोनों ही असफल हो सकते हैं, लेकिन जब वे मिलकर काम करते हैं तो वहाँ एक खास संगति पैदा होती है। विकास के मोर्चे पर होने वाली प्रगति को केवल बाज़ार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ बाज़ार न केवल असफल साबित होते हैं, बल्कि ऐसी भी संभावना होती है कि विकास के शुरुआती चरणों में उनका अस्तित्व ही न हो। ज़्यादातर सफल उन्नतशील देशों ने औद्योगिक और इससे जुड़ी नीतियों को लागू किया, जिन्होंने निजी क्षेत्र की क्षमताओं को इस तरह बढ़ाया कि वह मानव विकास में योगदान कर सकें, विशेषकर नए क्षेत्रकों में नौकरियाँ पैदा करके।

- *तुर्कीः* तुर्की में राज्य ने ऐसी उपयुक्त आर्थिक परिस्थितियाँ पैदा की हैं जिन्होंने काफ़ी संख्या में लोगों को रोज़गार दे सकने वाले विनिर्माण क्षेत्रक तथा

फ़र्नीचर, टेक्सटाइल, खाद्य व ऑटोमोबाइल निर्माण को बढ़ावा दिया है। उसके बाद से निर्यात होने वाले उत्पादों की प्रकृति में बदलाव आया है। अब तुर्की से निर्यात होने वाले उत्पाद पहले से ज़्यादा प्रसंस्कृत हैं, उनमें उच्च तकनीक और कुशल श्रम का इस्तेमाल होता है।[40]

- *ट्यूनीशियाः* ट्यूनीशिया ने 1970 के दशक के शुरुआत से निर्यात उन्मुख उद्योगों, विशेषकर कपड़ों के उत्पादन के लिए, घरेलू और विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन पर भरोसा किया है।[41] उद्योग-सरकार सम्बन्धों के विभिन्न प्रकारों ने तकनीकी उन्नयन को बढ़ाया और उद्योग समूहों को प्रोत्साहित किया। आज यूरोपीय संघ को वस्त्र निर्यात करने वाले शीर्ष पाँच देशों में ट्यूनीशिया शामिल है।[42] पड़ोसी देशों से वहाँ जाने वालों को इलाज उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्यात की भी क्षमता है,जो ट्यूनीशिया के निजी स्वास्थ्य क्षेत्रक के निर्गत के एक तिहाई के बराबर होगी।[43]
- *चिलीः*1990 के दशक में लोकतंत्र की बहाली के बाद से चिली ने उन क्षेत्रकों में निवेश और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा दिया है, जहाँ अपनी अन्तर्निहित (intrinsic) क्षमताओं के कारण देश तुलनात्मक लाभ की स्थिति में है। इसने निजी कंपनियों और विश्वविद्यालयों के बीच नवाचार आधारित संघों के संचालन और स्थापना को छूट (subsidy) दी और अन्य नवाचार-संवर्द्धन गतिविधियों में शामिल हुआ।[44]

दीर्घकालिक विकास और सुधार के लिए वचनबद्धता

स्थायी रूपान्तरण को हासिल करना एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, जिसके लिए देशों को विकास का तारतम्यपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। कुछ तकनीकी अथवा प्रबंधकीय समाधान कुछ समय के लिए आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वे अपर्याप्त होते हैं।

- *चीनः* 1970 के दशक के आखिर में बाज़ार उन्मुख सुधारों के बाद से चीन ने जटिल और अन्तर्सम्बद्ध बदलावों का अनुभव किया हैः नियंत्रित से बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था तक; गाँवों से शहरों तक; कृषि से विनिर्माण व सेवाओं तक, अनौपचारिक से औपचारिक आर्थिक गतिविधियों तक; काफ़ी हद तक खासी आत्मनिर्भर प्रांतीय अर्थव्यवस्थाओं के बिखरे से समूह से एक अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था तक; और एक ऐसी अर्थव्यवस्था से, जिसने अपने आपको विश्व बाज़ार से दूर रखा था, वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बहुत बड़ी शक्ति बनने तक बदला।[45] जिस बड़े स्तर पर ये बदलाव हुए, उनके लिए ज़रूरी था कि राज्य प्रतिबद्धता के साथ दीर्घ-कालिक परिकल्पना के साथ ज़रूरी संस्थाओं और क्षमताओं के निर्माण में जुटा रहे। नेतृत्व ने पुराने ऐसे लोगों को हटा दिया जो ऐसे परिवर्तन का विरोध कर सकते थे, और उनकी जगह नौकरशाही में अपेक्षाकृत युवा और अधिक शिक्षित लोगों को लाया गया। 1988 आते-आते स्थिति यह थी कि ज़िला स्तर से ऊपर के 90%अधिकारी ऐसे थे जो 1982 से नियुक्त किए गए थे।[46] क्षमता को उन्नत करना वहाँ अभी भी प्राथमिकता है और अधिकारियों की शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ा है। चीन की नौकरशाही को एक ठोस परिणाम-उन्मुखी नीयत से तैयार किया गया है, उनके करियर की प्रगति को आधुनिकीकरण और आर्थिक प्रगति के केंद्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ जोड़ा गया है।[47]

लोक-हितैषी विकासपरक राज्यों को मज़बूत राजनीतिक नेतृत्व की ज़रूरत होती है, जो समता और संवहनीयता के लिए वचनबद्ध हो। प्रभावी नेतृत्व नीति निर्माताओं के दीर्घकालीन लक्ष्यों को संगत बनाता है और मानव विकास के लिए सामाजिक एकीकरण और व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य के काम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मतदाता वर्ग को सक्षम बनाता है। इसके लिए विकास के एक संतुलित दृष्टिकोण और संकटों को अवसरों में बदलने की क्षमता की ज़रूरत होती है, ताकि व्यापक आर्थिक सुधार लागू किए जा सकें।

लोक-हितैषी विकासपरक राज्यों को मज़बूत राजनीतिक नेतृत्व की ज़रूरत होती है, जो समता और संवहनीयता के लिए वचनबद्ध हो

- *ब्राज़ीलः* जिस समय एक विकासपरक राज्य के रूप में ब्राज़ील का रूपान्तरण (1994 के आसपास) शुरू हुआ, उस समय तक सरकार 'रियल प्लान' के ज़रिए अति-मुद्रास्फीति (hyperinflation) को नियंत्रित करने के लिए व्यापक आर्थिक सुधारों को लागू कर चुकी थी और व्यापार उदारीकरण की 1988 में शुरु हुई प्रक्रिया को सम्पन्न कर चुकी थी, जो सीमा शुल्क में छूट व अन्य बाधाओं को हटाने के साथ शुरू हुए थे।[48] व्यापार का खुलापन और विवेक के साथ तैयार की गई मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ इसके बाद शुरु हुईं, और साथ ही नवाचारी सामाजिक कार्यक्रम, जिसने ग़रीबी और आय असमानता को कम किया।

बड़े और जटिल समाजों में किसी नीति विशेष का परिणाम अनिवार्य रूप से अनिश्चित होता है। इसलिए विकासपरक राज्यों को व्यावहारिक होने और विभिन्न विकल्पों का परीक्षण करने की ज़रूरत होती है।

- *चीनः* चीन में हुए आर्थिक सुधार और उसका खुलना परिणाम है, आर्थिक निर्णयों में लोगों की भागीदारी के रास्ते की बाधाओं को कम करने की नीयत से 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में किए गए स्पष्ट नीतिगत चयन का। लेकिन वे संस्थागत नवाचार,जिन्होंने चीन के बदलावों को आधार दिया, वे देंग श्याओपिंग के दृष्टिकोण से मिलते-जुलते थे, जिसमें 'पत्थरों का अहसास करते हुए नदी को पार करने' की बात कही गई थी।[49] वर्ष 1979 से 1989 के बीच चीन के

कम से कम 40% राष्ट्रीय अधिनियम प्रायोगिक माने गए थे। कृषि सुधारों के पहले चरण में किसानों को भूमि पट्टे पर देने, निर्धारित कीमतों पर उत्पादन का एक हिस्सा राज्य को देने और बाकी हिस्सा बेचने की अनुमति दी गई। इसके बाद ग्रामीण उद्यमों और नगर-क्षेत्र को विस्तार दिया गया।[50] क्रमशः सुधार करने का यह दृष्टिकोण चीनी नेताओं की व्यावहारिकता को दर्शाता है। इस व्यवहारिकता का एक अन्य कारण यह धारणा भी थी कि रूपांतरण के लिए योजना बनाना ही असंभव है– जो योजना बनाने के समूचे तंत्र के ही प्रति अविश्वास दिखाता था।

प्रचालक 2 : वैश्विक बाज़ारों का दोहन

दक्षिण के तेज़ी से विकास करने वाले देशों का एक सामान्य तत्व रहा है लोगों की क्षमता और कंपनियों की दक्षताओं को मज़बूत करते हुए विदेशी बाज़ारों को गले लगाना। इसने उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक कीमतों पर पूँजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती आगतों (intermediate inputs) को प्राप्त करने के उपयुक्त बनाया; साथ ही वे विदेशी जानकारी और प्रौद्योगिकी को हासिल करने और उनका लाभ लेकर वैश्विक बाज़ार में माल बेचने के योग्य बने।[51] सभी नव औद्योगीकृत देशों ने एक रणनीति का पालन किया है– 'विश्व के बाकी देशों की अहम जानकारियों का आयात, और विश्व की ज़रूरतों के हिसाब से निर्यात।'[52] यह सच है कि कुछ देश लंबी अवधि के पूँजी प्रवाह या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से किनारा करके भी सफलतापूर्वक विकसित हुए हैं; बहुत कम ही देश ऐसे हैं जो अपना व्यापार-निर्गत अनुपात बढ़ाए बग़ैर भी विकास को बरकरार रख पाएँ हों, और ऐसे प्रमाण तो बिल्कुल ही नहीं हैं कि युद्ध के बाद वाले काल में अंतर्मुखी अर्थव्यवस्थाओं ने ज़्यादा खुली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में व्यवस्थित तरीके से तेज़ विकास किया हो।[53]

जैसे-जैसे देश विकसित होते हैं, वे व्यापार बाधाओं को हटाने के लिए उन्मुख होते हैं और ज़्यादा खुले बन जाते हैं

हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देश, व्यापार और निवेश सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने मात्र से ही तेज़ विकास हासिल कर सकता है। 1990 के दशक में कुछ प्रभावशाली अंतर-देशीय अध्ययनों में दिखाने का प्रयास किया गया कि बाज़ार को तेज़ी से खोलने से अपने आप उच्च आर्थिक विकास हासिल होगा। लेकिन इनमें बाद में प्रणाली सम्बन्धी महत्वपूर्ण सीमाएँ पाई गईं।[54] विशेषकर, औसत सीमा-शुल्क और ग़ैर-सीमा शुल्क सम्बन्धी बाधाओं के स्तर से विकास की पर्याप्त व्याख्या नहीं की जा सकती।[55]

दक्षिण के वास्तविक विकास अनुभवों ने एक ज़्यादा सूक्ष्म भेद वाली (nuanced) आम सहमति को प्रदर्शित किया है।[56] इस दृष्टिकोण में राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार तथा लोगों, अधोसंरचना, और संस्थाओं में निवेश करते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था से क्रमबद्ध और धीरे-धीरे एकीकरण के परिणामस्वरूप सफल एवं संवहनीय प्रगति होने की संभावना अधिक होती है।[57]

देशों के अध्ययनों ने पुष्टि की है कि आवश्यकता एक ऐसे पैकेज की है जिसमें व्यापार, विनिमय दर, राजकोषीय, मौद्रिक और संस्थागत नीतियों में हुए सुधारों के बीच अन्तर्क्रियाएँ शामिल हों।[58] हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि वृहत्तर सुधारों की आधारशिला पर किए गए व्यापार के उदारीकरण से ज़्यादा निर्णायक लाभ प्राप्त हुएः 1950 से 1998 के बीच, उदारीकरण के बाद के काल में, जिन देशों के लिए माना जाता था कि उन्होंने ऐसी नीतियों पर अमल किया है, उन्होंने 1.5 प्रतिशत अंक ज़्यादा विकास दर हासिल की, उनकी निवेश दरें 1.5-2 प्रतिशत अंक ज़्यादा थीं और उनके व्यापार-निर्गत अनुपात 5 प्रतिशत अंक ज़्यादा थे।[59]

जैसे-जैसे देश विकसित होते हैं, वे व्यापार बाधाओं को हटाने के लिए उन्मुख होते हैं और ज़्यादा खुले बन जाते हैं।[60] व्यापार के खुलेपन में हुए बदलाव और 1990 से 2010 के बीच मा.वि.सू. मान में हुए सापेक्ष सुधार के बीच पारस्परिक जुड़ाव पर मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय का विश्लेषण इस निष्कर्ष का समर्थन करता है (अध्याय 2 में बॉक्स 2.1 देखें)। ऐसा भी नहीं है कि जिन देशों ने व्यापार में खुलेपन को बढ़ाया, उनमें से सभी ने अपने समकक्षों की तुलना में मा.वि.सू. मान में बहुत बड़ा सुधार किया। लेकिन जिन्होंने भी मा.वि.सू. मान में बड़ा सुधार किया, उन्होंने आमतौर पर अपने व्यापार-निर्गत अनुपात औसत को बढ़ाया, या फिर उन्होंने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मूल्यों वाले व्यापार-सूत्रों के जुड़ाव का एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित किया। 95 विकासशील देशों और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं के एक नमूने में, 1990 से 2012 के बीच तेजी से मा.वि.सू. सुधारने की छवि वाले देशों के व्यापार-निर्गत अनुपात में हुई औसत वृद्धि ज़्यादा मामूली वृद्धि करने वालों की तुलना में तकरीबन 13 प्रतिशत अंक ज़्यादा थी।

जैसा कि अध्याय 2 के बॉक्स 2.1 में चर्चा की गई, तकरीबन सभी देश, जिन्होंने पिछले दो दशकों के दौरान मा.वि.सू. मान में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की, वे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा एकीकृत हो गए हैं। उच्च मानव विकास प्राप्त करने वाले चुनिंदा देशों के संदर्भ में, जिन पर इस अध्याय में चर्चा की गई है, सारणी 3.2 इसकी पुष्टि करती है; इन देशों ने 1990 से 2010 के बीच विश्व बाज़ार में अपने निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाकर वैश्वीकरण द्वारा दिए गए मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाया है। केवल मॉरिशस इस समूह का अपवाद है। वह निर्यात उन्मुखी विकास रणनीति अपनाने वाले दक्षिण के उन पहले देशों में से एक है, जिसकी विश्व निर्यात में हिस्सेदारी 2001 में अपने शिखर पर पहुँची।[61] ज़्यादा आबादी वाले देश जैसे-जैसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपने जुड़ाव को गहराते जा रहे हैं, उन्होंने निर्माण और सेवाओं में अपनी ढाँचागत विविधता को बढ़ाया है और कृषि सम्बन्धी उत्पादकता को बढ़ाया है - इसने पिछले कुछ दशकों के दौरान करोड़ों लोगों को ग़रीबी से बाहर निकालने में मदद की है।

धीरे-धीरे और क्रमबद्ध एकीकरण

अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व बाज़ार के लिए अचानक खोलने के बजाय कुछ ज़्यादा सफल देशों ने इन्हें धीरे-धीरे और परिस्थितियों की माँग के अनुसार खोला।

- *चीनः* चीन में एकाएक खुलापन लाने की कोशिश से राज्य संचालित उपक्रम बंद हो सकते थे, बिना कोई नई औद्योगिक गतिविधियाँ किए; राज्य ने धीरे-धीरे सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (प्र.वि.नि.) को आकर्षित करने, नई नौकरियाँ पैदा करने व निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी सेज़ (एस.ई.जेड.) की स्थापना की जो अक्सर कम विकसित क्षेत्रों में स्थापित हुए।[62] इसी के साथ-साथ चीन ने विदेशी कंपनियों के सामने संयुक्त उपक्रमों, तकनीक का अंतरण करने या घरेलू वस्तुओं के लिए उच्च ज़रूरतों को पूरा करने की शर्त लगाकर अपने श्रमिकों और कंपनियों की क्षमता को बढ़ाया। 1960 और 1970 के दशक के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा में किये गए निवेश तथा कंपनियों व किसानों द्वारा हासिल की गई नई कुशलताओं को और संपुष्ट करते हुए 1990 के दशक की शुरुआत तक चीन बाहरी जगत के साथ होने वाली अन्तर्क्रिया को विस्तार देने के लिए तैयार हो गया था। 1993 से 1996 के बीच चीन, विश्व के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगती प्रवाह के 10% से अधिक का गंतव्य बन गया था।[63] इसका व्यापार-स.घ.उ. अनुपात तकरीबन दोगुना हो गया, 1980 में यह 21.7% से बढ़कर 1993-1994 में तकरीबन 42% पहुँच गया। 2011 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में 10 साल पूरे कर लिए और वस्तुओं व सेवाओं के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में जर्मनी से आगे निकल गया।[64]
- *भारतः* भारत ने 1980 के दशक के मध्य में घरेलू सुधार शुरू किए और 1990-1991 के बाह्य भुगतान संकट के बाद इसे विस्तार दिया। सुधारों से पहले भारत का आयात कोटा होता था और उसने विनिर्मित वस्तुओं पर उच्च सीमा शुल्क और विनिर्मित उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा रखे थे।[65] शुरुआती सुधारों में ध्यान औद्योगिक गतिविधि के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को हटाने तथा निवेश पर प्रतिबंधों को समाप्त करने पर रहा।[66] उत्पादित पूँजीगत वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को 1993 में समाप्त कर दिया गया। उत्पादित वस्तुओं पर सीमा शुल्क 1990 के 76.3% से तेज़ी से घटाकर 1992 में 42.9% कर दिए गए, लेकिन इसके बाद होने वाली कटौतियाँ दो दशकों तक पसरी थीं, जो 2009 में जाकर करीब 8% पर पहुँचीं। उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं पर लगे प्रतिबंध धीरे-धीरे हटाए गए और 2001 तक पूरी तरह से समाप्त हो गए, यानी सुधारों की प्रक्रिया शुरू होने के 10 साल बाद।[67]

सारणी 3.2

मानव विकास में उच्च उपलब्धियों वाले देशों की वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी, 1985-1990 और 2005-2010 (%)

देश	1985-1990	2000-2010
बांग्लादेश	0.042	0.089
ब्राज़ील	0.946	1.123
चिली	0.232	0.420
चीन	1.267	8.132
घाना	0.029	0.041
भारत	0.519	1.609
इण्डोनेशिया	0.624	0.803
मलेशिया	0.685	1.197
मॉरिशस	0.038	0.027
थाइलैण्ड	0.565	1.095
ट्यूनीशिया	0.116	0.118
तुर्की	0.449	0.852

नोटः दिए गए आँकड़े 1985-1990 तथा 2005-2010 के औसत मान हैं।
स्रोतः विश्व बैंक 2012a

भारत का व्यापार-निर्गत अनुपात 2010 में 46.3% था, जो 1990 में मात्र 15.7% के मुकाबले काफ़ी बेहतर था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (प्र.वि.नि.) 2008 में अपने शिखर मान पर पहुँचा और तब यह स.घ.उ. का 3.6% हुआ, जो 1990 के 0.1% से भी कम मान से काफ़ी अधिक था।[68]

वैश्विक बाज़ारों के लिए औद्योगिक क्षमताओं का निर्माण

आयात प्रतिस्थापन के दौर में कई देशों ने अपनी औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाया है और आगे चलकर विदेशी बाज़ारों में आपूर्ति के लिए इनका इस्तेमाल किया है।

आयात प्रतिस्थापन के दौर में कई देशों ने अपनी औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाया है और आगे चलकर विदेशी बाज़ारों में आपूर्ति के लिए इनका इस्तेमाल किया है

- *तुर्कीः* तुर्की का 1980 के दशक के बाद का व्यापार प्रदर्शन 1980 के पहले के समय के आयात-प्रतिस्थापक औद्योगीकरण (import-substituting industrialization) के फलस्वरूप बनीं उत्पादन क्षमताओं पर आधारित था।[69] 1990 और 2010 के बीच इसका व्यापार-स.घ.उ. अनुपात 32% से बढ़कर 48% पर पहुँच गया, जो बड़े घरेलू बाज़ार वाले एक मध्य आय देश के लिए अहम बढ़त थी। 2010 में सभी शीर्ष निर्यात– आटोमोबाइल, लौह एवं स्टील, और घरेलू उपकरण व उपभोक्ता

इलेक्ट्रॉनिक्स सामान– उन उद्योगों से निकले थे जो व्यापार संरक्षण के दौर में पनपे थे।

- *कोरिया गणतंत्रः* जब कोरिया गणतंत्र और अन्य पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में आयात-प्रतिस्थापन के मध्यम दौर से गुज़रीं तो उन्होंने पूँजीगत माल के घरेलू उत्पादकों को संरक्षण नहीं दिया।[70] 1980 के दशक में जब वे प्र.वि.नि. को लेकर असमंजस में थे, तब भी उन्होंने लाइसेंसिंग अनुबंधों के तहत तकनीक का आयात करने का विकल्प चुना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क स्थापित करने पर ध्यान दिया। इस कवायद का उद्देश्य यह था कि विदेशी तकनीकों को बाहर से लेकर और समविष्ट करके दीर्घकालिक उपयोग के लिए अपनी देशी क्षमताओं को बढ़ाया जाए।
- *थाइलैण्डः* थाइलैंड की विनिर्माण क्षमता के निरंतर सबलतर होते जाने के पीछे इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्कों में भागीदारी का हाथ है। वर्ष 2009-2010 इसके द्वारा अवयवों और संघटकों का निर्यात– खासकर आटोमोबाइल और इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में– $48 बिलियन आँका गया था, जो इसके कुल वाणिज्यिक वस्तु उत्पादों के निर्यात का चौथाई हिस्सा था। सरकार थाइलैण्ड को 'एशिया का डेट्राएट' बनाने को बहुत बेताब है– न केवल माल ढुलाई के एक क्लस्टर के रूप में बल्कि एक ऐसे हाइटेक केन्द्र के रूप में जो कंपनियों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच शोध के लिए सहकार स्थापित करने में भूमिका अदा करे।[71]
- *मलेशियाः* इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग के क्षेत्र में मलेशिया की शिखर-श्रेष्ठता की शुरुआत श्रम के अंतरराष्ट्रीय विभाजन के उदय काल में हुई थी, तब जब इसने उत्तर के देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लुभाना शुरू किया था। प्राथमिक रूप से इलैक्ट्रानिक सामानों का विनिर्माण करने वालों के लिए स्थापित किए गए 'मुक्त व्यापार क्षेत्रों'[72] ने 1970 से लेकर 1990 के दशकों के दौरान देश को तेज़ी से प्रगति करने में मदद की। यह दीगर है कि आज मलेशिया की अर्थव्यवस्था ''मध्य आय के जाल में'' देखी जाती है, जो पड़ोस के अल्प-लागती उत्पादन करने वाले देशों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं और उच्च तकनीकी दक्षता वाले वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों के लिए काम करने के हुनर से वंचित हैं।[73] सरकार की अपनी सलाहकार परिषद भी चिंतित है कि प्र.वि.नि. प्रवाह में मंदी का मतलब होगा उच्च-आय का स्तर पाने की संभावना का दूर छिटकना।[74] सेकेण्डरी शिक्षा में मलेशिया के बेहतर रिकॉर्ड ने भी, ऐसा लगता है, एक नवाचार-प्रचालित अर्थव्यवस्था के लिए मज़बूत आधार तैयार नहीं कियाः मलेशिया की भविष्यत प्रगति अनुसंधान और विकास की अपर्याप्त क्षमता तथा डिज़ाइन व प्रॉसेस इंजीनियरों तथा तकनीकी और उत्पादन कर्मचारियों के अभाव से बाधित है।[75]
- *इण्डोनेशियाः* इण्डोनेशिया और कुछ पूर्व एशियाई देशों ने 1990 वाले दशक में संरक्षण के आयामों से जुड़ी कीमतों से बचने के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (export processing zones), अनुबंधित वेयरहाउसों और ड्यूटी ड्राबैक प्रणालियों (duty drawback system) की स्थापना की। इस सभी के लिए दक्ष नौकरशाही की ज़रूरत होती है। लेकिन जब देशों को लगा कि उनमें यह अपेक्षित क्षमता नहीं है, तो उन्होंने अपारंपरिक तरीके अपनाए। इण्डोनेशिया ने तो कुछ समय के लिए अपने सीमा शुल्क प्रशासन का निजीकरण कर दिया।[76] 1997 के वित्तीय संकट को झेलकर आगे निकल कर इण्डोनेशिया आज अपने कमोडिटी निर्यात का प्रभावी प्रबंधन कर लेने के कारण सबसे अलग खड़ा दिखाई देता है।[77]

1997 के वित्तीय संकट को झेलकर आगे निकल कर इण्डोनेशिया आज अपने कमोडिटी निर्यात का प्रभावी प्रबंधन कर लेने के कारण सबसे अलग खड़ा दिखाई देता है

विशिष्ट उत्पादों की सवारी

छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक विकल्प होता है विशिष्ट उत्पादों के सहारे वैश्विक बाज़ारों का दोहन करना। सफल उत्पादों का चयन आकस्मिक या किस्मत भरोसे नहीं होता; बहुधा ही यह परिणाम होता है राज्य से बरसों-बरस मिली मदद और अनुकूलताओं का, जो या तो अस्तित्वमान क्षमताओं को बढ़ाती हैं या फिर नई क्षमताओं के सृजन में मददगार होती हैं।

- *चिलीः* राज्य की सक्रिय मदद के बल पर चिली की कंपनियों ने प्रसंस्करित खाद्य एवं पेय कृषि उत्पादों और वनोपज और मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में खासी सफलता अर्जित की है। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में शराब बनाने के लिए अंगूरों की खेती पर बड़ी मात्रा में सार्वजनिक क्षेत्र में शोध और विकास का काम हुआ। वानिकी में पौधारोपण के लिए छूट देने का भी लंबा इतिहास रहा है, और राज्य ने लकड़ी, गूदा व कागज़, और फ़र्नीचर क्लस्टर को निर्यात का एक प्रमुख उद्योग बनाने की दिशा में भी बहुत प्रयास किए हैं।[78] एक अलाभकारी निगम, *फ़ाउंडेशन चिली* से मिली इसी तरह की मदद से साल्मन मछली के व्यावसायिक पालन को दुनिया के सबसे सफल उदाहरणों में से एक बना दिया है।[79]
- *बांग्लादेशः* बांग्लादेश ने वस्त्रों के विश्व व्यापार में बाज़ार की विकृतियों का फायदा उठाया। लेकिन इसके उद्यमियों की पहल न होती, तो यह अवसर बेकार भी जा सकता था।[80] 1978 में देश कंपनी (Desh Company) ने एक कोरियाई कंपनी देवू (Daewoo) के साथ पाँच साल के एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय मानकों और वस्त्र खरीदारों के एक नेटवर्क से जोड़ा। देवू ने देश कंपनी कर्मचारियों को कोरिया गणतंत्र में उत्पादन और विपणन का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण पाने वाले कुल 130 लोगों में से 115 ने एक साल के भीतर

ही देश कंपनी छोड़ दी और खुद की वस्त्र निर्यात कंपनियाँ शुरू कर दी।[81] 2010 में बांग्लादेश की विश्व वस्त्र निर्यात बाज़ार में हिस्सेदारी 1990 के 0.8% से बढ़कर 4.8% हो गई है।[82]

- *मॉरिशस:* सीमित कृषि योग्य भूमि, बढ़ती जनसंख्या और केवल एक उत्पाद (चीनी) पर बहुत ज़्यादा निर्भरता वाले देश मॉरिशस को बाज़ार का रुख करना पड़ा था। कोटा-परमिट से परेशान एशियाई वस्त्र निर्माताओं को मजबूरी में व्यापक वैश्विक देश ने आकर्षित किया। 1990 के दशक तक मॉरिशस सबसे ज़्यादा संरक्षित अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन इसने आयातित आगतों की उपलब्धता को शुल्क मुक्त किया। इसके अलावा कर में छूट दी, लोचदार श्रम बाज़ार स्थितियाँ बनाई, जिसमें निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में श्रम-सघन नौकरियों (labour-intensive jobs) में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन शामिल था।[83]
- *घाना:* दशकों से कोको घाना की अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। हालाँकि, 1970 के दशक में और 1980 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र के लगभग ख़त्म होने की नौबत आ गई थी। 1983 में शुरू हुए सुधारों, विशेषकर मुद्रा का अवमूल्यन, भंडारण और विपणन में निजी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाकर और प्राप्त होने वाली कीमतों में किसानों को ज़्यादा उच्च हिस्सेदारी देकर घाना ने अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धिता को बहाल कर लिया। 1983 और 2006 के बीच देश में कोको का उत्पादन प्रति हेक्टेयर दोगुना हो गया और आज यह क्षेत्र 7 लाख लोगों की आजीविका का साधन है।[84] पिछले 10 वर्षों के दौरान घाना ने विविध सेवाओं के क्षेत्र में भी कदम रखे हैं और इसमें दूरसंचार क्षेत्र में तेज़ी से विकास के साथ, किसानों की बाज़ार सूचनाओं के स्रोत्रों के साथ जुड़ने की क्षमता बढ़ गई है। हाल के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 61% कोको किसानों के पास खुद के मोबाइल फ़ोन हैं।[85]

उन सभी अर्थव्यवस्थाओं में, जिनका शेष दुनिया से एक सार्थक रिश्ता रहा है, एक बात समान है कि सबने अपने लोगों के विकास में निवेश किया है। देश में या सहयोगी देशों के साथ, सीमा शुल्क सम्बन्धी सुधार निर्यात बाज़ारों के लिए एक आशातीत अवसर प्रदान कर सकता है; कुछ देश प्रचुर संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं या दूसरों की नकल करके छोटी अवधि की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, सीखने वाली बात यह है कि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादन प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार के लिए लोगों के कौशल में पर्याप्त निवेश के बिना विकास को बरकरार नहीं रखा जा सकता। यहाँ जिन देशों की चर्चा की गई, उन्होंने काफ़ी अलग-अलग शुरुआती परिस्थितियों से अपनी यात्रा प्रारम्भ की, और विश्व बाज़ारों द्वारा प्रस्तुत बाह्य अवसरों का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं को दुरुस्त और पोषित करने में निपुण हो गए हैं।

प्रचालक 3 : संकल्पशील सामाजिक नीति नवाचार

साक्ष्य यह बताते हैं कि बड़े स्तर पर किया गया सार्वजनिक निवेश– न केवल अधोसंरचना में बल्कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा में भी प्रभावी तरीके से नियोजित किया गया– मानव विकास के लक्ष्यों को पाने और उन्हें संवहनीय बनाने की कुंजी है। विकास की रणनीतियाँ तब तक सफल नहीं हो सकतीं, जब तक हर व्यक्ति को विकास के लाभों को उठाने का न्यायपूर्ण मौका मिलने के साथ ही अवसर की समानता के प्रति वचनबद्धता न दर्शाई जाए। अनेक देश इसके उदाहरण हैं कि उच्चतर मानव विकास के स्तरों पर जोर देने से आर्थिक प्रगति को त्वरित करने में सहायता मिलती है।[86]

विकास की रणनीतियाँ तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हर व्यक्ति को विकास के लाभ उठाने का न्यायपूर्ण मौका मिलने के साथ ही अवसर की समानता के प्रति वचनबद्धता न दर्शाई जाए

अवसर की समानता के प्रति सरकार की गंभीरता का पता शिक्षा के प्रसार के प्रति सरकार की दृढ़ता से चलता है, विशेषकर बालिका शिक्षा के प्रति। जिन देशों ने दीर्घकालीन वृद्धि को बरकरार रखा है, उन्होंने अपने नागरिकों को शिक्षा दिलाने और मानव पूँजी (Human capital) को समृद्ध करने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं।[87] गणित और विज्ञान की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को मापने पर पता चलता है कि शिक्षा में निवेश उनके संज्ञानात्मक कौशल में वृद्धि करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।[88] विशेषज्ञता कौशल को बढ़ाने में किए गए निवेश की तुलना में सभी के लिए शिक्षा पर निवेश के फ़ायदे कहीं अधिक हैं।[89] इसी प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार भी श्रम उत्पादकता को बढ़ाकर आर्थिक प्रगति में सहायक साबित होता है।[90]

जब प्रगति के साथ ही उच्च अथवा वृद्धिगत असमानता भी जुड़ी रहती है, तब अमूमन वह मानव विकास में बढ़त की गति धीमी करती है और निर्धनता में कमी की गति धीमी करने के साथ-साथ सामाजिक संघटन को भी कमजोर करती है। इसके अतिरिक्त यह सामान्य तौर पर असंवहनीय भी मानी जाती है।[91] अतः लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसे गुणकारी चक्रों का निर्माण किया जाए, जिनमें संवृद्धि और सामाजिक नीतियाँ एक-दूसरे को मज़बूती प्रदान करें। अधिकांशतः यह देखा गया है कि उच्च आय असमानता वाले देशों की तुलना में निम्न आय असमानता वाले देशों में निर्धनता को घटाने में प्रगति अधिक प्रभावशाली साबित हुई है। समय के साथ आय के वितरण के कमजोर होते जाने पर निर्धनता को घटाने में प्रगति कम प्रभावशाली साबित होती है।[92]

चीन और ब्राज़ील इस संदर्भ में अपवाद माने जा सकते हैं। पिछले 30 वर्षों के दौरान प्रगति की अत्यधिक उच्च दरों के परिणामस्वरूप, आय की असमानता में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद चीन निर्धनता में कमी लाने में सक्षम हो सका है। इसी प्रकार, 2000 के दशक की

शुरुआत में ब्राज़ील में उच्च आय असमानता के बावजूद निर्धनता को घटाने के लिए लक्षित नीतियों का उपयोग किया गया– हालाँकि इसी दौरान आय के वितरण में अधिक समानता आई।

समानता को प्रोत्साहित करना– खासतौर पर समूहों के बीच की समानता, जो क्षैतिज समानता के नाम से जानी जाती है–सामाजिक संघर्ष में कमी लाने में सहायक होती है। 1975 के बाद प्रगति में सर्वाधिक तीखे संकुचन वाले देश वे हैं, जो (असमानता और नस्लीय विखंडन (Ethnic fragmentation) के सूचकों के आधार पर मापे गए) विभाजित समाजों वाले हैं। ये देश संघर्ष प्रबंधन के लिए कमज़ोर संस्थाओं वाले तथा विधि के शासन, प्रजातांत्रिक अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सुनिश्चित करने की कम क्षमता रखने वाले, खराब गुणवत्ता की सरकारी संस्थाओं की समस्या से ग्रस्त हैं।[93]

शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सामाजिक संरक्षण, विधिक सशक्तीकरण और सामाजिक संगठन, ये सभी कारक निर्धन लोगों को प्रगति में सहभागी बनने में समर्थ बनाते हैं। लेकिन ये आधारभूत नीतिगत उपकरण वंचित समूहों को सशक्त करने में सफल नहीं भी हो सकते हैं। समाज के हाशिए पर स्थित निर्धन वर्ग अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करता है और सरकारें भी इस बात का हमेशा आकलन नहीं करती कि क्या सेवाएँ उन सभी लोगों तक पहुँच रही हैं, जिनके लिए वे हैं।[94] आमतौर पर समस्याएँ बाहरी आघातों के ज़रिए बढ़-चढ़ जाती हैं, परंतु अनेक मामलों में नीतियाँ वहाँ लागू की जाती हैं जहाँ, स्थानीय संस्थागत क्षमता और सामुदायिक सहभागिता की स्थितियाँ नीची होती हैं।

ऐसी सेवाएँ जो एक स्वस्थ और शिक्षित श्रम बल का निर्माण करती हैं, वे राष्ट्रीय स्थायित्व को मज़बूत करने, राजनीतिक असंतोष की आशंका में कमी लाने और सरकारों की वैधता को मज़बूती देने में सहायक होती हैं

- *युगाण्डाः* संघर्ष समाप्ति के बाद युगाण्डा में मूल्य नियंत्रण व विनिमय दरों में ढील देने से लेकर राज्य के नियंत्रण वाले उपक्रमों एवं प्रशासनिक सेवाओं में बदलावों तक किए गए समष्टि-अर्थशास्त्रीय सुधारों ने निर्धनता उन्मूलन की 1977 में शुरू की गई व्यापक योजना का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही युगाण्डा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत 2015 से पहले ही अपनी निर्धनता को 1992-93 के 56.4% से 2009-10 में 24.5% प्रतिशत तक पहुँचा कर उन कुछ गिने-चुने सब-सहारा अफ्रीकी देशों में शामिल हो गया, जिन्होंने इस अवधि में चरम निर्धनता को आधा कर दिया। हालाँकि आय की बढ़ती असमानता ने निर्धनता उन्मूलन की गति को धीमा किया है।[95] इन प्रयासों की सफलता यह बताती है कि कार्यक्रम तभी अधिक प्रभावशाली साबित होते हैं, जब राष्ट्रीय नेतृत्व सरकारी एजेंसियों के बीच लक्ष्यों और दृष्टिकोणों की संगतता बढ़ाकर निर्धनता में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध हो।[96] इसका लाभ यह है कि ऐसी सफलता नेताओं और उनकी सरकारों की वैधता पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

समावेशन को बढ़ावा

सभी देशों में, कम या अधिक मात्रा में, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुलतावादी समाज पाए जाते हैं, और भिन्न-भिन्न समूहों के मानव विकास के विभिन्न स्तर होते हैं। यहँ तक कि उन्नत देशों के श्रम बाज़ारों में भी कुछ नस्लीय समूहों के विरुद्ध भेदभाव पाया जाता है।[97] ग़ैर-बाज़ार (Non-market) भेदभाव भी उतना ही गंभीर और अस्थिरताजनक साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक भेदभाव के दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व के लिए यह लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो, भेदभाव न हो।

दक्षिण में भी उपलब्धियों के विभिन्न स्तरों के पीछे मूल कारण ऐतिहासिक अथवा औपनिवेशिक रहे हैं, उदाहरण के लिए भारत में उच्च और निम्न जातियों के बीच और मलेशिया में भूमिपुत्रों (मलय), चीनी और भारतीयों के बीच। केवल आर्थिक समृद्धि समूहों के बीच पाए जाने वाले उस भेदभाव को खत्म नहीं कर सकती, जो क्षैतिज असमानता को बढ़ाता है। भारत और मलेशिया, दोनों ने असमानता को कम करने के लिए और ऐतिहासिक अलाभताओं (disadvantages) में सुधार लाने के लिए आरक्षण जैसे सुविचारित नीतिगत हस्तक्षेपों को अपनाया है।

आधारभूत सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध कराना

राज्य ऐसी सेवाएँ प्रदान करके, जो एक स्वस्थ और शिक्षित श्रम बल का निर्माण करती हैं, दीर्घकालीन आर्थिक संवृद्धि को आधार प्रदान कर सकते हैं। ऐसे उपायों से राष्ट्रीय स्थायित्व को मज़बूत करने, राजनीतिक असंतोष की आशंका में कमी लाने और सरकारों की वैधता को मज़बूती देने में सहायता मिलती है।

विकासशील देशों को कभी-कभी यह नीतिगत परामर्श मिलता है कि वे आधारभूत सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को ऐसे व्यय के रूप में देखें, जो उसके लिए वहनीय नहीं है। लेकिन ऐसे निवेशों की सार्थकता दीर्घ काल में ही अनुभव में आती है। यद्यपि, सभी सेवाओं को सरकार द्वारा दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का एक न्यूनतम सार्वभौमिक स्तर स्थापित किए जाने की ज़रूरत है ताकि सेवा प्रदाता सरकारी हों या निजी, सभी नागरिकों का मानव विकास की मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। अनिवार्य सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ने यूरोप और कोस्टारिका जैसे कुछ विकासशील देशों के मानव विकास में निर्णायक भूमिका निभाई है।

उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच

मा.वि.सू. मान में संवृद्धि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी से जुड़ी है। औसतन यह देखा गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर उच्च सरकारी व्यय करने वाले देशों में मानव विकास में प्रगति उच्च होती है, हालाँकि इसमें कुछ स्थानीय विभिन्नताएँ हो सकती हैं।

- *इण्डोनेशियाः* इण्डोनेशिया के आर्थिक बसंत (economic boom) के वर्षों (1973 के बाद से) के दौरान सरकार ने विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूलों का निर्माण कराया और इसके बाद के दशक में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ कर दुगुने से अधिक हो गया।
- *भारतः* शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने के लिए किए गए संवैधानिक संशोधन का पालन करते हुए भारत में स्कूली तंत्र में भेदभाव के खात्मे के लिए प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं (बॉक्स 3.6)।
- *घानाः* स्वतंत्र घाना में सबसे पहले की गई पहलों में से एक थी, शिक्षा के लिए 1951 में शुरू की गई त्वरित शिक्षा विकास योजना, जिसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा का व्यापक प्रसार करना था। 1961 के शिक्षा अधिनियम में प्राथमिक शिक्षा के लिए फ़ीस को खत्म करने का प्रावधान किया गया था, ताकि परिवारों को केवल पुस्तकें खरीदने का मामूली खर्चा ही करना पड़े। इससे अगले छह वर्षों में सार्वजनिक प्राथमिक स्कूलों में नामांकन दुगुने हो गए। 1966 से 1970 के बीच लोक विमर्श का मुख्य जोर 'शिक्षा तक पहुँच' के स्थान पर 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' पर हो गया। लेकिन 1970 के दशक के प्रारंभ में फोकस पुनः 'शिक्षा तक पहुँच' पर हो गया, परंतु इस बार यह माध्यमिक शिक्षा के लिए था। सुधार का अगला महत्वपूर्ण चरण 1987 में देखने में आया। पाठ्यक्रम में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार किया गया, वह था, बच्चों को तीन भाषाओं में साक्षर बनाना। इनमें दो घाना की भाषाएँ और एक अंग्रेज़ी भाषा थी। इसके अतिरिक्त इसमें आधुनिक कृषि कौशल, व्यावसायिक कौशल और व्यावहारिक गणित का अध्ययन भी शामिल किया गया।
- *मॉरिशसः* सरकार ने गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था के लिए एक राष्ट्रीय सर्वानुमति विकसित की।
- *बांग्लादेशः* बांग्लादेश ने 1992 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और इसमें लैंगिक व निर्धनता अंतरालों को दूर करने के उद्देश्य से प्राथमिक और जन शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की। आपूर्ति-पक्ष के हस्तक्षेपों, विशेषकर महिला वजीफ़ा (Stipend) कार्यक्रम, माध्यमिक स्कूल सहयोग कार्यक्रम और शिक्षा के लिए भोजन कार्यक्रम, ने खासतौर पर लड़कियों में शिक्षा के प्रसार में वृद्धि की।

बॉक्स 3.6

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रगतिशील निर्णय दिया हैः निजी स्कूलों में सुविधाहीन तबके के बच्चों के लिए सीटें अनिवार्य होंगी

विकासशील देशों में ज़्यादातर स्कूल सरकार द्वारा संचालित हैं लेकिन सार्वजनिक स्कूलों के असफल होने की प्रतिक्रियास्वरूप निजी स्कूलों की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। कमजोर आधारभूत सुविधाएँ, बच्चों से अटी पड़ी कक्षाएँ, खराब पहुँच, शिक्षकों की कमी और उनका अनुपस्थित रहना इसकी असफलता के प्रमुख कारण हैं। जिन अभिभावकों के पास पर्याप्त धन है, वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं और इस तरह कई देशों में माता-पिता बच्चों को निजी और सार्वजनिक स्कूलों में विभाजित कर रहे हैं और कई देशों में एक विभाजित समाज स्थापित कर रहे हैं।

भारत ने 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना दिया है। सरकारी स्कूलों में भारी संख्या में बच्चों का नामांकन है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में अभिजात परिवारों के– अमीर, राजनीतिक वर्ग, सरकारी कर्मचारी और बढ़ रहे मध्य वर्ग– के ज़्यादातर बच्चे निजी स्कूलों में भेजे जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें लड़कों को निजी स्कूलों में भेजा जाता है जबकि लड़कियाँ मुफ्त शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं।

भारत में इस तरह के विभाजन की प्रवृत्ति को कम करने के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बाल अधिकार का अधिनियम 2009 (2009 Right of Children to Free and Compulsory Education Act) लाया गया जिसके तहत निजी स्कूलों को अपने यहाँ कम से 25% ऐसे बच्चों को प्रवेश देना होगा जो सामाजिक रूप से सुविधाहीन और निम्न-आय वर्ग वाले परिवारों से आते हैं। इसके बदले में निजी स्कूलों को या तो उनके शिक्षण खर्च या सरकारी स्कूलों में प्रति-विद्यार्थी के खर्च, जो भी कम होगा, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह अधिनियम निम्न तर्कों पर आधारित थाः

(1) स्कूल अनिवार्यतः सामाजिक एकीकरण के स्थल होने चाहिए, (2) निजी स्कूलों का राज्य से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो उन्हें ज़मीन और अन्य सुविधाएँ मुहैया कराता है, (3) जिन बच्चों के माता-पिता के पास निजी स्कूलों का शुल्क देने की क्षमता है उन्हें ही ऐसे स्कूलों में पढ़ने का अधिकार है, यह तर्क देकर निजी स्कूल सामाजिक जवाबदेही से बच नहीं सकते, और (4) वंचित तबकों के कम से कम 25% बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश देने का प्रावधान उचित है क्योंकि कुल आबादी में यह तबका तकरीबन 25% है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल, 2012 को अपने एक ऐतिहासिक फ़ैसले में अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और अपने इस फैसले के पक्ष में कुछ बिंदु भी रखे। पहला, अधिनियम ने जब से 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को कानूनी बाध्यता बनाया है, तो राज्य के पास यह तय करने की स्वतंत्रता है कि वह इस कानूनी बाध्यता को पूरा करने के लिए चाहे तो अपने स्कूलों या सहायता प्राप्त स्कूलों या ग़ैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का उपयोग करे। 2009 का यह अधिनियम बाल-केंद्रित है न कि संस्थान-केंद्रित। दूसरा, शिक्षा का अनुबंध राज्य और बच्चों के माता-पिता के बीच एक पारस्परिक समझौते की कल्पना करता है और यह हमारे नागर समाज में सभी सरोकारियों पर एक सकारात्मक बोझ डालता है। निजी, ग़ैर-वित्तीय सहायता प्राप्त स्कूल इस निर्दिष्ट श्रेणी के विद्यार्थियों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की राज्य के प्राथमिक कर्तव्य की पूर्ति में पूरक हैं।

स्रोतः भारत सरकार; भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2012

- *चीनः* चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 1986 में लिंग, नस्ल या जाति के भेदभाव को हटाते हुए नौ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान करने वाले कानून को पारित किया। 1990 से 2000 के दौरान ग्रामीण इलाकों के 15 या अधिक उम्र के लोगों के लिए स्कूली शिक्षा हासिल करने के औसत वर्ष 4.7 से 6.8 वर्ष तक हो गए।
- *युगाण्डाः* युगाण्डा ने 1997 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल फ़ीस को खत्म कर दिया। प्रारंभ में इससे शैक्षिक अधोसंरचना में बाधा आई।[98] गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने पाँच क्षेत्रों पर जोर दियाः पाठ्यक्रम विकास, आधारभूत अधिगम (Learning) सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण की भाषा और गुणवत्ता मानक (Quality standard)। इससे गुणवत्ता और स्कूली शिक्षा पूरी करने के वर्षों में आई शुरुआती गिरावट की दिशा अब पलट चुकी है और ठोस उपलब्धियाँ विस्तारित हो चुकी हैं।
- *ब्राज़ीलः* ब्राज़ील में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य द्वारा किए गए निवेश से विकास परिणामों में नाटकीय सुधार हुआ है। ब्राज़ील के शिक्षा तंत्र में रूपांतरण की शुरुआत सभी क्षेत्रों, राज्यों और नगर निकायों में वित्त की समान उपलब्धता से हुई। 1996 में स्थापित किए गए 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा कोष' ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रति विद्यार्थी पर होने वाले राष्ट्रीय न्यूनतम व्यय को सुनिश्चित करते हुए उत्तर-पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी मध्य राज्यों के प्राथमिक विद्यार्थियों (विशेष तौर पर नगरीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के) के लिए संसाधनों में वृद्धि की है। विद्यार्थियों तक पहुँच बढ़ाने के लिए कोष उपलब्ध कराने से स्कूली तंत्रों को नामांकनों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली है। इसी प्रकार, राज्यों से नगर निकायों के साथ संसाधनों को साझा करने को कहा गया, ताकि सभी राज्य और नगरपालिका स्कूल प्रति विद्यार्थी किए जाने वाले न्यूनतम व्यय की सीमा तक पहुँच सकें। यह इसी निवेश का परिणाम था कि 2000 से 2009 के बीच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम (Programme for International Student Assessment-PISA) पर ब्राज़ील के गणित स्कोर में 52 बिन्दुओं (रिकॉर्ड तीसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी) की वृद्धि हुई।

स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। कई देश यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कई मोर्चों पर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है

उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। पिछली *मानव विकास रिपोर्टों* में दिखाया गया है कि मानव ग़रीबी बहुआयामी है। कई देश यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कई मोर्चों पर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया ने पिछले 40 वर्षों में जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय बढ़त देखी है। संभावित स्पष्टीकरणों में स्वास्थ्य व दवा प्रौद्योगिकी में सुधार, व्यापक टीकाकरण, सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति, उन्नत जल और साफ़-सफ़ाई की बेहतर उपलब्धता, ऊर्जा विकल्पों में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य में निजी व सार्वजनिक निवेश शामिल हैं।

- *बांग्लादेशः* बच्चों की जीवितता की दर को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश ने एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का सहारा लिया। इसके तहत उसने महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार संभावनाओं का विस्तार किया, उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाया, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक गतिशीलता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया। प्रभावशाली तरीके से स्वास्थ्य जानकारियों का प्रसार किया और प्रभावी, समुदाय-आधारित ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की (बॉक्स 3.7)।

स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों का झुकाव सम्पन्न लोगों की तरफ़ काफ़ी रहा है। सम्पन्न वर्ग की सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुँच और निजी क्षेत्र की सेवाओं के लिए भुगतान कर पाने की क्षमता की संभावना अधिक होती है। स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग करने वाले लोग औपचारिक क्षेत्र के कर्मी होते हैं जो अपनी वार्षिक अदायगी के दम पर अपनी स्वास्थ्य ज़रूरतों को कुछ हद तक तो पूरा कर ही लेते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को यह उपलब्ध करा पाना ज़्यादा कठिन है। उदाहरण के लिए, भारत में स्पष्ट रूप से ऐसे चिन्हित नियमित रोज़गारदाता नहीं हैं, जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत तकरीबन 93% श्रम शक्ति की तरफ़ से योगदान कर सकें।[99]

प्रत्येक व्यक्ति समान गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं (same quality of health care) का पात्र होना चाहिए और कई देशों ने सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य कवरेज के दायरे में लाने और इसका वित्तीयन करने का प्रयास किया है। कुछ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को, विशेषकर ग़रीबों के लिए, लक्षित करके ऐसा किया है। लेकिन यह तरीका न तो वांछित है और न ही कार्यदक्ष, और आमतौर पर यह एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली को जन्म दे रहा है, जहाँ ग़रीबों को खराब गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्राप्त होती हैं, अक्सर ही सार्वजनिक सुविधाओं के तहत, वहीं दूसरी तरफ जो ग़रीब नहीं हैं, वे निजी क्षेत्र से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त कर लेते हैं। ग़रीबों के लिए लक्षित स्वास्थ्य सेवाओं को आमतौर पर फंडिंग की कमी झेलनी पड़ती है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वे ताकतवर लोग जो ग़रीब नहीं हैं, उनके इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के कोई सरोकार नहीं होते। इसके अलावा, ग़रीबों के लिए संचालित विशेष बीमा योजनाएँ कुल जनसंख्या के बीच जोखिम को जोड़ने के लाभ से वंचित रहती हैं, और इस कारण आर्थिक रूप से अवहनीय बन जाती हैं। इससे अक्सर संसाधनों का निवारक व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से अंतरण अधिक

बॉक्स 3.7

बांग्लादेश : बाल जीवितता में नाटकीय प्रगति

1990 में बांग्लादेश में शिशु मृत्यु दर 1,000 जन्मे बच्चों पर 97 थी। यह भारत की दर, 1,000 जन्मे बच्चों पर 81, से 16% अधिक थी। 2004 तक स्थितियाँ उलट गईं। बांग्लादेश की शिशु मृत्यु दर (38) भारत (48) की तुलना में 21% कम हो गई। इस नाटकीय सुधार की व्याख्या के तीन प्रमुख कारक प्रतीत होते हैं। पहला, कपड़ा उद्योग में रोज़गार के ज़रिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण और उनकी स्थिति को रूपांतरित कर देने वाले सूक्ष्म ऋण की उपलब्धता। कपड़ा उद्योग में ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में आई प्रवासी महिलाओं की संख्या है। युवा महिलाओं को मिली इस अभूतपूर्व रोज़गार संभावना से रोज़गार में लैंगिक असमानता और आय के अंतर में कमी आई। सूक्ष्म ऋण के प्रसार ने भी महिला सशक्तीकरण में अहम भूमिका अदा की। अकेले ग्रामीण बैंक ने 80 लाख कर्ज़ लेने वालों को 8.74 बिलियन डॉलर का ऋण दिया जिनमें 95 फीसदी महिलाएँ थीं। हालिया अनुमानों के मुताबिक इन छोटे कर्ज़ों ने कर्ज लेने वाले आधे से अधिक परिवारों को ग़रीबी रेखा से बाहर निकलने में सक्षम बनाया है और सूक्ष्म वित्त की आसान उपलब्धता के परिणामस्वरूप नई आर्थिक संभावनाएँ खुली हैं। जल्दी शादी न करने और जल्दी माँ न बनने का सीधा सम्बन्ध महिला सशक्तीकरण से है और इसका प्रभाव बच्चे की जीवितता पर भी पड़ता है।

दूसरा, महिलाओं का सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण ग़ैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित महिलाओं के समूहों की नियमित बैठकों के ज़रिए भी संभव हुआ। उदाहरण के लिए, ग्रामीण बैंक के तंत्र ने कर्ज़ लेने वालों को चुनाव प्रक्रिया से रूबरू करवाया है, क्योंकि इसके सदस्य हर साल अध्यक्ष और सचिवों, प्रमुखों और केंद्रों के उप-प्रमुखों के चुनाव में और हर तीसरे साल बोर्ड के सदस्यों के चुनाव में हिस्सा लेने लगे। इस अनुभव ने कई महिलाओं को सरकारी पदों की दौड़ में शामिल होने लायक बना दिया है। बैंकों में भागीदारी के ज़रिए भी महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त किया गया है। हाल का विश्लेषण बताता है कि कर्ज़ फ़ोरम में भागीदारी करने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ऐसे फ़ोरम में भाग न लेने वाली महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा है।

तीसरा, ग़ैर-सरकारी संगठनों द्वारा औपचारिक शिक्षा में लड़कियों की ज़्यादा भागीदारी बढ़ाई गई। ग़ैर-सरकारी संगठन बी.आर.ए.सी. द्वारा अनौपचारिक स्कूल चलाए जाते हैं जो उन किशोरों को 94% से अधिक अवरोधन दर (retention rate) के साथ चार साल की त्वरित प्राथमिक शिक्षा देते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। इससे पास होने के बाद विद्यार्थी औपचारिक स्कूली प्रणाली में जा सकते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसा करते हैं। नियमित स्कूल पाठ्यक्रम में मासिक आधार पर प्रजनन स्वास्थ्य सत्रों को जोड़ा गया है और इसमें किशोरावस्था, प्रजनन और मासिक धर्म, शादी व गर्भावस्था, परिवार नियोजन व गर्भ निरोधक, धूम्रपान और सम्बन्धित बुराइयाँ और लैंगिक मुद्दों को शामिल किया गया है। आज लड़कियों का नामांकन लड़कों के नामांकन को पार कर गया है (15 साल पहले स्कूल जाने वाली लड़कियाँ केवल 40% थीं)।

महिला सशक्तीकरण स्वास्थ्य सेवाओं और प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण सुधार के साथ-साथ हुआ है। सुई से लिए जाने वाले गर्भनिरोधकों की उपलब्धता से गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल बढ़ा है। आयु 15-40 के बीच की 53% महिलाएँ अब गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल करती हैं, जो उन्हें बहुधा सामुदायिक आउटरीच कार्यकर्ता के माध्यम से मिलती हैं। ये सेवाएँ अक्सर सामुदायिक कर्मियों के ज़रिए दी जाती हैं। बी.आर.ए.सी. ने 1.3 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को डायरिया से पीड़ित बच्चे के लिए रि-हाइड्रेशन के बारे में समुदाय-आधारित निर्देश उपलब्ध करवाए हैं। आज बांग्लादेश में ओरल रि-हाइड्रेशन इस्तेमाल की दर विश्व की सबसे ज़्यादा है और बच्चों की मौत के प्रमुख कारण के रूप में डायरिया का नाम नहीं लिया जाता है। भारत के केवल 73% बच्चों की तुलना में बांग्लादेश में 95% बच्चे टी.बी. के खिलाफ़ प्रतिरक्षित हैं। वयस्क टी.बी. के उपचार के मामले में भी बांग्लादेश बेहतर स्थिति में है। बी.आर.ए.सी. प्रायोजित सामुदायिक स्वयंसेवक 90% से अधिक मामलों का उपचार कर रहे हैं, जबकि भारत औपचारिक स्वास्थ्य प्रणाली के ज़रिए भी 70% तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहा है।

स्रोतः बी.आर.ए.सी.,एन.डी.; ग्रामीण बैंक एन.डी.; विश्व बैंक 2012a.

महँगी उच्च संरक्षा (tertiary care) की ओर हो जाता है।

सरकारें उपयोगकर्ता शुल्कों के ज़रिए भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन उपलब्ध कराने की कोशिश करती हैं। हालाँकि अब इस पर लगभग आम सहमति है कि इस तरह के शुल्कों का विपरीत प्रभाव पड़ता है, विशेषकर ग़रीबों पर। वे ग़रीबों को सेवाओं के इस्तेमाल से हतोत्साहित करती हैं और आमतौर पर बहुत कम ही संसाधन जुटा पाती हैं।[100]

वैश्विक अनुभव बताते हैं कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन का मुख्य स्रोत कराधान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, दक्षिण-पूर्व एशिया में ज़्यादातर देशों में इस विचार को अपनाया गया। सरकारों ने निजी आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय को कम करने की कोशिश की है, स्वास्थ्य वित्तीयन के लिए धन के पूल में इज़ाफ़े और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार की कोशिश की; हालाँकि इसकी कवरेज के विस्तार में विभिन्नता है।[101] ग़रीबों की पहचान और उन तक पहुँच की चुनौती बरकरार है और संसाधनों के मामले में ग़रीब देश, जैसे लाओ पी.डी.आर. और वियतनाम दानदाताओं के समर्थन वाले स्वास्थ्य इक्विटी कोषों (donor-supported health equity funds) पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहे हैं।

- *थाइलैण्डः* थाइलैण्ड के 2002 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम में प्रत्येक नागरिक के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था थी। 2009 तक लगभग 4.8 करोड़ लोग या आबादी का 76% सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना में पंजीकृत हो गए थे, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने या फिर ओ.पी.डी. में मुफ्त उपचार, मातृत्व सेवाएँ, दंत सेवाएँ और आपातकालीन संरक्षा की सुविधाएँ थीं। यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 2011 में इसका कुल बजट 3.4 करोड़ डॉलर या हर बीमाधारी के लिए 70 डॉलर का था, जो राष्ट्रीय बजट का 5.9% है।[102]
- *मैक्सिको:* मैक्सिको की सरकार ने 2003 में एक सार्वजनिक बीमा योजना सेगुरो पापुलर (Seguro Popular) को मंजूरी दी। यह परंपरागत रूप से सामाजिक सुरक्षा से वंचित ग़रीब परिवारों के लिए योजना से समग्र स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक संसाधनों को बढ़ाया गया है और ज़्यादा निष्पक्ष रूप से उनका वितरण किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उनके उपयोग का विस्तार हुआ है। वित्तीय

संरक्षण के सूचकों में सुधार हुआ है। 2007 के अंत तक 2 करोड़ ग़रीबों को इस योजना का लाभ मिला।[103] एक अभिनव वित्तपोषण तंत्र को 7अपनाकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाने वाला मैक्सिको एक अगुआ के रूप में उभरा है।

- *रवाण्डाः* समुदाय-आधारित स्वास्थ्य बीमा शुरू करके रवाण्डा ने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार किया है। संसाधनों से प्रदर्शन को जोड़कर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ ज़्यादा सस्ती हुईं और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार सामने आए हैं। पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जो 2000 में प्रति 1000 बच्चों पर 196 थी, कम होकर 2007 में 1000 बच्चों पर 103 हो गई है। और माताओं के मृत्यु अनुपात में 2000 से 2008 के बीच प्रति वर्ष 12% से ज़्यादा की गिरावट आई है। मातृ स्वास्थ्य के मामले में रवाण्डा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर है। कई देशों में दोहरी सेवाओं का उदय एक चिंता का विषय है। भले ही सार्वजनिक प्रावधान सिद्धांत में सार्वभौमिक हैं, पर इसकी गुणवता और उपलब्धता कमज़ोर होने के चलते लोग महँगे निजी प्रदाताओं की तरफ उन्मुख हो सकते हैं।
- *चीनः* चीन की स्वास्थ्य सेवाओं की ज़्यादातर कामयाबी 1950 से 1980 के बीच हुई जब सरकार ने एक त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की। इसमें ग्रामीण इलाकों में ग्राम दवाखाने, टाउनशिप स्वास्थ्य केंद्र और काउंटी अस्पताल व शहरी इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल शामिल थे। 1980 के दशक के बाद से हालाँकि स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा के लिए शुल्क मॉडल पर चलने लगे। इसके परिणामस्वरूप चीन की कुल स्वास्थ्य स्थिति में तो लगातार सुधार हुआ, पर पूर्वी और पश्चिमी प्रांतों तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच असमानता बढ़ी। देश के कई हिस्सों में ग़रीबों के लिए गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ अ-वहनीय हो गई।
- *चिलीः* 1980 से पहले चिली की स्वास्थ्य प्रणाली मूलरूप से सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कोषों के जरिए सार्वजनिक वित्तपोषित थी। 1981 में स्वास्थ्य सुधार के बाद हालाँकि जोखिम बीमा शुरू किया गया और बाज़ार तंत्रों ने सुरक्षा के स्तरों का नियमन शुरू किया। 2006 तक कवरेज की एक दोहरी प्रणाली चलन में आ चुकी थी। लाभार्थियों के प्रीमियम और संघीय सरकार के कर राजस्व द्वारा वित्त पोषित फ़ोनासा (Fondo Nacional de Salud - FONASA) ने कुल आबादी के 69% को अपने दायरे में लिया लेकिन इसके संसाधनों की कमी समय पर और गुणवत्ता वाली सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में बाधा बनी।

सार्वभौमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन इस तरह किया जा सकता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दायरे में लाने के लिए गुणवत्ता के साथ समझौता न करें

लाभ के लिए काम कर रही मुख्य निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनी इसाप्रेस (Instituciones de Salud Previsional - ISAPRES) ने 17% आबादी को अपने दायरे में लिया है। फ़ोनासा इस समय एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना प्रदान करती है। इस दोहरी प्रणाली की आलोचना होती थी क्योंकि यह कम आय वाली और ज़्यादा जोखिम में जीने वाली आबादी को मुख्य रूप से सार्वजनिक प्रणाली में, जो संसाधनों के मामले में कमजोर है और इसलिए इसमें कमतर गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करती है, उपचार से वंचित कर देती थी।

2004 में खतरों से जागरूक होकर सरकार ने (El Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas– Plan AUGE) शुरू किया जो एक चिकित्सा लाभ पैकेज की गारंटी देता है। इसमें 56 रोगों के लिए परीक्षण और उपचार की प्राथमिकता सूची और सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक कवरेज का प्रावधान है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान और कम से कम नौ साल की अनिवार्य शिक्षा के लिए राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता, सहभागिता और निरन्तरता की ज़रूरत होती है। दक्षिण में देशों के सामने चुनौती है स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुँच में समता और एक बुनियादी गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना ताकि एक ऐसे द्विमार्गी उद्योग से बच सकें जो ग़रीबों को तो नीची गुणवत्ता मुहैया कराता है (या कराता ही नहीं) और अमीरों को उच्चतर निजी सेवाएँ देता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन इस तरह किया जा सकता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दायरे में लाने के लिए गुणवत्ता के साथ समझौता न करें। ग़रीबों के पास सार्वजनिक प्रणाली का विकल्प नहीं होता लेकिन अमीर कीमत देकर निजी सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं। यह स्थिति असमानता बढ़ाती है, सामाजिक एकीकरण को कमजोर करती है और समावेशी मानव विकास को कमतर कर देती है। चीन, मेक्सिको और थाइलैण्ड जैसे देशों में शुरू किए गए नए कार्यक्रमों ने सभी के लिए और उचित गुणवत्ता वाली मूलभूत सेवाएँ सुनिश्चित कराने की संभावनाओं का खाका खींचा है। जब वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होगी तो सार्वजनिक सेवाएँ, निजी सेवाओं की तुलना में घटिया नहीं होंगी।

विकास के माध्यम से सामाजिक संघटन बढ़ाना

विकास को प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि सभी नागरिक दूसरों के प्रति आदर व दया की भावना और सामाजिक संघटन (cohesion) के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के साथ ही समाज के वृहत उद्देश्यों के तहत अपने अधिकारों का अनुभव कर सकें। इसके लिए राज्यों और नागरिकों को यह समझना होगा कि मानव विकास, मात्र व्यक्तिगत क्षमताएँ बढ़ाए जाने से कुछ अधिक है। हालाँकि यह एक व्यापक सामाजिक तंत्र से जुड़ा होता है, जिसकी बेहतर स्थिति सामाजिक सामर्थ्यों (competencies) को

बढ़ाए जाने से सम्बन्धित होती है। (अध्याय 1 में बॉक्स 1.7 देखें)

व्यक्तियों और समुदायों के अपने कल्याणार्थ जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए अधिक सक्षम सामाजिक सुरक्षा तंत्रों की भी ज़रूरत होती है। वैश्वीकरण ने, विशेषकर सार्वभौमिक प्रसार और व्यापक सरकारी व्यय पर आश्रित रहने वाले तंत्रों के संदर्भ में, सामाजिक सुरक्षा के कुछ आयामों को कमज़ोर किया है। परंतु इसी के साथ इससे सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता भी बढ़ी है क्योंकि अब आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव की निरंतरता में बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि मानव विकास के उन्नयन में सामाजिक नीतियाँ भी आर्थिक नीतियों की ही भाँति महत्वपूर्ण हो गई हैं। दरअसल, सामाजिक और आर्थिक नीतियों को पृथक करके देखना संभव नहीं है क्योंकि उनके लक्ष्य और उपकरण एक समान हैं।[104]

दक्षिण के बहुत से देशों ने नई अर्थव्यवस्था से निर्धनों को जोड़ने के लिए उनके लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की है। विशेषकर नकद अंतरण कार्यक्रम पुनर्वितरण के माध्यम से निर्धनता और आय असमानता में कमी लाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। परंतु अंतरण, सरकार द्वारा किए गए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधानों का विकल्प नहीं हो सकते (बॉक्स 3.8)। वे निर्धनों के लिए पूरक संसाधन होने से अधिक कुछ नहीं हैं। लोगों को अपनी पसंद की स्वास्थ्य सुविधाएँ खरीदने में सक्षम बनाने के लिए नकद सहायता उपलब्ध कराने से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती, जहाँ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का ही गंभीर अभाव हो। इसी प्रकार, स्कूल को चुनने में दी गई नकद सहायता निर्धनों के काम नहीं आ सकती यदि गुणवत्तापूर्ण स्कूलों की संख्या ही कम हो। और न ही नकद अंतरण यथोचित रोज़गार के ज़रिए आय प्राप्त करने का विकल्प हो सकता है।

- *भारतः* भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (नरेगा) ने ग्रामीण निर्धनों को कृषि क्षेत्र में न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध कराने के लिए 100 दिनों के अकुशल मानवीय श्रम की व्यवस्था की है। यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौसमी कार्य के विचलनों के विरुद्ध निर्धनों की आय तक पहुँच के साथ उनके लिए कुछ राहत उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही यह लोगों में काम से जुड़े आत्म-सम्मान और सशक्तीकरण की भावना को उत्पन्न करती है।[105] इसके अतिरिक्त यह अधोसंरचना का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का लक्ष्य भी रखती है।

नकद अंतरण कार्यक्रम–जो निर्धनता और आय असमानता में कमी लाने में महत्वपूर्ण हैं– सरकार द्वारा किए गए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधानों का विकल्प नहीं हो सकते

बॉक्स 3.8

केवडेट यिलमाज, विकास मंत्री, तुर्की

तुर्की में सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

हाल तक 2002 में तुर्की की अनुमानित 30% आबादी ग़रीबी सीमा 4.30 डॉलर रोजाना से कम पर रहती थी। सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी खर्च का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद का केवल 12% था जो यूरोपीय संघ के औसत 25% के आधे से कम था। और ग़रीबों के लिए सामाजिक सहायता पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.5% था। इससे तुर्की की सामाजिक सहायता प्रणाली की आलोचना होती थी कि वह विखंडित और अपर्याप्त, दोनों है।

लेकिन, पिछले दशक के दौरान तुर्की के मज़बूत आर्थिक प्रदर्शन के साथ-साथ सामाजिक नीतियों में ग़रीबों के हितों का ध्यान रखने वाले दृष्टिकोण और काफ़ी ज़्यादा संसाधनों के साथ लक्षित सहायता से ग़रीबी कम करने के प्रयासों को बढ़ावा मिला है। मुख्य नीतिगत बदलावों में सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से मज़बूत बनाना, सशर्त नकद अंतरण, सामाजिक सुरक्षा सुधार और राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एक महत्वाकांक्षी बदलाव शामिल हैं। 2003 में शुरू किए गए केवल सशर्त नकद अंतरण कार्यक्रम के तहत 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओ की सहायता प्राप्त हुई और तकरीबन 22 लाख लोगों को शिक्षा सहायता से लाभ पहुँचा है। एक नए मुफ्त स्कूली किताब कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को 2003 से 1.3 बिलियन से ज़्यादा किताबें हासिल हुईं और तकरीबन 10 लाख बच्चों को स्कूल के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

इनके और अन्य प्रयासों के परिणामस्वरूप 4.30 डॉलर से कम पर रोजाना जिंदगी बसर करने वाली आबादी के प्रतिशत में तेजी से गिरावट आई है। 2010 में ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कुल आबादी की 3.7% तक आ गई । इसी दौरान ग़रीबों के लिए सहायता और सम्बन्धित सामाजिक सेवाओं के लिए खर्च की जाने वाली राशि का स.घ.उ. में हिस्सा तकरीबन तिगुना होकर 1.2% हो गया।

यूरोपीय संघ के औसत की तुलना में तुर्की के स.घ.उ. में सामाजिक खर्च की हिस्सेदारी अब भी कम है और सामाजिक सहायता योजनाएँ ग़रीबी की दरों पर अपेक्षित प्रभाव अभी नहीं डाल सकी हैं। उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सरकार ग़रीबी मापन और सामाजिक सुरक्षा के नए तरीकों पर काम कर रही है। वस्तुओं के रूप में और नकद सहायता के नए दृष्टिकोण, रोज़गार संभावनाओं के दृढ़तर सूत्र और लक्षित समुदायों और परिवारों के साथ लगातार परामर्श इनमें शामिल हैं।

इसी तरह, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक प्रत्यक्ष मापनीय प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य बीमा अब पूरी आबादी के लिए उपलब्ध है। 2003 में शुरू किए गए स्वास्थ्य रूपांतरण कार्यक्रम के तहत मुफ्त प्राथमिक एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओ के साथ पारिवारिक चिकित्सकों को परिवारों की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। इसके परिणाम तेज़ और उत्साहजनक रहे हैं। पहली बार तकरीबन सभी बच्चों को नियमित रूप से मुफ्त टीके मिल रहे हैं। 70 लाख स्कूली बच्चों को रोजाना मुफ्त दूध मिल रहा है। माताओं और बच्चों को बिना किसी शुल्क के आयरन और विटामिन डी की खुराक उपलब्ध कराई जाती है। शिशु मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आई है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार 2003 में यह 1000 जन्मे शिशुओं पर 29 थी, जो घटकर 2010 में 10 के आँकड़े तक आ गई है। आठ वर्षों के भीतर दो तिहाई की यह गिरावट सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के तहत तय किए गए लक्ष्य को बेहतर ढंग से पार कर गई है।

बाल-हितैषी नीतियाँ स्वास्थ्य सेवाओ और शिक्षा से परे जाकर उनके स्थानीय समुदायों के लिए व्यापक सहायता तक जाती हैं। सरकार ने सामाजिक संघटन विकसित करने और सामाजिक एकीकरण को, विशेषकर देश के कम विकसित पूर्वी क्षेत्रों में, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2008 में शुरू किया। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक जीवन में अ-लाभितों की भागीदारी को बढ़ाना है, जो ग़रीबी और सामाजिक बहिष्करण के कारण हाशिए पर पड़े हैं। कम आय वाले क्षेत्रों में प्रचलित इन हज़ारों परियोजनाओं के लक्ष्य सिर्फ नौकरियाँ पैदा करने से कहीं आगे जाते हैं। इनमें शामिल है युवा लोगों और महिलाओं के लिए सहायता, जिससे वे अपने आपको सांस्कृतिक, कलात्मक और एथलेटिक उपलब्धियों के ज़रिए अभिव्यक्त कर सकें।

हालाँकि ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये सुधार तुर्की के सामान्य परिवारों के जीवन के लिए क्या मायने रखने लगे हैं। पूरे देश भर में माता-पिता और बच्चे, सब एक स्वस्थ, ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा संतोषजनक जिंदगी की आशा कर सकते हैं– जो मानव विकास का आधार लक्ष्य और मूल सिद्धांत है।

इस योजना में सामाजिक अंकेक्षण, उन्नत पर्यवेक्षण और सूचना तंत्र जैसी कई नवाचारी विशेषताएँ भी हैं।

- *चीनः* बढ़ते हुए निजीकरण और वैश्विक बाज़ार के साथ जुड़ने से आई सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नई चुनौतियों से निपटने के लिए चीन सरकार की प्रमुख प्रतिक्रिया है न्यूनतम आजीविका गारंटी योजना। यह वास्तविक आय और स्थानीय स्तर पर निश्चित की गई निर्धनता रेखा के मध्य के अंतराल को भर कर शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम आय की गारंटी देती है। इसलिए चीन में आय में असमानता बढ़ने के बाद भी निर्धनता घटाने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुनर्वितरण नीतियों की संभावनाएँ बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, शहरों में प्रवासियों को समान अधिकार देने का भी तुलनीय सामाजिक सेवाओं तक पहुँचने की उनकी योग्यता पर निर्णायक प्रभाव पड़ सकता है।
- *ब्राजीलः* चीन और भारत की तुलना में धीमी आर्थिक प्रगति के बाद भी ब्राज़ील ने ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा के प्रसार और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने जैसे उपायों से असमानता घटाई है। 2001 में प्रारंभ होने वाले इसके सशर्त नकद अंतरण कार्यक्रम बोल्सा एस्कोला (Bolsa Escola) ने मैक्सिको के प्रोग्रेसा (वर्तमान नाम अपॉर्च्युनिडेड्स (Oportunidades) बॉक्स 3.9) जैसे लैटिन अमेरिका के देशों के अवधारणात्मक आधार का अनुसरण किया। बोल्सा एस्कोला को 2003 में बहुत से अन्य नकद और वस्तु अंतरण कार्यक्रमों को कारगर प्रशासन के अंतर्गत एक एकीकृत लक्षित व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करते हुए बोल्सा फ़ैमिलिया (Bolsa Familia) के नाम से विकसित किया गया। बोल्सा फ़ैमिलिया कार्यक्रम 2009 तक देश भर के 1.2 करोड़ परिवारों या लक्षित जनसंख्या के 97.3% से अधिक लोगों तक विस्तृत हुआ। इन कार्यक्रमों ने बग़ैर बैंक खातों वाली कम आय की माताओं के लिए ए.टी.एम. कार्डों की उपलब्धता जैसे नवाचारी वितरण माध्यमों का विकास करते हुए कार्यक्रम प्रशासन और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्रों में बड़ी सफलता अर्जित की। इसी के परिणामस्वरूप निर्धनता और अतिनिर्धनता जैसी स्थितियों में संतोषजनक गिरावट और असमानता में कमी हुई।[106]
- *चिलीः* यह देखते हुए कि सरकारी अनुदान चरम निर्धनों तक नहीं पहुँच रहे थे, 2002 में सहायता और कौशल विकास के मिश्रण के साथ चरम निर्धन वर्ग तक पहुँचने के लिए चिली सॉलिडेरियो (Chile Solidario) नामक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। परिवारों की सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस कार्यक्रम ने इस धारणा को अपना आधार बनाया कि चरम ग़रीबी बहुआयामी होती है। यह मात्र आय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपर्याप्त मानवीय व सामाजिक पूँजी और बीमारी, दुर्घटना व बेरोज़गारी जैसी सामान्य घटनाओं से निपटने में बाधा बनने वाली कमज़ोरियों को दूर करने की ज़रूरत भी सम्मिलित होती है। अन्य सामाजिक नीतियों के साथ यह कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था के उछाल के समय में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की तीव्रता में वृद्धि करता है, वहीं आर्थिक मंदी के दौर में यह निर्धनों के लिए आवश्यक सुरक्षा तंत्र की उपलब्धता कर एक प्रतिचक्रीय भूमिका निभाता है।

बॉक्स 3.9

सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम और मैक्सिको का अपॉर्च्युनिडेड्स (Oportunidades)

सशर्त नकद अंतरण कार्यक्रमों को लाभार्थियों की आय और चिकित्सालयों तक जाने और स्कूल में उपस्थिति जैसी आवश्यकताओं पर अंतरण को सशर्त बनाकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक उनकी पहुँच को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये कार्यक्रम निश्चित लाभार्थियों (विशेषकर कम आय या वंचित परिवारों के लोगों) पर ध्यान केंद्रित करता है और इन वर्गों के लिए वस्तुओं के स्थान पर नकद सहायता की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त ये अंतरण स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर सशर्त होते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रभावशीलता के कड़े मूल्यांकन की व्यवस्था हो सकती है। उदाहरण के लिए, पराग्वे में टेकोपोरा कार्यक्रम ने पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और निर्धनता में कमी पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाए हैं और श्रम आपूर्ति पर भी इसका प्रभाव नकारात्मक नहीं रहा है।

मैक्सिको का अपॉर्च्युनिडेड्स एक सशर्त अंतरण कार्यक्रम है, जो बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति, मेडिकल चेकअप और निजी स्वास्थ्य व सफाई के सम्बन्ध में लाभार्थियों को सूचना देने वाली सामुदायिक बैठकों में उपस्थिति की शर्त पर ग़रीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह निर्धनता के पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारण के क्रम को तोड़ता है। मूल रूप से प्रोग्रेसा कहलाए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके वर्तमान और भविष्य की निर्धनता में कमी लाना है। 1997 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम विश्व के सर्वाधिक व्यापक सशर्त नकद अंतरण कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत 2012 में लगभग 50 लाख लाभार्थी परिवारों को लगभग तीन बिलियन डॉलर वितरित किए गए।

परिवारों की महिला प्रमुखों को हर दो महीने में दिए जाने वाले अपॉर्च्युनिडेड्स हस्तांतरण के दो भाग हैं। पहला भाग सभी लाभार्थी परिवारों को दिया जाता है और इसमें एक नियत खाद्य वजीफ़े की इस शर्त पर व्यवस्था होती है कि परिवार के सदस्य निवारक चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करेंगे और इसका उद्देश्य बेहतर पोषण पर खर्च करने में परिवारों की मदद करना है। दूसरा भाग शैक्षिक छात्रवृत्तियों के रूप में होता है और यह उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिनकी स्कूल में न्यूनतम 85% उपस्थिति दर्ज हो और जो एक कक्षा में दो वर्ष से अधिक न रहे हों। कक्षा और उम्र के अंतर के अधीन रहते हुए शैक्षिक भत्ता 18 वर्ष से कम आयु वाले और प्राथमिक स्कूल की तीसरी कक्षा तथा जूनियर हाईस्कूल की तीसरी (अंतिम) कक्षा के बीच नामांकित होने वाले प्रत्येक बच्चे को दिया जाता है। इसकी मात्रा प्राथमिक स्कूल की तुलना में स्नातक कक्षाओं में अधिक होती है और यह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के दौरान बालकों की तुलना में बालिकाओं के लिए अधिक होता है। लाभार्थी बच्चे वर्ष में एक बार स्कूल आपूर्ति के लिए भी धन पाते हैं।

सशर्त नकद अंतरण कार्यक्रमों की लागत वस्तु-आधारित परंपरागत सामाजिक सहायता कार्यक्रमों की तुलना में कम होती है। लैटिन अमेरिका के दो सर्वाधिक बड़े कार्यक्रम ब्राज़ील के बोल्सा फ़ैमिलिया और मैक्सिको के अपॉर्च्युनिडेड्स की लागत सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से कम है। कुछ मामलों में उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सार्वभौमिक मौलिक अधिकारों तक पहुँच उपलब्ध कराने का माध्यम माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें सेवाओं की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण स्थानीय क्षेत्रों में वंचितताओं को बढ़ाने का दोषी भी माना जाता है।

स्रोतः हैलू एंड वेरास सोएरस 2008; रिबास, वेरास सोएरस और हीराता 2008

यही कारण है कि उदयशील दक्षिण एक ऐसे व्यापक सामाजिक और ग़रीबी उन्मूलन एजेंडे का विकास कर रहा है जिसमें असमानताओं, संस्थागत विफलताओं, सामाजिक अड़चनों और व्यक्तिगत कमजोरियों को दूर करने वाली नीतियाँ उतनी ही महत्व की हो गई हैं, जितनी आर्थिक प्रगति सम्बन्धी नीतियाँ। इस एजेंडे की आवश्यकता अनुभव किए जाने का कारण इस समझ का विकसित होना है कि सामाजिक चुनौतियों का विस्तार आय की निर्धनता से परे भी है। इन चुनौतियों में शिक्षा तक पहुँच की कमी, कमज़ोर स्वास्थ्य, सामाजिक असमानता और सीमित सामाजिक एकीकरण शामिल हैं।

* * *

मानव विकास का उन्नयन करने वाले विकासपरक परिवर्तन के लिए एजेंडा बहुआयामी होता है। यह आधारभूत सामाजिक सेवाओं तक पहुँच का सार्वभौमीकरण, जनसंख्या, विशेषकर निर्धनों के लिए, अधिक ऋण की उपलब्धता, साझा संसाधनों की रक्षा और जहाँ आवश्यकता हो, भूमि सुधार लागू करके लोगों की संपत्ति का प्रसार करता है। यह लाभों का असमान वितरण होने पर समानता आधारित प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थानों के कार्यकरण में सुधार लाता है। रोज़गारों की उच्च स्तरीयता सुनिश्चित करने के लिए यह रोज़गार और कार्य में तीव्र प्रगति को अपनी प्राथमिकता में ऊपर रखता है। यह आर्थिक क्रियाओं और सामाजिक गतिशीलता की राह में बाधक बनने वाली नौकरशाही और सामाजिक अड़चनों में कमी लाता है। यह नेतृत्व को जवाबदेह बनाए रखता है। यह बजट प्राथमिकताओं को तय करने और सूचना के प्रसार के लिए समुदायों को लगातार जोड़े रखता है। और यह सामाजिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

दक्षिण के बहुत से देशों ने यह दिखाया है कि एक विकासपरक राज्य से क्या हासिल किया जा सकता है। लेकिन अधिक उपलब्धियों वाले देशों की भी भविष्य में सफलता तय नहीं है। दुनिया भर के देश बढ़ती असमानता और पर्यावरण अपकर्ष जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अगला अध्याय इन्हीं चुनौतियों और भविष्य में मानव विकास की प्रगति को बनाए रखने के उपायों को सम्बोधित है।

एक ऐसे व्यापक सामाजिक और ग़रीबी उन्मूलन एजेंडे की ज़रूरत है, जिसमें असमानताओं, संस्थागत विफलताओं, सामाजिक अड़चनों और व्यक्तिगत कमज़ोरियों को दूर करने वाली नीतियाँ उतनी ही महत्व की हैं जितना आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देना

बॉक्स 3.10

माइकल ब्लूमबर्ग, मेयर, न्यूयॉर्क शहर

निर्धनता उन्मूलन नीति पर परामर्श के लिए न्यूयार्क शहर दक्षिण की ओर क्यों देखता है

न्यूयॉर्क शहर में हम अपने निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत तरह से काम कर रहे हैं। हम अपने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। हमने धूम्रपान और मोटापे में कमी लाते हुए न्यूयॉर्क निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार किया है। और हमने साइकिलों के लिए अलग रास्तों की व्यवस्था और लाखों पेड़ लगाकर शहर की प्राकृतिक छटा को बेहतर बनाया है।

हमने आत्म-पर्याप्तता (self-sufficiency) के निर्माण के नए और बेहतर तरीके खोज कर ग़रीबी घटाने और अपने युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश की है। हमने इस प्रयास को गति देने के लिए *आर्थिक अवसर केंद्र* की स्थापना की है। इसका उद्देश्य नवाचारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पहलों के माध्यम से ग़रीबी के चक्र को तोड़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है।

विगत छह वर्षों में इस केंद्र ने शहरी एजेंसियों और सैकड़ों समुदाय-आधारित संगठनों के सहयोग से 50 से अधिक पायलट कार्यक्रम शुरू किए हैं। केंद्र ने प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक विशिष्ट मूल्यांकन रणनीति तैयार की है, ताकि उनके काम पर निगाह रखी जा सके, उनकी तुलना की जा सके और यह निश्चित किया जा सके कि ग़रीबी घटाने और अवसरों को बढ़ाने में कौन सी रणनीतियाँ सर्वाधिक सफल रही हैं। सफल पाए जाने वाले कार्यक्रमों को नए सार्वजनिक और निजी कोषों के माध्यम से जारी रखा जाता है। असफल कार्यक्रमों को रोक दिया जाता है और संसाधनों को नई रणनीतियों में लगाया जाता है। इसके बाद केंद्र की रिपोर्टों को देश और विश्व भर की सरकारी एजेंसियों, नीति निर्माताओं, अलाभकारी सहयोगियों व निजी दानदाताओं और अन्य सहयोगियों से भी साझा किया जाता है, जो ग़रीबी के चक्र को तोड़ने के नए रास्तों की तलाश कर रहे हैं।

न्यूयॉर्क भाग्यशाली है कि हमारे व्यापार क्षेत्र और विश्वविद्यालयों में विश्व के चंद सर्वाधिक मेधावी दिमाग काम कर रहे हैं, परंतु हम जानते हैं विश्व में दूसरी जगहों पर विकसित कार्यक्रमों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसीलिए केंद्र ने अपने काम की शुरुआत आशाजनक निर्धनता उन्मूलन रणनीतियों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वे से की।

केंद्र ने 2007 में संयुक्त राज्य के पहले सशर्त नकद अंतरण कार्यक्रम के रूप में अपॉर्च्युनिटी एन.वाई.सीः फैमिली रिवाइर्स (Opportunity NYC: Family Rewards) की शुरुआत की। केन्द्र 20 दूसरे देशों में चल रहे समान कार्यक्रमों पर आधारित फैमिली रिवाइर्स परिवारों को निवारक चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा और रोज़गार प्रशिक्षण के लिए ज़रूरी पैसा उपलब्ध कराता है। फैमिली रिवाइर्स की संरचना तैयार करने में हमने मैक्सिको, ब्राज़ील और दर्जन भर अन्य देशों से सीख ली। हमारी तीन वर्ष की पायलट परियोजना पूरी होने होने के बाद हम सीख चुके थे कि कौन से प्रावधान न्यूयॉर्क शहर के लिए उपयोगी हैं और कौन से नहीं। इससे प्राप्त जानकारी विश्व भर में नई पीढ़ी के कार्यक्रमों के लिए उपयोगी साबित हुई है।

इस रिवाइर्स की शुरुआत से पहले मैं मैक्सिको के सफल परिसंघीय सशर्त नकद अंतरण कार्यक्रम अपॉच्युनिडेड्स (Oportunidades) का जायजा लेने के लिए टोलुका (मैक्सिको) गया। हमने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित उत्तर-दक्षिण अधिगम विनिमय (North-South Learning Exchange) में भी सहभागिता की। हमने लैटिन अमेरिका के साथ इण्डोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में सशर्त नकद अंतरण कार्यक्रमों पर अनुभवों को साझा करने के लिए रॉकेफ़ेलर फाउंडेशन, विश्व बैंक, अमेरिकी राज्यों के संगठन व अन्य संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माताओं के साथ काम किया।

हमारे अंतरराष्ट्रीय अधिगम विनिमय इन नकद अंतरण पहलों तक सीमित नहीं हैं। इनमें शहरी परिवहन के नवाचारी दृष्टिकोण, नई शैक्षिक पहलों और अन्य कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाता है।

अच्छे विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, इसी कारण न्यूयॉर्क शहर अन्य शहरों और देशों के बेहतरीन अनुभवों से सीखना लगातार जारी रखेगा। चूँकि हम अपने शहर में नए कार्यक्रमों को अपनाते और उनका मूल्यांकन करते हैं, इसलिए हम बदले में कुछ देने और विश्वभर के समुदायों में प्रभावी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

‘‘जो पिछली पीढ़ी ने बोया है,
प्रत्येक अगली पीढ़ी वही काटेगी।’’

चीन की एक कहावत

‘‘हमें आधी मानव जाति, महिलाओं, को
आज़ाद करना होगा, ताकि वे शेष आधी
को आज़ाद करने में मदद कर सकें।’’

एमलाइन पैंकहर्स्ट

4.

गति क़ायम रखने की चुनौती

विकासशील देश मानव विकास के क्षेत्र में त्वरित गति से हो रही प्रगति की दृष्टि से विशेषतौर पर, हाल के दशकों में, चर्चा में रहे हैं। लेकिन भविष्य का क्या होगा? ये देश क्या इसी गति से मानव विकास के क्षेत्र में प्रगति जारी रखेंगे और क्या दक्षिण के दूसरे देश इससे लाभान्वित होंगे? सही नीतियाँ हों तो, हाँ। इसके लिए सही नीतियों में समता बढ़ाने, सहभागिता तथा अभिव्यक्ति को बुलन्द करने, पर्यावरणीय दबावों का मुकाबला करने व जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का प्रबंधन करने की ज़रूरत होगी। नीति निर्धारकों को महत्वाकांक्षी नीतियाँ निर्धारित करने के प्रयास करने होंगे और नीतिगत निष्क्रियता के गभीर दुष्परिणामों को समझना होगा।

विकासशील देशों के नीति निर्धारकों को आगामी कुछ वर्षों में एक ऐसा महत्वाकांक्षी एजेंडा अपनाना होगा जो कठिन वैश्विक परिस्थितियों का अनुकूल जवाब दे सके, विशेषतौर पर उस आर्थिक मंदी का, जिसने उत्तर की माँग कम की है। इसके साथ ही उन्हें अपनी महत्वपूर्ण व तात्कालिक नीतिगत प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देना होगा।

विकासशील देशों के लिए नीतिगत प्राथमिकताएँ

विकासशील देशों को यदि हाल के दशकों में प्राप्त हुई उपलब्धियों का सिलसिला बनाए रखना है और जो देश पिछड़ भी रहे हैं, उन्हें यदि इनसे लाभान्वित करना है, तो चार नीतिगत प्राथमिकताएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैंः

- *समता संवर्धन.* समता और सामाजिक न्याय स्वयं में तो बहुत ज़रूरी हैं ही, साथ ही ये क्षमताएँ बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण हैं।[1] असमता के बढ़ने या इसके लगातार बने रहने के कारण मानव विकास की गति बनाए रखना बहुत कठिन है।[2] विशिष्ट क्षमताओं में असमता, जिसे उदाहरण के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा के परिणामो में अन्तर के रूप में मापा जाता है, मानव विकास की प्रगति में बाधा डालती है, हालाँकि इनका प्रभाव कम स्पष्ट नज़र आता है। इन नकारात्मक सम्बन्धों में सबसे महत्वपूर्ण है लिंग असमानता, महिला का स्वास्थ्य और शिक्षा, जो जनसांख्यिकीय व मानव विकास सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में और अन्य स्थानों पर आय की असमानता में भारी कमी लाई गई है, लेकिन सभी देश स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में समानता के महत्व को नहीं समझते हैं।[3]
- *अभिव्यक्ति और सहभागिता को सम्भव बनाना.* जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है और सूचना व संचार तकनीक का विस्तार होता है, लोग राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक सहभागिता की माँग करने लगते हैं, फ़ैसले लेने वालों को अधिक जवाबदेह होने और खुली चर्चा के लिए अवसर बढ़ाने की चुनौती देते हैं। ऐसे समय में जब बेरोज़गारी बढ़ रही हो और आर्थिक परिदृश्य बिगड़ रहे हों, राजनीतिक सहभागिता के सीमित अवसरों से, सामाजिक असंतोष भड़क सकता है। राजनीतिक सहभागिता के अवसरों को बढ़ाने के साथ ही इन्सान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति सरकार की अधिक जवाबदेही मानव स्वतंत्रता और सतत मानव विकास को बढ़ा सकती है। अपेक्षाकृत वंचितों की सुदृढ़ राजनीतिक सहभागिता से मानव विकास के पक्षधर नीतिगत बदलावों को महत्वपूर्ण समर्थन मिलता है।
- *पर्यावरणीय दबावों का मुकाबला करना.* जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय दबाव तथा पारिस्थितिकीय तंत्र से प्रायः सभी देशों पर, वे विकास की जिस भी अवस्था में हों, पर्यावरण का निरन्तर दबाव बढ़ रहा है। यदि तत्काल आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में मानव विकास की गति जोखिम में पड़ जाएगी। *मानव विकास रिपोर्ट 2011* के लिए विकसित किए गए परिदृश्यों के परिप्रेक्ष्य में यह रिपोर्ट इन चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक कार्रवाई करने की ज़रूरत पर बल देती है।
- *जनसांख्यिकीय बदलावों का प्रबंधन करना.* कुछ विकासशील देशों, अधिकांशतः सब-सहारा अफ्रीकी देशों में, युवक भारी संख्या में रोज़गार क्षेत्र में आ रहे हैं। दूसरे देशों, खासतौर पर पूर्वी एशिया में, कार्यक्षम आयु के लोगों का अनुपात कम हो रहा है क्योंकि काम करने वाले लोगों में बुजुर्गों का अनुपात बढ़ रहा है। पर्याप्त उत्पादक रोज़गार सृजित करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए

नए नीतिगत हस्तक्षेप की ज़रूरत है।

मानव विकास के लिए अन्य चुनौतियाँ भी होंगी, इनमें माल, खासतौर पर खाद्य पदार्थों और ईंधन, की बढ़ती कीमतें शामिल हैं। तेज़ी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया में इन और अन्य चुनौतियों से एक पेचीदा माहौल बनेगा जिसमें परिस्थिति-जन्य खतरे भी शामिल होंगे। इनमें प्रगति की पलट गति (progress reversal), बढ़ती हुई असुरक्षा और असमानता शामिल हैं। ऐसे पेचीदा माहौल में भविष्य के लिए कोई भी आकलन करना बहुत कठिन है, क्योंकि इन अनुमानों को बनाने में कई महत्वपूर्ण परिवर्त (variables) छूट सकते हैं, जैसे तकनीकी विकास, जो उत्पादन और श्रमिक से जुड़ी क्षमताओं में नाटकीय बदलाव ला सकता है। फिर भी अलग-अलग परिदृश्यों के पूर्वनुमान से नीतियों के विकल्प और उनके संभावित प्रभावों को समझने में मदद मिलती है।

समता संवर्धन

अधिक समता, पुरुषों व महिलाओं के बीच और, साथ ही, विभिन्न समूहों के बीच, (जैसे धार्मिक, जातीय एवं अन्य) केवल अपने आप में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानव विकास के लिए भी अनिवार्य है। समता और मानव विकास को आगे बढ़ाने में सबसे शक्तिशाली है शिक्षा, जो व्यक्ति की क्षमताओं का निर्माण करती है, उसके विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता का विस्तार करती है। शिक्षा लोगों के आत्म विश्वास को बढ़ाती है

बॉक्स 4.1

कोरिया गणतंत्र और भारत में जनसंख्या की सम्भावनाओं में भिन्नता क्यों

कोरिया गणतंत्र में शैक्षिक स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सन् 1950 में जहाँ स्कूल जाने की आयु के बच्चों का एक बहुत बड़ा वर्ग किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करता था, वहीं आज युवा कोरियाई महिलाएँ दुनिया की सबसे शिक्षित महिलाएँ हैं, आधे से अधिक ने कॉलेज स्तर की शिक्षा पूर्ण कर ली है। इसके परिणामस्वरूप भविष्य के बुजुर्ग कोरियाई आज के बुजुर्ग कोरियाइयों के मुकाबले अधिक शिक्षित होंगे (आँकड़े देखें) और शिक्षा व स्वास्थ्य में सकारात्मक सम्बन्ध होने के कारण उनके अधिक स्वस्थ होने की भी सम्भावना है।

यह मानते हुए कि नामांकन की दर (जो अभी बहुत अधिक है) स्थिर रहेगी, 14 वर्ष से कम आयु की आबादी का अनुपात 2010 के 16% के मुकाबले 2050 में गिर कर 13% रह जायेगा। आबादी की शैक्षिक संरचना में भी उल्लेखनीय परिवर्तन होगा, उच्च स्तर की शिक्षा का अनुपात 26 से बढ़ कर 47% होने का अनुमान है। भारत के लिए परिदृश्य बहुत अलग दिखता है। सन् 2000 से पहले आधी से अधिक वयस्क जनसंख्या को कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। हाल ही में बेसिक शिक्षा में हुए विस्तार और शिक्षा प्राप्त भारतीयों की संख्या में प्रभावी वृद्धि (निस्सदेह इसका प्रमुख कारण हाल का आर्थिक विकास है) के बावजूद औपचारिक शिक्षा प्राप्त न कर सकने वाले वयस्कों का अनुपात बहुत धीमी गति से कम होगा। कुछ हद तक शिक्षा के इस निम्न स्तर के कारण, खासतौर पर महिलाओं की कमतर शिक्षा के, भारत की जनसंख्या के तेजी से बढ़ने का अनुमान है, और यह सर्वाधिक जनसंख्या वाले चीन को पीछे छोड़ देगा। बहुत ही आशावादी त्वरित गति परिदृश्य में भी, जिसमें कोरिया की भाँति शैक्षिक विस्तार हो, 2050 में भारत का शैक्षिक परिदृश्य बहुत ही असमान होगा, जिसमें अशिक्षित वयस्कों (अधिकांशतः वृद्ध) का प्रतिशत बहुत अधिक होगा। हालाँकि इस परिदृश्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार के चलते, बहुत शिक्षित युवा वयस्क श्रम बल का निर्माण होगा।

कोरिया गणराज्य तथा भारत की आबादी और शिक्षा का तुलनात्मक भविष्य

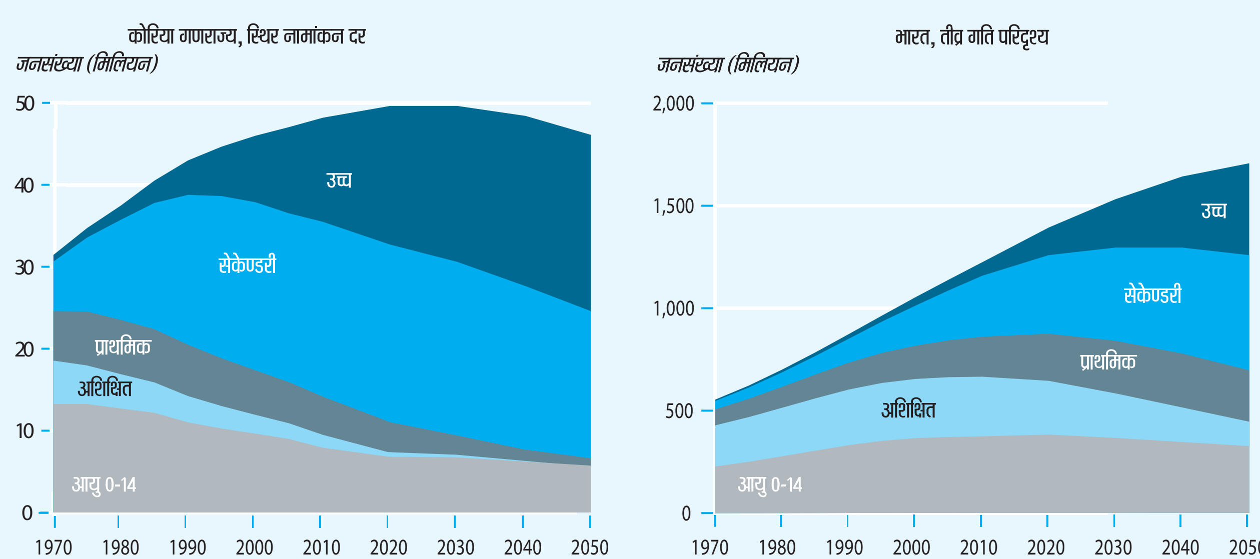

स्रोतः लुत्ज व के.सी. 2013

और उनके बेहतर कार्य ढूँढने के काम को आसान बनाती है, सार्वजनिक चर्चा में शामिल करती है और सरकार से स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अन्य हकों के लिए माँग करने की शक्ति प्रदान करती है।

स्वास्थ्य और मृत्यु दर को लेकर भी शिक्षा के आश्चर्यजनक लाभ हैं (कोरिया गणतंत्र और भारत में शिक्षा के भविष्य के अनुमानों के अंतर के लिए देखें बॉक्स 4.1)। पूरी दुनिया में प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि अभिभावकों की अच्छी शिक्षा, विशेषतौर पर माँ की शिक्षा, से बच्चे के जीवित रहने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। यही नहीं, कामकाजी महिलाओं और शिक्षित महिलाओं के (जो गर्भवती होने से पूर्व ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेती हैं) कम बच्चे होते हैं।[4] शिक्षित महिलाओं के बच्चे स्वस्थ भी होते हैं, जिनके जीवित रहने की सम्भावना ज़्यादा होती है (सारणी 4.1), इससे परिवार बड़ा करने की प्रवृत्ति कम होती है।[5] शिक्षित महिलाओं को गर्भ निरोधक उपाय ज़्यादा सुलभ होते हैं और वे इनका अधिक प्रभावी उपयोग करती हैं।[6]

जनसांख्यिकीय व स्वास्थ्य सर्वेक्षणों और सूक्ष्म-स्तर के सर्वेक्षणों के आधार पर इस रिपोर्ट में बलपूर्वक कहा गया है कि बच्चे के जीवित रहने की सम्भावनाओं में परिवार की आय या सम्पत्ति से कहीं ज़्यादा माँ की शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसके गम्भीर नीतिगत निहितार्थ हैं, परिवार की आय बढ़ाने के उपाय करने की बजाए लड़कियों की शिक्षा सुधारने पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है।

इस सम्बन्ध को बच्चों की मृत्यु दर के आँकड़ों के आधार पर भली भाँति दिखाया जा सकता है (सारणी 4.1)। कई अफ्रीकी देशों, खासतौर पर माली और नाइजर, में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। परन्तु सभी देशों में अधिक शिक्षित माताओं के बच्चों में मृत्यु दर कम है। कुछ देशों, जैसे नाइजीरिया में, बच्चों की निम्न मृत्यु दर प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी है, जबकि दूसरे देशों, जैसे लाइबेरिया और युगाण्डा में, यह अंतर स्पष्ट रूप से द्वितीयक शिक्षा से सम्बद्ध है।

बच्चे के जीवित रहने की सम्भावनाओं में परिवार की आय या सम्पत्ति से कहीं ज़्यादा माँ की शिक्षा महत्वपूर्ण है

इस रिपोर्ट के लिए करे गए पूर्वनुमानों में दो परिदृश्यों में 2010-2050 के दौरान शिक्षा के स्तर के बच्चों की मृत्यु दर पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा गया है। आधारिक परिदृश्य में यह माना गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी उल्लेखनीय नवीन आर्थिक सहायता या नीतिगत हस्तक्षेप के शिक्षा प्राप्ति की वर्तमान प्रवृत्तियाँ जारी रहेंगी। इस मान्यता के अन्तर्गत शिक्षा के अगले स्तर पर बच्चों के जाने का अनुपात, आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत करते हुए, समय के सापेक्ष स्थिर रहेगा (*देखें तकनीकी संलग्नक*)।

'तीव्र गति परिदृश्य' में यह माना गया है कि काफ़ी

सारणी 4.1

पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर, माँ के शैक्षिक स्तर के अनुसार

चुनिंदा देशों में, 2005 के बाद के अद्यतन उपलब्ध वर्ष के अनुसार

		पाँच से कम आयु में मृत्यु की दर (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर)				कुल प्रजनन दर (जन्म प्रति महिला)			
देश	सर्वेक्षण वर्ष	कोई शिक्षा नहीं	प्राथमिक	सेकेण्डरी या उच्च	कुल	कोई शिक्षा नहीं	प्राथमिक	सेकेण्डरी या उच्च	कुल
बांग्लादेश	2007	93	73	52	74	3.0	2.9	2.5	2.7
मिस्र	2008	44	38	26	33	3.4	3.2	3.0	3.0
इथियोपिया	2005	139	111	54	132	6.1	5.1	2.0	5.4
घाना	2008	103	88	67	85	6.0	4.9	3.0	4.0
भारत	2005/2006	106	78	49	85	3.6	2.6	2.1	2.7
इण्डोनेशिया	2007	94	60	38	51	2.4	2.8	2.6	2.6
लाइबेरिया	2009	164	162	131	158	7.1	6.2	3.9	5.9
माली	2006	223	176	102	215	7.0	6.3	3.8	6.6
नाइजर	2006	222	209	92	218	7.2	7.0	4.8	7.0
नाइजीरिया	2008	210	159	107	171	7.3	6.5	4.2	5.7
रवाण्डा	2007/2008	174	127	43	135	6.1	5.7	3.8	5.5
युगाण्डा	2006	164	145	91	144	7.7	7.2	4.4	6.7
जाम्बिया	2007	144	146	105	137	8.2	7.1	3.9	6.2

नोटः ये आँकड़े सर्वेक्षण होने के 10 वर्ष पहले के है।
स्रोतः लुत्ज व के.सी. 2013

महत्वाकांक्षी लक्ष्यों वाली शिक्षा नीति अपनाई जाएगी, जैसे लक्ष्य हाल के दशकों में कोरिया गणतंत्र में हासिल किए गए हैं, जहाँ स्कूली शिक्षा से अगले शैक्षिक स्तर पर जाने वाले छात्रों का अनुपात लगातार बढ़ता रहा है। इस तीव्र गति परिदृश्य के परिणाम माँ के शैक्षिक स्तर के बढ़ने के साथ ही बच्चों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाते हैं। मॉडल यह भी दर्शाता है कि शिक्षा में सुधार को अधिक प्राथमिकता दिए जाने पर, सभी देशों और क्षेत्रों में, लड़कियों की शिक्षा में सुधार के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बच्चों की मृत्यु दर में निरन्तर उल्लेखनीय गिरावट आएगी।

शिक्षा पर ज़्यादा ज़ोर देने से समस्त देशों और क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है

वर्ष 2010-2015 की अवधि के दौरान मरने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या भारत में सर्वाधिक है, लगभग 79 लाख और यह संख्या समूचे एशिया में पाँच वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या की लगभग आधी है।[7] पूर्वानुमानों की अंतिम अवधि 2045-2050 में आधारिक परिदृश्य के तहत करीब 61 लाख बच्चों की मृत्यु का अनुमान है लेकिन तीव्र गति परिदृश्य में यह संख्या इसकी ठीक आधी (31 लाख) होगी।

चीन की आबादी भारत से ज़्यादा है लेकिन वहाँ 2010-2015 की अवधि में मरने वाले बच्चों की संख्या भारत के एक चैथाई से कम (17 लाख) रहने का अनुमान है। शिक्षा के क्षेत्र में चीन में हुई उन्नति के कारण दोनों ही परिदृश्यों के पूर्वानुमान बहुत ही आशावादी हैं। चीन यदि तीव्र गति परिदृश्य अपनाता है, जैसा कि प्रतीत होता है, तो बच्चों की मृत्यु संख्या 2045-2050 तक घट कर लगभग पाँच लाख रह जाएगी, जो वर्तमान स्तर से एक तिहाई से भी कम है।

कुछ अन्य देशों के लिए पूर्वानुमान कम आशावादी हैं। उदाहरण के लिए केन्या में आधारिक परिदृश्य में बच्चों के मरने की संख्या 2010-2015 की 5,82,000 से बढ़ कर 2045-2050 में लगभग 16 लाख हो जाएगी। तीव्र गति परिदृश्य में 2045-2050 की अवधि में बच्चों के मरने की संख्या गिर कर 3,71,000 रह जाएगी, जो कि बेहतर स्थिति है, लेकिन यह 2010-2015 के स्तर से बहुत कम नहीं है।

बच्चों की मृत्यु दर में अनुमानित गिरावट अच्छी शिक्षा प्राप्त महिलाओं के कम बच्चे होने और इनमें कम बच्चों की मृत्यु होने के संयुक्त प्रभाव का परिणाम

सारणी 4.2

शिक्षा के परिदृश्य, 2010-2015, 2025-2030 तथा 2045-2050, के अनुसार पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित मृत्यु संख्या, (हज़ार में)

	2010-2015	2025-2030		2045-2050	
देश या क्षेत्र	आधारिक परिदृश्य	आधारिक परिदृश्य	तीव्र गति परिदृश्य	आधारिक परिदृश्य	तीव्र गति परिदृश्य
देश					
ब्राजील	328	224	177	161	102
चीन	1,716	897	871	625	526
भारत	7,872	6,707	4,806	6,096	3,064
केन्या	582	920	482	1,552	371
कोरिया गणतंत्र	9	8	9	7	7
माली	488	519	318	541	150
पाकिस्तान	1,927	1,641	1,225	1,676	773
दक्षिण अफ्रीका	288	198	165	134	93
क्षेत्र					
अफ्रीका	16,552	18,964	12,095	24,185	7,495
एशिया	15,029	11,715	8,924	10,561	5,681
यूरोप	276	209	204	196	187
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	1,192	963	704	950	413
उत्तरी अमेरिका	162	160	155	165	152
ओसियानिया	11	11	11	12	10

नोटः आधारिक और तीव्र गति परिदृश्यों पर चर्चा के लिए इस रिपोर्ट के अंत में *तकनीकी संलग्नक* देखें।
स्रोत.लुत्ज व के.सी. 2013.

दिखता है। इन अनुमानों से यह भी स्पष्ट होता है कि नीतिगत हस्तक्षेप का बेहतर प्रभाव वहाँ होता है, जहाँ शैक्षिक उपलब्धियाँ प्रारम्भिक तौर पर कमज़ोर थीं।

ये परिणाम घटते हुए लिंग भेद के महत्व को भी रेखांकित करते हैं, विशेष रूप से शिक्षा में और खासतौर पर निम्न मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) वाले देशों में। लैंगिक असमानता न केवल इसलिए खेदपूर्ण है कि यह महिला को सामाजिक अवसरों से वंचित करती है, बल्कि इसलिए भी कि इससे भावी पीढ़ियों की जीने की संभावनाएँ भी खतरे में पड़ती हैं।

अभिव्यक्ति और सहभागिता को सम्भव बनाना

मकबूल उल हक ने 1995 की *मानव विकास रिपोर्ट* में दिखाया कि जब तक आम आदमी की उन कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं में अर्थपूर्ण तरीके से सहभागिता नहीं होती, जो उनके जीवन को आकार देती हैं, तब तक राष्ट्रीय मानव विकास के मार्ग न तो वांछित होंगे और न ही टिकाऊ।

समतापरक और संवहनीय विकास के लिए जनसंवाद की ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत होती है जो नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और अपने सरोकारों को आवाज़ देते हुए राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। आम आदमी को नीति निर्धारण व परिणामों को प्रभावित करने में समर्थ होना चाहिए और युवाओं को बेहतर आर्थिक अवसरों और राजनीतिक जवाबदेही की आशा रहनी चाहिए। इस प्रक्रिया से बाहर रह जाने पर आम आदमी की अपने सरोकारों और ज़रूरतों को व्यक्त करने की क्षमता सीमित हो जाती है और इससे अन्याय बढ़ता है।

निरंकुश राज्य प्रतिबन्ध थोपते हैं, जिससे अनिवार्य स्वतंत्रता बाधित होती है, और यह सीधे-सीधे मानव विकास के लिए प्रतिगामी होता है। लेकिन कई लोकतांत्रिक देशों तक में ग़रीब लोगों और ग़रीब समुदाय को सूचना, अभिव्यक्ति या सार्वजनिक सहभागिता के सीमित अवसर उपलब्ध होते हैं, इन सबमें सुधार की ज़रूरत है। ग़रीबों के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपनी राजनीतिक आवाज़ प्रभावी बनाने के लिए एकजुट हो कर कार्य करें। फिर भी, कई देशों में ग़रीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों को समर्थन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों की जवाबदेही को, जो कि प्रायः सीमित अभिजात वर्ग तक ही संकुचित रहती है, सभी नागरिकों के लिए खोल देना चाहिए, विशेषतौर पर उनके लिए जिनका प्रतिनिधित्व जनसंवादों में कम होता है, जैसे महिलाएँ, युवा और ग़रीब।

जो सरकारें नागरिकों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देतीं या राजनीतिक सहभागिता के अवसरों का विस्तार नहीं करतीं, उन्हें अपनी वैधता गँवाने का खतरा रहता है। उत्तर और दक्षिण, दोनों ही क्षेत्रों में असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि लोग अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करने और नीतियों को प्रभावित करने के लिए अधिक अवसर चाहते हैं, खासतौर पर मौलिक सामाजिक सुरक्षा को लेकर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 'सामाजिक असंतोष सूचकांक' के आधार पर मापी गई सरकारों के प्रति असंतुष्टि 2010 के मुकाबले 2011 में 106 में से 57 देशों में बढ़ गई। सबसे ज़्यादा वृद्धि उत्तर के देशों में हुई, इसके बाद अरब और सब-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र के देश आते हैं।[9]

उत्तर में जनता कठोर बचत उपायों, सार्वजनिक खर्च में कटौती और नौकरियों में कमी के खिलाफ़ प्रदर्शन कर रही है, जैसा फ्रांस, यूनान, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है। नागरिकों ने सरकारों को चुनौती दी है कि वे अपनी नीतियों के सामाजिक दुष्प्रभावों पर ध्यान दें, क्योंकि कड़े बचत उपायों का ग़रीबों और सामाजिक रूप से वंचित लोगों पर असंगत बोझ पड़ रहा है।[10] असंतोष के अन्य कारणों में खाद्य पदार्थों के मूल्य, बेरोज़गारी और प्रदूषण के मुद्दे शामिल हैं :

- *खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें.* खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों के खिलाफ़ 2008 में हुए दंगों से 30 से अधिक अफ्रीकी और अरब देशों की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया।[11]
- *बेरोज़गारी और कम मज़दूरी.* श्रमिक माँग कर रहे हैं कि सरकार उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दे। कई देशों में बेरोज़गार अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं।[12] वियतनाम में मुद्रास्फीति के चलते वेतन बढ़ाने की माँग को लेकर श्रमिकों की हड़तालें 2011 में दोगुना हो गईं।[13]
- *पर्यावरणीय प्रदूषण.* पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ़ व्यापक प्रदर्शन बढ़े हैं। उदाहरणार्थ, शंघाई (चीन) में प्रदूषित पानी की प्रस्तावित पाइप लाइन को लेकर प्रदर्शन हुआ[14] और मलेशिया में स्थानीय लोग अपने पड़ोस में आ रही 'दुर्लभ धातुओं' की रिफ़ाइनरी का विरोध कर रहे हैं।[15]

प्रदर्शनकारियों में युवा सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, कुछ हद तक यह रोज़गार की कमी और शिक्षित युवकों के लिए नौकरियों के सीमित अवसरों के कारण है। सन् 2011 में 48 चुनिंदा देशों में युवाओं में बेरोज़गारी 20% से ज़्यादा हो गई, जो बेरोज़गारी की कुल औसत दर 9.6 से बहुत ज़्यादा है।[16] बढ़ती बेरोज़गारी के प्रति युवाओं के आक्रोश की आशंका उन क्षेत्रों में अधिक है, जहाँ शिक्षित वर्ग ज़्यादा है।[17] शिक्षा लोगों की आकांक्षाएँ बढ़ा देती है क्योंकि शिक्षा से सरकार के निर्णयों को चुनौती देने के लिए आवश्यक संसाधनों व राजनीतिक कौशल की समझ आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि शिक्षितों के अधिकार ज़्यादा हैं। लेकिन जब तक सरकारें रोज़गार सृजन को ज़्यादा

असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि लोग अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करने और नीतियों को प्रभावित करने के लिए अधिक अवसर चाहते हैं, खासतौर पर मौलिक सामाजिक सुरक्षा को लेकर

रेखांकन 4.1

तीव्र गति परिदृश्य के तहत शिक्षा के परिणाम बेहतर हो जाते हैं

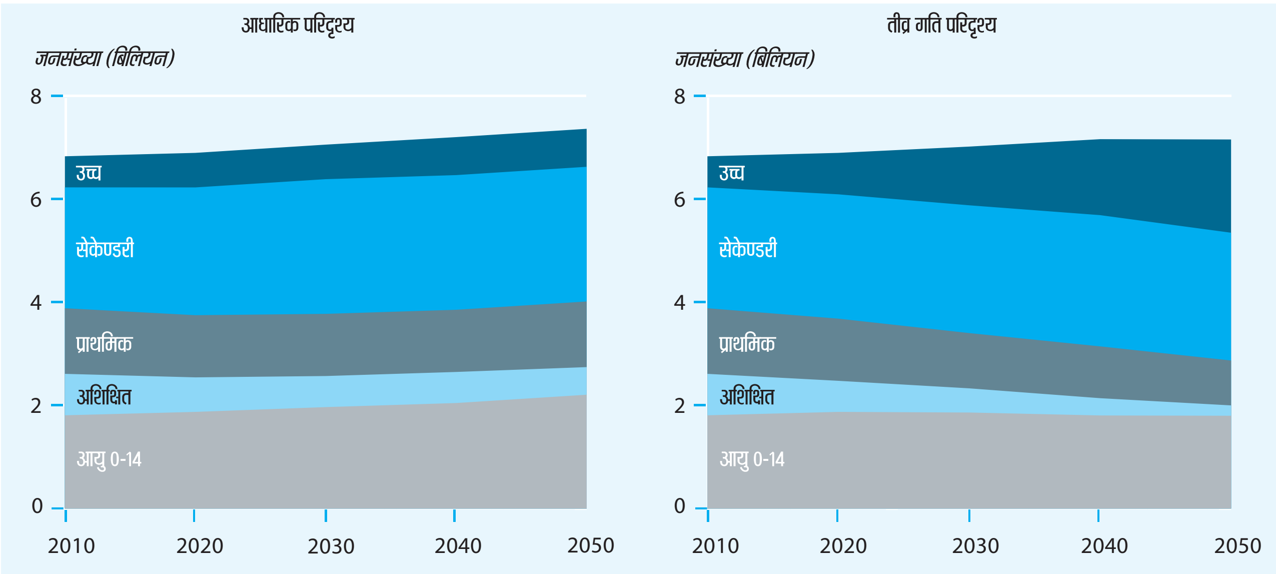

नोट : आधारिक और तीव्र गति परिदृश्यों पर चर्चा के लिए *तकनीकी परिशिष्ट* देखें।
स्रोत : लुट्ज और के.सी. (2013) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

प्राथमिकता नहीं देतीं, तब तक उन्हें युवकों के बढ़ते हुए असंतोष का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शिक्षा का दायरा बढ़ ही रहा है (रेखांकन 4.1)।[18]

इसके साथ ही मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इन्टरनेट और दूसरी आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ ऐसे नए द्वार खोल रही हैं जिनसे नागरिक, खासतौर पर युवा वर्ग, जवाबदेही की माँग कर सकते हैं। ये साधन विभिन्न देशों में लोगों को अपने विचार और अनुभव साझा करने में समर्थ बना रहे हैं और एक-दूसरे को निकट ला रहे हैं।

इन्टरनेट और सोशल मीडिया जनता की राय को कम लागत में इकट्ठा कर के जन-अभिव्यक्ति को दुनिया भर में ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन में 1990 के बाद की पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त, राजनीतिक रूप से जागरूक और सोशल मीडिया पर बहुत मुखर है।[19] जुलाई 2011 में वेनझू में हुई तीव्र गति रेलगाड़ी की दुर्घटना के बाद एक सप्ताह से भी कम समय में चीन के दो प्रमुख माइक्रो ब्लागों पर दुर्घटना पर टिप्पणियों और सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त करने वाले 2.6 करोड़ से भी ज़्यादा संदेश प्रसारित हुए।[20]

सामाजिक आन्दोलन और मीडिया विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान तो आकृष्ट करते हैं, परन्तु ये सदैव पूरे समाज को लाभान्वित करने वाले राजनीतिक बदलाव में परिणित नहीं होते। उदाहरण के लिए, भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ़ अन्ना हज़ारे के आन्दोलन ने बदलाव के लिए दबाव बनाया। हालाँकि आलोचकों का कहना है कि ऐसे आन्दोलन उन नीतियों के पक्षधर हो सकते हैं जिन्हें मतदाताओं का व्यापक समर्थन प्राप्त न हो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सहभागिता की प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाय जो राजनीतिक संतुलन बना सके, ऐसा संतुलन जो मुख्यधारा से बाहर के नागरिकों को मंच उपलब्ध कराए– जहाँ वे जवाबदेही और असमानताओं को दूर करने और व्यवस्थागत भेदभाव से लेकर अनुचित और अन्यायपूर्ण अपवर्जन को दूर करने की माँग कर सकें।[21]

सहभागिता और समावेशित किया जाना स्वयं में बहुत उपयोगी तो हैं ही, इनसे नीतियों और इनके कार्यान्वयन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है और भविष्य में होने वाली किसी भी उथल-पुथल की आशंका कम होती है

सहभागिता और समावेशित किया जाना स्वयं में बहुत उपयोगी तो हैं ही, इनसे नीतियों और इनके कार्यान्वयन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है और भविष्य में होने वाली किसी भी उथल-पुथल की आशंका कम होती है। जवाबदेह और संवेदनशील शासन विकसित न करने से असंतोष और घरेलू विवाद बढ़ता है। इससे मानव विकास की प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है। उदासीन-असंवेदनशील सरकारों के खिलाफ़ लोकप्रिय विद्रोहों से इतिहास भरा पड़ा है। असंतोष से निवेश में रुकावटें आती हैं, विकास में बाधा उत्पन्न होती है और निरंकुश सरकारें सीमित संसाधनों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगा देती हैं।

हाल के वर्षों में, उत्तर और दक्षिण, दोनों ही ओर के देशों की वैधता पर सवाल करे जा रहे हैं, जिसने नागरिकों और व्यवस्था के बीच टकराव की स्थिति बना दी है। अरब क्षेत्र के देशों में लाखों लोग अवसर,

सम्मान और प्रतिष्ठा-पूर्ण नागरिकता और जो उनके नाम पर शासन करेंगे, उनसे नए सामाजिक समझौतों की माँगों को लेकर उठ खड़े हुए। परिणाम स्वरूप मिस्र, लीबिया और ट्यूनीशिया के निरंकुश शासन उखड़ गए। यमन को अन्तरराष्ट्रीय हस्तक्षेप से सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार होना पड़ा, जॉर्डन और मोरक्को को राजनीतिक सुधार करने पड़े तथा सीरिया गृह युद्ध के भँवर में फँस गया।

शांतिपूर्ण बदलावों को प्रोत्साहित करने का एक ही रास्ता है कि नागर समाज को खुले माहौल में परिपक्व होने दिया जाए। यहाँ तक कि निरंकुश सरकारों में भी, जैसे ट्यूनीशिया और मिस्र में, विकसित सांगठनिक ढाँचे तथा आत्म-अनुशासित विरोधी राजनीतिक आंदोलन मौजूद थे। दूसरी तरफ़ लीबिया में इस तरह की व्यवस्था न होने के कारण वहाँ एक भीषण गृह युद्ध छिड़ा। संघर्ष के बाद राजनीतिक तालमेल बनना ऐसे देशों में बहुत कठिन है जहाँ नागरिक सहभागिता की परंपरा का अभाव होता है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों से यह दिखाई देता है कि राजनीतिक शासन बदल जाने से ही अभिव्यक्ति, सहभागिता, समावेशन या जवाबदेही को बढ़ावा नहीं मिल जाता, और न ही राज्य ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम करने लग जाते हैं।

जवाबदेही और समावेशन केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण हैं, और यह रोज़गार सृजन व सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहन देकर होता है, खासतौर पर उन समाजों में जहाँ शिक्षितों की संख्या अधिक हो और निरन्तर बढ़ रही हो। इसके लिए मध्यस्थता करने वाले तंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना आधुनिकीकरण अस्थिरता पैदा कर सकता है।[22] कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि लोगों को तभी शिक्षित किया जाए जब उनके लिए रोज़गार हों, मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान और शिक्षा तक पहुँच स्वयं में परिणिति है लेकिन हाल की सामाजिक क्रांतियों ने दिखा दिया कि शिक्षा और आर्थिक अवसरों के बे-मेल होने से, अलगाव और निराशा पनपती है, खासतौर पर युवकों में।

जिन 20 देशों में 1980-2010 के दौरान शिक्षा ग्रहण करने के वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, उनमें से आठ अरब देश हैं (रेखांकन 4.2)। इनमें से अधिकांश

जवाबदेही और समावेशन केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण हैं, और यह रोज़गार सृजन व सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहन देकर होता है

रेखांकन 4.2

अधिसंख्य देशों में रोज़गार के अवसर शैक्षिक उपलब्धता की गति के साथ नहीं बढ़ पाए

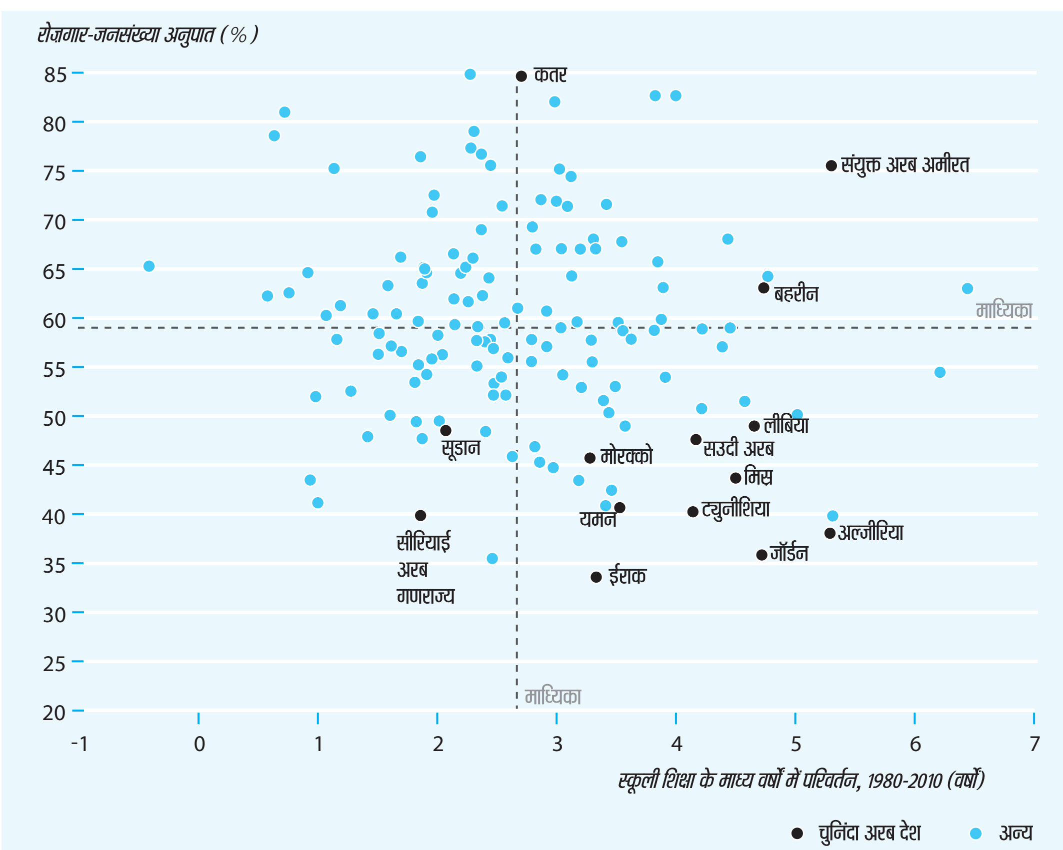

नोटः विश्लेषण में 141 देश शामिल किए गए। रोजगार और आबादी के अनुपात के आँकड़े 2006-2010 की अवधि में अद्यतन उपलब्ध वर्ष के है।
स्रोतः कैम्पैन्ट तथा कोर (2012) से लिए गए, नवीनतम आँकड़ों का प्रयोग करते हुए

देशों में रोज़गार के अवसर शिक्षा प्राप्ति की गति के साथ नहीं बढ़ पाए। अधिकांश देश, जो अरब देशों के असंतोष का हिस्सा रहे, वे रेखांकन 4.2 के निचले दाँए चतुष्टक में हैं। इसका कारण यह है कि इन देशों में शिक्षा प्राप्ति में महत्वपूर्ण उपलब्धि रही परन्तु आबादी के अनुपात में रोज़गार उपलब्ध कराने में उनका प्रदर्शन माध्यिका मान से नीचे रहा।[23]

ऐसी कोई भी भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है कि समाज उस अनिवर्ती स्थिति (tipping point) में कब आएँगे, जहाँ से वापस लौटना संभव न हो। कई कारक होते हैं जो बदलाव की माँग को बल देते हैं। जब शिक्षित युवकों को काम नहीं मिलता, तो वे प्रताड़ित सा महसूस करने लगते हैं। स्पष्ट है कि पिछले 30 वर्षों में सभी देशों में, जहाँ आँकड़े उपलब्ध हैं, विद्यालयी शिक्षा में बने रहने की औसत अवधि में वृद्धि हुई है।[24] लेकिन अकेले असंतोष से उथल-पुथल की शुरुआत नहीं होती। जनता क्रुद्ध हो सकती है, लेकिन यदि लोगों को यह विश्वास हो कि राजनीतिक कार्रवाई के प्रयास व इसमें लगने वाले समय की कीमत उनके बदलावों की सम्भावना से अधिक है, तो वे इस तरह की सक्रियता से परहेज़ कर सकते हैं।[25] जनांदोलन, विशेष तौर पर शिक्षित लोगों द्वारा, तभी भड़कते हैं, जब यह लगने लगे कि राजनीतिक प्रयासों में व्यय की गई ऊर्जा के मुकाबले आर्थिक अवसरों की सम्भावनाएँ बहुत क्षीण हैं। इस तरह की ''प्रयत्न-सघन (effort-intensive) राजनीतिक सहभागिता''[26] का तब आसानी से जनसंचार के नवीन स्वरूपों के माध्यम से समन्वयन हो जाता है।

पूरी दुनिया में लोग सरकारों से माँग कर रहे हैं कि वे नागरिकों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हों और नीति निर्धारण को प्रभावित करने की दृष्टि से जनता के लिए अवसरों का विस्तार करें। पहले ऐसे बदलाव हो चुके हैं। उदाहरण के लिए कार्ल पोल्यानी ने 1944 के 'ग्रेट ट्रांसफ़ॉर्मेशन' के बारे में लिखा है, जहाँ उत्तर के देशों की सरकारों ने नागर समाज और श्रमिक यूनियनों की बाज़ार को नियंत्रित करने और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने की माँगों के जवाब में समाज को बाज़ारों के आधीन बनाने के बजाए बाज़ार को समाज का सेवक बनाया था।[27] कई सरकारों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और सामाजिक सेवाओं व सामाजिक सुरक्षा का विस्तार कर कार्य स्थितियाँ सुधारने के लिए नियम बनाये। सरकारों ने वृहत आर्थिक नीतियों को नियंत्रित किया और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लगाए। 21वीं शताब्दी की चिंताओं और परिस्थितियों की दृष्टि से पुनः बदलाव के लिए यह सम्भवतः सही समय है।[28]

पूरी दुनिया में लोग सरकारों से माँग कर रहे हैं कि वे नागरिकों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हों और नीति निर्धारण को प्रभावित करने की दृष्टि से जनता के लिए अवसरों का विस्तार करें

रेखांकन 4.3

मा.वि.सू. के प्रत्येक स्तर पर कुछ देशों की कार्बन उत्पादकता दूसरों से ज़्यादा है

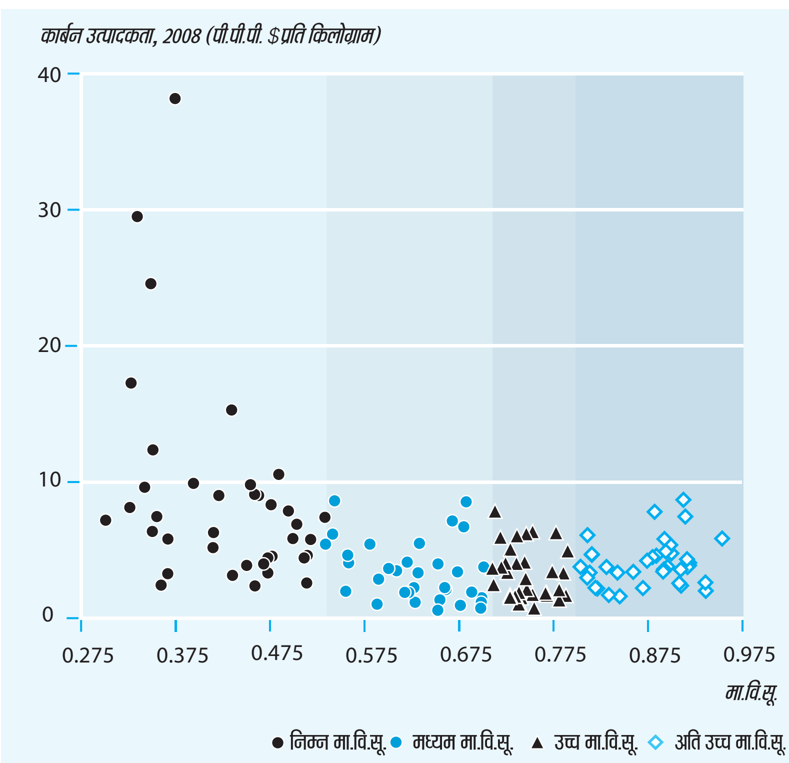

नोटः कार्बन उत्पादकता के मायने हैं प्रति इकाई कार्बन डाई ऑक्साइड पर स.घ.उ.। पी.पी.पी. से आशय क्रय शक्ति समता से है।
स्रोतः विश्व बैंक (2012 a) के आधार पर एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

पर्यावरणीय दबावों का सामना

ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। जबकि यह स्वाभाविक लग सकता है कि मानव विकास के साथ-साथ कार्बन की उत्पादकता (कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्पादन प्रति इकाई स.घ.उ.) बढ़ेगी, यह सह-सम्बन्ध बहुत कमज़ोर है (रेखांकन 4.3)। मानव विकास सूचकांक के प्रत्येक स्तर पर कुछ देशों में कार्बन उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक है।

मध्य मा.वि.सू. वाले ग्वाटेमाला और मोरक्को पर विचार करें, जिनका मा.वि.सू. मान लगभग समान है। ग्वाटेमाला की कार्बन उत्पादकता (5.00 डॉलर प्रति किलो, क्रय शक्ति समता के आधार पर) मोरक्को (2.6 डॉलर) से लगभग दो गुनी है। यह अन्तर कई देशों के अपने राज्यों के बीच में ही कहीं अधिक हो सकता है, जैसे कि चीन में।[29] इन निष्कर्षों के आधार पर यह तर्क पुनः प्रतिपादित हो जाता है कि मानव विकास की प्रगति के कारण कार्बन उपयोग की स्थिति गम्भीर हो ही, यह आवश्यक नहीं है और यह कि एक सुधरी-संतुलित पर्यावरण नीति मानव विकास के साथ-साथ अस्तित्व में रह सकती है।

मानव विकास में सतत प्रगति कायम रखने के लिए, इन्सान द्वारा पर्यावरण पर डाले जा रहे प्रभाव पर

ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लक्ष्य है, उच्च मानव विकास और प्रति व्यक्ति निम्न पारिस्थितिकीय फ़ुटप्रिंट (ecological footprints per capita) (रेखांकन 1.7, अध्याय 1 में निचला दाँया चतुष्टक)। भूमंडल के पारिस्थितिकी तंत्र पर किसी भी प्रकार का अरक्षणीय (unsustainable) दबाव डाले बिना मानव विकास के पुनरुत्पादनीय उच्च स्तर तक पहुँचने वाले केवल कुछ ही देश हैं। वैश्विक स्तर पर इस चुनौती से निपटने के लिए यह ज़रूरी है कि सभी देश अपने विकास-पथों में थोड़ा-बहुत बदलाव करें, विकसित देशों को अपने पारिस्थितिकीय फ़ुटप्रिंट घटाने होंगे जबकि विकासशील देशों को पारिस्थितिकीय फ़ुटप्रिंट में कोई वृद्धि होने दिए बिना अपना मा.वि.सू. मान बढ़ाना होगा। नवाचारी स्वच्छ प्रौद्योगिकी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

वैसे तो पर्यावरणीय खतरे, जैसे जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, जल व वायु प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएँ सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये ग़रीब देशों और ग़रीब समुदायों के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी होते हैं। जलवायु परिवर्तन पहले ही गम्भीर पर्यावरणीय खतरों को बदतर बना रहा है और पारिस्थितिकीय तंत्र को होने वाली हानि आजीविका के अवसरों को संकुचित कर रही है, खासतौर पर ग़रीबों के लिए। साफ़ और स्वच्छ पर्यावरण को एक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं। *मानव विकास रिपोर्ट 2011* ने स्पष्ट करा कि समता और संवहनीयता जटिल रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं। टिकाऊ समाजों को इस तरह के नीतिगत और ढाँचागत सुधार करने की ज़रूरत है जिससे मानव विकास और निम्न उत्सर्जन के लक्ष्य एकसाथ हासिल हो सकें, और इसके लिए निम्न उत्सर्जन वाली तथा जलवायु-प्रत्यास्थ (climate-resilient) रणनीतियों और नवाचारी सार्वजनिक-निजी वित्तीय व्यवस्थाओं की मदद लेनी होगी।[30]

सर्वाधिक वंचित वर्ग के लोगों का वैश्विक पर्यावरण क्षरण में बहुत कम योगदान होता है, परन्तु इसके दुष्प्रभावों को प्रायः इन्हें ही भुगतना पड़ता है।[31] उदाहरण के लिए, यद्यपि निम्न मा.वि.सू. देशों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन में अल्पतम योगदान होता है, परन्तु वार्षिक वर्षा में कमी को और वार्षिक वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता का सबसे तीखा दंश भी वही झेलते हैं, इससे आजीविका और कृषि उत्पादन गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं। इस तरह के भारी-भरकम नुकसान इस ज़रूरत को रेखांकित करते हैं कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लोच-बल से लोगों को लैस करने की तत्काल आवश्यकता है।[32]

प्राकृतिक आपदाएँ, जिनकी आवृत्ति और प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, भारी आर्थिक क्षति पहुँचाती हैं और मानवीय क्षमताओं में भी सेंध लगाती हैं। अकेले 2011 में भूकंप सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं (सुनामी, भूस्खलन और जमीन धँसने) से 20 हज़ार से अधिक मौतें हुई और 365 बिलियन डालर की क्षति हुई जिसमें दस लाख से अधिक लोगों का बेघर होना शामिल है।[33] छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए इसका असर कहीं ज़्यादा घातक है, इनमें कुछ देशों में क्षति स.घ.उ. का 1%, कुछ में 8% और कुछ में तो स.घ.उ. से कई गुना क्षति हुई है। उदाहरण के लिए सैंट लूसिया को 1988 में गिल्बर्ट तूफ़ान से इसके स.घ.उ. की चार गुना क्षति हुई और 2004 में ग्रेनाडा को इवान तूफ़ान से स.घ.उ. की दो गुना क्षति हुई।[34]

मानव विकास रिपोर्ट 2011 में कई पर्यावरणीय परिदृश्यों का अध्ययन किया गया था। ''पर्यावरणीय चुनौती'' के परिदृश्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण कृषि उत्पादन, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, सुधरी हुई सफ़ाई व्यवस्था और प्रदूषण पर पड़ने वाले सम्भावित दुष्प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इस परिदृश्य के तहत औसत वैश्विक मा.वि.सू. मान 2050 तक 'आधारिक परिदृश्य के मान के मुकाबले 8% कम होगा, इसमें यह मान्यता शामिल है कि वर्तमान पर्यावरणीय प्रवृत्ति और बिगड़ने के बजाए बरकरार रहेगी। बेहद आश्चर्य की बात यह है कि पर्यावरणीय चुनौती के परिदृश्य के तहत दक्षिण एशिया और सब-सहारा अफ्रीका में औसत क्षेत्रीय मा.वि.सू. मान आधारिक परिदृश्य की अपेक्षा पूरा 12% कम होगा। इससे भी गंभीर हालात में, यानी 'पर्यावरणीय आपदा' के परिदृश्य में, वैश्विक मा.वि.सू. के मान में आधारिक परिदृश्य की अपेक्षा 2050 में 15% की गिरावट आएगी, दक्षिण एशिया में यह गिरावट 22% और सब-सहारा अफ्रीका में 24% होगी, इससे दोनों क्षेत्रों में दशकों की मानव विकास प्रगति प्रभावी रूप से या तो ठहर जाएगी, या फिर इसकी दिशा उलट भी सकती है।

पर्यावरणीय आपदा के परिदृश्य में 2050 में तीव्र गति के परिदृश्य के मुकाबले लगभग 3.1 बिलियन अतिरिक्त लोग चरम . आय निर्धनता से प्रभावित होंगे

इस रिपोर्ट में विभिन्न पर्यावरणीय परिदृश्यों के चरम आय-निर्धनता में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है (रेखांकन 4.4)। पर्यावरणीय आपदा के परिदृश्य में 2050 में तीव्र प्रगति के परिदृश्य के मुकाबले लगभग 3.1 बिलियन अतिरिक्त लोग चरम आय निर्धनता से प्रभावित होंगे, जबकि 2010 में यह संख्या 1.2 बिलियन है (सारणी 4.3)। इसके विपरीत आधारिक परिदृश्य में दुनिया भर में चरम ग़रीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 2050 में घटेगी।

पर्यावरणीय आपदा के परिदृश्य में आधारिक परिदृश्य के मुकाबले करीब 2.7 बिलियन लोगों का चरम आय निर्धनता में जुड़ना दो परस्पर सम्बद्ध कारणों से होगा। पहला, मॉडल बताता है कि पर्यावरण क्षरण की वजह से चरम आय निर्धनता में रहने वालों की संख्या में 1.9 बिलियन की बढ़ोत्तरी होगी। दूसरे, पर्यावरणीय आपदाएँ लगभग 80 करोड़ लोगों को चरम आय निर्धनता से निकलने नहीं देंगी, जैसा कि

रेखांकन 4.4

विभिन्न पर्यावरणीय परिदृश्यों का चरम निर्धनता पर अलग-अलग प्रभाव होता है

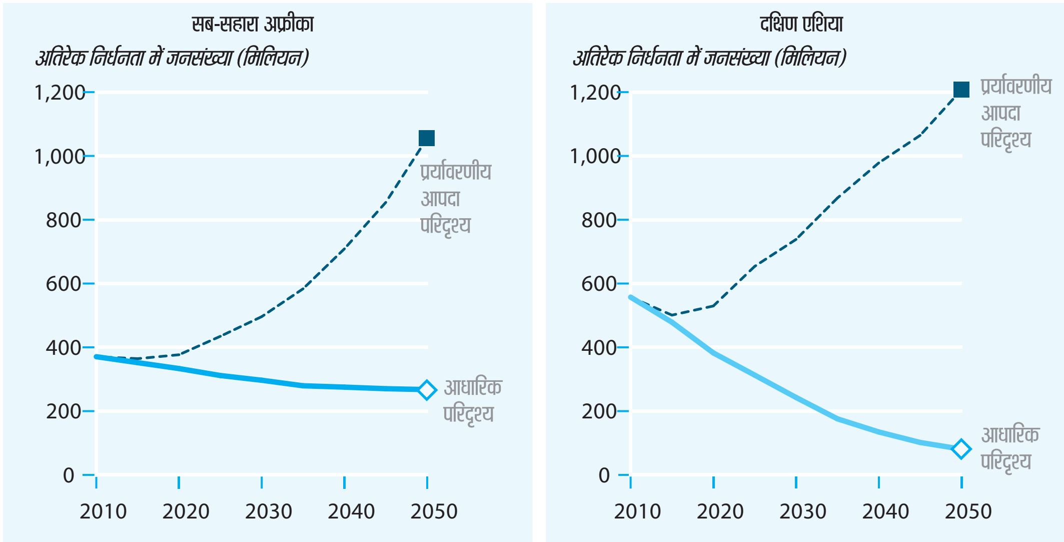

नोटः चरम ग़रीबी को 1.25 डालर प्रति दिन खरीद क्षमता की समता के रूप में परिभाषित किया गया है। आधारिक और तीव्र गति परिदृश्यों पर चर्चा के लिए *तकनीकी परिशिष्ट* देखें।
स्रोतः पार्डी सेंटर फ़ॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स (2013) के आधार पर एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

सारणी 4.3

पर्यावरणीय आपदा परिदृश्य में क्षेत्रानुसार चरम आय निर्धनता में जी रही आबादी, 2010-2050 (मिलियन में)

क्षेत्र	2010	2020	2030	2040	2050	वृद्धि, 2010-2050	अंतर: आधारिक परिदृश्य के सापेक्ष, 2050	अंतर: त्वरित प्रगति परिदृश्य के सापेक्ष, 2050
अरब देश	25	25	39	73	145	120	128	144
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	211	142	211	363	530	319	501	522
यूरोप एवं मध्य एशिया	14	6	17	32	45	30	41	44
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	34	50	90	138	167	134	135	155
दक्षिण एशिया	557	530	738	978	1,207	650	1,126	1,194
सब सहारा अफ्रीका	371	377	496	709	1,055	685	788	995
विश्व	**1,212**	**1,129**	**1,592**	**2,293**	**3,150**	**1,938**	**2,720**	**3,054**

नोटः चरम ग़रीबी को 1.25 डालर प्रति दिन खरीद क्षमता की समता के रूप में परिभाषित किया गया है। आधारिक और तीव्र गति परिदृश्यों पर चर्चा के लिए *तकनीकी परिशिष्ट* देखें।

स्रोतः पार्डी सेंटर फ़ॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स (2013) के आधार पर एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

आधारिक परिदृश्य के तहत इन्होंने कर लिया होता (देखें *तकनीकी संलग्नक*)।

यह परिणाम इस रिपोर्ट के एक केन्द्रीय संदेश को रेखांकित करते हैंः मानव विकास को ऊँचा उठाने की दृष्टि से पर्यावरणीय जोखिम सर्वाधिक गम्भीर रुकावटों में से एक हैं। ग़रीबी पर इसके दुष्परिणाम बहुत अधिक गंभीर होने की आशंका है। कार्रवाई करने में जितना विलंब होगा, उतनी अधिक कीमत चुकानी होगी।

जनसांख्यिकीय बदलावों का प्रबंधन करना

दुनिया की आबादी 1970 से 2011 के दौरान 3.6 बिलियन से बढ़ कर 7 बिलियन हो गई। इस आबादी की आयु-संरचना और इसके आकार से विकास की सम्भावनाएँ प्रभावित होती हैं।[35] कम होती प्रजनन दर और बदलती आयु संरचना से आर्थिक विकास पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं।[36] वर्ष 1970 से

2010 की अवधि के दौरान निर्भरता अनुपात (कार्यक्षम वर्ष 15-64 की आबादी के मुकाबले युवा और वृद्धों का अनुपात) कई क्षेत्रों में तेज़ी से गिरा है, पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तो बहुत ही नाटकीय तरीके से, जहाँ इसमें 39.5% की गिरावट आई है, इसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में जहाँ इसमें 34% की गिरावट आई है।

2010-2050 के दौरान मध्यम, उच्च और अति उच्च मा.वि.सू. वाले देशों में, खासतौर पर विकसित देशों, पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में निर्भरता अनुपात बढ़ने की सम्भावना है। ग़रीब क्षेत्रों, जैसे सब-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया में निर्भरता अनुपात का गिरना जारी रहेगा, परन्तु धीमी गति से।

बदलती हुई जनसांख्यिकी का आने वाले दशकों में दक्षिण के देशों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, लेकिन बहुत अलग तरीके से। कुछ ग़रीब देश जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि इससे आबादी में कार्यबल बढ़ेगा।[37] हालाँकि दक्षिण के अमीर क्षेत्रों को निर्भरता अनुपात के बढ़ने की चुनौतियों का सामना करना होगा, कमाने वाले लोगों की संख्या कम होगी और साथ-साथ वृद्धों की आबादी और स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा।

दीर्घावधि में सोचें तो शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाकर दोनों ही तरह की जनसांख्यिकीय चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। पहला, शिक्षा प्रजनन दर को वहाँ त्वरित गति से कम करती है, जहाँ पर वह काफ़ी अधिक है। दूसरे, अमीर देशों के अपेक्षाकृत छोटे कार्यबल की श्रमिक उत्पादकता को शिक्षा द्वारा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही, सरकार को रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होगी, जिससे युवकों और वृद्धों को उत्पादक रोज़गार के अवसर एकसमान उपलब्ध हो सकें।

इन जनसांख्यिकीय बदलावों के साथ आर्थिक अवसरों और उत्पादकता की गति न बनाए रख पाने वाले देश न केवल जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा उठाने से वंचित रहेंगे, इससे सामाजिक स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि हाल ही के वर्षों में अनेक देशों में देखने में आया है।

जनसांख्यिकी और शिक्षा के परिदृश्य

जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ निर्धारक नहीं होती हैं। इन्हें कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से बदला जा सकता है, कभी शैक्षिक नीतियों और कभी-कभी प्रवास-नीतियों के द्वारा।[38] जनसांख्यिकीय और शैक्षिक प्रवृत्तियों के विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर प्रभावी नीतिगत विकल्प चिन्हित किए जा सकते हैं।[39] अवधि 2010-2050 के लिए दो परिदृश्य अलग-अलग नीतियों के प्रभावों को प्रस्तुत करते हैंः आधारिक परिदृश्य, जिसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नामांकन अनुपात स्थिर रहे और तीव्र गति परिदृश्य, जिसमें शिक्षा के न्यूमतम स्तर वाले देश महत्वाकांक्षी शैक्षिक लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं।[40]

निर्भरता अनुपात एक चिंतनीय मसला बनता जा रहा है। बढ़ा हुआ निर्भरता अनुपात एक देश को ग़रीब बनाकर उसकी मानव विकास प्रगति को पलट सकता है। आधारिक परिदृश्य में अनुमान है कि 2010-2050 के दौरान निम्न मा.वि.सू. देशों में निर्भरता अनुपात में 9.7 प्रतिशत अंक की कमी आएगी, मध्यम मा.वि.सू. देशों में 9 प्रतिशत अंक की वृद्धि होगी, उच्च मा.वि.सू. देशों में 15.2 प्रतिशत अंक तथा अति उच्च मा.वि.सू. देशों में 28.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी (रेखांकन 4.5)। तीव्र गति परिदृश्य में 2010-2050 के दौरान निम्न मा.वि.सू. देशों में निर्भरता अनुपात 21.1 प्रतिशत अंक गिरेगा, जो कि आधारिक परिदृश्य के दो गुने से ज़्यादा होगा। निर्भरता अनुपात आधारिक परिदृश्य की अपेक्षा तीव्र गति परिदृश्य में ज़्यादा धीमी गति से बढ़ता है– मध्यम मा.वि.सू. देशों में 6.1 प्रतिशत और उच्च मा.वि. सू. देशों में 4.9 प्रतिशत; जबकि यह बढ़त अति उच्च मा.वि.सू. देशों में उतनी साफ़ नहीं है।

आधारिक परिदृश्य के अन्तर्गत सभी मा.वि.सू. समूहों में देश की आबादी में वृद्धों की संख्या बढ़ती देखी गईः निम्न मा.वि.सू. देशों में यह वृद्धि 3.9 प्रतिशत अंक, मध्यम मा.वि.सू. देशों में 17.7 प्रतिशत, उच्च मा.वि.सू. देशों में 20.2 प्रतिशत और अति उच्च मा.वि.सू. देशों में 22.3 प्रतिशत अंक।[41] अवधि 2010-2050 के दौरान युवा आबादी का प्रतिशत सभी मा.वि.सू. समूहों में गिरने का अनुमान है। निम्न मा.वि.सू. वाले देशों में निर्भरता अनुपात गिरेगा, क्योंकि वृद्धों की आबादी में बढ़ोतरी की तुलना में युवा आबादी धीमी गति से बढ़ेगी।

अरब देशों, दक्षिण एशिया और सब-सहारा अफ्रीकी देशों में आधारिक पदृश्य में निर्भरता अनुपात गिरने और तीव्र गति परिदृश्य में अधिक तेज़ी से गिरने का अनुमान है। उदाहरण के लिए सब-सहारा अफ्रीकी देशों में निर्भरता अनुपात आधारिक परिदृश्य में 11.8 प्रतिशत अंक गिरेगा तो तीव्र गति परिदृश्य में 25.7 प्रतिशत अंक।

पूर्व एशिया, प्रशांत क्षेत्र, यूरोप, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में निर्भरता अनुपात बढ़ने का अनुमान है। पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वृद्धों की आबादी में 25.8 प्रतिशत की बढ़त होगी, जो कि अति उच्च मा.वि.सू. देशों में अनुमानित वृद्धि से भी कहीं ज़्यादा है।

निर्भरता अनुपात बदलने के लिए महत्वाकांक्षी शिक्षा नीति में निहित सम्भावनाओं के उदाहरण ब्राज़ील और चिली में नज़र आते हैं। ब्राज़ील में आधारिक परिदृश्य में तो निर्भरता अनुपात 15.6 प्रतिशत अंक बढ़ता है जबकि तीव्र गति परिदृश्य में केवल 10.8 प्रतिशत अंक (सारणी 4.4)। चिली में भी इसी प्रकार 20.2 प्रतिशत अंक और 17.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि का अनुमान है।

जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ निर्धारक नहीं होती हैं। इन्हें शैक्षिक नीतियों और कभी-कभी प्रवास-नीतियों के द्वारा बदला जा सकता है

रेखांकन 4.5

शिक्षा नीतियाँ निर्भरता अनुपात को बदल सकती हैं

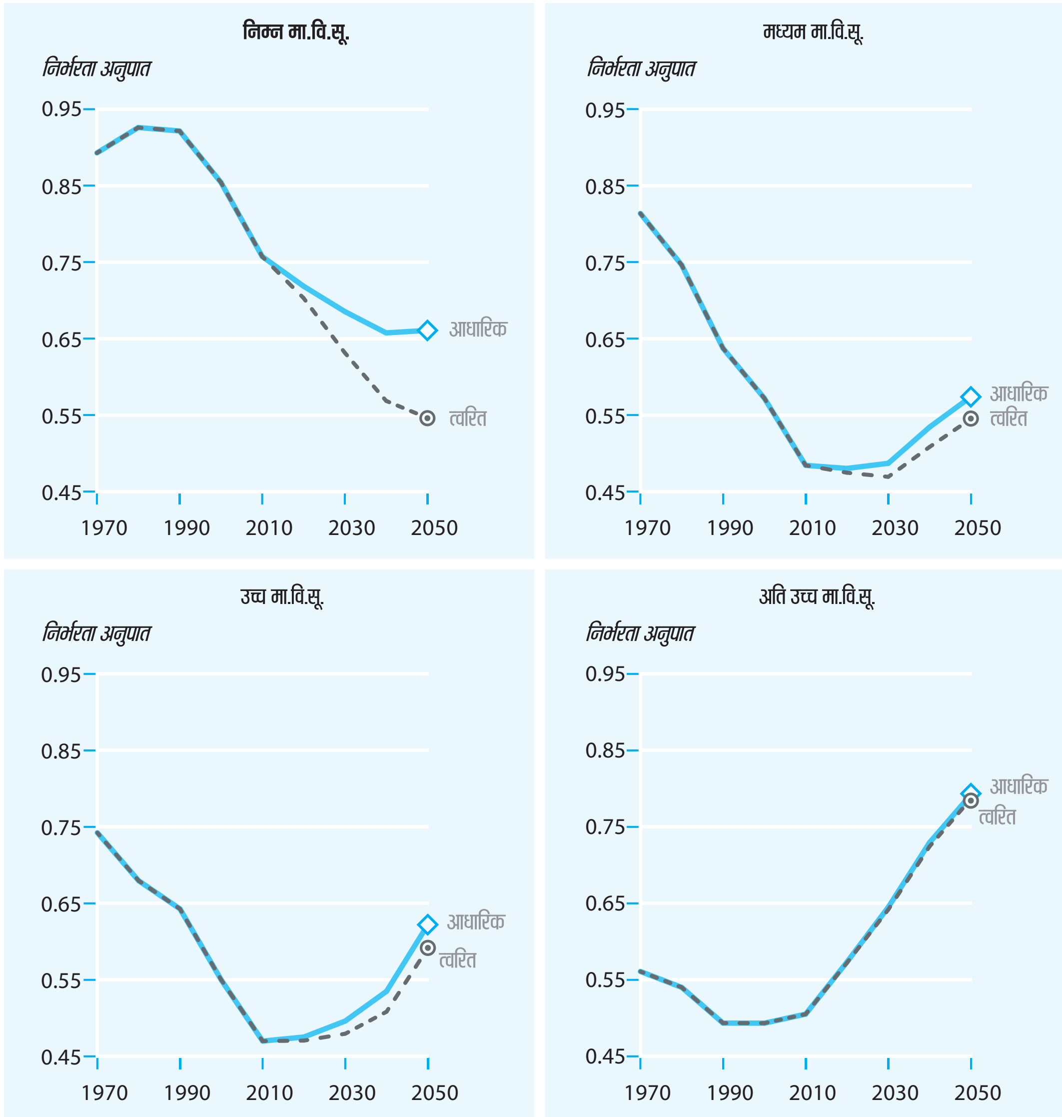

नोट: आधारिक तथा तीव्र गति परिदृश्यों पर चर्चा के लिए *तकनीकी संलग्नक* देखें।
स्रोत: लुत्ज और के. सी. (2013) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

दोनों परिदृश्यों में हर एक देश की चुनौतियाँ बहुत भिन्न हैं। आधारिक परिदृश्य में चीन में 27.3 प्रतिशत अंक की तेज़ वृद्धि का अनुमान है, जबकि थाइलैंड में 23.9 प्रतिशत अंक का और इण्डोनेशिया में 8.7 प्रतिशत। ये दोनों ऐसे देश हैं, जहाँ शिक्षा का स्तर पहले से ही काफ़ी ऊँचा है और इसीलिए बहुत महत्वाकांक्षी शिक्षा नीति के बावजूद इन देशों के निर्भरता अनुपात पर केवल सीमित प्रभाव ही पड़ने की सम्भावना होगी।

कम होते श्रमिक बल से निबटने के लिए देश कई तरीके अपना सकते हैं। वे बेरोज़गारी घटा सकते हैं, श्रमिक उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अधिक श्रम बल को, खासतौर पर महिलाओं और वृद्ध श्रमिकों को, रोज़गार के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे दूसरे देशों को उत्पादन का काम देकर आउटसोर्स कर सकते हैं या अन्तरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित कर सकते हैं।[42]

किसी उपयुक्त नीति के अभाव में, जनसांख्यिकी की पारस्परिक क्रियाएँ शुरू में असमानता बढ़ा सकती है, क्योंकि परिवारों के स्तर पर होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तन की अलहदा गतियों का शुरुआती लाभ अमीर परिवारों को ही मिलता है। घटती प्रजनन दर और आयु संरचना में बदलाव से आर्थिक विकास प्रभावित हो

सारणी 4.4

चुनिंदा देशों में निर्भरता अनुपात की प्रवृत्तियाँ, 1970-2050

देश	1970	1980	1990	2000	2010	परिदृश्य	2020	2030	2040	2050
बांग्लादेश	0.929	0.946	0.859	0.704	0.560	आधारिक परिदृश्य	0.462	0.434	0.433	0.481
						तीव्र गति परिदृश्य	0.457	0.422	0.418	0.465
ब्राज़ील	0.846	0.724	0.656	0.540	0.480	आधारिक परिदृश्य	0.443	0.484	0.540	0.637
						तीव्र गति परिदृश्य	0.437	0.460	0.499	0.589
चिली	0.811	0.629	0.564	0.540	0.457	आधारिक परिदृश्य	0.471	0.549	0.609	0.659
						तीव्र गति परिदृश्य	0.467	0.531	0.582	0.630
चीन	0.773	0.685	0.514	0.481	0.382	आधारिक परिदृश्य	0.408	0.450	0.587	0.655
						तीव्र गति परिदृश्य	0.404	0.434	0.562	0.628
घाना	0.934	0.946	0.887	0.799	0.736	आधारिक परिदृश्य	0.704	0.656	0.643	0.645
						तीव्र गति परिदृश्य	0.686	0.595	0.548	0.532
भारत	0.796	0.759	0.717	0.638	0.551	आधारिक परिदृश्य	0.518	0.496	0.491	0.511
						तीव्र गति परिदृश्य	0.510	0.474	0.463	0.480
इण्डोनेशिया	0.868	0.807	0.673	0.547	0.483	आधारिक परिदृश्य	0.452	0.457	0.504	0.571
						तीव्र गति परिदृश्य	0.451	0.454	0.501	0.567
थाइलैण्ड	0.904	0.756	0.532	0.447	0.417	आधारिक परिदृश्य	0.426	0.488	0.576	0.656
						तीव्र गति परिदृश्य	0.425	0.484	0.570	0.650
तुर्की	0.850	0.787	0.671	0.560	0.478	आधारिक परिदृश्य	0.458	0.467	0.504	0.585
						तीव्र गति परिदृश्य	0.450	0.443	0.473	0.547

स्रोतः लुत्ज एवं के.सी. (2013) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ। आधारिक परिदृश्य तथा तीव्र गति परिदृश्य पर चर्चा के लिए *तकनीकी संलग्नक* देखें।

सकता है।[43] इस रिपोर्ट के लिए किए गए कई देशों के विश्लेषणों की पुष्टि करता हुआ एक हालिया अध्ययन यह बताता है कि ग़रीब परिवारों में युवा निर्भरता का अनुपात अधिक है, अमीर परिवारों के बनिस्पत, खासतौर पर सब-सहारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, और समय के साथ ग़रीब व अमीर के बीच युवा निर्भरता अनुपात का यह अंतर लुप्त हो जाता है।[44] जनसांख्यिकीय बदलाव के दौरान सर्वाधिक समृद्ध वर्ग में प्रजनन दर सबसे जल्दी गिरती है और इसके कारण थोड़े समय के लिए आय में असमानता बढ़ जाती है क्योंकि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लाभ सबसे पहले ले लेते हैं। इसके बाद मध्यम वर्ग लाभ लेता है, लड़कियों को शिक्षित और परिवार को नियोजित करके, और अंत में कहीं जाकर ग़रीब इस बदलाव का लाभ लेने की स्थिति में आते हैं। अंततः सभी आय वर्गों में प्रजनन दर कम होती है और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के आर्थिक लाभ सभी वर्गों में अधिक समानता से वितरित होते हैं।[45] यह लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में पूर्व में हुए अध्ययनों के अनुरूप है।[46]

असमानता में यह अल्पकालिक वृद्धि अपरिहार्य ही हो, ऐसा नहीं है। इसे सार्वजनिक नीतियों से प्रभावित किया जा सकता है, खासतौर पर शिक्षा और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि ये दोनों ही जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लाभों को एक साथ सभी वर्गों तक पहुँचने देने में सहायक होते हैं। उन तीन देशों को देखें, जहाँ बच्चों में निर्भरता अनुपात में सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ हैः आइवरी कोस्ट (2011 में प्रति व्यक्ति स.घ.उ. 1,800 डालर), नामीबिया (6,800 डालर), और पेरू (10,300 डालर)। आइवरी कोस्ट में निर्भरता अनुपात में सबसे ज़्यादा ह्रास अमीरों में और सबसे कम ह्रास ग़रीबों में हुआ, नामीबिया में सबसे ज़्यादा गिरावट मध्यम आय वर्ग में हुई और पेरू में यह सभी वर्गों में प्रायः समान रूप से हुई।[47] चीन और घाना में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लाभों के वितरण पर चर्चा के लिए देखें बॉक्स 4.2।

जिन 18 में से 13 देशों में निर्भरता अनुपात में कमी के साथ 1970-2010 के दौरान महिला शिक्षा दर में वृद्धि, 1980-2008 के दौरान श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि, 2005-2010 के दौरान बेरोज़गारी में कमी और 2000-2004 से 2005-2010 के दौरान कुल श्रमिकों की

बॉक्स 4.2

चीन और घानाः जनसांख्यिकीय लाभांश से कौन लाभान्वित?

धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि और आबादी की आयु में बढ़ोतरी की वैश्विक प्रवृत्ति आंशिक रूप से चीन से प्रेरित है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला यह देश जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। सब-सहारा अफ़्रीका में फ़ास्ट ट्रैक शिक्षा नीति, जिसमें नामांकन वृद्धि होती रहे, से जनसांख्यिकीय परिवर्तन की गति तेज़ हो सकती है और इससे इस क्षेत्र के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश सृजित हो सकते हैं। चीन और घाना के मामले खाका प्रस्तुत करते हैं कि क्या हो सकता हैः.

चीन

चीन की आबादी में 1970 में युवा सबसे बड़ा अंश थे। परिणाम स्वरूप 0.77 मान के साथ निर्भरता अनुपात उच्च था (0 से 4 आयु वर्ग के बच्चों में प्रत्येक लड़की पर 1.08 लड़के थे) (रेखांकन 1)। 2010 तक चीन की आबादी का पिरामिड पूरी तरह भिन्न दिखाई देता है। जैसे प्रजनन दर गिरी, युवा की अपेक्षा कार्य करने वाले आयु वर्ग का अंश तेज़ी से बढ़ा, इससे निर्भरता अनुपात गिर कर 0.382 हो गया। शिशुओं में प्रत्येक लड़की पर 1.18 लड़कों के हो जाने पर लिंग असंतुलन अधिक गहरा हो गया। उत्पादक-आयु आबादी (आयु 35-50), जो फिलहाल आबादी का सबसे बड़ा अंश है, 15 से 25 वर्ष में सेवानिवृत्ति अवस्था में पहुँच जाएगी। इस प्रकार 2030 तक आते-आते चीन को वृद्ध होती आबादी की समस्या का सामना करना होगा, जिससे सामाजिक क्षेत्र पर अधिक दबाव होगा और निर्भरता अनुपात में वृद्धि होगी। सेवानिवृत्ति पर यह समूह 40 वर्ष पहले वाले अपने पूर्ववर्ती समूह से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त होगा।

तीव्र गति परिदृश्य के अन्तर्गत, दृढ़ शिक्षा नीति के चलते 2050 में चीन की आबादी की आयु संरचना बदल जाएगी, 60 से 64 वर्ष का आयु वर्ग सबसे बड़ा समूह होगा। कार्यक्षम आयु वर्ग का शैक्षिक स्तर उल्लेखनीय रूप से ऊपर उठेगा, परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादक कार्य बल होगा। अधिक निपुण और उत्पादक कार्य बल से उच्च निर्भरता अनुपात और वृद्ध आबादी का अंश अधिक होने के नकारात्मक प्रभावों की क्षतिपूर्ति हो सकती है। इस परिदृश्य में लड़कों और लड़कियों का अनुपात गिर कर 1.06 हो सकता है जो कि वैश्विक अनुपात के करीब होगा।

घाना

सन् 1970 में घाना की आबादी 87 लाख थी। आबादी में युवा सर्वाधिक थे, फलतः निर्भरता अनुपात काफ़ी अधिक था (0.934)। औपचारिक शिक्षा से वंचित आबादी का अनुपात भी काफ़ी था, खासकर महिलाओं में। 2010 आते-आते घाना की आबादी लगभग तिगुनी होकर 2.44 करोड़ हो गई। लेकिन इसकी आयु संरचना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया, हालाँकि जीवन प्रत्याशा में हुए सुधार ने जनसंख्या पिरामिड के बीच के हिस्से को चौड़ा कर दिया। युवाओं की आबादी 1970 की तुलना में कम रहने के बावजूद काफ़ी थी और निर्भरता अनुपात अभी भी अधिक ही था (0.736)। शैक्षिक स्तर में काफ़ी सुधार हो चुका था और आबादी में प्राथमिक व सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या बढ़ी थी।

शिक्षा नीति के दोनों परिदृश्यों में घाना की 2050 की सम्भावित तस्वीर में काफ़ी अंतर है। आधारिक परिदृश्य के अनुसार, जिसमें यह मान्यता है कि 2010-2050 के बीच नामांकन अनुपात स्थिर रहेगा, घाना का जनसंख्या पिरामिड त्रिकोणीय ही बना रहेगा, जिसमेंआबादी का काफ़ी हिस्सा युवा होगा और निर्भरता अनुपात उच्च होगा (0.645; रेखांकन 2)। आधारिक परिदृश्य में आबादी 6.56 करोड़ होने का अनुमान है, लेकिन तीव्र गति के परिदृश्य में आबादी मात्र 4.82 करोड़ होगी।

तीव्र गति के परिदृश्य में जनसांख्यिकीय तस्वीर काफ़ी बदली हुई होगी क्योंकि गिरती प्रजनन दर के कारण निर्भरता अनुपात नीचे आएगा (0.532) जो कुल आबादी में युवाओं के प्रतिशत में आई कमी से होगा। कार्यशील आयु वाले लोगों में अशिक्षितों की संख्या भी घटेगी, फलतः उत्पादकता और जनसांख्यिकीय बदलाव से लाभ लेने की क्षमता भी बढ़ेगी– शर्त केवल इतनी है कि इन समूहों से होने वाली श्रमिक बल की आपूर्ति को खपाने लायक रोज़गार के अवसर भी मौजूद हों।

रेखांकन 1 चीन के लिए जनसांख्यिकीय संभावनाएँ

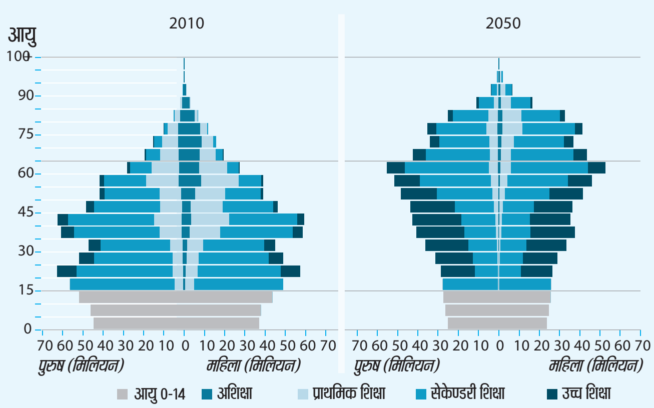

स्रोतः लुत्ज एवं के.सी. 2013; आधारिक तथा तीव्र गति परिदृश्यों पर चर्चा के लिए तकनीकी परिशिष्ट देखें

रेखांकन 2 घाना के लिए जनसांख्यिकीय सम्भावनाएँ

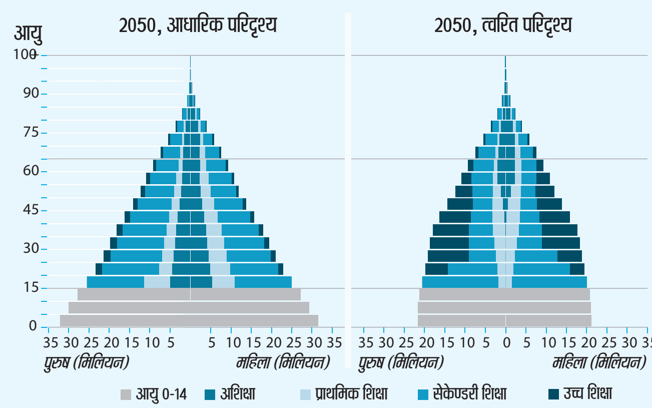

स्रोतः लुत्ज एवं के.सी. 2013; आधारिक तथा तीव्र गति परिदृश्यों पर चर्चा के लिए तकनीकी परिशिष्ट देखें

संख्या में वृद्धि के मुकाबले महिला श्रमिकों के अनुपात में अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई, वे श्रम बाज़ार में अधिक लैंगिक संतुलन दर्शाते हैं। हालाँकि ऐसा भी नहीं था कि शैक्षिक स्तर ऊँचा उठ जाने के कारण रोज़गार मिलना आसान हो गया हो। वास्तव में कुछ देशों में तो उच्च शिक्षित महिलाओं के लिए श्रम बाज़ार में स्थिति कठिन हो गई। अधिक शिक्षित और बढ़ते हुए श्रम बल को रोज़गार के उत्पादक अवसर उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त नीतिगत उपायों की ज़रूरत है, जिससे श्रम बाज़ार की स्थिति में सुधार हो।

आबादी की आयु वृद्धि का प्रभाव

प्रजनन दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से आबादियों की औसत आयु विगत के मुकाबले तेज़ी से बढ़ रही है।[48] उदाहरण के लिए वृद्धों की संख्या 7% से 14% होने में फ्रांस को एक शताब्दी से ज़्यादा (1865 से 1980) का समय लगा, स्वीडन को 85 वर्ष, आस्ट्रेलिया को 83 वर्ष और अमेरिका को 69 वर्ष लगे। विकासशील देशों में आयु में वृद्धि की दर और तेज़ है। सर्वेक्षणों के लिए चुने गए 9 में से 8 विकासशील देशों में 30 वर्ष या इससे कम समय में वृद्धों की संख्या 14% या इससे अधिक हो जाने का अनुमान है (रेखांकन 4.6)। केवल घाना एक अपवाद है जहाँ इसमें 50 या अधिक वर्ष लगेंगे।

आबादी की आयु में वृद्धि की दर महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि यदि जनसांख्यिकीय बदलावों के बाद भी विकासशील देश ग़रीब रहे, तो उन्हें वृद्ध आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कई विकासशील देशों में एक बड़ी कार्यक्षम आयु वाली आबादी के जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा उठाने के अवसर अभी बहुत कम हैं।[49]

महत्वाकांक्षी नीतियों की आवश्यकता

विकास की प्रगति त्वरित और टिकाऊ बनाने के लिए देशों को ऐसी महत्वाकांक्षी नीतियाँ अपनाने की आवश्यकता होगी जिससे महिलाओं की शिक्षा का विस्तार हो और जिससे मानव विकास के लिए अनेक सम्बन्धित लाभ हों। नीतियों को अपनाने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए जो भी देश तत्काल कार्रवाई करते हैं तथा अधिक पर्यावरणीय क्षति नहीं होने देते, वे बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो देश ऐसा नहीं करते, उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है जो कि समय के साथ-साथ बढ़ती जाएगी।

साहसिक और तत्काल नीतिगत कार्रवाई के परिणामों को दो अन्य परिदृश्यों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, जो नीतिगत उपायों के मा.वि.सू. पर 2050 में पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाते हैं। आधारिक परिदृश्य में हाल ही के दशकों की नीतियों और ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की निरन्तरता के आधार पर आकलन किया गया है। तीव्र गति परिदृश्य में कुछ विकल्पों और लक्ष्यों को, ग़रीबी उन्मूलन, अधोसंरचना विस्तार और अधिशासन में सुधार, के 12 नीतिगत आयामों पर आक्रामक परन्तु युक्ति-युक्त हस्तक्षेप के आधार पर आकलन किया गया है। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में, उदाहरण स्वरूप, 10 वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को दोगुना करने, 20 वर्षों में पलायन में 50% वृद्धि करने,[50] 10 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में 20%

रेखांकन 4.6

विकासशील देशों में आबादियाँ तेज़ी से बूढ़ी हो रही हैं

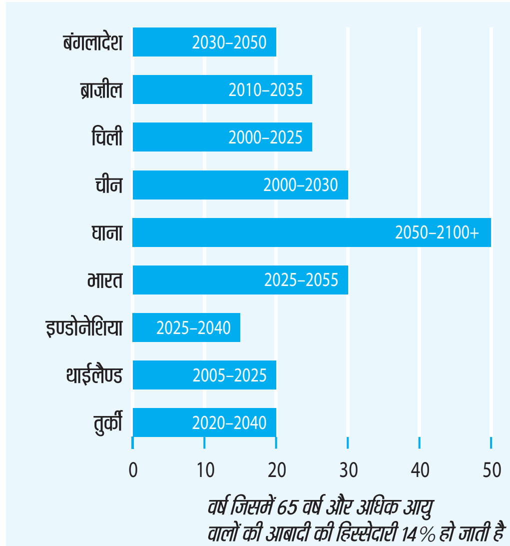

स्रोत. लुत्ज और के.सी. (2013) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ। आधारिक तथा तीव्र गति परिदृश्यों पर चर्चा के लिए तकनीकी संलग्नक देखे

रेखांकन 4.7

त्वरित प्रगति परिदृश्य में 2050 के लिए मानव विकास सम्भावनाएँ बहुत अधिक हैं, विशेषतौर पर निम्न मा.वि.सू. देशों के लिए

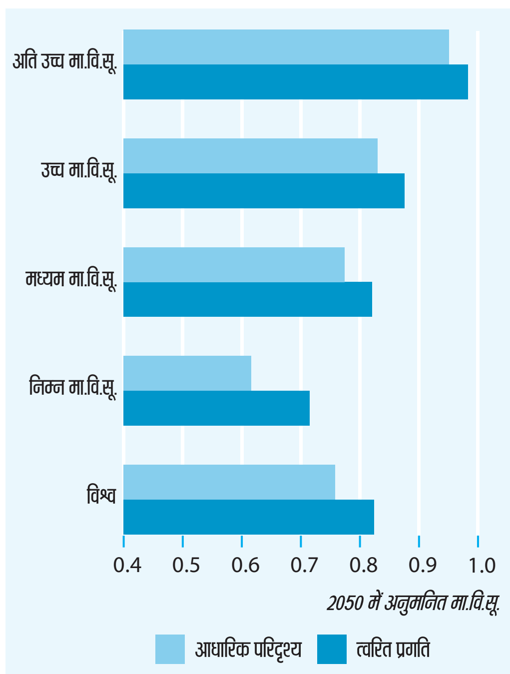

नोटः आधारिक एवं त्वरित प्रगति परिदृश्यों की परिभाषाओं के लिए देखें तकनीकी संलग्नक।
स्रोतः पार्डी सेंटर फ़ॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स (2013) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

वृद्धि करने, 30 वर्षों में अधोसंरचना में 20% विस्तार और 10 वर्षों में अधिशासन में 20% सुधार करना शामिल हैं।

आधारिक परिदृश्य के अनुमान बहुत ही आशावादी हैं क्योंकि उनके अनुसार मानव विकास में हुए नाटकीय सुधार के साथ हाल के दशकों में अपनाए गए सुधारों की गति आगे भी जारी रहेगी। तीव्र गति परिदृश्य में देशों का प्रदर्शन अधिक बेहतर रहेगा और निम्न मा.वि.सू. देशों में तेज़ प्रगति होगी (देखें रेखांकन 4.7)। सब-सहारा अफ्रीकी देशों में मा.वि.सू. में कुल 52% (0.402 से 0.612) और दक्षिण एशिया में 36% (0.527 से 0.714) की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस प्रकार निम्न मा.वि.सू. देशों के उच्च और अति उच्च मा.वि.सू. देशों द्वारा हासिल किए गए मानव विकास के स्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है।

महत्वाकांक्षी और पूर्णतः समन्वित नीतियाँ मानव विकास का स्तर सुधारने में मदद कर सकती हैं (रेखांकन 4.8)। सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया के लिए इसके प्रभाव सर्वाधिक कारगर होंगे। इसके बाद प्रभाव के क्रम में अरब देश, लैटिन अमेरिका, और कैरिबियाई देश आते हैं। यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव अपेक्षाकृत थोड़ा कमजोर होंगे।

रेखांकन 4.8

वर्ष 2050 तक मानव विकास उपलब्धियों में सुधार त्वरित प्रगति परिदृश्य में अधिक होगा

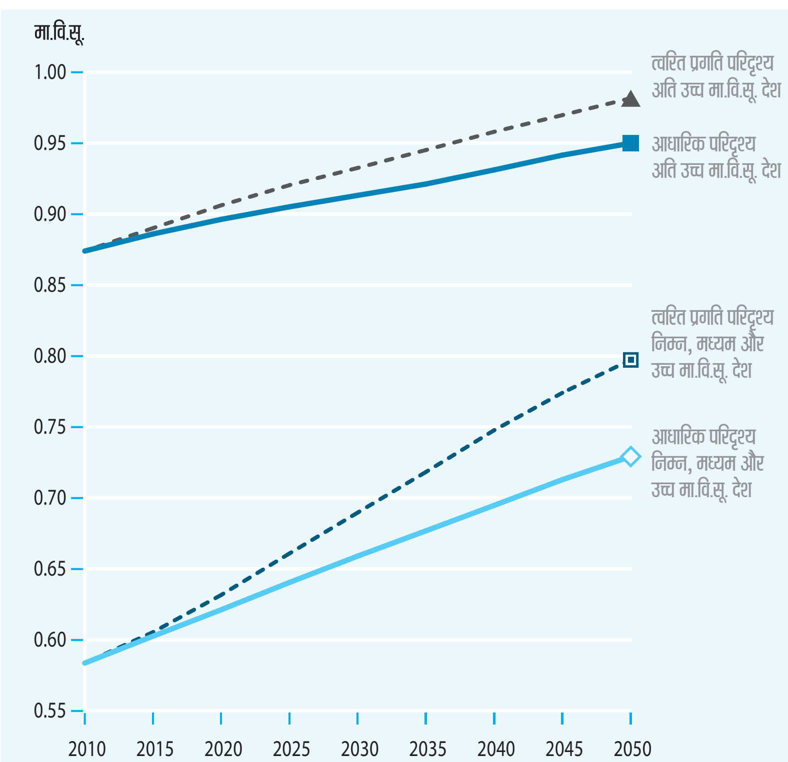

नोटः आधारिक एवं त्वरित प्रगति परिदृश्यों की परिभाषा के लिए *तकनीकी परिशिष्ट* देखें
स्रोतः पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स (2013) के आधार पर एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा में किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरण के लिए सब-सहारा अफ्रीका में महत्वाकांक्षी नीतियों के परिणाम स्वरूप 2050 में आधारिक परिदृश्य में मा.वि.सू. मान 0.612 से 0.651 तक पहुँचने का अनुमान है। इससे अगले क्रम में अधिकांश देशों में अधिशासन में सुधार का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है, इसमें भ्रष्टाचार में कमी, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ होना और महिलाओं का सशक्तीकरण शामिल है। हालाँकि दक्षिण एशिया और सब-सहारा अफ्रीका में अधोसंरचना में निवेश का महत्व कहीं अधिक है।

दोनों परिदृश्यों में मा.वि.सू. के वैयक्तिक आयामों में उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है। आधारिक परिदृश्य में सब-सहारा अफ्रीका में जीवन प्रत्याशा 2010 के 53.7 वर्ष से बढ़ कर 2050 में 69.4 वर्ष होने का अनुमान है, इसका श्रेय अंशतः एच.आई.वी./एड्स और अन्य संक्रामक रोगों के प्रति सतत प्रगति को भी है। लेकिन त्वरित प्रगति परिदृश्य में जीवन प्रत्याशा बढ़ कर 72.9 वर्ष होने का अनुमान है। इसी अवधि के दौरान सब-सहारा अफ्रीका में आधारिक परिदृश्य में औपचारिक शिक्षा के औसत वर्ष 4.3 से बढ़ कर 6.7 होने का अनुमान है जबकि त्वरित प्रगति परिदृश्य में यह 8.1 वर्ष है।

त्वरित प्रगति परिदृश्य में प्रति व्यक्ति स.घ.उ. के और भी अधिक होने का अनुमान है (रेखांकन 4.9)। यह सभी मा.वि.सू. वर्गों के लिए संगत है, जहाँ दोनों परिदृश्यों में उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है। वैश्विक स्तर पर आधारिक परिदृश्य में स.घ.उ. 2010 के 8,770 डालर प्रति व्यक्ति से बढ़ कर 2050 में 17,873 डालर होने का अनुमान है, जबकि त्वरित प्रगति परिदृश्य में यह बढ़ कर 27,995 डालर हो जाएगी। सर्वाधिक लाभ सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में होने का अनुमान है। सब-सहारा अफ्रीका में आधारिक परिदृश्य में प्रति व्यक्ति स.घ.उ. 2010 के 1,769 डालर से 2050 में 5,730 डालर होने का अनुमान है और त्वरित प्रगति परिदृश्य में इसके प्रभावी रूप से बढ़ कर 13-,210 डालर होने का अनुमान है, जो कि आधारिक परिदृश्य के दो गुने से भी ज़्यादा है। दक्षिण एशिया में त्वरित प्रगति परिदृश्य में प्रति व्यक्ति स.घ.उ. 2,871 डालर से चौंकाने वाली गति से बढ़ कर 23,661 डालर होने का अनुमान है।

आय में अलग-अलग गति से वृद्धि का सीधा असर आय-निर्धनता पर पड़ता है। आधारिक परिदृश्य में चीन में आय-निर्धनता करीब-करीब खत्म हो जाती है लेकिन सब-सहारा अफ्रीका में थोड़ी ही कमी होती है, क्योंकि जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है, और भारत में आय-निर्धनता अधिक बनी रहने का अनुमान है, जहाँ 2030 तक भी 13 करोड़ लोग ग़रीब होंगे। तीव्र गति परिदृश्य में ग़रीबों की संख्या में तेज़ी से कमी आती है और कुछ देशों व क्षेत्रों में ग़रीब लुप्त ही हो जाते हैं (रेखांकन 4.10)। 2050 तक ग़रीबी में उल्लेखनीय कमी लाना महत्वाकांक्षी नीतिगत उपायों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए विनाशकारी पर्यावरणीय आपदा परिदृश्य को दिलेरी से रोकने में असफलता का गंभीर असर ग़रीबी उन्मूलन के प्रयासों पर पड़ेगा।

सही वक्त पर क़दम उठाना

मानव विकास में बेहतर विकास सम्भव और अत्यावश्यक भी है, लेकिन त्वरित विकास के लिए विकास के सभी मोर्चों पर समन्वित नीतिगत उपायों की ज़रूरत होगी। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समता, क्योंकि अधिक समता वाले समाज में कल्याण के अधिकांश पहलुओं पर कहीं अधिक सफलता मिलती है और यह अधिक स्थाई होती है। दूसरा है, बच्चों की मृत्यु दर में कमी जो शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, के माध्यम से सभी देशों में तीव्र प्रगति ला सकती हैं।

नीतियों पर विचार के दौरान उन कारकों पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है जो विकास को प्रभावित करेंगे, विशेष रूप से उन प्रक्रियाओं में लोगों की सार्थक सहभागिता पर, जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पर्यावरणीय और जनसांख्यिकीय परिवर्तन। ज़रूरत इस बात की है कि देशों को जब भी अवसर मिलें, वे तत्काल उनका लाभ उठा कर कार्रवाई करें, ताकि मानव विकास में पिछड़ जाने की कीमत चुकाने से वे अपने-आप को बचा सकें।

मानव विकास को टिकाऊ बना रखने और इसकी गति को त्वरित करने वाले अधिसंख्य अवसर राष्ट्रीय सरकारों के हाथों में होते हैं। हालाँकि वैश्वीकरण की ओर बढ़ती दुनिया में सरकारें अकेले कार्य नहीं करतीं। अन्तिम अध्याय में अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के जटिल संजाल पर विचार किया गया है जिनके साथ राष्ट्रीय सरकारों को तालमेल रखने की ज़रूरत है और कैसे क्षेत्रीय और वैश्विक संस्थाएँ टिकाऊ मानव विकास के लिए अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकती हैं।

रेखांकन 4.9

त्वरित प्रगति परिदृश्य में 2050 तक के लिए प्रति व्यक्ति स.घ.उ. में बढ़त बहुत मज़बूत दिखती है

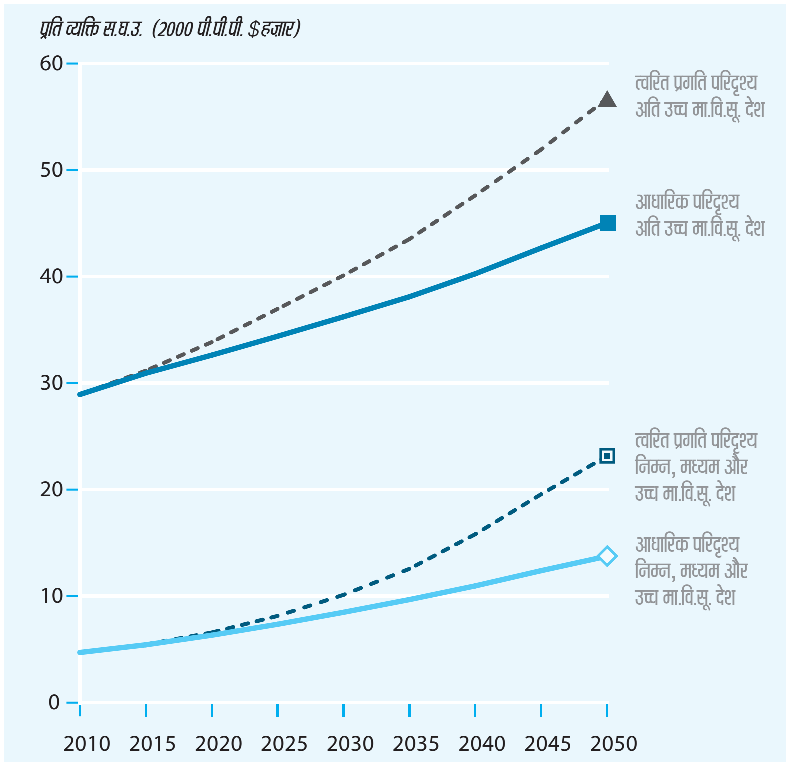

नोट: आधारिक एवं त्वरित प्रगति परिदृश्यों की परिभाषा के लिए *तकनीकी परिशिष्ट* देखें
स्रोत: पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स (2013) के आधार पर एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

सारणी 4.5

क्षेत्र और चुनिंदा देशों के अनुसार चरम निर्धनता में रह रहे लोग, आधारिक और त्वरित प्रगति परिदृश्य, 2010-2050 (मिलियन में)

क्षेत्र या देश	2010	2020	2030	2040	2050, आधारिक परिदृश्य	2050, त्वरित प्रगति
अरब देश	25	19	17	16	17	1
पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र	211	74	42	29	29	9
चीन	94	13	5	1	1	0
यूरोप और मध्य एशिया	14	2	3	3	4	1
लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र	34	29	26	27	32	13
दक्षिण एशिया	557	382	243	135	81	13
भारत	416	270	134	53	21	2
सब-सहारा अफ़्रीका	371	333	297	275	267	60
विश्व	1,212	841	627	485	430	96

नोट: चरम ग़रीबी को 1.25 डॉलर प्रति दिन क्रय शक्ति समता के रूप में परिभाषित किया जाता है। आधारिक एवं तीव्र गति परिदृश्यों पर चर्चा के लिए *तकनीकी परिशिष्ट* देखें
स्रोत: स्रोत: पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स (2013) के आधार पर एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

‘‘एक शांतिपूर्ण विश्व की रचना
के लिए हाथ मिलाइए, जहाँ
हम सुरक्षित सो सकें
और खुशी के साथ जागें।’’

आंग सान सू की

‘‘हमें अलग-अगल रखने वाले
आरोपित प्रभावों के मुकाबले
हमें एकजुट करने वाली ताकत
आंतरिक और ज़्यादा महान है।’’

क्वामे एनक्रूमह

5.

नए दौर का अधिशासन और भागीदारियाँ

अंतरराष्ट्रीय विकास और वैश्विक अधिशासन की प्रणालियाँ पुरानी संरचनाओं और नई व्यवस्थाओं का बहुरंगी ताना-बाना है, जो पिछड़े देशों और सारी दुनिया के लिए लगातार उपयोगी बन रहा है। आने वाले समय में विकासशील देशों का अभ्युदय इस व्यवस्था को और व्यापक-विविध बनाएगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रक्रियाओं का वृहत्तर जटिल तंत्र जुड़ता जाएगा। इन सरंचनाओं को और ज़्यादा समन्वित रूप में करने की जरूरत होगी– खासतौर से सार्वजनिक साधनों की पूर्ति के लिए। एक ही काम का दोहराव और सामान्य नियमों और लक्ष्यों पर सहमति न बन पाना केवल अकुशल ही नहीं, बल्कि आगे चलकर प्रति-प्रभावी भी हो सकता है, जिससे मानवीय प्रगति को धक्का लगेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्यों और हितधारकों के व्यापक समूह को प्रतिनिधित्व और जवाबदेही देते हुए, वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों को मज़बूत बनाया जाए, जो विकासशील देशों में उदित होती इन नई शक्तियों को परिलक्षित करे। इस अध्याय में भागीदारी के इस नए दौर के विकल्पों पर विचार और निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है।

विकासशील देश तेज़ी से विकसित हो रहे हैं और उनमें से अनेक विश्व मंच पर पहले से ज़्यादा सक्रिय हैं। वे अपने व्यक्तिगत और सामूहिक हितों को कई माध्यमों से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ासतौर से क्षेत्रीय व्यवस्थाओं और द्विपक्षीय भागीदारियों के माध्यम से, जो उन्हें अपने मसलों पर और अक्सर अपनी शर्तों पर एक-दूसरे से जुड़ने का मौका देती हैं। ब्राज़ील, चीन, भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने अपने पड़ोसियों तथा अन्य विकासशील देशों के साथ गहरे और मज़बूत रिश्ते बना लिए हैं: वे अपने वैश्विक बाज़ार और उत्पादन का तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं; उन्होंने ब्रेटन वुड्स वित्तीय संस्थाओं को नवाचारी सम्पूरक (innovative compliments) दिए हैं; व्यापार, धन और वित्त के वैश्विक नियमन पर लगातार प्रभावशाली हो रहे हैं; और वे संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, शांति और सुरक्षा पर प्रभाव डाल रहे हैं।

विकासशील देशों द्वारा समर्थित नई व्यवस्थाएँ और तत्परिणामी बहुलता, कई बार सीधे और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से वैकल्पिक क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय प्रणालियों के माध्यम से बहुपक्षीय वित्त, व्यापार, निवेश और स्वास्थ्य के परम्परागत प्रक्षेत्रों (domains) की विद्यमान संस्थाओं और प्रक्रियाओं को चुनौती दे रही हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय अधिशासन नई व्यवस्थाओं और पुरानी संरचनाओं का बहुरंगी मेलजोल बनता जा रहा है, जिसे कई तरीके के सामूहिक पोषण की आवश्यकता है। वैश्विक संस्थाओं में आंतरिक सुधार के काम में क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ उनके सहयोग को पुष्ट किया जाना चाहिए, और कुछ मामलों में उन क्षेत्रीय संस्थाओं को, व्यापक अधिकार सम्पन्न करना चाहिए। संगठनों की जवाबदेही को राष्ट्रों के वृहत्तर समूह से जोड़ना चाहिए, और साथ ही साथ हितधारकों के वृहत्तर समूह से भी। कुछ मामलों में, प्रगति कर पाना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। देशों के समूह बिखर रहे हैं, उनके समन्वय की क्रियाविधि दुष्कर होती जा रही है और कई मामलों में समूहों के बीच विमर्श लगभग ठप हो गया है।[1] इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय अधिशासन में आवाज़ों की बढ़ती विविधता मानव विकास की राह में नए अवसर और चुनौतियाँ, दोनों पैदा कर रही है।

इसके साथ ही वैश्विक नागर समाज में और अधिक विविधता के संकेत मिल रहे हैं।[2] विकासशील देशों से उभर रहे स्वर ज़्यादा जवाबदेही और व्यापक प्रतिनिधित्व की माँग कर रहे हैं। नागर समाज के संगठनों ने आर्थिक सहायता, ऋण, मानवाधिकार, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के मामलों में वैश्विक पारदर्शिता और नियम-निर्धारण को प्रभावित कर लिया है। इन सामाजिक संगठनों के नेटवर्क अब नवीन मीडिया और नई संचार तकनीकों का लाभ उठा सकते हैं, जिनके कारण स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय एक्टिविस्टों के बीच सम्पर्क आसान हो गया है। लोगों को अपने विचारों और सरोकारों के आदान-प्रदान से वैश्विक सार्वजनिक मंच पर सामूहिक दृष्टिकोणों को लाने का अवसर मिल रहा है।

आपस में जुड़ी हमारी दुनिया में, प्रत्येक देश की गतिविधियों का असर उसके पड़ोसी देशों पर, और अंततः समूची दुनिया के लोगों पर पड़ेगा– आज और भविष्य में भी। ज़िम्मेदार सम्प्रभुता की दरकार है कि राष्ट्रीय आचरण के वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभावों को सावधानी और गम्भीरता के साथ ध्यान में रखा जाए।

कुछ बड़ी चुनौतियों, जैसे क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा के मसलों से क्षेत्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर रचनात्मक तरीके से निपटा जा सकता है। फिर भी, इन मसलों के दीर्घ-कालीन अंतरराष्ट्रीय समाधानों की आवश्यकता होगी। दोहा (डब्ल्यू.टी.ओ.) वार्ता चक्र में निरंतर ठहराव अफ्रीका और अन्यत्र विकासशील देशों की कृषि में आत्मनिर्भरता और ग़रीबी तथा भूख के उन्मूलन की दिशा में प्रगति में रुकावट डाल रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे कुछ और तात्कालिक महत्ता

वाले मसले हैं जिनका समाधान वैश्विक स्तर पर ही सम्भव है। और यह वे मसले हैं जिनमें अगर सामूहिक पहलकदमी करने में चूक हुई तो भविष्य में ये समस्याएँ अधिक गम्भीर और खर्चीली बन जाएँगी।

सार्वजनिक साधनों पर नया वैश्विक दृष्टिकोण

वैश्विक अंतरराष्ट्रीय सरोकारों के जो क्षेत्र तत्काल सहयोग की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं, उनमें व्यापार, प्रवास, जलवायु परिवर्तन और विकास शामिल हैं। दक्षिण के देशों के उदय के साथ इनमें से हरेक क्षेत्र और उसके अधिशासन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं

सार्वजनिक साधनों (public goods) की उपलब्धता पर आज की बदलती दुनिया का गहरा असर पड़ने वाला हैः जैसे कि साफ़ हवा और अन्य साझा संसाधन, जिन्हें केवल बाज़ार ही तैयार करता है या अपर्याप्त मात्रा में आवंटित कर पाता है या बिलकुल नहीं दे पाता, और जिनके लिए राज्य-तंत्र आवश्यक है।[3] वांछनीय वैश्विक सार्वजनिक साधनों में स्थिर जलवायु और स्वस्थ सार्वजनिक स्थल शामिल हैं। ऐसे में अधिक स्थिर वित्तीय बाज़ार के लिए नियमों की आवश्यकता, व्यापार सुधार में प्रगति (जैसे कि व्यापार वार्ता का दोहा चक्र) और हरित प्रौद्योगिकी (green technologies) के उत्पादन तथा वित्त पोषण की क्रियाविधि की ज़रूरत होगी।

अब हमें इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि सार्वजनिक क्या है और निजी क्या। क्या चीज़ एकपक्षीय आधार पर हमें सबसे अच्छे तरीके से मिल सकती है और क्या बहुपक्षीय आधार पर? और सबसे महत्वपूर्ण यह कि जब हम सामूहिक पहल करते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? साधनों का सार्वजनिक प्रावधान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है लेकिन सार्वजनिक और निजी का सहअस्तित्व अटल है (बॉक्स 5.1)। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन और कोयले, तेल और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों की कमी के मद्देनज़र सरकारों ने ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर अनुसंधान और विकास पर निवेश करने के काम में निजी क्षेत्र से साझा किया है।

वैश्विक अंतरराष्ट्रीय सरोकारों के जो क्षेत्र तत्काल सहयोग की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं, उनमें व्यापार, प्रवास, जलवायु परिवर्तन और विकास शामिल हैं। विकासशील देशों के उदय के साथ इनमें से हरेक क्षेत्र और उसके अधिशासन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसके साथ ही दक्षिण के देशों का नया दर्जा सहमति और बेहतर सहकार की सम्भावनाएँ पेश करता है।

व्यापार

विश्व व्यापार संगठन के दोहा विकास चक्र के अपेक्षित दूरगामी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के पूरा होने से विकासशील देशों को लाभ मिलेगा। हालाँकि दोहा चक्र ठप्प है, फिर भी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं का विशद तंत्र विकसित हो गया है। बहुपक्षीय स्तर पर गतिरोध से बचते हुए ये व्यवस्थाएँ,

बॉक्स 5.1

सार्वजनिक और निजी के बीच की बदलती रेखाः परिवहन

जन-परिवहन व्यवस्था का सार्वजनिक या निजी होना, संवहनीयता और किफ़ायती सुलभता (affordable access) के साझा विकास-लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण असर डालता है। जो समाज समतामूलक परिणामों से ज़्यादा सरोकार रखता है, वहाँ सार्वजनिक परिवहन के व्यापक होने की सम्भावनाएँ ज़्यादा होती हैं। बड़े पैमाने की किफ़ायती आर्थिकी (economy of scale) से हासिल बचत का फ़ायदा जनता को अपेक्षाकृत सस्ते सार्वजनिक परिवहन के रूप में हस्तांतरित करा दिया जाता है। और ज़्यादा समतावादी समाजों में कम आमदनी वाले समूहों को, जिनमें छात्र, वृद्धजन और विकलांग शामिल हैं, और ज़्यादा छूट और सब्सिडी मिलने की सम्भावना होती है। उद्देश्य है, परिवहन सेवाओं के आम आदमी की पहुँच से बाहर चले जाने, यानी अपवर्जनीयता (excludability) को कम करना, उसे सुलभ बनाना।

सार्वजनिक जन-परिवहन सड़कों पर वाहनों की भीड़-भाड़ और उनके कार्बन उत्सर्जन को कम करने का काम भी कर सकता है, जो पारंपरिक रूप से निजी परिवहन के साथ जुड़ा है। जब एक दीर्घकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद हो, तब उसमें हरित-प्रौद्योगिकी को त्वरित गति से लागू करना आसान है। उदाहरण के लिए दिल्ली शहर में सार्वजनिक बसों में सी.एन.जी. गैस का इस्तेमाल अनिवार्य होता है, जो गैसोलीन (डीज़ल-पेट्रोल) से ज़्यादा स्वच्छ यानी पर्यावरण-मित्र है (यहाँ सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रकों द्वारा बसें चलाई जाती हैं)।

पर्यावरणीय चेतना वाले समाज निजी वाहनों पर सघनन (congestion) और कार्बन टैक्स लगाकर उनके स्थान पर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हैं, जैसे सिंगापुर, मिलान और लंदन शहर में है, और सैन फ्रांसिस्को इस पर विचार कर रहा है। सार्वजनिक परिवहन को किफ़ायती बनाना ही अकेली चुनौती नहीं है। चूँकि ज़्यादातर अमीर तबका आमतौर पर निजी वाहनों से चलना पसन्द करता है, इसलिए इसका उत्तर है कि सुरक्षा, कार्यकुशलता और विश्वसनीयता के मामले में सार्वजनिक परिवहन को निजी परिवहन से कमतर न रहने दिया जाए।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी भी एक रास्ता हो सकता है। परियोजना के निर्माण और संचालन में ये साझेदारियाँ ज़्यादा कार्यकुशल साबित होती हैं। इसमें सार्वजनिक भागीदार नियामक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए और कई बार सब्सिडी की मदद से निजी मॉडल से उपजने वाले लाभ और सामाजिक मॉडल से उपजने वाले लाभ के अंतर की पूर्ति करते हुए सम्पत्ति के अधिकारों की रक्षा करता है।

लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के ज़्यादातर रेलवे प्रोजेक्ट सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित हैं। परिवहन क्षेत्र में सबसे तेज़ी से सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रमों को चलाने वालों में भारत भी है। 1995 से 2006 के बीच, 15.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाले तकरीबन 230 सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रम लागू किए गए। चीन ने टोल वाली सड़कों और अन्य अधोसंरचना के लिए व्यापक स्तर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी की *बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफ़र* (BOT) पद्धति का इस्तेमाल किया, खासतौर से 2000 के दशक से।

गैस की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्राइवेट कम्पनियों से उम्मीद है कि वे खुद ही हरित ईंधन (greener fuels) और हरित प्रौद्योगिकी पर शोध करेंगी। फिर भी हरित ईंधन और हरित प्रौद्योगिकी पर शोध के अधिकतम (optimal) सामाजिक स्तर को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निवेश और प्रोत्साहनों की ज़रूरत भी होगी। वस्तुतः हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली खोजें सबसे ज़रूरी वैश्विक सार्वजनिक साधन हैं और उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए ही रहना चाहिए।

स्रोतः विश्व बैंक, 2003 एन.डी.; चेंग, ह्यू और झाओ 2009

जिनमें कम एवं समान हितों वाले भागीदार होते हैं, इनमें शामिल पक्षों के हितों को एक साथ लाकर उन्हें पारस्परिक लाभ दिलवा सकती हैं।

उप क्षेत्रीय व्यापार और निवेश समूहों, जैसे पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय और दक्षिण के साझा बाज़ार ने,अधिक आर्थिक-संवाद तथा परस्पर नीतिगत सहयोग द्वारा सुरक्षा से लेकर जल-संसाधन प्रबंधन जैसे कई दूसरे मसलों पर सहमति बनाई है। यह द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ दक्षिण-दक्षिण आर्थिक-एकीकरण को बढ़ावा देने के अवसर और प्रतिस्पर्धा की सामर्थ्य को पैदा करने के लिए प्रशिक्षण-स्थल उपलब्ध कराती हैं।[4]

द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के लाभ होने के बावजूद, बेहतर वैश्विक व्यापार व्यवस्था और तालमेल की क्रियाविधियों की अनुपस्थिति से लागत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जहाँ व्यापार समूह अपने सदस्य देशों के बीच मुक्ततर व्यापार को बढ़ावा देते हैं, वहीं वे एक-दूसरे के मुक्त-व्यापार में अवरोध खड़े कर देते हैं, जिससे अंततः वैश्विक कल्याण में बाधा पहुँचती है।[5] दूसरी हानियाँ उस बढ़ी हुई बाज़ार शक्ति से पैदा होती हैं, जो व्यापार समूहों में समेकित होने के कारण देशों को प्राप्त होती हैं।[6] इस रिपोर्ट के लिए हुआ शोध बताता है कि मुक्ततर और उचित व्यापार नियम, मानव विकास को तेज़ कर सकते हैं, यदि उनके साथ मानव क्षमताओं को बढ़ाने पर निरंतर सार्वजनिक निवेश किया जाए, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाएँ और आवश्यक अधोसंरचना, जैसे आधुनिक परिवहन और दूरसंचार सम्पर्क शामिल हैं।

मुक्ततर, भेदभाव-रहित व्यापार-व्यवस्था के अनेक पक्ष तब बेहतर साबित होते हैं जब वे मज़बूत बहुपक्षीय समझौतों की निगहबानी में हों। पर चूँकि क्षेत्रीयता शायद कायम रहेगी, इसलिए इसका अगला चरण यह हो सकता है कि क्रमशः ''बहुपक्षीकृत क्षेत्रवाद'' (multilateralized regionalism) की ओर बढ़ा जाए। इसके लिए विश्व व्यापार संगठन को (सॉफ्ट-लॉ जैसे) विचारों की पहल करनी होगी, जैसे नए क्षेत्रीय व्यापार समझौतों और विद्यमान समझौतों पर बातचीत के लिए स्वैच्छिक श्रेष्ठ-कार्यों की मार्गदर्शिका (best-practice guidelines)। मसलन, डब्ल्यू.टी.ओ. उत्तर-उत्तर, उत्तर-दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश तैयार कर सकता है।[7]

प्रवास

सन् 2010 में ग़रीब दक्षिण की कम से कम 25 अर्थ-व्यवस्थाओं के प्रवासियों द्वारा भेजी गई निधियाँ (remittance inflows) इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद के 10% से ज़्यादा थीं। फिर भी प्रवास का अधिशासन अधिकतर एकपक्षीय होता है– कार्यविधियाँ अधिकतर गंतव्य देश द्वारा संचालित– या फिर द्विपक्षीय। बहुपक्षीय तालमेल की कार्यविधियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं।[8] मानव विकास के वास्तविक सरोकार कसौटी पर चढ़े हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं प्रवासियों के अधिकार। जहाँ धन का प्रेषण ग़रीब परिवारों की आमदनी का ज़रिया बनता है, वहीं बड़े स्तर पर होने वाले प्रवास के साथ सामाजिक उठा-पटक और विघ्न-बाधाएँ भी जुड़ी हैं। बहुपक्षीय कार्यविधि लोगों को विदेश में काम खोजने में सहायक माध्यमों को उदार और सरल बना सकती है, प्रवासियों के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित कर सकती है, प्रवास से जुड़ी लागत कम कर सकती है और प्रवासी तथा गंतव्य समुदायों, दोनों के लिए बेहतर परिणाम दे सकती है।[9]

दक्षिण के उदय के साथ प्रवास का तरीका बदल रहा है। दक्षिण के देशों में विदेश से आने वाली लगभग आधी निधियाँ अन्य विकासशील देशों में ही काम कर रहे प्रवासी कामगारों द्वारा भेजी जाती हैं। हाल के वर्षों में क्षेत्रीय संगठनों और आर्थिक एकीकरण व्यवस्थाओं ने अपनी कार्यसूची में प्रवास को भी शामिल किया है। इनमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की एसोसिएशन (आसियान), अफ्रीकन यूनियन, कॉमन मार्केट ऑफ द साउथ और दक्षिणी अफ्रीका विकास समुदाय शामिल हैं।[10] सन् 2012 में प्रवास तथा विकास के वैश्विक मंच ने पहली बार दक्षिण-दक्षिण प्रवास पर विमर्श किया।

दक्षिण के उदय के साथ प्रवास का तरीका बदल रहा है। दक्षिण के देशों में विदेश से आने वाली लगभग आधी निधियाँ अन्य विकासशील देशों में ही काम कर रहे प्रवासी कामगारों द्वारा भेजी जाती हैं

हालाँकि प्रवास का अधिशासन अनिवार्य रूप से बहुपक्षीय मसला नहीं है, फिर भी अंतरराष्ट्रीय समन्वय प्रणालियाँ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौतों के तंत्र के लिए सहायक रूपरेखा उपलब्ध करा सकती हैं। प्रवास से जुड़े प्रश्नों पर वैश्विक पहलकदमी इन संवादों का लाभकारी असर और ज़्यादा बढ़ा सकती है।

चार दशक पहले के सालाना 7 करोड़ प्रवासियों की तुलना में अब अंतरराष्ट्रीय प्रवास 20 करोड़ सालाना से ज़्यादा लोगों का होता है और अधिकतर का उदगम दक्षिण से है। इस वृद्धि के साथ प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले तथा मूल व गंतव्य देशों के बीच उत्प्रवासियों के प्रवाह के आवागमन पर अंतरराष्ट्रीय सहमति वाले नियमों की ज़रूरत लगातार बढ़ती जा रही है।[11] ऐसे नियम, आर्थिक और सामाजिक स्तरों पर सभी पक्षों के लिए लाभकारी होंगे, जबकि निष्क्रियता की कीमतें भारी होती जाएँगी। यह कीमतें पूरी तरह से या बुनियादी तौर पर भी वित्तीय नहीं हैं: इनमें शामिल हैं लंबे समय के लिए परिवारों से मजबूरन अलग होने की गहरी मानवीय वेदनाएँ, कार्यस्थल पर प्रायः होने वाला दुर्व्यवहार, और विदेशी कामगारों को बुनियादी कानूनी अधिकार न मिल पाने के कारण मानवीय गरिमा को बेवज़ह लगने वाली ठेस।

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन सम्भवतः आसानी से समझ में आने वाला ऐसा सबसे बड़ा मसला है, जिसके लिए बहुपक्षीय समझौतों के मार्फ़त वैश्विक सहयोग की ज़रूरत है। दक्षिण के देशों में, द्विपक्षीय रास्तों के अलावा, जलवायु परिवर्तन से निपटने का काम राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में दर्शित हो रहा है। चीन ने सन् 2005 की तुलना में अपनी कार्बन तीव्रता (स.घ.उ. की प्रति इकाई की तुलना में कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन) को 2020 तक 40%-45% तक कम करने का संकल्प किया है।[12] सन् 2010 में भारत ने कार्बन तीव्रता में 20%-25% की कमी लाने की स्वैच्छिक घोषणा की।[13] कोरिया के विधि निर्माताओं ने मार्च 2012 में फैक्ट्रियों और बिजलीघरों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम को स्वीकृति दी।[14] रियो में मोज़ाम्बीक ने एक नई हरित-अर्थव्यवस्था की रूपरेखा पेश की, जबकि मैक्सिको ने हाल में विश्व के पहले व्यापक जलवायु परिवर्तन कानूनों को लागू किया है, जिनका लक्ष्य उत्सर्जन में कमी लाना और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रक को बढ़ाना है।[15]

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वास्तविक बहुपक्षीय पहल की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन को वांछनीय सीमा तक कम करने के लिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि पिछड़े दक्षिण की विकास अभिलाषाएँ पूरी हो सकें, उत्तर और दक्षिण को इस बात पर पारस्परिक सहमति का समझौता करना होगा कि ज़िम्मेदारियाँ किस तरीके से बाँटी जाएँ।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वास्तविक बहुपक्षीय पहल की ज़रूरत है

संवहनीय विकास पर रियो डि जेनेरो में 2012 में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अमीर और ग़रीब, सार्वजनिक और निजी, सिविल, कॉर्पोरेट और राज्य निकायों के समूहों के बीच सहयोग और गठबंधन की सम्भावनाओं को अवसर दिया। मसलन यूनीलीवर, कोका-कोला, और वॉलमार्ट उन 20 बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों में शामिल थे, जिन्होंने उपभोक्ता सामग्री फ़ोरम के मार्फ़त, संकल्प किया कि वे अपनी आपूर्ति श्रृंखला में से वनोन्मूलन को हटाएँगे।[16] माइक्रोसॉफ्ट ने 2012 में ही खुद को कार्बन-तटस्थ (carbon-neutral) कर लेने की घोषणा की। लैटिन अमेरिका की सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलर कम्पनी फेमसा ने कहा कि वह मैक्सिको में अपनी 85% ऊर्जा ज़रूरतों को अक्षय स्रोतों (renewable resources) से पूरा करेगी।[17] अनेक उत्साहजनक पहलकदमियों के बावजूद, उत्सर्जन में कटौती की ज़रूरत और दूसरी ओर इस कटौती के बारे में ढीली-ढाली वचनवद्धता के बीच बड़ा अंतर अभी भी कायम है।

विकास सहकारिता

अधिक समावेशी अंतरराष्ट्रीय अधिशासन के आवश्यक घटक के तौर पर विकास सहकारिता को और अधिक समावेशी और अधिक प्रभावकारी होना चाहिए। नई वित्तीय व्यवस्थाओं और तकनीकी सहयोग के द्वारा विकासशील देश द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर विकास सहायता और निवेश बढ़ा रहे हैं। इससे परम्परागत दान दाताओं के विकल्प तैयार हो रहे हैं या उनकी कार्यपद्धति को मज़बूत कर रहे हैं, जिससे सहायता पाने वाले देशों को बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सकें।

सन् 2011 में कोरिया गणतंत्र के बुसान में आयोजित 'अनुदान प्रभावशीलता' पर चतुर्थ उच्चस्तरीय फ़ोरम में विकासशील देशों और नागर समाज के संगठनों ने प्रभावकारी विकास सहकारिता के बुसान भागीदारी प्रस्ताव की संस्तुति की। नई वैश्विक निगरानी रूपरेखा के लिए स्वामित्व, परिणामों पर ध्यान, समावेशी विकास भागीदारी, पारस्परिक जवाबदेही और पारदर्शिता को आधार स्तम्भ के रूप में चुना गया। 'व्यापार करने' के लिए राष्ट्रीय-प्रणाली (country system) पर काफ़ी ज़ोर दिया गया और भागीदार देशों की ओर से माँग की गई कि यदि इसमें भटकाव या विचलन होता है तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकॉनमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (ओ.ई.सी.डी.) के परम्परागत दानदाताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करते हुए और व्यापक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए, एक अलग किस्म की अधिशासन-रूपरेखा की आवश्यकता होगी।[18] राष्ट्रीय स्वामित्व और सामर्थ्य के केन्द्रीय सिद्धांत पर आधारित यह सहभागिता, प्रगति के आकलन के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिशासन क्रिया-विधि और संकेतकों की स्थापना करेगी।

परम्परागत दाताओं के साथ, नए विकास सहभागियों ने, जिनमें ब्राज़ील, चीन और भारत शामिल हैं, राष्ट्रीय स्वामित्व और क्षमता-वर्धन के केन्द्रीय सिद्धांतों का समर्थन किया। फिर भी बुसान घोषणा में इस बात को रेखांकित किया गया कि इन नए विकास सहयोगियों की अपनी अलग घरेलू विकास सम्बन्धी चुनौतियाँ हैं और विदेशी सहयोग की भी उनकी स्थापित पद्धतियाँ हैं। यह बात घोषणापत्र के पाठ में परिलक्षित होती है, जिसमें कहा गया कि इन देशों के लिए, ''बुसान में सहमति पाने वाले सिद्धांत, प्रतिबद्धताएँ और कार्यवाही, दक्षिण-दक्षिण सहयोग में स्वैच्छिक आधार पर ही लागू होंगी।''[19] इससे आगे बढ़ते हुए ओ.ई.सी.डी. की डेवलपमेंट असिसटेंस कमिटी (DAC) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) को संयुक्त रूप से यू.एन. डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ़ोरम (UNDCF) के मार्फ़त नई 'प्रभावकारी विकास सहयोग की वैश्विक भागीदारी' को प्रभावशाली तरीके से चलाने के लिए समर्थन देना होगा। इस पर हस्ताक्षर करने वालों की पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्धता के बावजूद परिणामी

दस्तावेज़ (outcome document) में लक्ष्यों की ऐसी किसी समयबद्ध या मापी जाने वाली वचनबद्धता का ज़िक्र नहीं है, जिसे लेकर नागरिक उनको जवाबदेह ठहरा सकें।

बुसान के बाद की व्यवस्था ने अभी शक्ल नहीं ली है। पर कुछ बीच की प्राथमिकताएँ सामने आई हैं। इनमें एक है परम्परागत दान-दाताओं से यह अपेक्षा कि वे सहायता बढ़ाने और बेहतर समन्वय और तालमेल के बारे में 2005 के आठ देशों के समूह (जी-8) के ग्लेनईगल्स सम्मेलन के वादों को पूरा करें।[20] परम्परागत दानदाता अब उदीयमान दाताओं के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, जो विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में जानकारी और अनुभव का योगदान कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र इस प्रकार के त्रि-पक्षीय विकास सहयोग में, संयुक्त राष्ट्र विकास सहयोग फ़ोरम के माध्यम से, अपनी वैश्विक सदस्यता के सहारे दक्षिण के सहभागियों को जोड़ने के काम के लिए बेहतर स्थिति में है। इसमें एक मुख्य काम उत्तर-दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण के बीच विकास सहयोग और वैश्विक नियमों का बेहतर गठबंधन है।

बुसान समझौता एक पहल थी, जिससे देशों के बीच सहकारिता बढ़े और जो उदीयमान राष्ट्रों की क्षमताओं का कारगर रूप से उपयोग कर सके। जैसे कि अन्य सार्वजनिक साधनों के साथ होता है, जैसे ही वैश्विक स्तर पर सामान्य समझ पैदा होगी, इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन स्वीकृत रूपरेखा के तहत राष्ट्रीय सरकारों को विकेन्द्रीकृत किया जा सकेगा। सितम्बर 2000 की सहस्त्राब्दी घोषणा और उससे निकले सहस्त्राब्दी लक्ष्य के वैश्विक समझौते को नया सार्वजनिक कार्य मान सकते हैं। इन लक्ष्यों पर सहमति ने व्यापक स्तर पर गतिविधियों और संस्थाओं के बीच विकास सहयोग को प्रोत्साहन और ध्यान देते हुए एक सरल सत्य को रेखांकित किया: लोगों की सामर्थ्य और सभी समाजों के विकास को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण वैश्विक कार्य है।[21] इन लक्ष्यों के मामले में वास्तविक प्रगति देशों की पहल और स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ही हुई है।

दक्षिण के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व

वैश्विक स्तर पर आवाज़ों और शक्तियों में निरंतर बढ़ती विविधता को अंगीकार करने और विकास से जुड़ी संवहनीय दीर्घकालीन प्रगति के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिशासन की वर्तमान संस्थाओं और सिद्धांतों के पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। इनमें से अनेक की रचना दक्षिण के उदय के काफ़ी पहले द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की व्यवस्था के अनुरूप हुई थी, जो आज की वास्तविकता से मेल नहीं खाते।

परिणामस्वरूप, इन संस्थाओं में दक्षिण का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। बदलती वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं के बावजूद, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में वोटिंग-कोटा उत्तर के देशों के पक्ष में झुका हुआ है। उदाहरण के लिए चीन के पास, जो दुनिया की दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था है और जिसके पास 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है, विश्व बैंक में फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम से कमतर वोटिंग शेयर (3.35%) है।

इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति और सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्णय जिस स्थायी सदस्यता के माध्यम से करती है, वह 1945 की भू-राजनीतिक संरचना को प्रतिबिम्बित करती है। न्यूयॉर्क में 2012 की महासभा की बैठक में, दक्षिण के अनेक शासनाध्यक्षों ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों और भारत जैसी प्रतिनिधित्व-विमुख शक्तियों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की लम्बे समय से चली आ रही माँग को दोहराया।[22]

बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक प्रातिनिधिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। यदि ये संस्थाएँ सभी सदस्य राज्यों और उनकी जनता को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने में विफल रहीं ,तो ब्रेटन वुड्स संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की प्रासंगिकता के कम होने का खतरा है। इन संस्थाओं को दक्षिण और उत्तर, दोनों के अनुभवों का सम्मान करना और रचनात्मक रूप से उनके अनुभवों का उपयोग करना चाहिए ताकि वर्तमान तथा भावी पीढ़ी को समतापरक और संवहनीय परिणाम मिलें।

साथ ही साथ, अपनी बढ़ती आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव के अनुरूप, उभरते दक्षिण को वैश्विक स्तर पर बहुपक्षीय संगठनों में साधनों का और ज़्यादा योगदान करते हुए अधिक ज़िम्मेदारियों को अपने हाथ में लेना चाहिए।[23] दक्षिण को नेतृत्व की ज़्यादा बड़ी भूमिकाएँ केवल क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी निभानी चाहिए। वैश्विक संस्थाओं में अधिक पारदर्शिता और तथा जवाबदेही, जो यों भी ज़रूरी है, दक्षिण की बेहतर भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगी।

इस दिशा में कुछ सकारात्मक गतिविधियाँ हुई हैं। विकासशील देश, जी-20 राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलनों के माध्यम से, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं और वैश्विक वार्ता में पहले ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकॉनमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट ने कुछ विकासशील देशों को भी सदस्यता दी है। विकसित देशों को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की सफलता से उत्तर को भी लाभ होता है और सभी की समृद्धि के दरवाज़े खुलते हैं।

वास्तव में, कुछ अंतर-शासकीय प्रक्रियाएँ दक्षिण की बेहतर भागीदारी से मज़बूत होंगी, जो इन प्रक्रियाओं में अधिक वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधन ला सकते हैं। उदीयमान अर्थव्यवस्थाएँ सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को हासिल करने में, जलवायु परिवर्तन के शमन में

वैश्विक स्तर पर आवाज़ों और शक्तियों में निरंतर बढ़ती विविधता को अंगीकार करने और विकास से जुड़ी संवहनीय दीर्घकालीन प्रगति के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिशासन की वर्तमान संस्थाओं और सिद्धांतों के पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है

नवाचार और दोहा विकास-चक्र को पूरा करके, प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं।

वैश्विक संगठन, जो दुनिया के देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं, सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रीय सरकारों के मार्फ़त दुनिया की जनता के प्रति जवाबदेह बन जाते हैं। फिर भी अकेले राज्य की मध्यस्थता अपर्याप्त है। वैश्विक आंदोलनों और बहुराष्ट्रीय एक्टिविस्ट नेटवर्कों के मार्फ़त अनेक प्रकार की आवाज़ें और कर्ता (actors) अंतरराष्ट्रीय अधिशासन पर असर डालते हैं। वास्तव में, वैश्वीकरण-विरोधी आंदोलनों का ज़ोर इसी बात पर रहा है, जो खुद को 'वैश्विक लोकतंत्र' के रूप में व्याख्यायित करते हैं, कई प्रकार के मसलों से जुड़े हैं, कई प्रकार के सरोकारों को मुखर करते हैं और अनंत प्रकार के राजनीतिक संदेशों से जुड़े हैं, पर उन सबका बुनियादी सरोकार अंतरराष्ट्रीय शक्ति और अधिशासन को नागर समाज के प्रति जवाबदेह बनाना है।

वैश्विक आंदोलनों और बहुराष्ट्रीय एक्टिविस्ट नेटवर्कों के मार्फ़त अनेक प्रकार की आवाज़ें और कर्ता अंतरराष्ट्रीय अधिशासन पर असर डालते हैं

इन बातों से आज की बहुपक्षीय संस्थाओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधित्व और दिशा-निर्देशों के पुनर्मूल्यांकन की प्रेरणा मिलती है:

- *अभिव्यक्तिः* हितधारकों और निर्णयकारी समूहों को आपस में जोड़ना ताकि अपने सरोकारों वाले वैश्विक मसलों पर सबकी आवाज़ प्रभावशाली हो।
- *सार्वजनिक साधनः* आवश्यक वैश्विक सार्वजनिक साधनों के लिए बहुस्तरीय, बहुक्षेत्रीय और बहुकर्ता उत्पादन (multi actor production) को सुविधाजनक बनाने के लिए संगठनों के बीच समन्वय बनाना।
- *नेतृत्वः* जब मसले वैश्विक नीतिगत गतिरोध में फँस जाएँ या जहाँ संकट बहुत बड़ा रूप ले रहा हो, उन मसलों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहायता करने के लिए वैश्विक नेताओं को बढ़ावा देना, वे चाहे राज्य से जुड़े हों या ग़ैर-राज्य, व्यक्तिगत हों या सामूहिक।
- *संयोजन* (convening): बदलती वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप वर्तमान संगठनों का पुनर्गठन और उन्हें अधिकार तथा दक्षता प्रदान करना ताकि वे विविध प्रकार के हितधारकों के बीच मध्यस्थता कर सकें।
- *सूचना और संसाधनः* दक्षिण के निर्धन देशों के लिए बेहतर सूचना, तकनीकी सहायता और वित्त की व्यवस्था करना ताकि वे वैश्विक अधिशासन में ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से भाग ले सकें।
- *नागरिकों की भागीदारीः* नागरिकों के नेटवर्क और इसके पहले वैश्विक विमर्श के हाशिए पर चले गए भागीदारों के बहुमूल्य विचारों का लाभ उठाना।

अंतरराष्ट्रीय संगठन तेज़ी से बदलती दुनिया में पहले से ज़्यादा समावेशी और इसकी ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने विकास सहकारिता के बारे में और व्यापक विमर्श को बढ़ावा देने के लिए विकास सहायता फ़ोरम की स्थापना की है। नए तरीकों से बहुपक्षीयता बढ़ाने की प्रचुर सम्भावनाएँ हैं। फिर भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के अधिशासन में मामूली सुधार हुए हैं। दशकों की बहस के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आधारिक संरचना जस की तस है। जिन सवालों पर वैश्विक गतिरोध है, उनके बारे में यदि बहुपक्षीय संस्थाएँ बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहती हैं, तो और दृढ़ संकल्प के साथ सुधारों की ज़रूरत होगी।

वैश्विक नागर समाज

अंतरराष्ट्रीय अधिशासन संस्थाएँ केवल सदस्य देश ही नहीं, वैश्विक नागर समाज के प्रति भी जवाबदेह हैं, जो राज्यों और बाज़ार के प्रतिकारी बल के रूप में संतुलन प्रदान कर सकता है। तमाम तरह की स्वैच्छिक संस्थाएँ, जिनमें ग़ैर-सरकारी संगठन, सामाजिक आंदोलन, एडवोकेसी समूह, संगठन और सामुदायिक समूह शामिल हैं, चुनावों, लॉबीइंग, मीडिया और जन अभियानों जैसे प्रभावकारी माध्यमों का इस्तेमाल करती रही हैं और दक्षिण के अनेक बड़े देशों में सामाजिक बदलाव की वाहक बनी हैं– भारत, ब्राज़ील, मिस्र और दक्षिण अफ़्रीका इसके उदाहरणों में शामिल हैं। भारत के केरल राज्य में, नागरिक पहल का समृद्ध इतिहास है, जो सामाजिक अधिकारों, समतावादी सार्वजनिक नीतियों पर चलने के लिए सरकारों को प्रभावित करती रही है। ब्राज़ील में स्वास्थ्य सेवा के सैनिटारिस्टा आंदोलन ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने और उन्हें ग़रीबों तक ले जाने में केन्द्रीय भूमिका निभाई थी।[24]

अंतरराष्ट्रीय अधिशासन के परम्परागत औपचारिक तरीकों के बाहर राष्ट्रीय नागर समाज के समूह अपनी सरकारों से संवाद के अनुभवों का लाभ उठाते हुए उत्तर-दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण संवाद के स्वतंत्र नेटवर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुराष्ट्रीय नेटवर्क उस उदीयमान वैश्विक नागर समाज की बुनियाद तैयार कर रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन से लेकर प्रवास और मानवाधिकार तक के मसलों पर कार्रवाई की माँग कर रहा है।

वैश्विक नागर समाज की महत्वपूर्ण वैश्विक मसलों पर निर्णय प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की सामर्थ्य इंटरनेट क्रांति के कारण काफ़ी बढ़ गई है। इसने अलग-अलग प्रकार के समूहों के बीच तात्कालिक सक्रिय संपर्क कायम कर दिया है और विश्व भर के नागरिकों के बीच विचारों और सरोकारों का तेज़ी से प्रसार करने वाला मंच उपलब्ध कराया है। लोग एक-दूसरे से बात कर सकते हैं,

वैज्ञानिक तथा दूसरे व्यवसायी बाज़ार और राज्य के दबाव के बग़ैर आज़ादी से एक-दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। वैश्विक संचार में यह नई आज़ादी रचनात्मक भागीदारियों को बढ़ावा देकर व्यक्तियों और सामाजिक संगठनों का सशक्तीकरण कर रही है, जिससे नए प्रकार की एकता विकसित हो रही है और लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे से संपर्क करने और खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिल रहा है।

जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की परिणति के रूप में हाल में अरब देशों के विद्रोह ने दिखाया कि सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है, जिसकी अनदेखी विश्व के नेता और वैश्विक संस्थाएँ अपने नुकसान की कीमत पर ही करेंगे। युगाण्डा के छापामार समूह लॉर्ड्स रेसिस्टेंस आर्मी के नेता और घोषित युद्ध अपराधी जोसफ कोनी पर बने वीडियो (*कोनी 2012*) के तेज़ी से फैलने और जबर्दस्त प्रतिक्रिया होने से पता लगा कि सोशल मीडिया महत्वपूर्ण मसलों पर कुछ ही दिनों के भीतर करोड़ों लोगों को विमर्श में जोड़ सकता है।[25] किसी खास सरोकार या मंच की वैधानिकता को लेकर असहमति हो सकती है, पर इसे मानना होगा कि सूचना का जबर्दस्त प्रसार करने वाले सोशल नेटवर्क वैश्विक जनमत को और अंततः अंतरराष्ट्रीय अधिशासन को प्रभावित करते हैं।

वास्तव में, वैश्विक नागर समाज का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है उसकी वह सामर्थ्य जो उन नए नियमों और कायदों को गढ़ने में मदद करती है, जो राज्य और निजी कर्ताओं के व्यवहार को रूपांतरित कर सकते हैं। मसलों का मसौदा तैयार करके और राज्यों पर दबाव डालकर, नागर समाज के नेटवर्क नए मसलों को विचार की मेज पर ला सकते हैं, नई संधियों-समझौतों, मज़बूत प्रवर्तन कार्यविधियों (enforcement mechanisms), यहाँ तक कि सीधे हस्तक्षेप के लिए सरकारों को प्रभावित कर अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई को प्रेरित कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर नागर समाज के असर के बेहतरीन उदाहरणों में स्त्रियों के मताधिकार का वैश्विक प्रसार, गुलामी के विरोध में आंदोलन और रेड क्रॉस आंदोलन, जिसके कारण जिनेवा कन्वेंशन और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसायटी का गठन हुआ। हाल में, वैश्विक नागर समाज नेटवर्कों के प्रभाव से सुरंगी बम के खिलाफ़ नियम बने, एड्स की दवाओं की सुलभता बढ़ी और स्त्री-विरोधी हिंसा के खिलाफ़ अभियान चले।

हालाँकि वैश्विक सामाजिक संगठनों के भीतर अंतरराष्ट्रीय अधिशासन नियमों और निर्णय प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की जबर्दस्त सामर्थ्य है, पर उनकी और बहुराष्ट्रीय नेटवर्कों की ताकत को बहुत बढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। नागर समाज की लोकतांत्रिक प्रकृति को कई बार साधनों की कमी की चुनौती मिलती है। ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत के कारण कई बार उत्तर की अंतरराष्ट्रीय ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ वैश्विक नागर समाज के मंच पर अपने अनुपात से ज़्यादा प्रभाव रखती हैं।[26] उदाहरण के लिए मानवाधिकार व्यवस्था, अक्सर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ज़ोर देती है, जो पूर्वी यूरोप के नागर समाज का खास सरोकार है, सामाजिक अधिकारों पर नहीं जो दक्षिण के देशों के जनांदोलनों की माँगों के केन्द्र में होते हैं। लोकवृत्त की सीमाएँ और अन्य बंदिशें सामाजिक संगठनों की सक्रियता पर असर डालती हैं।[27] इसके अलावा पारदर्शिता का मसला है, जहाँ यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि नागर समाज के ये संगठन राज्य और बाज़ार-शक्तियों से किस हद तक निरपेक्ष हैं। जब सामाजिक संगठन राज्य शक्ति, आर्थिक प्रभाव अथवा पारंपरिक सत्ता-केन्द्र के विस्तार का रूप धारण कर लेते हैं, तब नागर समाज की गतिविधियों से असमानताएँ और अस्थिरता बजाय कम होने के बढ़ती है।[28]

अंतरराष्ट्रीय अधिशासन की भावी वैधानिकता निर्भर करेगी संस्थाओं की नागरिक नेटवर्कों और समुदायों से जुड़ने की उनकी क्षमताओं पर– उनके सरोकारों को समझने पर और समाधान के उनके विचारों और पद्धति को समझने पर, जिनसे वे अपने प्रयासों और ऊर्जा को दिशा दे पाते हैं। इस प्रकार का जुड़ाव उनके कार्य-व्यवहार की वैधानिकता को बढ़ाएगा और सदस्य राज्य के नागरिकों के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा (बॉक्स 5.2 भी देखें)। उदाहरण के लिए, पारिस्थितिकीय नागरिकता (ecological citizenship) का विचार वैश्विक सार्वजनिक साधनों के बारे में ज़मीन से लेकर ऊपर तक वैश्विक जनमत तैयार करने का अच्छा तरीका हो सकता है।[29]

वैश्विक नागर समाज में वह सामर्थ्य है जो उन नए नियमों और कायदों को गढ़ने में मदद करती है, जो राज्य और निजी कर्ताओं के व्यवहार को रूपांतरित कर सकते हैं

प्रभावी होने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संगठनों को दक्षिण और उत्तर में समान रूप से सोशल मीडिया समुदायों और ग़ैर-सरकारी संगठनों के साथ उपयोगी साझेदारी कायम करनी होगी। उन्हें नीतिगत बदलावों के प्रति समर्थन हासिल करने और अंतरराष्ट्रीय अधिशासन के अधिक समतापूर्ण सिद्धांतों और संस्थाओं की ओर रूपांतरण के लिए नागरिक समूहों से जुड़ना होगा। उदाहरण के लिए, 1980 के दशक में, विश्व स्वास्थ्य संगठन को तब राज्यों के हितों का सावधानी से प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की माँग का समायोजन करना पड़ा, जब निजीकरण पर ज़ोर दिया जा रहा था। सामुदायिक स्वास्थ्य के साथ उसकी केन्द्रीय प्रतिबद्धता और नागर समाज के साथ संपर्क ने उसे उन नीतियों पर चलते रहने का संबल दिया, जो स्वास्थ्य की अधिकार-आधारित पद्धति पर जोर देती हैं।[30]

वैश्विक लोकतंत्र के लिए विश्व संसद?

वैश्विक मसलों के अधिशासन के वैश्विक निर्णयों में विश्व के लोगों का प्रतिनिधित्व और वैधता ज़रूरी हैं, पर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में प्रभावशाली नागरिक भागीदारी की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। ऐसे समय में जब अंतर-शासन निर्णय प्रक्रिया ने अपनी सीमा ज़ाहिर कर दी है, समता और संवहनीयता की तलाश और धरती के सामने खड़ी चुनौतियों के तुरंत निवारण के लिए वैश्विक नागरिकता की ज़रूरत है।

विश्व संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूरक के रूप में काम करेगी– या तो औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था से जुड़कर या एक अलग संस्था के रूप में। यह विचार नया नहीं है, पर परिपक्व होता जा रहा है और इसे नागर समाज के कर्ताओं तथा क्षेत्रीय संसदों का समर्थन मिल रहा है, जिनमें यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और अफ़्रीकी संसद शामिल हैं। हाल में प्रबुद्ध जनों के एक बहुपक्षीय समूह ने 'मैनिफ़ेस्टो फ़ॉर ग्लोबल डेमोक्रेसी' जारी करके इसे रेखांकित किया।[1]

विश्व संसद राष्ट्रीय संसदों के प्रतिनिधियों से गठित होगी, जो हरेक देश के विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। चूँकि बहुसंख्यक राष्ट्रीय संसद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई होती हैं, इसलिए ऐसी संस्था में उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक जवाबदेही होगी। इस प्रकार विश्व संसद राष्ट्रीय नीति निर्धारण और वैश्विक निर्णयों के बीच की कड़ी का काम करेगी। राष्ट्रीय संसदों और सरकारों को उनके निर्णयों के राष्ट्रीय सीमा के बाहर होने वाले प्रभाव के बारे में जागरूक करेगी और साथ ही, वैश्विक मसलों के अधिशासन के अनुभवों और ज्ञान से परिचित भी कराएगी।

इस संसद का एक विस्तृत वार्षिक सत्र हो सकता है, जिसके दौरान वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए सिफ़ारिशें और मसौदे में शामिल करने वाले बिन्दुओं की सलाह दे सकती है। और इसके साथ ही स्वीकृत बहुमत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास विमर्श और निर्णय के लिए मसौदे के मुद्दे भेज सकेगी। इसके विचार-विमर्श के पीछे उच्च नैतिक और राजनीतिक प्राधिकार होगा, हालाँकि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय सरकारों का ही होगा। राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का निर्धारण या तो राष्ट्रीय संसद करेंगी या विशेष चुनाव के द्वारा नागरिकों को विश्व संसद में अपने प्रतिनिधि भेजने का मौका मिलेगा। प्रतिनिधियों की संख्या देश की जनसंख्या के अनुपात से होगी, यह पद्धति कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की पद्धति से काफ़ी अलग होगी, जहाँ मतदान का कोटा आर्थिक योगदान के आधार पर तय होता है।

सुसंगत बहुलवाद की ओर

दक्षिण के उदय की प्रतिक्रिया में बहुपक्षीय व्यवस्था के सामने खड़ी चुनौती विश्ववाद और क्षेत्रवाद के बीच या उत्तर की परम्परागत शक्तियों द्वारा विकसित और प्रबंधित पुरानी व्यवस्था तथा विकासशील देशों की ज़रूरतों से जन्मी नई व्यवस्थाओं के बीच का कोई फ़र्ज़ी फ़र्क नहीं है। बल्कि यह एकीकरण, समन्वय और कुछ मामलों में इन संस्थाओं से जुड़ा सुधार है ताकि वे मिलकर प्रभावशाली तरीके से काम कर सकें। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए वैश्विक अधिशासन में विविधता और लचीलापन बेहतर है, पर यह उन समस्याओं का समाधान नहीं है जो अपनी प्रकृति से मूलतः वैश्विक हैं। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे नीति-निर्माताओं को बहुपक्षीय अधिशासन में सुसंगत बहुलवाद की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें साझा कायदे और लक्ष्य हों, और जो क्षेत्रीय और वैश्विक विकास की विविध, पर एक-दूसरे की पूरक, पहल से जुड़े हों।

दक्षिण के उदय की प्रतिक्रिया में बहुपक्षीय व्यवस्था के सामने खड़ी चुनौती परम्परागत शक्तियों द्वारा विकसित और प्रबंधित पुरानी व्यवस्था तथा विकासशील देशों की ज़रूरतों से जन्मी नई व्यवस्थाओं के बीच का कोई फ़र्ज़ी फ़र्क नहीं है। यह एकीकरण, समन्वय और कुछ मामलों में इन संस्थाओं से जुड़ा सुधार है ताकि वे मिलकर प्रभावशाली तरीके से काम कर सकें

हाल में दक्षिण के काफ़ी इलाकों का अनुभव है कि कुछ सार्वजनिक साधन क्षेत्रीय स्तर पर बहुत अच्छे से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जैसा कि अध्याय-2 में बताया गया है, क्षेत्रीय संस्थाएँ कई बार क्षेत्रीय ज़रूरतों के प्रति वैश्विक संस्थाओं की तुलना में ज़्यादा तेज़ गति और प्रभावशाली तरीके से काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए इनमें स्थानिक बीमारियों के निवारण, साझे पारिस्थितिकीय तंत्र (shared eco-system) की रक्षा और अंतरक्षेत्रीय व्यापार बाधाओं को (यदि वे मूल रूप में वैश्विक के बजाय क्षेत्रीय हैं) हटाने का काम शामिल है। इन सब मामलों में समान समझ वाले पड़ोसी देशों के लिए यह अच्छा है कि वे इन चुनौतियों का सहकारिता के आधार पर सामना करें, साथ ही इनसे जुड़े वैश्विक मसलों का निपटारा जहाँ होना है, उन्हें वहाँ निपटाएँ।

क्षेत्रीय सहकारिता बढ़ने के नुकसान भी हैं– बहुपक्षीय संस्थाओं की पहले से मौजूद विविधता के साथ-साथ अपवर्जन (exclusion), दोहराव और अनेक एजेंसियों की आपसी प्रतियोगिता से जटिलता बढ़ती है। अनेक जगह क्षेत्रीय संस्थाएँ वैश्विक संरचनाओं की पूरक होती हैं, हालाँकि इस किस्म का समन्वय आज या तो काफ़ी कम है या अपर्याप्त है।

वैश्विक अधिशासन व्यवस्थाओं को उन मिली-जुली रणनीतियों का सम्मान करना चाहिए जिनपर अधिकतर देश चल रहे हैं। यह स्पष्ट है कि विकासशील और उदीयमान अर्थव्यवस्थाएँ विभिन्न तरीकों से सहयोग करना चाहती हैं। दिवपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय। वक्त के साथ, जैसे-जैसे नई चुनौतियाँ उभर रहीं हैं, देशों ने उनसे निपटने के लिए अधिशासन के नए तरीकों की रचना की है। मसलन, वित्तीय क्षेत्र में देश अपने जोखिम और बचाव के तरीकों को बदलना चाहते हैं। वे राष्ट्रीय मुद्रा भंडार, द्विपक्षीय ऋण सीमा (bilateral credit lines), क्षेत्रीय व्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का मिला-जुला उपयोग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बहुल (plural) होना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यविधियों और नीतियों से संगत हो।

इस 'सुसंगत बहुलवाद' का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्तरों पर संस्थाएँ समन्वित तरीके से काम करें ताकि वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक हितकारी काम हों। केवल वैश्विक और क्षेत्रीय संस्थाओं में ही नहीं, सार्वजनिक-निजी और नागर समाज

के संगठनों के बीच की, इस पारस्परिक पूरकता में रचनात्मकता है, भले ही अभी यह शैशवावस्था में या अपर्याप्त है। पुरानी व्यवस्था द्वारा छोड़े गए छिद्रों को भरने के लिए नई व्यवस्थाएँ और नई साझेदारियाँ जब तैयार होती हैं, तब उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे जितना सम्भव हो, दोहराव को रोकें। हर स्तर पर नई व्यवस्थाओं को एक-दूसरे के समन्वय में, हितों की एकता और ज़िम्मेदारियों को बाँटते हुए और विद्यमान बहुपक्षीय संगठन के साथ चलना चाहिए।

बहुलता और व्यापक विविधता जहाँ स्वागत योग्य घटनाक्रम है, वहीं नए संगठनों की प्रचुरता के साथ दोहराव और अकुशलता भी आती है। एक संगत रचना की दिशा में बढ़ते हुए कुछ संगठन कामयाब होंगे और कुछ अर्थहीन हो जाएँगे।

मानव विकास की दिशा में टिकाऊ प्रगति प्राप्त करने के लिए वैश्विक सार्वजनिक साधनों के अधिशासन के लिए प्रभावशाली बहुपक्षीयता की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भी मानव अधिकारों और अन्य सार्वभौमिक सिद्धांतों पर दिशा दिखा सकती हैं, और सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून के मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकती हैं। फिर भी नई चुनौतियों और भू-राजनीतिक यथार्थ का सामना करने के लिए बहुपक्षीयता को लचीला होना पड़ेगा। एक संगत बहुल व्यवस्था में, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ समन्वयकारी निकाय का काम कर सभी हितधारकों के लिए एक उत्प्रेरक या संयोजक की भूमिका अदा कर सकती हैं। इसे करने के लिए उन्हें अधिकारों, यथेष्ट निपुणता और साधनों की आवश्यकता होगी, ताकि वे मध्यस्थता और काम को सहज कर सकें, अंतर्विरोधी ज़रूरतों का विश्लेषण करके समाधान निकाल सकें, जिससे व्यावहारिक तथा पारस्परिक लाभकारी नतीज़ों पर पहुँचा जा सके। दक्षिण को पूरी तरह जोड़ने के लिए, अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सुधारने और बदलने की ज़रूरत होगी। और जब दक्षिण को लगेगा कि बहुपक्षीय संगठन विकसित देशों के हितों के साथ-साथ हमारे भी हितों का काम कर रहे हैं, तो वह बदले में उनका सहारा लेगा और उनकी मदद करेगा।

वित्तीय संरचनाः उभरते दक्षिण के लिए पुनर्रूपांकन

दक्षिण का उदय साधनों के संचय की नई बनावट पेश कर रहा है, जो कि सम्भवतः एक सघनतर, बहुस्तरीय, और विविध रंगत वाली वित्तीय संरचना है। यह संरचना वित्तीय स्थिरता और जीवंतता को बढ़ावा देगी, दीर्घकालीन उत्पादक क्षमता को मदद करेगी, मानव विकास को बढ़ावा देगी और राष्ट्रीय नीति के आकार को बढ़ाएगी।

कुछ मामलों में ये उदीयमान संस्थाएँ और व्यवस्थाएँ ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के कुछ कार्यों का स्थान लेंगी, पर अधिकतर मामलों में वे विश्व की विद्यमान आर्थिक संरचना की पूरक साबित होंगी। यही नहीं, ये उदीयमान संस्थाएँ प्रतिनिधित्व, अधिशासी सिद्धांतों और शर्तों से जुड़े मुद्दों की ओर ध्यान खींचकर ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के लिए रूपांतरकारी भी हो सकती हैं।

दक्षिण ने यों भी कुछ वैकल्पिक संस्थाओं और रास्तों को विकसित कर लिया है, जिनमें क्षेत्रीय मौद्रिक और सहायक व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

- सन् 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के दौरान, एशियाई देशों के बीच विनिमय (swap) व्यवस्थाओं के रूप में चियांग माई पहल का उदय हुआ। यह व्यवस्था चियांग माई इनीशिएटिव मल्टीलेटराइज़ेशन के रूप में विकसित हो गई, जो सदस्य देशों को भुगतान संतुलन और अल्पावधि नकदी की दिक़्क़तों में धनराशि के आहरण का अवसर देती है।
- सन् 1976 में लीग ऑफ अरब स्टेट्स के 22 सदस्य देशों ने अरब मुद्रा कोष बनाया, उसके पास अपने सदस्य देशों के आपात्कालीन वित्तीयन और व्यापक मुद्रा सहयोग के लिए 2.7 बिलियन डॉलर का भंडार है। इसके अलावा अरब देशों की एकीकृत मुद्रा बनाने की कामना भी है।[31]
- हाल में भारतीय रिज़र्व बैंक ने दक्षिण एशिया सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य देशों के लिए 2 बिलियन डॉलर की विनिमय व्यवस्था की घोषणा की।[32]
- लगभग 2.3 बिलियन डॉलर की पूँजी से बना लैटिन अमेरिकन रिज़र्व फंड, अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह थर्ड-पार्टी लोन की गारंटी भी लेता है और संचित निधि के निवेश की व्यवस्था और मौद्रिक नीतियों के लिए क्षेत्रीय समन्वय का काम करता है। अधूरी क्षेत्रीय सदस्यता के कारण इसकी सामर्थ्य सीमित है, इस इलाके की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश ब्राज़ील इसका सदस्य नहीं है।[33]
- सन् 1991 से 2007 के बीच कर्ज़ देने में चार गुना वृद्धि और सदस्य देशों के लगभग अनन्य स्वामित्व के कारण एंडियन विकास बैंक ने सबका ध्यान खींचा। इसके लगभग सभी सदस्य देश विकासशील हैं (पुर्तगाल और स्पेन के अलावा)।[34]

ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका कम नहीं हो जाती। इन पूँजियों

सुसंगत बहुलवाद का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्तरों पर संस्थाएँ समन्वित तरीके से काम करें ताकि वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक हितकारी काम हों

से होने वाले बड़े संवितरणों (disbursements) में उधार लेने वाले देश को आई.एम.एफ़. के निगरानी कार्यक्रम के तहत रहना पड़ सकता है, (बॉक्स 5.3) जैसा चियांग माई इनीशिएटिव मल्टीलेटराइज़ेशन में किया जा रहा है।

दक्षिण के देशों द्वारा प्रोत्साहित क्षेत्रीय वित्तीय संरचना उन नीतियों के लिए उत्साहवर्धक है जो विचारधारा के बजाय व्यावहारिकता पर ज़ोर देती हैं, और यह सुनिश्चित करती हैं कि शर्तें कम हों और देश के अनुकूल हों (बॉक्स 5.4)।[35] क्षेत्रीय संस्थाएँ जो अपने आसपास ही ऋण देती हैं, ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा बना सकती हैं, जो राजनीतिक सरोकारों के प्रति अधिक संवेदनशील हों और आर्थिक रूप से उपयुक्त हों, जिनमें हल्की निगरानी हो और शर्तों का बोझ कम हो।

कुछ संस्थाओं में, जैसे कि नवजात बैंक ऑफ द साउथ[36] है, ऋण पर शर्तें रखी ही नहीं जातीं। दूसरी हैं, जैसे कि चियांग माई इनीशिएटिव मल्टीलेटरलाइज़ेशन और अरब मुद्रा कोष, जहाँ शर्तों को कुछ खास परिस्थितियों में ही लागू किया जाता है, और यह सदस्य देशों के बीच विमर्श का बिन्दु है। फिर भी कुछ अन्य संगठन, जैसे कि लैटिन अमेरिकन रिज़र्व फंड, निगरानी ज़रूर रखते हैं, पर आई.एम.एफ़. की टॉप-डाउन पद्धति पर नहीं चलते, बल्कि आदाता सरकारों से सहयोग करते हैं।

क्षेत्रीय व्यापार समझौते

वैश्विक व्यापार संवाद के दोहा चक्र में गतिरोध के बावजूद, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ है। दक्षिण-दक्षिण व्यापार को खोलने वाले समझौतों की काफ़ी अच्छी सम्भावनाएँ हैं, उनके लाभ कम से कम उतने तो हैं, जिससे उन्हें उत्तर के बाज़ारों में प्रवेश मिले। ओ.ई.सी.डी. का अनुमान है कि यदि दक्षिण-दक्षिण टैरिफ़ को उत्तर-दक्षिण के स्तर तक कम कर दिया जाए तो दक्षिण को 59 बिलियन डॉलर का लाभ होगा।[37] केवल अफ्रीका के भीतर ही यदि और ज़्यादा खुले बाज़ार के लिए उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था हो सके तो इस इलाके की अनेक और विविध प्रकार की फसलों के व्यापार को बढ़ाने की प्रचुर सम्भावनाएँ हैं।

सफल क्षेत्रीय व्यवस्था का एक उदाहरण है 2010 का साओ पाउलो चक्र, जिसमें 22 विकासशील देशों ने आपस में तकरीबन 70% व्यापार के टैरिफ़ में 20% की कमी करने पर सहमति बनाई। यह कमी 1989 की वैश्विक व्यापार व्यवस्था की रूपरेखा के अंतर्गत की गई, जिसे विश्व व्यापार संगठन समझौते के उस खंड के तहत स्थापित किया गया था, जो विकासशील देशों को इस बात की अनुमति देता है कि वे सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र

बॉक्स 5.3

एशिया में क्षेत्रीय वित्त प्रबंधनः चियांग माई इनीशिएटिव मल्टीलेटराइज़ेशन और एशियाई विकास बैंक

मौजूदा वित्तीय संकट ने, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और चीन, जापान तथा कोरियाई गणराज्य (आसियान+3) की क्षेत्रीय व्यवस्था चियांग माई इनीशिएटिव के प्रभाव क्षेत्र को काफ़ी बढ़ा दिया है। सन् 2009 के शुरू में इस पहल को बहुपक्षीय बनाया गया और इसे नया नाम दिया चियांग माई इनीशिएटिव मल्टीलेटरलाइज़ेशन। क्षेत्रीय निगरानी की व्यवस्था बनाने और उसे लागू करने की मुश्किल के कारण, उस वक्त किसी देश के लिए उपलब्ध ऋण सीमा के 20% से अधिक के संवितरण पर यह व्यवस्था की गई थी कि कर्ज़ लेने वाले देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की निगरानी व्यवस्था में रहना होगा।

आसियान+3 सदस्य देश चियांग माई इनीशिएटिव मल्टीलेटराइज़ेशन को और मज़बूत बनाते जा रहे हैं। मई 2012 में मुद्रा विनिमय पूल (currency swap pool) को दुगना करके 240 बिलियन डॉलर का बना दिया गया। 2012-13 में किसी देश को अपनी अधिकतम सीमा के 30% के नीचे कर्ज़ लेने पर आई.एम.एफ़. कार्यक्रम के तहत नहीं रहना होगा (वर्तमान विमर्श का परिणाम सकारात्मक हुआ तो 2014 में यह 40% होगा)। आई.एम.एफ. से जुड़े और पृथक, दोनों ही विनिमयों की परिपक्वता अवधि बढ़ा दी गई है। और पहली बार एक एहतियाती ऋण सीमा रेखा (precautionary credit line) को शुरू किया गया है जो सदस्य देश को उसके आकार के आधार पर, निर्धारित फॉर्मूले के तहत, धनराशि आहरित करने का अधिकार देगी। (एशियाई बॉण्ड बाज़ार का विस्तार भी मई 2012 में हुआ)

सदस्यों की आई.एम.एफ. के अनुच्छेद-4 जैसी निगरानी करने के लिए 30 जनवरी 2012 को आसियान+3 मैक्रो इकॉनमिक रिसर्च ऑफ़िस शुरू किया गया। यह खुद को चियांग माई इनीशिएटिव मल्टीलेटराइज़ेशन की क्षेत्रीय निगरानी शाखा कहता है। इसके उद्देश्यों में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की निगरानी करना, उनका विश्लेषण करना तथा किसी भी जोखिम को जल्द से जल्द पकड़ कर उपचारात्मक कदम उठाना और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना शामिल है। कुछ पर्यवेक्षकों ने कार्यक्षेत्र के बारे में असहमति और एशियाई क्षेत्र में अपने पड़ोसियों की नीतियों की आलोचना करने से बचने की प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया है, जो कड़क निगरानी के रास्ते में रुकावट है।

वैश्विक वित्तीय संकट के पहले इस इलाके में विश्व बैंक से ज़्यादा एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ऋण वितरण कर रहा था। संकट ने इस ट्रेंड को बढ़ाया। ए.डी.बी. ने कुछ मामलों में आई.एम.एफ. और विश्व बैंक के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा बड़े लोन दिए और विकासशील तथा कम आय वाले देशों की मदद के लिए नए प्रकार के अस्थायी तीव्र वित्त-पोषण कार्यक्रम और प्रतिचक्रीय ऋण सुविधाएँ (countercyclical support facility) शुरू कीं। अप्रैल 2009 में इण्डोनेशिया ने पेशकश की कि आई.एम.एफ. के नए ऋण का एक हिस्सा ए.डी.बी. को हस्तांतरित कर दिया जाए। 20 देशों के समूह (जी-20) के समर्थन से ए.डी.बी. ने संकट से प्रभावित एशिया की अर्थ व्यवस्थाओं को 3 बिलियन डॉलर तक की प्रतिचक्रीय सहायता सुविधा देनी शुरू कीं।

सन् 2008 और 2009 के बीच ए.डी.बी. की ऋण वचनबद्धता 42% बढ़ गई और उसका संवितरण (disbursement) 33% बढ़ा। दूसरे क्षेत्रीय विकास बैंकों ने फ़ौरन ए.डी.बी. के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और उन्हें आई.एम.एफ. की उस नई राशि के अंश स्वीकृत हो गए जो उनके क्षेत्र में तीव्र प्रतिचक्रीय सहायता के लिए नई क्षेत्रीय ऋण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए निर्धारित की गई थी।

स्रोतः वुड्स 2010; चिन 2010, 2012; ओकैपो तथा अन्य 2010; ए.डी.बी. 2009; सिऑसियारी 2011; ए.एम.आर.ओ. 2012

(MFN) के दायित्वों से छेड़-छाड़ किए बग़ैर एक-दूसरे को छूट दे सकते हैं।

जब बहुपक्षीय वार्ताओं में गतिरोध पैदा हो जाए, तब द्विपक्षीय व्यवस्थाएँ व्यापार को सुचारु बना सकती हैं। भेद-भाव रहित, मुक्त व्यापार के दूसरे विकल्पों में अधिमान्य व्यापार व्यवस्थाएँ (preferential trade arrangements) शामिल हैं, जिनका पर्यवेक्षण विश्व व्यापार संगठन या क्षेत्रीय संगठन जैसी कोई वैश्विक बहुपक्षीय संस्था कर सकती है।

उदाहरण के लिए, विकसित देशों द्वारा कृषि उत्पादों और उनके निर्यात पर दी जाने वाली जबर्दस्त सब्सिडी पर होने वाली वार्ता को लें। ये सब्सिडी विश्व व्यापार को बिगाड़ती हैं और विकासशील देशों के किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर देती हैं। फिर भी, इस मसले को किसी द्विपक्षीय या क्षेत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत सुलझाना लगभग असम्भव है। इसके लिए बहुपक्षीय विमर्शों की ज़रूरत होगी, जो सिर्फ़ विश्व व्यापार संगठन में ही सम्भव है। अधिकतर देश यह स्वीकार करते हैं कि विश्व व्यापार के नियमों के पंच के रूप में एक मज़बूत बहुपक्षीय निकाय ज़रूरी है, यह जानते हुए कि क्षेत्रीयता कायम रहेगी आगे बढ़ने का एक तरीका है कि धीरे-धीरे क्षेत्रीयता को बहुपक्षीय बनाया जाए।[38]

उत्तरदायी सम्प्रभुता

जहाँ अधिकतर सरकारें बहुपक्षीयता के सिद्धांत का समर्थन करती हैं, वे स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय सम्प्रभुता के संरक्षण को लेकर संवेदनशील भी हैं। फिर भी राष्ट्रीय सम्प्रभुता को लेकर कठोर रुख से सीमा-पार प्रतिद्वंद्विता और सबके लिए नुकसानदेह विचारों को बढ़ावा मिलेगा। देश केवल अपनी सामर्थ्य से वित्तीय संकटों और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों से पार नहीं पा सकेंगे, और सिर्फ़ राष्ट्रीय प्रयासों से नागरिकों को वैश्विक सार्वजनिक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं

बॉक्स 5.4 *एनरिक गार्सिया, अध्यक्ष, सी.ए.एफ.*

सी.ए.एफ़ः लैटिन अमेरिका का एक विकास बैंक

सन् 1970 में अपनी स्थापना के समय बहुपक्षीय बैंक सी.ए.एफ. के पाँच एंडियन देश सदस्य थे (बोलीविया, कोलम्बिया, इक्वेडोर, पेरू और वेनेज़ुएला)। आज इसमें लैटिन अमेरिका, कैरीबियाई और यूरोप के 18 शेयरहोल्डर देश और 14 प्राइवेट बैंक शामिल हैं और यह अपनी ज्यादातर फंडिंग वैश्विक वित्त बाज़ार से करता है। सी.ए.एफ. लैटिन अमेरिका में ऋण प्रचालन, ग्रांट, तकनीकी सहायता के मार्फ़त संवहनीय विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है और पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर की परियोजनाओं की वित्तीय संरचना में मदद करता है। इसका मुख्यालय कैराकास में है और इसके दफ्तर एसंसियन, बोगोटा, ब्राज़ीलिया, ब्यूनस आयर्स, ला पाज़, लीमा, मैड्रिड, मोंतेवीदियो, क्विटो और पनामा सिटी में हैं। पिछले एक दशक में लैटिन अमेरिका ने बेहतर बाह्य माहौल के कारण तेजी से आर्थिक प्रगति की है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता सामग्री की कीमतें बढ़ीं, एक स्थिर समष्टि अर्थशीस्त्रीय माहौल बना, ग़रीबी कम होने और आय बढ़ने के कारण घरेलू माँग बढ़ी। सी.ए.एफ. ने एक समेकित विकास एजेंडा के माध्यम से, अपने सदस्य देशों की इन बेहतर आर्थिक स्थितियों का लाभ उठाने में मदद की है। इसमे क्षेत्रीय उत्पादक रूपांतरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने का काम किया गया ताकि संस्थाओं की गुणवत्ता सुधरे और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। सी.ए.एफ. ने ऐसे मौकों पर महत्वपूर्ण वित्त पोषण किया है, जब वित्तीय बाज़ार 'सूखे' थे और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ कर्ज़ देने पर कड़ी शर्तें लगा रहीं थीं।

इस इलाके में सी.ए.एफ. की सफलता के कुछ कारण इसके लैटिन-अमेरिकी होने, इसके सदस्य देशों की सशक्त राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धता, विवेक सम्मत वित्तीय नीतियों का निर्वहन, खास तौर से आर्थिक दबाव के मौके पर, और इसकी ग़ैर-शर्तबद्धता हैं। सन् 2011 में 10 अरब डॉलर से ज्यादा की स्वीकृतियों के साथ, जो लैटिन अमेरिका को स्वीकृत सकल बहुपक्षीय ऋणों का लगभग 30% है, आज सी.ए.एफ. इस क्षेत्र में अधोसंरचना और ऊर्जा के क्षेत्र में बहुपक्षीय वित्त पोषण के सबसे प्रमुख स्रोतों में एक है। (अंतर-अमेरिकी विकास बैंक के 12.4 अरब डॉलर और विश्व बैंक के 13.9 अरब डॉलर से तुलना करते हुए; देखें ओकैंपो और टाइटलमैन 2012)। खासतौर से मूल्यवान रही अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में आर्थिक अशांति के दौरान सी.ए.एफ. की प्रतिचक्रीय भूमिका(countercyclical role), और शेयरधारकों को मिला इसका समर्थन, जब कर्ज़ दुष्प्राप्य हो गया था। लैटिन अमेरिका के विकास के सामने खड़ी कुछ बाधाओं को पार करने के वास्ते, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से इस इलाके की ओर, खासतौर से अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए, पूँजी लाने के अलावा, सी.ए.एफ. ने सदस्य देशों के साथ मिलकर, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार किया है, जो अनुदानों के सहयोग से चलेगा।

एक निधीकरण रणनीति (funding strategy) के तहत सी.ए.एफ अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाज़ार में अपने वित्तीय स्रोतों को बढ़ाता रहता है, जिसका लक्ष्य ब्याज की दर और करेंसी जोखिमों को कम करना और साथ ही साथ, अपनी परिसम्पत्तियों और देनदारियों की वार्षिक परिपक्वता को उससे इस प्रकार मेल बनाकर रखना है, जिससे इसकी निधि में पर्याप्त नकदी बनी रहे। सी.ए.एफ. ने अपनी पहली क्रेडिट रेटिंग तीन मुख्य रेटिंग एजेंसियों से 1993 में प्राप्त की। तबसे इसकी रेटिंग बढ़ती गई है, खासतौर से इस क्षेत्र में वित्तीय संकट के दौरान भी। सी.ए.एफ. अब लैटिन अमेरिका में बार-बार बॉण्ड ज़ारी करने वाला सबसे उत्कृष्ट मूल्यांकन वाला संगठन है। सन् 1993 से सी.ए.एफ. ने एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाज़ारों से 87 बॉण्ड निर्गमों के माध्यम से 13.9 अरब डॉलर का उधार इकट्ठा किया है। विवेक सम्मत वित्तीय नीतियों के कारण सी.ए.एफ. एक लाभकारी संस्था बन गई है जो अनुदानों और तकनीकी सहयोग के मार्फ़त, अपने सदस्यों की सहायता के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं में पुनर्निवेश करती है।

बदलते और चुनौती देते माहौल में समयानुकूल बदलाव करने की सामर्थ्य के कारण सी.ए.एफ. का प्रदर्शन विशिष्ट हो गया है। खासतौर से महत्वपूर्ण है इसकी अधिशासन संरचना। इसके गठन के समय से सी.ए.एफ. के शेयरहोल्डरों ने इस संस्था को बग़ैर किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के अपनी संचालन नीतियों को बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता दी। सदस्य देशों ने हमेशा इसका समर्थन किया। सी.ए.एफ. के इतिहास में कोई भी सदस्य देश अपनी अदायगी में नहीं चूका, आर्थिक संकट के दौरान भी नहीं। इसका स्वामित्व लगभग पूरी तरह लैटिन अमेरिकी होने के कारण(स्पेन और पुर्तगाल इस क्षेत्र से अपने ऐतिहासिक रिश्तों के कारण अल्पसंयक शेयरहोल्डर हैं) सी.ए.एफ. ने उस प्रकार के टकरावों को टाला है, जो दाता और प्राप्तकर्ताओं के लक्ष्य एक जैसे न होने के कारण अमूमन अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में पैदा हो जाते हैं। इस मामले में सी.ए.एफ. को ऐसे संगठन के रूप में पहचाना जाता है, जो लैटिन अमेरिका द्वारा अपने लिए चलाया जाता है और जो व्यावहारिक वित्तीय एकीकरण का उपयोगी उदाहरण है।

होगी। कुछ सरकारें अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की पर्याप्त रक्षा करने में भी असमर्थ हैं। उत्तरदायी सम्प्रभुता एक बेहतर रणनीति होगी– इसके मायने हैं राष्ट्रीय नीतियाँ बनाते समय दीर्घकालीन दृष्टि से पूरी दुनिया के हितों को ध्यान में रखा जाए।

ज़्यादातर सार्वजनिक साधन सीमा-पार परिणामों के प्रभावी प्रबंधन और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय साधनों की पर्याप्त व्यवस्था पर, और इस प्रकार राष्ट्रीय संस्थागत क्षमता और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग की इच्छा पर, निर्भर करते हैं। देशों को सार्वजनिक साधनों की व्यवस्था करने में अपनी अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखना चाहिए और सामूहिक कल्याण तथा दूसरे देशों के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि प्रदूषण और ऐसा ही कोई और दुष्कृत्य। उत्तरदायी सम्प्रभुता में व्यापार उदारीकरण या जलवायु परिवर्तन की समस्या का शमन जैसे सामूहिक प्रयास शामिल हैं। प्रभावी तरीके से इनकी योजना बनाई जाए तो वे वैश्विक सामूहिक कल्याण को बढ़ाने वाले होंगे।

आपस में गहराई से जुड़ी दुनिया में, प्रभावशाली राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया, क्षेत्रीय और वैश्विक नीतियों से विमुख होकर एकाकी तरीके से पूरी नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय नीतियों के क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम होते हैं। मसलन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गिरावट की प्रतिक्रिया में राष्ट्रीय संरक्षणवाद, या अंधाधुंध मछली पकड़ने और सागर प्रदूषण को नियंत्रित न कर पाना। साथ ही साथ क्षेत्रीय और वैश्विक नीतियाँ राष्ट्रीय नीति-निर्माण के लिए संदर्भ का काम भी करती हैं। देशों और क्षेत्रीय तथा बहुदेशीय संगठनों को एक-दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्रीय नीतियों को समान अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ना चाहिए। तेज़ी से सार्वभौमिक होती और अन्तर्सम्पृक्त दुनिया में यह सर्व-कल्याणकारी स्व-हित है। आज राष्ट्रीय स्तर पर किए गए फैसले आने वाली पीढ़ी में सभी देशों को प्रभावित करेंगे।

उत्तरदायी सम्प्रभुता के माने हैं राष्ट्रीय नीतियाँ बनाते समय दीर्घकालीन दृष्टि से पूरी दुनिया के हितों को ध्यान में रखा जाए

यदि राष्ट्रीय नेता संकीर्ण नज़रिए से अपने अल्पकालिक राष्ट्रीय हितों के आगे नहीं देख पाएँगे, तो सहकारिता से सम्भव लाभ पीछे रह जाएँगे और निष्क्रियता के नुकसान की कीमत बढ़ती जाएगी। राष्ट्रीय नीतियाँ एक-दूसरे की पूरक बनने के बजाय एक-दूसरे को कमज़ोर करेंगी। इसके उदाहरणों में शामिल हैं वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सार्वजनिक व्यय और उत्प्रेरक नीतियाँ। विश्वभर के केन्द्रीय बैंकों के समन्वय से ब्याज दरों में कमी के कारण विश्व-व्यापी मंदी को गहरा होने से रोका जा सका।

अपने बढ़ते आर्थिक रसूख़ और राजनीतिक प्रभाव के कारण वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में दक्षिण एक महत्वपूर्ण भागीदार होता जा रहा है। दक्षिण के उदय और उसके साथ सीमा-पार सम्पर्कों में मज़बूती के कारण, निर्णय प्रक्रिया पहले से ज़्यादा परस्परावलम्बी हो गई है। आज की अनेक वैश्विक समस्याओं पर सार्थक प्रगति के लिए उत्तर और दक्षिण को सहमतियों के आधार तैयार करने चाहिए।

उत्तरदायी सम्प्रभुता की दरकार यह भी है कि राज्य अपने यहाँ रहने वालों के स्वीकृत मानवाधिकारों का सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए संरक्षा के दायित्व की पहल (responsibility to protect initiative) नए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार आदर्शों को विकसित करने की कोशिश है, जो जनसंहार, युद्ध अपराध, जातीय संहार और मानवता विरोधी अपराधों को रोक पाने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विफलता को सम्बोधित करती है। इस दृष्टि से सम्प्रभुता केवल अधिकार ही नहीं, एक ज़िम्मेदारी भी है।

जहाँ यह मानवीय सुरक्षा के वैश्विक अधिशासन के निर्देशक सिद्धांतों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, वहीं इस पहल में उस प्रक्रिया का अभाव है, जिसके तहत इन सिद्धांतों को लागू किया जाए।[39] उल्लंघनों और अत्याचारों की ऐसी तय सीमा रेखाएँ नहीं हैं, जिन्हें पार करते ही अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप स्वतः हो जाए। सिद्धांत और प्रक्रिया के बीच का यह बेमेल इस बात को रेखांकित करता है कि अंतरराष्ट्रीय अधिशासन व्यवस्था में वह क्षमता पैदा की जाए जो सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं को उन नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाए, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यों को अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए बाध्यकारी क्रिया-विधि तैयार किए बग़ैर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं की वैधता पर सवाल उठेगा। यदि वैश्विक निष्पक्षता और न्याय की पूर्व-शर्तें पूरी हो जाती हैं तो ज़िम्मेदार और पारस्परिक सहयोगकारी सम्प्रभुता के सिद्धांत पर समझौता हो सकता है।

नई संस्थाएँ, नई कार्यविधियाँ

दक्षिण के उदय ने, वैश्विक और क्षेत्रीय, दोनों स्तरों पर विकास साझेदारियों और विकास नीतियों की पद्धति के बाबत नवाचारी नई संरचनाओं की सम्भावनाओं के रास्ते खोले हैं। मसलन, दक्षिण की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बड़े विदेशी मुद्रा भंडारों का लाभ कम विकसित देशों के विकास-वित्तीयन में किया जा सकता है। विकासशील देशों के दायरे के भीतर सहायता, व्यापार और तकनीकी आदान-प्रदान की नई प्रक्रिया विद्यमान व्यवस्था के समांतर और पूरक रूप में काम कर सकती है। दक्षिण के देश, अत्यावश्यक अंतरराष्ट्रीय ज़रूरतों और 21 वीं सदी की इन चुनौतियों से निपटने के सबसे प्रभावशाली तरीकों से सम्बद्ध वैश्विक नीति-विमर्श में, ज़्यादा बड़ी नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभा सकते हैं।

अधोसंरचना विकास बैंक

दक्षिण का उदय समतापूर्ण और संवहनीय मानव विकास के लिए वित्त पोषण की नई सम्भावनाओं को भी तैयार कर रहा है। उदाहरण के लिए, ब्राज़ील, चीन, भारत, रूसी संघ और दक्षिण अफ्रीका ने, ब्रिक्स विकास बैंक बनाने की पेशकश की है, जो अपने बड़े मुद्राकोष का इस्तेमाल, विकासशील देशों की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए करेगा।[40] यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट के तर्ज़ पर, ऐसा बैंक, ऋण, इक्विटी, और गारंटी जैसी कई प्रकार की सेवाएँ दे सकता है। उत्पादक परियोजनाओं के वित्तीयन के अलावा, संसाधनों का यह प्रवाह, वैश्विक वित्तीय संतुलन में भी सहायता करेगा।

ऐसे रिज़र्व का एक महत्वपूर्ण उपयोग, आधारभूत संरचनाएँ तैयार करने में भी हो सकता है। तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, विकासशील देशों में अधोसंरचना संबंधित व्यय सन् 2020 तक वर्तमान स्तर 0.8-0.9 ट्रिलियन डॉलर या स.घ.उ. के 3% की तुलना में 1.8-2.3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष या स.घ.उ.का 6%-8% होना चाहिए।[41] इस प्रकार के निवेश को आसान बनाने का काम अधोसंरचना तथा संवहनीय विकास-बैंक के मार्फ़त हो सकता है। इससे विकासशील देशों को आर्थिक रूप से उत्पादक अधोसंरचना बनाने के लिए ऋण जुटाने में मदद मिलेगी।

चूँकि आदाताओं को ऋण संवहनीयता की फ़िक्र भी होगी, इसलिए घरेलू सरकारी आहरण से आगे जाकर अन्य प्रकार की वित्तीय सहायताओं के बारे में प्रयासों की ज़रूरत है। एक नई संस्था, गारंटी और दूसरे वित्तीय उपकरणों के मार्फ़त सही पूँजी को सहबद्ध (crowd in) करेगी।[42] विद्यमान क्षेत्रीय तथा वैश्विक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते और वित्त व निवेश के अंतरालों को भरते हुए, नई संस्थाएँ और ज़्यादा प्रभावकारी होंगी।

अध्याय-4 में एक तीव्र गति परिदृश्य प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सन् 2050 तक अलग-अलग तरह के सार्वजनिक व्यय के मार्फ़त सभी क्षेत्रों में मानव विकास सूचकांक सुधारने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इस परिदृश्य में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक अधोसंरचना में 20% सुधार होगा, 2030 तक बिजली की सार्वभौमिक उपलब्धता होगी, घरों में गर्म करने और खाना बनाने में ठोस ईंधन का इस्तेमाल 2030 तक खत्म हो जाएगा, सन् 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन अपनी संदर्भ रेखा से 50% ऊपर होगा और मोबाइल टेलीफ़ोन और ब्रॉडबैंड 2030 तक सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध होगा।

इस परिदृश्य में मानव विकास सूचकांक में सबसे बड़ा अनुमानित सुधार सब-सहारा अफ्रीका में(65%) और दक्षिण एशिया में(47%; रेखांकन 5.1) होगा। सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में मौजूदा औसतन सार्वजनिक निवेश स.घ.ऊ. का 7.7% है।[43]

जी-20 के नौ देशों के पास उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का एक छोटा अंश आवंटित कर देने से सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया के अधोसंरचना के लिए सार्वजनिक निवेश में महत्वपूर्ण अतिरिक्त साधन जुड़ जाएँगे(रेखांकन 5.2)। हालाँकि यह कोष के आवंटन अंश पर निर्भर करेगा, पर इससे सार्वजनिक निवेश 17.6%-52.8% तक बढ़ सकता है। वस्तुतः दक्षिण से जी-20 के नौ सदस्य देशों के कोष में से केवल 3% का आवंटन इन देशों में स.घ.उ. के 4.1% से 11.7% तक सार्वजनिक निवेश को बढ़ा देगा, जो सभी विकासशील देशों के औसत सार्वजनिक स्तर के करीब होगा।[44]

मुद्रा-कोष वाले देशों और उनकी सम्प्रभु निधियों (sovereign wealth funds), के लिए विकासशील देशों में निवेश करना वित्तीय रूप से आकर्षक होगा, इससे उन्हें कोई अतिरिक्त जोखिम उठाए बग़ैर अच्छा लाभ और मुद्रा कोष को बढ़ाने का मौका भी मिलेगा।[45] सम्प्रभु निधियों का लंबा निवेश क्षितिज है और भुगतान वापसी (redemption) का जोखिम कम है, जो उन्हें दीर्घकालीन निवेश में समर्थ बनाता है। चूँकि कई फंड निजी लाभ के मुकाबले सामाजिक लाभ को वरीयता देते हैं, वे सामाजिक रूप से ज़िम्मेदारी को महसूस भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नॉर्वे ने वैश्विक संवहनीयता को नोर्गेस बैंक इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट के मार्फ़त अपनी सम्प्रभु निधि के निवेश का आधार बनाया है, और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉपैक्ट नॉर्म्स के तहत गयाना, इण्डोनेशिया और तंज़ानिया में वनोन्मूलन रोकने की पहल से खुद को जोड़ा है।[46] अधिशासन के सामने चुनौती सामाजिक दायित्वों से जुड़े निवेशों के क्रियान्वयन, उपयुक्त मानक परिभाषित करने और सम्प्रभु निधियों के उन जगहों पर आसान निवेश की है, जहाँ मानव विकास पर सबसे गहरा प्रभाव हो।[47]

दक्षिण की संस्थाओं यानी ब्रिक्स बैंक से चियांग माई इनीशिएटिव मल्टीलेटराइज़ेशन और अफ्रीकी यूनियन तक में, अंतरराष्ट्रीय अधिशासन को प्रभावित करने की प्रबल सम्भावनाएँ हैं। सामूहिक पहल के लिए साझा नज़रिए की ज़रूरत होती है। इस नज़रिए के पीछे की सहमति को मानकर नहीं चला जा सकता। क्षेत्रीय तथा अन्य व्यवस्थाओं का प्रसार बताता है कि सरकारें सामूहिक विकास के फ़ायदों को पहचानती हैं और उनसे प्रतिबद्ध हैं।

दक्षिण के उदय ने, वैश्विक और क्षेत्रीय, दोनों स्तरों पर विकास भागीदारियों और विकास नीतियों की पद्धति के बाबत नवाचारी नई संरचनाओं की सम्भावनाओं के रास्ते खोले हैं

एक नया दक्षिण आयोग?

सन् 1987 में गुट-निरपेक्ष देशों के नेताओं ने आपसी सहयोग के क्षेत्रों और नीतियों की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए, दक्षिण आयोग बनाया था। तंज़ानिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जूलियस न्यरेरे और अर्थशास्त्री तथा भारत के भावी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सन् 1990 में तैयार की गई इसकी रिपोर्ट *द चैलेंज टु द साउथ* एक प्रभावशाली और दूरदर्शी विश्लेषण

रेखांकन 5.1

त्वरित प्रगति परिदृश्य के तहत मानव विकास सूचकांक में सबसे बड़ा अनुमानित सुधार सब-सहारा अफ़्रीका और दक्षिण एशिया में होगा

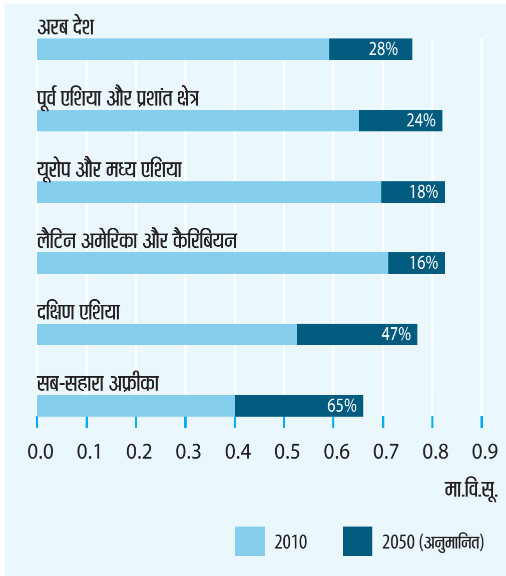

नोटः त्वरित प्रगति परिदृश्य पर विमर्श के लिए देखें अध्याय 4
स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणना पार्डी सेंटर फ़ॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स 2013 पर आधारित.

रेखांकन 5.2

जी-20 के नौ देशों के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक छोटे से अंश मात्र से सब-सहारा अफ़्रीका और दक्षिण एशिया की अधोसंरचना के लिए काफ़ी मात्रा में अतिरिक्त सार्वजनिक संसाधनों की व्यवस्था हो सकेगी

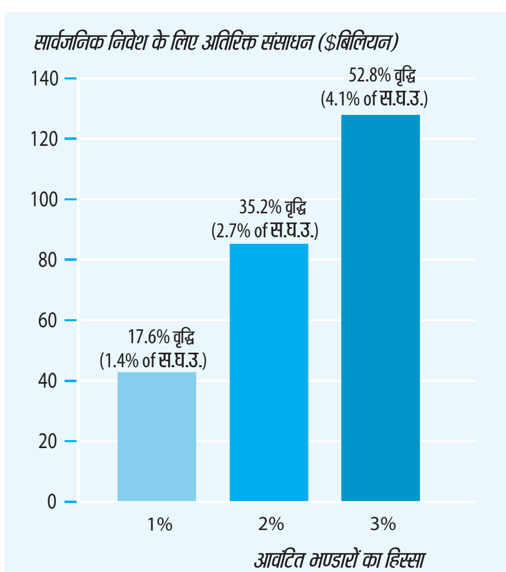

नोटः कोष्ठक में दिए गए अंक स.घ.उ. के अंश के रूप में सार्वजनिक निवेश में हुई बढ़त बताते हैं।
स्रोतः एचडीआरओ गणना विश्व बैंक पर आधारित(2012a)

था।[48] इसने जलवायु परिवर्तन को प्राथमिकता के रूप में चिह्नित किया और ग़रीबी, सामाजिक अपवर्जन और अमीरी और ग़रीबी के बीच बढ़ती खाई जैसी चुनौतियों को रेखांकित किया जो आज भी क़ायम हैं।[49] इतना ही नहीं अनुदान, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय नीति-निर्माण के अन्य पक्षों को लेकर उन दिनों उभरती दक्षिण-दक्षिण सहयोग की सम्भावनाओं पर भी दक्षिण आयोग ने बारीकी से ग़ौर किया था।

पिछले दो दशक में दुनिया और दक्षिण, दोनों का व्यापक रूपांतरण हुआ है। इक्कीसवीं सदी के दक्षिण का नेतृत्व तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ कर रही हैं, जिनके पास खरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और खरबों डॉलर अपनी सीमा के बाहर निवेश के लिए उपलब्ध हैं। दक्षिण के कारोबार अब दुनिया के सबसे बड़े कारोबारों में शामिल हैं। सामूहिक पहल की सम्भावनाएँ इससे बेहतर कभी नहीं थीं, फिर भी इस मामले में सहमति को निर्विवाद नहीं मान लेना चाहिए। दक्षिण-दक्षिण सहयोग की संस्थाएँ जैसे 77 देशों का समूह(जी-77), गुट-निरपेक्ष आंदोलन और दक्षिण शिखर सम्मेलन, वि-उपनिवेशवाद की पृष्ठभूमि में कठिन तपस्या में तपकर निकली हैं, जिसने विकासशील दुनिया के उदीयमान देशों के बीच मज़बूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित की है। वह प्रारम्भिक काल का अनुभव वर्तमान पीढ़ी से दूर छूट गया है, उसके अग्रजों की दक्षिण से जुड़ी प्रतिबद्धता की जगह आज कई मायनों में राष्ट्रीय हितों ने ले ली है।

21वीं सदी के नए यथार्थ की रोशनी में इन मसलों और दक्षिण के देशों के नेतृत्व में बने संगठनों को नए नज़रिए से समझने की ज़रूरत है। एक नया दक्षिण आयोग, जो पहले आयोग की तर्ज़ पर तैयार हो, पर जिसमें आज के दक्षिण की शक्ति और ज़रूरतें परिलक्षित हों, एक नई दृष्टि पैदा कर सकता है। यह स्वीकार करते हुए कि दक्षिण की विविधता कैसे एक नए प्रकार की एकता को जन्म दे सकती है, इस दृष्टि का लक्ष्य आने वाले दशकों में मानव विकास को त्वरित गति देना होगा। दक्षिण के भीतर की आर्थिक संलग्नताएँ और पारस्परिक सहयोग, इस प्रकार के निकाय की स्थापना में मददगार हो सकते हैं।

निष्कर्षः एक नए दौर के साझेदार

दक्षिण के उदय ने एक हद तक दुनिया को विस्मित कर दिया है। इसके पूर्व, अव्यक्त अनुमान यह था कि विकासशील देश धीरे-धीरे औद्योगिक देशों के मानव विकास के समेकित स्तर तक पहुँचेंगे। और यह भी कि औद्योगिक देश हमेशा ताकतवर और नेतृत्वकारी स्थिति में बने रहेंगे। कई मानों में अब भी स्थिति यही हैः दक्षिण के अनेक देशों में औसत मानव विकास सूचकांक काफ़ी नीचा है। पर दुनिया को जिस बात

ने सबसे ज़्यादा विस्मय दिया, वह यह है कि मानव विकास के निम्न स्तर पर होने के बावजूद वैश्विक मंच पर, अपने वित्तीय साधनों और राजनीतिक प्रभाव के कारण अंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया पर असर डालने के कारण, दक्षिण के देश वज़नी साबित हो रहे हैं।

यह बात 21वीं सदी के शुरूआती वर्षों में ज़ाहिर हो गई थी, जब चीन और दूसरी उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं ने काफ़ी बड़ा मुद्रा कोष अमेरिका के सरकारी बॉण्ड की शक्ल में जमा कर लिया था, जिससे अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़ी। पर स्थिति और साफ़ तब हुई, जब 2008 के बैंकिंग संकट और उसके बाद के आर्थिक झटकों ने कुछ अमीर देशों को मंदी के दौर में फँसा दिया और विश्व की एक महत्वपूर्ण मुद्रा के सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया। अब उत्तर के देश वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए दक्षिण की ओर देख रहे हैं।

व्यवहार में, देशों के हरेक समूह को पहले के मुकाबले अब दूसरों की ज़रूरत ज़्यादा है। उत्तर को सामग्री और सेवाओं के निर्यात के लिए दक्षिण के सर्वाधिक जीवंत देशों की आवश्यकता है, खासतौर से इसलिए कि खर्चों पर जबर्दस्त रोक के कारण उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में समाज व अर्थव्यवस्थाएँ कमज़ोर हो गई हैं। दक्षिण को उत्तर की ज़रूरत केवल परिपक्व बाज़ार के रूप में ही नहीं है, बल्कि एक नवाचारी और जटिल तकनीक के स्रोत के रूप में भी है।

दक्षिण के उदय ने प्रदर्शित किया है कि दुनिया अब पहले से ज़्यादा फैली हुई और आपस में जुड़ी है। इसका एक परिणाम यह है कि प्रेरणा के लिए उत्तर की ओर देखने के बजाय, विकासशील देश अपने विकास के लिए उपयुक्त मॉडल दक्षिण के अपने ही समूह में तलाशने लगे हैं। यहाँ वे, निर्जीव वैचारिक विकल्पों के बजाय, यह समझने की स्थिति में हैं कि क्या बात किस परिस्थिति के लिए उपयुक्त है, और वे सबसे उपयुक्त साधन चुनते हैं। अध्याय-3 में उन कार्यक्रमों और नीतियों के उदाहरण दिए गए, जो दक्षिण की उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में मानव विकास में सुधार करने में कामयाब हुए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश से लेकर सशर्त नकदी अन्तरण तक। ऐसे उदाहरण दूसरे देशों में ऐसी ही नीतियाँ लागू करने की प्रेरणा देते हैं, केवल राष्ट्र की विशिष्ट स्थितियों, संस्थाओं और ज़रूरतों को समझ कर लागू करने की ज़रूरत है।

इस रिपोर्ट में विकास के कुछ सबसे प्रभावशाली प्रचालकों (drivers) का सारांश दिया गया हैः एक प्रसक्रिय विकासपरक राज्य, वैश्विक बाज़ार के दोहन की क्षमता पाना, और सामाजिक समावेशन तथा व्यापक आधार पर मानव विकास को प्रोत्साहन। इनमें से प्रत्येक के अनेकानेक विकल्प हैं, पर कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं हैं। जो एक देश में चला, वह दूसरी जगह भी सफल हो, यह ज़रूरी नहीं।

फिर भी, सबसे सफल देशों ने साबित किया कि नवाचारी और कई बार प्रति-अंतर्प्रज्ञात्मक (counter intuitive) विकल्प काम कर जाते हैं। अभिभावकों को इस बात के लिए धनराशि देना कि वे अपने बच्चों को स्वास्थ्य केन्द्र ले जाएँ, निरर्थक बात लगती है, पर जैसा कि मैक्सिको के उदाहरण से ज़ाहिर है, बच्चों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए यह उपयोगी साबित हुआ; उसके सशर्त नकदी अन्तरण कार्यक्रम ने सारी दुनिया का ध्यान खींचा। इसी तरह केन्या और फ़िलीपीन्स में बैंकिंग के लिए मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल ने, उन लोगों के लिए जबर्दस्त काम किया, जिनके न तो कभी बैंक खाते थे और जिनके घर के पास बैंक नहीं थे।

दक्षिण के देश मानव विकास को नया संवेग देने के लिए अपने खुद के विचारों और ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी, एक जटिल वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक माहौल में, हो सकता है कि यह गतिशीलता संवहनीय परिणाम नहीं दे पाए। पहले ही बढ़ती असमानता और कुंठित अपेक्षाओं के बढ़ते संकेत हिंसक सामाजिक संघर्षों की ओर ले जा सकते हैं। और इस बात पर गम्भीर चिंताएँ हैं कि वैश्विक साधनों के अंधाधुंध दोहन और जलवायु परिवर्तन के असर से भावी पीढ़ियों को धरती तबाह मिलेगी।

इसीलिए इस रिपोर्ट का ध्यान इस बात पर है कि मानव विकास को किस प्रकार हासिल किया जाए कि वह उत्पादक भी हो और टिकाऊ भी। इसमें वे कदम भी शामिल हैं, जो समता, लोगों की आवाज़ सुनने और सहभागिता बढ़ाने वाले हों तथा पर्यावरणीय दबावों और जनसांख्यिकीय परिवर्तन का सामना कर सकें।

इन मसलों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय सरकारों और नागर समाज की संस्थाओं की प्रतिबद्धता और कौशल की आवश्यकता होगी। जैसा कि इस अध्याय में कहा गया है, आवश्यकता इस बात की भी होगी कि ज़्यादा फलदायी वैश्विक सहयोग की राह पकड़ी जाए, जहाँ राष्ट्रीय सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठन और वैश्विक नागर समाज संस्थाओं के मनोनुकूल पारस्परिक समझ और सहयोग के नए मॉडलों की ज़रूरत होगी। इनमें से कुछ मॉडलों के तहत नए सत्ता-संतुलन को समायोजित करने के लिए विद्यमान संस्थाओं में बदलाव की, और कुछ के तहत नए संस्थागत स्वरूपों का निर्माण होगा।

इन सबके मार्फ़त, मानव विकास का मौलिक सिद्धांत बना रहेगा। हमेशा की तरह, लक्ष्य यह है कि हरेक व्यक्ति की, चाहे वह कहीं का निवासी हो, सामर्थ्य और विकल्पों का दायरा बढ़ाया जाए। दक्षिण के अनेक देशों ने प्रदर्शित किया है कि क्या किया जा सकता है, पर वे इस दिशा में थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाए हैं। आने वाले वर्षों के लिए इस रिपोर्ट में पाँच व्यापक निष्कर्ष प्रस्तावित किए गए हैं।

प्रेरणा के लिए उत्तर की ओर देखने के बजाय, विकासशील देश अपने विकास के लिए उपयुक्त मॉडल दक्षिण के अपने ही समूह में तलाशने लगे हैं

दक्षिण की बढ़ती आर्थिक शक्ति का मानव विकास के साथ पूरी प्रतिबद्धता से मेल होना चाहिए

मानव विकास पर निवेश को केवल नैतिक आधार पर ही उचित नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसलिए भी कि ज़्यादा प्रतियोगी और गतिशील विश्व अर्थव्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में प्रगति सफलता से जुड़ी है। खासकर इन निवेशों के लक्ष्य ग़रीब होने चाहिए– जिन्हें बाज़ारों से जोड़ा जाए और उनकी आजीविका को बेहतर बनाया जाए। ग़रीबी एक अन्याय है, जिसे कटिबद्ध होकर खत्म किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। दुनिया के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, बशर्ते उन्हें इस दिशा में लगाया जाए।

अच्छे नीति-निर्माण के लिए, केवल व्यक्तिगत सामर्थ्य बढ़ाने से ही काम नहीं चलता, इसके लिए सामाजिक क्षमताएँ बढ़ाने पर भी ध्यान होना चाहिए। लोग-बाग सामाजिक संस्थाओं के भीतर रह कर ही काम करते हैं, जो उनकी सम्भावनाओं को बढ़ाती या घटाती हैं। मानवीय क्षमता को सीमित करने वाली परम्पराओं को बदलने की नीतियाँ, जैसे बाल विवाह और दहेज विरोधी कानून, लोगों को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं।

अच्छे नीति-निर्माण के लिए, केवल व्यक्तिगत सामर्थ्य बढ़ाने से ही काम नहीं चलता, इसके लिए सामाजिक क्षमताएँ बढ़ाने पर भी ध्यान होना चाहिए

जैसा कि 2013 की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है, दक्षिण के उदय का एक परिणाम यह हुआ कि ज़्यादातर देशों के पास, ग़रीबी दूर करने, पूर्ण रोज़गार प्रदान करने और निम्न-कार्बन पर्यावरण नवाचार के लिए बड़े लक्ष्य स्थापित करने की नीतियाँ और वित्तीय सामर्थ्य है। अंतरराष्ट्रीय सहायता और संसाधन प्राप्त करने के लिए भारी-भारी शर्तों से लदे कर्ज़ों से काफ़ी देश मुक्त हो रहे हैं, हाल में वस्तुओं की कीमत में बढ़ोत्तरी के कारण प्राथमिक सामग्री तैयार करने वाले अनेक उत्पादक व्यापार में पहले जिस गिरावट का सामना कर रहे थे, उससे वे उबर रहे हैं।[50] इसके कारण उनके पास कुछ संसाधन एकत्र हो गए हैं, जिनका इस्तेमाल संसाधनहीनता के श्राप (resource curse) से बचने वाली सरकारें राष्ट्रीय मानव विकास को सुधारने में कर सकती हैं।

अध्याय-4 में प्रस्तुत परिदृश्य इस बिन्दु को मज़बूत करते हैं। वे दर्शाते हैं कि मानव विकास के प्रति कटिबद्धता और समझदार समष्टि-आर्थिक नीतियों के सहारे, सब-सहारा अफ्रीका में, जहाँ संदर्भ रेखा के परिदृश्य के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर आर्थिक विकास-दर से ज़्यादा होने के कारण ग़रीबों की संख्या बढ़ेगी, वहाँ भी नाटकीय तरीके से ग़रीबी कम करने की सम्भावना है।

कम विकसित देश दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं की सफलता से सीख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं

दक्षिण (6.8 ट्रिलियन डॉलर) और उत्तर (3.3 ट्रिलियन डॉलर) में सम्प्रभु निधियों और मुद्राकोष के अप्रत्याशित संचयन से व्यापक स्तर की त्वरित-प्रगति का मौका तैयार हुआ है। मानव विकास और ग़रीबी निवारण में लगी इन निधियों का छोटा सा अंश भी बड़ा योगदान कर सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, दक्षिण की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की 3% राशि के सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सार्वजनिक निवेश से स.घ.उ. में 11.7% की वृद्धि की जा सकती है।

इसके साथ ही साथ, दक्षिण-दक्षिण व्यापार और निवेश प्रवाह से विदेशी बाज़ारों की प्रभावोत्पादकता में नए किस्म का सुधार हो सकता है, जैसे वस्तुओं, सेवाओं में मूल्यवर्धन के लिए भागीदारी, जो विचारों और तकनीकों के विस्तार को आसान कर सकती है। दक्षिण-दक्षिण का बढ़ता हुआ व्यापार और खासतौर से निवेश उत्पादन, क्षमताओं को कम विकसित क्षेत्रों और देशों में ले जाने का आधार तैयार कर सकता है। हाल में अफ्रीका में भारतीय और चीनी संयुक्त उद्यमों और उत्पादन केन्द्रों को शुरू करने पर हुआ निवेश ऐसी ही भावी सम्भावनाओं की प्रस्तावना है। इस सम्भावना का पूरी तरह लाभ लेने के लिए नई और नवाचारी संस्थाओं की ज़रूरत होगी। अंतरराष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क इन देशों को, एक छलांग में अत्याधुनिक उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का मौका उपलब्ध कराते हैं और साथ ही विदेशी मुद्रा की कीमतों में उतार-चढ़ाव की परेशानी से बचाकर विकास प्रक्रिया में तेज़ी लाते हैं।

दक्षिण-दक्षिण विकास सहयोग और तकनीकी अंतरण के कारण भी मानव विकास की प्रचुर सम्भावनाएँ पैदा होती हैं। उत्तर से टेक्नॉलजी लेकर उसे अपने संदर्भ में ढालना महँगा होता है, जबकि दक्षिण के भीतर ही टेक्नोलॉजी के अंतरण में लगभग समान स्थानीय स्थितियों और ज़्यादा उपयुक्त तकनीक तथा उत्पादों के कारण इन्हें ज़रूरत के हिसाब से ढालने की आवश्यकता कम होती है। विकासशील देशों में बढ़ते बाज़ार ने दक्षिण की कंपनियों को नवाचार और किफायती उत्पादों, जैसे खाद्य सामग्री, परिधान, उपकरण और मोटर गाड़ियों के लिए व्यापक बाज़ार उपलब्ध कराए। महत्वपूर्ण यह है कि चीन और भारत के नेतृत्व में वैश्विक प्रतियोगिता शुरू होने के कारण पूँजीगत माल की कीमतों में भारी गिरावट आने से अनेक विकासशील देशों में विनिर्माण क्षमता तैयार करने के काम में तेज़ी आ सकती है। ऐसा उत्पादन स्थानीय उपभोक्ताओं की आय और पसंद के अनुकूल

बनाया जा सकता है। इस व्यवस्था में उपभोक्ता सामग्री तक ग़रीबों की पहुँच बढ़ सकती है, जबकि नवाचारी रोज़गार तैयार करके उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

नई संस्थाएँ और नई साझेदारियाँ क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण-दक्षिण सम्बन्धों को सुगम बना सकती हैं

नई संस्थाएँ और साझेदारियाँ देशों को ज्ञान, अनुभव और टेक्नोलॉजी को साझा करने में मदद कर सकती हैं।

वित्त और सहायता के क्षेत्र में, सक्रियता के साथ, दक्षिण क्षेत्रीय अधिशासन संस्थाएँ स्थापित कर रहा है। आई.एम.एफ. के क्षेत्रीय विकल्पों, जैसे चियांग माई इनीशिएटिव मल्टीलेटराइज़ेशन और लैटिन अमेरिकन रिज़र्व फंड ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संरक्षण के लिए नीतिगत स्वतंत्रता दी है, साथ ही भुगतान संतुलन और अल्पावधि में नकदी सम्बन्धित मसलों का समाधान किया है।

मज़बूत क्षेत्रीय संस्थाओं के लिए बुनियाद तैयार है, पर इन सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। चूँकि अमीर देशों ने राष्ट्रीय मसलों के लिए सहायता कम कर दी है, विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था क्षेत्रीय विकास बैंकों और द्विपक्षीय सहायता के मार्फ़त हो रही है। सहायता के ये नए तौर-तरीके व्यावहारिकता को विचारधारा के मुकाबले ज़्यादा तरज़ीह दे रहे हैं। उदाहरण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, विकास वित्त पोषण की नई सम्भावनाएँ पेश कर रहे हैं। ब्राज़ील, चीन, भारत, रूसी संघ और दक्षिण अफ्रीका ने अपने बड़े मुद्राकोष को विकासशील देशों की परियोजनाओं में लगाने के लिए एक विकास बैंक बनाने की पेशकश की है। अधोसंरचना बनाना ऐसे मुद्राकोष का महत्वपूर्ण उपयोग होगा।

दूसरे विकासशील देशों के साथ व्यापार का अधिकतर हिस्सा वाणिज्य वस्तुओं और उत्पादों के निर्यात की शक्ल में होता है, और अधिकतर यह कौशल और तकनीक-केन्द्रित होता है। इस दक्षिण-दक्षिण व्यापार और निवेश संलग्नता को आसान बनाने के लिए अब मज़बूत संस्थाओं की आवश्यकता होगी। विस्तारित दक्षिण-दक्षिण व्यापार और निवेश, उत्तर की आर्थिक गिरावट की मार को कम कर सकता है, और विदेशी बाज़ारों का लाभ नए तरीकों से उठाने के अवसर तैयार करता है।

क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के रिश्ते कई प्रकार से मज़बूत किए जा सकते हैं, पारगमन, परिवहन और कस्टम प्रक्रियाओं को सुचारू बनाकर; नियामक स्कीमों को सुसंगत बनाकर; क्षेत्रीय परिवहन अधोसंरचना पर निवेश करके और दक्षिण-दक्षिण व्यापार में तैयार माल पर शुल्क कम करके। यह अनुमान लगाया गया है कि शुल्क को कम करने से दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं को लगभग 59 बिलियन डॉलर का सामूहिक लाभ होगा।[51]

21 वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों के लिए नया दक्षिण आयोग इस बात को नई दृष्टि प्रदान करेगा कि किस प्रकार दक्षिण की शक्ति और विविधता विकास-एकता के लिए एक वैश्विक ताकत बन सकती है। इसके प्रमुख तत्व हैंः विभिन्न निधियाँ विस्तारित आदान-प्रदान का आधार बनती हैं; विविध अनुभव साझा किए जाने के लिए उपलब्ध हैं; नई सीमा-पार साझेदारियाँ विश्व बाज़ारों की प्रतियोगिता में शामिल हो सकती हैं; और इन सबके ऊपर इस बात को स्वीकार और लागू किया जाना कि परस्पर लाभकारी रणनीति नए किस्म के दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्रेरित कर सकती है।

दक्षिण और नागर समाज संस्थाओं को बेहतर प्रतिनिधित्व देने से प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर त्वरित प्रगति होगी

दक्षिण का उदय विश्व मंच पर स्वरों की विविधता को बढ़ावा देगा। यह बात उन अवसरों की ओर इशारा करती है, जिनमें ऐसे क्षेत्रों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली अधिशासी संस्थाओं को बनाने का मौका मिलेगा, जो वैश्विक समस्याओं के समाधान हासिल करने में इस विविधता का रचनात्मक उपयोग करें।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों के ऐसे नए निर्देशक सिद्धांतों की ज़रूरत होगी, जिनमें दक्षिण के अनुभव शामिल हों। जी-20 उनके अनुभवों को शामिल करता है, पर दक्षिण के देशों को ब्रेटन वुड्स संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बेहतर समतापरक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर पर सक्रिय नागर समाज और सामाजिक आंदोलन, निष्पक्ष और न्यायसंगत अधिशासन की स्थापना के लिए आवाज़ उठाने में मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंदोलनों का विस्तार और महत्वपूर्ण संदेशों तथा माँगों को उठाने वाले मंचों की प्रसार-वृद्धि, अधिशासी संस्थाओं को चुनौती देती हैं कि वे लोकतांत्रिक तथा समावेशी सिद्धांतों पर चलें। और सीधे लफ्ज़ों में कहें तो एक उचित और कम असमान दुनिया में स्वरों की बहुलता और सार्वजनिक विमर्श की व्यवस्था की दरकार है।

दक्षिण का उदय सार्वजनिक साधनों की बेहतर उपलब्धता के अवसर तैयार करता है

एक संवहनीय विश्व के लिए बेहतर अधिशासन और प्रचुर वैश्विक सार्वजनिक साधनों की उपलब्धता चाहिए। आज वैश्विक मसलों की संख्या और उनकी

मज़बूत क्षेत्रीय संस्थाओं के लिए बुनियाद तैयार है, पर इन सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है

उत्कृष्टता बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन का शमन और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक-वित्तीय अस्थिरता से लेकर आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ाई तथा नाभिकीय प्रसार तक। उनके लिए वैश्विक हल चाहिए। पर, अनेक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग धीमा और कई बार खतरनाक ढंग से दुविधाभरा है। दक्षिण के उदय ने सार्वजनिक साधनों की बेहतर उपलब्धता और आज ठप पड़े अनेक वैश्विक मसलों को सुलझाने की नई सम्भावनाओं को जन्म दिया है।

आमतौर पर 'सार्वजनिकता' और 'निजता' सार्वजनिक साधनों की अंतर्जात (innate) प्रवृत्ति न होकर एक सामाजिक रचना है। ये नीतिगत विकल्प हैं। जब कमी हो, तब राष्ट्रीय सरकारें उसमें पहल कर सकती हैं, पर जब वैश्विक चुनौतियाँ खड़ी हों, तब अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक, और अनेक सरकारों की स्वैच्छिक क्रियाशीलता से ही सम्भव, होगा। सिर पर खड़ी अनेक चुनौतियों के मद्देनज़र यह तय करने के लिए कि क्या काम सार्वजनिक है और क्या निजी, मज़बूत, प्रतिबद्ध व्यक्तिगत और संस्थागत नेतृत्व की आवश्यकता होगी।

* * *

दक्षिण का उदय मूलतः विकासशील दुनिया के तीव्र रूपांतरण और मानव विकास के विभिन्न पहलुओं पर इसके गहरे असर की कहानी है। इस घटनाचक्र पर अब तक जो वैश्विक विमर्श हुआ है, उसका केन्द्रबिन्दु, लगभग पूरी तरह, बड़े विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि पर रहा है। यह रिपोर्ट मानव विकास के नज़रिए से इसे और व्यापक स्तर पर ले जाकर यह दर्शाती है कि विकासशील देशों की बड़ी संख्या के इससे जुड़े होने और लगातार बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और सम्भावनाओं के गुँथे होने के लिहाज़ से इसके असर बहुत व्यापक हैं– पर्यावरणीय संवहनीयता, ग़रीबी उन्मूलन, समता और वैश्विक संस्थाओं में सुधार। व्यापार, यात्रा और दूर संचार के मार्फ़त व्यापक दुनिया के साथ पारस्परिक संवाद की मदद से ऐसी अपूर्व गति और आकार में बदलाव हो रहा है, जो पहले सम्भव न था।

एक उचित और कम असमान दुनिया में स्वरों की बहुलता और सार्वजनिक विमर्श की व्यवस्था की दरकार है

तेज़ी से विकसित हो रहे देश यों तो अपनी खुद तय की हुई राह पर चलते हैं, फिर भी वे कुछ खास बातों में समान हैं, जैसे सरकारों का प्रभावकारी नेतृत्व, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ खुला सम्पर्क और मानव विकास की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नवाचारी सामाजिक नीतियाँ। इसके अलावा उनके सामने सामाजिक असमानताओं से लेकर पर्यावरणीय जोखिमों तक एक जैसी चुनौतियाँ हैं। और उन्होंने, अपने आंतरिक कारणों से, क्रमशः बढ़ती स्वायत्तता के साथ अपनी घरेलू नीति तय कर ली है, जो शर्तों और थोपे गए बाहरी मॉडलों के दबाव से मुक्त है।

दक्षिण की प्रगति को विकसित देशों के साथ जुड़ने से भी गति मिली है, और विकासशील देशों के साथ वास्तव में आर्थिक आदान-प्रदान परम्परागत उत्तर-दक्षिण आधार के मुकाबले दक्षिण-दक्षिण आधार पर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग संचार के नए माध्यमों के सहारे विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान कर रहे हैं और सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ज़्यादा जवाबदेही की माँग कर रहे हैं। सदियों बाद दक्षिण पहली बार समग्र रूप में वैश्विक आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव का वाहक बना है। दक्षिण को अब भी उत्तर की आवश्यकता है, पर उत्तर को भी दक्षिण की ज़रूरत बढ़ रही है।

शब्दावली

1.	Actor/s	कर्ता
2.	Adjusted	समायोजित
3.	Adjustment	समायोजन
4.	Austerity	मितव्ययिता
5.	Bio-mass	जैव-पदार्थ
6.	Child Survival	बाल जीवितता
7.	Cohesion	संघटन
8.	Cohesive	संघटित
9.	Cohort	समूह / वर्ग
10.	Complementary	सम्पूरक
11.	Composite	मिश्रित / सम्मिश्रित
12.	Demography	जनसांख्यिकी
13.	Deprivations	वंचितताएँ
14.	Deprived	वंचित
15.	Disparity	विषमता
16.	Drivers	प्रचालक
17.	Entitlements	हकदारियाँ
18.	Equitable	समतापूर्ण / समतापरक
19.	Equity	समत
20.	Exclusion	अपवर्जन / बहिष्करण
21.	Financing	वित्तीयन
22.	FDI	प्र.वि.नि.
23.	GDP	स.घ.उ.
24.	Generic	प्रजातिगत
25.	Globalization	वैश्वीकरण/ भू-मंडलीकरण
26.	Governance	अधिशासन/ अभिशासन
27.	Gross Domestic Production	सकल घरेलू उत्पाद
28.	Gross National Income (GNI)	सकल राष्ट्रीय आय (स.रा.आ)
29.	Growth	संवृद्धि/ वृद्धि
30.	HDI	मा.वि.सू.
31.	Inclusion	समावेशन
32.	Inclusive	समावेशी
33.	Index	सूचकांक
34.	Inequality	असमता
35.	Infrastructure	अधोसंरचना/ अधिसंरचना
36.	Innovation	नवाचार
37.	Integration	एकीकरण/ समेकन
38.	Inter-connectedness	अंतर्सम्पृक्तता
39.	Landlocked	भूरुद्ध/थल-रुद्ध
40.	Marginalisation	हाशियाकरण
41.	Migration	प्रवास / पलायन
42.	Multi-lateralisation	बहुपक्षीकरण
43.	Multidimensional Poverty Index	बहुआयामी निर्धनता सूचकांक
44.	MPI	ब.नि.सू.
45.	Parts and Components	अवयव एवं संघटक
46.	Proactive	प्रसक्रिय
47.	Progress	प्रगति
48.	Projection	अनुमान
49.	Public –Private	सार्वजनिक - निजी
50.	Quadrant	चतुष्टक
51.	Quartile	चतुर्थांश
52.	Regionalism	क्षेत्रीयता
53.	Renewable Energy	अक्षय ऊर्जा
54.	Resilience	प्रत्यास्थता / लोच
55.	Sovereignty	सम्प्रभुता
56.	Supplementary	पूरक
57.	Sustainability	संवहनीयता
58.	Sustainable	संवहनीय/ टिकाऊ
59.	Synergy	संगति
60.	Tertiary	उच्च
61.	Transformation	बदलाव/ रूपान्तरण
62.	Vulnerable	अरक्षित/ वेध्य
63.	Weighted	भारित
64.	Withdrawal	आहरण

नोट

विहगावलोकन

1 एट्समॉन और अन्य 2012
2 समाके और यांग 2011
3 जनसांख्यिकी लाभांश को अतिरिक्त आर्थिक संवृद्धि के लिए अवसरों का झरोखा माना गया है जब कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है। जनसांख्यिकी बदलाव में प्रजनन स्तरों के घटने के कारण बच्चों की संख्या घटती है जबकि कार्यशील-आयु की आबादी बढ़ती है। इससे निर्भरता अनुपात घटता है। कोई देश निर्भरों के निम्नतर अनुपात से जुड़ी उच्चतर उत्पादक क्षमता के फायदे उठा सकता है। हालाँकि, प्रजनन दर में गिरावट जारी रहने के साथ अंततः सेवानिवृत्त कामगारों में वृद्धि के साथ निर्भरता अनुपात बढ़ता है।

प्रस्तावना

1 विश्व बैंक (2012a) के अनुसार, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के उच्च-आय वाले सदस्यों की औसत स.घ.उ. वृद्धि दर 2009 में -3.6% थी, इसके मुकाबले पूर्वी एशिया और प्रशांत में 7.5%, दक्षिण एशिया में 7.4%, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 3.6% और सब-सहारा अफ्रीका में 2.1% थी।
2 मैडिसन (2010) के अनुसार, प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (अंतरराष्ट्रीय डॉलरों में) यूनाइटेड किंगडम में 1700 में $1,250 के मुकाबले बढ़कर 1850 में $2,330 हो गया और यूनाटेड स्टेट्स में 1820 में $1,257 से 1870 में $2,445 हो गया।
3 एट्समॉन और अन्य 2012
4 बीते वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में मतदान की हिस्सेदारी और वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियाँ बढ़ने के अलावा दक्षिण ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में नेतृत्वकारी पद हासिल किए हैं।
5 चेन और रावालियन (2012) प्रतिदिन $1.25 की ग़रीबी रेखा का इस्तेमाल करते हुए।
6 उदाहरण के लिए, 1990 में, युगाण्डा का मा.वि.सू. (0.306) बेनिन, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और गैंबिया से तुलनीय था। 2012 तक युगाण्डा का मा.वि.सू. बढ़कर 0.456 हो गया, जो उसके समकक्षों की तुलना में पर्याप्त सुधार दर्शाता है (और 95% के स्तर पर सांख्यिकीय दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है)। बेनिन की बढ़त 0.314 से 0.436, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की 0.312 से 0.352 और ज़ाम्बिया की 0.323 से 0.439 रही।
7 *मानव विकास रिपोर्ट* में क्रय शक्ति समता के अर्थों में मानक स.घ.उ. और स.रा.आ. की गणना की गई है।
8 सात अर्थव्यवस्थाओं के समूह और ब्राज़ील, चीन और भारत के बीच दीर्घावधि ऐतिहासिक तुलना में जापान को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत के करीब तक उसका औद्योगीकरण नहीं हुआ था और 20वीं शताब्दी में आधी सदी के बाद तक वह प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं उभरा था।
9 मौजूदा अमेरिकी डॉलर में।
10 विश्व बैंक (2012a) के अनुसार प्रतिदिन $1.25 से कम में (2005 क्रय शक्ति समता के अर्थों में) गुजारा करने वाली आबादी का अनुपात।
11 अनुमान 2002 और 2011 के बीच के वर्षों से संबंधित।
12 12 प्रयुक्त मापकों– जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष – की ऊपरी सीमाएँ हैं, जिनकी ओर अंततः विकासशील देश अभिमुख होते दिखते हैं। आय की अभिमुखता की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
13 एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट (2012) पर आधारित। मध्य वर्ग में प्रतिदिन $10–$100 आय या व्यय करने वाले लोग शामिल हैं, 2005 क्रय शक्ति समता के अर्थों में।
14 डौब्स और अन्य 2012; अली और दादुश (2012) ने मध्यम वर्ग में शामिल होने के लिए कार के स्वामित्व को प्रतीकात्मक पैमाना मानते हुए बताया कि विकासशील जी-20 देशों में 60 करोड़ तक लोग मध्यम वर्ग में शामिल हैं, जो मिलानोवी और यित्जहाकी (2002) के पिछले अनुमानों के मुकाबले 50% अधिक है, जिन्होंने मध्यम वर्ग से संबंधित होने के लिए क्रय शक्ति समता के अर्थों में प्रतिदिन $10–$50 आय वाले लोगों की गणना की थी।
15 यू.एन.डी.पी. 2009; विश्व बैंक 2010a।
16 अंकटाड 2010।
17 ज़ुकरबर्ग 2012।
18 एस्टेवाडियोर्डल, फ्रैंत्ज़ और टेलर (2003); व्यापार और सघउ का अनुपात वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात और आयात को कुल निर्गत से विभाजित करने पर मिलता है।
19 चालू व्यापार अनुपात 2006 से 2010 तक पाँच वर्षीय औसत है, जिसे विश्व बैंक (2012a) से लिया गया है।
20 हमदानी 2013.
21 हेल्मैन 2008.
22 संयुक्त राष्ट्र 2012a
23 संयुक्त राष्ट्र 2012a
24 खरास, मैकिनो और जंग (2011) के 2005 और 2008 के बीच के आँकड़ों और उसके बाद अनुमानों (extrapolation) पर आधारित।

अध्याय 1

1 यह सामान्य अर्थों में है। क्रय शक्ति समता अर्थों में यह हिस्सा लगभग 46% है।
2 आई.एम.एफ. 2011b
3 इले और लेविस (2011), आई.एम.एफ. (2011b) भी देखें।
4 एचडीआरओ गणनाएं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवेलपमेंट से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पर सामान्य सरकारी खर्च के आँकड़ों पर आधारित। वे दिखाते हैं कि कुछ औद्योगीकृत देशों ने, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और नॉर्वे सहित, 2007 और 2010 के बीच सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ाया।
5 ऊंचे कर्ज स्तरों का सामना कर रहे कुछ देशों (जैसे ग्रीस, इटली और जापान) के लिए, सबप्राइम संकट बढ़ कर संप्रभु ऋण संकट में बदल गया। इसने राजकोषीय समेकन को टालने के लिए बहुत थोड़ी वित्तीय जगह छोड़ी। हॉलैंड और पोर्टेस (2010) सुझाते हैं कि जहां सामान्य काल में वित्तीय समेकन ऋण-से-सकउ अनुपातों को घटाता, यूरोपीय संघ के इन मौजूदा हालात में आयरलैंड को छोड़ कर इस क्षेत्र में 2013 में यह समेकन उच्चतर ऋण-से-स.घ.उ. अनुपातों को जन्म देगा।
6 गुआजार्दो, ले और पेस्कातोरी 2011
7 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 2012
8 सेन 2012
9 कीन्स 1937
10 अंश्रसं 2012 (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन)
11 पूरे संकट के दौरान जिन उपायों को लागू किया गया (जैसे वित्तीय समेकन और आसान मौद्रिक नीतियां) उनकी आलोचना होती रही है अपनी सीमा तक पहुँच जाने के लिए, अपने द्वितीयक प्रभावों के लिए और अपनी अस्थायी प्रकृति के लिए। कुछ देशों में इन उपायों ने अर्थव्यवस्था को सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया है, और दूसरों में उन्हें अल्पावधि ब्याज दरों को महत्वपूर्ण मौद्रिक बाज़ारों में शून्य तक पहुँचा दिया है। ये नीतियां नए परिसंपत्ति बुलबुलों को पैदा करने और दक्षिण के देशों में मुद्रास्फीति दबावों को निर्यात कर देने के जोखिम से भरी हैं। अधिक ब्योरे के लिए नकवी और आचार्य (2012, पृष्ठ 11-12) देखें।
12 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2011b, पृष्ठ 29) कहता है कि ''उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक निर्गत का लगभग आधा और वैश्विक संवृद्धि का दो तिहाई भाग बनाती हैं क्रय शक्ति समता के अर्थ में।'' साथ ही, वह तर्क देता है कि हालाँकि उभरते और विकासशील देशों का उपभोग (स्थिर अमेरिकी डालरों में मापा गया, क्रय शक्ति समता के अर्थों में स.घ.उ. में नहीं) अपने आप में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के निम्नतर उपभोग योगदान की भरपाई नहीं करता, लेकिन जब यह संयुक्त राज्य अमेरिका (या यूरोपीय) उपभोग के साथ मिल जाता है तो पुनर्संतुलन करने के लिए पर्याप्त विशाल होता है।
13 एचडीआरओ गणनाएं दिखाती हैं कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे भिन्न भिन्न देशों को भी स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकारी निवेश से दीर्घावधि में लाभ पहुँचा है। (अधिक ब्योरे के लिए अध्याय 3 देखें।)
14 सेशल्स ($22,615) और कॉन्गो जनतांत्रिक गणतंत्र ($319) के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अनुपात द्वारा दिया गया।
15 एचडीआरओ गणनाएं, बुर्ड-शार्प और लेविस (2010) के आधार पर
16 ये विषमताएं उसी मात्रा की हैं जैसी विषमताएं, उदाहरण के लिए, एक ओर मेक्सिको (0.78) या इक्वाडोर (0.72) के मा.वि.सू. मानों के बीच हैं और दूसरी ओर नाइजीरिया, सेनेगल या मॉरितानिया (0.47) के बीच। उपराष्ट्रीय मा.वि.सू. मानों की सीधी तुलना राष्ट्रीय मा.वि.सू. मानों से नहीं की सकती क्योंकि उनके सूचक अलग होते हैं और भिन्न वर्षों के लिए होते हैं।
17 ये विषमताएं एक जैसे परिमाण की हैं जैसी विषमता एक ओर बेल्जियम (0.90) और दूसरी ओर हॉन्डुरास या किरीबाती (0.63) के मा.वि.सू. मानों के बीच।
18 विश्व बैंक (2012a) से आँकड़ों और एक संतुलित पैनल तुलना पर आधारित।
19 चूँकि आय एक प्रवाह परिवर्त है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य स्टॉक परिवर्त, कई बार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय और मा.वि.सू. रैंक के बीच एक सकारात्मक अन्तर सामने आ सकता है जब एक देश ने अपनी विकास उपलब्धियों को बढ़ाया है लेकिन उसकी आय अल्पावधि में गिर जाती है (जैसे जिम्बाब्वे में)।
20 संयुक्त राष्ट्र 2010a
21 विश्व बैंक 2012a
22 संयुक्त राष्ट्र इनेबल 2012
23 सेन 2007।
24 स्मिथ 1776
25 यू.एन.डी.पी. 2011a
26 अनुमान 2002 और 2011 के बीच के वर्षों के हैं।
27 विश्व बैंक 2012b
28 उदाहरण के लिए देखें, विल्किन्सन और पिकेट (2009)
29 मा.वि.सू. आयामों में असमानता को एटकिन्सन असमानता सूचकांक से नापा जाता है, जो एकरूपता के साथ समूहों के भीतर और बीच में असमानता के वितरण को शामिल करता है। साथ ही, यह वितरण के निचले स्तर को ज़्यादा भारित करता है इसलिए जिनी कोएफिशेंट की अपेक्षा बाल

मृत्यु, निरक्षरता और आय निर्धनता को बेहतर समझाता है।

30 ओईसीडी (2011b) दिखाता है कि ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनोमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट देशों के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और स्वीकार्य जीवन स्तरों के प्रावधान के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पुनर्वितरण प्रभाव पड़ते हैं, विशेषतः उच्च निर्धनता जोखिम वाले समूहों पर। लोक सेवाओं के पूरे फलक में स्वास्थ्य और शिक्षा असमानता घटाने में सबसे बड़ा योगदान करते हैं।

31 आनन्द और सेगल, 2008

32 सला-ई-मार्टिन 2006। वह देश-स्तरीय वितरणों के माध्य की गणना के लिए जनसंख्या-भारित प्रति व्यक्ति स.घ.उ. का इस्तेमाल करते हैं और हर माध्य के प्रकीर्णों (dispersions) को व्यष्टि सर्वेक्षणों से लेते हैं। प्रत्येक देश और वर्ष के लिए आय के वितरण का अनुमान लगाने के बाद, वह सारे राष्ट्रीय वितरणों को एकीकृत करके विश्व वितरण का निर्माण करते हैं।

33 मिलानोविक 2009

34 बोर्गियोन और मॉरिसन 2002

35 भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में एक सरकारी आदेश को कायम रखा जो कहता है कि निजी स्कूल अपनी सीटों का एक चौथाई ग़रीब बच्चों के लिए दें, एक कदम जिसमें शिक्षा तक पहुँच में आर्थिक विभाजन को काफ़ी कम करने की संभावना है।

36 उन 78 देशों पर आधारित जिनके लिए लैं.अ.सू. उपलब्ध है।

37 चीन (1.18), अजरबैजान (1.15), आर्मेनिया (1.14), जॉर्जिया (1.11), कोरिया गणतंत्र (1.10), सोलोमन द्वीप (1.09), भारत (1.08), पूर्व मैकेडोनिया यूगोस्लाव गणतंत्र (1.08), मॉन्टेनिग्रो (1.08), पापुआ न्यू गिनी (1.08), समोआ (1.08), सर्बिया (1.08) और सुरीनाम (1.08)।

38 यहां दहेज से अर्थ विवाह के समय स्त्री के परिवार द्वारा उसके पति के परिवार को दिए जाने वाले नकद और उपहारों से है। बहुत से देशों में दहेज प्रथाएं हैं जिनमें छोटी या मध्यम श्रेणी के उपहार दिए जाते हैं, लेकिन कुछ देशों में, जैसे भारत, विवाहों के दौरान वधू के परिवार से दहेज में बेहद ज़्यादा धन माँगा जा सकती है।

39 उदाहरण के लिए, 1961 का दहेज निषेध कानून भारत में दहेज देने और लेने को अवैध बनाता है। लेकिन, यह चलन जारी है, समय समय पर कन्याभ्रूणहत्या और नई वधुओं की दहेज मृत्यु दोनों को बढ़ाते हुए।

40 क्लेलैंड 2002, ड्रेज़ और मूर्ति 1999, मार्टन और जुआरेज़ 1995।

41 एल्सन 2002

42 फुकुदा-पार 2003

43 जैसा मानव विकास रिपोर्ट 1994 में संकेत किया गया (यू.एन.डी.पी.,1994), जीवन दावों की सार्वभौमिकता अवसर की समानता की पैरवी करती है, आय की समानता की नहीं – हालाँकि एक सभ्य समाज में हर एक को एक बुनियादी न्यूनतम आय की गारंटी होनी चाहिए।

44 यू.एन.डी.पी. 1994, पृष्ठ 18

45 रॉकस्ट्रॉम और अन्य 2009, पृष्ठ 32

46 संयुक्त राष्ट्र महासचिव का वैश्विक संवहनीयता पर उच्चस्तरीय पैनल 2012

47 ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क 2011

48 पारिस्थितिकी फुटप्रिंट प्रकृति से मनुष्यता की मांग की माप है। यह भूमि और जल क्षेत्रफल की उस मात्रा को मापता है जिसका उपयोग एक देश प्रकृति से अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए करता है। इसमें शामिल हैं वे क्षेत्र जिनका इस्तेमाल वह अपने उपभोग के संसाधनों के उत्पादन के लिए करता है, अपनी इमारतों और सड़कों के लिए जगह, और कार्बन डाईऑक्साइड जैसे अपने उत्सर्जनों को सोखने के लिए पारिस्थितिकीतंत्र। (ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, 2011)

49 ब्लैंडेन और अन्य (2005), विल्किन्सन और पिकेट (2012)

50 यू.एन.डी.पी. 2010b

51 बोर्गियोन, फेरेरा और मेनेडेज़ 2007

52 डि होयोज़, मार्टिनेज़ ड ला काले और ज़केले 2009

53 इवानोव और अन्य 2003, इवानोव और अन्य 2008

54 यू.एन.डी.पी. 1994

55 रोज़ेनफेल्ड, मेसनर और बॉमर (2001) ने परिकल्पित किया कि सामाजिक संघटन के केन्द्रीय तत्व - नागर जुड़ाव और भरोसा, मज़बूत सामाजिक संगठन से जुड़े हैं और इसलिए निम्न आपराधिक हिंसा के संकेतक हैं।

56 यू.एन.डी.पी. 2012

57 आँकड़े 2005 से 2012 के बीच उपलब्ध सबसे हालिया वर्ष के हैं। हत्या आँकड़े पूरक हत्या रिपोर्टिंग में प्रक्रियात्मक गलतियों और देशों के स्तर पर रिपोर्टिंग तंत्रों में असंगतिताओं से ग्रस्त होते हैं, दूसरी समस्याओं के साथ।

58 सेन 2007, पृष्ठ 106

59 हत्या की घटनाओं का औसत सारे भारतीय शहरों के लिए प्रति 100,000 लोगों में 2.7 है और दिल्ली में 2.9। इसकी तुलना में यह लंदन में 2.4, न्यूयॉर्क में 5.0, लॉस एजेल्स में 8.8, जोहानिसबर्ग में 21.5, साओ पॉलो में 24.0 और रियो ड जनेरियो में विस्मयकारी 34.9 है।

60 यूनाइटेड किंगडम, उप प्रधानमंत्री कार्यालय, सामाजिक अपवर्जन ईकाई 2002। बहुत से कैदी सारा जीवन अपवर्जित किए गए हैं। सामान्य जनसंख्या की तुलना में कैदियों के बचपन में राज्य बाल गृहों में रहे होने की संभावना ज़्यादा है (13 गुना), बेरोज़गार होने की (13 गुना), परिवार के एक सदस्य के किसी अपराध में दोषी घोषित किये जाने की (2.5 गुना) और एचआईवी पाज़िटिव होने की (15 गुना)।

61 बहुत से कैदी सेवाओं तक पहुँच से अपवर्जित किए गए थे। कैदियों के अनुमानित 50% का हिरासत में आने से पहले कोई चिकित्सक नहीं था, सामान्य जनसंख्या की तुलना में कैदियों के स्कूल से अपवर्जित किए जाने की संभावना 20 गुनी से ज़्यादा है, और कम से कम एक मामले में, हालाँकि कारावास में प्रवेश करने वालों में 70% नशे से समस्याग्रस्त थे, उनमें से 80% को कभी नशे के इलाज की कोई सेवा नहीं मिली थी। (उप प्रधानमंत्री कार्यालय, सामाजिक अपवर्जन ईकाई 2002)

62 पिंकर 2011, सेंटर फॉर सिस्टेमिक पीस 2012

63 ब्रैक्ज़िक 2004

64 दहल और अन्य 2003

65 आयर 2009

66 चूँकि आंतरिक संघर्षों के प्रतिभागियों में एक बड़ी संख्या राज्येतर तत्वों की होती है, हथियारों पर उनके खर्च के आधिकारिक रेकार्ड नहीं हैं। सैन्य खर्च पर आँकड़े केवल सरकारों के खर्च के हैं, राज्येतर तत्वों के खर्चों के नहीं।

67 बर्ड 1981

68 ग्रीन 2010

69 जस्टिन 2008

70 यू.एन.डी.पी. 1991, पृष्ठ 37

अध्याय 2

1 1-1.6 बिलियन बहुआयामी निर्धन लोगों में से तीन-चौथाई दक्षिण के मध्यम-आय देशों में रहते हैं।

2 एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ यू.एन.एस.डी. (2012) पर आधारित।

3 इंटरनेट संबंधित आँकड़े विश्व बैंक (2012a) से हैं; पर्यटन संबंधित आँकड़े यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. (2011) से हैं।

4 एस्टेवाडियोर्डल, फ्रैंत्ज़ और टेलर 2003

5 विश्व बैंक (2012a)। ये अनुपात निर्यात और आयात में सकल मूल्यों, न कि मूल्य, के वर्धन पर आधारित हैं, जिसके लिए फिलहाल वैश्विक तुलनात्मक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक पहल जारी है, ताकि दुनिया में व्यापार का मूल्य वर्धन में आकलन और विश्लेषण किया जा सके।

6 6- 127 विकासशील देशों के संतुलित पैनल पर आधारित। एच.डी.आर.ओ. गणनाओं पर आधारित, जब केवल दक्षिण के साथ व्यापार को शामिल करने के लिए व्यापार-उत्पादन अनुपात को समायोजित किया गया, तो 144 में 141 अर्थव्यवस्थाओं (जिनके लिए आँकड़े उपलब्ध हैं) ने 1990-1991 और 2010-2011 के बीच दक्षिण के साथ व्यापार को बढ़ाया है (डोमिनिका, मालदीव और तुवालू जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाएँ अपवाद थीं); इसके विपरीत, 92 ने उत्तर के साथ व्यापार में कमी की है।

7 विश्व बैंक (2008)। आम धारणा के विपरीत, हवाई और समुद्री परिवहन की वास्तविक कीमतें 1970 के दशक के बाद से अधिक नहीं बदली हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पोत लदान के घटते वज़न-मूल्य अनुपात और हवाई परिवहन के बढ़ते इस्तेमाल ने फैशन, प्रसंस्करित खाद्य और इलेक्ट्रानिक्स जैसे समय के प्रति संवेदनशील वस्तुओं को सुलभ किया है।

8 एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ यू.एन.एस.डी. (2012) पर आधारित।

9 विश्व बैंक 2012a

10 आठ देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, भारत, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। हालाँकि, निम्न विकसित देशों ने 20 से कम से .150, केवल आठगुनी वृद्धि देखी।

11 जब वस्तुओं के निर्यात में सेवा निर्यात को जोड़ लिया गया, सब-सहारा अफ्रीका और भारत के बीच प्रति व्यक्ति निर्यात आय में अंतर 221 से घटकर $130 हो गया। भारत जैसे बड़े देशों, जिनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक है, के मुकाबले छोटे देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक संबद्धता का रुझान दिखा। इतना ही नहीं, अफ्रीकी निर्यात में कमोडिटिस का वर्चस्व था, जिनकी कीमतें 2000 के दशक में बढ़ी।

12 1996 के मूल्यों से तुलनायोग्य बनाने के लिए समायोजित 2011 के संकेतिक मूल्यों पर आधारित।

13 कुल व्यापार सांख्यिकी से ईंधन, धातु और अयस्कों को निकाल दिया जाए तो इसका अर्थ है कि विश्व व्यापार में दक्षिण-दक्षिण व्यापार की हिस्सेदारी 1980 के 6.3% से बढ़कर 2011 में 26.1% हो गयी और उत्तर-उत्तर व्यापार की हिस्सेदारी 1980 के 50.6% घटकर 2011 में 31.4% प्रतिशत रह गयी।

14 अवयव और संगटक का व्यापार बढ़ने कारण उच्च अथवा निम्न प्रौद्योगिकी के रूप में वस्तुओं का परंपरागत वर्गीकरण कम अर्थपूर्ण हो गया।

15 रोमेरो 2012

16 ए.एफ.डी.बी. और अन्य 2011

17 गुप्ता और वांग 2012

18 हुक और क्लार्क 2012

19 इस अनुच्छेद में पर्यटन संबंधी सांख्यिकी यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. (2011) पर आधारित।

20 संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यू.एन.सी.टी.डी.) के आँकड़ों पर आधारित। इसकी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी, जिसमें हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.), कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और चीन का ताईवान प्रांत शामिल है लेकिन स्वतंत्र राज्यों के राष्टमंडल देश शामिल नहीं हैं, की सकल एफ.डी.आई. अंतर्प्रवाह में हिस्सेदारी 1990–1991 में 5.3% और 2009–2010 में 8% प्रतिशत थी।

21 यू.एन.सी.टी.ए.डी. 2011b

22 इसके अलावा, दक्षिण-दक्षिण एफ.डी.आई. मेजबान और प्राप्तकर्ता देशों के बीच संस्थागत गुणवत्ता में अंतर से कम प्रभावित होता है। ऐसे ही तर्क के अनुसान, स्थानीय व्यक्तियों को रोज़गार और निम्न ऊपरी लागत दक्षिण-दक्षिण एफ.डी.आई को स्थानीय मुद्दों के प्रति अधिक लोचदार बना सकती है। क्योंकि निवेश और क्षेत्रों के चयन का उद्देश्य अक्सर अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि दक्षिण-दक्षिण एफ.डी.आई उत्तर-दक्षिण एफ.डी.आई की जगह लेती है; इसे और अधिक आकर्षित

किया जा सकता है। (बेरा और गुप्ता 2009; अलेक्स्यान्सका और हैविरेयलचिक 2011)

23 यह आँकड़ा 2010 के लिए है और इसमें हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.) शामिल हैं।

24 इस अनुच्छेद में प्रमाण हमदानी (2013) से लिये गये हैं।

25 ब्लइंडर 2006

26 यू.एन.आई.डी.ओ. 2009

27 यू.एन.डी.पी. 2009; विश्व बैंक 2010a।

28 ये एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ विश्व बैंक (2010a) की द्विपक्षीय प्रवास मैक्ट्रिस पर आधारित हैं।

29 राथा और शॉ 2007

30 जैसा कि विश्व बैंक (2006) में बताया गया है, दक्षिण-दक्षिण धनप्रेषण का अनुमान इस पर निर्भर करता है कि, उसके प्रवासी नागरिकों के गंतव्य देशों में प्रत्येक देश द्वारा प्राप्त कुल धनप्रेषण को विभाजित करने के लिए किस व्याख्यात्मक चर का इस्तेमाल किया गया है। दक्षिण-दक्षिण धनप्रेषण का अनुमान उस समय अधिक (30%) है जब प्रवाह प्रवासी स्टॉक के फलन के रूप में हैं और उस समय कम (18%) है जब वे प्रवासी स्टॉक और मेजबान तथा प्रेषक देशों की औसत आय के योग का फलन हैं। जब सउदी अरब की गणना एक विकासशील देश के रूप में की जाती है तो 45% ऊपरी सीमा प्राप्त होती है।

31 फेलबेरमेर और जंग (2009) और कुगलर तथा रेपोपोर्ट (2011) में अन्य दृष्टान्त देखें।

32 फोले और कैर 2011

33 दि इकॉनामिस्ट (2011a) और उसमें उद्धत कार्य देखें।

34 एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ विश्व बैंक (2012a) और आई.टी.यू. (2012a) द्वारा 144 देशों के आँकड़ों पर आधारित।

35 socialbakers.com 2012, जुकरबर्ग (2012) द्वारा अधिक हालिया तथ्य यह है कि अब फेसबुक के एक बिलियन से अधिक सक्रिय मासिक उपयोगकर्ता हैं, जिनमें अधिकांश उपयोगकर्ता ब्राज़ील, भारत, इण्डोनेशिया, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के हैं।

36 श्रम बल, जिसमें नियोजित व्यक्ति और बेरोज़गार व्यक्ति दोनों शामिल हैं, सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश कर रहा है।

37 फू 2008

38 जब नमूनों से विकसित देशों को हटा दिया गया, सहसंबंध कोइनीश्यिन सांख्यिकी रूप से उल्लेखनीय बना रहा लेकिन 0.66 से घटकर 0.48 रह गया।

39 अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, और ज़ाम्बिया जैसे संसाधन-संपन्न देशों में चीन से आवक एफ.डी.आई. द्वारा वार्षिक वृद्धि दर में योगदान के अनुमानों के लिए व्हेलेय और वाइसब्रोड (2011) देखें। यू.एन. सी.टी.ए.डी. (2011a) के अनुसार इन छह देशों में औसत एफ.डी.आई. अंतर्प्रवाह 1990–2000 के $2.4 अरब के मुकाबले चार गुना बढ़कर 2001–2011 में $9 बिलियन हो गया।

40 जोन्स और किर्जक्रोस्की 2001

41 वॉस 2010

42 आई.एम.एफ. 2011a

43 समाके और यांग 2011

44 व्हेलेय और वीसब्रॉड 2011

45 हजार्ड और अन्य 2009; कामाऊ, मैकक्रोमिक और पिनॉड 2009; कैपलिन्स्कॉय 2008

46 केन्याई मामले के लिए कामाऊ, मैकक्रोमिक और पिनॉड (2009) देखें; कैपलिन्सकॉय और मोरिस (2009);

47 जेनकिन्स और बारबोसा 2012

48 आई.सी.टी.एस.डी.(I.C.T.S.D) 2011

49 डेवीस 2011

50 ब्राउटिगम 2009

51 सोनोबे, अकोतन और ओटसुका 2009

52 ब्राउटिगम 2009

53 संयुक्त राष्ट्र 2012b

54 मोचो 2012

55 हेस्त्रा – वान डे हार्स्ट (2011) के अनुसार अब चीन दुनिया के फर्नीचर बाज़ार के तीसरे हिस्से पर काबिज़ है।

56 कैपलिंस्कॉय, तेरहेगन और तिजाजा 2011

57 संयुक्त राष्ट्र 2012b

58 ये बिंदु डॉब्स और अन्य (2012) के हैं; सर्वे में पाया गया कि उदाहरण के लिए मिस्र के उपभोक्ताओं में इंग्लैण्ड या अमेरिका के उपभोक्ताओं की तुलना में दोस्तों और परिवारजनों द्वारा उत्पादों की सकारात्मक अनुशंसा तीन गुनी अधिक महत्वपूर्ण थी।

59 एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ ब्रुकिंग संस्थान पर आधारित (2012)

60 डब्स और अन्य 2012

61 विश्व बैंक, 2012a

62 2008 में, दक्षिणी देशों को दूसरे दक्षिणी देशों द्वारा दी गयी सहायता $15.3 बिलियन थी जो कुल सहायता का लगभग 10% है. यू.एन. डी.ई.एस.ए. (NDESA 2010).

63 2005 और 2008 में खार्स, माकिनो और जंग (2011) के आँकड़ों पर आधारित और बाद के वर्षों के लिए बहिर्वेषित.

64 क्राग्लैंड, 2013.

65 संयुक्त राष्ट्र 2012b.

66 इसकी बहुआयामी तकनीकी सहायता के पहल में अन्य चीजों के अलावा अमेरिकी स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थाओं के लिए, भारत में केन्द्रित ब्राडबैंड संयोजन उपलब्ध कराना तथा 1,600 युवा अफ्रीकी छात्रों को हर साल भारत में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है (संयुक्त राष्ट्र 2012b).

67 संयुक्त राष्ट्र 2012b.

68 बड़े विकासशील देशों ने भले कम लेकिन लम्बे समय वाले विकास सहायता कार्यक्रम अमेरीका में चलाये हैं। भारत का तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम 1987 में स्थापित किया गया। ब्राजील की सहयोग एजेंसी 1987 में स्थापित हुई। चीन के अफ्रीका के साथ सहयोग का इतिहास और पुराना है, हालाँकि यह अब चीन-अफ्रीका सहयोग मंच के रूप में औपचारिक रूप में 2000 में स्थापित कर दिया गया है. (क्रेग्लैंड 2013).

69 ब्रेमर 2012.

70 विश्व बैंक 2010c.

71 संयुक्त राष्ट्र के अनुसार (2012b), वे थे इस्लामिक विकास बैंक, द कुवैत फ़ंड फ़ॉर अरब इकान्मिक डेवेलपमेंट, द अरब फ़ंड फ़ॉर इकानमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, द अरब बैंक फ़ॉर इकानामिक डेवेलपमेंट इन अफ्रीका, द सऊदी फ़ंड फ़ॉर डेवेलपमेंट और द अबू धाबी फ़ंड फ़ॉर डेवलपमेंट।

72 ये क्षेत्रीय संस्थाएँ ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से नीतिगत प्रेरणा लेती लगती हैं। न ही ए.डी. बी. और न आई.ए.डी.बी. वर्तमान नियमों के अंतर्गत अपने मालिकाना ढाँचे में कोई बड़ा बदलाव करने में सक्षम हैं। अमेरिका ने पूँजी आधार पर किसी परिवर्तन को रोकने के लिए वीटो अधिकार अपने पास रखा है जो इन दो संस्थाओं में नीतिगत स्पेस को तंग बना दिया है। यदि, उदाहरण के लिए, ए.डी. बी. अपने आपको पूरी तरह से एशियाई संस्था बनना चाहे जो अपना खुद का नीति-स्पेस स्थापित करना चाहे, तो इसे अपना मालिकाना ढाँचा चीन, भारत और कोरिया गणराज्य जैसे देशों को अधिक बड़ा योगदान और अधिक मतदान अधिकार देकर फिर से बनाना पडेगा। (सोभन, 2012)

73 म्वासे और यंग 2012

74 जुजाना और एंडीकुमना का प्रकाश्य कार्य।

75 विकासशील देशों ने दक्षिणी देशों के बीच का आपसी सीमा-शुल्क को उत्तर-दक्षिण देशों के स्तर पर कम करके $59 बिलियन तक का लाभ हासिल कर सकते हैं (ओ.ई.सी.डी. 2010a)

76 ग्राबेल 2013.

77 ग्राबेल, 2013.

78 अवसर लागतें उन लाभों को मापती हैं जो संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग से हासिल हो सकते थे। देखिए रोड्रिक (2006) और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2011b).

79 चीन का हिस्सा मतदान में पांचवा सबसे बड़ा है, लेकिन बोर्ड आफ गवर्नर्स का 2010 में किया एक समझौता अगर लागू हुआ तो यह तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। (आई.एम.एफ. 2010b)

80 विश्व बैंक, 2010d

81 हनसन, 2010

82 यू.एन.डी.पी. 2009

83 लीप, 2012

84 रोमेरो एंड ब्राडर 2012

85 कोहन एंड विक्टर, 2010

86 ली 2010; ब्राडशेर 2010

87 आर.ई.एन.21 2012

88 देखें, जैकब (2012); उदाहरण के लिए अफ्रीका में चीन की अधोसंरचनात्मक कंपनियाँ भारी मशीनरी और अन्य पूँजीगत आयातों की मांग को बढ़ा रही हैं।

89 आक्युज़ (2012) यह तर्क देता है कि बड़े देशों को अपना रास्ता बदलने की ज़रुरत है। विकासशील देशों को 2000 के दशक में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के असंवहनीय उपभोग तरीकों से असामान्य लाभ हुआ। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से विकासशील देश अपनी घरेलू मांगों पर अधिक निर्भर रहे हैं।

अध्याय 3

1 उदाहरण के लिए जीवन प्रत्याशा वर्ष 1949 के 35 से लगभग दोगुनी होकर वर्ष 198 1 में 67.9 वर्ष तक पहुँच गई थी। (यू.एन. डी.पी. 2008)

2 एक समस्या यह भी है कि इस विधि के माध्यम से मानव विकास सूचकांक में तीव्र वृद्धि प्रदर्शित करने वाले देशों की पहचान, उच्च मा.वि.सू. मान वाले देशों की ओर झुकाव रखती है। परंतु मा.वि.सू. के प्रतिशत सुधार आकने के सीधे तरीके से मा.वि.सू. पर तीव्र वृद्धि रखने वाले देशों की पहचान, न्यून मा.वि.सू. मूल्य वाले देशों की ओर झुकाव रखती है। इसलिए कोई भी विधि संपूर्ण नहीं है।

3 (रेनीस और स्टीवर्ट 2005)

4 1990 की सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ हांगकांग, चीन (एसएआर), इजराइल, सिंगापुर, और मध्य व पूर्वी यूरोप के वे देश जो यूरोपीय संघ में शामिल हो चुके हैं, ये सभी इस सूची के बाहर हैं। इससे 1990 और 2012 के मध्य 96 देशों का एक संतुलित पैनेल मिलता है।

5 आंतरिक सशस्त्र संघर्ष यह भी इंगित करता है कि राष्ट्रीय आँकड़ें में देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से के आँकड़े अक्सर शामिल नहीं थे।

6 यूएनडीपी 1993, 1996

7 यूएनडीपी 1996

8 एबी 2006

9 विकास के लिए स्वामित्व और क्षमता की अवधारणाओं की व्योया के लिए फ़ुकुदा-पर्र, लोप्स और मलिक (2002) देखें।

10 प्रगति और विकास आयोग (2008) देखें।

11 उदाहरण के लिए, रॉड्रिक (2004) ने इस तथ्य पर जोर दिया कि विकासशील देशों की प्रगति के लिए कोई पहले से तैयार नीतिगत सुधारों की सूची लागू नहीं की जा सकती।

12 हॉसमैन, प्रिचेट और रॉड्रिक 2005

13 सेर्रा और स्टि्ग्लट्ज 2008

14 हॉसमैन, रॉड्रिक और वेलास्को 2005

15 अरीघी (2007) तर्क देते हैं कि आत्म-विनियमित बाज़ार (Self-regulating market) विकास के साधन नहीं होते हैं और बाज़ार विनिमय और श्रम विभाजन को सुसंगठित करने में सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

16 एक देश को तुलनात्मक लाभ की स्थिति में तब माना जा सकता है जब वहां पर किसी आर्थिक गतिविधि के संदर्भ में विकल्प लागत दूसरे देशों की तुलना में कम हो।

17 नवजात उद्योगों (Infant industry) के संरक्षण और औद्योगिक नीति के अन्य प्रकारों पर एकल-उद्योग, अंतउर्द्योग और अंतर्देशीय साक्ष्यों के लिए हैरीसन और रोड्रिग्ज-क्लेयर (2010) देखें। वैश्विक बाज़ारों में सफल होना, सरकारी सहायता को न्यायोचित ठहराने का केवल एक मापदंड ('' मिल'' परीक्षण) है। ऐसी सफलता अर्थव्यवस्था के लिए एक शुद्ध कल्याण लागत और ''बास्टेबिल''

परीक्षण में असफल होने पर भी आ सकती है। इसके लिए अल्पावधि में संरक्षण की लागतों की क्षतिपूर्ति हेतु भविष्य के लाभों को घटाने की आवश्यकता होती है। हैरीसन और रोड्रिग्ज-क्लेयर (2010) के अनुसार ज़्यादातर औद्योगिक नीतियाँ बास्टेबिल की अपेक्षा मिल परीक्षण पर खरी उतरती हैं।

18 रोड्रिक 2012, पेज-9

19 छिब्बर 1999

20 ओस्मानी 2005

21 रेनीस और स्टीवर्ट 2005

22 भारतीय वित्त मंत्रालय 2012

23 रोड्रिक 2005

24 दास (2000) और डीलांग (2004) देखें।

25 अंकटाड 2003

26 डोन 2011; 1996 और 2005 के बीच इंब्रेयर ने विश्व भर में 710 क्षेत्रीय जेट विमान उपलब्ध कराये (बेयर 2008)

27 पाशा और पलानीवेल 2004

28 नोट्स। 7 127

29 यूएनडीपी 1993, 1996।

30 फाइन एवं अन्य (2012) द्वारा किए गए अफ्रीका के वर्गीकरण में उत्तरी अफ्रीका के साथ-साथ उप-सहारा अफ्रीका भी शामिल है।

31 फाइन एवं अन्य 2012

32 एफडीबी एवं अन्य 2012

33 सुब्रमण्यन एवं रॉय 2001

34 चूहान-पोल और एंगवाफो 2011

35 निर्धनता की गिनती 1983-1984 के 52% से गिर कर 1991-1992 में 50% हो गई। वर्ष 2000 तक यह 40% तक घट गई। (ओस्मानी व अन्य 2006)

36 खान 2005

37 नील्सन और स्पेन्सीले 2011

38 कबानानुक्ये और अन्य 2004

39 इस अनुच्छेद में दिए थाइलैण्ड व ब्राजील के आँकड़े फाइन एवं अन्य (2012) से लिये गये हैं।

40 इस्लाम (2002) जिसकी चर्चा खान (2005) में है।

41 खान 2005

42 कामिंस्की और एन.जी. 2006।

43 अयादी एवं अन्य 2005।

44 केंमेट 2007।

45 लॉशियर 2008।

46 एगोसिन 1997।

47 हुसैन एवं स्टर्न 2006, पेज-14।

48 मलिक 2006।

49 हॉवेल 2004।

50 रेवालियन 2009।

51 मलिक 2012।

52 रोड्रिक 2011।

53 आर्थिक प्रगति को तीव्र करने के लिए वैश्विक बाज़ारों में जगह बनाना ही पर्याप्त नहीं है; इसके लिए परिष्कृत निर्यात भी उतना ही आवश्यक है। और इसके लिए विदेशी तकनीक ज्ञान की सहायता से सतत सुधार भी महत्वपूर्ण हैं (हॉसमैन, ह्वांग और रॉड्रिक 2007 देखें)।

54 प्रगति और विकास पर आयोग (2008, पेज-22)

55 रोड्रिक 2001।

56 इस क्रम में चार प्रभावपूर्ण पर्चों- डॉलर (1992), सैक्स एवं वार्नर (1995), एडवर्ड्स (1998) और फ्रेंकेल एवं रोमर (1999) की समीक्षा के लिए देखें रॉड्रिग्ज एवं रोड्रिक (2001)।

57 विंटर्स 2004।

58 नीति तंत्रों को समझने और उनके मूल्यांकन के लिए देश-विशिष्ट गहन केस-अध्ययनों के प्रयोग की सबसे अच्छी वकालत भगवती और श्रीनिवासन (2001) ने करी है। इनके अनुसार यदि अधिकांश देशपारीय समाश्रयणों में निहित निरी-सैद्धांतिक, आँकड़े और प्रणालीगत कमजोरियों पर ध्यान न भी दिया जाए तो देशपारीय परिणाम, देशों में पाए जाने वाले वैयक्तिक प्रतिक्रियात्मक भेदों को ढकते हुए केवल औसत प्रभावों को ही इंगित करते हैं।

59 रोड्रिक 2001।

60 बाल्डविन (2004) और उसमें दिए गए देशों के विशिष्ट केस अध्ययनों पर गौर करने के संदर्भों को देखें।

61 वेकजिआर्ग और वेल्च 2008।

62 रोड्रिक 2011।

63 1970 के दशक के प्रारंभ में मॉरिशस ने व्यापार प्राथमिकताओं और कोटा का भरपूर उपयोग करते हुए, विशेषकर चीनी और वस्त्रों के निर्यात के माध्यम से वैश्विक बाज़ारों को अंगीकार किया। 2000 के दशक में वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में वैश्विक व्यापार को अभिशासित करने वाले कोटा के खात्मे और ई.यू. के चीनी प्रोटोकॉल मूल्यों में कमी के साथ मॉरिशस ने ऑफशोर बैंकिंग और आईसीटी जैसे उपायों के जरिये हल्के विनिर्माणों और सेवाओं के रूप में निर्यातों को विविधीकृत किया (जफर 2011)।

64 हालाँकि सरकारी एकाधिपत्य के पहले ही खत्म कर दिया गया था और इनका स्थान 1990 के दशक टैरिस, नॉन टैरिफ बाधाएं और आयात अवरोधक लाइसेंसों ने ले लिया। 1980 से 2000 के बीच, चीन ने विश्व व्यापार संगठन के अंतरराष्ट्रीय नियमों अवरोधों का सामना किए बग़ैर अपने औद्योगिक आधार को सशक्त किया। (2001 में चीन इसका सदस्य बना)।

65 2008 और 2010 के बीच, चीन (हांगकांग, (चीन-एसएआर) को छोड़कर) ने वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह के औसतन 7.2त्न हिस्से को आकर्षित किया (अंकटाड 2011 ए)।

66 चीन का उदाहरण एक उत्तरोत्तर दृष्टिकोण के लाभ को इंगित करता है। जैसा कि अरीघी (2007) के अनुसार चीन के सुधारोपायों में शामिल हैं- क्रमिकता, बाज़ार का अभिशासन के माध्यम के तौर पर उपयोग, कृषि में शुरुआती सुधारों के बाद क्रमशः उद्योगों व विदेशी व्यापार की ओर बढ़ना जिससे से पूँजीपति आपस में प्रतिस्पर्द्धा में करें।

67 अहलूवालिया 2002।

68 ओईसीडी 2007।

69 अहलूवालिया 2002।

70 विश्व बैंक 2012 ए।

71 सेलासन 1994।

72 औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आयात संरक्षण के साथ निर्यात उन्नयन को भी बढ़ावा दिया गया। इन उपायों में शामिल हैं- अनुदानित ऋष्ठा, करों की दर में कमी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, अनुबंध आधारित विनिर्माण वेयरहाउस, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क प्रशासन का निजीकरण और प्रत्यक्ष निर्यात अनुदान।

73 विश्व बैंक 2010 बी। थाइलैण्ड में हालिया वर्षों में हुई राजनितिक अस्थिरता के बावजूद वहाँ विदेशी कंपनियों की क्षमताओं में वृद्धि देखी जा रही है। 2010 में फोर्ड, जनरल मोटर्स, माज्दा और टोयॉटा ने नई निवेश योजनाओं की उद्घोषणा की। इसके साथ बीएमडब्ल्यू और टाटा जैसे नए निवेशकों के भी मैदान में उतरने की उमेद है।

74 पेनांग के निर्यात हब के तौर पर उदय होने के विस्तृत अध्ययन के लिए अथुकोराला (2011) देखें ।

75 विश्व बैंक 2011 ए।

76 एनईएसी 2010।

77 अथुकोराला एवं वाग्ले 2011।

78 राडेलेट, सैक्स एवं ली 1997।

79 शर्मा 2012।

80 क्लैप 1995, एगोसिन 1997, रोड्रिक 2004।

81 अंकटाड 2006।

82 वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में वैश्विक व्यापार का अभिशासन 40 वर्ष से भी अधिक समय तक कोटा प्रणाली से संचालित हुआ। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में कॉटन टेक्सटाइल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लघु एवं दीर्घ अवधि व्यवस्थाओं के साथ हुई थी। इसके बाद क्रमशः 1974 और 1994 के बीच मल्टी-फाइबर व्यवस्था और 2004 तक चलने वाला विश्व व्यापार संगठन का वस्त्र एवं परिधानों पर समझौता। इनमें से विशेषकर मल्टी-फाइबर व्यवस्था ने बहुत सी सफल निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं (विशेषकर पूर्वी एशिया की) को निवेश के लिए ऐसे देशों का रुख करने के लिए बाध्य किया, जो द्विपक्षीय कोटा प्रणाली की औपचारिकताओं से कम प्रभावित हों। इसने वैश्विक व्यापार को विकृत किया लेकिन बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे देशों को विनिर्माण के क्षेत्र में बढ़ने की दिशा में मदद की।

83 कबीर एवं महमूद 2004।

84 संयुक्त राष्ट्र कमोडिटी ट्रेड स्टेटिस्टिक्स डाटाबेस के दोहरे व्यापार आँकड़ों के अनुसार; स्टैंडर्ड अंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (संशोधन 3) डिवीजन 84 से जुड़े उत्पादों को परिधान निर्यातों के तौर पर वर्गीकृत किया गया। विश्लेषण उन देशों तक सीमित है जिन्होंने हर वर्ष परिधान निर्यातों के आँकड़े प्रस्तुत किए।

85 सुब्रमण्यन एवं रॉय 2001।

86 चौहान-पोल एवं एंग्वाफो 2011।

87 ओफोसू-असारे 2011।

88 सूरी एवं अन्य 2011। इन्होंने विशेष तौर पर पाया कि शिशु मृत्यु दर में होने वाली एक स्टैंडर्ड डीवेयेशन की कमी से एक दशक के दौरान आर्थिक प्रगति में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी। इसी तरह एक दशक के दौरान जीवन प्रत्याशा में होने वाली एक स्टैंडर्ड डीवेयेशन बढ़त, संवृद्धि में 2.7 प्रतिशत की तेजी को इंगित करता है, जबकि एक दशक के दौरान हुई सेकेंडरी नामांकन दर में एक स्टैंडर्ड डीवेयेशन बढ़त, संवृद्धि को 1.9 प्रतिशत तक बढ़ा देती है।

89 प्रगति एवं विकास पर आयोग 2008।

90 हानुशेक और अन्य (2008) ने पाया कि उनके द्वारा अध्ययन किए गए 50 देशों में औसत स्कूलिंग के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष ने सकल घरेलू उत्पाद के 40 वर्ष की औसत वृद्धि दर को 0.37 प्रतिशत बढ़ा दिया। हालाँकि, उन्होंने पाया कि 1960 के दशक के दौरान वह देश जिनका परीक्षण स्कोर दूसरे देश की तुलना में 0.5 स्टैंडर्ड डीवेयेशन उच्च था, उसकी औसत वृद्धि दर अगले 40 वर्ष के दौरान वार्षिक तौर पर 1 प्रतिशत उच्च थी।

91 इस सवाल के ज़वाब के लिए, हानुशेक एवं अन्य (2008) ने प्रत्येक देश में उन विद्यार्थियों के भाग को मापा, जो गणित और विज्ञान में एक मूलभूत योग्यता की सीमा तक पहुँचे। इसके अलावा उन विद्यार्थियों को भी मापा गया जिनका निष्पादन अत्यंत उच्च रहा।

92 ब्लूम, कैनिंग एवं सेविला (2007) ने पाया कि जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा में एक वर्ष की वृद्धि निर्गत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करती है। इस प्रकार, प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के साथ भी सकारात्मक प्रभाव जुड़े हुए हैं। 97 देशों में किए गए अध्ययन में ब्लूम एवं अन्य (2009) ने पाया कि प्रजनन की उच्च दर का संबंध प्रजनन के लिए उपयुक्त वर्षों में महिलाओं की श्रम बल में कम सहभागिता से होता है। प्रत्येक अतिरिक्त शिशु से 20 से 44 वर्ष की महिलाओं की श्रम बल में सहभागिता में औसतन 5 से 10 प्रतिशत की कमी हो जाती है।

93 स्टर्न 2003।

94 कोर्निया 2004।

95 रोड्रिक 1998।

96 स्टर्न 2003।

97 सेवान्याना, माटोवू एवं ट्विमुक्ये 2011।

98 फोस्टर एवं मिजूंबी 2002।

99 बर्टेंड एवं मुलैयनाथन 2003।

100 एस्समा-न्स्साह 2011।

101 सिवानांथिरन एवं वेंकट रकम 2005।

102 त्सोउंटा 2009।

103 तेंगचेरोएनसेथियन एवं अन्य 2011।

104 यूनेस्केप 2011।

105 फ्रेंक, गोमेज-डेन्ट्स एवं नॉल 2009।

106 केनबर 2004।

107 रेवैलियन 2009।

108 ग्लेवी एवं कसॉफ 2008।

अध्याय 4

1 समता और समानता के बीच अंतर, क्या देखा जा सकता है और क्या नहीं, इसके बीच के अंतर के साथ जुड़ा हुआ है। समता का संबंध समान अवसरों के साथ है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता है। दुर्भाग्यवश, चूँकि केवल नतीजों को देखा जा सकता है और उनका आकलन किया जा सकता है, इसलिए क्या

समाज समतामूलक है, इस बात का मूल्याँकन केवल प्रचलित असमानता की मात्रा पर आधारित सटीक अनुमान द्वारा ही किया जा सकता है।

2 नस्लीय, जातीय और धार्मिक समूहों के बीच असमानता खासतौर से राजनीतिक हिंसा का कारण बन सकती है और यदि व्यापक नीतियों के ज़रिये इसका सामना नहीं किया गया तो यह अत्यधिक जटिल रूप ले सकती है। (स्टुवर्ट 2013)

3 लैटिन अमेरिका के ये लाभप्रद रुझान श्रम आय असमानता में कमी, कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच मज़दूरी का अंतर समाप्त होने और सशर्त नकदी हस्तांतरण के कारण है (लोपेज-साल्वा और लस्टिग 2010)।

4 क्लीलैंड 2002। मार्टिन और हुआरेज़ (1995) का तर्क है कि कुछ मामलों में अल्पावधि के दौरान शिक्षा पुनरुत्पादन व्यवहार को अनिवार्य रूप से तत्काल प्रभावित नहीं करती है। होरी (2011); सरबेसा (2002); कॉकरन (1979); ब्लूम एवं अन्य (2009); साचेरोपोलस और ज़ायनोटस (1992) भी देखें।

5 टेलर, न्यूमैन और केली 1976।

6 यूएनडीईएसए 2007; डायमंड, न्यूबे और वार्ले 1999; जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो 2000।

7 इस सूचकांक को सामान्य रूप से प्रति 1,000 जीवित जन्में बच्चों के मुकाबले मृत्यु या शिशु मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार प्रति वर्ष 1000 जीवत जन्में बच्चों के मुकाबले 61.7 की मृत्यु हो जाती है।

8 यूएनडीपी 1995।

9 आईएलओ 2012। अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन ने गैलप सर्वेक्षण आँकड़ों के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया है।

10 वेस्टावे 2012।

11 लागी, बर्ट्रेन्ड और बार-यैम 2011। खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक 2008 में 180 की ऊँचाई पर पहुँच गया।

12 आईएलओ 2012। गैलप आँकड़ों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमानों के मुताबिक दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में अधिकांश लोग बेहतर नौकरी की उपलब्धता को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। मध्य और पूर्वी यूरोप तथा सब-सहारा अफ्रीका में यह असंतुष्टि चरम है, जिसके बाद पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका का स्थान है।

13 ब्लैण्ड 2012

14 तेजाडा 2012

15 गूच 2012

16 आईएलओ 2012

17 उदाहरण के लिए जैनकींस और वैलेस (1996) देखें, जिन्होंने शिक्षा और विरोध भागीदारी के बीच संबंध का पता लगाया, और डॉल्टन, वेन सिकेल और वेलडन, जिन्होंने विकसित से लेकर विकासशील देशों तक शिक्षा स्तर और विरोध भागीदारी के बीच सशक्त सकारात्मक सह-संबंध का पता लगाया।

18 18 विभिन्न मान्यताओं के तहत अनुमान है कि अब से लेकर 2050 के बीच 15 वर्ष से अधिक की वैश्विक जनसंख्या जो अशिक्षित है, की हिस्सेदारी 2010 के 12 प्रतिशत के मुकाबले घटकर या तो 3 प्रतिशत रह जायेगी या 8 प्रतिशत, जो परिदृश्य पर निर्भर करेगा। द्वितीयक या तृतीयक शिक्षा हासिल करने वाली जनसंख्या की हिस्सेदारी 2010 के 44 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर या 50 प्रतिशत हो जायेगी या 64 प्रतिशत, जो परिदृश्य पर निर्भर करेगा (देखें चित्र 4.1)।

19 हुक 2012

20 लाफ्रानेयर 2011; वाइन्स और लाफ्रानेयर 2011

21 अमर्त्य सेन ने इस अंतर के बारे में बताया: अनुचित अपवर्जन का अर्थ है कि कुछ लोगों को बाहर रखा गया है या छोड़ दिया गया है; अन्यायपूर्ण अपवर्जन का अर्थ है कि कुछ लोगों को अत्यधिक प्रतिकूल शर्तों पर शामिल किया गया है (एपीआरआई 2003)।

22 हंटिंगटन (1968), कैपैन्ट तथा कोर (2012) में उद्धत।

23 कैपैन्ट तथा कोर (2012) देखें।

24 वर्ष 1980-2011 के दौरान 78 देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय उपलब्धियों पर आधारित। इसके विपरीत समान अवधि के दौरान कुछ देशों में विद्यालयीय शिक्षा की अवधि, स्वास्थ्य और आय उपलब्धियों के औसत वर्ष विपरीत रहे हैं।

25 कैपैन्ट तथा कोर 2012

26 कैपैन्ट तथा कोर 2012, पेज 175

27 पोल्यानी 1944

28 फित्ज़जेरॉल्ड, स्टीवर्ट और वेणुगोपाल 2006

29 उदाहरण के लिए गुआंग्डोंग प्रांत और लियाओनिंग प्रांत का एचआईडी मूल्य समान है, लेकिन लियाओनिंग के मुकाबले गुआंग्डोंग का कार्बन उत्सर्जन तीन गुना अधिक है (यूएनडीपी 2010ग।

30 यूएनडीपी 2011अ

31 अधिक जानकारी के लिए यूएनडीपी (2011अ) देखें।

32 आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति ने लोच-बल को इस प्रकार परिभाषित किया है, ÷किसी तंत्र, समुदाय या समाज में खतरों को उजागर कराने की क्षमता, ताकि उसका प्रतिरोध किया जा सके, उसे अवशोषित और समायोजित किया जा सके और खतरों के असर से समय रहते प्रभावशाली ढंग से उबरने की क्षमता, जिसमें बुनियादी संरचना और कार्यप्रणाली का संरक्षण और बहाली शामिल है।÷ (आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय 2009)।

33 डैनियल और वर्वीक 2012

34 आईपीसीसी 2012

35 जनसंख्या के प्रत्येक आयु वर्ग की विभिन्न ज़रूरतें होती हैं और वे अलग बर्ताव करते हैं। बाल जनसंख्या (0-14 वर्ष) के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश ज़रूरी है। कार्यशील व्यस्कों (15-65) को रोज़गार और वित्तीय बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत होती है, ताकि उत्पादन तथा बचता को प्रोत्साहन दिया जा सके। उम्रदराज़ व्यस्कों (65 वर्ष और अधिक) को स्वास्थ देखभाल और सेवानिवृत्ति आय की ज़रूरत होती है। इस तरह किसी देश की आयु संरचना उसकी चुनौतियाँ और अवसरों को बदल देती है।

36 चूँकि कुछ ही बच्चों का पालन करना है, इसलिए माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते है (बेकर, मर्फी और तामूरा 1990, ग्लोर 2006), अपनी सेवानिवृत्ति के लिए अधिक बचत करते हैं (ब्लूम, कैनिंग और सेविला 2003), और महिलाएँ अधिक संख्या में औपचारिक श्रम बाज़ार में भागीदार बनती हैं (ब्लूम और अन्य 2009)। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक वृद्धि तेज होती है, जिससे जनसाँयिकी जनसाँयिकी लाभांश बढ़ता है (ब्लूम, कैनिंग और सेविला 2003)।

37 आश्रितों द्वारा खर्च की निम्न माँग को देखते हुए निम्न निर्भरता अनुपात की स्थिति में जनसाँयिकी लाभांश बढ़ सकता है। श्रम बल में वृद्धि आर्थिक विकास और अधिक निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है। (लुत्ज़ और केसी 2013 के पूर्वानुमानों पर आधारित जनसाँयिकी रुझानों के विस्तृत विश्लेषण के लिए अबदुराजाकोव, मिनसेट और पिनेडा (2013) देखें)। लेकिन देश इन लाभांशों का फायदा तभी उठा सकते हैं जबकि वे श्रम बल में बड़ी संख्या में नये शामिल लोगों को लाभकारी रोज़गार मुहैया करा सकें।

38 लुत्ज़ और केसी 2013

39 शिक्षा स्तर वितरण का ऐसा परिदृश्य जहाँ सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा व्यापक आधार वाली द्वितीयक शिक्षा द्वारा परिपूर्ण की जाती है, वहाँ युवा लोगों की बड़ी हिस्सेदारी वाले निम्न एचडीआई देशों में अत्यधिक वार्षिक आर्थिक वृद्धि देखने को मिलती है (आईआईएएसए 2008)। इस विश्लेषण में उन आँकड़ों का इस्तेमाल किया गया है जो प्रत्येक देश की जनसंख्या को आयु, लिंग और शैक्षिक योग्यता के रूप में विभाजित हैं। ऐसे में प्रत्येक पाँच वर्षीय जनसंख्या समूह की हिस्सेदारी को अशिक्षित, प्राथमिक शिक्षा, द्वितीयक शिक्षा या तृतीयक शिक्षा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इन योग्यताओं को लिंग के आधार पर अलग-अलग किया जा सकता है। जन्म दर, मृत्यु दर और विस्थापन के रूझानों के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षीय समूह में जनसंख्या की बनावट बदल जाती है। इसी प्रकार समय के साथ युवा, कार्यशील आयु और वृद्ध आबादी का अनुपात भी बदल जाता है।

40 यह नज़रिया सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों और सर्व शिक्षा पहल के अनुरूप ही है। इस परिदृश्य के कई प्रमुख लक्ष्य हैं- 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (99 प्रतिशत), 2030 तक 50 प्रतिशत और 2030 तक 90 प्रतिशत निम्न माध्यमिक शिक्षा, और 2050 तक 60 प्रतिशत तृतीयक शिक्षा।

41 एचडीआरओ गणना लुत्ज़ और केसी (2013) पर आधारित है।

42 यूएनडीईएसए 2007। विकसित देशों के लिए, अंतरराष्ट्रीय विस्थापन पौढ़ जनसंख्या के आर्थिक प्रभावों को कम नहीं कर सकेगा क्योंकि आवश्यक विस्थापन की मात्रा राजनीतिक रूप से संभव मात्रा के मुकाबले काफ़ी अधिक है। अध्ययन के परिदृश्य तीन में, 1995-2050 के दौरान पौढ़ आबादी के अनुपात में आनुमानित वृद्धि को रोकने के लिए जितने विस्थापन की ज़रूरत है, वह ब्रिटेन के लिए औसतन वार्षिक 11 लाख लोगों का अंतर्प्रवाह, फ्रांस के लिए 17 लाख और जापान तथा अमेरिका दोनों के लिए 1 करोड़ से अधिक है।

43 बेकर, मर्फी और तमूरा 1990; ग्लोर 2006; ब्लूम, केनिंग और सेविला 2003; ब्लूम और अन्य 2009।

44 ब्लूम और अन्य 2012। सब-सहारा अफ्रीका में युवा निर्भरता अनुपात 20 प्रतिशत सबसे ग़रीब परिवारों के लिए 1.07 और 20 प्रतिशत सबसे धनी परिवारों के लिए 0.72 है। लैटिन अमेरिका में सबसे ग़रीब परिवारों के लिए अनुपात 0.91 और सबसे धनी परिवारों के लिए 0.57 प्रतिशत है।

45 ब्लूम और अन्य (2012) अध्ययन के मेुय परिणामों पर चर्चा के लिए दि इकॉनामिस्ट (2012ब) देखें।

46 हॉसमैन और सेकेयी (2001) ने पाया कि लैटिन अमेरिका में जनसांख्यिकी बदलावों ने मौजूदा असमानता के रुझानों को अधिक स्पष्ट कर दिया। वहाँ अत्यधिक धनी जनसंख्या समूह में काफ़ी तेजी से और काफ़ी पहले जनसांख्यिकी बदलाव देखने को मिले, जिससे अमीर और ग़रीब के बीच का अंतर अधिक चौड़ा हो गया। गिरौक्स (2008) ने पाया कि यद्यपि शिक्षा के साथ जुड़ी जन्म दर विविधता सब-सहारा अफ्रीकी देशों में तुलनात्मक रूप से स्थिर रही है, लेकिन राष्ट्रीय जन्म दर घटने के साथ ही असमानता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि जनसंख्या के शैक्षिक गठन में बदलावों ने क्षेत्र में प्रजनन असमानता के हालिया परिवर्तन को आकार दिया है।

47 ब्लूम और अन्य 2012

48 विश्व बैंक 2011सी

49 कई देशों में यदि सेवानिवृत्ति की मौजूदा उम्र को न बदला जाये, यह खिड़की कुछ दशकों में बंद हो जायेगी। इससे पता चलता है कि कई देशों में जहाँ जनसंख्या तेजी से वृद्ध हो रही है, वहाँ सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा जोर पकड़ती जायेगी।

50 पिछले खंड में जनसांख्यिकी रुझानों में विस्थापन की भूमिका पर चर्चा की गयी; यहाँ विस्थापन की भूमिका अधिक व्यापक है क्योंकि यह पूरी तरह से एक ऐसे मॉडल के साथ एकीकृत है, जिसमें जनसांख्यिकी रुझान इन पूर्वानुमान अेयास में इस्तेमाल किये गये कई मापांक में से एक है।

अध्याय 5

1 व्यापार वार्ताओं का दोहा चक्र 2008 से ठप है (कासल एंड लैंडलर 2008 : डब्ल्यूटीओ 2012 एनडी) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा समझौते के दिसेबर 2012 दोहा में हुए 18 वें सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के बाध्यकारी मेुय समझौते क्योटो संधि को

सन 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। देशों ने इस बात को दोहराया कि वे सन 2015 में एक नई ÷ संधि, एक विधिक उपकरण अथवा विधिक शक्ति सेपन्न परिणाम÷ तैयार कर लेंगे जो 2020 से प्रभावी होगी। हालाँकि नए प्रोटोकॉल की संरचना और वित्तीय क्रिया पद्धति को तय करने का काम अगले साल तक के लिए छोड़ दिया गया (ब्रोडर 2012ऱ हार्वे 2012)

2 हैलर 2012 .

3 वैश्विक सार्वजनिक साधन वे हैं, जिनका प्रभाव सीमा-पार तक होता है। राष्ट्रीय सरकारें अपनी कोशिशों से, और बाज़ार भी, पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक साधनों की आपूर्ति नहीं कर पाते। इसके लिए सामूहिक अन्तर-शासन पहल की आवश्यकता होती है। ऐसी दुनिया में जहाँ व्यापार, वित्तीय प्रवाह, पर्यावरणीय संसाधन और प्रदूषण लगातार राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाकर प्रभावित करते हैं, मानव विकास के लिए आवश्यक सार्वजनिक साधनों को जुटाने के लिए आपूर्ति बहुपक्षीय सहयोग ज़रूरी हो जाता है (कौल 2013)

4 जहाँ द्विपक्षीय व्यवस्थाएँ कई बार कमज़ोर भागीदार के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ अमीरों देशों के साथ वार्ताओं में ग़रीब इलाकों के लिए मददगार हो सकती हैं।

5 इसे व्यापार पथांतर कहते हैं। व्यापार बढ़ाने के लिए शुल्क बाधाओं को कम करना, व्यापार रचना कहलाता है। देखें क्रूगमान (1991)

6 देखें क्रूगमान (1991) जो आगे कहते हैं कि वैश्विक कार्यकुशलता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की सेभावना नहीं होती क्योंकि व्यापारिक ब्लॉक भौगोलिक पड़ोसियों से बनते हैं। चूँकि ये देश विशेष व्यवस्थाओं के बग़ैर भी स्वाभाविक व्यापार सहयोगी होते हैं, इसलिए व्यापार पथांतर से नुकसान बहुत छोटा होता है, जबकि व्यापार रचना से लाभ काफ़ी बड़ा होता है।

7 क्षेत्रीयता के बहुपक्षीयकरण के लिए व्यापार नियमनों की विविधता को (जैसे कि स्थानीय सामग्री के मूल को तय करने के विविध नियम) एकरूपता देने और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को विस्तार देने की ज़रूरत होगी, जिसमें यथासेभव ज़्यादा से ज़्यादा विकासशील देशों को शामिल किया जाए। ये विचार बाल्डविन (2007) में।

8 अंतरराष्ट्रीय प्रवास संगठन के पास, जो संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का अंग नहीं है, किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था के प्रवास सेबद्ध मसलों पर सबसे व्यापक अधिदेश हैं। 146 सदस्य देशों के साथ यह अंतरराष्ट्रीय प्रवास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच बन गया है।

9 यूएनडीपी 2009

10 हैनसेन 2010

11 बैट्स तथा अन्य 2012

12 किंग, रिचर्डस और टिल्डैस्ले 2011

13 यूएनडीपी 2011a

14 हान 2012

15 लीप 2012

16 लीप 2012

17 रोमेरो और ब्रॉडर 2012

18 ग्लेनी 2011

19 ओ.ई.सी.डी. 2011c

20 जी8 2005

21 ओकैपो 2010

22 शासनाध्यक्षों के महासभा-सेबोधन 25 सितेबर-1 अक्टूबर (संयुक्त राष्ट्र समाचार सेवा http://www.un.org/news)

23 जी-20 के लॉस काबोस (2012 में) शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील, चीन, भारत, रूसी संघ और दक्षिण अफ्रीका ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों में 75 अरब डॉलर के योगदान की घोषणा की। यह संसाधन अनेक शर्तों से बँधे हैं। इसका इस्तेमाल तभी होगा जब वर्तमान साधन काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल हो जाएं। धनराशि इस आशा पर दी गई है कि

‘सन 2010 में जिन सुधारों पर सहमति बनी थी वे समयबद्ध तरीके से पूरी तरह लागू हो जाएंगे, जिसमें मतदान की शक्ति और कोटा शेयर में व्यापक सुधार शामिल हैं।’ चॉवला (2012)

24 हैलर 2013

25 इस वीडियो को 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा और यह सार्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय वीडियो में एक है।

26 चंढोक 2009ऱ हैलर 2013

27 यह कई रूप ले सकता है - ग़ैर सरकारी संगठनों के लिए बाध्यकारी नियम, विदेशी मुद्रा और टैक्स विनियमन, पंजीकरण आवश्यकताएं आदि। सरकारें इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, ग़ैर सरकारी संगठनों की ज़वाबदेही न होना, समन्वय व नियंत्रण जैसे आधारों पर उचित ठहराती हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर नॉन प्रॉफिट लॉ और CIVICUS वैश्विक स्तर पर इसके बारे में सूचनाएं देने और विश्लेषण का काम करते रहे हैं।

28 कैस्टेल्स 2003 ः बूरावॉय 2003

29 ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतकार एंड्र्यू डॉबसन ने ‘पारिस्थितिकीय नागरिकता’ की अवधारणा करी। पारिस्थितिकी के संदर्भ में विचार करना नागरिकता के व्यापक पक्ष को प्रकट करता है। जिसमें पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट को कम करने का लक्ष्य शामिल है। पारिस्थितिकीय नागरिकता व्यक्तिगत दायित्व से बाहर जाकर काम करती है, क्योंकि पारिस्थितिकीय चिंतन नागरिक को समुदाय (और उसके परिस्थितिक तंत्र) का उत्पाद और उसे प्रभावित करने वाला मानता है। (रेवकिन 2012)

30 शोरेव 2012

31 ग्रेबेल 2012। उपयोगी सारांश के लिए लैबर्ट और मॉर्गन (2012) को भी देखें।

32 भारत का रिज़र्व बैंक 2012

33 ग्रेबेल 2013

34 ओकैपो और टाइटेलमैन 2009

35 ग्रेबेल 2013

36 बैंक ऑफ द साउथ की स्थापना वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज़ ने सन 2007 में की थी और इसका आधिकारिक रूप से सन 2009 में उद्घाटन किया गया। मूल रूप में इसका बहुत व्यापक लक्ष्य था, पर 2009 में इसका उद्घाटन आते-आते इसका कार्यक्षेत्र दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तीयन तक सीमित हो गया (चिन 2010)। इसके स्पष्ट कार्यों और लक्ष्यों को लेकर सदस्य देशों के बीच विमर्श जारी है।

37 ओईसीडी 2010a

38 बाल्डविन 2006

39 देखें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (2011), जिसमें ब्राज़ील सरकार द्वारा विकसित, संरक्षण के साथ दायित्व का अवधारणा पत्र शामिल है।

40 भारत का विदेश मंत्रालय 2012

41 भट्टाचार्य, रोमानी और स्टर्न 2012

42 भट्टाचार्य, रोमानी और स्टर्न 2012

43 क्षेत्र में सन 2005 से 2010 के बीच प्रत्येक देश के औसत व्यय की एचडीआरओ गणना विश्व बैंक (2012इ) आँकड़ों पर आधारित।

44 एचडीआरओ गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्राभंडार के विश्व बैंक (2012इ) आँकड़ों पर आधारित। यह देखते हुए कि अंतरराष्ट्रीय कोष मौद्रिक और विनिमय दर नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोष के बड़े हिस्से को अन्य कार्यों के लिए आबंटित करने की आशा करना महत्वाकांक्षी होगा।

45 कुछ लोगों ने एक वैश्विक अधोसंरचना पहल का प्रस्ताव किया है, ताकि अमीर देश अपनी निवेश पूँजी को विकासशील देशों में लगाएं जहाँ उन्हें अपने देश में निवेश पर मिलने वाले लाभ से बेहतर लाभ मिलें (हार्डिंग 2012) । यह सिद्धांत उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के निवेश पर लागू होता है।

46 बोल्टन, समामा और स्टिग्लिट्ज़ 2011। नार्वे ने भी ब्राज़ील को उसके वनोन्मूलन रोकने के प्रयासों के लिए 1 अरब डॉलर की पेशकश की। हालाँकि यह राशि उसके सेप्रभु कोष से नहीं मिलेगी।

47 सार्वजनिक और निजी भागीदारी तथा सामुदायिक पहलें भी सेप्रभु कोषों के निवेश के दायरे और प्रभाव को बढ़ा सकती हैं।

48 देखें हमदानी (2012) और दक्षिण आयोग (1990)

49 दक्षिण आयोग कई साल तक दक्षिण के नेताओं के बीच चले अनौपचारिक विमर्श के बाद औपचारिक रूप से 1987 में स्थापित हुआ था। दक्षिण आयोग की रपट (1990) ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकासशील देशों की अनेक समस्याएं और अनुभव समान हैं। यह पाया गया कि वैश्विक स्तर पर दक्षिण अच्छी तरह से संगठित नहीं है अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और सौदा-शक्ति का प्रभावकारी इस्तेमाल नहीं कर पाया है। रिपोर्ट में सेबद्ध नीति-निर्माताओं को व्यावहारिक सुझाव दिए गए थे।

50 ऐवासे और यांग 2012

51 ओ.ई.सी.डी. 2010a

संदर्भ

Abdurazakov, A., A. Minsat, and J. Pineda. 2013. "Implications of Education Policies in a Country's Demographic Prospects: Detailed Analysis of Demographic Trends Based on Projections by Lutz and KC." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Abe, M. 2006. "The Developmental State and Educational Advance in East Asia." *Educate* 6 (1): 6–12.

ADB (Asian Development Bank). **2009.** *Annual Report 2009*. Vol. 1. Manila. www.adb.org/documents/adb-annual-report-2009. Accessed 15 May 2012.

AfDB (African Development Bank), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), UNDP (United Nations Development Programme), and UNECA (United Nations Economic Commission for Africa). 2011. *African Economic Outlook 2011: Africa and Its Emerging Partners*. Paris and Tunis.

———. 2012. *African Economic Outlook 2012: Promoting Youth Employment*. Paris and Tunis.

Agosin, M. 1997. "Trade and Growth in Chile: Past Performance and Future Prospects." United Nations Economic Commission for Latin America, International Trade Unit, Santiago. www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/4234/P4234.xml&xsl=/comercio/tpl-i/p9f.xsl&base=/comercio/tpl/top-bottom.xsl. Accessed 15 May 2012.

Ahluwalia, M.S. 2002. "Economic Reforms in India since 1991: Has Gradualism Worked?" *Journal of Economic Perspectives* 16 (3): 67–88.

Akyuz, Y. 2012. "The Staggering Rise of the South." Research Paper 44. South Center, Geneva.

Aleksynska, M., and O. Havrylchyk. 2011. "FDI from the South: The Role of Institutional Distance and Natural Resources." Working Paper 2011-05. Centre D'Études Prospectives et D'Informations Internationales, Paris. www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/pdf/2011/wp2011-05.pdf. Accessed 15 May 2012.

Ali, S., and U. Dadush. 2012. *In Search of the Global Middle Class: A New Index*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace. http://carnegieendowment.org/files/middle_class-edited.pdf. Accessed 4 October 2012.

AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office). 2012. "The Joint Statement of the 15th ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting." Manila. www.amro-asia.org/wp-content/uploads/2012/05/120503AFMGM+3-JS.pdf. Accessed 31 May 2012.

Anand, S., and P. Segal. 2008. "What Do We Know about Global Income Inequality?" *Journal of Economic Literature* 46: 57–94.

Anderson, L. 2011. "Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences between Tunisia, Egypt, and Libya." *Foreign Affairs* 90 (3): 2–7.

APRI (Asia Pacific Regional Human Development Reports Initiative). 2003. "Potential and Challenges in Human Development Reporting." Report of the UNDP Training Workshop, 24–26 September 2003, Colombo, Sri Lanka. UNDP Asia-Pacific Regional Centre, Bangkok.

Arrighi, G. 2007. "China's Market Economy in the Long Run." In Ho-Fung Hung, ed., *China and the Transformation of Global Capitalism*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Athukorala, P. 2011. "Production Networks and Trade Patterns in East Asia: Regionalization or Globalization?" *Asian Economic Papers* 10 (1): 65–95.

Athukorala, P., and S. Waglé. 2011. "Foreign Direct Investment in Southeast Asia: Is Malaysia Falling Behind?" *ASEAN Economic Bulletin* 28 (2): 115–33.

Atkinson, A. 2011. "Public Economics after the Idea of Justice." 1st Annual Amartya Sen Lecture, 5 September, The Hague, The Netherlands. www.ethicsandtechnology.eu/images/uploads/1stAnnualAmartyaSenLecture_TonyAtkinson.pdf. Accessed 15 May 2012.

———. 2012. "Public Economics in an Age of Austerity." Agnar Sandmo Lecture, 12 January, Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, Norway.

Atsmon, Y., P. Child, R. Dobbs, and L. Narasimhan. 2012. "Winning the $30 Trillion Decathlon: Going for Gold in Emerging Markets." *McKinsey Quarterly*, August. www.mckinseyquarterly.com/Winning_the_30_trillion_decathlon_Going_for_gold_in_emerging_markets_3002. Accessed 15 August 2012.

Ayadi, M., G. Boulila, M. Lahoulel, and P. Montigny. 2005. "Pro-Poor Growth in Tunisia." International Development and Strategies, Paris.

Baer, W. 2008. *The Brazilian Economy: Growth and Development*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Baldwin, R.E. 2004. "Openness and Growth: What's the Empirical Relationship? In R.E. Baldwin and L.A. Winters, eds., *Challenges to Globalization: Analyzing the Economics*. Chicago, IL: University of Chicago Press. www.nber.org/chapters/c9548.pdf. Accessed 6 August 2012.

———. 2006. "Multilateralizing Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocks on the Path to Global Free Trade." *World Economy* 29 (11): 1451–1518.

———. 2007. "Ideas for a WTO Action Plan on Regionalism: Implications for Asia." Post-event Statement. Asian Development Bank Institute Distinguished Speaker Seminar, 26 November, Tokyo. www.adbi.org/event/2366.dance.east.asia.reflections/. Accessed 23 October 2012.

Barro, R.J., and J.-W. Lee. 2010. Educational Attainment Dataset. www.barrolee.com. Accessed 5 May 2012.

Becker, G., K. Murphy, and R. Tamura. 1990. "Human Capital, Fertility, and Economic Growth." *Journal of Political Economy* 98 (5): S12–S37.

Beeston, K. 2012. "Time for Democracy 2.0? The Launch of the Manifesto For A Global Democracy." *Global Policy Journal*, 5 July. www.globalpolicyjournal.com/blog/05/07/2012/time-democracy-20-launch-manifesto-global-democracy. Accessed 28 December 2012.

Bera, S., and S. Gupta. 2009. "South-South FDI vs. North-South FDI: A Comparative Analysis in the Context of India." Working Paper 238. Indian Council of Research in International Economic Relations, New Delhi. www.icrier.org/pdf/WorkingPaper238.pdf. Accessed 15 May 2012.

Berg, J., and S. Cazes. **2007.** "The Doing Business Indicators: Measurement Issues and Political Implications." Economic and Labour Market Paper 2007/6. International Labour Organization, Geneva.

Bertrand, M., and S. Mullainathan. 2003. *Are Emily and Greg More Employable than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor and Market Discrimination*. Working Paper 9873. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. www.nber.org/papers/w9873. Accessed 15 May 2012.

Betts, A., J. Prantl, D. Sridhar, and N. Woods. 2013. "Transforming Global Governance for the Twenty-First Century." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York. www.spp.nus.edu.sg/docs/HDR-GEG2012-LKYSPP.pdf. Accessed 15 May 2012.

Bhagwati, J., and Srinivasan, T. 2001. "Outward-Orientation and Development: Are Revisionists Right?" In D. Lal and R. Snape, eds., *Trade, Development, and Political Economy*. London: Palgrave.

Bhattacharya, A., M. Romani, and N. Stern. 2012. "Infrastructure for Development: Meeting the Challenge." Centre for Climate Change Economics and Policy, London. www.cccep.ac.uk/Publications/Policy/docs/PP-infrastructure-for-development-meeting-the-challenge.pdf. Accessed 15 May 2012.

Bird, L.A. 1981. *Costa Rica: A Country without an Army*. Bolton, UK: Leeds Northern Friends Peace Board.

Bland, B. 2012. "Vietnam's Factories Grapple with Growing Unrest." *Financial Times*, 19 January. www.ft.com/intl/cms/s/0/67380b5c-427e-11e1-97b1-00144feab49a.html. Accessed 21 December 2012.

Blanden, J., A. Goodman, P. Gregg, and S. Machin. 2005. "Changes in Intergenerational Income Mobility in Britain." In M. Corak, ed., *Generational Income Mobility in North America and Europe*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Blinder, A. 2006. "Offshoring: The Next Industrial Revolution?" *Foreign Affairs* 85 (2): 113.

Block, F. 2008. "Swimming Against the Current: The Rise of a Hidden Developmental State in the United States." *Politics and Society* 36 (2): 169–206.

———. 2013. "Can the Path of the World's Richer Nations be Sustained? The Future of the U.S. Model." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Bloom, D.E., D. Canning, G. Fink, and J.E. Finlay. 2009. "Fertility, Female Labor Force Participation, and the Demographic Dividend." *Journal of Economic Growth* 14 (2): 79–101.

———. 2012. "Microeconomic Foundations of the Demographic Dividend." Working Paper 93. Harvard University, Program on the Global Demography of Aging, Cambridge, MA. www.hsph.harvard.edu/pgda/WorkingPapers/2012/PGDA_WP_93.pdf. Accessed 27 December 2012.

Bloom, D.E., D. Canning, and J. Sevilla. 2003. *The Demographic Dividend: A New Perspective on the*

Economic Consequences of Population Change. Santa Monica, CA: Rand Corporation.

———. **2007.** "The Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach." Working Paper 28. Harvard University, Program on the Global Demography of Aging, Cambridge, MA. www.hsph.harvard.edu/pgda/WorkingPapers/2007/PGDA_WP_28.pdf. Accessed 10 August 2012.

Bolton, P, F. Samama, and J. Stiglitz. 2011. *Sovereign Wealth Funds and Long-Term Investing*. New York: Columbia University Press.

Bourguignon, F., F.H.G. Ferreira, and M. Menéndez. 2007. "Inequality of Opportunity in Brazil." *Review of Income and Wealth* 53 (4): 585–618.

Bourguignon, F., and C. Morrisson. 2002. "Inequality among World Citizens: 1820–1992." *American Economic Review* 92 (4): 727–744.

BRAC. n.d. "About BRAC Bangladesh." www.brac.net/content/about-brac-bangladesh. Accessed 15 May 2012.

Bradsher, K. 2010. "China Leading Global Race to Make Clean Energy." *The New York Times*, 30 January. www.nytimes.com/2010/01/31/business/energy-environment/31renew.html. Accessed 15 May 2012.

Branczik, A. 2004. "Humanitarian Aid and Development Assistance." Beyond Intractability. www.beyondintractability.org/bi-essay/humanitarian-aid. Accessed 15 May 2012.

Bräutigam, D. 2009. *The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Bremmer, I. 2012. "Africa and the Power of the Pivot." *The New York Times*, 14 May. www.nytimes.com/2012/05/15/opinion/africa-and-the-power-of-the-pivot.html. Accessed 15 May 2012.

Broder, J.M. 2012. "Climate Talks Yield Commitment to Ambitious, but Unclear, Actions." *The New York Times*, 8 December. www.nytimes.com/2012/12/09/science/earth/talks-on-climate-produce-promises-and-complaints.html. Accessed 8 December 2012.

Brookings Institution. 2012. "Middle Class Measures." Development, Aid and Governance Indicators. Washington, DC. www.brookings.edu/research/interactives/development-aid-governance-indicators. Accessed 4 October 2012.

Burawoy, M. 2003. "For A Sociological Marxism: The Complementary Convergence of Antonio Gramsci and Karl Polanyi." *Politics and Society* 31 (2): 193–261.

Burd-Sharp, S., and K. Lewis. 2010. *The Measure of America 2010–2011: Mapping Risks and Resilience*. New York: NYU Press.

Cammett, M. 2007. "Business-Government Relations and Industrial Change: The Politics of Upgrading in Morocco and Tunisia." *World Development* 35 (11): 1889–1903.

Campante, F., and D. Chor. 2012. "Why Was the Arab Spring Poised for Revolution? Schooling, Economic Opportunities, and the Arab Spring." *Journal of Economic Perspectives* 26 (2): 167–188.

Castells, M. 2003. *The Power of Identity*. Malden, MA: Blackwell.

Castle, S., and M. Landler. 2008. "After 7 Years, Talks Collapse on World Trade." *The New York Times*, 30 July.

Celasun, M. 1994. "Trade and Industrialization in Turkey: Initial Conditions, Policy and Performance in the 1990s." In G. Helleiner, ed., *Trade and Industrialization in Turbulent Times*. London: Routledge.

Center for Systemic Peace. 2012. "Global Conflict Trends: Measuring Systemic Peace." Vienna, VA. www.systemicpeace.org/conflict.htm. Accessed 15 May 2012.

Chandhoke, N. 2009. "What Is the Relationship Between Participation and Representation?" In O. Törnquist, N. Webster, and K. Stokke, eds. *Rethinking Popular Representation*. New York: Palgrave Macmillan.

Chang, H.J. 2010. "How to 'Do' a Developmental State: Political, Organizational and Human Resource Requirements for the Developmental State." In O. Edigheji, ed., *Constructing a Democratic Developmental State in South Africa, Potentials and Challenges*. Cape Town: HSRC Press.

Chen, S., and M. Ravallion. 2012. "More Relatively-Poor People in a Less Absolutely-Poor World." Policy Research Working Paper 6114. Washington, DC, World Bank.

Cheng, H., Y. Hu, and J. Zhao. 2009. "Meeting China's Water Shortage Crisis: Current Practices and Challenges. *Environmental Science & Technology* 43 (2): 240–244.

Chibber, V. 1999. "Building a Developmental State: The Korean Case Reconsidered." *Politics & Society* 27 (3): 309–346.

Chin, G. 2010. "Remaking the Architecture: The Emerging Powers, Self-Insuring and Regional Insulation." *International Affairs* 86 (3): 693–715.

———. **2012.** "Responding to the Global Financial Crisis: The Evolution of Asian Regionalism and Economic Globalization." Working Paper 343. Asian Development Bank Institute, Tokyo. www.adbi.org/working-paper/2012/01/31/4846.gfc.evolution.asian.regionalism.economic.globalization/. Accessed 15 May 2012.

***China Daily*. 2012.** "Overseas M&A Deals Hit $43b in 2011." 27 February. www.chinadaily.com.cn/bizchina/2012-02/27/content_14703801.htm. Accessed 15 May 2012.

Chorev, N. 2012. *The World Health Organization between North and South*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Chowla, P. 2012. "Spotlight G20: Does BRICS Money for the IMF Mean They Are Bailing Out Europe?" 21 June. Triple Crisis: Global Perspectives on Finance, Development, and Environment. http://triplecrisis.com/spotlight-g-20-does-brics-money-for-the-imf-mean-they-are-bailing-out-europe/. Accessed 8 December 2012.

Chuhan-Pole, P., and M. Angwafo, eds. 2011. *Yes Africa Can: Success Stories From A Dynamic Continent*. Washington, DC: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/258643-1271798012256/YAC_Consolidated_Web.pdf. Accessed 10 August 2012.

Ciorciari, J. 2011. "Chiang Mai Initiative, Multilateralization International Politics and Institution-Building in Asia." *Asian Survey* 51 (5): 926–952.

Clapp, R.A. 1995. "Creating Comparative Advantage: Forest Policy as Industrial Policy in Chile." *Economic Geography* 71 (3): 273–296.

Cleland, J. 2002. "Education and Future Fertility Trends with Special Reference to Mid-Transitional Countries." United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York. www.un.org/esa/population/publications/completingfertility/RevisedCLELANDpaper.PDF. Accessed 15 May 2012.

Cochrane, S.H. 1979. *Fertility and Education: What Do We Really Know?* Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Commission on Growth and Development. 2008. *The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development*. Washington, DC: World Bank.

Cornia, G.A. 2004. *Inequality, Growth and Poverty in an Era of Liberalization and Globalization*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Dahal, S.H., H. Gazdar, S.I. Keethaponcalan, and P. Murthy. 2003. "Internal Conflict and Regional Security in South Asia." United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva. www.unidir.org/pdf/ouvrages/pdf-1-92-9045-148-3-en.pdf. Accessed 15 May 2012.

Dalton, R., A. Van Sickle, and S. Weldon. 2010. "The Individual–Institutional Nexus of Protest Behaviour." *British Journal of Political Science* 40 (1): 51–73.

Daniell, J., and A. Vervaeck. 2012. "Damaging Earthquakes Database 2011—the Year in Review." Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology, Potsdam, Germany. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3285.pdf.

Das, G. 2000. *India Unbound: The Social and Economic Revolution from Independence to the Global Information Age*. New York: Anchor Books.

Davies, J.E. 2011. "Washington's Growth and Opportunity Act or Beijing's Overarching Brilliance: Will African Governments Choose Neither?" *Third World Quarterly* 32 (6): 1147–1163.

De Hoyos, R., J.M. Martínez de la Calle, and M. Székely. 2009. "Education and Social Mobility in Mexico." Mexico Education Ministry, Mexico City. www.pegnet.ifw-kiel.de/activities/de_hoyos_de_la_calle_szekely2009.pdf. Accessed 15 May 2012.

Deloitte. 2011. "The Connected Archipelago: The Role of the Internet in Indonesia's Economic Development." Deloitte Access Economics, Sydney. www.deloitte.com/view/en_gx/global/bde64a5db2134310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm. Accessed 15 May 2012.

———. **2012a.** "Lateral Trades, Breathing Fire into the BRICS: China Outbound M&A Activity into Brazil, Russia, India and South Africa." China Services Group, Beijing. www.deloitte.com.mx/documents/BoletinFactorChina/LateralTrades-BreathingFireintotheBRICS-English.pdf. Accessed 21 June 2012.

———. **2012b.** "Turkish Outbound M&A." Corporate Finance, Istanbul. www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/turkey_tr_mnaoutbound_27012012.pdf. Accessed 10 May 2012.

DeLong, J.B. 2004. "India since Independence: An Analytic Growth Narrative." In D. Rodrik, ed., *Modern Economic Growth: Analytical Country Studies*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Diamond, I., M. Newby, and S. Varle. 1999. "Female Education and Fertility: Examining the Links." In C. Bledsoe, J. Casterline, J. Johnson-Kuhn, and J. Haaga, eds., *Critical Perspectives on Schooling and Fertility in the Developing World*. Washington, DC: National Academy of Science Press.

Dobbs, R., J. Remes, J. Manyika, C. Roxburgh, S. Smit, F. Schaer. 2012. *Urban World: Cities and the Rise of the Consuming Class*. New York: McKinsey Global Institute. www.mckinsey.com/insights/mgi/research/urbanization/

urban_world_cities_and_the_rise_of_the_consuming_class. Accessed 28 August 2012.

Dolan, P., R. Layard, and R. Metcalfe. 2011. *Measuring Subjective Well-Being for Public Policy.* London: UK Office for National Statistics.

Dollar. D. 1992. "Outward-Oriented Developing Countries Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976–85." *Economic Development and Cultural Change* 40 (30): 523–544.

Done, K. 2011. "Embraer Faces Headwinds." *Financial Times*, 10 October.

Drèze, J., and M. Murthi. 1999. "Fertility, Education and Development: Further Evidence from India." Research Paper DEDPS20. London School of Economics, Suntory and Toyota Centres for Economics and Related Disciplines, London, UK.

Duhigg, C., and K. Bradsher. 2012. "How the U.S. Lost Out on iPhone Work." *The New York* Times, 21 January. www.nytimes.com/2012/01/22/business/apple-america-and-a-squeezed-middle-class.html. Accessed 22 January 2012.

Duhigg, C., and S. Greenhouse. 2012. "Electronic Giant Vowing Reforms in China Plants." *The New York Times*, 30 March. www.nytimes.com/2012/03/30/business/apple-supplier-in-china-pledges-changes-in-working-conditions.html. Accessed 15 May 2012.

***The Economist*. 2011a.** "The Magic of Diasporas." 19 November. www.economist.com/node/21538742. Accessed 15 May 2012.

———. 2011b. "South-North FDI: Role Reversal." 24 September. www.economist.com/node/21528982. Accessed 15 May 2012.

———. 2012a. "Indian Takeovers Abroad: Running with the Bulls." 3 March. www.economist.com/node/21548965. Accessed 15 May 2012.

———. 2012b. "Points of Light." 14 July. www.economist.com/node/21558591. Accessed 4 November 2012.

Edigheji, O. 2010. *Constructing a Democratic Developmental State in South Africa: Potentials and Challenges*. Cape Town: HSRC Press.

Edwards, S. 1998. "Openness, Productivity, and Growth: What Do We Really Know?" *Economic Journal* 108 (447): 383–398.

Elson, D. 2002. "Gender Justice, Human Rights and Neo-liberal Economic Policies." In M. Molyneux and S. Razavi, eds., *Gender Justice, Development and Rights*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Engerman, S.L., and K.L. Sokoloff. 2002. *Factor Endowments, Inequality, and Paths of Development among New World Economics.* Working Paper 9259. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. www.nber.org/papers/w9259. Accessed 15 May 2012.

Essama-Nssah, B. 2011. "Achieving Universal Primary Education through School Fee Abolition: Some Policy Lessons from Uganda." In P. Chuhan-Pole and M. Angwafo, eds., *Yes Africa Can: Success Stories From A Dynamic Continent*. Washington, DC: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/258643-1271798012256/YAC_Consolidated_Web.pdf. Accessed 10 August 2012.

Estevadeordal, A., B. Frantz, and A.M. Taylor. 2003. "The Rise and Fall of World Trade, 1870–1939." *Quarterly Journal of Economics* 2 (118): 359–407.

Evans, P.B. 2010. "Constructing the 21st Century Developmental State: Potentialities and Pitfalls." In O. Edigheji, ed., *Constructing a Democratic Developmental State in South Africa: Potentials and Challenges*. Cape Town: HSRC Press.

Fan, S., B. Nestorova, and T. Olofinbiyi. 2010. "China's Agricultural and Rural Development: Implications for Africa." China–Development Assistance Committee Study Group on Agriculture, Food Security and Rural Development, 27–28 April, Bamako. www.ifpri.org/sites/default/files/publications/chinaafricadac.pdf. Accessed 23 October 2012.

Fan, S., and A. Saurkar. 2006. "Public Spending in Developing Countries: Trends, Determination, and Impact." World Bank, Washington, DC. http://siteresources.worldbank.org/EXTRESPUBEXPANAAGR/Resources/ifpri2.pdf. Accessed 23 October 2012.

Felbermayr, G.J., and B. Jung. 2009. "The Pro-Trade Effect of the Brain Drain: Sorting Out Confounding Factors." *Economics Letters* 104 (2): 72–75.

Fine, D., A. van Wamelen, S. Lund, A. Cabral, M. Taoufiki, N. Dörr, A. Leke, C. Roxburgh, J. Schubert, and P. Cook. 2012. *Africa at Work: Job Creation and Inclusive Growth*. New York: McKinsey Global Institute. www.mckinsey.com/insights/mgi/research/africa_europe_middle_east/africa_at_work. Accessed 23 September 2012.

FitzGerald, V., F. Stewart, and R. Venugopal. 2006. *Globalization, Violent Conflict and Self-Determination*. Basingstoke: UK: Palgrave Macmillan.

Foley, C.F., and W. R. Kerr. 2011. "Ethnic Innovation and U.S. Multinational Firm Activity." Working Paper 12-006. Harvard Business School, Cambridge, MA. www.people.hbs.edu/ffoley/foleykerr.pdf. Accessed 15 May 2012.

Foster, M., and P. Mijumbi. 2002. "How, When and Why Does Poverty Get Budget Priority: Poverty Reduction Strategy and Public Expenditure in Uganda." Case Study 1. Working Paper 163. Overseas Development Institute, London. www.odi.org.uk/resources/docs/2061.pdf. Accessed 15 May 2012.

Frankel, J.A., and D. Romer. 1999. "Does Trade Cause Growth?" *American Economic Review* 89 (3) 379–399.

Frenk, J., O. Gómez-Dantés, and F.M. Knaul. 2009. "The Democratization of Health in Mexico: Financial Innovations for Universal Coverage." *Bulletin of the World Health Organization* 87 (7): 542–548.

Fu, X. 2008. "Foreign Direct Investment, Absorptive Capacity and Regional Innovation Capabilities in China." *Oxford Development Studies* 36 (1): 89–110.

Fukuda-Parr, S. 2003. "The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen's Ideas on Capabilities." *Feminist Economics* 19 (2–3: 301–317.

Fukuda Parr, S., C. Lopes, and K. Malik. 2002. "Overview. Institutional Innovations for Capacity Development." In *Capacity for Development: New Solutions to Old Problems*. London: Earthscan.

G8 (Group of Eight). 2005. "The Gleneagles Communiqué: Climate Change, Energy and Sustainable Development." 8 July. www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/government_support/PostG8_Gleneagles_Communique.pdf. Accessed 15 May 2012.

Gallup. 2012. Gallup World Poll Database. http://worldview.gallup.com. Accessed 15 May 2012.

Galor, O. 2006. "Economic Growth in the Very Long-Run." Working Paper 2006-16. Brown University, Department of Economics, Providence, RI.

Giroux, S.C. 2008. "Child Stunting Across Schooling and Fertility Transitions: Evidence from Sub-Saharan Africa." DHS Working Paper 57. United States Agency for International Development, Washington, DC. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADM570.pdf. Accessed 21 December 2012.

Glennie, J. 2011. "Busan Has Been an Expression of Shifting Geopolitical Realities." *The Guardian*, 2 December. www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/dec/02/busan-shifting-geopolitical-realities. Accessed 15 May 2012.

Glewwe, P., and A.L. Kassouf. 2008. "The Impact of the Bolsa Escola/Família: Conditional Cash Transfer Program on Enrollment, Grade Promotion and Drop-Out Rates in Brazil." Annals of the 36th Brazilian Economics Meeting of the Brazilian Association of Graduate Programs in Economics. www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807211140170-.pdf. Accessed 15 May 2012.

Global Footprint Network. 2011. "The National Footprint Accounts, 2011 Edition." Oakland, CA. www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_data_and_results/. Accessed 15 May 2012.

Gooch, L. 2012. "Seeking the Right to Be Female in Malaysia." *The New York Times,* 5 October. www.nytimes.com/2012/10/06/world/asia/seeking-the-right-to-be-female-in-malaysia.html. Accessed 21 December 2012.

Government of India. 2009. "The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009." *The Gazette of India,* 2009: 35.

Grabel, I. 2013. "Financial Architectures and Development: Resilience, Policy Space, and Human Development." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Grameen Bank. n.d. "A Short History of Grameen Bank". www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=114. Accessed 15 May 2012.

Green, G. 2010. "Imagine There's No Army." *Diplomat Magazine*, 1 September. www.diplomatmagazine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=. Accessed 15 May 2012.

Guajardo, J., D. Leigh, and A. Pescatori. 2011. "Expansionary Austerity: New International Evidence." Working Paper WP/11/158. International Monetary Fund, Washington, DC. www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11158.pdf. Accessed 15 May 2012.

Gupta, A., and H. Wang. 2012. "India's Misguided China Anxiety." *Businessweek*, 21 March. www.businessweek.com/printer/articles/14394-indias-misguided-china-anxiety. Accessed 15 May 2012.

Hailu, D., and V. Veras Soares. 2008. "Cash Transfers in Africa and Latin America: An Overview." Poverty in Focus 15. International Poverty Centre for Inclusive Growth, Brasilia.

Hamdani, K. 2013. "The Challenge of the South." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Han, S. 2012. "South Korean Parliament Approves Carbon Trading System." *Bloomberg*, 2 May. www.bloomberg

.com/news/2012-05-02/south-korean-parliament-approves-carbon-trading-system.html. Accessed 15 May 2012.

Hansen. R. 2010. "An Assessment of Principal Regional Consultative Processes." Migration Research Series 38. International Organization for Migration, Geneva.

Hanushek, E.A., D. Jamison, E. Jamison, and L. Woessmann. 2008. "Education and Economic Growth." *Education Next*, Spring. http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/ednext_20082_62.pdf. Accessed 8 August 2012.

Harding, R. 2012. "Interview: Justin Yifu Lin: Funding Developing World Infrastructure Could Buy Time for Europe to Reform, Hears Robin Harding." *Financial Times*, 6 June.

Harrison, A., and A. Rodriguez-Clare. 2010. "Trade, Foreign Investment and Industrial Policy for Developing Countries." In D. Rodrik and M. Rosenzweig, eds., *Handbook of Development Economics*, Vol. 5. New York: North-Holland.

Harvey, F. 2012. "Doha Climate Change Deal Clears Way for 'Damage Aid' to Poor Nations." *The Observer*, 8 December. www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/08/doha-climate-change-deal-nations?intcmp=122. Accessed 8 December 2012.

Hausmann, R., J. Hwang, and D. Rodrik. 2007. "What You Export Matters." *Journal of Economic Growth* 12 (1): 1–25.

Hausmann, R., L. Pritchett, D. Rodrik. 2005. "Growth Accelerations." *Journal of Economic Growth* 10 (4): 303–329.

Hausmann, R., D. Rodrik, and A. Velasco. 2005. "Growth Diagnostics." Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Cambridge, MA.

Hausmann, R., and M. Székely. 2001. "Inequality and the Family in Latin America." In N. Birdsall, A.C. Kelley, and S. Sinding, eds., *Population Matters: Demographic Change, Economic Growth, and Poverty in the Developing World*. New York: Oxford University Press.

Hazard, E., L. De Vries, M.A. Barry, A.A. Anouan, and N. Pinaud. 2009. "The Developmental Impact of the Asian Drivers in Senegal." *World Economy* 32 (11): 1563–1585.

Heilmann, S. 2008. "Policy Experiments in China's Economic Rise." *Studies in Comparative International Development* 43 (1): 1–26.

Heller, P. 2013. "Civil Society and Social Movements in a Globalizing World." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Hiemstra-van der Horst, G. 2011. "We Are Scared to Say No: Facing Foreign Timber Companies in Sierra Leone's Community Woodlands." *Journal of Development Studies* 47 (4): 574–594.

HM Treasury. 2010. *Spending Review*. London. http://cdn.hm-treasury.gov.uk/sr2010_completereport.pdf. Accessed 15 May 2012.

Hoff, K. 2003. "Paths of Institutional Development: A View from Economic History." *World Bank Research Observer* 18 (2): 205–226.

Holland, D., and K. Portes. 2012. "Self-Defeating Austerity?" *National Institute Economic Review* 222 (1): F4–F10.

Hook, L. 2012. "China's Post-90 Generation Make their Mark." *The Financial Times*, 9 July. www.ft.com/intl/cms/s/0/4fcbab6c-c67d-11e1-963a-00144feabdc0.html. Accessed 15 July 2012.

Hook, L., and P. Clark. 2012. "China's Wind Groups Pick up Speed." *The Financial Times*, 15 July. www.ft.com/intl/cms/s/0/fb4bc872-c674-11e1-963a-00144feabdc0.html. Accessed 15 July 2012.

Hori, T. 2011. "Educational Gender Inequality and Inverted U-Shaped Fertility Dynamics." *Japanese Economic Review* 62 (1): 126–150.

Howell, J. 2004. *Governance in China*. Lanham, MA: Rowman & Littlefield.

Huntington, S. 1968. *Political Order in Changing Societies*. Fredericksburg, VA: BookCrafters, Inc.

Hussain, A., and N. Stern. 2006. "Public Finance: The Role of the State and Economic Transformation in China: 1978–2020." *Comparative Studies* 26: 25–55.

Hvistendahl, M. 2011. "Unnatural Selection." *Psychology Today*, 5 July. www.psychologytoday.com/articles/201107/unnatural-selection. Accessed 24 July 2012.

ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development). 2011. "Brazil Pushes Forward with Currency Discussion at WTO." *Bridges Weekly Trade News Digest* 15 (32): 5–7. http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/114573/.

IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). 2008. "Economic Growth in Developing Countries: Education Proves Key." Policy Brief 03. Laxenburg, Austria. www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/policy-briefs/pb03-web.pdf. Accessed 4 June 2012.

Iley, R.A., and M.K. Lewis. 2011. "Has the Global Financial Crisis Produced a New World Order?" *Accounting Forum* 35 (2): 90–103.

ILO (International Labour Organization). 2012. *World of Work Report 2012: Better Jobs for a Better Economy*. Geneva. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_179453.pdf. Accessed 4 June 2012.

IMF (International Monetary Fund). 2010. "IMF Executive Board Approves Major Overhaul of Quotas and Governance." Press release 10/418. Washington, DC. www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10418.htm. Accessed 15 May 2012.

———. 2011a. "New Growth Drivers for Low-Income Countries: The Role of BRICs." Strategy, Policy, and Review Department, Washington, DC. www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/011211.pdf. Accessed 15 May 2012.

———. 2011b. *World Economic Outlook*. Washington, DC. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/. Accessed 15 May 2012.

India Ministry of External Affairs. 2012. "Fourth BRICS Summit – Delhi Declaration." 29 March. New Delhi. www.mea.gov.in/mystart.php?id=190019162. Accessed 15 May 2012.

India Ministry of Finance. 2012. "Human Development." In *Economic Survey 2011–2012*. New Delhi. www.indiabudget.nic.in/es2011-12/echap-13.pdf. Accessed 15 May 2012.

Institute for Economics and Peace. 2012. "Global Peace Index Fact Sheet." Sydney. www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2012/06/2012GPI-Fact-Sheet2.pdf. Accessed 28 August 2012

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2012. *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation*. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press. http://ipcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf. Accessed 15 May 2012.

Islam, I. 2002. "Poverty, Employment and Wages: An Indonesian Perspective." International Labour Organization, Recovery and Reconstruction Department, Geneva.

ITU (International Telecommunications Union). 2012. World Telecommunication/ICT Indicators Database. www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/. Accessed 15 May 2012.

Ivanov, A., M. Collins, C. Grosu. J. Kling, S. Milcher, N. O'Higgins, B. Slay, and A. Zhelyazkova. 2006. *At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe*. Bratislava: United Nations Development Programme Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States.

Ivanov, A., K. Mizsei, B. Slay, D. Mihailov, and N. O'Higgins. 2003. *Avoiding the Dependency Trap: The Roma Human Development Report*. Bratislava: United Nations Development Programme Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States.

Iyer, L. 2009. "The Bloody Millennium: Internal Conflict in South Asia." Working Paper 09-086. Harvard Business School, Cambridge, MA. www.hbs.edu/research/pdf/09-086.pdf. Accessed 15 May 2012.

Jacob, R. 2012. "Flagging Western Demand Drives China's Exporters to New Markets." *Financial Times*, 13 June. www.ftchinese.com/story/001045040/en/. Accessed 15 May 2012.

Jenkins, J.C., and M. Wallace. 1996. "The Generalized Action Potential of Protest Movements: The New Class, Social Trends and Political Exclusion Explanations." *Sociological Forum* 11 (2): 183–207.

Jenkins, R., and A. Barbosa. 2012. "Fear for Manufacturing? China and the Future of Industry in Brazil and Latin America." *The China Quarterly* 209: 59–81.

Jones, R., and H. Kierzkowski. 2001. "Horizontal Aspects of Vertical Fragmentation." In L. Cheng and H. Kierzkowski, eds., *Global Production and Trade in East Asia*. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers.

Justino, P. 2008. "Tackling Civil Unrest: Policing or Redistribution?" MICROCON Policy Briefing Paper 2. Institute of Development Studies, Brighton, UK. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1141142&http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1141142. Accessed 15 May 2012.

Kabananukye, K. I. B., A. E.K. Kanbananukye, J. Krishnamurty, and D. Owomugasho. 2004. "Economic Growth, Employment, Poverty and Pro-Poor Policies in Uganda." Issues in Employment and Poverty Discussion Paper 16. International Labour Organization, Geneva. www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/WCMS_120732/lang--en/index.htm. Accessed 24 September 2012.

Kabeer, N., and S. Mahmud. 2004. "Rags, Riches and Women Workers: Export Oriented Garment Manufacturing in Bangladesh." In M. Carr, ed., *Chains of Fortune: Linking Women Producers and Workers with Global Markets*. London: Commonwealth Secretariat.

Kahneman, D., and A. Krueger. 2006. "Developments in the Measurement of Subjective Well-Being." *Journal of Economic Perspectives* 20 (21): 3–24.

Kamau, P., D. McCormick, and N. Pinaud. 2009. "The Developmental Impact of Asian Drivers on Kenya with Emphasis on Textiles and Clothing Manufacturing." *World Economy* 32 (11): 1586–1612.

Kaminski, B., and F. Ng. 2006. "Turkey's Evolving Trade Integration into Pan-European Markets." Working Paper 3908. World Bank, Development Research Group, Washington, DC. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1294804. Accessed 15 May 2012.

Kanbur, R. 2004. "Growth, Inequality and Poverty: Some Hard Questions." Commentary prepared for the State of the World Conference at the Princeton Institute for International and Regional Studies, 13–14 February, Princeton, NJ. www.arts.cornell.edu/poverty/kanbur/GroIneqPov.pdf. Accessed 15 May 2012.

Kaplinsky, R. 2008. "What Does the Rise of China do for Industrialisation in Sub-Saharan Africa?" *Review of African Political Economy* 35 (1): 7–22.

Kaplinsky, R., and M. Morris. 2009. "The Asian Drivers and SSA: Is There a Future for Export-Oriented African Industrialization?" *The World Economy* 32 (11): 1638–1655.

Kaplinsky, R., A. Terheggen, and J. Tijaja. 2011. "China as a Final Market: The Gabon Timber and Thai Cassava Value Chains." *World Development* 39 (7): 1177–1190.

Karimuddin, A. 2011. "MarkPlus Insight Survey: Indonesia Has 55 Million Internet Users." *DailySocial.net*, 1 November. http://dailysocial.net/en/2011/11/01/markplus-insight-survey-indonesia-has-55-million-internet-users/. Accessed 15 May 2012.

Kaul, I. 2013. "The Rise of the Global South: Implications for the Provisioning of Global Public Goods." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Keohane, R., and D. Victor. 2010. "The Regime Complex for Climate Change." Discussion Paper 10-33. Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Harvard Project on International Climate Agreements. http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Keohane_Victor_Final_2.pdf. Accessed 15 May 2012.

Keynes, J.M. 1937. "How to Avoid a Slump." *The Times*, 12–14 January. Reprinted in *The Collected Writings of John Maynard Keynes* Vol. 21. London: Macmillan.

Khan, A.R. 2005. "Growth, Employment and Poverty: An Analysis of the Vital Nexus Based on Some Recent UNDP and ILO/SIDA Studies." Issues in Employment and Poverty Discussion Paper 19. International Labour Office, Geneva. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_120683.pdf. Accessed 24 September 2012.

Kharas, H., K. Makino, and W. Jung, eds. 2011. *Catalyzing Development: A New Vision of Aid.* Washington, DC: Brookings Institution Press.

King, D., K. Richards, and S. Tyldesley. 2011. "International Climate Change Negotiations: Key Lessons and Next Steps." University of Oxford, Smith School of Enterprise and the Environment, UK. www.smithschool.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2011/03/Climate-Negotiations-report_Final.pdf. Accessed 15 May 2012.

Kraemer, K., G. Linden, and J. Dedrick. 2011. "Capturing Value in Global Networks: Apple's iPad and iPhone." University of California, Irvine, University of California, Berkeley, and Syracuse University, NY. http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/Value_iPad_iPhone.pdf. Accessed 15 May 2012.

Kragelund, P. 2013. "New Development Partnerships." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Krueger, A.B., and D.A. Schkade. 2008. "The Reliability of Subjective Well-Being Measures." *Journal of Public Economics* 92 (8–9): 1833–1845.

Krugman, P. 1991. "The Move Towards Free Trade Zones." Symposium of the Federal Reserve Bank of Kansas City, 22–24 August, Jackson Hole, WY. www.kansascityfed.org/publicat/sympos/1991/S91krugm.pdf. Accessed 23 October 2012.

Kugler, M., and H. Rapoport. 2011. "Migration, FDI, and the Margins of Trade." Working Paper 222. Harvard University, Center for International Development, Cambridge, MA.

LaFraniere, S. 2011. "Five Days Later, Chinese Concede Design Flaw Had Role in Wreck." *The New York Times*, 28 July. www.nytimes.com/2011/07/29/world/asia/29trains.html. Accessed 15 May 2012.

Lamberte, M., and P.J. Morgan. 2012. "Regional and Global Monetary Cooperation." Working Paper 346. Asian Development Bank Institute, Tokyo. www.adbi.org/working-paper/2012/02/21/5006.regional.global.monetary.cooperation/. Accessed 15 May 2012.

Lautier, M. 2008. "Export of Health Services from Developing Countries: The Case of Tunisia." *Social Science and Medicine* 67: 101–110.

Leape, J. 2012. "It's Happening, But Not in Rio." *The New York Times*, 24 June. www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/action-is-happening-but-not-in-rio.html. Accessed 24 June 2012

Li, J. 2010. "Decarbonising Power Generation in China—Is the Answer Blowing in the Wind?" *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 14 (4): 1154–1171.

López-Calva, L., and N. Lustig, eds. 2010. *Declining Inequality in Latin America: A Decade of Progress?* Harrisonburg, VA: RR Donnelley.

Luedi, T. 2008. "China's Track Record in M&A." *McKinsey Quarterly*, June. www.mckinseyquarterly.com/Chinas_track_record_in_MA_2151. Accessed 15 May 2012.

Lutz, W., and S. KC. 2013. "Demography and Human Development: Education and Population Projections." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Maddison, A. 2010. Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1–2008 AD. Groningen Growth and Development Centre, The Netherlands. www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm. Accessed 15 May 2012.

Malik, M. 2006. "Bilateral Investment Treaties of South Asian States: Implications for Development." United Nations Development Programme, Asia-Pacific Trade and Investment Initiative, Colombo.

———. 2012. *Why Has China Grown So Fast For So Long?* New Delhi: Oxford University Press India.

Martin, T.C., and F. Juarez. 1995. "The Impact of Women's Education on Fertility in Latin America: Searching for Explanations." *International Family Planning Perspectives* 12 (2): 52–57, 80.

Milanović, B. 2009. "Global Inequality and the Global Inequality Extraction Ratio." Policy Research Working Paper 5044. World Bank, Development Research Group, Poverty and Inequality Team, Washington, DC. http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/09/09/000158349_20090909092401/Rendered/PDF/WPS5044.pdf. Accessed 15 May 2012.

———. 2010. *The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality*. New York: Basic Books.

Milanović, B., and S. Yitzhaki. 2002. "Decomposing World Income Distribution: Does the World Have a Middle Class?" *Review of Income and Wealth* 48(2): 155–178.

Moyo, D. 2012. "Beijing, a Boon for Africa." *The New York Times*, 27 June. www.nytimes.com/2012/06/28/opinion/beijing-a-boon-for-africa.html. Accessed 28 August 2012.

Mwase, N., and Y. Yang. 2012. "BRICs' Philosophies for Development Financing and Their Implications for LICs." Working Paper WP/12/74. International Monetary Fund, Washington, DC.

Nagel, T. 1974. "What Is It Like To Be a Bat?" *The Philosophical Review* 83 (4): 435–450.

Naqvi, H., and V.V. Acharya. 2012. "Bank Liquidity and Bubbles: Why Central Banks Should Lean Against Liquidity. In D. Evanoff, G. Kaufman, and A.G. Malliaris, eds., *New Perspectives on Asset Price Bubbles: Theory, Evidence and Policy.* Oxford, UK: Oxford University Press.

Nayyar, D. 2012. "Macroeconomics and Human Development." *Journal of Human Development and Capabilities* 13 (1): 7–30.

NEAC (Malaysia National Economic Advisory Council). 2010. "New Economic Model for Malaysia, Parts 1 and 2." Kuala Lumpur.

Nielsen H., and A. Spenceley. 2011. "The Success of Tourism in Rwanda: Gorillas and More." In P. Chuhan-Pole and M. Angwafo, eds., *Yes Africa Can: Success Stories from a Dynamic Continent*. Washington, DC: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/258643-1271798012256/YAC_Consolidated_Web.pdf. Accessed 10 August 2012.

Ocampo, J.A. 2010. "Rethinking Global Economic and Social Governance." *Journal of Globalization and Development* 1 (1).

Ocampo J.A., S. Griffith-Jones, A. Noman, A. Ortiz, J. Vallejo, and J. Tyson. 2010. "The Great Recession and the Developing World." Paper presented at the conference on Development Cooperation in Times of Crisis and on Achieving the MDGs, 9–10 June, Madrid.

Ocampo, J.A., and D. Titelman. 2009. "Subregional Financial Cooperation: the South American Experience." *Journal of Post-Keynesian Economics* 32 (2): 249–68.

———. 2012. "Regional Monetary Cooperation in Latin America." Columbia University, Initiative for Policy Dialogue, New York, and United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Financing for Development Division, Santiago.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2006. *Promoting Pro-Poor Growth: Agriculture*. Paris. www.oecd.org/dac/povertyreduction/37922155.pdf. Accessed 23 October 2012.

———. 2007. "Economic Survey of India, 2007." *OECD Observer*, October. Policy Brief. www.oecd.org/economy/

economicsurveysandcountrysurveillance/39452196.pdf. Accessed 6 August 2012.

———**. 2010a.** *Perspectives on Global Development 2010: Shifting Wealth*. Paris.

———**. 2010b.** *PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do*. Vol. I. Paris. www.oecd.org/dataoecd/10/61/48852548.pdf. Accessed 24 July 2012.

———**. 2011a.** "Brazil." In *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2011*. Paris. www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2011/brazil_agr_pol-2011-22-en. Accessed 23 October 2012.

———**. 2011b.** *Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising*. Paris.

———**. 2011c.** "Busan Partnership for Effective Development Cooperation." Paris. www.oecd.org/dac/aideffectiveness/busanpartnership.htm. Accessed 24 July 2011.

Ofosu-Asare, K. 2011. "Mobile Phone Revolution in Ghana's Cocoa Industry." *International Journal of Business and Social Science* 2 (13): 91–99.

Osmani, S.R. 2005. "The Employment Nexus between Growth and Poverty: An Asian Perspective." Swedish International Development Cooperation Agency, Stockholm.

Osmani, S.R., W. Mahmud, B. Sen, H. Dagdeviren, and A. Seth. 2006. "The Macroeconomics of Poverty Reduction: The Case Study of Bangladesh." United Nations Development Programme, Asia-Pacific Regional Programme on the Macroeconomics of Poverty Reduction, New York.

Pardee Center for International Futures. 2013. "Development-Oriented Policies and Alternative Human Development Paths." Background paper for the 2013 *Human Development Report*. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Park, K. 2011. "New Development Partners and a Global Development Partnership." In H. Kharas, K. Makino, and W. Jung, eds., *Catalyzing Development: A New Vision for Aid*. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Pasha, H.A., and T. Palanivel. 2004. "Pro-Poor Growth and Policies: The Asian Experience." United Nations Development Programme, Asia-Pacific Regional Programme on the Macroeconomics of Poverty Reduction, New York.

Pinker, S. 2011. "Violence Vanquished." *The Wall Street Journal,* 24 September. http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904106704576583203589408180.html. Accessed 15 May 2012.

Polanyi, K. 1944. *The Great Transformation*. New York: Rinehart.

Population Reference Bureau. 2000. "Is Education the Best Contraceptive?" Policy Brief. Population Reference Bureau, Washington, DC. www.prb.org/Publications/PolicyBriefs/ IsEducationtheBestContraceptive.aspx. Accessed 15 May 2012.

Psacharopoulos G., and Z. Tzannatos. 1992. "Latin American Women's Earnings and Participation in the Labor Force." Working Paper 856. World Bank, Washington, DC. http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuPK=64166322&entityID=000009265_3961002093302. Accessed 15 May 2012.

Radelet, S., J. Sachs, and J.-W., Lee. 1997. "Economic Growth in Asia." Development Discussion Paper 609. Harvard Institute for International Development, Cambridge, MA.

Ranis, G., and F. Stewart. 2005. "Dynamic Links Between the Economy and Human Development." Working Paper 8. United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York. www.un.org/esa/desa/papers/2005/wp8_2005.pdf. Accessed 15 May 2012.

Ratha, D., and W. Shaw. 2007. "South-South Migration and Remittances." Working Paper 102. World Bank, Washington, DC. http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/SouthSouthMigrationandRemittances.pdf. Accessed 15 May 2012.

Ravallion, M. 2009. "A Comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China and India." Policy Research Working Paper 5080. World Bank, Washington, DC. http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469382&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000158349_20091130085835. Accessed 15 May 2012.

REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century). 2012. *Renewables Global Status Report*. Paris. www.map.ren21.net/GSR/GSR2012.pdf. Accessed 15 May 2012.

Reserve Bank of India. 2012. "Reserve Bank of India Announces SAARC Swap Arrangement." Press Release, 16 May. Mumbai. www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=26475. Accessed 15 May 2012.

Revkin, A. 2012. "Beyond Rio: Pursuing 'Ecological Citizenship.'" *The New York Times*, 25 June. http://dotearth.blogs.nytimes.com/2012/06/25/beyond-rio-pursuing-ecological-citizenship/. Accessed 25 June 2012.

Ribas, R., V. Veras Soares, and G. Hirata. 2008. "The Impact of CCTs: What We Know and What We Are Not Sure About." Poverty in Focus 15. International Poverty Centre for Inclusive Growth, Brasilia.

Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F.S. Chapin, III, E. Lambin, T.M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. Schellnhuber, B. Nykvist, C.A. De Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P.K. Snyder, R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R.W. Corell, V.J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. Richardson, P. Crutzen, and J. Foley. 2009. "Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity." *Ecology and Society* 14 (2). www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/. Accessed 15 May 2012.

Rodriguez, F., and D. Rodrik. 2001. "Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic's Guide to the Cross-National Evidence." *NBER Macroeconomics Annual 2000* 15: 261–338.

Rodrik, D. 1998. *Democracies Pay Higher Wages*. Working Paper 6364. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

———**. 2001.** "The Global Governance of Trade as if Development Really Mattered." Background Paper prepared for the United Nations Development Programme. www.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/529__Rodrik5.pdf. Accessed 6 August 2012.

———**. 2004.** "Industrial Policy for the Twenty-first Century." Draft prepared for the United Nations Industrial Development Organization. Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Cambridge, MA. www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research%20papers/UNIDOSep.pdf. Accessed 6 August 2012.

———**. 2005.** "Notes on Trade and Industrialization Policy, in Turkey and Elsewhere." *METU Studies in Development* 32 (1): 259–274.

———**. 2006.** *The Social Cost of Foreign Exchange Reserves*. Working Paper 11952. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. www.nber.org/papers/w11952. Accessed 15 May 2012.

———**. 2011.** *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W.W. Norton.

———**. 2012.** "Global Poverty amid Global Plenty: Getting Globalization Right." *Americas Quarterly*, Spring: 40–45.

Romero, S. 2012. "Brazil Gains Business and Influence as It Offers Aid and Loans in Africa." *The New York Times*, 7 August. www.nytimes.com/2012/08/08/world/americas/brazil-gains-in-reaching-out-to-africa.html. Accessed 8 August 2012.

Romero, S., and J.M. Broder. 2012. "Progress on the Sidelines as Rio Conference Ends." *The New York Times*, 23 June. www.nytimes.com/2012/06/24/world/americas/rio20-conference-ends-with-some-progress-on-the-sidelines.html. Accessed 4 November 2012.

Rose, P. 1995. "Female Education and Adjustment Programs: A Cross-Country Statistical Analysis." *World Development* 23 (11): 1931–1949.

Rosenfeld, R., S. Messner, and E. Baumer. 2001. "Social Capital and Homicide." *Social Forces* 80 (1): 283–310.

Sachs, J.D., and A. Warner. 1995. "Economic Reform and the Process of Global Integration." *Brookings Papers on Economic Activity* 1: 1–118.

Sala-i-Martin, X. 2006. "The World Distribution of Income: Falling Poverty and . . . Convergence, Period." *Quarterly Journal of Economics* 121 (2): 351–397.

Samake, I., and Y. Yang. 2011. "Low-Income Countries' BRIC Linkage: Are There Growth Spillovers?" Working Paper 11/267. International Monetary Fund, Washington, DC. www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11267.pdf. Accessed 15 May 2012.

Sen, A. 2007. "Unity and Discord in Social Development." Keynote lecture delivered at the 15th Symposium of the International Consortium for Social Development at the Polytechnic University of Hong Kong, 16–20 July, Hong Kong, China (SAR).

———**. 2012.** "A Crisis of European Democracy." *The New York Times*, 22 May. www.nytimes.com/2012/05/23/opinion/the-crisis-of-european-democracy.html. Accessed 15 July 2012.

Serbessa, D.D. 2002. "Differential Impact of Women's Educational Level on Fertility in Africa: The Case of Ethiopia." Hiroshima University, Japan. http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/e-forum/69Differential%20Impact%20Ed%20on%20Pop%20_Final_.pdf. Accessed 15 May 2012.

Serra, N., and J. E. Stiglitz. 2008. *The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Sharma, R. 2012. *Breakout Nations: In Pursuit of the Next Economic Miracles*. New York: W.W. Norton.

Sivananthiran, A., and C.S. Venkata Ratnam, eds. 2005. *Informal Economy: The Growing Challenge for*

Labor Administration. Geneva: International Labour Office.

Smith, A. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. New York: Modern Library.

Sobhan, R. 2010. *Challenging the Injustice of Poverty*. Washington, DC: Sage.

———. 2013. "Commentary on Financial Architectures and Development: Resilience, Policy Space, and Human Development in the Global South by Prof. Ilene Grabel." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Socialbakers.com. 2012. Facebook Statistics by Country. www.socialbakers.com/facebook-statistics/. Accessed 15 May 2012.

Sonobe, T., J.E. Akoten, and K. Otsuka. 2009. "An Exploration into the Successful Development of the Leather-Shoe Industry in Ethiopia." *Review of Development Economics* 13 (4): 719–736.

South Commission. 1990. *The Challenge to the South: The Report of the South Commission*. Oxford, UK: Oxford University Press. www.southcentre.org/files/Old%20Books/The%20Challenge%20to%20the%20Southresized.pdf. Accessed 23 October 2012.

Ssewanyana, S., J.M. Matovu, and E. Twimukye. 2011. "Building on Growth in Uganda." In P. Chuhan-Pole and M. Angwafo, eds., *Yes Africa Can: Success Stories From A Dynamic Continent*. Washington, DC: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/258643-1271798012256/YAC_Consolidated_Web.pdf. Accessed 10 August 2012.

Stads, G.-J., and N.M. Beintema. 2009. *Public Agricultural Research in Latin America and the Caribbean: Investment and Capacity Trends*. ASTI Synthesis Report. Washington: International Food Policy Research Institute. www.asti.cgiar.org/pdf/LAC_Syn_Report.pdf. Accessed 23 October 2012.

Stern, N. 2003. "Public Policy for Growth and Poverty Reduction." *CESifo Economic Studies* 49 (1): 5–25.

———. 2006. *The Stern Review Report on the Economics of Climate Change*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Stewart, F. 2013. "Capabilities and Human Development: Beyond the Individual: The Critical Role of Social Institutions and Social Competencies." Human Development Research Paper. United Nations Development Programme, Human Development Report Office, New York.

Stiglitz, J.E. 2012. "Macroeconomic Fluctuations, Inequality, and Human Development." *Journal of Human Development and Capabilities* 13 (1): 31–58.

Stiglitz, J.E., A. Sen, and J.-P. Fitoussi. 2009. *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

Subramanian, A., and D. Roy. 2001. "Who Can Explain the Mauritian Miracle: Meade, Romer, Sachs, or Rodrik?" Working Paper 01/116. International Monetary Fund, Washington, DC. www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=15215.0. Accessed 15 May 2012.

Supreme Court of India. 2012. "Society for Un-aided Private Schools of Rajasthan Petitioner(s) versus U.O.I. & Anr." Supreme Court judgement of 12 April 2012 on Writ Petition (C) No. 95 of 2010.

Suri, T., M.A. Boozer, G. Ranis, and F. Stewart. 2011. "Paths to Success: The Relationship between Human Development and Economic Growth." *World Development* 39 (4): 506–522.

Tangcharoensathien, V., W. Patcharanarumol, P. Ir, S.M. Aljunid, A.G. Mukti, K. Akkhavong, E. Banzon, D.B. Huong, H. Thabrany, and A. Mills. 2011. "Health-Financing Reforms in Southeast Asia: Challenges in Achieving Universal Coverage." *The Lancet* 377 (9768): 863–873.

Taylor, C.E., J.S. Newman, and N.U. Kelly. 1976. "The Child Survival Hypothesis." *Population Studies* 30 (2): 263–278.

Tejada, C. 2012. "China Cancels Waste Project after Protests Turn Violent." *Wall Street Journal*, 28 July. http://business.newsplurk.com/2012/07/china-cancels-waste-project-after.html. Accessed 21 December 2012.

Thorp, R., and M. Paredes. 2011. *Ethnicity and the Persistence of Inequality: The Case of Peru*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Tomlinson, B.R. 2003. "What Was the Third World?" *Journal of Contemporary History* 38 (2): 307–321.

Tsounta, E. 2009. "Universal Health Care 101: Lessons from the Eastern Caribbean and Beyond." Working Paper WP/09/61. International Monetary Fund, Washington, DC. www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0961.pdf. Accessed 15 May 2012.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 2003. *World Investment Report 2003: FDI Policies for Development: National and International Perspectives*. New York and Geneva.

———. 2006. *A Case Study of the Salmon Industry in Chile*. New York and Geneva. http://unctad.org/en/docs/iteiit200512_en.pdf. Accessed 15 May 2012.

———. 2011a. World Investment Report 2011 Annex Tables. http://archive.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5823&lang=1. Accessed 15 May 2012.

———. 2011b. "South-South Integration Is Key to Rebalancing the Global Economy." Policy Brief 22. United Nations Conference on Trade and Development, Geneva. http://unctad.org/en/Docs/presspb20114_en.pdf. Accessed 2 November 2012.

UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). 2007. *World Economic and Social Survey 2007: Development in an Ageing World*. New York: United Nations Publications.

———. 2010. *Development Cooperation for the MDGs: Maximizing Results*. New York: United Nations.

UNDP (United Nations Development Programme). 1991. *Human Development Report 1991*. New York: Oxford University Press.

———. 1993. *Human Development Report 1993*. New York: Oxford University Press.

———. 1994. *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.

———. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.

———. 1996. *Human Development Report 1996*. New York: Oxford University Press.

———. 2008. *China Human Development Report 2007/08: Access for All: Basic Public Services for 1.3 Billion People*. Beijing: China Translation and Publishing Corporation.

———. 2009. *Human Development Report 2009: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development*. New York: Palgrave Macmillian.

———. 2010a. *Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development*. New York: Oxford University Press.

———. 2010b. *Regional Human Development Report for Latin America and the Caribbean 2010: Acting on the Future: Breaking the Intergenerational Transmission of Inequality*. New York.

———. 2010c. *China Human Development Report 2009/10: China and A Sustainable Future: Towards a Low Carbon Economy and Society*. Beijing: China Translation and Publishing Corporation.

———. 2011a. *Human Development Report 2011: Sustainability and Equality: A Better Future for All*. New York: Palgrave Macmillian

———. 2011b. *Regional Human Development Report: Beyond Transition: Towards Inclusive Societies*. Bratislava.

———. 2012. *Caribbean Human Development Report 2012: Human Development and the Shift to Better Citizen Security*. New York.

UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific). 2011. *The Promise of Protection: Social Protection and Development in Asia and the Pacific*. Bangkok.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) Institute for Statistics. Various years. Data Centre. http://stats.uis.unesco.org. Accessed 15 May 2012.

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). 2009. *Industrial Development Report 2009: Breaking In and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries*. Vienna.

United Kingdom, Office of the Deputy Prime Minister, Social Exclusion Unit. 2002. "Reducing Re-Offending by Ex-Prisoners." London. www.thelearningjourney.co.uk/file.2007-10-01.1714894439/file_view. Accessed 15 May 2012.

United Nations. 2012a. "The State of South-South Cooperation: Report of the Secretary-General." Sixty-Seventh Session of the General Assembly. New York.

———. 2012b. *The Millennium Development Goals Report 2012*. New York. www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf. Accessed 15 May 2012.

United Nations Enable. 2012. "Factsheet on Persons with Disabilities." www.un.org/disabilities/default.asp?id=18. Accessed 24 July 2012.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 2009. "Terminology." Geneva. www.unisdr.org/we/inform/terminology. Accessed 8 December 2012.

United Nations Secretary-General's High Level Panel on Global Sustainability. 2012. *Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing*. New York: United Nations.

United Nations Security Council. 2011. "Letter Dated 9 November 2011 from the Permanent Representative of Brazil to the United Nations Addressed to the

Secretary-General." Sixty-Sixth Session, Agenda Items 14 and 117. UN-Doc A/66/551-S/2011/701. www.un.int/brazil/speech/Concept-Paper-%20RwP.pdf. Accessed 15 May 2012.

UNODC (United Nations Office on Drug and Crime). 2012. *2011 Global Study on Homicide: Trends, Contexts, Data*. www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf. Accessed 30 May 2012.

UNSD (United Nations Statistics Division). 2012. United Nations Commodity Trade Statistics Database. http://comtrade.un.org. Accessed 15 May 2012.

UNWTO (World Tourism Organization). 2011. *Tourism Highlights: 2011 Edition*. Geneva.

Vos, R. 2010. "The Crisis of Globalization as an Opportunity to Create a Fairer World." *Journal of Human Development and Capabilities* 11 (1): 143–160.

Wacziarg, R., and K.H. Welch. 2008. "Trade Liberalization and Growth: New Evidence." *World Bank Economic Review* 22 (2): 187–231.

Westaway, J. 2012. "Globalization, Sovereignty and Social Unrest." *Journal of Politics and Law* 5 (2): 132–139.

Whalley, J., and A. Weisbrod. 2011. "The Contribution of Chinese FDI to Africa's Pre-Crisis Growth Surge." VoxEU, 21 December. www.voxeu.org/article/contribution-chinese-fdi-africa-s-growth. Accessed 15 May 2012.

Wilkinson, R., and K. Pickett. 2009. *The Spiritual Level*. New York: Bloomsbury Press.

———. 2012. "Sorry Nick Clegg – Social Mobility and Austerity Just Don't Mix." *The Guardian*, 15 May. www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/may/15/nick-clegg-social-mobility-austerity. Accessed 15 May 2012.

Wines, M., and S. LaFraniere. 2011. "In Baring Facts of Train Crash, Blogs Erode China Censorship." *The New York Times*, 28 July. www.nytimes.com/2011/07/29/world/asia/29china.html. Accessed 15 May 2012.

Winters, L.A. 2004. "Trade Liberalisation and Economic Performance: An Overview." *Economic Journal* 114 (493): F4–F21.

Wiseman, P. 2002. "China Thrown Off Balance as Boys Outnumber Girls." *USA Today*, 19 June. www.usatoday.com/news/world/2002/06/19/china-usat.htm. Accessed 24 July 2012.

Woods, N. 2010. "Global Governance after the Financial Crisis: A New Multilateralism or the Last Gasp of the Great Powers?" *Global Policy* 1 (1): 51–63.

World Bank. 2003. *Private Participation in Infrastructure: Trends in Developing Countries in 1990–2001.* Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/2003/01/2522708/private-participation-infrastructure-trends-developing-countries-1990-2001. Accessed 15 May 2012.

———. 2006. *Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migration*. Washington, DC. http://go.worldbank.org/0G6XW1UPP0. Accessed 15 May 2012.

———. 2008. *World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography*. Washington, DC. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23062295~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html. Accessed 15 May 2012.

———. 2010a. Bilateral Migration and Remittances. http://go.worldbank.org/JITC7NYTT0 . Accessed 15 May 2012.

———. 2010b. *Thailand Economic Monitor*. Bangkok. http://siteresources.worldbank.org/THAILANDEXTN/Resources/333295-1280288892663/THM_June2010_fullreport.pdf. Accessed 15 May 2012.

———. 2010c. *Arab Development Assistance: Four Decades of Cooperation*. Washington, DC. http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/ADAPub82410web.pdf. Accessed 15 May 2012.

———. 2010d. "World Bank Reforms Voting Power, Gets $86 Billion Boost." Press Release, 25 April. Washington, DC. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22556045~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html. Accessed 15 May 2012.

———. 2011a. *Malaysia Economic Monitor: Brain Drain*. Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/04/14134061/malaysia-economic-monitor-brain-drain. Accessed 15 May 2012.

———. 2011b. *Growing Old in Older Brazil*. Washington, DC.

———. 2012a. World Development Indicators Database. http://data.worldbank.org/. Accessed 15 May 2012.

———. 2012b. "An Update to World Bank's Estimates of Consumption Poverty in the Developing World." Briefing Note. Washington, DC. http://siteresources.worldbank.org/INTPOVCALNET/Resources/Global_Poverty_Update_2012_02-29-12.pdf. Accessed 15 May 2012.

———. n.d. "India Transport: Public Private Partnership." http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/0,,contentMDK:22020973~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:223547,00.html. Accessed 15 May 2012.

WTO (World Trade Organization). n.d. "The Doha Round." www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm. Accessed 28 December 2012.

Xing, Y., and N. Detert. 2010. "How the iPhone Widens the United States Trade Deficit with the People's Republic of China." Working Paper 257. Asian Development Bank Institute, Tokyo. www.adbi.org/working-paper/2010/12/14/4236.iphone.widens.us.trade.deficit.prc/. Accessed 15 May 2012.

Zafar. A. 2011. "Mauritius: An Economic Success Story." In P. Chuhan-Pole and M. Angwafo, eds., *Yes Africa Can: Success Stories From A Dynamic Continent*. Washington, DC: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/258643-1271798012256/YAC_Consolidated_Web.pdf. Accessed 10 August 2012.

Zuckerberg, M. 2012. "One Billion People on Facebook." http://newsroom.fb.com/News/457/One-Billion-People-on-Facebook. Accessed 4 October 2012.

Zuzana, B., and L. Ndikumana. Forthcoming. "The Global Financial Crisis and Africa: The Effects and Policy Responses." In G. Epstein and M. H. Wolfson, eds., *The Oxford Handbook of the Political Economy of Financial Crisis*. Oxford, UK: Oxford University Press.

सांख्यिकीय परिशिष्ट

पाठकों के लिए मार्गदर्शिका 140

कुंजिकाः मा.वि.सू. देश और श्रेणी, 2012 143

सांख्यिकीय सारणियाँ 144

मानव विकास सूचकांक

1 मानव विकास सूचकांक और इसके संघटक 44

2 मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियाँ 1980-2012 148

3 असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक 152

प्रायोगिक सूचकांक

4 लैंगिक असमानता सूचकांक 156

5 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 160

मानव विकास के सूचक

6 संसाधनों पर नियंत्रण 162

7 स्वास्थ्य 166

8 शिक्षा 170

9 सामाजिक एकीकरण 174

10 वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह 178

11 अंतरराष्ट्रीय पूँजी प्रवाह और प्रवास 182

12 नवाचार और प्रौद्योगिकी 186

13 पर्यावरण 190

14 जनसंख्या रुझान 194

क्षेत्र 198

सांख्यिकीय संदर्भ 199

तकनीकी परिशिष्टः पूर्वानुमान से संबंधित व्याख्या 200

पाठकों के लिए मार्गदर्शिका

ये 14 सांख्यिकीय सारणियाँ मानव विकास के प्रमुख पहलू का सिंहावलोकन प्रस्तुत करती हैं। इन सारणियों में मानव विकास रिपोर्ट ऑफ़िस (एच.डी.आर.ओ.) को 15 मई 2012 तक उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर एच.डी.आर.ओ. द्वारा आकलित मिश्रित सूचकांक (composite indices) शामिल हैं। सभी सूचकों समेत मिश्रित सूचकांकों की गणना के तकनीकी नोट तथा अतिरिक्त स्रोतों के बारे में जानकारी ऑनलाइन http://hdr.undp.org/en/statistics पर उपलब्ध है।

देशों और अंचलों को उनके 2012 के मा.वि.सू. मानों के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है। सुदृढ़ता एवं विश्वसनीयता विश्लेषण (Robustness and reliability analysis) ने दर्शाया है कि अधिकतर देशों के लिए मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) मान दशमलव के तीसरे स्थान के बाद सांख्यिकीय दृष्टि से अहम नहीं है (देखें अगूना एवं कोवासेविक, 2011, और हॉयलैंड, मोएने, और विलुमसेन, 2011)। इसी कारण से जिन देशों के मा.वि.सू मान दशमलव के तीसरे स्थान पर समान हैं, उन्हें उनकी सहबद्ध श्रेणी (Tied rank) के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है।

स्रोत तथा परिभाषाएँ

एच.डी.आर.ओ. अंतरराष्ट्रीय डेटा एजेंसियों के आँकड़ों का उपयोग करता है, जो निर्दिष्ट सूचकांकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आँकड़े एकत्र करने (विशेष हालात को छोड़कर) के लिए अधिकृत, संसाधन सम्पन्न होती हैं तथा इस काम को अंजाम देने की दक्षता से पूरी तरह लैस हैं।

हरेक सारणी के अंत में सूचकांकों की परिभाषाएँ तथा मूलभूत आँकड़ों के स्रोतों के बारे में जानकारी दी गई है और स्रोतों की विस्तृत जानकारी सांख्यिकीय संदर्भ शीर्षक में दी गई है।

समय सापेक्ष तथा रिपोर्ट के संस्करणों पर आधारित तुलनाएँ

चूँकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ लगातार अपनी डेटा सीरीज़ को सुधारती रहती हैं, इसलिए इस रिपोर्ट में प्रस्तुत आँकड़ों की– इनमें मा.वि.सू. तथा श्रेणीक्रम (Rank) शामिल हैं– रिपोर्ट के पिछले संस्करणों में प्रकाशित आँकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती। मा.वि.सू. के लिए, सुसंगत आँकड़ों के प्रयोग से तैयार किए गए रुझान, जिनकी 1980 से 2012 के बीच पाँच वर्षों के अंतराल के लिए गणना की गई है, वे सारणी-2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अनुमानों में विसंगतियाँ

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आँकड़ों के अनुमानों में कई बार असमानता हो सकती है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ विभिन्न देशों के राष्ट्रीय आँकड़ों को तुलनात्मक बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा अनुरूपीकरण (Harmonization) पद्धतियों का उपयोग करती हैं, बहुधा अनुपलब्ध आँकड़ों के अनुमान प्रस्तुत करती हैं, या फिर एकदम हाल के राष्ट्रीय आँकड़ों को शामिल नहीं करती हैं। जब एच.डी.आर.ओ. इन विसंगतियों से अवगत हुआ है, तो इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आँकड़ा प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

देशों का समूहीकरण और समुच्चय

सारणियों में अनेक भारित समुच्चय (Weighted aggregates) प्रस्तुत किए गए हैं। आम तौर पर समुच्चय रूप को तभी पेश किया जाता है जब कम से कम आधे देशों के लिए प्रासंगिक आँकड़ा उपलब्ध हो और वह उस वर्गीकरण में उपलब्ध कम से कम दो तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। समुच्चय के प्रत्येक वर्गीकरण में उन देशों का प्रतिनिधित्व होता है, जिनके लिए आँकड़े उपलब्ध हैं।

मानव विकास वर्गीकरण

मा.वि.सू. वर्गीकरण सापेक्ष (Relative) होते हैं जो कि देशों के बीच मा.वि.सू. वितरण के चतुर्थांश (Quartiles) पर आधारित हैं और मा.वि.सू. के कुल 187 देशों में अति उच्च, उच्च, मध्यम (प्रत्येक में 47 देश) तथा निम्न (46 देशों के साथ) रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं।

क्षेत्रीय समूहीकरण

देशों को क्षेत्रों में समूहीकृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के क्षेत्रीय वर्गीकरण को आधार बनाया गया है। अल्प विकसित देशों और छोटे द्विपीय विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्गीकरणों के आधार पर परिभाषित किया गया है।

देशों के बारे में नोट

जब तक अन्यथा इंगित न किया जाए, चीन के आँकड़ों में चीन का विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र हाँगकांग, चीन का विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र मकाओ या ताइवान प्रांत शामिल नहीं हैं। और जब तक अन्यथा इंगित न किया गया हो, सूडान के आँकड़ों में दक्षिण सूडान के आँकड़े शामिल हैं ।

प्रतीक

दो वर्षों के बीच का एक डैश (-), जैसे 2005-2012 के बीच, यह बताता है कि प्रस्तुत आँकड़े इस विस्तृत अवधि के सबसे हाल के वर्ष के लिए उपलब्ध आँकड़े हैं। दो वर्षों के बीच लगा स्लैश(/), जैसे 2005/2011, प्रदर्शित वर्षों के लिए औसत बताता है। वृद्धि दरें (ग्रोथ रेट) आमतौर पर दिए गए समयांतराल के पहले और अंतिम वर्ष के बीच के वृद्धि का सालाना औसत है।

सारणियों में निम्नलिखित प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं:

..	अनुपलब्ध
0 या 0.0	शून्य या नगण्य
–	लागू नहीं

सांख्यिकीय आभार

इस रिपोर्ट के मिश्रित सांख्यिकीय सूचकांक और सांख्यिकीय स्रोत, विशेष क्षेत्रों में विविध प्रकार के अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्वाधिक सम्मानित डेटा उपलब्धकर्ताओं से प्राप्त किए गए हैं, पर आधारित हैं। खासतौर पर हम इनके आभारी हैंः अमेरिकी ऊर्जा विभाग के कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ़ॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपीडेमियालॉजी ऑफ़ डिज़ास्टर; यूरोस्टैट, फ़ूड एग्रिकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन; गैलप; आई.सी.एफ़. मैक्रो; इंटरनैशनल एनर्जी एजेंसी; इंटरनैशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन; इंटरनैशनल मॉनिटरी फ़ंड; इंटरनैशनल टेलिकम्यूनिकेशन यूनियन; इंटरनैशनल यूनियन फॉर कन्ज़र्वेशन ऑफ़ नेचर; इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन; लक्ज़मबर्ग इनकम स्टडी; ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट; स्टॉकहोम इंटरनैशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट; युनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन फ़ंड; युनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेन्स ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट; युनाइटेड नेशन्स डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक एण्ड सोशल अफ़ेयर्स; युनाइटेड नेशन्स इकोनॉमिक कमिशन फ़ॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन; युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइन्टिफ़िक एण्ड कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन इन्स्टिट्यूट फ़ॉर स्टैटिस्टिक्स; युनाइटेड नेशन्स ऑफ़िस ऑन ड्रग एंड क्राइम; युनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गनाइज़ेशन; वर्ल्ड बैंक; वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन,और वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन। इस रिपोर्ट के सूचकांकों की गणना के लिए रॉबर्ट बारो (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी) और जॉन्ग व्हा ली (कोरिया यूनिवर्सिटी) द्वारा तैयार किया गया शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक डेटाबेस भी एक अन्य अमूल्य स्रोत है।

सांख्यिकीय सारणियाँ

पहली पाँच सारणियों में मिश्रित मानव विकास सूचकांक और उनके संघटक दिए गए हैं; अन्य नौ सारणियों में मानव विकास से संबंधित सूचकों के व्यापक समुच्चय के बारे में बताया गया है। चार मिश्रित मानव विकास सूचकांक– मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू), असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (अ.मा.वि.सू), लैंगिक असमानता सूचकांक (लै.अ.सू), और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (ब.नि.सू)– 2010 की मानव विकास रिपोर्ट के बाद से प्रस्तुत किए गए हैं। लै.अ.सू. और ब.नि.सू. प्रयोगात्मक सूचकांक ही रहेंगे।

सारणी 1 में मा.वि.सू. मान के साथ जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक प्राप्तियाँ और आय के चार संघटक सूचकों के मान को प्रस्तुत किया गया है। देशों को मा.वि.सू. मान के हिसाब से श्रेणीबद्ध किया गया है। सकल राष्ट्रीय आय और मा.वि.सू. के अनुसार श्रेणी में अंतर यह बताता है कि देश कुशलतापूर्वक अपनी आय का इस्तेमाल दो ग़ैर आय वाले मा.वि.सू. के आयामों में प्रगति के लिए कर रहे है या नहीं। ग़ैर आय मा.वि.सू. की गणना अंतर-देशीय तुलना के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने के लिए और ग़ैर आय आयामों में उपलब्धियों के अनुसार देशों को क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। मा.वि.सू. मानों की समय श्रृंखला 2012 में उपलब्ध आँकड़ों पर आधारित है, इस प्रकार ऐतिहासिक आँकड़ों और कार्यविधि की सर्वाधिक ताज़ा समीक्षा का इस्तेमाल करते हुए, उसे **सारणी 2** में प्रस्तुत किया गया है। सिर्फ़ यही साधन है, जो 2012 के मा.वि.सू. मान की तुलना पूर्व के वर्षों से कर सके। पिछले पाँच वर्षों और 2011 तथा 2012 के बीच मा.वि.सू. श्रेणी में बदलाव के साथ ही चार कालावधियों के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर से मा.वि.सू. बदलावों की दिशा और गति के आसान मूल्यांकन की अनुमति मिलती है।

सारणी 3 असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक के आँकड़े समक्ष रखती है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में किसी देश की औसत उपलब्धियों से परे जाकर, असमानता स्तर के अनुसार प्रत्येक आयाम के मान को घटाते हुए यह दर्शाती है कि निवासियों के बीच उपलब्धियों का वितरण किस प्रकार किया गया है। अ.मा.वि.सू. को मानव विकास (असमानता के अनुसार) के वास्तविक स्तर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि मा.वि.सू. संभावित मानव विकास है, जिसे, यदि निवासियों के बीच उपलब्धियों का समान वितरित कर दिया जाए, तो हासिल किया जा सकता है। मा.वि.सू. और असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (अ.मा.वि.सू.)के बीच अंतर को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया हो, तो यह असमानता के कारण संभावित मानव विकास में हानि को परिभाषित करता है। मा.वि.सू. और अ.मा.वि.सू. के अनुसार पदानुक्रम में अंतर दर्शाता है कि असमानता को ध्यान में रखते हुए किसी देश की श्रेणी घट सकती है (नकारात्मक मान) या बेहतर हो सकती है (सकारात्मक)।

सारणी 4 लैंगिक असमानता सूचकांक (लै.अ.सू.) के बारे में जानकारी देता है, जो तीन आयामोंः प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम बाज़ार में महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धियों की असमानता के लिए एक प्रयोगात्मक समग्र मापक है। लै.अ.सू. को नीतिगत विश्लेषणों और उसकी पैरवी के प्रयासों के लिए अनुभवजन्य बुनियाद उपलब्ध कराने के लिए आकल्पित किया गया है। उच्च मान, महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिक असमानता का संकेत करता है।

सारणी 5 में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (ब.नि.सू.) को प्रस्तुत किया गया है। यह एक प्रयोगात्मक मापक है, जो लोगों को शिक्षा-स्वास्थ्य और जीवन स्तर में परस्पर व्याप्त अभावों का पता लगना के लिए तैयार किया गया है। ब.नि.सू. ग़ैर आय बहुआयामी निर्धनता के फैलाव (बहुआयामी निर्धनता में रह रहे लोगों की संख्या) और उसकी तीव्रता (एक ही समय में वंचित व्यक्तियों के अनुभवों की सापेक्ष संख्या), दोनों के बारे में बताता है। ग़रीबी में जी रहे लोगों की व्यापक तस्वीर मुहैया कराने के लिए समग्र निर्धनता के प्रत्येक आयाम में वंचितता के योगदान को शामिल किया गया है। देशों को वर्णमाला के अनुसार दो समूहों में ब.नि.सू. के अनुमानों के लिए प्रयुक्त सर्वेक्षण वर्ष के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6 में सार्वजनिक व्यय के संकेतकों के साथ सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.), सकल स्थिर पूँजी (gross fixed capital) सृजन और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों को शामिल किया गया है। आर्थिक अनिश्चितता या मंदी के दौरान सकल स्थिर पूँजी सृजन आमतौर पर घटता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति के मापक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। खर्च में बदलाव का बेहतर विश्लेषण करने के लिए सार्वजनिक व्यय के संकेतकों को दो कालखंडों में व्यक्त किया गया है। इन संकेतकों का इस्तेमाल सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकताओं और व्यय के तरीकों और यह मानव विकास के नतीजों से किस तरह संबंधित है, इसका परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।

सारणी 7 में बच्चों, युवा और वयस्कों से संबंधित कई संकेतकों के साथ ही स्वास्थ्य गुणवत्ता के दो संकेतकों को प्रस्तुत किया गया है। **सारणी 8** में मानक शिक्षा संकेतकों के साथ ही वाचन, गणित और विज्ञान में औसत परीक्षा प्राप्तांक (और औसत प्राप्तांक से विचलन) सहित शिक्षा की गुणवत्ता पर भी संकेतक शामिल हैं। शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित संकेतक आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) द्वारा प्रबंधित कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के 63 सदस्य देशों के लिए 2009 के आँकड़ों का इस्तेमाल करते हुए 15 वर्षीय विद्यार्थियों के मानक परीक्षण पर आधारित हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के दो अतिरिक्त संकेतक, प्राथमिक दर्जे में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ एक अवधारणा आधारित संतुष्टि का संकेतक, परीक्षण आधारित गुणवत्ता संकेतकों को पूर्ण बना देते हैं।

सामाजिक एकीकरण पर **सारणी 9** के आँकड़े संकेत करते हैं कि क्या एक समाज समावेशी और एकीकृत है। संकेतक खासतौर से रोज़गार, व्यापक असमानता, मानव सुरक्षा, और विश्वास तथा सामुदायिक संतुष्टि के लिए समान अधिकार और अवसरों की सीमा को दर्शाते हैं। पूरक उद्देश्य संकेतक और अवधारणा आधारित संकेतक सामाजिक एकीकरण का अधिक सटीक दृश्य दर्शाते हैं। जीवन, आज़ादी और रोज़गार से संतुष्टि शीर्षक के तहत दिए गए आँकड़े लोगों की निजी दशाओं को लेकर व्यक्तिगत राय पर केन्द्रित हैं जबकि सामुदाय से संतुष्टि समेत लोगों और सरकार पर भरोसे से जुड़े आँकड़ों से व्यापक समाज के साथ लोगों की संतुष्टि को लेकर अंतर्दृष्टि मिलती है।

कोई देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ किस सीमा तक एकीकृत हो सकता है, इसे **सारणी 10** में दर्शाया गया है। वैश्विक मूल्य वर्धित और उत्पादन साझेदारी की परिघटना

को समझने के लिए तैयार वस्तु के व्यापार और अवयव-संघटकों के व्यापार में अंतर किया गया है, जिसके वैश्विक व्यापार की वृद्धि और दक्षिण के देशों में आर्थिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ हैं।

वैश्वीकरण के दो पहलुओं पर संकेतकः पूँजी प्रवाह और मानव आवागमन को **सारणी 11** में दर्शाया गया है। बढ़ता विदेशी निवेश बढ़ते आर्थिक वैश्वीकरण का एक माप है। प्रवासन काम करने और धन को वापस घर भेजने के लिए एक अवसर है। जबकि प्राप्तकर्ता देश में श्रम बल का विस्तार हो रहा है। सभी तरह का मानव आवागमन अंतर-सांस्कृतिक समझ के लिए भी महत्वपूर्ण कारक है।

सारणी 12 मानव विकास को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से अपनाने तथा इस्तेमाल के लिए देश में क्षमता निर्माण के लिए शोध और विकास में निवेश के महत्व को बताती है।

सारणी 13 पर्यावरणीय संवहनीयता पर प्रकाश डालती है। यह ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन और अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी दर्शाती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन आँकड़ों पर विचार करने के लिए तीन नज़रियों को प्रस्तुत करती है और पारिस्थितिकी तथा प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण उपायों को बताती है। सारणी में भौतिक पर्यावरणीय बदलावों के सीधे इन्सानों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित संकेतक भी हैं।

जनसंख्या की वर्तमान दशाओं और परिवर्तन की दिशा को समझने के लिए ज़रूरी प्रमुख जनसंख्या संकेतकों को **सारणी 14** में प्रस्तुत किया गया है। जनसंख्या की माध्यिका आयु, निर्भरता अनुपात और कुल प्रजनन दर के आँकड़ों की तुलना करके श्रम बल पर पड़ने वाले भार तथा खुद को बचाये रखने की समाज की योग्यता का आकलन किया जा सकता है। जन्म के समय प्राकृतिक लिंगानुपात से विचलन के जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर की दृष्टि से निहितार्थ हैं और यह लिंग भेद तथा भविष्य में संभावित सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की ओर संकेत करता है।

कुंजिका : मा.वि.सू. देश व उनकी श्रेणी, 2012

अफ़गानिस्तान	175
अल्बानिया	70
अल्जीरिया	93
अंडोरा	33
अंगोला	148
एंटिगुआ एवं बरबूडा	67
अर्जेन्टीना	45
आर्मेनिया	87
ऑस्ट्रेलिया	2
ऑस्ट्रिया	18
अज़रबैजान	82
बहामास	49
बहरीन	48
बांग्लादेश	146
बारबाडोस	38
बेलारूस	50
बेल्जियम	17
बेलीज	96
बेनिन	166
भूटान	140
प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	108
बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	81
बोत्स्वाना	119
ब्राज़ील	85
ब्रुनेई दारस्सलाम	30
बुल्गारिया	57
बुर्किना फ़ासो	183
बुरुण्डी	178
कंबोडिया	138
कैमरून	150
कनाडा	11
केप वर्दे	132
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य	180
चाड	184
चिली	40
चीन	101
कोलम्बिया	91
कॉमोरॉस	169
कॉन्गो	142
कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य	186
कोस्टा रिका	62
आइवरी कोस्ट	168
क्रोएशिया	47
क्यूबा	59
साइप्रस	31
चेक गणराज्य	28
डेनमार्क	15
जिबूती	164
डोमिनिका	72
डोमिनिकन गणराज्य	96
इक्वाडोर	89
मिस्र	112
अल सल्वाडोर	107
इक्वेटोरियल गिनी	136
एरिट्रिया	181
एस्टोनिया	33
इथियोपिया	173
फ़िजी	96
फ़िनलैण्ड	21
फ़्रांस	20
गैबन	106
गैम्बिआ	165

जॉर्जिआ	72
जर्मनी	5
घाना	135
यूनान	29
ग्रेनाडा	63
ग्वाटेमाला	133
गिनी	178
गिनी-बिसाउ	176
गयाना	118
हैती	161
होण्डुरास	120
हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	13
हंगरी	37
आइसलैण्ड	13
भारत	136
इण्डोनेशिया	121
इस्लामिक गणराज्य ईरान	76
इराक	131
आयरलैण्ड	7
इस्राइल	16
इटली	25
जमैका	85
जापान	10
जॉर्डन	100
कज़ाकिस्तान	69
केन्या	145
किरिबाती	121
कोरिया गणराज्य	12
कुवैत	54
किर्गिस्तान	125
लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	138
लात्विया	44
लेबनान	72
लेसोथो	158
लाइबेरिया	174
लीबिया	64
लिक्टन्सटाइन	24
लिथुआनिया	41
लक्ज़मबर्ग	26
मैडागास्कर	151
मलावी	170
मलेशिया	64
माल्दीव	104
माली	182
माल्टा	32
मॉरितानिया	155
मॉरिशस	80
मैक्सिको	61
फ़ेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	117
माल्डोवा गणराज्य	113
मंगोलिया	108
मॉन्टीनेग्रो	52
मोरक्को	130
मोज़ाम्बीक	185
म्यॉमार	149
नामीबिआ	128
नेपाल	157
नीदरलैण्ड	4
न्यूज़ीलैंड	6
निकारागुआ	129
नाइजर	186
नाइजीरिया	153

नॉर्वे	1
ओमान	84
पाकिस्तान	146
पलाउ	52
अधिकृत फ़लीस्तीनी क्षेत्र	110
पनामा	59
पापुआ न्यू गिनी	156
पराग्वे	111
पेरू	77
फ़िलीपीन्स	114
पोलैण्ड	39
पुर्तगाल	43
कतर	36
रोमानिआ	56
रूसी संघ	55
रवाण्डा	167
सेंट किट्स एवं नेविस	72
सेंट लूसिआ	88
सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	83
समोआ	96
साओ टोमे एवं प्रिन्साइप	144
सउदी अरब	57
सेनेगल	154
सर्बिआ	64
सेशेल्स	46
सिएरा लिओन	177
सिंगापुर	18
स्लोवाकिया	35
स्लोवेनिया	21
सॉलोमन द्वीप समूह	143
दक्षिण अफ़्रीका	121
स्पेन	23
श्रीलंका	92
सूडान	171
सूरीनाम	105
स्वाज़ीलैण्ड	141
स्वीडन	7
स्विटज़रलैण्ड	9
सीरियाई अरब गणराज्य	116
ताजिकिस्तान	125
तन्ज़ानिया संयुक्त गणराज्य	152
थाइलैण्ड	103
मेसाडोनिया, पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	78
टिमोर लेस्ट	134
टोगो	159
टोन्गा	95
ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	67
ट्यूनीशिया	94
तुर्की	90
तुर्कमेनिस्तान	102
युगाण्डा	161
युक्रेन	78
संयुक्त अरब अमीरात	41
यूनाइटेड किंगडम	26
यूनाइटेड स्टेट्स	3
उरुग्वे	51
उज़्बेकिस्तान	114
वनुआतू	124
वेनेज़ुएला, बोलिवेरियाई गणराज्य	71
वियतनाम	127
यमन	160
ज़ाम्बिया	163
ज़िम्बाब्वे	172

सारणी 1

मानव विकास सूचकांक और इसके संघटक

		मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.)	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	विद्यालय जाने के माध्य वर्ष	विद्यालय जाने के प्रत्याशित वर्ष	सकल घरेलू आय (स.घ.आ.) प्रति व्यक्ति	स.घ.आ. प्रति व्यक्ति श्रेणी से मा.वि.सू श्रेणी घटाकर	गैर आय मा.वि.सू.
		मान	(वर्षों में)	(वर्षों में)	(वर्षों में)	(2005 पी.पी.पी. $)		मान
मा.वि.सू. श्रेणी		2012	2012	2010[a]	2011[b]	2012	2012	2012
अति उच्च मानव विकास								
1	नार्वे	0.955	81.3	12.6	17.5	48,688	4	0.977
2	ऑस्ट्रेलिया	0.938	82.0	12.0[c]	19.6[d]	34,340	15	0.978
3	यूनाइटेड स्टेट्स	0.937	78.7	13.3	16.8	43,480	6	0.958
4	नीदरलैण्ड	0.921	80.8	11.6[c]	16.9	37,282	8	0.945
5	जर्मनी	0.920	80.6	12.2	16.4[e]	35,431	10	0.948
6	न्यूज़ीलैण्ड	0.919	80.8	12.5	19.7[d]	24,358	26	0.978
7	आयरलैण्ड	0.916	80.7	11.6	18.3[d]	28,671	19	0.960
7	स्वीडन	0.916	81.6	11.7[c]	16.0	36,143	6	0.940
9	स्विटजरलैण्ड	0.913	82.5	11.0[c]	15.7	40,527	2	0.926
10	जापान	0.912	83.6	11.6[c]	15.3	32,545	11	0.942
11	कनाडा	0.911	81.1	12.3	15.1	35,369	5	0.934
12	कोरिआ गणराज्य	0.909	80.7	11.6	17.2	28,231	15	0.949
13	हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	0.906	83.0	10.0	15.5	45,598	–6	0.907
13	आइसलैण्ड	0.906	81.9	10.4	18.3[d]	29,176	12	0.943
15	डेनमार्क	0.901	79.0	11.4[c]	16.8	33,518	4	0.924
16	इस्राइल	0.900	81.9	11.9	15.7	26,224	13	0.942
17	बेल्जियम	0.897	80.0	10.9[c]	16.4	33,429	3	0.917
18	ऑस्ट्रिया	0.895	81.0	10.8	15.3	36,438	–5	0.908
18	सिंगापुर	0.895	81.2	10.1[c]	14.4[f]	52,613	–15	0.880
20	फ्रांस	0.893	81.7	10.6[c]	16.1	30,277	4	0.919
21	फ़िनलैण्ड	0.892	80.1	10.3	16.9	32,510	2	0.912
21	स्लोवेनिया	0.892	79.5	11.7	16.9	23,999	12	0.936
23	स्पेन	0.885	81.6	10.4[c]	16.4	25,947	8	0.919
24	लिक्टेन्स्टाइन	0.883	79.8	10.3[g]	11.9	84,880[h]	–22	0.832
25	इटली	0.881	82.0	10.1[c]	16.2	26,158	5	0.911
26	लक्ज़मबर्ग	0.875	80.1	10.1	13.5	48,285	–20	0.858
26	यूनाइटेड किंगडम	0.875	80.3	9.4	16.4	32,538	–5	0.886
28	चेक गणराज्य	0.873	77.8	12.3	15.3	22,067	10	0.913
29	यूनान	0.860	80.0	10.1[c]	16.3	20,511	13	0.899
30	ब्रूनेई दारस्सलाम	0.855	78.1	8.6	15.0	45,690	–23	0.832
31	साइप्रस	0.848	79.8	9.8	14.9	23,825	4	0.869
32	माल्टा	0.847	79.8	9.9	15.1	21,184	9	0.876
33	अंडोरा	0.846	81.1	10.4[i]	11.7	33,918[j]	–15	0.839
33	एस्टोनिआ	0.846	75.0	12.0	15.8	17,402	13	0.892
35	स्लोवाकिआ	0.840	75.6	11.6	14.7	19,696	9	0.872
36	कतर	0.834	78.5	7.3	12.2	87,478[k]	–35	0.761
37	हंगरी	0.831	74.6	11.7	15.3	16,088	13	0.874
38	बारबाडोस	0.825	77.0	9.3	16.3	17,308	10	0.859
39	पोलैण्ड	0.821	76.3	10.0	15.2	17,776	7	0.851
40	चिली	0.819	79.3	9.7	14.7	14,987	13	0.863
41	लिथुआनिया	0.818	72.5	10.9	15.7	16,858	7	0.850
41	संयुक्त अरब अमीरात	0.818	76.7	8.9	12.0	42,716	–31	0.783
43	पुर्तगाल	0.816	79.7	7.7	16.0	19,907	0	0.835
44	लातीविया	0.814	73.6	11.5[c]	14.8	14,724	10	0.856
45	अर्जेंटीना	0.811	76.1	9.3	16.1	15,347	7	0.848
46	सेशेल्स	0.806	73.8	9.4[l]	14.3	22,615	–9	0.808
47	क्रोएशिया	0.805	76.8	9.8[c]	14.1	15,419	4	0.837
उच्च मानव विकास								
48	बहरीन	0.796	75.2	9.4	13.4[e]	19,154	–3	0.806
49	बहामास	0.794	75.9	8.5	12.6	27,401	–21	0.777
50	बेलारूस	0.793	70.6	11.5[l]	14.7	13,385	11	0.830
51	उरुग्वे	0.792	77.2	8.5[c]	15.5	13,333	11	0.829
52	मॉन्टीनेग्रो	0.791	74.8	10.5[l]	15.0	10,471	24	0.850
52	पलाउ	0.791	72.1	12.2	13.7[e]	11,463[m]	18	0.840
54	कुवैत	0.790	74.7	6.1	14.2	52,793	–51	0.730
55	रूसी गणराज्य	0.788	69.1	11.7	14.3	14,461	0	0.816
56	रोमानिया	0.786	74.2	10.4	14.5	11,011	16	0.836
57	बुल्गारिया	0.782	73.6	10.6[c]	14.0	11,474	12	0.826
57	सऊदी अरब	0.782	74.1	7.8	14.3	22,616	–21	0.774
59	क्यूबा	0.780	79.3	10.2	16.2	5,539[n]	44	0.894
59	पनामा	0.780	76.3	9.4	13.2	13,519	1	0.810

	मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू)	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	विद्यालय जाने के माध्य वर्ष	विद्यालय जाने के प्रत्याशित वर्ष	सकल घरेलू आय (स.घ.आ.) प्रति व्यक्ति	स.घ.आ. प्रति व्यक्ति श्रेणी से मा.वि.सू श्रेणी घटाकर	गैर आय मा.वि.सू.
	मान	(वर्षों में)	(वर्षों में)	(वर्षों में)	(2005 पी.पी.पी. $)		मान
मा.वि.सू. श्रेणी	2012	2012	2010[a]	2011[b]	2012	2012	2012
61 मैक्सिको	0.775	77.1	8.5	13.7	12,947	4	0.805
62 कोस्टा रिका	0.773	79.4	8.4	13.7	10,863	12	0.816
63 ग्रेनाडा	0.770	76.1	8.6 [e]	15.8	9,257	21	0.827
64 लीबिया	0.769	75.0	7.3	16.2	13,765	–8	0.791
64 मलेशिया	0.769	74.5	9.5	12.6	13,676	–7	0.791
64 सर्बिया	0.769	74.7	10.2 [c]	13.6	9,533	16	0.823
67 एंटिगुआ और बरबूडा	0.760	72.8	8.9	13.3	13,883	–12	0.776
67 ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	0.760	70.3	9.2	11.9	21,941	–28	0.743
69 कज़ाकिस्तान	0.754	67.4	10.4	15.3	10,451	8	0.791
70 अल्बानिआ	0.749	77.1	10.4	11.4	7,822	21	0.807
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	0.748	74.6	7.6 [c]	14.4	11,475	–2	0.774
72 डोमिनिका	0.745	77.6	7.7 [l]	12.7	10,977	–1	0.771
72 जॉर्जिआ	0.745	73.9	12.1 [o]	13.2	5,005	37	0.845
72 लेबनान	0.745	72.8	7.9 [l]	13.9	12,364	–5	0.762
72 सेंट किट्स एवं नेविस	0.745	73.3	8.4 [e]	12.9	12,460	–5	0.763
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	0.742	73.2	7.8	14.4	10,695	–1	0.769
77 पेरू	0.741	74.2	8.7	13.2	9,306	6	0.780
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	0.740	75.0	8.2 [o]	13.4	9,377	2	0.777
78 यूक्रेन	0.740	68.8	11.3	14.8	6,428	22	0.813
80 मॉरिशस	0.737	73.5	7.2	13.6	13,300	–17	0.745
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	0.735	75.8	8.3 [l]	13.4	7,713	13	0.787
82 अज़रबैजान	0.734	70.9	11.2 [l]	11.7	8,153	5	0.780
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	0.733	72.5	8.6 [e]	13.3	9,367	–1	0.767
84 ओमान	0.731	73.2	5.5 [l]	13.5	24,092	–51	0.694
85 ब्राज़ील	0.730	73.8	7.2	14.2	10,152	–8	0.755
85 जमैका	0.730	73.3	9.6	13.1	6,701	14	0.792
87 आर्मेनिआ	0.729	74.4	10.8	12.2	5,540	16	0.808
88 सेंट लूसिआ	0.725	74.8	8.3 [e]	12.7	7,971	1	0.768
89 इक्वाडोर	0.724	75.8	7.6	13.7	7,471	7	0.772
90 तुर्की	0.722	74.2	6.5	12.9	13,710	–32	0.720
91 कोलम्बिया	0.719	73.9	7.3	13.6	8,711	–6	0.751
92 श्रीलंका	0.715	75.1	9.3 [c]	12.7	5,170	18	0.792
93 अल्जीरिया	0.713	73.4	7.6	13.6	7,418	4	0.755
94 ट्यूनीशिया	0.712	74.7	6.5	14.5	8,103	–6	0.746
मध्यम मानव विकास							
95 टोंगा	0.710	72.5	10.3 [c]	13.7	4,153	26	0.807
96 बेलीज	0.702	76.3	8.0 [c]	12.5	5,327	8	0.767
96 डोमीनिकन गणराज्य	0.702	73.6	7.2 [c]	12.3	8,506	–11	0.726
96 फ़िजी	0.702	69.4	10.7 [c]	13.9	4,087	24	0.794
96 समोआ	0.702	72.7	10.3 [l]	13.0	3,928	28	0.800
100 जॉर्डन	0.700	73.5	8.6	12.7	5,272	8	0.766
101 चीन	0.699	73.7	7.5	11.7	7,945	–11	0.728
102 तुर्कमेनिस्तान	0.698	65.2	9.9 [p]	12.6 [e]	7,782	–10	0.727
103 थाइलैण्ड	0.690	74.3	6.6	12.3	7,722	–10	0.715
104 माल्दीव	0.688	77.1	5.8 [c]	12.5	7,478	–9	0.715
105 सूरीनाम	0.684	70.8	7.2 [o]	12.4	7,327	–7	0.710
106 गैबन	0.683	63.1	7.5	13.0	12,521	–40	0.668
107 अल सल्वाडोर	0.680	72.4	7.5	12.0	5,915	–5	0.723
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	0.675	66.9	9.2	13.5	4,444	7	0.740
108 मंगोलिया	0.675	68.8	8.3	14.3	4,245	10	0.746
110 फ़लस्तीन राज्य	0.670	73.0	8.0 [l]	13.5	3,359 [q]	20	0.761
111 पराग्वे	0.669	72.7	7.7	12.1	4,497	4	0.730
112 मिस्र	0.662	73.5	6.4	12.1	5,401	–6	0.702
113 माल्डोवा गणराज्य	0.660	69.6	9.7	11.8	3,319	19	0.747
114 फ़िलीपीन्स	0.654	69.0	8.9 [c]	11.7	3,752	11	0.724
114 उज़्बेकिस्तान	0.654	68.6	10.0 [o]	11.6	3,201	19	0.740
116 सीरियाई अरब गणराज्य	0.648	76.0	5.7 [c]	11.7 [e]	4,674 [r]	–2	0.692
117 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	0.645	69.2	8.8 [p]	11.4 [e]	3,352 [m]	14	0.719
118 गयाना	0.636	70.2	8.5	10.3	3,387	11	0.703
119 बोत्स्वाना	0.634	53.0	8.9	11.8	13,102	–55	0.596
120 होण्डुरास	0.632	73.4	6.5	11.4	3,426	8	0.695
121 इण्डोनेशिया	0.629	69.8	5.8	12.9	4,154	–3	0.672

मा.वि.सू. श्रेणी		मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू)	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	विद्यालय जाने के माध्य वर्ष	विद्यालय जाने के प्रत्याशित वर्ष	सकल घरेलू आय (स.घ.आ.) प्रति व्यक्ति	स.घ.आ. प्रति व्यक्ति श्रेणी से मा.वि.सू श्रेणी घटाकर	गैर आय मा.वि.सू.
		मान	(वर्षों में)	(वर्षों में)	(वर्षों में)	(2005 पी.पी.पी. $)		मान
		2012	2012	2010[a]	2011[b]	2012	2012	2012
121	किरिबाती	0.629	68.4	7.8 [e]	12.0	3,079	13	0.701
121	दक्षिण अफ़्रीका	0.629	53.4	8.5 [c]	13.1 [e]	9,594	–42	0.608
124	वनुआतू	0.626	71.3	6.7 [e]	10.6	3,960	–1	0.672
125	किर्गिस्तान	0.622	68.0	9.3	12.6	2,009	24	0.738
125	ताजिकिस्तान	0.622	67.8	9.8	11.5	2,119	19	0.731
127	वियतनाम	0.617	75.4	5.5	11.9	2,970	9	0.686
128	नामीबिया	0.608	62.6	6.2	11.3	5,973	–27	0.611
129	निकारागुआ	0.599	74.3	5.8	10.8	2,551	10	0.671
130	मोरक्को	0.591	72.4	4.4	10.4	4,384	–13	0.608
131	इराक	0.590	69.6	5.6	10.0	3,557	–4	0.623
132	केप वर्दे	0.586	74.3	3.5 [e]	12.7	3,609	–6	0.617
133	ग्वाटेमाला	0.581	71.4	4.1	10.7	4,235	–14	0.596
134	टिमोर लेस्ट	0.576	62.9	4.4 [s]	11.7	5,446	–29	0.569
135	घाना	0.558	64.6	7.0	11.4	1,684	22	0.646
136	इक्वेटोरिअल गिनी	0.554	51.4	5.4 [o]	7.9	21,715	–97	0.463
136	भारत	0.554	65.8	4.4	10.7	3,285	–3	0.575
138	कम्बोडिया	0.543	63.6	5.8	10.5	2,095	9	0.597
138	लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	0.543	67.8	4.6	10.1	2,435	2	0.584
140	भूटान	0.538	67.6	2.3 [s]	12.4	5,246	–31	0.516
141	स्वाज़ीलैण्ड	0.536	48.9	7.1	10.7	5,104	–30	0.515
निम्न मानव विकास								
142	कौंगो	0.534	57.8	5.9	10.1	2,934	–5	0.553
143	सॉलोमन द्वीपसमूह	0.530	68.2	4.5 [p]	9.3	2,172	1	0.572
144	साओ टोम एवं प्रिन्साइप	0.525	64.9	4.7 [s]	10.8	1,864	7	0.579
145	केन्या	0.519	57.7	7.0	11.1	1,541	15	0.588
146	बांग्लादेश	0.515	69.2	4.8	8.1	1,785	9	0.567
146	पाकिस्तान	0.515	65.7	4.9	7.3	2,566	–9	0.534
148	अंगोला	0.508	51.5	4.7 [s]	10.2	4,812	–35	0.479
149	म्यॉंमार	0.498	65.7	3.9	9.4	1,817	5	0.537
150	कैमरून	0.495	52.1	5.9	10.9	2,114	–4	0.520
151	मैडागास्कर	0.483	66.9	5.2 [p]	10.4	828	28	0.601
152	तंज़ानिया गणराज्य	0.476	58.9	5.1	9.1	1,383	10	0.527
153	नाइजीरिया	0.471	52.3	5.2 [s]	9.0	2,102	–6	0.482
154	सेनेगल	0.470	59.6	4.5	8.2	1,653	4	0.501
155	मॉरिटानिया	0.467	58.9	3.7	8.1	2,174	–12	0.473
156	पापुआ न्यू गिनी	0.466	63.1	3.9	5.8 [e]	2,386	–15	0.464
157	नेपाल	0.463	69.1	3.2	8.9	1,137	11	0.526
158	लेसोथो	0.461	48.7	5.9 [c]	9.6	1,879	–8	0.476
159	टोगो	0.459	57.5	5.3	10.6	928	16	0.542
160	यमन	0.458	65.9	2.5	8.7	1,820	–7	0.474
161	हैती	0.456	62.4	4.9	7.6 [e]	1,070	7	0.521
161	युगाण्डा	0.456	54.5	4.7	11.1	1,168	5	0.511
163	ज़ाम्बिया	0.448	49.4	6.7	8.5	1,358	0	0.483
164	जिबूती	0.445	58.3	3.8 [o]	5.7	2,350	–22	0.435
165	गैम्बिया	0.439	58.8	2.8	8.7	1,731	–9	0.448
166	बेनिन	0.436	56.5	3.2	9.4	1,439	–5	0.459
167	रवाण्डा	0.434	55.7	3.3	10.9	1,147	0	0.476
168	आइवरी कोस्ट	0.432	56.0	4.2	6.5	1,593	–9	0.444
169	कोमोरॉस	0.429	61.5	2.8 [p]	10.2	986	4	0.484
170	मलावी	0.418	54.8	4.2	10.4	774	10	0.492
171	सूडान	0.414	61.8	3.1	4.5	1,848	–19	0.405
172	ज़िम्बाब्वे	0.397	52.7	7.2	10.1	424 [t]	14	0.542
173	इथियोपिया	0.396	59.7	2.2 [s]	8.7	1,017	–2	0.425
174	लाइबेरिया	0.388	57.3	3.9	10.5 [e]	480	11	0.502
175	अफ़ग़ानिस्तान	0.374	49.1	3.1	8.1	1,000	–3	0.393
176	गिनी बिसाउ	0.364	48.6	2.3 [o]	9.5	1,042	–6	0.373
177	सिएरा लिओन	0.359	48.1	3.3	7.3 [e]	881	0	0.380
178	बुरुण्डी	0.355	50.9	2.7	11.3	544	4	0.423
178	गिनी	0.355	54.5	1.6 [s]	8.8	941	–4	0.368
180	मध्य अफ़्रीकी गणराज्य	0.352	49.1	3.5	6.8	722	1	0.386
181	इरिट्रिया	0.351	62.0	3.4 [e]	4.6	531	3	0.418
182	माली	0.344	51.9	2.0 [c]	7.5	853	–4	0.359
183	बुर्किना फ़ासो	0.343	55.9	1.3 [o]	6.9	1,202	–18	0.332

	मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू)	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	विद्यालय जाने के माध्य वर्ष	विद्यालय जाने के प्रत्याशित वर्ष	सकल घरेलू आय (स.घ.आ.) प्रति व्यक्ति	स.घ.आ. प्रति व्यक्ति श्रेणी से मा.वि.सू श्रेणी घटाकर	गैर आय मा.वि.सू.
	मान	(वर्षों में)	(वर्षों में)	(वर्षों में)	(2005 पी.पी.पी. $)		मान
मा.वि.सू. श्रेणी	2012	2012	2010[a]	2011[b]	2012	2012	2012
184 चाड	0.340	49.9	1.5[p]	7.4	1,258	–20	0.324
185 मोज़ाम्बीक	0.327	50.7	1.2	9.2	906	–9	0.327
186 कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	0.304	48.7	3.5	8.5	319	0	0.404
186 नाइज़र	0.304	55.1	1.4	4.9	701	–4	0.313
अन्य देश अथवा अंचल							
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	..	69.0	..	..	..	..	..
मार्शल द्वीप समूह	..	72.3	..	11.7	..	..	..
मोनाको	..	82.3	..	..	..	..	..
नाउरू	..	80.0	..	9.3	..	..	..
सैन मैरीनो	..	81.9	..	12.5	..	..	..
सोमालिया	..	51.5	..	2.4	..	..	..
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..
तुवालू	..	67.5	..	10.8	..	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह							
अति उच्च मानव विकास	0.905	80.1	11.5	16.3	33,391	—	0.927
उच्च मानव विकास	0.758	73.4	8.8	13.9	11,501	—	0.781
मध्यम मानव विकास	0.640	69.9	6.3	11.4	5,428	—	0.661
निम्न मानव विकास	0.466	59.1	4.2	8.5	1,633	—	0.487
क्षेत्र							
अरब देश	0.652	71.0	6.0	10.6	8,317	—	0.658
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	0.683	72.7	7.2	11.8	6,874	—	0.712
यूरोप एवं मध्य एशिया	0.771	71.5	10.4	13.7	12,243	—	0.801
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	0.741	74.7	7.8	13.7	10,300	—	0.770
दक्षिण एशिया	0.558	66.2	4.7	10.2	3,343	—	0.577
सब-सहारा अफ्रीका	0.475	54.9	4.7	9.3	2,010	—	0.479
न्यूनतम विकसित देश	0.449	59.5	3.7	8.5	1,385	—	0.475
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	0.648	69.8	7.3	10.7	5,397	—	0.673
विश्व	**0.694**	**70.1**	**7.5**	**11.6**	**10,184**	**—**	**0.690**

नोट

a आँकड़े 2010 के या उपलब्ध सबसे हाल के वर्ष के।

b आँकड़े 2011 के या उपलब्ध सबसे हाल के वर्ष के।

c यूनेस्को के 2011 के आँकड़ों के आधार पर एच.डी.आर.ओ. द्वारा अद्यतन की गई।

d मा.वि.सू. गणना के लिए इस मान की सीमा 18 वर्ष तय की गई है।

e विभिन्न देशों के बीच समाश्रायण (regresion) पर आधारित।

f सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई गणना।

g वही बालिग माध्य वर्ष मान लिए गए जो स्विट्जरलैंड में अद्यतन अपडेट के पहले थे।

h क्रय शक्ति समानता (पी.पी.पी.) दर और स्विट्जरलैंड की प्रक्षेपित संवृद्धि दर के आधार पर अनुमानित।

i क्रय शक्ति समानता (पी.पी.पी.) दर और स्पेन की प्रक्षेपित संवृद्धि दर के आधार पर अनुमानित।

j क्रय शक्ति समानता (पी.पी.पी.) दर और स्पेन की प्रक्षेपित संवृद्धि दर के आधार पर अनुमानित।

k आई.एम.एफ.(2012) के अंतर्निहित परिवर्तन कारकों पर आधारित

l यूनेस्को सांख्यिकी संस्था (2012) के शैक्षिक उपलब्धि वितरण के अनुमान पर आधारित.

m एशियाई विकास बैंक (2012) द्वारा प्रक्षेपित संवृद्धि दरों पर आधारित।

n सभी देशों के बीच समाश्रयण पर आधारित क्रय शक्ति समानता अनुमान, ECLAC (2012) और UNDESA (2012C) द्वारा प्रक्षेपित संवृद्धि दरों पर आधारित संवृद्धि दर।

o यूनिसेफ के विविध संकेतक क्लस्टर सर्वे 2002–2012 पर आधारित।

p विश्व बैंक अंतराराष्ट्रीय आय वितरण डाटाबेस में उपलब्ध घरेलू सर्वे के बालिगों के स्कूल जाने के वर्षों के आँकड़ें पर आधारित।

q विश्व बैंक के क्रय शक्ति समानता परिवर्तन दर के अप्रकाशित अनुमान और UNESCWA (2012) और UNDESA (2012C) द्वारा संक्षेपित संवृद्धि दरों पर आधारित।

r UNDESA (2012C) के प्रक्षेपित संवृद्धि दरों पर आधारित।

s आई.सी.एफ. मैक्रो (2012) के आंकडों पर आधारित.

t आई.एम.एफ. (2012) के क्रय शक्ति समानता आँकड़ों पर आधारित.

परिभाषाएँ

मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) : मानव जीवन के तीन प्राथमिक आयामों– लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और सम्मानजनक जीवन स्तर– में औसत उपलब्धियों को मापने वाला एक सम्मिश्र सूचकांक। मा.वि.सू. की गणना किस तरह की जाती है, यह देखने के लिए तकनीकी नोट 1 को http://hdr.unp.org/en/media/HDR_2013_EN_TechNotes.pdf पर देखें।

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा : यदि आयु-विशेष सम्बन्धी मौजूदा मृत्यु दरें जन्म के समय से नवजात के जीवन भर स्थिर रहें, तो उन वर्षों की संख्या जितने वर्ष नवजात के जीने की प्रत्याशा की जा सकती है।

स्कूल जाने के माध्य वर्ष : पच्चीस वर्ष तथा इससे अधिक आयु के लोगों के शिक्षा ग्रहण के औसत वर्ष, शैक्षिक उपलब्धिके स्तरों को परिवर्तित करके प्राप्त– हरेक स्तर की अवधि के लिए आधिकारिक मान का प्रयोग करते हुए।

स्कूली शिक्षा के सम्भावित वर्ष : स्कूल में प्रवेश पाने योग्य उम्र के बच्चे के लिए स्कूली शिक्षा पाने का वे वर्ष जिनकी वह उम्मीद कर सकता है यदि आयु विशेष सम्बन्धी स्कूल नामांकन की मौजूदा दरें बच्चे के पूरे जीवन में स्थिर रहें।

प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (स.रा.आ.): किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा सृजित वह कुल आय जो उसके उत्पादन तथा उसके उत्पादन के कारकों के स्वामित्व से पैदा होती है, इस में से वह आय घटाएँ जिसका भुगतान शेष विश्व द्वारा उत्पादन के कारकों के उपयोग के लिए किया गया, इसे क्रय शक्ति समतुल्यता दरों का उपयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय डालरों में बदलें और प्राप्त मान को देश की वर्ष-माध्य की जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त मान।

प्रति व्यक्ति स.रा.आ. श्रेणी मान व मा.वि.सू. श्रेणी मान का अंतर: प्रति व्यक्ति स.रा.आ. और मा.वि.सू. के श्रेणी मानों का अंतर। नकारात्मक मान का अर्थ है कि उस देश की श्रेणी मा.वि.सू. के मुकाबले स.रा.आ. में बेहतर है।

ग़ैर आय मा.वि.सू. : मा.वि.सू. का वह मान जो जीवन प्रत्याशा के तथा शिक्षा के सूचकों मात्र से आकलित किया गया है।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1:एच.डी.आर.ओ. की UNDESA (2011), बर्रो एवं ली (2011), यूनेस्को सांख्यिकी संस्था (2012), विश्व बैंक (2012a) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2012) पर आधारित गणनाएँ।

कॉलम 2 : UNDESA (2011)।

कॉलम 3 : बर्रो एवं ली (2011) और यूनेस्को सांख्यिकी संस्था के शिक्षा प्राप्ति के आँकड़ों तथा बर्रो एवं ली (2010) की कार्यविधि पर आधारित एच.डी.आर.ओ. के अद्यतन अपडेट।

कॉलम 4 : यूनेस्को सांख्यिकी संस्था (2012)।

कॉलम 5 : विश्व बैंक (2012a), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2012) और यू.एन.एस.डी. (2012a) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. की गणनाएँ।

कॉलम 6: कॉलम 1 तथा 5 पर आधारित गणनाएँ।

कॉलम 7: कॉलम 2,3 तथा 4 पर आधारित गणनाएँ।

सारणी 2

मानव विकास सूचकांक प्रवृत्तियाँ, 1980-2012

मा.वि.सू. श्रेणी	मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.)								मा.वि.सू. श्रेणी		औसत वार्षिक मा.वि.सू. वृद्धि			
	मान								परिवर्तन		(%)			
	1980	1990	2000	2005	2007	2010	2011	2012	2007–2012[a]	2011–2012[a]	1980/1990	1990/2000	2000/2010	2000/2012
अति उच्च मानव विकास														
1 नार्वे	0.804	0.852	0.922	0.948	0.952	0.952	0.953	0.955	0	0	0.59	0.79	0.32	0.29
2 ऑस्ट्रेलिया	0.857	0.880	0.914	0.927	0.931	0.935	0.936	0.938	0	0	0.27	0.37	0.23	0.22
3 यूनाइटेड स्टेट्स	0.843	0.878	0.907	0.923	0.929	0.934	0.936	0.937	0	–1	0.40	0.33	0.29	0.27
4 नीदरलैण्ड	0.799	0.842	0.891	0.899	0.911	0.919	0.921	0.921	2	0	0.52	0.56	0.31	0.28
5 जर्मनी	0.738	0.803	0.870	0.901	0.907	0.916	0.919	0.920	5	0	0.85	0.81	0.53	0.47
6 न्यूज़ीलैण्ड	0.807	0.835	0.887	0.908	0.912	0.917	0.918	0.919	–1	0	0.34	0.60	0.33	0.29
7 आयरलैण्ड	0.745	0.793	0.879	0.907	0.918	0.916	0.915	0.916	–3	0	0.62	1.04	0.42	0.35
7 स्वीडन	0.792	0.823	0.903	0.905	0.909	0.913	0.915	0.916	0	0	0.38	0.93	0.11	0.12
9 स्विटज़रलैण्ड	0.818	0.840	0.882	0.898	0.901	0.912	0.912	0.913	3	0	0.27	0.49	0.33	0.29
10 जापान	0.788	0.837	0.878	0.896	0.903	0.909	0.910	0.912	1	0	0.61	0.48	0.35	0.32
11 कनाडा	0.825	0.865	0.887	0.906	0.909	0.909	0.910	0.911	–4	–1	0.48	0.25	0.24	0.22
12 कोरिआ गणराज्य	0.640	0.749	0.839	0.875	0.890	0.905	0.907	0.909	4	0	1.58	1.14	0.76	0.67
13 हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	0.712	0.788	0.815	0.857	0.877	0.900	0.904	0.906	10	1	1.02	0.34	1.00	0.89
13 आइसलैण्ड	0.769	0.815	0.871	0.901	0.908	0.901	0.905	0.906	–4	0	0.58	0.67	0.34	0.33
15 डेनमार्क	0.790	0.816	0.869	0.893	0.898	0.899	0.901	0.901	–2	0	0.33	0.63	0.34	0.30
16 इस्राइल	0.773	0.809	0.865	0.885	0.892	0.896	0.899	0.900	–2	0	0.45	0.68	0.34	0.33
17 बेल्जियम	0.764	0.817	0.884	0.884	0.891	0.896	0.897	0.897	–2	0	0.67	0.79	0.14	0.12
18 ऑस्ट्रिया	0.747	0.797	0.848	0.867	0.879	0.892	0.894	0.895	2	0	0.66	0.62	0.51	0.46
18 सिंगापुर	..	0.756	0.826	0.852	..	0.892	0.894	0.895	7	0	..	0.89	0.77	0.67
20 फ्रांस	0.728	0.784	0.853	0.877	0.885	0.891	0.893	0.893	–1	0	0.75	0.85	0.44	0.38
21 फ़िनलैण्ड	0.766	0.801	0.845	0.882	0.890	0.890	0.892	0.892	–5	0	0.45	0.54	0.52	0.45
21 स्लोवेनिया	..	..	0.842	0.876	0.888	0.892	0.892	0.892	–3	0	..	..	0.58	0.48
23 स्पेन	0.698	0.756	0.847	0.865	0.874	0.884	0.885	0.885	1	0	0.80	1.15	0.43	0.37
24 लिक्टेन्स्टाइन	..	..	..	..	..	0.882	0.883	0.883	..	0	..	..	..	..
25 इटली	0.723	0.771	0.833	0.869	0.878	0.881	0.881	0.881	–2	0	0.64	0.78	0.56	0.46
26 लक्ज़मबर्ग	0.735	0.796	0.861	0.875	0.879	0.875	0.875	0.875	–5	0	0.81	0.78	0.16	0.14
26 यूनाइटेड किंगडम	0.748	0.784	0.841	0.865	0.867	0.874	0.875	0.875	2	0	0.47	0.70	0.39	0.33
28 चेक गणराज्य	..	..	0.824	0.862	0.869	0.871	0.872	0.873	–1	0	..	..	0.56	0.48
29 यूनान	0.726	0.772	0.810	0.862	0.865	0.866	0.862	0.860	0	0	0.62	0.48	0.67	0.50
30 ब्रूनेई दारस्सलाम	0.765	0.782	0.830	0.848	0.853	0.854	0.854	0.855	0	0	0.22	0.59	0.28	0.25
31 साइप्रस	0.715	0.779	0.808	0.817	0.827	0.849	0.849	0.848	4	0	0.86	0.36	0.50	0.41
32 माल्टा	0.713	0.757	0.801	0.827	0.829	0.844	0.846	0.847	2	1	0.59	0.57	0.52	0.46
33 अंडोरा	..	..	..	..	..	0.846	0.847	0.846	..	–1	..	..	..	..
33 एस्टोनिआ	..	0.728	0.786	0.830	0.841	0.839	0.844	0.846	–2	1	..	0.76	0.65	0.62
35 स्लोवाकिआ	..	0.754	0.785	0.814	0.830	0.836	0.838	0.840	–1	0	..	0.40	0.64	0.57
36 कतर	0.729	0.743	0.801	0.828	0.833	0.827	0.832	0.834	–3	0	0.18	0.76	0.32	0.33
37 हंगरी	0.709	0.714	0.790	0.820	0.826	0.829	0.830	0.831	1	0	0.07	1.02	0.48	0.42
38 बारबाडोस	0.706	0.760	0.790	0.798	0.808	0.823	0.824	0.825	2	0	0.73	0.38	0.41	0.37
39 पोलैण्ड	..	..	0.778	0.798	0.806	0.817	0.819	0.821	3	0	..	..	0.49	0.46
40 चिली	0.638	0.702	0.759	0.789	0.800	0.813	0.817	0.819	5	0	0.96	0.78	0.68	0.64
41 लिथुआनिया	..	0.732	0.756	0.802	0.810	0.810	0.814	0.818	–2	2	..	0.32	0.68	0.65
41 संयुक्त अरब अमीरात	..	..	..	0.831	0.827	0.816	0.817	0.818	–5	–1	..	..	..	..
43 पुर्तगाल	0.644	0.714	0.783	0.796	0.806	0.817	0.817	0.816	–1	–3	1.04	0.93	0.43	0.35
44 लातीविया	0.675	0.699	0.738	0.792	0.808	0.805	0.809	0.814	–4	1	0.35	0.55	0.87	0.82
45 अर्जेंटीना	0.675	0.701	0.755	0.771	0.787	0.805	0.810	0.811	4	–1	0.38	0.74	0.64	0.60
46 सेशेल्स	..	..	0.774	0.781	0.792	0.799	0.804	0.806	1	0	..	..	0.31	0.33
47 क्रोएशिया	..	0.716	0.755	0.787	0.798	0.804	0.804	0.805	–1	–1	..	0.52	0.63	0.54
उच्च मानव विकास														
48 बहरीन	0.644	0.713	0.781	0.802	0.802	0.794	0.795	0.796	–4	0	1.02	0.92	0.16	0.15
49 बहामास	..	..	..	..	..	0.791	0.792	0.794	..	0	..	..	..	..
50 बेलारूस	..	..	..	0.730	0.756	0.785	0.789	0.793	12	1	..	..	..	..
51 उरुग्वे	0.664	0.693	0.741	0.744	0.771	0.785	0.789	0.792	3	0	0.42	0.68	0.58	0.55
52 मॉन्टीनेग्रो	..	..	..	0.756	0.775	0.787	0.791	0.791	0	–2	..	..	..	..
52 पलाउ	..	..	0.765	0.786	0.792	0.779	0.786	0.791	–4	2	..	..	0.18	0.27
54 कुवैत	0.695	0.712	0.781	0.784	0.787	0.786	0.788	0.790	–4	–1	0.25	0.92	0.06	0.10
55 रूसी गणराज्य	..	0.730	0.713	0.753	0.770	0.782	0.784	0.788	0	0	..	–0.23	0.93	0.84
56 रोमानिया	..	0.706	0.709	0.756	0.772	0.783	0.784	0.786	–3	–1	..	0.05	0.99	0.86
57 बुल्गारिया	0.673	0.704	0.721	0.756	0.766	0.778	0.780	0.782	0	0	0.45	0.24	0.77	0.67
57 सऊदी अरब	0.575	0.653	0.717	0.748	0.756	0.777	0.780	0.782	5	0	1.29	0.93	0.81	0.74
59 क्यूबा	0.626	0.681	0.690	0.735	0.770	0.775	0.777	0.780	–4	0	0.83	0.14	1.17	1.02
59 पनामा	0.634	0.666	0.724	0.746	0.758	0.770	0.776	0.780	1	1	0.49	0.85	0.62	0.62
61 मैक्सिको	0.598	0.654	0.723	0.745	0.758	0.770	0.773	0.775	–1	0	0.89	1.00	0.64	0.59
62 कोस्टा रिका	0.621	0.663	0.705	0.732	0.744	0.768	0.770	0.773	4	0	0.65	0.62	0.85	0.76
63 ग्रेनाडा	..	..	..	..	..	0.768	0.770	0.770	..	–1	..	..	..	..

	मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.)								मा.वि.सू. श्रेणी		औसत वार्षिक मा.वि.सू. वृद्धि			
	मान								परिवर्तन		(%)			
मा.वि.सू. श्रेणी	1980	1990	2000	2005	2007	2010	2011	2012	2007–2012[a]	2011–2012[a]	1980/1990	1990/2000	2000/2010	2000/2012
64 लीबिया	..	..	..	0.746	0.760	0.773	0.725	0.769	–5	23[b]	..	..	..	..
64 मलेशिया	0.563	0.635	0.712	0.742	0.753	0.763	0.766	0.769	1	1	1.21	1.15	0.69	0.64
64 सर्बिया	..	..	0.726	0.751	0.760	0.767	0.769	0.769	–5	0	..	..	0.56	0.49
67 एंटिगुआ और बरबूडा	..	..	..	..	..	0.761	0.759	0.760	..	–1	..	..	..	..
67 ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	0.680	0.685	0.707	0.741	0.752	0.758	0.759	0.760	–1	–1	0.08	0.32	0.70	0.60
69 कज़ाकिस्तान	..	..	0.663	0.721	0.734	0.744	0.750	0.754	2	–1	..	..	1.15	1.08
70 अल्बानिआ	..	0.661	0.698	0.729	0.737	0.746	0.748	0.749	0	–1	..	0.54	0.66	0.59
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	0.629	0.635	0.662	0.694	0.712	0.744	0.746	0.748	9	–1	0.11	0.41	1.17	1.03
72 डोमिनिका	..	..	0.722	0.732	0.739	0.743	0.744	0.745	–3	0	..	..	0.28	0.26
72 जॉर्जिआ	..	..	..	0.713	0.732	0.735	0.740	0.745	0	3	..	..	..	..
72 लेबनान	..	..	..	0.714	0.728	0.743	0.744	0.745	3	0	..	..	..	..
72 सेंट किट्स एवं नेविस	..	..	..	..	..	0.745	0.745	0.745	..	–1	..	..	..	..
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	0.443	0.540	0.654	0.685	0.706	0.740	0.742	0.742	7	–2	1.99	1.94	1.25	1.05
77 पेरू	0.580	0.619	0.679	0.699	0.716	0.733	0.738	0.741	3	–1	0.65	0.93	0.78	0.73
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	..	..	..	0.711	0.719	0.736	0.738	0.740	1	–2	..	..	..	..
78 यूक्रेन	..	0.714	0.673	0.718	0.732	0.733	0.737	0.740	–5	0	..	–0.58	0.85	0.80
80 मॉरिशस	0.551	0.626	0.676	0.708	0.720	0.732	0.735	0.737	–2	–1	1.28	0.77	0.81	0.73
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	..	..	..	0.724	0.729	0.733	0.734	0.735	–6	–1	..	..	..	..
82 अजरबैजान	..	..	..	..	..	0.734	0.732	0.734	..	–1	..	..	..	..
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	..	..	..	..	..	0.731	0.732	0.733	..	–2	..	..	..	..
84 ओमान	..	..	..	..	..	0.728	0.729	0.731	..	–1	..	..	..	..
85 ब्राज़ील	0.522	0.590	0.669	0.699	0.710	0.726	0.728	0.730	0	0	1.23	1.26	0.82	0.73
85 जमैका	0.612	0.642	0.679	0.695	0.701	0.727	0.729	0.730	4	–2	0.47	0.57	0.69	0.61
87 अर्मेनिआ	..	0.628	0.648	0.695	0.723	0.722	0.726	0.729	–7	–1	..	0.33	1.08	0.98
88 सेंट लूसिआ	..	..	..	..	..	0.723	0.724	0.725	..	0	..	..	..	..
89 इक्वाडोर	0.596	0.635	0.659	0.682	0.688	0.719	0.722	0.724	10	0	0.63	0.37	0.89	0.79
90 तुर्की	0.474	0.569	0.645	0.684	0.702	0.715	0.720	0.722	–1	0	1.85	1.26	1.04	0.95
91 कोलम्बिया	0.556	0.600	0.658	0.681	0.698	0.714	0.717	0.719	0	0	0.76	0.93	0.82	0.75
92 श्रीलंका	0.557	0.608	0.653	0.683	0.693	0.705	0.711	0.715	5	0	0.88	0.72	0.78	0.76
93 अल्जीरिया	0.461	0.562	0.625	0.680	0.691	0.710	0.711	0.713	5	–1	2.01	1.07	1.28	1.10
94 ट्यूनीशिया	0.459	0.553	0.642	0.679	0.694	0.710	0.710	0.712	2	0	1.87	1.51	1.01	0.86
मध्यम मानव विकास														
95 टोंगा	..	0.656	0.689	0.704	0.705	0.709	0.709	0.710	–7	0	..	0.49	0.28	0.25
96 बेलीज	0.621	0.653	0.672	0.694	0.696	0.700	0.701	0.702	–4	0	0.51	0.29	0.40	0.35
96 डोमीनिकन गणराज्य	0.525	0.584	0.641	0.669	0.683	0.697	0.700	0.702	4	2	1.07	0.93	0.85	0.76
96 फ़िजी	0.572	0.614	0.670	0.693	0.695	0.699	0.700	0.702	–3	2	0.71	0.87	0.43	0.39
96 समोआ	..	..	0.663	0.689	0.695	0.699	0.701	0.702	–3	0	..	..	0.52	0.48
100 जॉर्डन	0.545	0.592	0.650	0.684	0.695	0.699	0.699	0.700	–7	0	0.83	0.95	0.72	0.62
101 चीन	0.407	0.495	0.590	0.637	0.662	0.689	0.695	0.699	4	0	1.96	1.78	1.55	1.42
102 तुर्कमेनिस्तान	..	..	..	..	..	0.688	0.693	0.698	..	0	..	..	..	..
103 थाइलैण्ड	0.490	0.569	0.625	0.662	0.676	0.686	0.686	0.690	–1	1	1.50	0.94	0.93	0.82
104 माल्दीव	..	..	0.592	0.639	0.663	0.683	0.687	0.688	1	–1	..	..	1.43	1.26
105 सूरीनाम	..	..	..	0.666	0.672	0.679	0.681	0.684	–2	0	..	..	..	..
106 गैबन	0.526	0.610	0.627	0.653	0.662	0.676	0.679	0.683	0	0	1.49	0.27	0.75	0.72
107 अल सल्वाडोर	0.471	0.528	0.620	0.655	0.671	0.678	0.679	0.680	–3	–1	1.14	1.62	0.90	0.78
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	0.489	0.557	0.620	0.647	0.652	0.668	0.671	0.675	0	0	1.31	1.08	0.75	0.71
108 मंगोलिया	..	0.559	0.564	0.622	0.638	0.657	0.668	0.675	4	2	..	0.08	1.54	1.51
110 फ़लस्तीन राज्य	..	..	..	..	..	0.662	0.666	0.670	..	1	..	..	..	..
111 पराग्वे	0.549	0.578	0.617	0.641	0.650	0.668	0.670	0.669	–1	–2	0.52	0.66	0.79	0.67
112 मिस्र	0.407	0.502	0.593	0.625	0.640	0.661	0.661	0.662	0	0	2.12	1.68	1.08	0.92
113 माल्डोवा गणराज्य	..	0.650	0.592	0.636	0.644	0.652	0.657	0.660	–2	0	..	–0.93	0.96	0.91
114 फ़िलीपीन्स	0.561	0.581	0.610	0.630	0.636	0.649	0.651	0.654	0	0	0.35	0.49	0.61	0.58
114 उज्बेकिस्तान	..	..	..	0.617	0.630	0.644	0.649	0.654	1	1	..	..	..	..
116 सीरियाई अरब गणराज्य	0.501	0.557	0.596	0.618	0.623	0.646	0.646	0.648	0	0	1.07	0.67	0.80	0.70
117 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	..	..	..	..	..	0.639	0.640	0.645	..	0	..	..	..	..
118 गयाना	0.513	0.502	0.578	0.610	0.617	0.628	0.632	0.636	1	1	–0.21	1.41	0.83	0.79
119 बोत्स्वाना	0.449	0.586	0.587	0.604	0.619	0.633	0.634	0.634	–1	–1	2.71	0.00	0.77	0.66
120 होण्डुरास	0.456	0.520	0.563	0.582	0.594	0.629	0.630	0.632	3	0	1.33	0.79	1.12	0.97
121 इण्डोनेशिया	0.422	0.479	0.540	0.575	0.595	0.620	0.624	0.629	1	3	1.26	1.21	1.39	1.28
121 किरिबाती	..	..	..	..	..	0.628	0.627	0.629	..	0	..	..	..	..
121 दक्षिण अफ़्रीका	0.570	0.621	0.622	0.604	0.609	0.621	0.625	0.629	0	1	0.87	0.01	–0.01	0.11
124 वनुआतू	..	..	..	..	..	0.623	0.625	0.626	..	–2	..	..	..	..
125 किर्गिस्तान	..	0.609	0.582	0.601	0.612	0.615	0.621	0.622	–3	0	..	–0.45	0.54	0.56

	मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.)								मा.वि.सू. श्रेणी		औसत वार्षिक मा.वि.सू. वृद्धि			
	मान								परिवर्तन		(%)			
मा.वि.सू. श्रेणी	1980	1990	2000	2005	2007	2010	2011	2012	2007–2012[a]	2011–2012[a]	1980/1990	1990/2000	2000/2010	2000/2012
125 ताजिकिस्तान	..	0.615	0.529	0.582	0.587	0.612	0.618	0.622	3	1	..	–1.50	1.47	1.36
127 वियतनाम	..	0.439	0.534	0.573	0.590	0.611	0.614	0.617	0	0	..	1.98	1.37	1.22
128 नामीबिया	..	0.569	0.564	0.579	0.592	0.604	0.606	0.608	–2	0	..	–0.10	0.69	0.64
129 निकारागुआ	0.461	0.479	0.529	0.572	0.583	0.593	0.597	0.599	0	0	0.37	1.01	1.15	1.04
130 मोरक्को	0.371	0.440	0.512	0.558	0.571	0.586	0.589	0.591	0	0	1.71	1.54	1.35	1.20
131 इराक	..	..	..	0.564	0.567	0.578	0.583	0.590	1	1	..	..	..	..
132 केप वर्दे	..	..	0.532	..	..	0.581	0.584	0.586	..	–1	..	..	0.88	0.81
133 ग्वाटेमाला	0.432	0.464	0.523	0.551	0.570	0.579	0.580	0.581	–1	0	0.72	1.20	1.02	0.89
134 टिमोर लेस्ट	..	..	0.418	0.461	0.519	0.565	0.571	0.576	5	0	..	..	3.06	2.71
135 घाना	0.391	0.427	0.461	0.491	0.506	0.540	0.553	0.558	7	0	0.90	0.77	1.58	1.60
136 इक्वेटोरिअल गिनी	..	..	0.498	0.523	0.533	0.547	0.551	0.554	–2	0	..	..	0.96	0.90
136 भारत	0.345	0.410	0.463	0.507	0.525	0.547	0.551	0.554	–1	0	1.75	1.23	1.67	1.50
138 कम्बोडिया	..	..	0.444	0.501	0.520	0.532	0.538	0.543	–1	0	..	..	1.82	1.68
138 लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	..	0.379	0.453	0.494	0.510	0.534	0.538	0.543	3	0	..	1.80	1.66	1.53
140 भूटान	..	..	..	..	..	0.525	0.532	0.538	..	1	..	..	..	..
141 स्वाज़ीलैण्ड	..	0.533	0.502	0.504	0.520	0.532	0.536	0.536	–3	–1	..	–0.59	0.58	0.55
निम्न मानव विकास														
142 कौंगो	0.470	0.510	0.482	0.506	0.511	0.529	0.531	0.534	–1	0	0.82	–0.56	0.94	0.86
143 सॉलोमन द्वीपसमूह	..	..	0.486	0.510	0.522	0.522	0.526	0.530	–6	0	..	..	0.70	0.71
144 साओ टोम एवं प्रिन्साइप	..	..	..	0.488	0.503	0.520	0.522	0.525	0	0	..	..	..	..
145 केन्या	0.424	0.463	0.447	0.472	0.491	0.511	0.515	0.519	1	0	0.88	–0.33	1.34	1.24
146 बांग्लादेश	0.312	0.361	0.433	0.472	0.488	0.508	0.511	0.515	1	1	1.49	1.83	1.61	1.46
146 पाकिस्तान	0.337	0.383	0.419	0.485	0.498	0.512	0.513	0.515	–1	0	1.29	0.89	2.03	1.74
148 अंगोला	..	..	0.375	0.406	0.472	0.502	0.504	0.508	1	0	..	..	2.97	2.56
149 म्याँमार	0.281	0.305	0.382	0.435	0.464	0.490	0.494	0.498	1	0	0.83	2.27	2.52	2.23
150 कैमरून	0.373	0.431	0.429	0.453	0.459	0.488	0.492	0.495	1	0	1.46	–0.05	1.29	1.20
151 मैडागास्कर	..	..	0.428	0.467	0.478	0.484	0.483	0.483	–3	0	..	..	1.24	1.02
152 तंज़ानिया गणराज्य	..	0.353	0.369	0.395	0.408	0.466	0.470	0.476	15	1	..	0.43	2.36	2.15
153 नाइजीरिया	..	..	..	0.434	0.448	0.462	0.467	0.471	1	1	..	..	..	..
154 सेनेगल	0.322	0.368	0.405	0.441	0.454	0.470	0.471	0.470	–2	–2	1.32	0.97	1.50	1.25
155 मॉरिटानिया	0.340	0.357	0.418	0.441	0.454	0.464	0.464	0.467	–3	0	0.48	1.61	1.04	0.92
156 पापुआ न्यू गिनी	0.324	0.368	0.415	0.429	..	0.458	0.462	0.466	1	0	1.29	1.22	0.99	0.96
157 नेपाल	0.234	0.341	0.401	0.429	0.440	0.458	0.460	0.463	2	0	3.85	1.62	1.35	1.21
158 लेसोथो	0.422	0.474	0.429	0.425	0.431	0.452	0.456	0.461	2	1	1.18	–0.99	0.53	0.61
159 टोगो	0.357	0.382	0.426	0.436	0.442	0.452	0.455	0.459	–2	1	0.67	1.11	0.60	0.62
160 यमन	..	0.286	0.376	0.428	0.444	0.466	0.459	0.458	–4	–2	..	2.78	2.16	1.66
161 हैती	0.335	0.399	0.422	0.437	..	0.450	0.453	0.456	–6	1	1.77	0.56	0.64	0.65
161 युगाण्डा	..	0.306	0.375	0.408	0.427	0.450	0.454	0.456	0	0	..	2.06	1.84	1.65
163 ज़ाम्बिया	0.405	0.398	0.376	0.399	0.411	0.438	0.443	0.448	3	0	–0.18	–0.56	1.52	1.46
164 जिबूती	..	..	..	0.405	0.419	0.431	0.442	0.445	0	0	..	..	..	..
165 गैम्बिया	0.279	0.323	0.360	0.375	0.383	0.437	0.440	0.439	5	0	1.47	1.09	1.95	1.65
166 बेनिन	0.253	0.314	0.380	0.414	0.420	0.432	0.434	0.436	–3	0	2.16	1.95	1.28	1.14
167 रवाण्डा	0.277	0.233	0.314	0.377	0.400	0.425	0.429	0.434	2	0	–1.74	3.05	3.07	2.73
168 आइवरी कोस्ट	0.348	0.360	0.392	0.405	0.412	0.427	0.426	0.432	–3	1	0.34	0.85	0.86	0.81
169 कोमोरॉस	..	..	..	0.425	0.425	0.426	0.428	0.429	–7	–1	..	..	..	..
170 मलावी	0.272	0.295	0.352	0.363	0.381	0.413	0.415	0.418	1	1	0.83	1.78	1.61	1.44
171 सूडान	0.269	0.301	0.364	0.390	0.401	0.411	0.419	0.414	–3	–1	1.15	1.89	1.22	1.08
172 ज़िम्बाब्वे	0.367	0.427	0.376	0.352	0.355	0.374	0.387	0.397	0	1	1.53	–1.26	–0.04	0.46
173 इथियोपिया	..	..	0.275	0.316	0.350	0.387	0.392	0.396	1	–1	..	..	3.49	3.09
174 लाइबेरिया	0.298	..	0.304	0.301	0.334	0.367	0.381	0.388	3	0	..	..	1.88	2.04
175 अफ़ग़ानिस्तान	0.209	0.246	0.236	0.322	0.346	0.368	0.371	0.374	0	0	1.63	–0.41	4.54	3.91
176 गिनी बिसाउ	..	..	..	0.348	0.355	0.361	0.364	0.364	–4	0	..	..	..	..
177 सिएरा लिओन	0.255	0.247	0.244	0.315	0.331	0.346	0.348	0.359	1	2	–0.28	–0.15	3.58	3.29
178 बुरुण्डी	0.217	0.272	0.270	0.298	0.323	0.348	0.352	0.355	2	–1	2.26	–0.07	2.59	2.31
178 गिनी	..	..	..	0.331	0.342	0.349	0.352	0.355	–2	–1	..	..	..	..
180 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य	0.285	0.312	0.294	0.308	0.316	0.344	0.348	0.352	2	–1	0.94	–0.59	1.59	1.50
181 इरिट्रिया	..	..	..	..	..	0.342	0.346	0.351	..	1	..	..	..	..
182 माली	0.176	0.204	0.270	0.312	0.328	0.344	0.347	0.344	–2	–1	1.50	2.86	2.45	2.04
183 बुर्किना फ़ासो	..	..	..	0.301	0.314	0.334	0.340	0.343	1	0	..	..	..	..
184 चाड	..	..	0.290	0.317	0.319	0.336	0.336	0.340	–2	0	..	..	1.47	1.32
185 मोज़ाम्बीक	0.217	0.202	0.247	0.287	0.301	0.318	0.322	0.327	0	0	–0.70	2.00	2.57	2.37
186 कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	0.286	0.297	0.234	0.258	0.280	0.295	0.299	0.304	0	0	0.37	–2.34	2.35	2.19
186 नाइजर	0.179	0.198	0.234	0.269	0.278	0.298	0.297	0.304	1	1	0.98	1.72	2.42	2.20

मा.वि.सू. श्रेणी	मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.)								मा.वि.सू. श्रेणी		औसत वार्षिक मा.वि.सू. वृद्धि			
	मान								परिवर्तन		(%)			
	1980	1990	2000	2005	2007	2010	2011	2012	2007–2012[a]	2011–2012[a]	1980/1990	1990/2000	2000/2010	2000/2012
अन्य देश अथवा अंचल														
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मार्शल द्वीप समूह	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मोनाको	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
नाउरू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
सैन मैरीनो	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
सोमालिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
तुवालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह														
अति उच्च मानव विकास	0.773	0.817	0.867	0.889	0.896	0.902	0.904	0.905	—	—	0.56	0.59	0.40	0.36
उच्च मानव विकास	0.605 [c]	0.656 [c]	0.695	0.725	0.738	0.753	0.755	0.758	—	—	0.81	0.58	0.80	0.72
मध्यम मानव विकास	0.419 [c]	0.481	0.549	0.589	0.609	0.631	0.636	0.640	—	—	1.38	1.32	1.41	1.29
निम्न मानव विकास	0.315	0.350	0.385	0.424	0.442	0.461	0.464	0.466	—	—	1.05	0.95	1.82	1.62
क्षेत्र														
अरब देश	0.443	0.517	0.583	0.622	0.633	0.648	0.650	0.652	—	—	1.56	1.21	1.07	0.94
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	0.432 [c]	0.502 [c]	0.584	0.626	0.649	0.673	0.678	0.683	—	—	1.51	1.51	1.43	1.31
यूरोप एवं मध्य एशिया	0.651 [c]	0.701 [c]	0.709	0.743	0.757	0.766	0.769	0.771	—	—	0.74	0.12	0.77	0.70
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	0.574	0.623	0.683	0.708	0.722	0.736	0.739	0.741	—	—	0.83	0.93	0.74	0.67
दक्षिण एशिया	0.357	0.418	0.470	0.514	0.531	0.552	0.555	0.558	—	—	1.58	1.19	1.60	1.43
सब-सहारा अफ्रीका	0.366	0.387	0.405	0.432	0.449	0.468	0.472	0.475	—	—	0.58	0.44	1.47	1.34
न्यूनतम विकसित देश	0.290 [c]	0.327 [c]	0.367	0.401	0.421	0.443	0.446	0.449	—	—	1.22	1.15	1.91	1.70
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	0.530 [c]	0.571 [c]	0.600 [c]	0.623	0.658	0.645	0.647	0.648	—	—	0.75	0.50	0.73	0.65
विश्व	**0.561 [c]**	**0.600**	**0.639**	**0.666**	**0.678**	**0.690**	**0.692**	**0.694**	**—**	**—**	**0.68**	**0.64**	**0.77**	**0.68**

नोट

a एक सकारात्मक मान का अर्थ है श्रेणी में सुधार।

b लीबिया के सकल घरेलू उत्पाद में 2011 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्राक्कलन के अद्यतन किए जाने के कारण श्रेणी में काफी अधिक सुधार हुआ है।

c समूह या क्षेत्र में आधे से कम देशों पर आधारित।

परिभाषाएँ

मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) : मानव जीवन के तीन प्राथमिक आयामों– लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और सम्मानजनक जीवन स्तर– में औसत उपलब्धियों को मापने वाला एक सम्मिश्र सूचकांक। मा.वि.सू. की गणना किस तरह की जाती है, यह देखने के लिए तकनीकी नोट 1 को http://hdr.unp.org/en/media/HDR_2013_EN_TechNotes.pdf पर देखें।

औसत वार्षिक मा.वि.सू. वृद्धि : वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर के रूप में आकलित तथा एक समयावधि में वार्षिक आधार पर अनुकूलित मा.वि.सू. की वृद्धि दर।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1-8: एच.डी.आर.ओ. की UNDESA (2011), बर्रो एवं ली (2011), यूनेस्को सांख्यिकी संस्था (2012), विश्व बैंक (2012a) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2012) पर आधारित गणनाएँ।

कॉलम 9-14 : प्रासंगिक वर्ष के लिए मानव विकास सूचकांक मानों पर आधारित गणनाएँ।

सारणी 3

असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक

		मानव विकास सूचकांक (म.वि.सू.)	असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (अ.मा.वि.सू.)			असमानता-समायोजित जीवन प्रत्याशा सूचकांक		असमानता-समायोजित शिक्षा सूचकांक		असमानता-समायोजित आय सूचकांक		क्विन्टाइल आय अनुपात	आय का गिनी गुणांक
		मान	मान	कुल हानि (%)	मा.वि.सू. श्रेणी से अंतर[a]	मान	हानि (%)	मान	हानि (%)	मान	हानि (%)		
मा.वि.सू. श्रेणी		2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012[b]	2012	2012[b]	2012	2000–2010[c]	2000–2010[c]
अति उच्च मानव विकास													
1	नार्वे	0.955	0.894	6.4	0	0.928	3.7	0.968	2.2	0.797	12.8	3.9	25.8
2	ऑस्ट्रेलिया	0.938	0.864	7.9	0	0.930	4.7	0.965	1.7	0.719	16.6	..	..
3	यूनाइटेड स्टेट्स	0.937	0.821	12.4	–13	0.863	6.6	0.941	5.3	0.681	24.1 [d]	8.4	40.8
4	नीदरलैण्ड	0.921	0.857	6.9	0	0.916	4.3	0.897	3.9	0.766	12.3	..	..
5	जर्मनी	0.920	0.856	6.9	0	0.915	4.0	0.927	1.8	0.741	14.5	4.3	28.3
6	न्यूज़ीलैण्ड	0.919	..	..	..	0.907	5.2	..	..	..	..	..	..
7	आयरलैण्ड	0.916	0.850	7.2	0	0.915	4.3	0.933	3.2	0.720	13.8	5.7	34.3
7	स्वीडन	0.916	0.859	6.2	3	0.937	3.3	0.878	3.8	0.772	11.2	4.0	25.0
9	स्विटज़रलैण्ड	0.913	0.849	7.0	1	0.942	4.1	0.856	2.0	0.760	14.3	5.5	33.7
10	जापान	0.912	..	..	..	0.965	3.5	..	..	..	..	..	..
11	कनाडा	0.911	0.832	8.7	–4	0.913	5.0	0.879	3.2	0.718	17.1	5.5	32.6
12	कोरिआ गणराज्य	0.909	0.758	16.5	–18	0.915	4.3	0.702	25.5	0.679	18.4	..	..
13	हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	0.906	..	..	..	0.962	2.9	..	..	..	..	..	..
13	आइसलैण्ड	0.906	0.848	6.4	3	0.945	3.0	0.889	2.5	0.727	13.2	..	..
15	डेनमार्क	0.901	0.845	6.2	3	0.887	4.4	0.891	3.1	0.764	11.0	..	..
16	इस्राइल	0.900	0.790	12.3	–8	0.935	3.9	0.840	7.9	0.627	23.7	7.9	39.2
17	बेल्जियम	0.897	0.825	8.0	–1	0.903	4.4	0.822	7.6	0.756	11.9	4.9	33.0
18	ऑस्ट्रिया	0.895	0.837	6.6	3	0.919	4.2	0.838	2.5	0.760	12.7	4.4	29.2
18	सिंगापुर	0.895	..	..	..	0.935	2.9	..	..	..	..	..	..
20	फ्रांस	0.893	0.812	9.0	–2	0.930	4.2	0.788	9.4	0.732	13.3	..	..
21	फ़िनलैण्ड	0.892	0.839	6.0	6	0.909	3.9	0.859	2.4	0.757	11.3	3.8	26.9
21	स्लोवेनिया	0.892	0.840	5.8	7	0.898	4.1	0.905	3.3	0.729	9.9	4.8	31.2
23	स्पेन	0.885	0.796	10.1	–1	0.930	4.1	0.823	5.5	0.659	19.7	6.0	34.7
24	लिक्टेन्स्टाइन	0.883	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
25	इटली	0.881	0.776	11.9	–4	0.937	3.9	0.740	13.1	0.673	18.1	6.5	36.0
26	लवज़मबर्ग	0.875	0.813	7.2	4	0.913	3.5	0.729	6.3	0.807	11.6	4.6	30.8
26	यूनाइटेड किंगडम	0.875	0.802	8.3	2	0.903	4.8	0.806	2.6	0.709	16.9	..	..
28	चेक गणराज्य	0.873	0.826	5.4	9	0.874	3.9	0.904	1.3	0.712	10.7	..	..
29	यूनान	0.860	0.760	11.5	–3	0.899	4.8	0.759	11.3	0.644	18.1	6.2	34.3
30	ब्रूनेई दारस्सलाम	0.855	..	..	..	0.862	5.8	..	..	..	..	..	..
31	साइप्रस	0.848	0.751	11.5	–4	0.901	4.1	0.672	16.3	0.698	13.6	..	..
32	माल्टा	0.847	0.778	8.2	3	0.893	5.1	0.771	5.5	0.683	13.6	..	..
33	अंडोरा	0.846	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
33	एस्टोनिआ	0.846	0.770	9.0	2	0.813	6.0	0.894	2.6	0.627	17.7	6.4	36.0
35	स्लोवाकिआ	0.840	0.788	6.3	6	0.825	5.7	0.856	1.5	0.692	11.3	3.6	26.0
36	कतर	0.834	..	..	..	0.854	7.2	..	..	..	..	13.3	41.1
37	हंगरी	0.831	0.769	7.4	3	0.810	5.7	0.854	4.1	0.658	12.2	4.8	31.2
38	बारबाडोस	0.825	..	..	..	0.814	9.2	..	..	..	..	..	..
39	पोलैण्ड	0.821	0.740	9.9	0	0.834	5.8	0.767	6.3	0.634	17.1	5.5	34.1
40	चिली	0.819	0.664	19.0	–10	0.871	6.6	0.689	13.7	0.488	34.1	13.5	52.1
41	लिथुआनिया	0.818	0.727	11.0	–1	0.767	7.2	0.830	5.0	0.605	20.1	6.7	37.6
41	संयुक्त अरब अमीरात	0.818	..	..	..	0.836	6.3	..	..	..	..	..	..
43	पुर्तगाल	0.816	0.729	10.8	1	0.893	4.9	0.700	5.6	0.619	20.8	..	..
44	लातीविया	0.814	0.726	10.9	–1	0.784	7.1	0.837	3.6	0.583	20.9	6.6	36.6
45	अर्जेंटीना	0.811	0.653	19.5	–8	0.796	9.7	0.716	12.1	0.487	34.4	11.3	44.5
46	सेशेल्स	0.806	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18.8	65.8
47	क्रोएशिया	0.805	0.683	15.1	–3	0.845	5.5	0.703	10.4	0.537	27.8	5.2	33.7
उच्च मानव विकास													
48	बहरीन	0.796	..	..	..	0.815	6.2	..	..	..	..	..	..
49	बहामास	0.794	..	..	..	0.783	10.9	..	..	..	..	..	..
50	बेलारूस	0.793	0.727	8.3	3	0.737	7.4	0.819	5.4	0.636	12.1	4.0	27.2
51	उरुग्वे	0.792	0.662	16.4	–4	0.815	9.3	0.682	10.8	0.521	27.9	10.3	45.3
52	मॉन्टीनेग्रो	0.791	0.733	7.4	8	0.803	6.8	0.817	2.5	0.600	12.6	4.6	30.0
52	पलाउ	0.791	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
54	कुवैत	0.790	..	..	..	0.803	6.7	..	..	..	..	..	..
55	रूसी गणराज्य	0.788	..	..	..	0.689	10.8	..	..	0.647	11.9	7.3	40.1
56	रोमानिया	0.786	0.687	12.6	2	0.770	9.6	0.779	5.0	0.540	22.2	4.6	30.0
57	बुल्गारिया	0.782	0.704	9.9	5	0.776	7.8	0.760	6.1	0.592	15.4	4.3	28.2
57	सऊदी अरब	0.782	..	..	..	0.754	11.5	..	..	..	..	..	..
59	क्यूबा	0.780	..	..	..	0.882	5.4	..	..	..	..	..	..

	मानव विकास सूचकांक (म.वि.सू.)	असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (अ.मा.वि.सू.)			असमानता-समायोजित जीवन प्रत्याशा सूचकांक		असमानता-समायोजित शिक्षा सूचकांक		असमानता-समायोजित आय सूचकांक		क्विन्टाइल आय अनुपात	आय का गिनी गुणांक
	मान	मान	कुल हानि (%)	मा.वि.सू. श्रेणी से अंतर[a]	मान	हानि (%)	मान	हानि (%)	मान	हानि (%)		
मा.वि.सू. श्रेणी	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012[b]	2012	2012[b]	2012	2000–2010[c]	2000–2010[c]
59 पनामा	0.780	0.588	24.6	–15	0.776	12.4	0.609	17.8	0.431	40.5	17.1	51.9
61 मैक्सिको	0.775	0.593	23.4	–12	0.801	10.9	0.564	21.9	0.463	35.6	11.3	48.3
62 कोस्टा रिका	0.773	0.606	21.5	–10	0.862	7.8	0.601	15.7	0.430	37.9	14.5	50.7
63 ग्रेनाडा	0.770	..	..	..	0.798	9.6	..	..	..	..	..	..
64 लीबिया	0.769	..	..	..	0.782	9.7	..	..	..	..	..	..
64 मलेशिया	0.769	..	..	..	0.799	6.7	..	..	..	..	11.3	46.2
64 सर्बिया	0.769	0.696	9.5	8	0.788	8.3	0.709	9.9	0.603	10.3	4.2	27.8
67 एंटिगुआ और बरबूडा	0.760	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
67 ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	0.760	0.644	15.3	–3	0.660	16.6	0.652	6.6	0.621	21.9	..	..
69 कज़ाकिस्तान	0.754	0.652	13.6	3	0.624	16.2	0.781	6.9	0.567	17.3	4.2	29.0
70 अल्बानिआ	0.749	0.645	13.9	0	0.797	11.2	0.640	11.9	0.526	18.3	5.3	34.5
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	0.748	0.549	26.6	–17	0.754	12.2	0.571	18.1	0.385	44.9	11.5	44.8
72 डोमिनिका	0.745	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
72 जॉर्जिआ	0.745	0.631	15.3	–2	0.720	15.1	0.814	3.3	0.428	25.9	8.9	41.3
72 लेबनान	0.745	0.575	22.8	–9	0.718	13.5	0.531	24.1	0.498	30.0	..	..
72 सेंट किट्स एवं नेविस	0.745	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	0.742	..	..	..	0.703	16.1	..	..	..	..	7.0	38.3
77 पेरू	0.741	0.561	24.3	–10	0.727	14.8	0.538	24.6	0.452	32.5	13.5	48.1
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	0.740	0.631	14.7	2	0.784	9.4	0.612	12.3	0.524	21.8	9.5	43.2
78 यूक्रेन	0.740	0.672	9.2	13	0.687	10.5	0.808	6.1	0.548	10.9	3.8	26.4
80 मॉरिशस	0.737	0.639	13.3	5	0.760	9.8	0.570	13.5	0.602	16.6	..	..
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	0.735	0.650	11.5	11	0.794	9.6	0.668	5.2	0.518	19.2	6.5	36.2
82 अजरबैजान	0.734	0.650	11.4	11	0.636	20.6	0.697	8.3	0.620	4.5	5.3	33.7
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	0.733	..	..	..	0.710	14.0	..	..	..	..	..	..
84 ओमान	0.731	..	..	..	0.777	7.2	..	..	..	..	..	..
85 ब्राज़ील	0.730	0.531	27.2	–12	0.725	14.4	0.503	25.3	0.411	39.7	20.6	54.7
85 जमैका	0.730	0.591	19.1	2	0.710	15.3	0.669	10.6	0.434	30.1	9.6	45.5
87 अर्मेनिआ	0.729	0.649	10.9	13	0.728	14.9	0.735	3.7	0.510	13.9	4.5	30.9
88 सेंट लूसिआ	0.725	..	..	..	0.773	10.4	..	..	..	..	..	..
89 इक्वाडोर	0.724	0.537	25.8	–8	0.754	14.1	0.529	22.1	0.390	38.8	12.5	49.3
90 तुर्की	0.722	0.560	22.5	–1	0.743	12.8	0.442	27.4	0.534	26.5	7.9	39.0
91 कोलम्बिया	0.719	0.519	27.8	–11	0.732	13.7	0.523	21.5	0.366	44.5	20.1	55.9
92 श्रीलंका	0.715	0.607	15.1	11	0.786	9.4	0.618	14.6	0.461	20.8	6.9	40.3
93 अल्जीरिया	0.713	..	..	..	0.717	14.5	..	..	..	..	..	..
94 ट्यूनीशिया	0.712	..	..	..	0.752	12.6	..	..	..	..	8.1	41.4
मध्यम मानव विकास												
95 टोंगा	0.710	..	..	..	0.712	13.8	..	..	..	..	..	..
96 बेलीज़	0.702	..	..	..	0.777	12.2	..	..	..	..	..	..
96 डोमीनिकन गणराज्य	0.702	0.510	27.3	–15	0.708	16.0	0.458	26.8	0.410	37.6	11.3	47.2
96 फ़िजी	0.702	..	..	..	0.676	13.0	..	..	..	..	8.0	42.8
96 समोआ	0.702	..	..	..	0.718	13.4	..	..	..	..	..	..
100 जॉर्डन	0.700	0.568	19.0	5	0.732	13.1	0.541	22.4	0.462	21.1	5.7	35.4
101 चीन	0.699	0.543	22.4	0	0.731	13.5	0.481	23.2	0.455	29.5	9.6	42.5
102 तुर्कमेनिस्तान	0.698	..	..	..	0.521	26.7	..	..	..	..	..	..
103 थाइलैण्ड	0.690	0.543	21.3	0	0.768	10.1	0.491	18.0	0.424	34.0	7.1	40.0
104 माल्दीव	0.688	0.515	25.2	–8	0.834	7.3	0.335	41.2	0.489	23.2	6.8	37.4
105 सूरीनाम	0.684	0.526	23.0	–2	0.680	15.0	0.504	20.1	0.426	32.8	..	..
106 गैबन	0.683	0.550	19.5	6	0.489	27.8	0.611	7.3	0.556	22.1	7.8	41.5
107 अल सल्वाडोर	0.680	0.499	26.6	–11	0.699	15.2	0.429	32.4	0.415	31.1	14.3	48.3
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	0.675	0.444	34.2	–12	0.553	25.1	0.537	27.6	0.294	47.4	27.8	56.3
108 मंगोलिया	0.675	0.568	15.9	13	0.623	18.8	0.661	8.9	0.444	19.7	6.2	36.5
110 फ़लस्तीन राज्य	0.670	..	..	..	0.725	13.1	..	..	..	..	5.8	35.5
111 पराग्वे	0.669	..	..	..	0.681	17.8	..	..	0.374	33.4	17.3	52.4
112 मिस्र	0.662	0.503	24.1	–7	0.724	13.9	0.347	40.9	0.505	14.2	4.4	30.8
113 माल्डोवा गणराज्य	0.660	0.584	11.6	18	0.693	11.2	0.670	6.1	0.429	17.0	5.3	33.0
114 फ़िलीपीन्स	0.654	0.524	19.9	4	0.654	15.2	0.587	13.5	0.375	30.0	8.3	43.0
114 उज़्बेकिस्तान	0.654	0.551	15.8	13	0.578	24.3	0.706	1.4	0.409	20.1	6.2	36.7
116 सीरियाई अरब गणराज्य	0.648	0.515	20.4	3	0.793	10.0	0.372	31.5	0.464	18.3	5.7	35.8
117 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	0.645	..	..	..	0.625	19.2	..	..	..	..	40.2	61.1
118 गयाना	0.636	0.514	19.1	2	0.618	21.7	0.559	10.5	0.393	24.4	..	..
119 बोत्स्वाना	0.634	..	..	..	0.394	24.3	..	..	..	..	..	..
120 होण्डुरास	0.632	0.458	27.5	–3	0.694	17.4	0.413	28.2	0.335	35.8	29.7	57.0

मा.वि.सू. श्रेणी	मानव विकास सूचकांक (म.वि.सू.)	असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (अ.मा.वि.सू.)			असमानता-समायोजित जीवन प्रत्याशा सूचकांक		असमानता-समायोजित शिक्षा सूचकांक		असमानता-समायोजित आय सूचकांक		क्विन्टाइल आय अनुपात	आय का गिनी गुणांक
	मान	मान	कुल हानि (%)	मा.वि.सू. श्रेणी से अंतर[a]	मान	हानि (%)	मान	हानि (%)	मान	हानि (%)		
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012[b]	2012	2012[b]	2012	2000–2010[c]	2000–2010[c]
121 इण्डोनेशिया	0.629	0.514	18.3	3	0.652	16.8	0.459	20.4	0.453	17.7	5.1	34.0
121 किरिबाती	0.629	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
121 दक्षिण अफ्रीका	0.629	..	..	..	0.376	28.4	0.558	20.8	..	..	25.3	63.1
124 वनुआतू	0.626	..	..	..	0.681	15.6	..	..	..	..	..	..
125 किर्गिस्तान	0.622	0.516	17.1	8	0.606	19.8	0.674	6.5	0.336	24.1	6.4	36.2
125 ताजिकिस्तान	0.622	0.507	18.4	2	0.548	27.2	0.623	12.2	0.383	15.0	4.7	30.8
127 वियतनाम	0.617	0.531	14.0	14	0.755	13.4	0.447	17.1	0.444	11.4	5.9	35.6
128 नामीबिया	0.608	0.344	43.5	–16	0.528	21.1	0.402	27.8	0.191	68.3	21.8	63.9
129 निकारागुआ	0.599	0.434	27.5	1	0.735	13.9	0.351	33.3	0.317	33.6	7.6	40.5
130 मोरक्को	0.591	0.415	29.7	0	0.686	16.7	0.243	45.8	0.430	23.0	7.3	40.9
131 इराक	0.590	..	..	..	0.622	20.3	0.334	33.0	..	..	4.6	30.9
132 केप वर्दे	0.586	..	..	..	0.746	12.7	..	..	..	..	12.3	50.5
133 ग्वाटेमाला	0.581	0.389	33.1	–3	0.659	18.6	0.280	36.1	0.318	42.5	19.6	55.9
134 टिमोर लेस्ट	0.576	0.386	33.0	–3	0.471	30.2	0.251	47.6	0.485	17.8	4.6	31.9
135 घाना	0.558	0.379	32.2	–3	0.508	27.5	0.352	40.9	0.303	27.2	9.3	42.8
136 इक्वेटोरिअल गिनी	0.554	..	..	..	0.270	45.4	..	..	..	..	..	..
136 भारत	0.554	0.392	29.3	1	0.525	27.1	0.264	42.4	0.434	15.8	4.9	33.4
138 कम्बोडिया	0.543	0.402	25.9	3	0.488	28.8	0.372	28.3	0.358	20.3	6.1	37.9
138 लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	0.543	0.409	24.7	4	0.589	21.7	0.311	31.2	0.374	20.6	5.9	36.7
140 भूटान	0.538	0.430	20.0	8	0.568	24.1	0.312	12.2	0.450	23.1	6.8	38.1
141 स्वाज़ीलैण्ड	0.536	0.346	35.4	–3	0.296	35.0	0.409	29.8	0.343	40.9	14.0	51.5
निम्न मानव विकास												
142 कौंगो	0.534	0.368	31.1	1	0.374	37.0	0.384	25.4	0.348	30.3	10.7	47.3
143 सॉलोमन द्वीपसमूह	0.530	..	..	..	0.602	20.7	..	..	..	..	..	..
144 साओ टोम एवं प्रिन्साइप	0.525	0.358	31.7	1	0.503	28.8	0.379	20.0	0.241	44.2	10.8	50.8
145 केन्या	0.519	0.344	33.6	–2	0.390	34.1	0.405	30.7	0.259	36.0	11.0	47.7
146 बांग्लादेश	0.515	0.374	27.4	5	0.595	23.2	0.252	39.4	0.350	17.7	4.7	32.1
146 पाकिस्तान	0.515	0.356	30.9	2	0.487	32.3	0.217	45.2	0.426	11.0	4.2	30.0
148 अंगोला	0.508	0.285	43.9	–12	0.267	46.1	0.303	34.6	0.286	50.0	30.9	58.6
149 म्यॉंमार	0.498	..	..	..	0.537	25.3	..	..	..	..	..	..
150 कैमरून	0.495	0.330	33.4	–1	0.288	43.0	0.346	35.3	0.361	19.9	6.9	38.9
151 मैडागास्कर	0.483	0.335	30.7	1	0.549	25.6	0.342	30.1	0.199	36.1	9.3	44.1
152 तंज़ानिया गणराज्य	0.476	0.346	27.3	5	0.414	32.4	0.326	28.3	0.307	20.9	6.6	37.6
153 नाइजीरिया	0.471	0.276	41.4	–13	0.286	43.8	0.250	45.2	0.295	34.5	12.2	48.8
154 सेनेगल	0.470	0.315	33.0	2	0.432	30.7	0.223	44.6	0.325	21.6	7.4	39.2
155 मॉरिटानिया	0.467	0.306	34.4	1	0.391	36.2	0.212	42.1	0.346	23.8	7.8	40.5
156 पापुआ न्यू गिनी	0.466	..	..	..	0.508	25.2	..	..	..	..	..	..
157 नेपाल	0.463	0.304	34.2	0	0.622	19.5	0.202	43.6	0.225	37.4	5.0	32.8
158 लेसोथो	0.461	0.296	35.9	–1	0.297	34.3	0.379	24.3	0.229	47.0	19.0	52.5
159 टोगो	0.459	0.305	33.5	3	0.371	37.2	0.291	41.5	0.263	20.0	5.6	34.4
160 यमन	0.458	0.310	32.3	6	0.541	25.1	0.156	49.8	0.353	17.6	6.3	37.7
161 हैती	0.456	0.273	40.2	–7	0.461	30.9	0.241	40.7	0.182	47.9	26.6	59.2
161 युगाण्डा	0.456	0.303	33.6	3	0.331	39.1	0.327	32.2	0.257	29.1	8.7	44.3
163 ज़ाम्बिया	0.448	0.283	36.7	–2	0.269	41.9	0.383	23.8	0.221	42.6[e]	16.6	54.6
164 जिबूती	0.445	0.285	36.0	1	0.380	36.9	0.166	47.0	0.365	21.7	7.7	40.0
165 गैम्बिया	0.439	..	..	..	0.404	33.9	..	..	..	..	11.0	47.3
166 बेनिन	0.436	0.280	35.8	–1	0.343	40.3	0.213	42.0	0.301	23.6	6.6	38.6
167 रवाण्डा	0.434	0.287	33.9	6	0.330	41.3	0.285	29.4	0.251	30.2	12.7	53.1
168 आइवरी कोस्ट	0.432	0.265	38.6	–3	0.352	37.8	0.197	43.2	0.268	34.4	8.5	41.5
169 कोमोरॉस	0.429	..	..	..	0.440	32.6	0.189	47.4	..	..	26.7	64.3
170 मलावी	0.418	0.287	31.4	7	0.329	39.9	0.309	30.2	0.232	23.1	6.6	39.0
171 सूडान	0.414	..	..	..	0.440	33.0	..	..	..	..	6.2	35.3
172 ज़िम्बाब्वे	0.397	0.284	28.5	5	0.357	30.6	0.469	17.8	0.137	35.8	..	..
173 इथियोपिया	0.396	0.269	31.9	1	0.404	35.4	0.179	38.3	0.271	20.8	4.3	29.8
174 लाइबेरिया	0.388	0.251	35.3	0	0.367	37.6	0.230	46.4	0.188	19.0	7.0	38.2
175 अफ़गानिस्तान	0.374	..	..	..	0.225	50.9	0.205	39.3	..	..	4.0	27.8
176 गिनी बिसाउ	0.364	0.213	41.4	–3	0.224	50.1	0.185	40.3	0.234	32.5	5.9	35.5
177 सिएरा लिओन	0.359	0.210	41.6	–3	0.242	45.3	0.171	47.4	0.222	31.0	8.1	42.5
178 बुरुण्डी	0.355	..	..	..	0.264	45.6	..	..	..	..	4.8	33.3
178 गिनी	0.355	0.217	38.8	0	0.311	42.7	0.145	42.0	0.228	31.1	7.3	39.4
180 मध्य अफ्रीकी गणराज्य	0.352	0.209	40.5	–2	0.247	46.0	0.176	45.9	0.210	28.1	18.0	56.3

	मानव विकास सूचकांक (म.वि.सू.)	असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (अ.मा.वि.सू.)			असमानता-समायोजित जीवन प्रत्याशा सूचकांक		असमानता-समायोजित शिक्षा सूचकांक		असमानता-समायोजित आय सूचकांक		क्विन्टाइल आय अनुपात	आय का गिनी गुणांक
	मान	मान	कुल हानि (%)	मा.वि.सू. श्रेणी से अंतर[a]	मान	हानि (%)	मान	हानि (%)	मान	हानि (%)		
मा.वि.सू. श्रेणी	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012[b]	2012	2012[b]	2012	2000–2010[c]	2000–2010[c]
181 इरिट्रिया	0.351	..	..	..	0.485	26.6	..	..	..	..	..	..
182 माली	0.344	..	..	..	0.269	46.3	0.162	36.9	..	..	5.2	33.0
183 बुर्किना फ़ासो	0.343	0.226	34.2	4	0.329	41.7	0.125	36.2	0.281	23.4	7.0	39.8
184 चाड	0.340	0.203	40.1	–1	0.226	52.0	0.126	43.4	0.295	21.0	7.4	39.8
185 मोज़ाम्बीक	0.327	0.220	32.7	5	0.286	40.8	0.182	18.2	0.205	37.0[f]	9.8	45.7
186 काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य	0.304	0.183	39.9	–1	0.226	50.0	0.249	31.2	0.108	36.8	9.3	44.4
186 नाइजर	0.304	0.200	34.2	0	0.317	42.6	0.107	39.5	0.236	17.9	5.3	34.6
अन्य देश अथवा अंचल												
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मार्शल द्वीप समूह	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मोनाको	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
नाउरू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
सैन मैरीनो	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
सोमालिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	45.5
तुवालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह												
अति उच्च मानव विकास	0.905	0.807	10.8	—	0.897	5.2	0.851	6.8	0.688	19.8	—	—
उच्च मानव विकास	0.758	0.602	20.6	—	0.736	12.4	0.592	19.9	0.500	28.6	—	—
मध्यम मानव विकास	0.640	0.485	24.2	—	0.633	19.3	0.395	30.2	0.456	22.7	—	—
निम्न मानव विकास	0.466	0.310	33.5	—	0.395	35.7	0.246	38.7	0.307	25.6	—	—
क्षेत्र												
अरब देश	0.652	0.486	25.4	—	0.669	16.7	0.320	39.6	0.538	17.5	—	—
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	0.683	0.537	21.3	—	0.711	14.2	0.480	21.9	0.455	27.2	—	—
यूरोप एवं मध्य एशिया	0.771	0.672	12.9	—	0.716	11.7	0.713	10.5	0.594	16.3	—	—
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	0.741	0.550	25.7	—	0.744	13.4	0.532	23.0	0.421	38.5	—	—
दक्षिण एशिया	0.558	0.395	29.1	—	0.531	27.0	0.267	42.0	0.436	15.9	—	—
सब-सहारा अफ्रीका	0.475	0.309	35.0	—	0.335	39.0	0.285	35.3	0.308	30.4	—	—
न्यूनतम विकसित देश	0.449	0.303	32.5	—	0.406	34.6	0.240	36.2	0.287	26.1	—	—
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	0.648	0.459	29.2	—	0.633	19.2	0.412	30.1	0.370	37.2	—	—
विश्व	**0.694**	**0.532**	**23.3**	**—**	**0.638**	**19.0**	**0.453**	**27.0**	**0.522**	**23.5**	**—**	**—**

नोट

a उन देशों पर आधारित जिनके असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक की गणना की गई।

b असमानताओं के आकलन के लिए किए गए सर्वेक्षणों की सूची http://hdr.undp.org पर उपलब्ध है।

c आँकड़े उल्लिखित अवधि के अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए हैं।

d 2010 के मौजूदा जनसंख्या सर्वेक्षण (लक्ज़मबर्ग इनकम स्टडी डाटाबेस) पर आधारित। वर्ष 2011 में *मानव विकास रिपोर्ट* में आय असमानता 2005 के अमेरिकन कम्यूनिटी सर्वे (विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय आय वितरण डाटाबेस) पर आधारित थी। ये दो स्रोत असंगत प्रतीत होते हैं।

e 2007 के जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आय वितरण के अनुमानों पर आधारित। वर्ष 2011 की *मानव विकास रिपोर्ट* में खपत की असमानता 2002-2003 के लिविंग कन्डीशन्स मॉनिटरिंग सर्वे पर आधारित थी।

f 2009 के जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आय वितरण के अनुमानों पर आधारित, 2011 की *मानव विकास रिपोर्ट* में खपत की असानता 2003 के नेशनल हाउज़होल्ड सर्वे ऑफ लिविंग कन्डीशन्स पर आधारित।

परिभाषाएँ

मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) : मानव जीवन के तीन प्राथमिक आयामों– लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और सम्मानजनक जीवन स्तर– में औसत उपलब्धियों को मापने वाला एक सम्मिश्र सूचकांक। मा.वि.सू. की गणना किस तरह की जाती है, यह देखने के लिए तकनीकी नोट 1 को http://hdr.unp.org/en/media/HDR_2013_EN_TechNotes.pdf पर देखें।

असमानता-समायोजित मा.वि.सू (अ. मा.वि.सू): मानव विकास के तीन प्राथमिक आयामों में असमानता के लिए समायोजित मा.वि.सू. मान। अ.मा.वि.सू. की गणना किस तरह की जाती है, यह देखने के लिए तकनीकी नोट 2 को http://hdr.unp.org/en/media/HDR_2013_EN_TechNotes.pdf पर देखें।

कुल हानि: मानव विकास में असमानता के कारण होने वाली सम्भाव्य हानि, असमानता-समायोजित मा.वि.सू. तथा मा.वि.सू. के बीच प्रतिशत अंतर के रूप में निकाली गई।

असमानता-समायोजित जीवन प्रत्याशा सूचकांक : सम्भावित जीवनावधि के वितरण की असमानता की दृष्टि से समायोजित मा.वि.सू. जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जो आधारित है आँकड़ों के मुख्य स्रोत में वर्णित जीवन सारणियों के आँकड़ों पर।

असमानता-समायोजित शिक्षा सूचकांक : स्कूली शिक्षा के वर्षों के वितरण में व्याप्त असमानता की दृष्टि से समायोजित मा.वि.सू. शिक्षा सूचकांक, जो आँकड़े के मुख्य स्रोतों में सूचीकृत घरेलू सर्वे के आँकड़ों पर आधारित है।

असमानता-समायोजित आय सूचकांक: आय के वितरण की असमानता की दृष्टि से समायोजित मा.वि.सू. आय सूचकांक, जो आँकड़ों के मुख्य स्रोतों में सूचीकृत घरेलू सर्वे के आँकड़ों पर आधारित है।

क्विंटाइल आय अनुपात : आबादी के सबसे अमीर 20% लोगों तथा सबसे ग़रीब 20% लोगों की औसत आय का अनुपात।

आय का गिनी गुणांक : किसी देश के व्यक्तियों या परिवारों की आय (या उपभोग) के वितरण में एक पूर्णतः समान वितरण के सापेक्ष विचलन का मापक। इसके 0 मान का अर्थ है पूरी समानता तथा 100 मान का अर्थ है पूर्ण असमानता।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1 : एच.डी.आर.ओ. की UNDESA (2011), बर्रो एवं ली (2011), यूनेस्को साख्यिकी संस्था (2012), विश्व बैंक (2012a) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2012) पर आधारित गणनाएँ।

कॉलम 2: कॉलम 5, 7 तथा 9 के मानों के गुणात्मक माध्य के रूप में निकाले गए मान, तकनीकी नोट 2 की कार्यविधि के आधार पर।

कॉलम 3: कॉलम 1 तथा 2 के आँकड़ों के आधार पर निकाले गए मान।

कॉलम 4: कॉलम 2 के आँकड़ों तथा अ.मा.वि.सू. वाले देशों की पुनर्आकलित मा.वि.सू. श्रेणी के आधार पर निकाले गए मान।

कॉलम 5: UNDESA (2011) की संक्षिप्त जीवन सारणियों पर आधारित गणनाएँ।

कॉलम 6: कॉलम 5 और अ-समायोजित जीवन प्रत्याशा सूचकांक पर आधारित गणनाएँ।

कॉलम 7 और 9: एल.आई.एस. (2012), यूरोस्टैट (2012), विश्व बैंक (2012b), यूनिसेफ़ के 2002-2012 के मल्टीपलइंडीकेटर क्लस्टर सर्वेक्षणों) और आई.सी.एफ. मैक्रो (2012) के आँकड़ों पर आधारित गणनाएँ, तकनीकी नोट 2 की कार्यविधि के आधार पर।

कॉलम 8 : कॉलम 7 के आँकड़ों और अ-समायोजित शिक्षा सूचकांक पर आधारित गणनाएँ।

कॉलम 10: कॉलम 9 के आँकड़ों और अ-समायोजित आय सूचकांक पर आधारित गणनाएँ।

कॉलम 11 और 12: विश्व बैंक (2012a)।

सारणी 4 लैंगिक असमानता सूचकांक

	लैंगिक असमानता सूचकांक		मातृ मृत्यु अनुपात[a]	किशोरी प्रजनन दर[b]	राष्ट्रीय संसद में सीटें[c]	कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त जनसंख्या (% आयु 25 एवं अधिक)		श्रम बल में भागीदारी की दर (% उम्र 15 और अधिक)	
	श्रेणी	मान	(मृत्यु प्रति 100,000 जीवित जन्म)	15-19 आयु वर्ग की प्रति 1,000 महिलाओं पर जन्म	(स्त्री %)	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष
मा.वि.सू. श्रेणी	2012	2012	2010	2012[d]	2012	2006–2010[e]	2006–2010[e]	2011	2011
अति उच्च मानव विकास									
1 नार्वे	5	0.065	7	7.4	39.6	95.6	94.7	61.7	70.1
2 ऑस्ट्रेलिया	17	0.115	7	12.5	29.2	92.2	92.2	58.8	72.3
3 यूनाइटेड स्टेट्स	42	0.256	21	27.4	17.0 [f]	94.7	94.3	57.5	70.1
4 नीदरलैण्ड	1	0.045	6	4.3	37.8	87.5	90.4	58.3	71.3
5 जर्मनी	6	0.075	7	6.8	32.4	96.2	96.9	53.0	66.5
6 न्यूज़ीलैण्ड	31	0.164	15	18.6	32.2	82.8	84.7	61.6	74.1
7 आयरलैण्ड	19	0.121	6	8.8	19.0	74.8	73.0	52.6	68.5
7 स्वीडन	2	0.055	4	6.5	44.7	84.4	85.5	59.4	68.1
9 स्विट्ज़रलैण्ड	3	0.057	8	3.9	26.8	95.1	96.6	60.6	75.0
10 जापान	21	0.131	5	6.0	13.4	80.0 [g]	82.3 [g]	49.4	71.7
11 कनाडा	18	0.119	12	11.3	28.0	100.0	100.0	61.9	71.4
12 कोरिआ गणराज्य	27	0.153	16	5.8	15.7	79.4 [g]	91.7 [g]	49.2	71.4
13 हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	..	..	..	4.2	..	68.7	76.4	51.0	68.1
13 आइसलैण्ड	10	0.089	5	11.6	39.7	91.0	91.6	70.8	78.4
15 डेनमार्क	3	0.057	12	5.1	39.1	99.3	99.4	59.8	69.1
16 इस्राइल	25	0.144	7	14.0	20.0	82.7	85.5	52.5	62.4
17 बेल्जियम	12	0.098	8	11.2	38.9	76.4	82.7	47.7	60.6
18 ऑस्ट्रिया	14	0.102	4	9.7	28.7	100.0	100.0	53.9	67.6
18 सिंगापुर	13	0.101	3	6.7	23.5	71.3	78.9	56.5	76.6
20 फ्रांस	9	0.083	8	6.0	25.1	75.9	81.3	51.1	61.9
21 फ़िनलैण्ड	6	0.075	5	9.3	42.5	100.0	100.0	55.9	64.2
21 स्लोवेनिया	8	0.080	12	4.5	23.1	94.2	97.1	53.1	65.1
23 स्पेन	15	0.103	6	10.7	34.9	63.3	69.7	51.6	67.4
24 लिक्टेंन्स्टाइन	..	..	..	6.0	24.0	..	..	..	..
25 इटली	11	0.094	4	4.0	20.7	68.0	78.1	37.9	59.6
26 लक्ज़मबर्ग	26	0.149	20	8.4	25.0	77.1	78.7	49.2	65.2
26 यूनाइटेड किंगडम	34	0.205	12	29.7	22.1	99.6	99.8	55.6	68.5
28 चेक गणराज्य	20	0.122	5	9.2	21.0	99.8	99.8	49.6	68.2
29 यूनान	23	0.136	3	9.6	21.0	57.7	66.6	44.8	65.0
30 ब्रूनेई दारस्सलाम	..	..	24	22.7	..	66.6 [g]	61.2 [g]	55.5	76.5
31 साइप्रस	22	0.134	10	5.5	10.7	71.0	78.1	57.2	71.5
32 माल्टा	39	0.236	8	11.8	8.7	58.0	67.3	35.2	67.4
33 अंडोरा	..	..	..	7.3	50.0	49.5	49.3	..	..
33 एस्टोनिआ	29	0.158	2	17.2	19.8	94.4 [g]	94.6 [g]	56.7	68.2
35 स्लोवाकिआ	32	0.171	6	16.7	17.3	98.6	99.1	51.2	68.1
36 कतर	117	0.546	7	15.5	0.1 [h]	70.1	62.1	51.8	95.2
37 हंगरी	42	0.256	21	13.6	8.8	93.2 [g]	96.7 [g]	43.8	58.4
38 बारबाडोस	61	0.343	51	40.8	19.6	89.5 [g]	87.6 [g]	64.8	76.2
39 पोलैण्ड	24	0.140	5	12.2	21.8	76.9	83.5	48.2	64.3
40 चिली	66	0.360	25	56.0	13.9	72.1	75.9	47.1	74.2
41 लिथुआनिया	28	0.157	8	16.1	19.1	87.9	93.1	54.1	63.9
41 संयुक्त अरब अमीरात	40	0.241	12	23.4	17.5	73.1 [g]	61.3 [g]	43.5	92.3
43 पुर्तगाल	16	0.114	8	12.5	28.7	40.9	40.2	56.5	68.0
44 लातीविया	36	0.216	34	12.8	23.0	98.6	98.2	55.2	67.2
45 अर्जेंटीना	71	0.380	77	54.2	37.7	57.0 [g]	54.9 [g]	47.3	74.9
46 सेशेल्स	..	..	..	47.6	43.8	66.9	66.6	..	..
47 क्रोएशिया	33	0.179	17	12.8	23.8	57.4 [g]	72.3 [g]	46.0	59.7
उच्च मानव विकास									
48 बहरीन	45	0.258	20	14.8	18.8	74.4 [g]	80.4 [g]	39.4	87.3
49 बहामास	53	0.316	47	28.3	16.7	91.2	87.6	69.3	79.3
50 बेलारूस	..	..	4	20.5	29.7	..	..	50.2	62.6
51 उरुग्वे	69	0.367	29	59.0	12.3	50.6	48.8	55.6	76.5
52 मॉन्टीनेग्रो	..	..	8	14.8	12.3	97.5	98.8	..	..
52 पलाउ	..	..	..	12.7	6.9	..	..	..	..
54 कुवैत	47	0.274	14	14.4	6.3	53.7	46.6	43.4	82.3
55 रूसी गणराज्य	51	0.312	34	23.2	11.1	93.5 [g]	96.2 [g]	56.3	71.0
56 रोमानिया	55	0.327	27	28.8	9.7	83.4	90.5	48.6	64.9
57 बुल्गारिया	38	0.219	11	36.2	20.8	90.9	94.4	48.6	60.3
57 सऊदी अरब	145	0.682	24	22.1	0.1 [h]	50.3 [g]	57.9 [g]	17.7	74.1
59 क्यूबा	63	0.356	73	43.9	45.2	73.9 [g]	80.4 [g]	43.3	69.9
59 पनामा	108	0.503	92	75.9	8.5	63.5 [g]	60.7 [g]	49.6	82.5

	लैंगिक असमानता सूचकांक		मातृ मृत्यु अनुपात[a]	किशोरी प्रजनन दर[b]	राष्ट्रीय संसद में सीटें[c]	कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त जनसंख्या (% आयु 25 एवं अधिक)		श्रम बल में भागीदारी की दर (% उम्र 15 और अधिक)	
	श्रेणी	मान	(मृत्यु प्रति 100,000 जीवित जन्म)	15-19 आयु वर्ग की प्रति 1,000 महिलाओं पर जन्म	(स्त्री %)	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष
मा.वि.सू. श्रेणी	2012	2012	2010	2012[d]	2012	2006–2010[e]	2006–2010[e]	2011	2011
61 मैक्सिको	72	0.382	50	65.5	36.0	51.2	57.0	44.3	80.5
62 कोस्टा रिका	62	0.346	40	61.9	38.6	54.4[g]	52.8[g]	46.4	78.9
63 ग्रेनाडा	..	..	24	35.4	17.9	..	..	..	..
64 लीबिया	36	0.216	58	2.6	16.5	55.6[g]	44.0[g]	30.1	76.8
64 मलेशिया	42	0.256	29	9.8	13.2	66.0[g]	72.8[g]	43.8	76.9
64 सर्बिया	..	..	12	19.2	32.4	80.1	90.7	..	..
67 एंटिगुआ और बरबूडा	..	..	..	49.1	19.4	..	..	..	..
67 ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	50	0.311	46	31.6	27.4	59.4	59.2	54.9	78.3
69 कज़ाकिस्तान	51	0.312	51	25.5	18.2	99.3	99.4	66.6	77.2
70 अल्बानिआ	41	0.251	27	14.9	15.7	78.8	85.0	49.6	71.3
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	93	0.466	92	87.3	17.0	55.1	49.8	52.1	80.2
72 डोमिनिका	..	..	..	18.9	12.5	29.7	23.2	..	..
72 जॉर्जिआ	81	0.438	67	39.5	6.6	89.7	92.7	55.8	74.2
72 लेबनान	78	0.433	25	15.4	3.1	53.0	55.4	22.6	70.8
72 सेंट किट्स एवं नेविस	..	..	..	33.2	6.7	..	..	..	..
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	107	0.496	21	25.0	3.1	62.1	69.1	16.4	72.5
77 पेरू	73	0.387	67	48.7	21.5	47.3	59.1	67.8	84.7
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	30	0.162	10	17.8	30.9	72.0	85.3	42.9	68.9
78 यूक्रेन	57	0.338	32	26.1	8.0	91.5[g]	96.1[g]	53.3	66.6
80 मॉरिशस	70	0.377	60	31.8	18.8	45.2[g]	52.9[g]	44.1	75.5
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	..	..	8	13.4	19.3	..	..	35.2	58.6
82 अज़रबैजान	54	0.323	43	31.4	16.0	90.0	95.7	61.6	68.5
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	..	..	48	54.1	17.4	..	..	55.7	78.4
84 ओमान	59	0.340	32	9.3	9.6	47.2	57.1	28.3	81.6
85 ब्राज़ील	85	0.447	56	76.0	9.6	50.5	48.5	59.6	80.9
85 जमैका	87	0.458	110	69.7	15.5	74.0[g]	71.1[g]	56.0	71.8
87 आर्मेनिआ	59	0.340	30	33.2	10.7	94.1[g]	94.8[g]	49.4	70.2
88 सेंट लूसिआ	..	..	35	55.9	17.2	..	..	64.2	77.3
89 इक्वाडोर	83	0.442	110	80.6	32.3	36.6	36.6	54.3	82.7
90 तुर्की	68	0.366	20	30.5	14.2	26.7	42.4	28.1	71.4
91 कोलम्बिया	88	0.459	92	68.1	13.6	43.8	42.4	55.8	79.7
92 श्रीलंका	75	0.402	35	22.1	5.8	72.6	75.5	34.7	76.3
93 अल्जीरिया	74	0.391	97	6.1	25.6	20.9	27.3	15.0	71.9
94 ट्यूनीशिया	46	0.261	56	4.4	26.7	29.9	44.4	25.5	70.0
मध्यम मानव विकास									
95 टोंगा	90	0.462	110	18.0	3.6[i]	71.6[g]	76.7[g]	53.6	75.0
96 बेलीज	79	0.435	53	70.8	13.3	35.2[g]	32.8[g]	48.3	81.8
96 डोमीनिकन गणराज्य	109	0.508	150	103.6	19.1	43.3	41.7	51.0	78.6
96 फ़िजी	..	..	26	42.8	..	57.5	58.1	39.3	79.5
96 समोआ	..	..	..	25.5	4.1	64.3	60.0	42.8	77.8
100 जॉर्डन	99	0.482	63	23.7	11.1	68.9	77.7	15.6	65.9
101 चीन	35	0.213	37	9.1	21.3	54.8[g]	70.4[g]	67.7	80.1
102 तुर्कमेनिस्तान	..	..	67	16.9	16.8	..	..	46.4	76.0
103 थाइलैण्ड	66	0.360	48	37.0	15.7	29.0	35.6	63.8	80.0
104 माल्दीव	64	0.357	60	10.2	6.5	20.7	30.1	55.7	76.8
105 सूरीनाम	94	0.467	130	34.9	11.8	40.5	47.1	40.5	68.7
106 गैबन	105	0.492	230	81.0	16.7	53.8[g]	34.7[g]	56.3	65.0
107 अल सल्वाडोर	82	0.441	81	76.2	26.2	34.8	40.8	47.4	78.6
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	97	0.474	190	74.7	30.1	39.8	49.7	64.1	80.9
108 मंगोलिया	56	0.328	63	18.7	12.7	83.0[g]	81.8[g]	54.3	65.5
110 फ़लस्तीन राज्य	..	..	64	48.3	..	48.0	56.2	15.1	66.3
111 पराग्वे	95	0.472	99	66.7	13.6	35.0	39.0	57.9	86.3
112 मिस्र	126	0.590	66	40.6	2.2	43.4[g]	59.3[g]	23.7	74.3
113 माल्डोवा गणराज्य	49	0.303	41	29.1	19.8	91.6	95.3	38.4	45.1
114 फ़िलीपीन्स	77	0.418	99	46.5	22.1	65.9[g]	63.7[g]	49.7	79.4
114 उज़्बेकिस्तान	..	..	28	12.8	19.2	..	..	47.7	74.7
116 सीरियाई अरब गणराज्य	118	0.551	70	36.5	12.0	27.4	38.2	13.1	71.6
117 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	..	..	100	18.5	0.1	..	..	..	..
118 गयाना	104	0.490	280	53.9	31.3	61.5[g]	48.8[g]	41.8	79.1
119 बोत्स्वाना	102	0.485	160	43.8	7.9	73.6[g]	77.5[g]	71.7	81.6
120 होण्डुरास	100	0.483	100	85.9	19.5	20.7	18.8	42.3	82.8
121 इण्डोनेशिया	106	0.494	220	42.3	18.2	36.2	46.8	51.2	84.2

मा.वि.सू. श्रेणी		लैंगिक असमानता सूचकांक		मातृ मृत्यु अनुपात[a]	किशोरी प्रजनन दर[b]	राष्ट्रीय संसद में सीटें[c]	कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त जनसंख्या		श्रम बल में भागीदारी की दर	
				(मृत्यु प्रति 100,000 जीवित जन्म)	15-19 आयु वर्ग की प्रति 1,000 महिलाओं पर जन्म	(स्त्री %)	(% आयु 25 एवं अधिक)		(% उम्र 15 और अधिक)	
		श्रेणी	मान				स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष
		2012	2012	2010	2012[d]	2012	2006–2010[e]	2006–2010[e]	2011	2011
121	किरिबाती	..	..	..	16.4	8.7	..	..	..	..
121	दक्षिण अफ्रीका	90	0.462	300	50.4	41.1[j]	68.9	72.2	44.0	60.8
124	वनुआतू	..	..	110	50.6	1.9	..	..	61.3	79.7
125	किर्गिस्तान	64	0.357	71	33.0	23.3	81.0[g]	81.2[g]	55.5	78.6
125	ताजिकिस्तान	57	0.338	65	25.7	17.5	93.2[g]	85.8[g]	57.4	75.1
127	वियतनाम	48	0.299	59	22.7	24.4	24.7[g]	28.0[g]	73.2	81.2
128	नामीबिया	86	0.455	200	54.4	25.0	33.0[g]	34.0[g]	58.6	69.9
129	निकारागुआ	89	0.461	95	104.9	40.2	30.8[g]	44.7[g]	46.7	80.0
130	मोरक्को	84	0.444	100	10.8	11.0	20.1[g]	36.3[g]	26.2	74.7
131	इराक	120	0.557	63	85.9	25.2	22.0[g]	42.7[g]	14.5	69.3
132	केप वर्दे	..	..	79	69.2	20.8	..	..	50.8	83.3
133	ग्वाटेमाला	114	0.539	120	102.4	13.3	12.6	17.4	49.0	88.3
134	टिमोर लेस्ट	..	..	300	52.3	38.5	..	..	38.4	74.1
135	घाना	121	0.565	350	62.4	8.3	45.7[g]	61.8[g]	66.9	71.8
136	इक्वेटोरिअल गिनी	..	..	240	114.6	10.0	..	..	80.6	92.3
136	भारत	132	0.610	200	74.7	10.9	26.6[g]	50.4[g]	29.0	80.7
138	कम्बोडिया	96	0.473	250	32.9	18.1	11.6	20.6	79.2	86.7
138	लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	100	0.483	470	30.1	25.0	22.9[g]	36.8[g]	76.5	79.5
140	भूटान	92	0.464	180	44.9	13.9	34.0	34.5	65.8	76.5
141	स्वाज़ीलैण्ड	112	0.525	320	67.9	21.9	49.9[g]	46.1[g]	43.6	70.8
निम्न मानव विकास										
142	कौंगो	132	0.610	560	112.6	9.6	43.8[g]	48.7[g]	68.4	72.9
143	सॉलोमन द्वीपसमूह	..	..	93	64.6	..	..	..	53.2	79.9
144	साओ टोम एवं प्रिन्साइप	..	..	70	55.4	18.2	..	..	43.7	76.6
145	केन्या	130	0.608	360	98.1	9.8	25.3	52.3	61.5	71.8
146	बांग्लादेश	111	0.518	240	68.2	19.7	30.8[g]	39.3[g]	57.2	84.3
146	पाकिस्तान	123	0.567	260	28.1	21.1	18.3	43.1	22.7	83.3
148	अंगोला	..	..	450	148.1	38.2[k]	..	..	62.9	77.1
149	म्याँमार	80	0.437	200	12.0	4.6	18.0[g]	17.6[g]	75.0	82.1
150	कैमरून	137	0.628	690	115.1	13.9	21.1[g]	34.9[g]	64.2	77.4
151	मैडागास्कर	..	..	240	122.7	15.9	..	..	83.4	88.7
152	तंज़ानिया गणराज्य	119	0.556	460	128.7	36.0	5.6[g]	9.2[g]	88.2	90.3
153	नाइजीरिया	..	..	630	111.3	6.7	..	..	47.9	63.3
154	सेनेगल	115	0.540	370	89.7	41.6	4.6	11.0	66.1	88.4
155	मॉरिटानिया	139	0.643	510	71.3	19.2	8.0[g]	20.8[g]	28.7	79.2
156	पापुआ न्यू गिनी	134	0.617	230	62.0	2.7	6.8[g]	14.1[g]	70.6	74.1
157	नेपाल	102	0.485	170	86.2	33.2	17.9[g]	39.9[g]	80.4	87.6
158	लेसोथो	113	0.534	620	60.8	26.1	21.9	19.8	58.9	73.4
159	टोगो	122	0.566	300	54.3	11.1	15.3[g]	45.1[g]	80.4	81.4
160	यमन	148	0.747	200	66.1	0.7	7.6[g]	24.4[g]	25.2	72.0
161	हैती	127	0.592	350	41.3	4.0	22.5[g]	36.3[g]	60.1	70.6
161	युगाण्डा	110	0.517	310	126.4	35.0	23.0	23.9	76.0	79.5
163	ज़ाम्बिया	136	0.623	440	138.5	11.5	25.7	44.2	73.2	85.6
164	जिबूती	..	..	200	19.5	13.8	..	..	36.0	67.2
165	गैम्बिया	128	0.594	360	66.9	7.5	16.9[g]	31.4[g]	72.4	83.1
166	बेनिन	135	0.618	350	97.0	8.4	11.2[g]	25.6[g]	67.4	78.2
167	रवाण्डा	76	0.414	340	35.5	51.9	7.4[g]	8.0[g]	86.4	85.4
168	आइवरी कोस्ट	138	0.632	400	105.7	11.0	13.7[g]	29.9[g]	51.8	81.2
169	कोमोरॉस	..	..	280	51.1	3.0	..	..	35.1	80.4
170	मलावी	124	0.573	460	105.6	22.3	10.4[g]	20.4[g]	84.8	81.3
171	सूडान	129	0.604	730	53.0	24.1	12.8[g]	18.2[g]	30.9	76.5
172	ज़िम्बाब्वे	116	0.544	570	53.4	17.9	48.8[g]	62.0[g]	83.0	89.5
173	इथियोपिया	..	..	350	48.3	25.5	..	..	78.4	89.8
174	लाइबेरिया	143	0.658	770	123.0	11.7	15.7[g]	39.2[g]	57.9	64.4
175	अफ़गानिस्तान	147	0.712	460	99.6	27.6	5.8[g]	34.0[g]	15.7	80.3
176	गिनी बिसाउ	..	..	790	96.2	10.0	..	..	68.0	78.2
177	सिएरा लिओन	139	0.643	890	104.2	12.9	9.5[g]	20.4[g]	66.3	69.1
178	बुरुण्डी	98	0.476	800	20.9	34.9	5.2[g]	9.2[g]	83.7	82.1
178	गिनी	..	..	610	133.7	..[l]	..	..	65.4	78.3
180	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	142	0.654	890	98.6	12.5	10.3[g]	26.2[g]	72.5	85.1
181	इरिट्रिया	..	..	240	53.7	22.0	..	..	79.8	90.0
182	माली	141	0.649	540	168.9	10.2	11.3	9.2	36.8	70.0

	लैंगिक असमानता सूचकांक		मातृ मृत्यु अनुपात[a]	किशोरी प्रजनन दर[b]	राष्ट्रीय संसद में सीटें[c]	कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त जनसंख्या (% आयु 25 एवं अधिक)		श्रम बल में भागीदारी की दर (% उम्र 15 और अधिक)	
	श्रेणी	मान	(मृत्यु प्रति 100,000 जीवित जन्म)	15-19 आयु वर्ग की प्रति 1,000 महिलाओं पर जन्म	(स्त्री %)	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष
मा.वि.सू. श्रेणी	2012	2012	2010	2012[d]	2012	2006–2010[e]	2006–2010[e]	2011	2011
183 बुर्किना फ़ासो	131	0.609	300	117.4	15.3	0.9	3.2	77.5	90.4
184 चाड	..	..	1,100	138.1	12.8	..	..	64.4	80.2
185 मोज़ाम्बीक	125	0.582	490	124.4	39.2	1.5[g]	6.0[g]	86.0	82.9
186 कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	144	0.681	540	170.6	8.2	10.7[g]	36.2[g]	70.2	72.5
186 नाइजर	146	0.707	590	193.6	13.3	2.5[g]	7.6[g]	39.9	89.9
अन्य देश अथवा अंचल									
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	..	..	81	0.6	15.6	..	..	71.6	83.7
मार्शल द्वीप समूह	..	..	..	37.7	3.0	..	..	..	..
मोनाको	..	..	..	1.5	19.0	..	..	..	..
नाउरू	..	..	..	23.0	0.1	..	..	..	..
सैन मैरीनो	..	..	..	2.5	18.3	..	..	..	..
सोमालिया	..	..	1,000	68.0	13.8	..	..	37.7	76.8
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	24.3	..	..	..	..
तुवालू	..	..	..	21.5	6.7	..	..	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह									
अति उच्च मानव विकास	..	0.193	15	18.7	25.0	84.7	87.1	52.7	68.7
उच्च मानव विकास	..	0.376	47	45.9	18.5	62.9	65.2	46.8	75.3
मध्यम मानव विकास	..	0.457	121	44.7	18.2	42.1	58.8	50.5	79.9
निम्न मानव विकास	..	0.578	405	86.0	19.2	18.0	32.0	56.4	79.9
क्षेत्र									
अरब देश	..	0.555	176	39.2	13.0	31.8	44.7	22.8	74.1
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	..	0.333	73	18.5	17.7	49.6	63.0	65.2	80.6
यूरोप एवं मध्य एशिया	..	0.280	28	23.1	16.7	81.4	85.8	49.6	69.0
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	..	0.419	74	70.6	24.4	49.8	51.1	53.7	79.9
दक्षिण एशिया	..	0.568	203	66.9	18.5	28.3	49.7	31.3	81.0
सब-सहारा अफ्रीका	..	0.577	475	105.2	20.9	23.7	35.1	64.7	76.2
न्यूनतम विकसित देश	..	0.566	394	90.9	20.3	16.9	27.1	64.8	82.4
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	..	0.481	193	61.1	22.0	48.0	53.0	53.0	73.9
विश्व	**..**	**0.463**	**145**	**51.2**	**20.3**	**52.3**	**62.9**	**51.3**	**77.2**

नोट

a आँकड़ों की गणना देशों के बीच तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए की गई है और ये अनिवार्य रूप से देश के आधिकारिक आँकड़ों के समान नहीं हैं, वे वैकल्पिक परिशुद्ध पद्धतियों पर आधारित हो सकते हैं। आँकड़ों को इस आधार पर पूर्णता (rounding) दी गई हैः 100 से कम, कोई पूर्णता नहीं; 100-999, निकटतम 10 पर पूर्णता; 1,000 से अधिक, निकटतम 100 पर पूर्णता।

b मध्यम प्रजनन वेरियंट पर आधारित।

c द्विसदनीय विधायी प्रणाली वाले देशों के लिए राष्ट्रीय संसद में सीटों की हिस्सेदारी की गणना दोनों सदनों के आधार पर की गई है।

d आँकड़े 2010-2015 के लिए अनुमानित मूल्यों के वार्षिक औसत हैं।

e आँकड़े निर्दिष्ट अवधि में अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए हैं।

f गणना में निर्दिष्ट हर (denominator) प्रतिनिधि सभा के केवल वोट देने वाले सदस्यों को इंगित करता है।

g 2010 के लिए बर्रो और ली (2011) के अनुमान।

h लैंगिक असमानता सूचकांक की गणना के लिए 0.1 % का मान उपयोग में लाया गया है।

i 2010 में कोई भी महिला निर्वाचित नहीं हुई; हालाँकि एक महिला कैबिनेट में नियुक्त हुई।

j आँकड़ों में अस्थाई रूप से नियुक्त 36 विशेष आवर्ती क्रम वाले प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है।

k अनुमान 31 अगस्त 2012 के चुनावों से पहले के हैं।

l 2008 दिसंबर में तख्तापलट के बाद संसद भंग कर दी गई थी।

परिभाषाएँ

लैंगिक असमानता सूचकाँकः एक समिश्र मापक जो महिलाओं और पुरुषों की तीन आयामों में उपलब्धियों में असमानता को प्रतिबिम्बित करता हैः प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम बजार। लैंगिक असमानता सूचकाँक की गणना की जानकारी के लिए http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_TechNotes.pdf पर तकनीकी सारणी 3 देखें।

मातृ मृत्यु अनुपातः किसी एक साल में होने वाली माताओं की मृत्यु और जीवित जन्में कुल शिशुओं की संख्या का अनुपात, प्रति लाख जीवित जन्मों के आधार पर व्यक्त।

किशोरी प्रजनन दरः 15 से 19 आयु वर्ग की 1000 महिलाओं पर 15 से 19 आयु वर्ग की महिलाओं को होने वाले बच्चों की संख्या।

राष्ट्रीय संसद में सीटेंः निचले सदन या एकल सदन या उच्च सदन या सीनेट में महिलाओं द्वारा काबिज सीटों का अनुपात, कुल सीटों के प्रतिशत के रूपमें व्यक्त।

कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त जनसंख्याः 25 साल या उससे अधिक आयु वाले उन लोगों का प्रतिशत जो सेकेण्डरी शिक्षा तक पहुँचे।

श्रम बल सहभागिता दरः किसी देश के काम करने की उम्र वाले उन लोगों का अनुपात जो कि श्रम बाजार में सम्बद्ध है– या तो काम करते हुए या काम की तलाश में सक्रिय। काम करने वाली कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1 और 2: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ डब्ल्यू.एच.ओ. और अन्य (2012), UNDESA (2011), आई.पी.यू. (2012), बर्रो और ली (2010), यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (2012) और आई.एल.ओ. (2012) पर आधारित।

कॉलम 3: डब्ल्यू.एच.ओ. और अन्य (2012)।

कॉलम 4: UNDESA (2011)।

कॉलम 5: आई.पी.यू. (2012)।

कॉलम 6 और 7: यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (2012)।

कॉलम 8 और 9: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (2012)।

सारणी 5

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

	बहुआयामी निर्धनता सूचकांक		बहुआयामी निर्धनता में जनसंख्या[a]			गरीबी के प्रति अरक्षित जनसंख्या	घोर गरीबी में जी रही जनसंख्या	समग्र गरीबी में वंचितता की हिस्सेदारी (%)			आय निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या (%)	
			गणना		वंचितता की तीव्रता						पी.पी.पी. $1.25 प्रति दिन	राष्ट्रीय गरीबी रेखा
	वर्ष[b]	मान[a]	(%)	(हज़ार)	(%)	(%)	(%)	शिक्षा	स्वास्थ्य	जीवन स्तर	2002–2011[c]	2002–2012[c]
2007-2011 के सर्वेक्षणों पर आधारित अनुमान												
अल्बानिया	2008/2009 (D)	0.005	1.4	45	37.7	7.4	0.1	32.0	44.9	23.0	0.6	12.4
आर्मेनिया	2010 (D)	0.001	0.3	6	35.2	3.0	0.0	25.8	64.8	9.4	1.3	35.8
बांग्लादेश	2007 (D)	0.292	57.8	83,207	50.4	21.2	26.2	18.7	34.5	46.8	43.3	31.5
भूटान	2010 (M)	0.119	27.2	198	43.9	17.2	8.5	40.4	21.2	38.4	10.2	23.2
प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	2008 (D)	0.089	20.5	1,972	43.7	18.7	5.8	19.8	27.5	52.6	15.6	60.1
बुर्किना फ़ासो	2010 (D)	0.535	84.0	13,834	63.7	7.1	65.7	36.2	27.9	35.9	44.6	
कम्बोडिया	2010 (D)	0.212	45.9	6,415	46.1	21.4	17.0	22.1	32.7	45.1	22.8	30.1
कोलम्बिया	2010 (D)	0.022	5.4	2,500	40.9	6.4	1.1	31.8	33.5	34.7	8.2	37.2
कौन्गो	2009 (D)	0.208	40.6	1,600	51.2	17.7	22.9	10.4	45.6	44.0	54.1	50.1
कौन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य	2010 (M)	0.392	74.0	48,815	53.0	15.1	45.9	18.0	25.1	56.9	87.7	71.3
डोमिनिकियाई गणराज्य	2007 (D)	0.018	4.6	439	39.4	8.6	0.7	39.1	22.6	38.2	2.2	34.4
मिस्र	2008 (D)	0.024	6.0	4,699	40.7	7.2	1.0	48.1	37.3	14.5	1.7	22.0
इथियोपिया	2011 (D)	0.564	87.3	72,415	64.6	6.8	71.1	25.9	27.6	46.5	39.0	38.9
घाना	2008 (D)	0.144	31.2	7,258	46.2	21.6	11.4	32.1	19.5	48.4	28.6	28.5
गयाना	2009 (D)	0.030	7.7	58	39.2	12.3	1.0	17.4	50.4	32.2	..	..
इण्डोनेशिया	2007 (D)	0.095	20.8	48,352	45.9	12.2	7.6	15.7	50.6	33.8	18.1	12.5
जॉर्डन	2009 (D)	0.008	2.4	145	34.4	1.3	0.1	49.6	47.4	3.1	0.1	13.3
केन्या	2008/2009 (D)	0.229	47.8	18,863	48.0	27.4	19.8	12.7	30.1	57.2	43.4	45.9
लेसोथो	2009 (D)	0.156	35.3	759	44.1	26.7	11.1	21.9	18.9	59.2	43.4	56.6
लाइबेरिया	2007 (D)	0.485	83.9	3,218	57.7	9.7	57.5	29.7	25.0	45.3	83.8	63.8
मैडागास्कर	2008/2009 (D)	0.357	66.9	13,463	53.3	17.9	35.4	34.3	16.7	49.1	81.3	68.7
मलावी	2010 (D)	0.334	66.7	9,633	50.1	23.4	31.4	19.5	27.1	53.3	73.9	52.4
मालद्वीव	2009 (D)	0.018	5.2	16	35.6	4.8	0.3	13.6	81.1	5.3	..	..
मॉरिटानिया	2007 (M)	0.352 [d]	61.7 [d]	1,982 [d]	57.1 [d]	15.1 [d]	40.7 [d]	32.0	21.6	46.5	23.4	42.0
मोरक्को	2007 (N)	0.048 [d]	10.6 [d]	3,287 [d]	45.3 [d]	12.3 [d]	3.3 [d]	35.5	27.5	37.0	2.5	9.0
मोज़ाम्बीक	2009 (D)	0.512	79.3	18,127	64.6	9.5	60.7	23.9	36.2	39.9	59.6	54.7
नामीबिया	2006/2007 (D)	0.187	39.6	855	47.2	23.6	14.7	15.1	31.0	53.9	31.9	38.0
नेपाल	2011 (D)	0.217	44.2	13,242	49.0	17.4	20.8	21.8	33.7	44.4	24.8	25.2
नाइजीरिया	2008 (D)	0.310	54.1	83,578	57.3	17.8	33.9	27.0	32.2	40.8	68.0	54.7
पाकिस्तान	2006/2007 (D)	0.264 [d]	49.4 [d]	81,236 [d]	53.4 [d]	11.0 [d]	27.4 [d]	30.8	37.9	31.2	21.0	22.3
फलस्तीन राज्य	2006/2007 (N)	0.005	1.4	52	37.3	8.8	0.1	33.9	55.3	10.8	0.0	21.9
पेरू	2008 (D)	0.066	15.7	4,422	42.2	14.9	3.9	18.6	20.8	60.6	4.9	31.3
फ़िलीपीन्स	2008 (D)	0.064	13.4	12,083	47.4	9.1	5.7	15.8	56.5	27.7	18.4	26.5
रवाण्डा	2010 (D)	0.350	69.0	6,900	50.8	19.4	34.7	19.5	30.9	49.6	63.2	44.9
साओ टोम एवं प्रिन्साइप	2008/2009 (D)	0.154	34.5	56	44.7	24.3	10.7	28.8	27.5	43.6	..	66.2
सेनेगल	2010/2011 (D)	0.439	74.4	7,642	58.9	11.7	50.6	31.8	40.6	27.6	33.5	50.8
सिएरा लिओन	2008 (D)	0.439	77.0	4,321	57.0	13.1	53.2	31.5	19.3	49.2	53.4	66.4
दक्षिण अफ़्रीका	2008 (N)	0.057	13.4	6,609	42.3	22.2	2.4	7.5	50.5	42.0	13.8	23.0
स्वाज़ीलैण्ड	2010 (M)	0.086	20.4	242	41.9	23.1	3.3	16.7	29.9	53.4	40.6	69.2
तंज़ानिया संयुक्त गणराज्य	2010 (D)	0.332	65.6	28,552	50.7	21.0	33.4	18.3	26.4	55.3	67.9	33.4
टिमोर लैस्ट	2009/2010 (D)	0.360	68.1	749	52.9	18.2	38.7	21.3	31.0	47.7	37.4	49.9
यूक्रेन	2007 (D)	0.008	2.2	1,018	35.5	1.0	0.2	4.7	91.1	4.2	0.1	2.9
युगाण्डा	2011 (D)	0.367	69.9	24,122	52.5	19.0	31.2	15.6	34.1	50.4	51.5	31.1
वनुआतू	2007 (M)	0.129	30.1	67	42.7	33.5	6.5	29.7	17.3	53.0	..	..
वियतनाम	2010/2011 (M)	0.017	4.2	3,690	39.5	7.9	0.7	32.8	25.1	42.1	40.1	28.9
ज़ाम्बिया	2007 (D)	0.328	64.2	7,740	51.2	17.2	34.8	17.5	27.9	54.7	68.5	59.3
जिम्बाब्वे	2010/2011 (D)	0.172	39.1	4,877	44.0	25.1	11.5	10.2	33.6	56.3	..	72.0
2002-2006 के सर्वेक्षणों पर आधारित अनुमान												
अर्जेन्टीना	2005 (N)	0.011 [f]	2.9 [f]	1,160 [f]	37.6 [f]	5.8 [f]	0.2 [f]	41.9	12.9	45.2	0.9	..
अज़रबैजान	2006 (D)	0.021	5.3	461	39.4	12.5	0.6	24.4	49.4	26.2	0.4	15.8
बेलारूस	2005 (M)	0.000	0.0	0	35.1	0.8	0.0	16.6	61.8	21.7	0.1	5.4
बेलीज़	2006 (M)	0.024	5.6	16	42.6	7.6	1.1	22.8	35.8	41.4	..	33.5
बेनिन	2006 (D)	0.412	71.8	5,652	57.4	13.2	47.2	33.6	25.1	41.3	47.3	39.0
बोस्निया एवं हर्ज़ेगोवीना	2006 (M)	0.003	0.8	30	37.2	7.0	0.1	29.2	51.8	19.0	0.0	14.0
ब्राज़ील	2006 (N)	0.011	2.7	5,075	39.3	7.0	0.2	39.0	40.2	20.7	6.1	21.4
बुरुण्डी	2005 (M)	0.530	84.5	6,128	62.7	12.2	61.9	31.5	22.4	46.1	81.3	66.9
कैमरून	2004 (D)	0.287	53.3	9,149	53.9	19.3	30.4	25.7	24.5	49.8	9.6	39.9
चाड	2003 (W)	0.344	62.9	5,758	54.7	28.2	44.1	40.9	4.6	54.5	61.9	55.0
चीन	2002 (W)	0.056	12.5	161,675	44.9	6.3	4.5	64.8	9.9	25.2	13.1	2.8
क्रोएशिया	2003 (W)	0.016	4.4	196	36.3	0.1	0.3	45.0	46.7	8.3	0.1	11.1
चेक गणराज्य	2002/2003 (W)	0.010	3.1	316	33.4	0.0	0.0	0.0	99.9	0.1	..	..

	बहुआयामी निर्धनता सूचकांक		बहुआयामी निर्धनता में जनसंख्या[a]			गरीबी के प्रति आरक्षित जनसंख्या	घोर गरीबी में जी रही जनसंख्या	समग्र गरीबी में वंचितता की हिस्सेदारी (%)			आय निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या (%)	
			संख्या		वंचितता की तीव्रता						पी.पी.पी. $1.25 प्रति दिन	राष्ट्रीय गरीबी रेखा
	वर्ष[b]	मान[a]	(%)	(हज़ार)	(%)	(%)	(%)	शिक्षा	स्वास्थ्य	जीवन स्तर	2002–2011[c]	2002–2012[c]
आइवरी कोस्ट	2005 (D)	0.353	61.5	11,083	57.4	15.3	39.3	32.0	38.7	29.3	23.8	42.7
जिबूती	2006 (M)	0.139	29.3	241	47.3	16.1	12.5	38.3	24.6	37.1	18.8	..
इक्वाडोर	2003 (W)	0.009	2.2	286	41.6	2.1	0.6	78.6	3.3	18.1	4.6	32.8
एस्टोनिया	2003 (W)	0.026	7.2	97	36.5	1.3	0.2	91.2	1.2	7.6	0.5	..
गैम्बिया	2005/2006 (M)	0.324	60.4	935	53.6	17.6	35.5	33.5	30.7	35.8	33.6	48.4
जॉर्जिया	2005 (M)	0.003	0.8	36	35.2	5.3	0.0	23.2	33.8	43.0	15.3	24.7
ग्वाटेमाला	2003 (W)	0.127[d]	25.9[d]	3,134[d]	49.1[d]	9.8[d]	14.5[d]	57.2	10.0	32.8	13.5	51.0
गिनी	2005 (D)	0.506	82.5	7,459	61.3	9.3	62.3	35.5	23.0	41.5	43.3	53.0
हैती	2005/2006 (D)	0.299	56.4	5,346	53.0	18.8	32.3	27.0	21.5	51.5	..	..
होण्डुरास	2005/2006 (D)	0.159	32.5	2,281	48.9	22.0	11.3	38.0	18.5	43.6	17.9	60.0
हंगरी	2003 (W)	0.016	4.6	466	34.3	0.0	0.0	1.8	95.6	2.7	0.2	..
भारत	2005/2006 (D)	0.283	53.7	612,203	52.7	16.4	28.6	21.8	35.7	42.5	32.7	29.8
इराक	2006 (M)	0.059	14.2	3,996	41.3	14.3	3.1	47.5	32.1	20.4	2.8	22.9
कज़ाकिस्तान	2006 (M)	0.002	0.6	92	36.9	5.0	0.0	14.6	56.8	28.7	0.1	8.2
किर्गिस्तान	2005/2006 (M)	0.019	4.9	249	38.8	9.2	0.9	36.6	36.9	26.4	6.2	33.7
लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य	2006 (M)	0.267	47.2	2,757	56.5	14.1	28.1	33.1	27.9	39.0	33.9	27.6
लात्विया	2003 (W)	0.006[d]	1.6[d]	37[d]	37.9[d]	0.0[d]	0.0[d]	0.0	88.0	12.0	0.1	5.9
माली	2006 (D)	0.558	86.6	11,771	64.4	7.6	68.4	34.5	26.2	39.3	50.4	47.4
मैक्सिको	2006 (N)	0.015	4.0	4,313	38.9	5.8	0.5	38.6	23.9	37.5	1.2	51.3
मॉल्डोवा गणराज्य	2005 (D)	0.007	1.9	72	36.7	6.4	0.1	24.7	34.3	41.1	0.4	21.9
मंगोलिया	2005 (M)	0.065	15.8	403	41.0	20.6	3.2	15.4	27.9	56.6	..	35.2
मॉन्टेनेग्रो	2005/2006 (M)	0.006	1.5	9	41.6	1.9	0.3	37.5	47.6	14.9	0.1	6.6
निकारागुआ	2006/2007 (D)	0.128	28.0	1,538	45.7	17.4	11.2	27.9	13.6	58.5	11.9	46.2
नाइजर	2006 (D)	0.642	92.4	12,437	69.4	4.0	81.8	35.4	21.5	43.2	43.6	59.5
पराग्वे	2002/2003 (W)	0.064	13.3	755	48.5	15.0	6.1	35.1	19.0	45.9	7.2	34.7
रूसी संघ	2003 (W)	0.005[d]	1.3[d]	1,883[d]	38.9[d]	0.8[d]	0.2[d]	84.2	2.5	13.3	0.0	11.1
सर्बिया	2005/2006 (M)	0.003	0.8	79	40.0	3.6	0.1	30.5	40.1	29.4	0.3	9.2
स्लोवाकिया	2003 (W)	0.000[e]	0.0[e]	0[e]	0.0[e]	0.0[e]	0.0[e]	0.0	0.0	0.0	0.1	..
स्लोवेनिया	2003 (W)	0.000[e]	0.0[e]	0[e]	0.0[e]	0.4[e]	0.0[e]	0.0	0.0	0.0	0.1	..
सोमालिया	2006 (M)	0.514	81.2	6,941	63.3	9.5	65.6	34.2	18.6	47.2	..	..
श्रीलंका	2003 (W)	0.021[d]	5.3[d]	1,027[d]	38.7[d]	14.4[d]	0.6[d]	6.3	35.4	58.3	7.0	8.9
सूरीनाम	2006 (M)	0.039	8.2	41	47.2	6.7	3.3	36.1	18.8	45.1	..	..
सीरियाई अरब गणराज्य	2006 (M)	0.021[e]	5.5[e]	1,041[e]	37.5[e]	7.1[e]	0.5[e]	45.4	42.7	11.8	1.7	..
ताजिकिस्तान	2005 (M)	0.068	17.1	1,104	40.0	23.0	3.1	18.7	45.0	36.3	6.6	46.7
थाईलैण्ड	2005/2006 (M)	0.006	1.6	1,067	38.5	9.9	0.2	40.7	31.2	28.1	0.4	8.1
मेसिडोनिया का पूर्व युगोस्लावी गणराज्य	2005 (M)	0.008	1.9	39	40.9	6.7	0.3	59.9	12.8	27.3	0.0	19.0
टोगो	2006 (M)	0.284	54.3	3,003	52.4	21.6	28.7	28.3	25.4	46.3	38.7	61.7
ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	2006 (M)	0.020	5.6	74	35.1	0.4	0.3	1.3	94.3	4.4	..	..
ट्यूनीशिया	2003 (W)	0.010[d]	2.8[d]	272[d]	37.1[d]	4.9[d]	0.2[d]	25.0	47.3	27.6	1.4	3.8
तुर्की	2003 (D)	0.028	6.6	4,378	42.0	7.3	1.3	42.3	38.4	19.2	0.0	18.1
संयुक्त अरब अमीरात	2003 (W)	0.002	0.6	20	35.3	2.0	0.0	94.4	0.4	5.2	..	..
उरुग्वे	2002/2003 (W)	0.006	1.7	57	34.7	0.1	0.0	96.0	0.6	3.4	0.2	18.6
उज़्बेकिस्तान	2006 (M)	0.008	2.3	603	36.2	8.1	0.1	23.2	55.7	21.1	..	..
यमन	2006 (M)	0.283	52.5	11,176	53.9	13.0	31.9	27.0	40.5	32.4	17.5	34.8

नोट

a सभी देशों के लिए सभी संकेतक उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए देशों के बीच तुलना करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ पर आँकड़े अनुपलब्ध हैं, वहाँ संकेतकों के मान को समायोजित किया गया है ताकि सबका जोड़ 100 हो। देशों के अनुपलब्ध आँकड़ों की विस्तृत जानकारी के लिए अल्काइर और अन्य (2011) तथा अल्काइर, कनकोनी और सँश (2012) देखें।

b D संकेत है जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वे के आँकड़ों का, M संकेत है मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे के आँकड़ों का, W संकेत है विश्व स्वास्थ्य सर्वे का और N संकेत है राष्ट्रीय सर्वे का।

c आँकड़े निर्दिष्ट अवधि में अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए हैं।

d निम्न सीमा सापेक्ष आकलन।

e उच्च सीमा सापेक्ष आकलन।

f देश के एक हिस्से को ही इंगित करता है।

परिभाषाएँ

बहुआयामी निर्धनता सूचकांकः बहुआयामी निर्धनता झेल रहे लोगों की आबादी का प्रतिशत, उनकी वंचितताओं की तीव्रता के अनुसार समायोजित। बहुआयामी निर्धनता की विस्तृत गणना के विवरण के लिए http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_TechNotes.pdf पर तकनीकी नोट 4 देखें।

बहुआयामी निर्धनता की गणना (headcount)**:** आबादी का वह प्रतिशत जिसकी भारित वंचितता का सांख्यिकी भार कम से कम 33% है।

बहुआयामी निर्धनता की वंचितता की तीव्रताः बहुआयामी निर्धनता में जी रहे लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली औसत वंचितता का प्रतिशत।

गरीबी के प्रति अरक्षित जनसंख्याः अनेक वंचितताओं के शिकार होने के जोखिम से घिरी जनसंख्या का प्रतिशत– यानी वह जनसंख्या जिसका वंचितता मान 20%-33% है।

घोर गरीबी में जी रही जनसंख्याः घोर बहुआयामी निर्धनता में जी रही जनसंख्या का प्रतिशत– यानी वे लोग जिनकी वंचितता का मान 50% या उससे अधिक है।

समग्र निर्धनता में वंचितता का योगदानः प्रत्येक आयाम में वंचितता के कारण बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रतिशत।

पी.पी.पी. 1.25 प्रतिदिन से कम आय वाली जनसंख्याः अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा $1.25 प्रतिदिन (क्रय शक्ति समतुल्यता के रूप में) से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत।

राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जनसंख्या : राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। वह रेखा जिसे किसी देश के प्राधिकारियों द्वारा उचित समझा जाता है। राष्ट्रीय आकलन आधारित है हाउसहोल्ड सर्वेक्षणों से प्राप्त जनसंख्या भारित उप-समूह आकलनों पर।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1-2: सन 2000 से 2010 के बीच किए गए आई.सी.एफ. मैक्रो डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, युनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड मल्टिपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षणों सहित कई घरेलू सर्वेक्षणों से संगणित।

कॉलम 3-10: विभिन्न पारिवारिक सर्वेक्षणों (जो कि कॉलम 1 में सूचीबद्ध हैं) से प्राप्त शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर की घरेलू वंचितताओं के आँकड़ों के आधार पर की गई गणनाएँ।

कॉलम 11 और 12: विश्व बैंक (2012a)

सारणी 6

संसाधनों पर नियंत्रण

मा.वि.सू. श्रेणी		अर्थव्यवस्था				सार्वजनिक व्यय									
		स.घ.उ. (2005 पी.पी.पी. $ बिलियन)	प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (2005 पी.पी.पी. $)	फ़िक्स्ड सकल पूँजी निर्माण (स.घ.उ. का %)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2005 = 100)	आम शासकीय अंतिम उपभोग व्यय (स.घ.उ. का %)		स्वास्थ्य (स.घ.उ. का %)		शिक्षा (स.घ.उ. का %)		सैन्य[a] (स.घ.उ. का %)		कुल ऋण सेवा (स.घ.उ. का %)	
		2011	2011	2011	2010	2000	2011	2010	2010	2000	2005–2010[b]	2000	2010	2000	2009
अति उच्च मानव विकास															
1	नार्वे	232.7	46,982	20.2	112	19.3	21.5	6.4	8.0	6.6	7.3	1.7	1.5	..	..
2	ऑस्ट्रेलिया	781.5	34,548	27.1	116	17.6	18.0	5.4	5.9	4.7	5.1	1.8	1.9	..	..
3	यूनाइटेड स्टेट्स	13,238.3	42,486	14.7[c]	112	14.3	17.5[c]	5.8	9.5	..	5.4	3.0	4.8	..	..
4	नीदरलैण्ड	621.9	37,251	18.6	108	22.0	28.1	5.0	9.4	5.0	5.9	1.5	1.4	..	..
5	जर्मनी	2,814.4	34,437	18.2	108	19.0	19.5	8.2	9.0	..	4.6	1.5	1.4	..	..
6	न्यूज़ीलैण्ड	108.4[c]	24,818[c]	18.9[c]	115	17.3	20.3[c]	6.0	8.4	..	7.2	1.2	1.2	..	..
7	आयरलैण्ड	159.9	35,640	11.5[c]	107	14.2	18.9[c]	4.6	6.4	4.2	5.7	0.7	0.6	..	..
7	स्वीडन	331.3	35,048	18.4	108	25.8	26.6	7.0	7.8	7.2	7.3	2.0	1.3	..	..
9	स्विटज़रलैण्ड	300.3	37,979	20.9[c]	104	11.1	11.5[c]	5.6	6.8	5.2	5.4	1.1	0.8	..	..
10	जापान	3,918.9	30,660	20.1[c]	100	16.9	19.8	6.2	7.8	3.7	3.8	1.0	1.0	..	..
11	कनाडा	1,231.6	35,716	22.1[c]	109	18.6	21.8[c]	6.2	8.0	5.6	4.8	1.1	1.5	..	..
12	कोरिआ गणराज्य	1,371.0	27,541	28.6[c]	116	12.0	15.3[c]	2.2	4.1	..	5.0	2.6	2.7	..	..
13	हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	310.0	43,844	21.5[c]	112	9.1	8.4[c]	..	..	..	3.6	..	..	..	..
13	आइसलैण्ड	10.7	33,618	14.1	149	23.4	25.2	7.7	7.6	6.7	7.8	0.0	0.1[d]	..	..
15	डेनमार्क	180.6	32,399	17.2	111	25.1	28.6	6.8	9.7	8.3	8.7	1.5	1.5	..	..
16	इस्राइल	207.5	26,720	18.7	114	25.8	23.9	4.7	4.6	6.5	5.8	8.0	6.5	..	..
17	बेल्जियम	364.7	33,127	20.9	111	21.3	24.1	6.1	8.0	..	6.4	1.4	1.1	..	..
18	ऑस्ट्रिया	306.1	36,353	21.1	109	19.0	19.3	7.6	8.5	5.7	5.5	1.0	0.9	..	..
18	सिंगापुर	277.8	53,591	23.4	114	10.9	10.3	1.3	1.4	3.4	3.3	4.6	3.7	..	..
20	फ्रांस	1,951.2	29,819	20.1	108	22.9	24.5	8.0	9.3	5.7	5.9	2.5	2.3	..	..
21	फ़िनलैण्ड	173.8	32,254	19.2	110	20.6	23.9	5.1	6.7	5.9	6.8	1.3	1.4	..	..
21	स्लोवेनिया	51.2	24,967	19.5	115	18.7	20.6	6.1	6.9	..	5.7	1.1	1.6	..	..
23	स्पेन	1,251.3	27,063	21.7	112	17.1	20.3	5.2	6.9	4.3	5.0	1.2	1.0	..	..
24	लिक्टेन्स्टाइन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2.1	..	..	..	..
25	इटली	1,645.0	27,069	19.5	110	18.3	20.5	5.8	7.4	4.4	4.7	2.0	1.7	..	..
26	लक्ज़मबर्ग	35.4	68,459	19.0	111	15.1	16.5	5.2	6.6	..	..	0.6	0.6	..	..
26	यूनाइटेड किंगडम	2,034.2	32,474	14.3	114	18.6	22.5	5.6	8.1	4.5	5.6	2.4	2.6	..	..
28	चेक गणराज्य	252.8	23,967	23.9	115	20.3	20.9	5.9	6.6	4.0	4.5	2.0	1.3	..	..
29	यूनान	255.0	22,558	14.0	117	18.9	17.5	4.7	6.1	3.4	4.1	3.6	2.3	..	..
30	ब्रूनेई दारस्सलाम	18.2[c]	45,507[c]	15.9[c]	105	25.8	22.4[c]	2.6	2.4	3.7	2.0	5.7	3.2	..	..
31	साइप्रस	21.0	26,045	18.4[c]	113	16.0	19.7[c]	2.4	2.5	5.3	7.9	3.0	2.1	..	..
32	माल्टा	9.6	23,007	15.0	112	18.2	21.1	4.9	5.7	..	5.8	0.7	0.7	..	..
33	अंडोरा	..	..	..	..	..	..	4.9	5.3	..	2.9	..	..	..	..
33	एस्टोनिआ	24.0	17,885	21.5	126	19.8	19.5	4.1	4.7	5.4	5.7	1.4	1.7	..	..
35	स्लोवाकिआ	112.9	20,757	22.4	115	20.1	18.1	5.6	5.8	3.9	4.1	1.7	1.3	..	..
36	कतर	145.8	77,987	39.6[d]	136	19.7	24.8[d]	1.6	1.4	..	2.4	..	2.3[e]	..	..
37	हंगरी	172.5	17,295	16.7	130	21.5	10.0	5.0	5.1	5.0	5.1	1.7	1.0	..	..
38	बारबाडोस	4.8[d]	17,564[d]	14.6[c]	132	21.2	20.3[c]	4.1	5.2	5.6	6.7	..	..	..	..
39	पोलैण्ड	691.2	18,087	19.9[c]	115	17.4	18.9[c]	3.9	5.4	5.0	5.1	1.8	1.9	..	..
40	चिली	263.7	15,272	23.2	101	12.5	11.8	3.4	3.8	3.9	4.5	3.8	3.2	8.2	6.2
41	लिथुआनिया	54.1	16,877	17.6	129	22.8	18.9	4.5	5.2	..	5.7	1.7	1.1	9.7	24.3
41	संयुक्त अरब अमीरात	333.7	42,293	23.8[c]	115	..	8.2[c]	2.5	2.7	1.3	1.0	9.4	6.9	..	..
43	पुर्तगाल	226.8	21,317	18.1	109	19.0	20.1	6.4	7.5	5.2	5.8	1.9	2.1	..	..
44	लातीविया	30.6	13,773	22.4	139	20.8	15.6	3.2	4.1	5.4	5.6	0.9	1.1	7.7	43.9
45	अर्जेंटीना	631.9	15,501	22.6	154	13.8	15.1	5.0	4.4	4.6	6.0	1.1	0.9	9.4	3.8
46	सेशेल्स	2.0	23,172	22.0[d]	185	24.2	11.1[d]	4.0	3.1	..	5.0	1.7	1.3	3.4	5.0
47	क्रोएशिया	71.2	16,162	21.9	117	23.8	21.2	6.7	6.6	..	4.3	3.1	1.7	..	..
उच्च मानव विकास															
48	बहरीन	26.9[c]	21,345[c]	26.6[d]	114	17.6	15.5[d]	2.7	3.6	..	2.9	4.0	3.4	..	..
49	बहामास	9.8	28,239	26.0	113	10.8	15.0	2.8	3.6	2.8	..	..	..	..	..
50	बेलारूस	125.0	13,191	37.6	162	19.5	13.5	4.9	4.4	6.2	4.5	1.3	1.4	2.9	2.6
51	उरुग्वे	44.9	13,315	19.0	142	12.4	13.0	6.1	5.6	2.4	2.9	2.8	2.0	5.3	3.5
52	मॉन्टीनेग्रो	6.6	10,402	22.1	122	21.9	18.2	5.4	6.1	..	..	..	1.9	..	2.4
52	पलाउ	0.3	13,176	..	..	..	..	8.5	7.9	9.8	..	..	..	..	..
54	कुवैत	135.1	47,935	17.8[d]	130	21.5	13.5	1.9	2.1	..	3.8	7.2	3.6	..	..
55	रूसी गणराज्य	2,101.8	14,808	23.1	163	15.1	16.9	3.2	3.2	2.9	4.1	3.7	3.9	4.6	4.2
56	रोमानिया	233.3	10,905	32.2	135	7.2	15.8	3.5	4.4	2.9	4.3	2.5	1.3	6.7	11.5
57	बुल्गारिया	88.2	11,799	23.3	138	19.0	15.4	3.6	3.7	..	4.4	2.7	1.9	10.0	8.4
57	सऊदी अरब	601.8	21,430	19.0	129	26.0	19.8	3.1	2.7	5.9	5.6	10.6	10.1	..	..

	अर्थव्यवस्था				सार्वजनिक व्यय									
	स.घ.उ.	प्रति व्यक्ति स.घ.उ.	फ़िक्स्ड सकल पूँजी निर्माण	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	आम शासकीय अंतिम उपभोग व्यय		स्वास्थ्य		शिक्षा		सैन्य[a]		कुल ऋण सेवा	
	(2005 पी.पी.पी. $ बिलियन)	(2005 पी.पी.पी. $)	(स.घ.उ. का %)	(2005 = 100)	(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)	
मा.वि.सू. श्रेणी	2011	2011	2011	2010	2000	2011	2010	2010	2000	2005–2010[b]	2000	2010	2000	2009
59 क्यूबा	..	..	9.9 [c]	..	29.6	37.9 [c]	6.1	9.7	7.7	12.9	..	..	..	..
59 पनामा	49.2	13,766	27.5 [c]	123	13.2	11.2 [c]	5.3	6.1	5.0	3.8	0.0	0.0	7.6	4.0
61 मैक्सिको	1,466.6	12,776	20.4	124	11.1	12.0	2.4	3.1	4.9	5.3	0.6	0.5	10.1	3.0
62 कोस्टा रिका	50.7	10,732	19.8	158	13.3	17.6 [c]	5.0	7.4	4.4	6.3	0.0	0.0	4.1	3.0
63 ग्रेनाडा	1.0	9,806	23.1 [d]	121	11.7	15.6 [d]	4.2	2.6	..	..	..	..	2.8	3.3
64 लीबिया	96.2 [d]	15,361 [d]	..	125	20.8	..	1.9	2.7	..	..	3.1	1.2 [e]	..	..
64 मलेशिया	394.6	13,672	20.3 [c]	114	10.2	12.7 [c]	1.7	2.4	6.0	5.8	1.6	1.6	6.9	5.6
64 सर्बिया	71.2	9,809	25.3	153	19.6	18.2	5.2	6.4	..	5.0	5.5	2.2	2.0	11.2
67 एंटिगुआ और बरबूडा	1.3	14,139	18.3 [d]	112	19.0	17.6 [d]	3.3	4.3	..	2.5	..	..	..	..
67 ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	30.6	22,761	..	155	9.3	..	1.7	3.4	3.8	..	..	..	..	..
69 कज़ाकिस्तान	191.5	11,568	23.9	162	12.1	9.8	2.1	2.5	3.3	3.1	0.8	1.1	18.4	32.3
70 अल्बानिआ	25.3	7,861	24.9	115	8.9	9.3	2.3	2.6	..	..	1.2	1.6	0.8	3.9
71 वेनेजुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	329.6	11,258	17.0	163	12.4	10.4	2.4	1.7	..	3.7	1.5	0.9	5.4	1.5
72 डोमिनिका	0.8	11,120	22.3 [c]	116	18.5	17.2 [c]	4.1	5.2	..	3.6	..	..	3.3	3.3
72 जॉर्जिआ	21.6	4,826	17.2	143	8.5	9.4	1.2	2.4	2.2	3.2	0.6	3.9	3.9	7.0
72 लेबनान	54.9	12,900	30.0	105	17.3	12.3	3.2	2.8	1.9	1.8	5.4	4.2	8.6	10.9
72 सेंट किट्स एवं नेविस	0.7	13,291	30.3 [d]	122	17.6	16.0 [d]	3.3	4.0	5.2	4.5	..	..	5.1	6.7
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	765.2 [d]	10,462 [d]	..	206	13.9	..	1.9	2.2	4.4	4.7	3.7	1.8 [e]	2.9	..
77 पेरू	266.0	9,049	23.8	115	10.6	9.8	2.8	2.7	..	2.7	1.8	1.3	4.8	4.4
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	19.5	9,451	21.5	115	18.2	18.0	4.9	4.5	..	..	1.9	1.4	3.9	7.3
78 यूक्रेन	290.6	6,359	19.3	195	20.9	18.8	2.9	4.4	4.2	5.3	3.6	2.7	11.7	22.1
80 मॉरिशस	16.4	12,737	24.4	137	14.1	14.0	2.0	2.5	3.8	3.1	0.2	0.1	9.9	1.3
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	28.5	7,607	20.7	118	..	22.1	4.1	6.8	..	..	..	1.2	5.8	8.2
82 अज़रबैजान	81.5	8,890	17.2	164	9.5	11.8	0.9	1.2	3.9	3.2	2.3	2.9	2.5	0.8
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	1.0	9,482	23.5 [d]	124	16.4	19.5 [d]	3.6	3.9	7.9	4.9	..	..	3.3	4.7
84 ओमान	72.1 [c]	25,330 [d]	..	131	20.7	19.9 [d]	2.5	2.2	3.1	4.3	10.8	8.5	..	..
85 ब्राज़ील	2,021.3	10,278	19.3	126	19.2	20.7	2.9	4.2	4.0	5.7	1.8	1.6	10.1	2.1
85 जमैका	19.2	7,074	22.9	179	14.3	17.7	2.9	2.6	5.0	6.1	0.5	0.8	7.8	8.5
87 अर्मेनिआ	15.8	5,112	30.9	131	11.8	11.8	1.1	1.8	2.8	3.2	3.6	4.2	2.4	10.3
88 सेंट लूसिआ	1.4	8,231	33.5 [c]	115	18.2	16.0 [c]	3.2	5.3	7.1	4.4	..	..	4.2	3.6
89 इक्वाडोर	109.2	7,443	24.2	124	9.8	15.8	1.3	3.0	1.3	..	1.6	3.6	11.8	3.2
90 तुर्की	991.7	13,466	20.0	153	11.7	8.1	3.1	5.1	2.6	2.9	3.7	2.4	7.8	8.0
91 कोलम्बिया	415.8	8,861	21.9	126	16.7	10.6	5.5	5.5	3.5	4.8	3.0	3.6	5.1	3.4
92 श्रीलंका	102.9	4,929	34.6	172	10.5	7.5	1.8	1.3	..	2.1	5.0	3.0	4.8	2.9
93 अल्जीरिया	275.0	7,643	38.3 [d]	122	13.6	14.2 [d]	2.6	3.2	..	4.3	3.4	3.6	8.2	0.4
94 ट्यूनीशिया	88.1	8,258	24.0	123	16.7	13.4	3.3	3.4	6.2	6.3	1.8	1.4	8.9	5.3
मध्यम मानव विकास														
95 टोंगा	0.4	4,092	24.3 [c]	131	18.2	18.9 [c]	4.0	4.1	4.9	..	..	..	2.4	1.4
96 बेलीज	2.1	5,896	..	113	12.9	..	2.2	3.3	5.0	6.1	0.9	1.1	9.2	7.2
96 डोमीनिकन गणराज्य	87.0	8,651	16.7	136	7.8	5.2	2.2	2.7	1.9	2.2	1.0	0.7	2.2	2.6
96 फ़िजी	3.6	4,199	..	127	17.2	..	3.2	3.4	5.9	4.5	1.9	1.6	1.5	0.7
96 समोआ	0.7	4,008	..	131	..	..	4.0	5.7	4.0	5.3	..	..	2.2	1.8
100 जॉर्डन	32.6	5,269	21.3	134	23.7	18.9	4.7	5.4	..	..	6.3	5.0	8.7	2.5
101 चीन	9,970.6	7,418	45.5	115	15.8	13.1	1.8	2.7	..	..	1.9	2.1	2.2	1.0
102 तुर्कमेनिस्तान	41.1	8,055	60.0	..	14.2	11.1	3.2	1.5	..	..	..	..	16.1	0.8
103 थाइलैण्ड	530.6	7,633	25.8	116	11.3	13.3	1.9	2.9	5.4	3.8	1.5	1.5	11.4	3.5
104 माल्दीव	2.5	7,834	..	138	22.9	..	4.1	3.8	..	8.7	..	..	3.2	9.8
105 सूरीनाम	3.7 [c]	7,110 [c]	..	145	37.5	..	3.9	3.4	..	..	..	..	..	..
106 गैबन	21.5	13,998	25.1	113	9.6	8.8	1.0	1.8	3.8	..	1.8	0.9	6.9	3.4
107 अल सल्वाडोर	37.6	6,032	14.2	119	10.2	11.1	3.6	4.3	2.5	3.2	1.3	1.1	2.8	5.0
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	45.4	4,499	16.6 [c]	137	14.5	13.2	3.7	3.0	5.5	6.3	2.1	1.7	7.6	3.3
108 मंगोलिया	11.7	4,178	48.6	168	15.3	14.0	3.9	3.0	5.6	5.4	2.1	1.1	3.4	2.8
110 फ़लस्तीन राज्य	..	..	..	..	27.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
111 पराग्वे	31.2	4,752	21.3	140	12.7	10.4	3.7	2.1	5.3	4.0	1.1	0.9	5.0	2.5
112 मिस्र	457.8	5,547	19.4	173	11.2	11.3	2.2	1.7	..	3.8	3.2	2.0	1.8	1.4
113 माल्डोवा गणराज्य	10.6	2,975	23.9	153	10.3	22.7	3.2	5.4	4.5	9.1	0.4	0.3	11.6	6.7
114 फ़िलीपीन्स	344.4	3,631	15.8	127	11.4	10.2	1.6	1.3	3.3	2.7	1.6	1.2	8.7	6.5
114 उज़्बेकिस्तान	85.2	2,903	23.5	..	18.7	16.6	2.5	2.8	..	..	1.2	..	6.4	1.5
116 सीरियाई अरब गणराज्य	96.9 [c]	4,741 [c]	18.8 [c]	142	12.4	10.1 [c]	2.0	1.6	..	4.9	5.5	4.1	2.5	1.1
117 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	0.3	3,017	..	..	..	..	7.7	12.9	6.7	..	..	..	..	..

मा.वि.सू. श्रेणी		अर्थव्यवस्था				सार्वजनिक व्यय									
		स.घ.उ.	प्रति व्यक्ति स.घ.उ.	फ़िक्स्ड सकल पूँजी निर्माण	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	आम शासकीय अंतिम उपभोग व्यय		स्वास्थ्य		शिक्षा		सैन्य[a]		कुल ऋण सेवा	
		(2005 पी.पी.पी. $ बिलियन)	(2005 पी.पी.पी. $)	(स.घ.उ. का %)	(2005 = 100)	(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)	
		2011	2011	2011	2010	2000	2011	2010	2010	2000	2005–2010[b]	2000	2010	2000	2009
118	गयाना	2.3 [c]	3,104 [c]	26.3 [c]	136	24.7	15.1 [c]	4.6	5.1	8.5	3.7	1.5	2.1	9.7	1.4
119	बोत्स्वाना	26.3	12,939	27.9	156	25.4	19.9	2.9	6.0	..	7.8	3.3	2.4	1.2	0.5
120	होण्डुरास	27.7	3,566	22.2	139	13.4	17.1	3.0	4.4	..	..	0.7	1.1	5.5	3.4
121	इण्डोनेशिया	992.1	4,094	32.4	146	6.5	4.5	0.7	1.3	..	3.0	..	0.7	10.1	4.1
121	किरिबाती	0.2	2,220	..	..	..	..	7.5	9.3	11.0	..	..	..	..	..
121	दक्षिण अफ़्रीका	489.6	9,678	18.9	140	18.1	21.5	3.4	3.9	5.6	6.0	1.5	1.3	2.9	1.4
124	वनुआतू	1.0	4,062	..	119	20.8	..	2.7	4.8	7.0	5.2	..	..	0.7	0.9
125	किर्गिस्तान	11.7	2,126	24.8	167	20.0	19.1	2.1	3.5	3.5	6.2	2.9	4.4	12.6	11.6
125	ताजिकिस्तान	14.3	2,052	18.7	170	8.3	28.9	0.9	1.6	2.3	4.0	1.2	..	7.3	12.1
127	वियतनाम	264.6	3,013	31.9	167	6.4	5.7	1.6	2.6	..	5.3	..	2.5	4.2	1.3
128	नामीबिया	13.9	5,986	26.5	141	23.5	21.6	4.2	4.0	7.9	8.1	2.7	3.9	..	..
129	निकारागुआ	15.1	2,579	29.7	159	12.2	10.1	3.7	4.9	3.9	..	0.8	0.7	7.3	7.9
130	मोरक्को	143.5	4,373	30.6	111	18.4	15.4	1.2	2.0	5.8	5.4	2.3	3.5	7.3	3.6
131	इराक	112.5	3,412	..	171	..	..	0.4	6.8	..	..	..	2.4	..	..
132	केप वर्दे	1.8	3,616	36.5	121	30.7	20.7	3.4	3.1	..	5.6	1.3	0.5	3.0	2.2
133	ग्वाटेमाला	64.2	4,351	14.6	134	7.0	10.5	2.2	2.5	..	3.2	0.8	0.4	2.0	3.8
134	टिमोर लेस्ट	1.6	1,393	..	134	35.2	..	6.3	5.1	..	14.0	..	4.9	..	..
135	घाना	41.3	1,652	21.8	189	10.2	8.5	3.0	3.1	..	5.5	0.7	0.4	7.8	1.0
136	इक्वेटोरिअल गिनी	23.1	32,026	60.1 [d]	129	4.6	3.9 [d]	1.0	3.4	0.7	..	..	..	..	..
136	भारत	3,976.5	3,203	29.5	152	12.6	11.7	1.3	1.2	4.4	3.1	3.1	2.7	2.3	1.2
138	कम्बोडिया	29.8	2,080	16.2 [c]	148	5.2	6.3 [c]	1.3	2.1	1.7	2.6	2.2	1.6	0.9	0.6
138	लाओ जनतात्रिक गणराज्य	15.5	2,464	27.4	127	6.7	9.8	1.0	1.5	1.5	3.3	0.8	0.3	2.3	4.3
140	भूटान	3.8	5,096	41.3 [d]	134	20.4	21.4 [d]	5.3	4.5	5.8	4.0	..	..	1.6	5.6
141	स्वाज़ीलैण्ड	5.7	5,349	10.4	144	18.2	19.4	3.3	4.2	5.5	7.4	1.5	3.0	2.0	1.1
निम्न मानव विकास															
142	काँगो	16.1	3,885	23.4	130	11.6	9.7	1.2	1.1	..	6.2	..	1.1	1.4	1.6
143	सॉलोमन द्वीपसमूह	1.4	2,581	..	152	25.2	..	4.8	8.0	..	6.1	..	..	2.1	3.0
144	साओ टोम एवं प्रिन्साइप	0.3	1,805	..	260	..	..	3.6	2.7	..	..	..	..	..	0.8
145	केन्या	62.7	1,507	24.3	180	15.1	13.3	1.9	2.1	5.2	6.7	1.3	1.9	4.7	1.2
146	बांग्लादेश	236.0	1,568	24.7	145	4.6	5.5	1.1	1.2	2.4	2.2	1.3	1.1	1.6	1.0
146	पाकिस्तान	428.4	2,424	11.8	181	8.6	8.2	0.6	0.8	1.8	2.4	3.7	2.8	3.9	2.5
148	अंगोला	102.0	5,201	10.7	186	..	17.7	1.9	2.4	2.6	3.4	6.4	4.2	18.7	2.8
149	म्यॉमार	..	..	..	225	..	..	0.3	0.2	0.6	..	2.3	..	..	..
150	कैमरून	41.9	2,090	..	117	9.5	..	1.0	1.5	1.9	3.5	1.3	1.6	5.5	0.9
151	मैडागास्कर	18.2	853	33.0 [d]	159	9.0	11.6 [d]	2.5	2.3	2.9	3.2	1.2	0.7	3.0	0.6
152	तंज़ानिया गणराज्य	59.8	1,334	28.1	151	11.7	18.2	1.6	4.0	..	6.2	1.5	1.2	1.6	0.9
153	नाइजीरिया	360.8	2,221	..	161	..	..	1.5	1.9	..	..	0.8	1.0	4.0	0.2
154	सेनेगल	22.2	1,737	30.7	115	12.8	8.8	1.6	3.1	3.2	5.6	1.3	1.6	4.8	2.3
155	मॉरिटानिया	8.0	2,255	25.9	133	20.2	12.3	3.1	2.3	..	4.3	3.5	3.8	6.4	3.0
156	पापुआ न्यू गिनी	16.6	2,363	14.8	130	16.6	8.4	3.3	2.6	..	..	0.9	0.4	8.6	8.6
157	नेपाल	33.6	1,102	21.2	155	8.9	9.6	1.3	1.8	3.0	4.7	0.8	1.4	1.9	1.2
158	लेसोथो	3.3	1,504	34.9	141	41.7	32.6	3.4	8.5	11.8	13.0	4.0	3.1	8.2	1.6
159	टोगो	5.6	914	19.4	116	10.5	..	1.4	3.4	4.4	4.5	..	1.7	2.3	1.1
160	यमन	51.1	2,060	11.7 [c]	167	13.6	11.8 [c]	2.4	1.3	9.7	5.2	4.4	3.9 [e]	2.5	0.8
161	हैती	10.5	1,034	..	150	7.8	..	1.7	1.5	..	..	0.0	0.0	..	2.0
161	युगाण्डा	41.0	1,188	24.4	150	14.5	11.3	1.8	2.0	2.5	3.2	2.5	1.6	1.2	0.4
163	ज़ाम्बिया	19.2	1,423	21.3	167	9.5	11.6	2.9	3.6	2.0	1.3	..	1.7	5.7	0.9
164	जिबूती	..	2,087 [d]	..	129	29.7	..	3.9	4.7	9.7	8.4	5.1	3.7 [e]	2.4	..
165	गैम्बिया	3.3	1,873	17.5	123	11.2	9.9	1.9	2.9	2.7	5.0	1.0	0.6	2.7	1.9
166	बेनिन	13.0	1,428	27.4	119	11.6	..	1.9	2.0	3.3	4.5	0.6	1.0 [e]	3.3	0.6
167	रवाण्डा	12.0	1,097	21.0 [c]	155	11.0	15.5 [c]	1.7	5.2	4.1	4.7	3.5	1.3	2.1	0.3
168	आइवरी कोस्ट	31.9	1,581	16.4	114	7.2	9.1	1.3	1.1	3.8	4.6	..	1.6	9.8	1.7
169	कोमोरॉस	0.7	980	12.4 [d]	118	11.7	15.3 [d]	1.5	3.0	..	7.6	..	..	1.6	0.8
170	मलावी	12.4	805	20.8	156	14.6	15.7	2.8	4.0	5.2	5.7	0.7	1.1	3.6	0.4
171	सूडान	83.8	1,878	24.7	166	7.6	17.7	0.9	1.9	..	..	4.5	3.4	2.0	0.7
172	ज़िम्बाब्वे	..	..	6.5	..	24.3	18.3	0.0	..	..	2.5	4.7	1.3	6.3	1.5
173	इथियोपिया	83.0	979	19.0	223	17.9	9.0	2.3	2.6	3.9	4.7	7.5	0.9	1.7	0.6
174	लाइबेरिया	2.1	506	33.3	162	7.5	20.2	1.3	3.9	..	2.8	..	0.9	0.1	0.6
175	अफ़गानिस्तान	37.2 [c]	1,083 [c]	16.3 [c]	141	..	10.7 [c]	2.3	0.9	..	..	..	3.8	..	0.1
176	गिनी बिसाउ	1.7	1,097	..	119	14.0	..	1.0	0.9	..	..	4.4	..	2.4	2.1

		अर्थव्यवस्था				सार्वजनिक व्यय									
		स.घ.उ.	प्रति व्यक्ति स.घ.उ.	फ़िक्स्ड सकल पूँजी निर्माण	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	आम शासकीय अंतिम उपभोग व्यय		स्वास्थ्य		शिक्षा		सैन्य[a]		कुल ऋण सेवा	
		(2005 पी.पी.पी. $ बिलियन)	(2005 पी.पी.पी. $)	(स.घ.उ. का %)	(2005 = 100)	(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)		(स.घ.उ. का %)	
मा.वि.सू. श्रेणी		2011	2011	2011	2010	2000	2011	2010	2010	2000	2005–2010[b]	2000	2010	2000	2009
177	सिएरा लिओन	4.6	769	14.9	163	14.3	11.1	1.1	1.5	4.9	4.3	3.7	1.2	7.3	0.6
178	बुरुण्डी	4.6	533	18.4	163	15.5	26.3	2.1	4.4	3.2	9.2	6.0	3.8[e]	2.6	0.2
178	गिनी	10.1	990	20.0[c]	237	6.8	7.5[c]	0.7	0.6	2.5	2.4	1.5	..	5.0	1.8
180	मध्य अफ़्रीकी गणराज्य	3.2	716	10.8[d]	124	14.0	4.5[d]	1.6	1.4	1.5	1.2	..	2.6	1.5	0.1
181	इरिट्रिया	2.8	516	..	..	63.8	..	2.5	1.3	3.2	2.1	32.7	..	0.5	1.1
182	माली	15.3	964	..	116	8.6	..	2.1	2.3	3.6	4.5	2.2	1.9	3.8	0.6
183	बुर्किना फ़ासो	19.5	1,149	..	115	20.8	..	2.0	3.4	..	4.0	1.2	1.3	1.8	0.6
184	चाड	15.5	1,343	31.8[c]	117	7.7	13.2[c]	2.7	1.1	2.6	2.8	1.9	2.7	1.8	0.9
185	मोज़ाम्बीक	20.6	861	24.3	157	9.0	12.3	4.2	3.7	..	5.0	1.3	0.9[d]	2.3	1.0
186	कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	22.3	329	28.7[d]	..	7.5	7.6[d]	0.1	3.4	..	2.5	1.0	1.3	0.6	2.0
186	नाइजर	10.3	642	..	117	13.0	..	1.8	2.6	3.2	3.8	1.2	0.9	1.4	0.5
अन्य देश अथवा अंचल															
	कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	मार्शल द्वीप समूह	..	..	..	..	..	..	19.8	15.0	14.6	..	..	..	..	..
	मोनाको	..	..	..	..	..	..	2.8	3.8	1.3	1.2	..	..	..	..
	नाउरू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	सैन मैरीनो	..	..	..	114	..	..	6.5	6.1	..	..	..	..	..	..
	सोमालिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तुवाल	..	..	..	..	..	..	12.3	14.2	..	..	..	..	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह															
	अति उच्च मानव विकास	37,231.3	32,931	18.4	—	16.7	19.4	6.0	8.2	4.5	5.1	2.2	2.7	..	..
	उच्च मानव विकास	11,740.8	11,572	21.4	—	15.5	15.8	2.9	3.6	..	4.7	2.8	2.7	8.1	4.7
	मध्यम मानव विकास	18,095.7	5,203	38.4	—	13.9	12.4	1.8	2.4	..	3.6	2.2	2.0	3.7	1.6
	निम्न मानव विकास	1,948.5	1,623	18.4	—	10.1	11.1	1.4	1.8	..	3.5	2.5	2.0	3.9	1.3
क्षेत्र															
	अरब देश	2,808.0	8,104	24.3	—	19.2	15.4	2.4	2.6	..	3.9	6.8	5.5	..	..
	पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	12,580.2	6,616	..	—	..	..	1.7	2.5	..	..	..	..	..	..
	यूरोप एवं मध्य एशिया	5,946.1	12,458	22.5	—	15.7	15.4	3.7	4.3	..	4.1	2.8	2.7	6.8	8.3
	लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	6,046.4	10,429	20.1	—	14.7	16.1	3.2	3.8	4.3	5.3	1.4	1.4	8.9	2.8
	दक्षिण एशिया	5,586.1	3,241	27.6	—	11.8	10.9	1.3	1.2	4.0	3.2	3.2	2.5	2.6	1.3
	सब-सहारा अफ़्रीका	1,691.4	2,094	20.8	—	15.9	16.9	2.5	3.0	..	5.2	1.9	1.5	4.1	1.2
न्यूनतम विकसित देश		1,065.9	1,346	..	—	9.7	..	1.7	2.2	..	3.7	..	2.2	3.1	1.3
छोटे द्वीपीय विकासशील देश		223.2	5,340	..	—	17.3	..	3.6	3.0	..	..	..	..	..	..
विश्व		**69,016.4**	**10,103**	**22.3**	**—**	**16.3**	**17.5**	**5.3**	**6.5**	**..**	**4.9**	**2.3**	**2.6**	**..**	**..**

नोट

a देश विशेष के फुटनोट के लिए www.sipri.org/research/armaments/mile&/mile&_database पर स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति शोध संस्थान के सैन्य व्यय आँकड़ों को देखें।

b आँकड़े निर्दिष्ट अवधि में अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए हैं।

c 2010 के लिए संदर्भित।

d 2009 के लिए संदर्भित।

e 2008 के लिए संदर्भित।

परिभाषाएँ

सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.): अर्थव्यवस्था में सभी निवासी उत्पादकों द्वारा कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर शुल्क, जिनमें उत्पादों पर मिले अनुदानों को शामिल नहीं किया गया है और क्रय शक्ति समता दरों का इस्तेमाल करते हुए 2005 अंतरराष्ट्रीय डॉलर में व्यक्त है।

प्रति व्यक्ति स.घ.उ.: अर्थव्यवस्था में सभी निवासी उत्पादकों द्वारा कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर शुल्क, जिनमें उत्पादों पर मिले अनुदानों को शामिल नहीं किया गया है और क्रय शक्ति समता दरों का इस्तेमाल करते हुए 2005 अंतरराष्ट्रीय डॉलर में व्यक्त है और समान अवधि के दौरान कुल जनसंख्या से विभाजित।

सकल अचल पूँजी सृजन: कारोबारी क्षेत्र, सरकारों और परिवारों द्वारा अधिग्रहित नई और मौजूदा अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मूल्य (उनके अनिगमित उद्यम शामिल नहीं) से निस्तारित की गई अचल परिसंपत्तियों का अंतर। अचल परिसंपत्तियों के क्षरण के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: एक सूचकांक जो आम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है, जो नियत हो सकता है या विशेष समयांतराल के लिए, जैसे वार्षिक।

अंतिम आम शासकीय उपभोग व्यय: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सभी सरकारी वर्तमान व्यय, स.घ.उ. के प्रतिशत में व्यक्त (कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति और राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा पर अधिकांश व्यय शामिल, लेकिन सरकार का वह सैन्य व्यय शामिल नहीं जो सरकारी पूँजी सृजन का हिस्सा है।)

स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय: सरकारी (केन्द्र और राज्य) बजटों द्वारा चालू और पूँजी व्यय, बाह्य उधारी और अनुदान (अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा दान शामिल), सामाजिक (या अनिवार्य) स्वास्थ्य बीमा कोष, स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में व्यक्त।

शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय: शिक्षा पर कुल सार्वजनिक व्यय (चालू और पूँजी), स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में व्यक्त।

सेना पर सार्वजनिक व्यय: रक्षा मंत्रालय के सभी व्यय और अन्य मंत्रालयों द्वारा सैन्य कर्मियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण पर और सैन्य आपूर्ति तथा उपकरणों की खरीद पर व्यय, स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में व्यक्त।

कुल ऋण सेवाएँ: दीर्घावधि ऋणों पर विदेशी मुद्रा, वस्तुओं, या सेवाओं के रूप में मूलधन पुनर्भुगतान और वास्तविक चुकाये गए ब्याज का योग, लघु-अवधि ऋण पर ब्याज भुगतान, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को पुनर्भुगतान (पुनर्खरीद और शुल्क), स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में व्यक्त।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1-10: विश्व बैंक (2012a)।

कॉलम 11 और 12: स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति शोध संस्थान (2012)।

कॉलम 13 और 14: कुल ऋण सेवाएँ सकल राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में आँकड़े, विश्व बैंक (2012a) पर आधरित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

स्वास्थ्य

मा.वि.सू. श्रेणी		टीकाकरण कवरेज: डी.टी.पी. (एक वर्ष उम्र का %) 2010	टीकाकरण कवरेज: खसरा (एक वर्ष उम्र का %) 2010	कम वज़न वाले बच्चे (थोड़ा-बहुत और गंभीर) (पाँच वर्ष तक के बच्चों का %) 2006–2010[b]	एचआईवी संक्रमण, युवा: स्त्री (15-24 उम्र का %) 2009	एचआईवी संक्रमण, युवा: पुरुष (15-24 उम्र का %) 2009	मृत्यु दर: नवजात (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत्यु) 2010	मृत्यु दर: पाँच से कम (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत्यु) 2010	मृत्यु दर: वयस्क: स्त्री (प्रति 1,000 वयस्क) 2009	मृत्यु दर: वयस्क: पुरुष (प्रति 1,000 वयस्क) 2009	स्पष्ट कारण: मलेरिया के कारण (प्रति 100,000 व्यक्ति प्रति वर्ष) 2008	स्पष्ट कारण: हैजा के कारण (संख्या) 2005–2010[b]	स्पष्ट कारण: हृदय रोग और मधुमेह के कारण (प्रति 1,000 व्यक्ति) 2008	स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता: चिकित्सक (प्रति 1,000 व्यक्ति) 2005–2010[b]	स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता: स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से संतुष्टि (% संतुष्ट) 2007–2009[b]
अति उच्च मानव विकास															
1	नार्वे	99	93	..	0.1	0.1	3	3	50	83	0.0	0	124	4.1	68
2	ऑस्ट्रेलिया	97	94	..	0.1	0.1	4	5	45	79	0.0	0	112	3.0	60
3	यूनाइटेड स्टेट्स	99	92	..	0.2	0.3	7	8	78	134	0.0	0	156	2.7	56
4	नीदरलैण्ड	99	96	..	0.1	0.1	4	4	56	75	0.0	0	122	3.9	77
5	जर्मनी	97	96	..	0.1	0.1	3	4	53	99	0.0	0	170	3.5	47
6	न्यूज़ीलैण्ड	95	91	..	0.1	0.1	5	6	57	86	0.0	0	138	2.4	64
7	आयरलैण्ड	98	90	..	0.1	0.1	3	4	57	97	0.0	..	141	3.2	47
7	स्वीडन	99	96	..	0.1	0.1	2	3	47	74	0.0	0	141	3.6	81
9	स्विटज़रलैण्ड	98	90	..	0.1	0.2	4	5	43	74	0.0	0	114	4.1	81
10	जापान	99	94	..	0.1	0.1	2	3	42	86	0.0	0	91	2.1	54
11	कनाडा	92	93	..	0.1	0.1	5	6	53	87	0.0	0	121	1.9	73
12	कोरिआ गणराज्य	96	98	..	0.1	0.1	4	5	46	109	0.0	0	141	2.0	60
13	हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	67
13	आइसलैण्ड	98	93	..	0.1	0.1	2	2	43	65	0.0	..	121	3.9	87
15	डेनमार्क	93	85	..	0.1	0.1	3	4	65	107	0.0	0	143	3.4	82
16	इस्राइल	96	98	..	0.1	0.1	4	5	45	78	0.0	..	116	3.6	70
17	बेल्जियम	99	94	..	0.1	0.1	4	4	59	105	0.0	0	131	3.0	88
18	ऑस्ट्रिया	93	76	..	0.2	0.3	4	4	50	102	0.0	0	155	4.7	89
18	सिंगापुर	98	95	..	0.1	0.1	2	3	42	76	0.0	..	140	1.8	86
20	फ्रांस	99	90	..	0.1	0.2	3	4	54	117	0.0	0	98	3.5	84
21	फ़िनलैण्ड	99	98	..	0.1	0.1	2	3	56	124	0.0	0	157	2.7	85
21	स्लोवेनिया	98	95	..	0.1	0.1	2	3	54	131	0.0	0	168	2.5	68
23	स्पेन	99	95	..	0.1	0.2	4	5	43	94	0.0	0	113	3.7	84
24	लिक्टेन्स्टाइन	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..
25	इटली	98	90	..	0.1	0.1	3	4	41	77	0.0	0	128	4.2	59
26	लक्ज़मबर्ग	99	96	..	0.1	0.1	2	3	57	95	0.0	..	150	2.9	90
26	यूनाइटेड किंगडम	98	93	..	0.1	0.2	5	5	58	95	0.0	0	133	2.7	81
28	चेक गणराज्य	99	98	..	0.1	0.1	3	4	63	138	0.0	..	258	3.6	63
29	यूनान	99	99	..	0.1	0.1	3	4	44	106	0.0	..	186	6.0	45
30	ब्रूनेई दारस्सलाम	98	94	..	..	..	6	7	82	105	0.0	..	284	1.4	..
31	साइप्रस	99	87	..	..	..	3	4	41	81	0.0	..	188	2.3	60
32	माल्टा	97	73	..	0.1	0.1	5	6	44	76	0.0	..	175	3.1	81
33	अंडोरा	99	99	..	..	..	3	4	44	94	0.0	..	..	3.7	..
33	एस्टोनिआ	96	95	..	0.2	0.3	4	5	77	234	0.0	..	342	3.4	47
35	स्लोवाकिआ	99	98	..	0.1	0.1	7	8	74	184	0.0	..	343	3.0	..
36	कतर	98	99	..	0.1	0.1	7	8	48	69	0.0	0	195	2.8	..
37	हंगरी	99	99	..	0.1	0.1	5	6	99	229	0.0	..	324	3.1	50
38	बारबाडोस	95	85	..	1.1	0.9	17	20	80	136	0.1	..	233	1.8	..
39	पोलैण्ड	99	98	..	0.1	0.1	5	6	76	197	0.0	0	283	2.1	45
40	चिली	93	93	..	0.1	0.2	8	9	59	116	0.0	..	156	1.1	45
41	लिथुआनिया	98	96	..	0.1	0.1	5	7	95	274	0.0	..	375	3.7	29
41	संयुक्त अरब अमीरात	94	94	..	..	..	6	7	66	84	0.0	..	277	1.9	..
43	पुर्तगाल	99	96	..	0.2	0.3	3	4	54	123	0.0	..	154	3.8	69
44	लातीविया	97	93	..	0.1	0.2	8	10	105	284	0.0	..	420	3.0	42
45	अर्जेंटीना	98	99	2.3[c]	0.2	0.3	12	14	88	160	0.0	..	207	3.2	66
46	सेशेल्स	99	99	..	..	..	12	14	108	227	0.0	0	..	1.5	..
47	क्रोएशिया	98	95	..	0.1	0.1	5	6	60	153	0.0	..	294	2.6	..
उच्च मानव विकास															
48	बहरीन	99	99	..	..	..	9	10	87	127	0.1	..	339	1.4	..
49	बहामास	99	94	..	3.1	1.4	14	16	126	202	0.0	..	239	..	..
50	बेलारूस	99	99	1.3	0.1	0.1	4	6	117	324	0.0	..	525	4.9	45
51	उरुग्वे	98	95	5.4	0.2	0.3	9	11	84	156	0.0	..	211	3.7	77
52	मॉन्टीनेग्रो	97	90	1.7	..	..	7	8	85	161	0.0	..	419	..	..
52	पलाउ	99	75	..	..	..	15	19	110	229	0.0	..	..	1.3	..
54	कुवैत	98	98	..	..	..	10	11	50	66	0.0	..	274	1.8	..
55	रूसी गणराज्य	99	98	..	0.3	0.2	9	12	144	391	0.0	0	580	4.3	35
56	रोमानिया	99	95	3.5	0.1	0.1	11	14	90	219	0.0	..	398	1.9	44
57	बुल्गारिया	96	97	..	0.1	0.1	11	13	86	205	0.0	..	464	3.6	..

	टीकाकरण कवरेज			एचआईवी संक्रमण, युवा		मृत्यु दर							स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता	
								वयस्क		स्पष्ट कारण				
	डी.टी.पी.	खसरा	कम वज़न वाले बच्चे (थोड़ा-बहुत और गंभीर)	स्त्री	पुरुष	नवजात	पाँच से कम	स्त्री	पुरुष	मलेरिया के कारण	हैजा के कारण	हृदय रोग और मधुमेह के कारण	चिकित्सक	स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से संतुष्टि
	(एक वर्ष उम्र का %)		(पाँच वर्ष तक के बच्चों का %)	(15-24 उम्र का %)		(प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत्यु)		(प्रति 1,000 वयस्क)		(प्रति 100,000 व्यक्ति प्रति वर्ष)	(संख्या)	(प्रति 1,000 व्यक्ति)	(प्रति 1,000 व्यक्ति)	(% संतुष्ट)
मा.वि.सू. श्रेणी	2010	2010	2006–2010[b]	2009	2009	2010	2010	2009	2009	2008	2005–2010[b]	2008	2005–2010[b]	2007–2009[b]
57 सऊदी अरब	98	98	..	..	..	15	18	102	186	0.0	..	456	0.9	69
59 क्यूबा	98	99	..	0.1	0.1	5	6	78	120	0.0	..	215	6.4	..
59 पनामा	98	95	3.9	0.3	0.4	17	20	82	145	0.0	..	174	..	54
61 मैक्सिको	96	95	3.4	0.1	0.2	14	17	88	157	0.0	0	237	2.9	69
62 कोस्टा रिका	96	83	1.1	0.1	0.2	9	10	69	115	0.0	..	159	..	75
63 ग्रेनाडा	99	95	..	..	..	9	11	143	248	0.0	..	299	..	..
64 लीबिया	98	98	..	..	..	13	17	101	175	0.0	..	396	1.9	..
64 मलेशिया	98	96	12.9	0.1	0.1	5	6	95	175	0.1	2	278	0.9	89
64 सर्बिया	97	95	1.4	0.1	0.1	6	7	90	184	0.0	..	422	2.0	..
67 एंटिगुआ और बरबूडा	99	98	..	..	..	7	8	158	197	0.0	..	..	..	..
67 ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	96	92	..	0.7	1.0	24	27	120	225	0.0	..	427	1.2	32
69 कज़ाकिस्तान	99	99	3.9	0.2	0.1	29	33	185	432	0.0	0	696	3.9	49
70 अल्बानिआ	99	99	5.2	..	..	16	18	88	126	0.0	..	443	1.1	..
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	90	79	3.7	..	..	16	18	92	196	0.1	..	237	..	75
72 डोमिनिका	99	99	..	..	..	11	12	103	192	0.0	..	..	..	..
72 जॉर्जिआ	99	94	1.1	0.1	0.1	20	22	97	235	0.0	..	505	4.5	61
72 लेबनान	83	53	..	0.1	0.1	19	22	85	166	0.0	0	332	3.5	50
72 सेंट किट्स एवं नेविस	98	99	..	..	..	7	8	90	185	0.0	..	..	..	..
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	99	99	..	0.1	0.1	22	26	90	144	0.0	11	385	0.9	73
77 पेरू	97	94	4.2	0.1	0.2	15	19	96	123	0.1	..	135	0.9	48
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	98	98	1.5	..	..	10	12	79	144	0.0	..	465	2.5	..
78 यूक्रेन	96	94	..	0.3	0.2	11	13	148	395	0.0	0	593	3.1	23
80 मॉरिशस	99	99	..	0.2	0.3	13	15	99	219	0.0	0	444	1.1	..
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	95	93	1.4	..	..	8	8	67	145	0.0	..	398	1.4	..
82 अजरबैजान	80	67	7.7	0.1	0.1	39	46	134	221	0.0	..	619	3.8	53
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	99	99	..	..	..	19	21	110	204	0.0	..	340	..	..
84 ओमान	99	97	8.6	0.1	0.1	8	9	85	157	0.0	..	455	1.9	..
85 ब्राज़ील	99	99	1.7	..	..	17	19	102	205	0.1	0	264	1.7	44
85 जमैका	99	88	2.0	0.7	1.0	20	24	131	224	0.0	..	248	0.9	..
87 अर्मेनिआ	98	97	4.7	0.1	0.1	18	20	103	246	0.0	..	537	3.7	61
88 सेंट लूसिआ	98	95	..	..	..	14	16	90	188	0.0	..	278	0.5	..
89 इक्वाडोर	99	98	6.2	0.2	0.2	18	20	96	173	0.0	..	167	..	64
90 तुर्की	97	97	1.7	0.1	0.1	14	18	73	134	0.0	..	362	1.5	67
91 कोलम्बिया	96	88	3.4	0.1	0.2	17	19	80	166	0.3	..	186	1.4	63
92 श्रीलंका	99	99	21.1	0.1	0.1	14	17	82	275	0.0	..	312	0.5	83
93 अल्जीरिया	99	95	3.2	0.1	0.1	31	36	105	135	0.0	0	277	1.2	52
94 ट्यूनीशिया	98	97	3.3	0.1	0.1	14	16	70	129	0.1	..	257	1.2	80
मध्यम मानव विकास														
95 टोंगा	99	99	..	..	..	13	16	233	135	0.8	..	396	0.3	..
96 बेलीज़	99	98	4.3	1.8	0.7	14	17	129	202	0.0	..	256	0.8	50
96 डोमीनिकन गणराज्य	96	79	7.1	0.7	0.3	22	27	149	172	0.1	0	320	..	58
96 फ़िजी	99	94	..	0.1	0.1	15	17	157	263	0.0	..	457	0.5	..
96 समोआ	97	61	..	..	..	17	20	167	198	0.9	..	427	0.3	..
100 जॉर्डन	98	98	1.9	..	..	18	22	111	195	0.0	..	468	2.5	66
101 चीन	99	99	3.8[c]	..	..	16	18	87	142	0.0	4	287	1.4	..
102 तुर्कमेनिस्तान	99	99	8.2	..	..	47	56	212	380	0.0	..	773	2.4	..
103 थाइलैण्ड	99	98	7.0	..	..	11	13	139	270	0.4	0	311	0.3	85
104 माल्दीव	97	97	17.3	0.1	0.1	14	15	70	97	0.9	..	351	1.6	..
105 सूरीनाम	99	89	7.2	0.4	0.6	27	31	124	217	2.5	..	351	..	..
106 गैबन	69	55	..	3.5	1.4	54	74	262	321	31.0	0	370	0.3	..
107 अल सल्वाडोर	97	92	5.5	0.3	0.4	14	16	128	281	0.0	..	203	1.6	59
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	87	79	4.3	0.1	0.1	42	54	132	203	0.0	..	290	..	59
108 मंगोलिया	98	97	5.0	0.1	0.1	26	32	141	305	0.0	0	379	2.8	52
110 फ़लस्तीन राज्य	..	..	..	..	..	20	22	..	..	..	..	..	..	50
111 पराग्वे	96	94	3.4	0.1	0.2	21	25	98	168	0.0	0	249	1.1	66
112 मिस्र	97	96	6.0	0.1	0.1	19	22	130	215	0.2	..	406	2.8	53
113 माल्डोवा गणराज्य	93	97	3.2	0.1	0.1	16	19	134	309	0.0	..	525	2.7	41
114 फ़िलीपीन्स	89	88	21.6[c]	0.1	0.1	23	29	130	240	0.2	2	345	1.2	81
114 उज़्बेकिस्तान	99	98	4.0	0.1	0.1	44	52	139	220	0.0	..	641	2.6	..

	टीकाकरण कवरेज			एचआईवी संक्रमण, युवा		मृत्यु दर							स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता	
								वयस्क		स्पष्ट कारण				
	डी.टी.पी.	खसरा	कम वज़न वाले बच्चे (थोड़ा-बहुत और गंभीर)	स्त्री	पुरुष	नवजात	पाँच से कम	स्त्री	पुरुष	मलेरिया के कारण	हैजा के कारण	हृदय रोग और मधुमेह के कारण	चिकित्सक	स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से संतुष्टि
	(एक वर्ष उम्र का %)		(पाँच वर्ष तक के बच्चों का %)	(15-24 उम्र का %)		(प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत्यु)		(प्रति 1,000 वयस्क)		(प्रति 100,000 व्यक्ति प्रति वर्ष)	(संख्या)	(प्रति 1,000 व्यक्ति)	(प्रति 1,000 व्यक्ति)	(% संतुष्ट)
मा.वि.सू. श्रेणी	2010	2010	2006–2010[b]	2009	2009	2010	2010	2009	2009	2008	2005–2010[b]	2008	2005–2010[b]	2007–2009[b]
116 सीरियाई अरब गणराज्य	89	82	10.1	..	..	14	16	95	159	0.0	..	400	1.5	56
117 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	90	80	..	..	..	34	42	161	183	0.3	0	412	0.6	..
118 गयाना	99	95	10.5	0.8	0.6	25	30	224	286	5.0	..	452	..	63
119 बोत्स्वाना	98	94	11.2	11.8	5.2	36	48	324	372	1.0	0	346	0.3	72
120 होण्डुरास	99	99	8.1	0.2	0.3	20	24	134	237	0.1	..	376	..	68
121 इण्डोनेशिया	94	89	18.4	0.1	0.1	27	35	143	234	3.2	19	350	0.3	79
121 किरिबाती	97	89	..	..	..	39	49	173	325	2.6	..	..	0.3	..
121 दक्षिण अफ्रीका	73	65	8.7 [c]	13.6	4.5	41	57	479	521	0.2	28	321	0.8	63
124 वनुआतू	78	52	..	..	..	12	14	159	200	8.5	..	399	0.1	..
125 किर्गिस्तान	99	99	2.2	0.1	0.1	33	38	162	327	0.0	..	605	2.3	57
125 ताजिकिस्तान	95	94	15.0	0.1	0.1	52	63	160	183	0.0	..	523	2.0	64
127 वियतनाम	93	98	20.2	0.1	0.1	19	23	107	173	0.1	0	339	1.2	74
128 नामीबिया	87	75	16.6	5.8	2.3	29	40	357	540	29.0	0	495	0.4	68
129 निकारागुआ	99	99	5.5	0.1	0.1	23	27	122	210	0.0	..	234	0.4	66
130 मोरक्को	99	98	8.6	0.1	0.1	30	36	87	126	0.0	..	355	0.6	..
131 इराक	81	73	6.4	..	..	31	39	145	292	0.0	24	424	0.7	44
132 केप वर्दे	99	96	..	..	..	29	36	111	272	0.2	0	300	0.6	..
133 ग्वातेमाला	96	93	13.0 [c]	0.3	0.5	25	32	151	280	0.1	..	190	..	60
134 टिमोर लेस्ट	75	66	44.7	..	..	46	55	154	233	83.0	..	318	0.1	..
135 घाना	96	93	13.9	1.3	0.5	50	74	253	402	48.0	51	386	0.1	74
136 इक्वेटोरिअल गिनी	65	51	..	5.0	1.9	81	121	355	373	98.0	33	484	0.3	..
136 भारत	83	74	42.5	0.1	0.1	48	63	169	250	1.9	6	336	0.6	67
138 कम्बोडिया	93	93	28.3	0.1	0.1	43	51	190	350	3.7	0	408	0.2	75
138 लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	81	64	31.1	0.2	0.1	42	54	251	289	2.9	3	430	0.3	69
140 भूटान	94	95	12.7	0.1	0.1	44	56	194	256	0.2	..	425	0.0	..
141 स्वाज़ीलैण्ड	95	94	5.8	15.6	6.5	55	78	560	674	0.3	0	499	0.2	..
निम्न मानव विकास														
142 कौंगो	90	76	11.4	2.6	1.2	61	93	320	409	121.0	0	463	0.1	34
143 सॉलोमन द्वीपसमूह	85	68	11.8	..	..	23	27	119	170	30.0	..	367	0.2	..
144 साओ टोम एवं प्रिन्साइप	98	92	13.1	..	..	53	80	104	161	9.2	33	308	0.5	..
145 केन्या	93	86	16.1	4.1	1.8	55	85	282	358	12.0	21	363	0.1	62
146 बांग्लादेश	98	94	41.0	0.1	0.1	38	48	222	246	1.8	..	418	0.3	69
146 पाकिस्तान	90	86	31.3	0.1	0.1	70	87	189	225	0.6	0	422	0.8	41
148 अंगोला	97	93	15.6 [c]	1.6	0.6	98	161	353	377	89.0	0	483	0.1	62
149 म्यॉंमार	93	88	22.6	0.3	0.3	50	66	188	275	34.0	1	369	0.5	..
150 कैमरून	92	79	16.0	3.9	1.6	84	136	409	420	121.0	110	498	0.2	54
151 मैडागास्कर	78	67	..	0.1	0.1	43	62	198	273	8.5	0	376	0.2	82
152 तंज़ानिया गणराज्य	98	92	15.8	3.9	1.7	50	76	311	456	87.0	94	427	0.0	30
153 नाइजीरिया	77	71	23.1	2.9	1.2	88	143	365	377	146.0	174	456	0.4	55
154 सेनेगल	80	60	13.7	0.7	0.3	50	75	218	266	76.0	458	373	0.1	57
155 मॉरिटानिया	82	67	14.7 [c]	0.3	0.4	75	111	262	315	36.0	70	422	0.1	31
156 पापुआ न्यू गिनी	80	55	18.4	0.8	0.3	47	61	221	274	45.0	0	428	0.1	..
157 नेपाल	85	86	38.6	0.1	0.2	41	50	159	234	0.0	0	350	0.2	80
158 लेसोथो	93	85	13.2	14.2	5.4	65	85	573	676	0.1	0	452	0.1	..
159 टोगो	97	84	16.6	2.2	0.9	66	103	278	338	65.0	15	403	0.1	22
160 यमन	94	73	43.1	..	..	57	77	180	237	4.9	3	494	0.3	..
161 हैती	83	59	17.7	1.3	0.6	70	165	227	278	5.7	3,990	411	..	35
161 युगाण्डा	83	55	15.9	4.8	2.3	63	99	348	539	103.0	98	473	0.1	48
163 ज़ाम्बिया	99	91	14.6	8.9	4.2	69	111	477	580	104.0	7	518	0.1	53
164 जिबूती	90	85	22.9	1.9	0.8	73	91	271	326	1.2	27	490	0.2	56
165 गैम्बिया	99	97	18.1	2.4	0.9	57	98	246	296	93.0	13	417	0.0	..
166 बेनिन	94	69	18.4	0.7	0.3	73	115	246	385	105.0	11	454	0.1	52
167 रवाण्डा	92	82	11.4	1.9	1.3	59	91	258	304	15.0	0	408	0.0	78
168 आइवरी कोस्ट	95	70	15.9	1.5	0.7	86	123	456	528	116.0	6	536	0.1	..
169 कोमोरॉस	81	72	..	0.1	0.1	63	86	229	284	58.0	0	450	0.2	..
170 मलावी	97	93	12.8	6.8	3.1	58	92	496	691	87.0	11	587	0.0	66
171 सूडान	99	90	27.0	1.3	0.5	66	103	275	291	23.0	1,011	548	0.3	48
172 ज़िम्बाब्वे	94	84	9.7	6.9	3.3	51	80	574	672	40.0	26	324	0.2	27
173 इथियोपिया	90	81	33.2	..	..	68	106	379	445	10.0	0	508	0.0	19

	टीकाकरण कवरेज			एचआईवी संक्रमण, युवा		मृत्यु दर							स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता	
								वयस्क		स्पष्ट कारण				
	डी.टी.पी.	खसरा	कम वज़न वाले बच्चे (थोड़ा-बहुत और गंभीर)	स्त्री	पुरुष	नवजात	पाँच से कम	स्त्री	पुरुष	मलेरिया के कारण	हैजा के कारण	हृदय रोग और मधुमेह के कारण	चिकित्सक	स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से संतुष्टि
	(एक वर्ष उम्र का %)		(पाँच वर्ष तक के बच्चों का %)	(15-24 उम्र का %)		(प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत्यु)		(प्रति 1,000 वयस्क)		(प्रति 100,000 व्यक्ति प्रति वर्ष)	(संख्या)	(प्रति 1,000 व्यक्ति)	(प्रति 1,000 व्यक्ति)	(% संतुष्ट)
मा.वि.सू. श्रेणी	2010	2010	2006–2010[b]	2009	2009	2010	2010	2009	2009	2008	2005–2010[b]	2008	2005–2010[b]	2007–2009[b]
174 लाइबेरिया	75	64	14.9[c]	0.7	0.3	74	103	337	389	98.0	18	437	0.0	38
175 अफ़गानिस्तान	86	62	32.9	..	..	103	149	352	440	0.3	0	675	0.2	46
176 गिनी बिसाउ	92	61	18.1	2.0	0.8	92	150	369	431	203.0	399	513	0.0	..
177 सिएरा लिओन	96	82	21.1	1.5	0.6	114	174	363	414	239.0	0	440	0.0	46
178 बुरुण्डी	99	92	28.8	2.1	1.0	88	142	407	424	39.0	18	464	0.0	47
178 गिनी	75	51	20.8	0.9	0.4	81	130	337	474	165.0	107	520	0.1	31
180 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य	64	62	24.4	2.2	1.0	106	159	470	461	192.0	0	498	0.1	..
181 इरिट्रिया	99	99	34.5	0.4	0.2	42	61	179	249	0.7	0	383	0.1	..
182 माली	90	63	26.7	0.5	0.2	99	178	218	357	131.0	76	406	0.0	44
183 बुर्किना फ़ासो	98	94	25.7	0.8	0.5	93	176	262	443	221.0	16	463	0.1	50
184 चाड	71	46	30.3	2.5	1.0	99	173	384	412	235.0	14	500	0.0	42
185 मोज़ाम्बीक	77	70	18.3	8.6	3.1	92	135	434	557	171.0	24	512	0.0	69
186 कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	67	68	24.2	..	..	112	170	331	442	193.0	244	477	0.1	..
186 नाइजर	80	71	40.2[c]	0.5	0.2	73	143	224	229	184.0	55	381	0.0	46
अन्य देश अथवा अंचल														
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	94	99	18.8	..	..	26	33	126	207	0.0	..	303	3.3	..
मार्शल द्वीप समूह	99	97	..	..	..	22	26	386	429	1.1	..	..	0.6	..
मोनाको	99	99	..	..	..	3	4	51	112	0.0	..	..	..	..
नाउरू	99	99	4.8	..	..	32	40	303	448	0.0	..	..	0.7	..
सैन मैरीनो	95	93	..	..	..	2	2	48	57	0.0	..	..	..	..
सोमालिया	55	46	31.6	0.6	0.4	108	180	350	382	28.0	1,182	572	0.0	..
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
तुवालू	99	85	1.6	..	..	27	33	280	255	0.0	..	..	0.6	..
मानव विकास सूचकांक समूह														
अति उच्च मानव विकास	98	94	..	..	..	5	6	60	114	0.0	..	150	2.9	62
उच्च मानव विकास	97	95	..	..	..	16	18	105	221	0.0	..	357	2.3	..
मध्यम मानव विकास	90	85	22.7	..	..	33	42	132	204	1.3	..	324	1.0	..
निम्न मानव विकास	87	78	26.1	..	..	73	110	287	346	65.4	138	450	0.3	50
क्षेत्र														
अरब देश	93	87	..	..	..	36	48	139	198	3.5	..	409	1.4	..
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	97	95	9.7	..	..	20	24	103	168	1.5	..	305	1.2	..
यूरोप एवं मध्य एशिया	98	96	..	..	..	17	21	118	281	0.0	..	492	3.1	45
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	96	93	4.0	..	..	18	23	99	181	0.2	..	236	..	57
दक्षिण एशिया	86	78	40.2	..	..	50	65	173	245	1.6	..	360	0.6	65
सब-सहारा अफ़्रीका	84	75	21.2	..	..	76	120	355	430	98.1	86	447	0.2	..
न्यूनतम विकसित देश	88	78	27.3	..	..	71	108	282	357	62.1	190	459	0.2	..
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	89	72	..	..	..	41	70	155	207	15.6	..	342	2.6	..
विश्व	**91**	**85**	**..**	**..**	**..**	**40**	**55**	**137**	**211**	**12.2**	**..**	**323**	**1.4**	**..**

नोट

a अनुमान उम्र-मानकीकृत हैं और देशों की जीवन सारणियों, मृत्यु कारण मॉडलों, क्षेत्रीय मृत्यु-कारण रुझानों, और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा एच.आई.वी./एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का साझा कार्यक्रम के कुछ प्रमुख कारकों के लिए अनुमानों (पुरानी बीमारियाँ शामिल नहीं) के मिश्रण पर आधारित।

b आँकड़े निर्दिष्ट अवधि में अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए हैं।

c आँकड़े मानक परिभाषा से अलग हैं या देश के केवल एक हिस्से से संबंधित है।

परिभाषाएँ

डी.टी.पी. टीकाकरण का कवरेज: एक वर्ष के उन शिशुओं का प्रतिशत जिन्हें डिप्थीरिया, टिटेनस टॉक्साइड और परट्यूसिस (डी.टी.पी.) के संयुक्त टीके की तीन खुराकें मिलीं।

खसरा टीकाकरण का कवरेज: एक वर्ष के उन शिशुओं का प्रतिशत जिन्हें खसरे के टीके की कम से कम एक खुराक मिली।

कम वज़न वाले बच्चे : उन 5 वर्ष से छोटे बच्चों का प्रतिशत जिनका वज़न संदर्भ आबादी के उम्र-समतुल्य-वज़न के माध्यिका मान की तुलना में दो मानक विचलन (standard deviations) या उससे अधिक कम है।

एच.आई.वी. व्याप्तता: 15-24 आयु वर्ग की आबादी का प्रतिशत जो एच.आई.वी. से संक्रमित है।

शिशु मृत्यु दर: जन्म और ठीक एक साल की आयु के बीच मरने की प्रायिकता (Probability), प्रति 1000 जीवित जन्मों के सापेक्ष।

पाँच वर्ष से कम मृत्यु दर: जन्म और ठीक पाँच साल की आयु के बीच मरने की प्रायिकता, प्रति 1000 जीवित जन्मों के सापेक्ष।

वयस्क मृत्यु दर: इस बात की प्रायिकता कि 15 साल उम्र का कोई व्यक्ति 60 साल का होने से पहले मर जायेगा, प्रति 1,000 व्यस्कों के सापेक्ष

कारण-विशेष से हुई मृत्यु: किसी ख़ास बीमारी या कारण के फलस्वरूप हुई मृत्यु

चिकित्सक: चिकित्सकों की संख्या (सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ, दोनों), प्रति 1000 लोगों के सापेक्ष

स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से संतुष्टि: गैलप वर्ल्ड सर्वेक्षण के प्रश्न, 'क्या इस देश में आपको स्वास्थ्य सेवा या चिकित्सा प्रणाली पर भरोसा है?' पर उन प्रतिभागियों का प्रतिशत जिनका उत्तर 'हाँ' था।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1, 2, 8 और 9: डब्ल्यू.एच.ओ. (2012a)।

कॉलम 3-5: यूनीसेफ़ (2012)।

कॉलम 6, 10, 11 और 13: डब्ल्यू.एच.ओ. (2012b)।

कॉलम 7: बाल मृत्यु आकलन के लिए अंतर-एजेंसी समूह (2012)।

कॉलम 12: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ डब्ल्यू.एच.ओ. (2012b) द्वारा हृदय रोगों और मधुमेह के चलते महिला मृत्यु और पुरुष मृत्यु और UNDESA (2011) के जनसंख्या आँकड़ों पर आधारित।

कॉलम 14: गैलप (2012)।

सारणी 8

शिक्षा

मा.वि.सू. श्रेणी	शैक्षिक उपलब्धि: वयस्क साक्षरता दर (% उम्र 15 और अधिक)	शैक्षिक उपलब्धि: कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त जनसंख्या (% उम्र 25 और अधिक)	सकल नामांकन अनुपात: प्राथमिक (%)	सकल नामांकन अनुपात: सेकेण्डरी (%)	सकल नामांकन अनुपात: उच्च (%)	शैक्षिक गुणवत्ता: पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (%)	15 वर्षीय विद्यार्थियों का प्रदर्शन: माध्य प्राप्तांक: वाचन[a]	माध्य प्राप्तांक: गणित[b]	माध्य प्राप्तांक: विज्ञान[c]	माध्य से विचलन: वाचन	माध्य से विचलन: गणित	माध्य से विचलन: विज्ञान	शैक्षिक गुणवत्ता से संतुष्टि (% संतुष्ट)	प्राथमिक स्कूल छोड़ने की दर (प्राथमिक स्कूल समूह का %)
	2005–2010[d]	2010	2002–2011[d]	2002–2011[d]	2002–2011[d]	2005–2011[d]	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2011	2002–2011[d]
अति उच्च मानव विकास														
1 नार्वे	..	95.2	99.0	110.0	73.8	..	503	498	500	91	85	90	..	0.5
2 ऑस्ट्रेलिया	..	92.2	104.0	129.0	75.9	..	515	514	527	99	94	101	67.3	..
3 यूनाइटेड स्टेट्स	..	94.5	102.0	96.0	94.8	..	500	487	502	97	91	98	62.8	6.9
4 नीदरलैंड	..	88.9	108.0	120.0	62.7	..	508	526	522	89	89	96	60.3	..
5 जर्मनी	..	96.5	102.0	103.0	..	..	497	513	520	95	98	101	65.6 [e]	4.4
6 न्यूज़ीलैंड	..	83.7	101.0	119.0	82.6	..	521	519	532	103	96	107	69.9	..
7 आयरलैंड	..	73.9	108.0	117.0	61.0	..	496	487	508	95	86	97	83.6	..
7 स्वीडन	..	85.0	100.0	100.0	70.8	..	497	494	495	99	94	100	61.6	1.0
9 स्विटज़रलैंड	..	95.8	102.0	95.0	51.5	..	501	534	517	93	99	96	..	..
10 जापान	..	81.1 [f]	103.0	102.0	59.0	..	520	529	539	100	94	100	54.6	0.0
11 कनाडा	..	100.0	99.0	101.0	60.0	..	524	527	529	90	88	90	75.4	..
12 कोरिआ गणराज्य	..	85.4 [f]	104.0	97.0	103.9	..	542	546	538	79	89	82	50.5	1.2
13 हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	..	72.3	102.0	83.0	59.7	95.6	533	555	549	84	95	87	49.6	0.5
13 आइसलैंड	..	91.3	99.0	107.0	74.1	..	500	507	496	96	91	95	..	2.5
15 डेनमार्क	..	99.4	99.0	117.0	74.4	..	495	503	499	84	87	92	64.5	0.5
16 इस्राइल	..	84.1	113.0	91.0	62.5	..	474	447	455	112	104	107	64.0	1.1
17 बेल्जियम	..	79.4	105.0	111.0	67.5	..	506	515	507	102	104	105	62.1	6.6
18 ऑस्ट्रिया	..	100.0	100.0	100.0	60.2	..	470	496	494	100	96	102	63.7	2.3
18 सिंगापुर	96.1 [g]	75.0	101.8	106.9	71.0	94.3	526	562	542	97	104	104	91.8	0.9
20 फ्रांस	..	78.4	111.0	113.0	54.5	..	496	497	498	106	101	103	58.5	..
21 फ़िनलैंड	..	100.0	99.0	108.0	91.6	..	536	541	554	86	82	89	81.9	0.5
21 स्लोवेनिया	99.7 [h]	95.6	98.0	97.0	86.9	..	483	501	512	91	95	94	72.6	0.5
23 स्पेन	97.7	66.4	107.0	119.0	73.2	..	481	483	488	88	91	87	59.0	0.5
24 लिख्टेन्स्टाइन	..	..	106.0	70.0	34.4	..	499	536	520	83	88	87	..	18.2
25 इटली	98.9 [h]	72.8	103.0	99.0	66.0	..	486	483	489	96	93	97	46.7	0.3
26 लक्ज़मबर्ग	..	77.9	100.0	98.0	10.5	..	472	489	484	104	98	104	64.8	..
26 यूनाइटेड किंगडम	..	99.7	106.0	102.0	58.5	..	494	492	514	95	87	99	76.9 [e]	..
28 चेक गणराज्य	..	99.8	106.0	90.0	60.7	..	478	493	500	92	93	97	71.4	0.4
29 यूनान	97.2 [h]	62.0	100.0	101.0	89.4	..	483	466	470	95	89	92	47.9	2.6
30 ब्रूनेई दारस्सलाम	95.2 [h]	63.8 [f]	108.0	110.0	17.2	87.1	..	..	..	..	..	..	..	3.9
31 साइप्रस	98.3 [h]	74.5	105.0	98.0	52.0	..	..	..	..	..	..	..	65.6	4.7
32 माल्टा	92.4	62.5	95.0	105.0	33.4	..	..	..	..	..	..	..	58.5	20.3
33 अंडोरा	..	49.4	84.0	87.0	11.2	100.0	..	..	..	..	..	..	..	..
33 एस्टोनिआ	99.8 [h]	94.5 [f]	99.0	104.0	62.7	..	501	512	528	83	81	84	49.5	1.6
35 स्लोवाकिआ	..	98.8	102.0	89.0	54.2	..	477	497	490	90	96	95	58.4	2.3
36 कतर	96.3	63.4	103.0	94.0	10.0	42.9	372	368	379	115	98	104	69.9	6.4
37 हंगरी	99.0 [i]	94.8 [f]	102.0	98.0	61.7	..	494	490	503	90	92	86	56.4	2.3
38 बारबाडोस	..	88.6 [f]	120.0	101.0	65.9	58.5	..	..	..	..	..	..	..	4.2
39 पोलैण्ड	99.5 [i]	80.0	97.0	97.0	70.5	..	500	495	508	89	88	87	60.8	2.4
40 चिली	98.6	74.0	106.0	88.0	59.2	..	449	421	447	83	80	81	44.0	2.6
41 लिथुएनिया	99.7 [h]	90.2	97.0	98.0	77.4	..	468	477	491	86	88	85	51.1	1.6
41 संयुक्त अरब अमीरात	90.0	64.3 [f]	104.0	92.0	22.5	100.0	459 [j]	453 [j]	466 [j]	107 [j]	99 [j]	106 [j]	80.6 [e]	3.3
43 पुर्तगाल	95.2 [i]	40.4	114.0	107.0	62.2	..	489	487	493	87	91	83	64.9	..
44 लातीविया	99.8 [h]	98.4	101.0	95.0	60.1	..	484	482	494	80	79	78	51.0	5.4
45 अर्जेंटीना	97.8 [h]	56.0 [f]	118.0	89.0	71.2	..	398	388	401	108	93	102	62.6	6.2
46 सेशेल्स	91.8	66.8	117.0	119.0	..	99.4	..	..	..	..	..	..	..	15.1
47 क्रोएशिया	98.8 [h]	64.4 [f]	93.0	95.0	49.2	..	476	460	486	88	88	85	63.7	1.0
उच्च मानव विकास														
48 बहरीन	91.9 [h]	78.0 [f]	107.0	103.0	..	..	..	..	..	..	..	..	80.5 [e]	1.8
49 बहामास	..	89.6	114.0	96.0	..	91.5	..	..	..	..	..	..	..	10.5
50 बेलारूस	99.6	..	100.0	96.0	83.0	99.8	..	..	..	..	..	..	55.4	0.3
51 उरुग्वे	98.1	49.8	113.0	90.0	63.3	..	426	427	427	99	91	97	55.8	4.8
52 मॉन्टीनेग्रो	98.4 [h]	98.2	107.0	104.0	47.6	..	408	403	401	93	85	87	62.1	..
52 पलाउ	..	..	101.0	96.0	37.9	..	..	..	..	..	..	..	..	..
54 कुवैत	93.9	48.9	106.0	101.0	21.9	100.0	..	..	..	..	..	..	61.2 [e]	4.0
55 रूसी गणराज्य	99.6 [h]	94.7 [f]	99.0	89.0	75.9	..	459	468	478	90	85	90	38.0	3.9
56 रोमानिया	97.7 [h]	86.8	96.0	95.0	63.8	..	424	427	428	90	79	79	45.3	4.9

	शैक्षिक उपलब्धि		सकल नामांकन अनुपात			शैक्षिक गुणवत्ता								
						पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक	15 वर्षीय विद्यार्थियों का प्रदर्शन							
	वयस्क साक्षरता दर	कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त जनसंख्या	प्राथमिक	सेकेण्डरी	उच्च		माध्य प्राप्तांक			माध्य से विचलन			शैक्षिक गुणवत्ता से संतुष्टि	प्राथमिक स्कूल छोड़ने की दर
	(% उम्र 15 और अधिक)	(% उम्र 25 और अधिक)	(%)			(%)	वाचन[a]	गणित[b]	विज्ञान[c]	वाचन	गणित	विज्ञान	(% संतुष्ट)	(प्राथमिक स्कूल समूह का %)
मा.वि.सू. श्रेणी	2005–2010[d]	2010	2002–2011[d]	2002–2011[d]	2002–2011[d]	2005–2011[d]	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2011	2002–2011[d]
57 बुल्गारिया	98.4	92.6	103.0	88.0	53.0	..	429	428	439	113	99	106	35.4	6.2
57 सऊदी अरब	86.6 [h]	54.6 [f]	106.0	101.0	36.8	91.5	..	..	..	..	..	..	61.8 [e]	6.7
59 क्यूबा	99.8 [h]	77.1 [f]	103.0	89.0	95.2	100.0	..	..	..	..	..	..	..	3.8
59 पनामा	94.1	62.1 [f]	108.0	74.0	44.6	91.6	371	360	376	99	81	90	73.2	6.2
61 मैक्सिको	93.1	53.9	115.0	87.0	27.0	95.6	425	419	416	85	79	77	64.5	6.0
62 कोस्टा रिका	96.2 [h]	53.6 [f]	110.0	100.0	25.6	89.5	..	..	..	..	..	..	80.0	11.2
63 ग्रेनाडा	..	..	103.0	108.0	52.8	65.3	..	..	..	..	..	..	..	..
64 लीबिया	89.2 [i]	49.6 [f]	114.0	110.0	54.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
64 मलेशिया	93.1	69.4 [f]	96.0	68.0	40.2	..	..	..	..	..	..	..	91.4	2.3
64 सर्बिया	99.3 [h]	85.1	96.0	91.0	49.1	94.2	442	442	443	84	91	84	58.0	1.4
67 एंटिगुआ और बरबूडा	99.0	..	102.0	105.0	16.4	54.8	..	..	..	..	..	..	..	..
67 त्रिनिडाड टोबैगो	98.8 [h]	59.3	105.0	90.0	11.5	88.0	416	414	410	113	99	108	83.3	10.6
69 कज़ाकिस्तान	99.7 [h]	99.3	111.0	100.0	40.8	..	390	405	400	91	83	87	49.9	0.2
70 अल्बानिआ	95.9	81.7	87.0	89.0	18.4	..	385	377	391	100	91	89	54.7	4.8
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	95.5	52.4	103.0	83.0	78.1	88.4	..	..	..	..	..	..	81.2	7.9
72 डोमिनिका	..	26.5	112.0	98.0	3.6	60.8	..	..	..	..	..	..	..	11.9
72 जॉर्जिआ	99.7 [h]	91.0	109.0	86.0	28.2	94.6	..	..	..	..	..	..	65.7	3.8
72 लेबनान	89.6	54.2	105.0	81.0	54.0	..	..	..	..	..	..	..	67.6 [e]	8.2
72 सेंट किट्स एवं नेविस	..	..	93.0	97.0	18.2	61.6	..	..	..	..	..	..	..	26.5
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	85.0	66.0	108.0	84.0	42.8	98.4	..	..	..	..	..	..	67.9	5.7
77 पेरु	89.6	52.9	109.0	92.0	35.0	..	370	365	369	98	90	89	49.1	..
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	97.3 [h]	78.6	89.0	83.0	40.4	..	..	..	..	..	..	..	61.6	2.5
78 यूक्रेन	99.7 [h]	93.5 [f]	99.0	96.0	79.5	99.9	..	..	..	..	..	..	50.1	2.3
80 मॉरिशस	88.5 [h]	49.0 [f]	99.0	89.0	24.9	100.0	..	..	..	..	..	..	83.5	2.2
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	97.9 [h]	..	88.0	90.0	35.9	..	..	..	..	..	..	..	67.9	26.8
82 अज़रबैजान	99.8	92.7	94.0	85.0	19.3	100.0	362	431	373	76	64	74	53.0	3.6
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	..	..	105.0	107.0	..	84.1	..	..	..	..	..	..	..	..
84 ओमान	86.6	53.9	105.0	100.0	24.5	100.0	..	..	..	..	..	..	70.0 [e]	2.7
85 ब्राज़ील	90.3	49.5	127.0	101.0	36.1	..	412	386	405	94	81	84	53.7	24.3
85 जमैका	86.6 [i]	72.6 [f]	89.0	93.0	29.0	..	..	..	..	..	..	..	73.7	4.8
87 अर्मेनिआ	99.6 [h]	94.4 [f]	103.0	92.0	51.5	77.5	..	..	..	..	..	..	45.7	2.3
88 सेंट लूसिआ	..	..	94.0	96.0	11.3	86.8	..	..	..	..	..	..	..	7.9
89 इक्वाडोर	91.9	36.6	114.0	80.0	39.8	82.6	..	..	..	..	..	..	74.5	19.4
90 तुर्की	90.8	34.5	102.0	78.0	45.8	..	464	445	454	82	93	81	54.3	8.2
91 कोलम्बिया	93.4	43.1	115.0	96.0	39.1	100.0	413	381	402	87	75	81	71.7	15.5
92 श्रीलंका	91.2	73.9	99.0	87.0	15.5	..	..	..	..	..	..	..	77.9	1.4
93 अल्जीरिया	72.6	24.1	110.0	95.0	30.8	99.3	..	..	..	..	..	..	67.1 [e]	5.0
94 ट्यूनीशिया	77.6	37.0	109.0	90.0	34.4	..	404	371	401	85	78	81	54.8 [e]	5.3
मध्यम मानव विकास														
95 टोंगा	99.0	74.0 [f]	110.0	101.0	6.5	..	..	..	..	..	..	..	..	9.6
96 बेलीज	..	34.0 [f]	121.0	75.0	21.5	45.2	..	..	..	..	..	..	..	9.7
96 डोमीनिकन गणराज्य	89.5	42.5	108.0	76.0	34.0	84.9	..	..	..	..	..	..	68.9	..
96 फ़िजी	..	57.8	105.0	86.0	16.1	97.8	..	..	..	..	..	..	..	9.1
96 सामोआ	98.8 [h]	62.1	108.0	85.0	7.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..
100 जॉर्डन	92.6	73.3	97.0	91.0	41.8	..	405	387	415	91	83	89	63.3 [e]	6.6
101 चीन	94.3 [h]	62.7 [f]	111.0	81.0	25.9	..	556 [k]	600 [k]	575 [k]	80 [k]	103 [k]	82 [k]	62.6	..
102 तुर्कमेनिस्तान	99.6 [h]	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	74.3	..
103 थाइलैंड	93.5	32.2	91.0	79.0	47.7	..	421	419	425	72	79	80	88.7	..
104 माल्दीव	98.4	25.4	109.0	71.0	..	77.0	..	..	..	..	..	..	..	..
105 सूरीनाम	94.7	43.7	113.0	75.0	12.1	100.0	..	..	..	..	..	..	..	9.7
106 गैबन	88.4 [i]	44.4 [f]	182.0	53.0	..	..	..	..	..	..	..	..	46.5	..
107 अल सल्वाडोर	84.5	37.5	114.0	65.0	23.4	92.7	..	..	..	..	..	..	72.7	13.5
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	91.2	44.5	105.0	80.0	38.6	..	..	..	..	..	..	..	68.2	16.3
108 मंगोलिया	97.4 [h]	82.4 [f]	100.0	93.0	53.3	97.6	..	..	..	..	..	..	57.9	5.9
110 फ़लस्तीन राज्य	94.9	52.1	91.0	86.0	50.2	100.0	..	..	..	..	..	..	63.5 [e]	1.5
111 पराग्वे	93.9	36.9	100.0	67.0	36.6	..	..	..	..	..	..	..	66.9	21.9
112 मिस्र	72.0	51.2 [f]	106.0	85.0	30.4	..	..	..	..	..	..	..	42.6 [e]	..
113 माल्डोवा गणराज्य	98.5 [h]	93.3	94.0	88.0	38.1	..	..	..	..	..	..	..	53.7	4.8

मा.वि.सू. श्रेणी		शैक्षिक उपलब्धि		सकल नामांकन अनुपात			शैक्षिक गुणवत्ता								
							पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक	15 वर्षीय विद्यार्थियों का प्रदर्शन							
		वयस्क साक्षरता दर	कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त जनसंख्या	प्राथमिक	सेकेण्डरी	उच्च		माध्य प्राप्तांक			माध्य से विचलन			शैक्षिक गुणवत्ता से संतुष्टि	प्राथमिक स्कूल छोड़ने की दर
		(% उम्र 15 और अधिक)	(% उम्र 25 और अधिक)	(%)			(%)	वाचन[a]	गणित[b]	विज्ञान[c]	वाचन	गणित	विज्ञान	(% संतुष्ट)	(प्राथमिक स्कूल समूह का %)
मा.वि.सू. श्रेणी		2005–2010[d]	2010	2002–2011[d]	2002–2011[d]	2002–2011[d]	2005–2011[d]	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2011	2002–2011[d]
114	फ़िलीपीन्स	95.4	64.8 [f]	106.0	85.0	28.9	..	..	..	..	..	..	..	79.2	24.2
114	उज्बेकिस्तान	99.4 [h]	..	95.0	106.0	8.9	100.0	..	..	..	..	..	..	85.0	1.9
116	सीरियाई अरब गणराज्य	83.4 [h]	32.8	118.0	72.0	..	..	..	..	..	..	..	..	59.1 [e]	5.4
117	फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	..	..	110.0	83.0	14.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
118	गुयाना	..	55.6 [f]	85.0	91.0	11.9	66.1	..	..	..	..	..	..	..	16.5
119	बोत्स्वाना	84.5	75.5 [f]	108.0	80.0	7.4	97.4	..	..	..	..	..	..	66.4	13.2
120	होण्डुरास	84.8	19.8	116.0	73.0	18.8	36.4	..	..	..	..	..	..	63.6	23.8
121	इण्डोनेशिया	92.6	41.4	118.0	77.0	23.1	..	402	371	383	66	70	69	80.1	20.0
121	किरिबाती	..	..	113.0	86.0	..	85.4	..	..	..	..	..	..	..	21.1
121	दक्षिण अफ़्रीका	88.7	70.4	102.0	94.0	..	87.4	..	..	..	..	..	..	69.3	23.0
124	वनुआतू	82.6	..	117.0	55.0	4.7	100.0	..	..	..	..	..	..	..	28.5
125	किर्गिस्तान	99.2	81.1 [f]	100.0	84.0	48.8	68.4	314	331	330	99	81	91	47.7	2.4
125	ताजिकिस्तान	99.7 [h]	89.7 [f]	102.0	87.0	19.7	92.9	..	..	..	..	..	..	76.4	1.1
127	वियतनाम	93.2	26.3 [f]	106.0	77.0	22.3	98.3	..	..	..	..	..	..	80.4	7.9
128	नामीबिया	88.8 [h]	33.5 [f]	107.0	64.0	9.0	95.6	..	..	..	..	..	..	..	17.4
129	निकारागुआ	78.0	37.6 [f]	118.0	69.0	18.0	74.9	..	..	..	..	..	..	81.0	51.6
130	मोरक्को	56.1	28.0 [f]	114.0	56.0	13.2	100.0	..	..	..	..	..	..	41.6 [e]	9.5
131	इराक	78.2 [h]	32.4 [f]	105.0	53.0	16.4	..	..	..	..	..	..	..	38.0	33.3
132	केप वर्दे	84.3 [h]	..	110.0	88.0	17.8	90.0	..	..	..	..	..	..	..	14.3
133	ग्वाटेमाला	75.2 [h]	14.8	116.0	59.0	17.8	..	..	..	..	..	..	..	71.8	35.2
134	टिमोर लेस्ट	58.3	..	117.0	56.0	16.7	..	..	..	..	..	..	..	..	33.4
135	घाना	67.3 [h]	53.8 [f]	107.0	58.0	8.8	50.6	..	..	..	..	..	..	57.2	27.8
136	इक्वेटोरिअल गिनी	93.9 [h]	..	87.0	27.0	3.3	45.3	..	..	..	..	..	..	..	38.1
136	भारत	62.8	38.7 [f]	118.0	60.0	16.2	..	..	..	..	..	..	..	74.8	34.2
138	कम्बोडिया	77.6	15.7 [f]	127.0	46.0	7.8	99.1	..	..	..	..	..	..	94.1	45.5
138	लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	72.7	29.7 [f]	121.0	45.0	13.4	96.9	..	..	..	..	..	..	78.9	33.0
140	भूटान	52.8	34.4	111.0	70.0	8.8	91.5	..	..	..	..	..	..	..	9.0
141	स्वाज़ीलैण्ड	87.4 [h]	48.1 [f]	116.0	58.0	4.4	73.1	..	..	..	..	..	..	77.8	16.1
निम्न मानव विकास															
142	कौंगो	..	46.2 [f]	115.0	45.0	5.5	86.8	..	..	..	..	..	..	46.6	29.7
143	सॉलोमन द्वीपसमूह	..	..	109.0	36.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
144	साओ टोम एवं प्रिन्साइप	89.2 [h]	..	134.0	59.0	4.5	40.5	..	..	..	..	..	..	..	32.0
145	केन्या	87.4 [h]	41.9	113.0	60.0	4.0	96.8	..	..	..	..	..	..	59.6	27.2
146	बांग्लादेश	56.8 [h]	35.1 [f]	..	..	10.6	58.4	..	..	..	..	..	..	81.6	33.8
146	पाकिस्तान	54.9	31.2	95.0	34.0	5.4	84.2	..	..	..	..	..	..	60.5	38.5
148	अंगोला	70.1 [h]	..	124.0	31.0	3.7	..	..	..	..	..	..	..	42.0	68.1
149	म्याँमार	92.3 [h]	17.8 [f]	126.0	54.0	11.0	99.9	..	..	..	..	..	..	..	25.2
150	कैमरून	70.7	27.9 [f]	120.0	42.0	11.5	57.1	..	..	..	..	..	..	62.1	33.8
151	मैडागास्कर	64.5	..	149.0	31.0	3.7	90.4	..	..	..	..	..	..	45.8	65.4
152	तंज़ानिया गणराज्य	73.2 [h]	7.4 [f]	102.0	..	2.1	94.5	..	..	..	..	..	..	44.8	18.6
153	नाइजीरिया	61.3 [h]	..	83.0	44.0	10.3	66.1	..	..	..	..	..	..	47.4	20.1
154	सेनेगल	49.7	7.5 [f]	87.0	37.0	7.9	47.9	..	..	..	..	..	..	38.0	40.4
155	मॉरिटानिया	58.0 [h]	14.2 [f]	102.0	24.0	4.4	100.0	..	..	..	..	..	..	39.2 [e]	29.3
156	पापुआ न्यू गिनी	60.6 [h]	10.5 [f]	60.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
157	नेपाल	60.3 [h]	28.3 [f]	115.0	44.0	5.6	80.7	..	..	..	..	..	..	73.0	38.3
158	लेसोथो	89.6 [h]	20.9	103.0	46.0	3.5	63.4	..	..	..	..	..	..	43.2	30.7
159	टोगो	57.1	29.8 [f]	140.0	46.0	5.9	76.7	..	..	..	..	..	..	45.4	40.6
160	यमन	63.9	16.0 [f]	87.0	44.0	10.2	..	..	..	..	..	..	..	37.2 [e]	40.5
161	हैती	48.7	29.1 [f]	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	39.9	..
161	युगाण्डा	73.2	23.4	121.0	28.0	4.2	89.4	..	..	..	..	..	..	48.8	68.2
163	ज़ाम्बिया	71.2	35.0 [f]	115.0	..	2.4	..	..	..	..	..	..	..	68.0	46.9
164	जिबूती	..	..	59.0	36.0	4.9	100.0	..	..	..	..	..	..	66.6	35.7
165	गैम्बिया	50.0 [h]	24.0 [f]	83.0	54.0	4.1	..	..	..	..	..	..	..	..	38.9
166	बेनिन	42.4 [h]	18.4 [f]	126.0	37.0	6.0	42.6	..	..	..	..	..	..	60.7	35.7
167	रवाण्डा	71.1 [h]	7.7 [f]	143.0	32.0	5.5	91.5	..	..	..	..	..	..	83.9	63.0
168	आइवरी कोस्ट	56.2 [h]	22.1 [f]	88.0	27.0	8.9	100.0	..	..	..	..	..	..	..	39.2
169	कोमोरॉस	74.9 [h]	..	104.0	46.0	7.9	57.4	..	..	..	..	..	..	46.0 [e]	25.9
170	मलावी	74.8 [h]	15.3 [f]	135.0	32.0	0.7	95.9	..	..	..	..	..	..	65.2	47.2

	शैक्षिक उपलब्धि		सकल नामांकन अनुपात			शैक्षिक गुणवत्ता								
						पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक	15 वर्षीय विद्यार्थियों का प्रदर्शन							
	वयस्क साक्षरता दर	कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त जनसंख्या	प्राथमिक	सेकेण्डरी	उच्च		माध्य प्राप्तांक			माध्य से विचलन			शैक्षिक गुणवत्ता से संतुष्टि	प्राथमिक स्कूल छोड़ने की दर
	(% उम्र 15 और अधिक)	(% उम्र 25 और अधिक)		(%)		(%)	वाचन[a]	गणित[b]	विज्ञान[c]	वाचन	गणित	विज्ञान	(% संतुष्ट)	(प्राथमिक स्कूल समूह का %)
मा.वि.सू. श्रेणी	2005–2010[d]	2010	2002–2011[d]	2002–2011[d]	2002–2011[d]	2005–2011[d]	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2011	2002–2011[d]
171 सूडान	71.1[h]	15.5[f]	73.0	39.0	6.1	59.7	..	..	..	..	..	..	43.0	9.1
172 ज़िम्बाब्वे	92.2[h]	55.4[f]	..	..	6.2	..	..	..	..	..	..	..	66.4	..
173 इथियोपिया	39.0	..	102.0	36.0	5.5	39.4	..	..	..	..	..	..	..	52.5
174 लाइबेरिया	60.8[i]	27.3[f]	96.0	..	19.1	40.2	..	..	..	..	..	..	49.6	54.4
175 अफ़गानिस्तान	..	20.3[f]	97.0	46.0	3.3	..	..	..	..	..	..	..	58.5	..
176 गिनी बिसाउ	54.2[h]	..	123.0	36.0	2.7	38.9	..	..	..	..	..	..	..	..
177 सिएरा लिओन	42.1	14.8	125.0	..	2.1	48.0	..	..	..	..	..	..	35.3	..
178 बुरुण्डी	67.2[h]	7.1[f]	156.0	25.0	3.2	91.2	..	..	..	..	..	..	70.9	43.8
178 गिनी	41.0[h]	..	94.0	38.0	9.5	65.2	..	..	..	..	..	..	39.0	34.3
180 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य	56.0[h]	17.9[f]	93.0	13.0	2.6	..	..	..	..	..	..	..	40.7	53.1
181 इरिट्रिया	67.8[h]	..	45.0	32.0	2.0	93.8	..	..	..	..	..	..	..	31.0
182 माली	31.1	10.3	82.0	39.0	5.8	50.0	..	..	..	..	..	..	34.6	24.5
183 बुर्किना फ़ासो	28.7	2.0	79.0	23.0	3.3	85.7	..	..	..	..	..	..	53.0	36.4
184 चाड	34.5[h]	..	90.0	26.0	2.2	45.3	..	..	..	..	..	..	60.1	76.7
185 मोज़ाम्बीक	56.1[h]	3.6[f]	115.0	25.0	1.5	75.9	..	..	..	..	..	..	63.2	64.6
186 काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य	66.8[h]	23.2[f]	94.0	38.0	6.2	91.7	..	..	..	..	..	..	39.3	45.2
186 नाइजर	28.7	5.1[f]	71.0	13.0	1.5	96.4	..	..	..	..	..	..	55.3	30.7
अन्य देश अथवा अंचल														
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	100.0	..	..	..	..	..	539	..	..	..	..	..	..	..
मार्शल द्वीप समूह	..	..	102.0	99.0	16.2	..	..	..	..	..	..	..	..	16.5
मोनाको	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
नाउरू	..	..	93.0	63.0	..	74.2	..	..	..	..	..	..	..	..
सैन मैरीनो	..	..	94.0	97.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
सोमालिया	..	..	32.0	8.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
तुवालू	..	..	100.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह														
अति उच्च मानव विकास	..	85.9	104.2	100.4	75.8	..	—	—	—	—	—	—	61.3	3.8
उच्च मानव विकास	92.7	64.2	110.5	91.0	48.7	..	—	—	—	—	—	—	58.0	7.3
मध्यम मानव विकास	82.3	50.5	113.4	70.7	22.1	..	—	—	—	—	—	—	69.2	18.8
निम्न मानव विकास	60.8	25.2	98.2	37.4	6.8	73.8	—	—	—	—	—	—	56.5	41.7
क्षेत्र														
अरब देश	74.5	38.4	97.7	71.1	24.1	..	—	—	—	—	—	—	50.0	9.9
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	93.8	..	111.0	78.8	26.1	..	—	—	—	—	—	—	..	..
यूरोप एवं मध्य एशिया	98.1	83.5	99.9	91.2	57.5	..	—	—	—	—	—	—	51.8	4.2
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	91.3	50.4	115.9	90.9	42.5	92.3	—	—	—	—	—	—	..	14.3
दक्षिण एशिया	62.8	39.2	113.6	57.6	15.7	77.2	—	—	—	—	—	—	73.3	21.4
सब-सहारा अफ़्रीका	63.0	29.7	100.3	40.3	6.2	73.9	—	—	—	—	—	—	52.0	37.8
न्यूनतम विकसित देश	60.7	..	101.8	36.0	6.6	71.9	—	—	—	—	—	—	58.2	40.9
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	..	..	97.0	77.0	45.2	89.4	—	—	—	—	—	—	..	..
विश्व	**81.3**	**57.7**	**107.9**	**71.2**	**28.7**	**..**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**64.2**	**18.0**

नोट

a वाचन के लिए ओ.ई.सी.डी. देशों का औसत प्राप्तांक 493 है।

b गणित के लिए ओ.ई.सी.डी. देशों का औसत प्राप्तांक 495 है।

c विज्ञान के लिए ओ.ई.सी.डी. देशों का औसत प्राप्तांक 501 है।

d आँकड़े निर्दिष्ट अवधि में अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए हैं।

e इस अवधि के दौरान दो या अधिक सर्वेक्षणों का औसत।

f बर्रो और ली (2011) के 2010 के अनुमान।

g 2011 के संदर्भ में।

h सांख्यिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थान (यू.आई.एस) के अनुमान वैश्विक आयु-विशिष्ट साक्षरता अनुमान मॉडल से व्युत्पन्न हैं, जो 2000 के बाद के राष्ट्रीय आँकड़ों पर आधारित है।

i यू.आई.एस. के अनुमान वैश्विक आयु-विशिष्ट साक्षरता अनुमान मॉडल से व्युत्पन्न हैं जो 2000 से पहले के राष्ट्रीय आँकड़ों पर आधारित है।

j केवल दुबई के संदर्भ में।

k केवल शंघाई के संदर्भ में।

परिभाषाएँ

वयस्क साक्षरता दर: 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी में उन लोगों का प्रतिशत जो समझ के साथ अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन के बारे में एक संक्षिप्त और साधारण ब्यौरा पढ़ और लिख सकें।

कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त जनसंख्या: 25 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी में उन लोगों का प्रतिशत जिन्हें कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा मिली हो।

सकल नामांकन अनुपात: उम्र की बंदिश से मुक्त, शिक्षा के किसी एक स्तर (प्राथमिक, सेकेण्डरी या उच्च) में हुए कुल नामांकन, उसी शैक्षिक स्तर की अधिकृत स्कूली उम्र की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित।

पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक: उन प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों का प्रतिशत जिन्होंने (सेवाकाल से पहले या सेवाकाल में) प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए ज़रूरी न्यूनतम व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

वाचन, गणित और विज्ञान में प्रदर्शन: समाज में सहभागिता के लिए अनिवार्य इन विषयों में 15 वर्षीय विद्यार्थियों के कौशल और ज्ञान के परीक्षण में मिले अंक।

माध्य से विचलन: औसत प्राप्तांक की तुलना में वाचन, गणित और विज्ञान में प्राप्तांकों का अंतर।

शैक्षिक गुणवत्ता से संतुष्टि: गैलप विश्व सर्वेक्षण के प्रश्न, 'क्या आप शैक्षिक प्रणाली से संतुष्ट या असंतुष्ट हैं?' पर उन प्रतिभागियों का प्रतिशत जिनका उत्तर 'संतुष्ट' था।

प्राथमिक स्कूल छोड़ने की दर: किसी खास समूह में ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत जो प्राथमिक विद्यालय में दाखिल तो हुए लेकिन प्राथमिक शिक्षा के अंतिम दर्जे तक पहुँचने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया। इसकी गणना प्राथमिक शिक्षा के अंतिम दर्जे तक पहुँच पाए विद्यार्थियों की दर को 100 से घटाकर मिलती है और मान कर चलती है कि उस वर्ग के पूरे जीवन काल में प्रवाह दर अपरिवर्तित रहती है और शाला-त्यागी बच्चे दोबारा स्कूल में दाखिल नहीं होंगे।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1,2-6 और 14— यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (2012)।
कॉलम 7-12— ओ.ई.सी.डी. (2010)।

कॉलम 13— गैलप (2012)।

सामाजिक एकीकरण

मा.वि.सू. श्रेणी	रोज़गार, अ-रक्षितता और समता				व्यक्तिगत खुशहाली की धारणा			समाज की धारणाएँ			मानव सुरक्षा			
	रोज़गार व आबादी का अनुपात	युवा बेरोज़गारी	बाल श्रम	असमानता के कारण मानव विकास सूचकांक में कुल हानि	कुल मिलाकर जीवन से संतुष्टि	चयन की आज़ादी को लेकर संतुष्टि	रोज़गार से संतुष्टि	लोगों में भरोसा	समुदाय से संतुष्टि[a]	राष्ट्रीय सरकार पर भरोसा	सुरक्षा की धारणा	हत्या की दर	आत्महत्या की दर (प्रति 100,000 व्यक्ति)	
	(% उम्र 25 और अधिक)	(% उम्र 15-24)	(% उम्र 5-14)	(%)	(0, न्यूनतम संतुष्ट, 10, सर्वाधिक संतुष्ट)	(% संतुष्ट)		("हाँ" उत्तर देने वालों का %)			("हाँ" उत्तर देने वालों का %)	(प्रति 100,000 व्यक्ति)	महिला	पुरुष
	2011	2005–2011[b]	2001–2010[b]	2012	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2011	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2004–2011[b]	2001–2010[b]	2001–2010[b]
अति उच्च मानव विकास														
1 नार्वे	65.9	9.3	..	6.4	7.6	93.0	..	..	92.8	54.0	81.0	0.6	6.5	17.3
2 ऑस्ट्रेलिया	62.4	11.9	..	7.9	7.4	94.0	87.4	..	91.9	53.0	64.0	1.0	3.6	12.8
3 यूनाइटेड स्टेट्स	61.2	18.7	..	12.4	7.1	85.0	87.4	37.0	83.8	38.0	75.0	4.2	4.5	17.7
4 नीदरलैंड	61.5	7.8	..	6.9	7.6	91.0	94.5	46.0	94.5	60.0	79.0	1.1	5.5	13.1
5 जर्मनी	57.2	9.1	..	6.9	6.7	89.0	89.0	31.0	93.9	43.0	78.0	0.8	6.0	17.9
6 न्यूज़ीलैंड	66.2	18.2	..	..	7.2	93.0	89.0	..	88.1	64.0	67.0	0.9	5.5	18.1
7 आयरलैंड	55.8	35.3	..	7.2	7.0	95.0	89.1	30.0	93.6	53.0	70.0	1.2	4.7	19.0
7 स्वीडन	62.5	23.8	..	6.2	7.5	93.0	91.8	55.0	92.5	64.0	78.0	1.0	6.8	18.7
9 स्विटज़रलैंड	65.5	7.9	..	7.0	7.5	88.0	..	44.0	93.5	58.0	76.0	0.7	11.4	24.8
10 जापान	59.7	8.9	..	..	6.1	78.0	76.2	33.0	84.6	23.0	69.0	0.4	13.2	36.2
11 कनाडा	62.7	15.9	..	8.7	7.4	94.0	91.5	42.0	91.7	55.0	79.0	1.6	5.4	17.3
12 कोरिआ गणराज्य	64.8	12.1	..	16.5	6.9	66.0	71.1	26.0	78.5	28.0	54.0	2.6	22.1	39.9
13 हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	61.2	11.0	..	..	5.5	89.0	84.4	29.0	84.1	58.0	88.0	0.2	10.7	19.0
13 आइसलैंड	71.9	18.4	..	6.4	6.9	86.0	..	..	81.8	24.0	77.0	0.3	7.0	16.5
15 डेनमार्क	59.8	15.7	..	6.2	7.8	93.0	94.0	60.0	93.4	47.0	79.0	0.9	6.4	17.5
16 इस्राइल	60.9	11.8	..	12.3	7.4	52.0	84.0	26.0	82.3	45.0	59.0	2.1	1.5	7.0
17 बेल्जियम	54.0	18.7	..	8.0	6.9	86.0	90.3	30.0	91.2	29.0	64.0	1.7	10.3	28.8
18 ऑस्ट्रिया	58.6	8.8	..	6.6	7.5	92.0	94.1	29.0	94.4	41.0	82.0	0.6	7.1	23.8
18 सिंगापुर	69.2	6.7	..	..	6.5	82.0	86.5	33.0	92.9	83.0	89.0	0.3	7.7	12.9
20 फ्रांस	54.4	23.2	..	9.0	7.0	90.0	87.4	20.0	89.4	38.0	63.0	1.1	8.5	24.7
21 फ़िनलैंड	57.8	19.3	..	6.0	7.4	93.0	87.7	58.0	91.2	57.0	78.0	2.2	10.0	29.0
21 स्लोवेनिया	57.2	16.8	..	5.8	6.0	90.0	85.0	15.0	90.6	18.0	84.0	0.7	9.4	34.6
23 स्पेन	49.5	48.2	..	10.1	6.5	80.0	85.7	22.0	87.8	31.0	68.0	0.8	3.4	11.9
24 लिख्टेन्स्टाइन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2.8	..	..
25 इटली	47.5	32.0	..	11.9	6.1	55.0	81.0	20.0	75.7	26.0	52.0	0.9	2.8	10.0
26 लवज़मबर्ग	59.9	20.8	..	7.2	7.1	95.0	93.5	26.0	94.7	77.0	77.0	2.5	3.2	16.1
26 यूनाइटेड किंगडम	58.8	22.0	..	8.3	6.9	90.0	88.3	35.0	86.6	49.0	70.0	1.2	3.0	10.9
28 चेक गणराज्य	59.7	18.1	..	5.4	6.3	73.0	79.9	24.0	88.1	21.0	59.0	1.7	4.4	23.9
29 यूनान	49.1	51.5	..	11.5	5.4	52.0	70.3	16.0	74.2	18.0	53.0	1.5	1.0	6.0
30 ब्रूनेई दारस्सलाम	69.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.5	..	..
31 साइप्रस	66.2	23.1	..	11.5	6.7	73.0	87.1	11.0	88.7	40.0	70.0	1.7	1.7	7.4
32 माल्टा	48.3	14.0	..	8.2	6.2	86.0	86.0	16.0	84.1	49.0	64.0	1.0	1.0	5.9
33 अंडोरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1.3	..	..
33 एस्टोनिआ	58.4	23.8	..	9.0	5.5	69.0	81.1	33.0	86.3	42.0	56.0	5.2	7.3	30.6
35 स्लोवाकिआ	57.5	33.6	..	6.3	5.9	68.0	78.6	21.0	86.6	28.0	59.0	1.5	3.4	22.3
36 कतर	89.9	8.9	..	..	6.6	90.0	86.0	23.0	90.4	89.0	87.0	0.9	..	..
37 हंगरी	49.6	27.2	..	7.4	4.9	61.0	80.5	13.0	74.2	36.0	57.0	1.3	10.6	40.0
38 बारबाडोस	66.9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11.3	0.0	7.3
39 पोलैण्ड	55.1	28.9	..	9.9	5.6	80.0	77.0	25.0	88.2	27.0	59.0	1.1	4.1	26.4
40 चिली	62.9	21.1	3.0	19.0	6.6	77.0	78.2	15.0	78.4	48.0	46.0	3.2	4.2	18.2
41 लिथुएनिया	55.6	34.6	..	11.0	5.4	52.0	78.2	25.0	84.2	18.0	39.0	6.6	10.4	61.3
41 संयुक्त अरब अमीरात	83.4	21.8	..	..	7.2	87.0	88.7	18.0	93.8	..	90.0	0.8	..	..
43 पुर्तगाल	58.0	31.7	3.0	10.8	5.2	79.0	88.7	27.0	90.1	21.0	63.0	1.2	4.0	15.6
44 लातीविया	55.1	29.6	..	10.9	5.0	54.0	80.6	13.0	84.8	11.0	48.0	3.1	8.2	40.0
45 अर्जेंटीना	62.6	22.2	7.0	19.5	6.4	79.0	80.7	23.0	89.0	61.0	50.0	3.4	3.0	12.6
46 सेशेल्स	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8.3	0.0	8.9
47 क्रोएशिया	49.1	36.8	..	15.1	5.6	46.0	..	16.0	66.0	..	64.0	1.4	7.5	28.9
उच्च मानव विकास														
48 बहरीन	72.2	..	5.0	..	4.5	73.0	79.3	11.0	88.2	..	60.0	0.6	3.5	4.0
49 बहामास	71.9	21.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27.4	0.6	1.9
50 बेलारूस	54.4	..	5.0	8.3	5.2	57.0	65.7	34.0	76.6	59.0	60.0	4.9	8.8	48.7
51 उरुग्वे	65.9	21.7	8.0	16.4	6.1	78.0	78.0	27.0	83.8	73.0	48.0	5.9	6.3	26.0
52 मॉन्टीनेग्रो	..	40.0	10.0	7.4	5.5	50.0	..	21.0	68.3	..	78.0	3.5	..	..
52 पलाउ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.0	..	..
54 कुवैत	75.5	11.8	..	..	6.6	75.0	84.9	11.0	81.5	..	..	2.2	1.7	1.9
55 रूसी गणराज्य	62.8	15.7	..	..	5.4	54.0	67.9	24.0	69.4	48.0	40.0	10.2	9.5	53.9
56 रोमानिया	57.3	23.8	1.0	12.6	5.0	60.0	69.5	15.0	78.1	12.0	55.0	2.0	3.5	21.0

	रोज़गार, अ-रक्षितता और समता				व्यक्तिगत खुशहाली की धारणा			समाज की धारणाएँ			मानव सुरक्षा			
	रोज़गार व आबादी का अनुपात	युवा बेरोज़गारी	बाल श्रम	असमानता के कारण मानव विकास सूचकांक में कुल हानि	कुल मिलाकर जीवन से संतुष्टि	चयन की आज़ादी को लेकर संतुष्टि	रोज़गार से संतुष्टि	लोगों में भरोसा	समुदाय से संतुष्टि[a]	राष्ट्रीय सरकार पर भरोसा	सुरक्षा की धारणा	हत्या की दर	आत्महत्या की दर (प्रति 100,000 व्यक्ति)	
	(% उम्र 25 और अधिक)	(% उम्र 15-24)	(% उम्र 5-14)	(%)	(0, न्यूनतम संतुष्ट, 10, सर्वाधिक संतुष्ट)	(% संतुष्ट)		("हाँ" उत्तर देने वालों का %)			("हाँ" उत्तर देने वालों का %)	(प्रति 100,000 व्यक्ति)	महिला	पुरुष
मा.वि.सू. श्रेणी	2011	2005–2011[b]	2001–2010[b]	2012	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2011	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2004–2011[b]	2001–2010[b]	2001–2010[b]
57 बुल्गारिया	52.0	27.6	..	9.9	3.9	60.0	73.3	20.0	74.0	27.0	52.0	2.0	6.2	18.8
57 सऊदी अरब	59.7	45.8	..	..	6.7	57.0	81.8	36.0	85.9	..	77.0	1.0	..	..
59 क्यूबा	58.7	3.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.0	5.5	19.0
59 पनामा	68.3	14.6	7.0	24.6	7.3	80.0	88.5	21.0	86.6	46.0	47.0	21.6	1.9	9.0
61 मैक्सिको	63.9	10.4	5.0	23.4	6.8	80.0	74.4	29.0	73.7	38.0	42.0	22.7	1.5	7.0
62 कोस्टा रिका	65.6	21.6	5.0	21.5	7.3	92.0	87.4	14.0	82.5	32.0	41.0	11.3	1.9	10.2
63 ग्रेनाडा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11.5	0.0	0.0
64 लीबिया	53.6	..	..	..	4.9	41.0	64.3	..	68.7	..	91.0	2.9	..	..
64 मलेशिया	66.6	11.3	..	..	5.8	79.0	85.6	14.0	87.3	79.0	46.0	2.3	..	..
64 सर्बिया	..	46.1	4.0	9.5	4.5	41.0	..	17.0	60.0	..	68.0	1.2	10.0	28.1
67 एंटिगुआ और बरबूडा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6.8	..	..
67 त्रिनिडाड टोबैगो	66.6	12.9	1.0	15.3	6.7	81.0	89.9	..	87.3	29.0	42.0	35.2	3.8	17.9
69 कज़ाकिस्तान	75.0	5.0	2.0	13.6	5.5	76.0	77.9	33.0	79.7	72.0	56.0	8.8	9.4	43.0
70 अल्बानिआ	56.5	28.3	12.0	13.9	5.3	46.0	..	7.0	67.7	..	67.0	4.0	3.3	4.7
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	68.1	22.0	8.0	26.6	7.5	75.0	85.1	13.0	79.0	59.0	31.0	45.1	1.2	5.3
72 डोमिनिका	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	22.1	..	..
72 जॉर्जिआ	62.8	35.6	18.0	15.3	4.2	58.0	55.0	16.0	78.3	66.0	91.0	4.3	1.7	7.1
72 लेबनान	47.6	22.3	7.0	22.8	5.2	65.0	70.8	7.0	74.1	37.0	69.0	2.2	..	..
72 सेंट किट्स एवं नेविस	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	38.2	..	..
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	46.1	33.9	..	..	4.8	57.0	65.0	..	76.3	56.0	55.0	3.0	..	..
77 पेरु	77.4	16.2	34.0	24.3	5.6	72.0	74.1	12.0	75.3	19.0	46.0	10.3	1.0	1.9
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	43.4	55.7	6.0	14.7	4.2	56.0	..	11.0	66.7	..	63.0	1.9	4.0	9.5
78 यूक्रेन	58.3	18.7	7.0	9.2	5.1	53.0	61.4	29.0	71.4	24.0	48.0	5.2	7.0	37.8
80 मॉरिशस	60.8	28.0	..	13.3	5.5	83.0	84.6	..	90.5	67.0	55.0	2.5	1.9	11.8
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	37.2	60.0	5.0	11.5	4.7	33.0	..	18.0	61.7	..	67.0	1.5	..	..
82 अजरबैजान	70.8	15.2	7.0	11.4	4.7	49.0	57.8	27.0	73.4	74.0	74.0	2.2	0.3	1.0
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	22.9	1.9	5.4
84 ओमान	65.7	..	..	..	6.9	91.0	85.3	..	89.9	..	..	0.7	..	..
85 ब्राज़ील	68.2	23.1	3.0	27.2	6.8	80.0	81.3	15.0	78.5	51.0	40.0	21.0	2.0	7.7
85 जमैका	65.9	37.9	6.0	19.1	..	..	68.3	..	72.2	..	..	52.2	..	..
87 अर्मेनिआ	47.3	54.7	4.0	10.9	4.4	41.0	45.4	15.0	52.7	34.0	75.0	1.4	1.1	2.8
88 सेंट लूसिआ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	25.2	0.0	4.9
89 इक्वाडोर	71.5	18.1	8.0	25.8	5.8	78.0	79.8	9.0	86.0	59.0	49.0	18.2	3.6	10.5
90 तुर्की	48.8	20.7	3.0	22.5	5.3	44.0	71.2	8.0	78.9	60.0	51.0	3.3	..	..
91 कोलम्बिया	68.3	29.9	9.0	27.8	6.4	81.0	81.5	14.0	82.9	55.0	43.0	33.4	2.0	7.9
92 श्रीलंका	58.2	24.7	..	15.1	4.2	81.0	84.7	17.0	89.7	86.0	77.0	3.6	..	..
93 अल्जीरिया	43.9	37.5	5.0	..	5.2	53.0	58.7	16.0	73.9	53.0	49.0	1.5	..	..
94 ट्यूनीशिया	46.3	31.4	..	..	4.7	58.0	59.4	15.0	66.0	47.0	47.0	1.1	..	..
मध्यम मानव विकास														
95 टोंगा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1.0	..	..
96 बेलीज़	66.3	28.8	40.0	..	6.5	62.0	..	..	67.1	26.0	43.0	41.4	0.7	6.6
96 डोमीनिकन गणराज्य	62.4	44.5	10.0	27.3	4.7	82.0	76.3	15.0	79.2	45.0	38.0	25.0	0.7	3.9
96 फ़िजी	62.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2.8	..	..
96 सामोआ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1.1	..	..
100 जॉर्डन	44.9	46.8	..	19.0	5.7	72.0	74.9	9.0	75.6	77.0	81.0	1.8	0.0	0.2
101 चीन	74.6	..	..	22.4	5.0	77.0	69.9	57.0	77.1	..	80.0	1.1	..	..
102 तुर्कमेनिस्तान	62.6	..	..	..	5.8	..	93.6	27.0	97.5	..	83.0	4.2	..	..
103 थाइलैंड	76.9	3.0	8.0	21.3	6.7	92.0	96.3	27.0	95.2	54.0	74.0	4.8	3.8	12.0
104 मालदीव	64.7	30.5	..	25.2	..	..	..	..	..	..	..	1.6	0.0	0.7
105 सूरीनाम	56.4	..	6.0	23.0	..	..	..	..	..	..	..	4.6	4.8	23.9
106 गैबन	68.2	..	..	19.5	..	77.0	53.7	..	54.8	53.0	39.0	13.8	..	..
107 अल सल्वाडोर	64.5	13.0	5.0	26.6	6.7	74.0	77.3	18.0	81.9	49.0	42.0	69.2	3.6	12.9
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	77.4	..	26.0	34.2	5.8	67.0	83.9	10.0	84.8	38.0	44.0	8.9	..	..
108 मंगोलिया	67.9	..	18.0	15.9	5.0	64.0	82.1	14.0	80.6	29.0	47.0	8.7	..	..
110 फ़लस्तीन राज्य	41.2	49.6	..	..	4.8	51.0	70.8	9.0	71.5	49.0	59.0	4.1	..	..
111 पराग्वे	73.4	17.8	15.0	..	5.8	71.0	85.6	12.0	85.5	48.0	38.0	11.5	2.0	5.1
112 मिस्र	51.3	54.1	7.0	24.1	4.1	57.0	64.7	22.0	61.0	63.0	58.0	1.2	0.0	0.1
113 माल्डोवा गणराज्य	43.9	15.8	16.0	11.6	5.8	58.0	66.1	12.0	70.6	24.0	50.0	7.5	5.6	30.1

मा.वि.सू. श्रेणी	रोज़गार, अ-रक्षितता और समता				व्यक्तिगत ख़ुशहाली की धारणा			समाज की धारणाएँ			मानव सुरक्षा			
	रोज़गार व आबादी का अनुपात	युवा बेरोज़गारी	बाल श्रम	असमानता के कारण मानव विकास सूचकांक में कुल हानि	कुल मिलाकर जीवन से संतुष्टि	चयन की आज़ादी को लेकर संतुष्टि	रोज़गार से संतुष्टि	लोगों में भरोसा	समुदाय से संतुष्टि[a]	राष्ट्रीय सरकार पर भरोसा	सुरक्षा की धारणा	हत्या की दर	आत्महत्या की दर (प्रति 100,000 व्यक्ति)	
	(% उम्र 25 और अधिक)	(% उम्र 15-24)	(% उम्र 5-14)	(%)	(0, न्यूनतम संतुष्ट, 10, सर्वाधिक संतुष्ट)	(% संतुष्ट)		("हाँ" उत्तर देने वालों का %)			("हाँ" उत्तर देने वालों का %)	(प्रति 100,000 व्यक्ति)	महिला	पुरुष
	2011	2005–2011[b]	2001–2010[b]	2012	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2011	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2004–2011[b]	2001–2010[b]	2001–2010[b]
114 फ़िलीपीन्स	68.8	19.3	..	19.9	5.0	88.0	81.1	14.0	85.6	72.0	62.0	5.4	..	..
114 उज़्बेकिस्तान	62.8	..	..	15.8	5.1	90.0	87.3	26.0	93.8	..	80.0	3.1	2.3	7.0
116 सीरियाई अरब गणराज्य	45.8	40.2	4.0	20.4	4.1	47.0	55.5	9.0	44.8	..	65.0	2.3	..	..
117 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.9	..	..
118 गुयाना	61.0	50.0	16.0	19.1	6.0	66.0	..	..	74.8	46.0	47.0	18.6	13.4	39.0
119 बोत्स्वाना	73.8	..	9.0	..	3.6	82.0	45.9	9.0	56.5	74.0	31.0	14.5	..	..
120 होण्डुरास	67.3	11.2	16.0	27.5	5.9	77.0	79.4	13.0	82.8	29.0	45.0	91.6	..	..
121 इण्डोनेशिया	70.1	23.0	7.0	18.3	5.2	86.0	74.1	21.0	92.3	74.0	88.0	8.1	..	..
121 किरिबाती	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7.3	..	..
121 दक्षिण अफ़्रीका	49.6	55.0	..	..	4.7	84.0	56.5	17.0	62.0	63.0	38.0	31.8	0.4	1.4
124 वनुआतू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.9	..	..
125 किर्गिस्तान	70.4	16.2	4.0	17.1	4.9	71.0	75.2	34.0	84.8	44.0	62.0	20.1	3.6	14.1
125 ताजिकिस्तान	70.3	..	10.0	18.4	4.3	70.0	82.7	31.0	89.9	89.0	85.0	2.1	2.3	2.9
127 वियतनाम	81.3	..	16.0	14.0	5.8	61.0	71.8	26.0	70.1	77.0	67.0	1.6	..	..
128 नामीबिया	57.4	63.8	..	43.5	4.9	76.0	..	..	76.5	82.0	33.0	17.2	..	..
129 निकारागुआ	66.3	9.7	15.0	27.5	5.7	75.0	79.8	11.0	86.0	54.0	51.0	13.6	2.6	9.0
130 मोरक्को	50.9	18.1	8.0	29.7	5.1	54.0	65.4	58.0	69.4	60.0	67.0	1.4	..	..
131 इराक	41.9	..	11.0	..	5.0	30.0	64.2	15.0	66.7	37.0	41.0	2.0	..	..
132 केप वर्दे	66.7	..	3.0	..	..	..	..	..	..	..	..	11.6	..	..
133 ग्वाटेमाला	69.7	7.1	21.0	33.1	6.3	74.0	79.8	15.0	85.7	36.0	41.0	38.5	1.7	5.6
134 टिमोर लेस्ट	62.8	..	4.0	33.0	..	..	..	..	..	..	..	6.9	..	..
135 घाना	81.3	..	34.0	32.2	5.6	85.0	63.8	19.0	68.9	68.0	78.0	15.7	..	..
136 इक्वेटोरिअल गिनी	86.5	..	28.0	..	..	..	..	..	..	..	..	20.7	..	..
136 भारत	61.0	11.5	12.0	29.3	4.6	80.0	71.2	20.0	82.6	58.0	70.0	3.4	7.8	13.0
138 कम्बोडिया	86.7	3.5	39.0	25.9	4.2	92.0	77.6	9.0	90.2	90.0	68.0	3.4	..	..
138 लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	85.1	..	11.0	24.7	5.0	87.0	87.9	..	94.3	98.0	84.0	4.6	..	..
140 भूटान	80.3	10.9	18.0	20.0	..	..	..	..	..	..	..	1.0	..	..
141 स्वाज़ीलैण्ड	55.9	..	9.0	35.4	..	..	55.1	..	62.3	..	..	12.9	..	..
निम्न मानव विकास														
142 काँगो	78.8	..	25.0	31.1	4.5	76.0	56.4	..	67.1	48.0	58.0	30.8	..	..
143 सॉलोमन द्वीपसमूह	73.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.7	..	..
144 साओ टोम एवं प्रिन्साइप	..	..	8.0	31.7	..	..	..	..	..	..	..	1.9	..	..
145 केन्या	75.9	..	26.0	33.6	4.4	71.0	50.0	10.0	69.3	46.0	50.0	20.1	..	..
146 बांग्लादेश	74.0	13.6	13.0	27.4	5.0	78.0	76.4	15.0	91.3	79.0	80.0	2.7	..	..
146 पाकिस्तान	55.4	10.5	..	30.9	5.3	34.0	73.2	20.0	83.6	28.0	46.0	7.8	..	..
148 अंगोला	75.8	..	24.0	43.9	4.2	69.0	65.2	..	49.8	61.0	53.0	19.0	..	..
149 म्याँमार	83.4	..	..	..	..	..	..	..	80.4	..	..	10.2	..	..
150 कैमरून	80.3	..	31.0	33.4	4.4	82.0	62.2	13.0	69.4	65.0	56.0	19.7	..	..
151 मैडागास्कर	90.5	2.8	28.0	30.7	4.4	54.0	38.0	..	72.0	65.0	53.0	8.1	..	..
152 तंज़ानिया गणराज्य	84.2	10.1	21.0	27.3	4.1	74.0	63.0	26.0	67.4	56.0	61.0	24.5	..	..
153 नाइजीरिया	61.7	..	29.0	41.4	4.8	77.0	58.6	13.0	67.4	55.0	69.0	12.2	..	..
154 सेनेगल	76.3	20.1	22.0	33.0	3.8	64.0	42.2	28.0	52.1	30.0	55.0	8.7	..	..
155 मॉरिटानिया	44.7	..	16.0	34.4	5.0	56.0	55.3	30.0	62.2	43.0	62.0	14.7	..	..
156 पापुआ न्यू गिनी	78.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13.0	..	..
157 नेपाल	86.4	..	34.0	34.2	3.8	43.0	87.3	17.0	86.7	33.0	61.0	2.8	..	..
158 लेसोथो	59.7	41.9	23.0	35.9	..	..	46.9	..	52.4	..	..	35.2	..	..
159 टोगो	84.1	..	47.0	33.5	2.8	56.0	42.4	..	57.7	51.0	52.0	10.9	..	..
160 यमन	50.9	..	23.0	32.3	3.7	59.0	54.3	27.0	51.9	39.0	67.0	4.2	..	..
161 हैती	74.6	..	21.0	40.2	3.8	37.0	43.4	30.0	57.9	46.0	42.0	6.9	0.0	0.0
161 युगाण्डा	86.9	5.4	25.0	33.6	4.2	73.0	50.1	17.0	69.7	52.0	42.0	36.3	..	..
163 ज़ाम्बिया	76.6	23.4	41.0	36.7	5.0	65.0	47.3	31.0	62.6	40.0	54.0	38.0	..	..
164 जिबूती	..	..	8.0	36.0	4.4	74.0	70.0	55.0	75.3	68.0	72.0	3.4	..	..
165 गैम्बिया	81.1	..	25.0	..	..	..	..	..	..	..	..	10.8	..	..
166 बेनिन	80.6	..	46.0	35.8	3.7	76.0	46.7	..	66.8	78.0	58.0	15.1	..	..
167 रवाण्डा	92.3	..	35.0	33.9	4.0	82.0	58.6	30.0	74.3	95.0	92.0	17.1	..	..
168 आइवरी कोस्ट	72.8	..	35.0	38.6	4.2	76.0	..	13.0	40.6	42.0	47.0	56.9	..	..
169 कोमोरोस	62.7	..	27.0	..	3.9	50.0	49.8	35.0	77.2	44.0	78.0	12.2	..	..
170 मलावी	92.0	..	26.0	31.4	5.1	88.0	50.9	33.0	80.8	83.0	55.0	36.0	..	..
171 सूडान	89.0	..	..	..	4.4	56.0	48.8	31.0	72.7	54.0	75.0	24.2	..	..

	रोज़गार, अ-रक्षितता और समता				व्यक्तिगत खुशहाली की धारणा			समाज की धारणाएँ			मानव सुरक्षा			
	रोज़गार व आबादी का अनुपात	युवा बेरोज़गारी	बाल श्रम	असमानता के कारण मानव विकास सूचकांक में कुल हानि	कुल मिलाकर जीवन से संतुष्टि	चयन की आज़ादी को लेकर संतुष्टि	रोज़गार से संतुष्टि	लोगों में भरोसा	समुदाय से संतुष्टि[a]	राष्ट्रीय सरकार पर भरोसा	सुरक्षा की धारणा	हत्या की दर	आत्महत्या की दर (प्रति 100,000 व्यक्ति)	
	(% उम्र 25 और अधिक)	(% उम्र 15-24)	(% उम्र 5-14)	(%)	(0, न्यूनतम संतुष्ट, 10, सर्वाधिक संतुष्ट)	(% संतुष्ट)		(''हाँ'' उत्तर देने वालों का %)			(''हाँ'' उत्तर देने वालों का %)	(प्रति 100,000 व्यक्ति)	महिला	पुरुष
मा.वि.सू. श्रेणी	2011	2005–2011[b]	2001–2010[b]	2012	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2011	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2007–2011[b]	2004–2011[b]	2001–2010[b]	2001–2010[b]
172 ज़िम्बाब्वे	89.0	..	..	28.5	4.8	63.0	58.6	15.0	68.4	43.0	39.0	14.3	..	..
173 इथियोपिया	84.0	29.4	53.0	31.9	4.4	39.0	..	..	52.1	32.0	49.0	25.5	..	..
174 लाइबेरिया	72.1	6.6	21.0	35.3	4.2	82.0	63.0	12.0	63.4	54.0	38.0	10.1	..	..
175 अफ़गानिस्तान	59.4	..	13.0	..	3.8	47.0	82.0	25.0	71.7	31.0	29.0	2.4	..	..
176 गिनी बिसाउ	78.1	..	57.0	41.4	..	..	..	..	..	..	..	20.2	..	..
177 सिएरा लिओन	77.4	..	48.0	41.6	4.1	77.0	61.3	16.0	52.3	58.0	50.0	14.9	..	..
178 बुरुण्डी	88.5	..	19.0	..	3.8	49.0	64.7	38.0	76.0	85.0	65.0	21.7	..	..
178 गिनी	79.1	..	25.0	38.8	4.0	79.0	58.9	..	75.3	77.0	62.0	22.5	..	..
180 मध्य अफ्रीकी गणराज्य	82.8	..	47.0	40.5	3.6	68.0	66.5	37.0	75.8	75.0	62.0	29.3	..	..
181 इरिट्रिया	84.1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	17.8	..	..
182 माली	56.0	..	36.0	..	3.8	75.0	54.9	45.0	63.9	71.0	80.0	8.0	..	..
183 बुर्किना फ़ासो	86.0	4.6	38.0	34.2	4.0	58.0	60.1	26.0	78.2	55.0	62.0	18.0	..	..
184 चाड	77.0	..	48.0	40.1	3.7	54.0	72.0	21.0	70.1	39.0	30.0	15.8	..	..
185 मोज़ाम्बीक	90.1	..	22.0	32.7	5.0	64.0	63.1	..	83.1	63.0	42.0	8.8	..	..
186 काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य	82.8	..	42.0	39.9	4.0	62.0	45.6	39.0	60.2	35.0	38.0	21.7	..	..
186 नाइजर	66.2	..	43.0	34.2	4.1	82.0	69.7	40.0	85.2	78.0	81.0	3.8	..	..
अन्य देश अथवा अंचल														
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	78.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15.2	..	..
मार्शल द्वीप समूह	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मोनाको	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.0	..	..
नॉरू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9.8	..	..
सैन मैरीनो	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
सोमालिया	59.9	..	49.0	..	..	..	..	..	..	..	..	1.5	..	..
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
तुवालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह														
अति उच्च मानव विकास	58.8	19.5	..	10.8	6.7	81.5	84.3	30.9	85.9	38.1	68.4	2.1	6.6	20.6
उच्च मानव विकास	61.2	22.4	..	20.6	5.9	66.3	73.4	19.3	76.4	..	47.6	13.0	..	..
मध्यम मानव विकास	68.4	..	..	24.2	4.9	77.8	71.4	..	79.9	..	73.4	3.9	..	..
निम्न मानव विकास	72.2	..	29.7	33.5	4.5	61.8	63.4	..	72.2	50.8	57.7	14.6	..	..
क्षेत्र														
अरब देश	52.6	..	..	25.4	4.8	54.6	63.9	24.9	67.6	..	62.9	4.5	..	..
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	74.5	..	..	21.3	..	..	..	..	..	..	..	2.8	..	..
यूरोप एवं मध्य एशिया	58.4	20.9	..	12.9	5.3	58.5	71.0	21.5	76.5	43.9	53.5	5.5	6.9	35.4
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	67.2	19.6	8.5	25.7	6.5	77.9	..	..	79.0	47.1	42.0	22.2	2.1	8.1
दक्षिण एशिया	61.2	12.9	..	29.1	4.7	72.9	72.1	19.5	83.2	56.1	66.9	3.7	..	..
सब-सहारा अफ्रीका	74.5	..	33.5	35.0	4.4	69.1	56.2	..	65.2	53.6	55.3	20.4	..	..
न्यूनतम विकसित देश	77.4	..	30.2	32.5	4.3	64.2	63.2	..	72.3	56.4	59.5	14.6	..	..
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	65.9	..	..	29.2	..	..	..	..	..	..	..	14.6	..	..
विश्व	**65.8**	**..**	**..**	**23.3**	**5.3**	**73.9**	**73.1**	**29.8**	**79.0**	**52.0**	**66.0**	**6.9**	**..**	**..**

नोट

a शहरों में व्यापक संतुष्टि पर गैलप सर्वेक्षण के प्रश्नों पर आधारित।

b आँकड़े निर्दिष्ट अवधि में अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए हैं।

परिभाषाएँ

आबादी में रोज़गार का अनुपात: 25 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी में उन लोगों का प्रतिशत जो कार्यरत है।

युवा बेरोज़गारी: 15-24 वर्ष आयु की श्रम बल आबादी में उन लोगों का प्रतिशत जो वेतनभोगी कर्मचारी या स्व-रोज़गार सपन्न नहीं है लेकिन काम के लिए उपलब्ध है और उन्होंने वेतनभोगी रोज़गार या स्व-रोज़गार पाने के लिए कोशिश की है।

बाल श्रम: 5–11 वर्ष के उन बच्चों का प्रतिशत जिन्होंने संदर्भित सप्ताह के दौरान, कम से कम एक घंटे के लिए आर्थिक गतिविधि में भाग लिया हो या कम से कम 28 घंटों तक घरेलू काम किया या 12–14 उम्र के उन बच्चों का प्रतिशत जिन्होंने संदर्भित सप्ताह के दौरान कम से कम 14 घंटे आर्थिक गतिविधि में भाग लिया हो या कम से कम 28 घंटों तक घरेलू काम किया हो।

असमानता के कारण मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) में कुलल हानि: असमानता के कारण संभावित मानव विकास सूचकांक की हानि जिसे मा.वि.सू. और असमानता-समायोजित मा.वि.सू. के अंतर के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। असमानता-समायोजित मा.वि.सू. के माप के विवरण के लिए तकनीकी नोट 2 देखें।

कुल मिलाकर जीवन से संतुष्टि: गैलप विश्व सर्वेक्षण के इस प्रश्न पर औसत प्रतिक्रिया: कृपया एक सीढ़ी की कल्पना करें जिसके पहले पायदान का मान शून्य और एक-एक बढ़ते हुए अंतिम पायदान का मान 10 है। अब मान लीजिए, हम आपसे यह कहें कि सबसे ऊँचा पायदान प्रतीक है आपके लिए श्रेष्ठतम संभव जीवन का। अब बतायें कि आप स्वयं को मौजूदा हालत में किस पायदान पर खड़ा पाते हैं, यह मानते हुए कि इससे ऊँचे पायदान पर जाकर आपको अपने जीवन के बारे में और अच्छा लगेगा और इससे नीचे पायदान पर जाकर आपको अपने जीवन के बारे में ख़राब लगेगा? कौन सा पायदान आपके एहसास के सबसे क़रीब बैठता है?

चयन की आज़ादी को लेकर संतुष्टि: विश्व सर्वेक्षण के प्रश्न, ''इस देश में क्या आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं, वैसा बनाने के लिए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं?'' के जवाब में जिन्होंने ''हाँ'' में जवाब दिया, उनका प्रतिशत।

रोज़गार से संतुष्टि: गैलप विश्व सर्वेक्षण के प्रश्न, ''क्या आप अपने रोज़गार से संतुष्ट या असंतुष्ट हैं?'' पर उन प्रतिभागियों का प्रतिशत जिनका उत्तर ''संतुष्ट'' था।

लोगों में भरोसा: गैलप विश्व सर्वेक्षण के प्रश्न, ''आमतौर पर क्या आप कह सकते है कि ज़्यादातर लोगों पर भरोसा किया जा सकता है या लोगों के साथ व्यवहार करते समय आपको सतर्क रहना पड़ता है?'' पर उन प्रतिभागियों का प्रतिशत, जिनका उत्तर ''हाँ'' था।

समुदाय से संतुष्टि: गैलप विश्व सर्वेक्षण के प्रश्न, ''इस समय क्या आप सोचते है कि शहर या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ की आर्थिक दशाएँ कुल मिलाकर बेहतर होने जा रही है या बुरी?'' के जवाब में जिन लोगों ने ''हाँ'' कहा, उनका प्रतिशत।

राष्ट्रीय सरकार पर भरोसा: गैलप विश्व सर्वेक्षण के प्रश्न, ''इस देश में, क्या आपको राष्ट्रीय सरकार पर भरोसा है?'' पर उन प्रतिभागियों का प्रतिशत जिनका उत्तर ''हाँ'' था।

सुरक्षा का बोध: गैलप विश्व सर्वेक्षण के प्रश्न, ''क्या आप शहर में या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ रात में अकेले घूमते हुए सुरक्षित महसूस करते हैं?'' पर उन प्रतिभागियों का प्रतिशत जिनका उत्तर ''हाँ'' था।

हत्या की दर: इरादतन की गई हत्याओं की संख्या– यानी किसी खास मकसद से एक व्यक्ति द्वारा की गई दूसरे की हत्या– प्रति 100,000 व्यक्तियों के सापेक्ष निकाला गया मान।

आत्महत्या की दर: जानबूझकर आत्मघात से हुई मौतों की कुल संख्या, कुल आबादी या किसी खास लिंग या आयु में, संदर्भित आबादी की कुल संख्या से विभाजित, प्रति 100,000 व्यक्ति के रूप में व्यक्त।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1 और 2: आई.एल.ओ. (2012)।

कॉलम 3: यूनीसेफ़ (2012)।

कॉलम 4: गणनाएँ तालिका 1 और 3 के मा.वि.सू. और असमानता-समायोजित मा.वि.सू. मूल्यों पर आधारित।

कॉलम 5-11: गैलप (2012)।

कॉलम 12: यू.एन.ओ.डी.सी. (2012)।

कॉलम 13 और 14: डब्ल्यू.एच.ओ. (2012c)।

सारणी 10 वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह

		वस्तु व्यापार[a]				सेवाओं का व्यापार				वाणिज्यिक वस्तुओं की संरचना					
		वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात		वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात		सेवाओं का निर्यात		सेवाओं का आयात		वाणिज्यिक निर्यात की हिस्सेदारी (%)		वाणिज्यिक आयात की हिस्सेदारी (%)		अवयव और संघटक[b]	
		($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	कृषि निर्यात	विनिर्मित निर्यात	कृषि आयात	विनिर्मित आयात	(विनिर्मित निर्यात का %)	(विनिर्मित आयात का %)
मा.वि.सू. श्रेणी		2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
अति उच्च मानव विकास															
1	नार्वे	130.7	33.0	77.3	19.5	39.7	10.0	42.8	10.8	7.8	18.6	9.4	75.1	37.0	21.5
2	ऑस्ट्रेलिया	206.7	20.1	187.9	18.3	48.5	4.7	51.5	5.0	13.1	12.8	5.9	72.4	24.2	21.6
3	यूनाइटेड स्टेट्स	1,121.8	7.9	1,966.5	13.9	544.4	3.9	402.0	2.8	12.3	65.2	5.9	68.8	30.3	28.8
4	नीदरलैंड	492.6	62.9	440.0	56.2	95.4	12.2	85.2	10.9	16.2	56.5	11.4	56.5	26.0	28.9
5	जर्मनी	1,271.1	38.8	1,066.8	32.5	237.6	7.2	263.2	8.0	6.0	81.8	8.6	67.4	28.1	32.0
6	न्यूज़ीलैंड	29.7	22.9	30.2	23.3	8.7	6.7	9.1	7.1	65.6	20.3	11.2	70.0	16.0	18.6
7	आयरलैंड	118.3	55.3	60.5	28.3	97.1	45.4	108.4	50.7	9.7	84.2	13.0	66.4	13.5	22.6
7	स्वीडन	158.4	36.5	148.8	34.3	64.4	14.8	48.5	11.2	8.8	74.5	10.2	69.2	28.6	31.1
9	स्विटजरलैंड	195.6	38.3	176.3	34.5	83.6	16.4	39.6	7.8	4.1	87.6	6.8	79.6	15.9	16.9
10	जापान	769.8	14.6	692.6	13.2	141.5	2.7	157.6	3.0	1.3	88.3	11.2	50.0	36.0	31.8
11	कनाडा	362.1	24.8	388.3	26.6	69.2	4.7	91.3	6.3	14.2	46.7	8.2	74.7	22.7	29.5
12	कोरिआ गणराज्य	466.4	50.6	425.2	46.1	..	..	..	..	2.0	88.3	6.3	56.4	36.8	35.3
13	हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	14.8	6.8	441.4	203.9	..	..	..	..	5.7	46.3	4.7	84.7	18.1	56.9
13	आइसलैंड	4.6	37.3	3.9	31.9	2.5	20.0	2.2	17.7	41.9	14.6	12.2	58.8	8.9	29.0
15	डेनमार्क	96.5	31.0	84.5	27.1	59.9	19.2	50.7	16.3	21.3	60.4	16.0	72.7	22.1	22.8
16	इस्राइल	58.4	28.4	59.2	28.7	24.7	12.0	18.1	8.8	4.0	65.4	8.5	57.4	28.7	24.1
17	बेल्जियम	411.1	87.5	389.5	82.9	83.3	17.7	78.5	16.7	10.3	70.7	9.8	66.9	13.5	17.6
18	ऑस्ट्रिया	144.9	38.2	150.6	39.7	54.5	14.4	36.9	9.7	8.7	79.5	9.5	72.5	30.2	27.0
18	सिंगापुर	351.9	180.9	310.8	159.8	112.3	57.7	96.5	49.6	2.2	72.1	3.5	64.7	64.5	61.4
20	फ्रांस	511.7	19.8	592.1	22.9	143.7	5.6	129.8	5.0	12.9	78.2	9.9	73.1	26.5	25.8
21	फ़िनलैंड	70.1	29.5	68.8	28.9	24.6	10.3	21.7	9.1	8.5	76.5	9.6	60.5	23.1	26.2
21	स्लोवेनिया	24.4	50.9	26.5	55.2	5.8	12.0	4.4	9.1	6.0	84.8	11.2	69.1	25.6	26.4
23	स्पेन	246.3	17.3	315.5	22.2	124.1	8.7	87.1	6.1	16.2	71.9	11.8	65.3	21.3	26.7
24	लिख्टेन्स्टाइन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
25	इटली	446.8	21.5	487.0	23.5	98.3	4.7	110.1	5.3	8.6	81.7	11.3	63.0	24.2	23.0
26	लक्ज़मबर्ग	13.8	26.4	20.3	38.8	67.5	128.6	37.3	71.2	11.3	79.3	12.3	63.3	19.0	17.7
26	यूनाइटेड किंगडम	405.9	18.4	559.3	25.3	237.9	10.8	168.8	7.6	7.0	68.2	10.9	67.1	26.0	26.1
28	चेक गणराज्य	132.1	67.1	125.7	63.8	21.7	11.0	18.2	9.2	5.3	86.4	6.7	76.9	40.6	43.2
29	यूनान	21.7	7.0	63.9	20.6	37.5	12.1	20.2	6.5	27.5	49.1	13.4	59.2	14.7	12.5
30	ब्रूनेई दारस्सलाम	..	..	..	..	1.1[d]	7.9	1.4[d]	12.4	..	..	..	..	..	..
31	साइप्रस	0.8	3.2	8.6	37.0	11.5	49.5	4.2	17.9	36.1	50.2	15.6	61.6	34.2	14.6
32	माल्टा	3.7	45.7	5.7	70.5	4.0	49.0	2.6	31.6	5.3	67.6	11.3	62.6	60.4	37.1
33	अंडोरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
33	एस्टोनिआ	12.8	67.3	13.2	69.4	4.5	23.7	2.8	14.6	15.2	62.2	13.6	63.8	24.9	27.1
35	स्लोवाकिआ	64.0	73.4	64.0	73.5	..	..	..	..	5.6	86.3	7.7	75.5	26.6	43.9
36	कतर	48.3	43.0	..	..	2.3	2.0	6.2	5.5	0.1	6.8	..	..	0.9	..
37	हंगरी	94.7	74.0	87.4	68.3	19.1	14.9	15.9	12.4	8.1	81.7	5.8	71.8	50.1	51.6
38	बारबाडोस	0.2	6.1	1.2	31.1	1.5	38.1	0.8	19.6	33.5	63.9	26.7	70.0	15.7	16.7
39	पोलैण्ड	157.1	34.9	174.1	38.7	32.5	7.2	29.0	6.4	12.0	79.1	9.4	74.2	30.6	29.2
40	चिली	70.9	36.5	59.4	30.5	10.8	5.6	11.8	6.1	22.2	12.0	7.7	68.7	9.7	19.3
41	लिथुएनिया	20.8	56.9	23.4	63.9	4.1	11.3	2.8	7.7	19.7	54.0	14.2	49.9	13.4	16.4
41	संयुक्त अरब अमीरात	..	..	..	..	11.7	4.1	41.7	14.7	..	..	..	..	..	..
43	पुर्तगाल	48.7	21.2	75.6	32.8	23.3	10.1	14.4	6.2	13.9	73.1	15.1	66.7	24.8	22.1
44	लातीविया	8.9	35.5	11.1	44.7	3.7	14.7	2.2	8.8	30.0	57.6	16.3	59.1	13.7	16.0
45	अर्जेंटीना	68.2	20.2	56.8	16.8	13.2	3.9	14.1	4.2	50.8	32.2	3.7	84.4	13.1	29.1
46	सेशेल्स	..	..	..	..	0.4	47.7	0.3	36.8	..	..	..	..	..	..
47	क्रोएशिया	11.8	19.0	20.1	32.3	11.0	17.7	3.5	5.6	15.0	68.0	11.5	67.2	24.6	17.2
उच्च मानव विकास															
48	बहरीन	15.5	73.3	16.0	75.7	4.0	19.2	1.9	9.0	1.9	5.6	8.1	38.8	1.4	25.1
49	बहामास	0.3	3.9	2.9	37.0	..	..	..	..	25.6	63.4	19.3	52.9	0.0	14.1
50	बेलारूस	25.2	48.3	34.9	66.7	4.5	8.6	2.9	5.5	14.7	52.9	9.4	47.5	10.7	20.2
51	उरुग्वे	5.4[d]	15.4	6.9[d]	19.8	2.5	7.1	1.4	4.1	73.5	23.7	12.2	62.5	10.5	15.6
52	मॉन्टीनेग्रो	..	..	..	..	1.0	24.0	0.4	9.7	..	..	..	..	..	..
52	पलाउ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
54	कुवैत	50.3	43.8	..	..	7.7	6.7	13.6	11.8	0.4	6.2	..	..	3.4	..
55	रूसी गणराज्य	400.1	29.5	248.7	18.4	44.3	3.3	73.5	5.4	4.1	14.1	14.0	68.6	9.7	21.7
56	रोमानिया	49.4	30.6	62.0	38.4	8.6	5.3	9.4	5.8	10.1	78.5	9.1	75.3	37.0	32.6
57	बुल्गारिया	20.6	42.8	25.4	52.7	7.0	14.5	4.5	9.3	17.5	49.3	10.6	54.9	22.1	20.4
57	सऊदी अरब	245.9	59.4	106.9	25.8	10.7	2.6	76.8	18.5	1.2	11.0	16.5	76.1	2.7	23.0

		वस्तु व्यापार[a]				सेवाओं का व्यापार				वाणिज्यिक वस्तुओं की संरचना					
		वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात		वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात		सेवाओं का निर्यात		सेवाओं का आयात		वाणिज्यिक निर्यात की हिस्सेदारी (%)		वाणिज्यिक आयात की हिस्सेदारी (%)		अवयव और संघटक[b]	
		($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	कृषि निर्यात	विनिर्मित निर्यात	कृषि आयात	विनिर्मित आयात	(विनिर्मित निर्यात का %)	(विनिर्मित आयात का %)
मा.वि.सू. श्रेणी		2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
59	क्यूबा	..	..	..	..	8.0[d]	..	1.4[d]	..	..	..	..	..	..	..
59	पनामा	0.7	2.8	16.7	65.8	6.1	24.0	2.8	10.9	67.6	11.9	8.2	89.7	0.1	11.8
61	मैक्सिको	298.3	31.0	301.5	31.4	15.4	1.6	25.6	2.7	6.3	74.5	7.8	79.5	40.3	46.2
62	कोस्टा रिका	9.0	27.6	13.9	42.4	4.2	12.7	1.8	5.4	37.3	60.7	10.1	73.0	43.9	31.8
63	ग्रेनाडा	..	..	0.3[d]	36.2	0.1	17.7	0.1	13.0	..	..	25.8	58.8	..	14.1
64	लीबिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
64	मलेशिया	198.8	92.3	164.5	76.3	34.0	15.8	33.7	15.6	14.5	67.0	9.8	73.2	54.5	54.5
64	सर्बिया	..	..	..	..	3.5	9.0	3.5	9.0	..	..	..	..	..	..
67	एंटिगुआ और बरबूडा	0.0	0.2	0.5	42.3	0.5	43.2	0.2	18.8	50.7	47.6	22.5	48.3	0.0	23.1
67	त्रिनिडाड टोबैगो	10.0	49.1	6.5	31.9	0.9	4.2	0.4	2.1	2.6	31.0	11.9	49.9	1.0	20.0
69	कज़ाकिस्तान	..	..	..	..	4.2	3.2	11.3	8.6	..	..	..	..	..	..
70	अल्बानिआ	1.5	12.9	4.6	38.4	2.2	18.7	2.0	16.8	6.9	62.0	19.0	63.6	5.7	12.5
71	वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	67.0	18.5	32.3	9.0	..	..	..	..	0.2	4.0	16.7	80.8	7.2	25.0
72	डोमिनिका	0.0	5.9	0.2	47.1	0.1	24.7	0.1	13.2	27.1	66.0	25.1	57.1	0.9	16.2
72	जॉर्जिआ	1.3	11.5	5.1	45.5	1.6	14.3	1.1	9.7	21.5	46.3	18.9	60.2	6.0	13.3
72	लेबनान	4.3	11.5	18.0	48.6	15.3	41.3	13.0	35.2	12.6	54.6	16.7	54.8	18.4	11.7
72	सेंट किट्स एवं नेविस	0.0	3.9	0.3	39.6	..	..	..	..	12.7	87.2	21.6	73.7	87.8	17.5
76	ईरान इस्लामिक गणराज्य	83.8	25.3	54.7	16.5	..	..	..	..	6.5	15.6	17.6	70.0	4.3	21.3
77	पेरु	35.2	25.1	30.0	21.4	4.0	2.8	6.0	4.3	16.9	10.9	12.0	72.5	4.5	17.9
78	मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	2.7[d]	29.2	5.0[d]	54.7	..	..	..	..	25.4	69.0	17.4	74.8	7.0	11.8
78	यूक्रेन	51.4	40.7	60.7	48.0	17.1	13.5	12.2	9.7	20.4	63.7	10.3	52.9	13.9	16.9
80	मॉरिशस	1.5	16.1	4.4	47.5	2.7	29.1	2.0	21.4	39.5	56.3	23.1	54.6	1.6	15.6
81	बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	4.8	28.5	9.2	54.7	1.3	7.6	0.6	3.5	13.2	54.7	19.7	57.8	27.6	15.6
82	अजरबैजान	21.3	43.8	6.6	13.6	2.1	4.3	3.8	7.8	2.8	2.5	20.2	76.3	6.0	23.1
83	सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	0.0	5.2	0.4	56.3	..	..	..	..	82.4	15.7	24.0	53.3	0.2	15.1
84	ओमान	31.6	60.4	19.8	37.8	1.8	3.4	6.5	12.5	2.6	10.5	12.7	73.3	8.6	21.9
85	ब्राज़ील	197.4	10.5	179.7	9.6	31.8	1.7	62.6	3.3	34.8	35.8	6.0	73.9	22.8	30.7
85	जमैका	1.2	9.5	5.2	39.7	2.6	20.0	1.8	13.9	24.8	7.9	18.7	48.7	1.5	14.5
87	अर्मेनिआ	0.9	9.6	3.7	41.5	0.8	8.5	1.0	11.1	17.3	21.2	18.6	52.5	10.4	17.1
88	सेंट लूसिआ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
89	इक्वाडोर	17.5	31.8	20.6	37.4	1.4	2.5	3.0	5.4	34.1	9.6	9.4	67.8	12.9	17.4
90	तुर्की	114.0	16.9	185.5	27.6	34.4	5.1	19.7	2.9	10.9	77.7	6.9	62.5	14.8	21.3
91	कोलम्बिया	39.5	15.0	40.5	15.4	4.4	1.7	8.0	3.0	14.6	21.0	11.1	80.9	8.4	17.3
92	श्रीलंका	8.3	18.1	12.4	27.0	2.5	5.4	3.1	6.8	30.8	61.2	16.7	61.8	5.5	13.7
93	अल्जीरिया	57.1	38.0	41.0	27.3	3.6	2.4	11.9	7.9	0.6	0.8	17.9	78.4	2.9	20.5
94	ट्यूनीशिया	16.4	37.4	22.2	50.6	5.8	13.2	3.3	7.6	8.2	76.0	11.5	72.3	28.9	26.8
मध्यम मानव विकास															
95	टोंगा	0.0	2.4	0.2	47.0	0.0	12.2	0.0	13.5	90.6	7.6	31.3	44.8	0.2	16.3
96	बेलीज़	0.3	20.5	0.7	50.9	0.4	25.7	0.2	11.8	62.3	1.3	17.4	60.9	0.3	12.3
96	डोमीनिकन गणराज्य	4.8	9.7	15.1	30.8	5.1	10.3	2.1	4.4	28.5	67.6	14.6	59.4	10.4	18.7
96	फ़िजी	0.6	18.6	1.8	60.2	0.7[d]	23.3	0.5[d]	14.9	62.2	22.1	18.7	48.1	5.7	19.1
96	सामोआ	0.1	10.6	0.3	55.3	0.2	28.3	0.1	15.5	21.5	78.2	26.9	54.0	97.8	17.4
100	जॉर्डन	5.9	23.6	15.3	60.8	5.2	20.5	4.3	17.0	16.5	72.0	17.6	56.3	5.4	18.4
101	चीन	1,577.8	28.9	1,289.1	23.6	171.2	3.1	193.3	3.5	3.3	93.4	8.4	60.9	28.7	44.8
102	तुर्कमेनिस्तान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
103	थाइलैंड	195.3	67.0	180.1	61.8	34.0	11.7	45.9	15.7	18.0	71.6	6.6	66.2	38.1	40.9
104	माल्दीव	0.1	3.7	1.1	54.5	0.8	38.3	0.3	15.3	96.2	0.1	24.6	50.2	0.0	21.1
105	सूरीनाम	2.0	49.2	1.4	33.9	0.2	5.9	0.3	6.3	2.9	1.9	15.3	63.7	27.8	18.3
106	गैबन	5.4[d]	44.4	2.5[d]	20.7	0.4	3.3	1.9	15.9	9.6	4.2	17.6	74.1	30.3	26.1
107	अल सल्वाडोर	4.5	21.4	8.5	40.3	1.0	4.6	1.1	5.1	21.9	71.5	18.5	63.8	7.8	14.1
108	प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	7.0	37.7	5.6	30.3	..	..	..	..	16.1	6.3	8.4	78.1	2.6	12.3
108	मंगोलिया	..	..	..	..	0.5	9.0	0.8	14.5	..	..	..	..	..	..
110	फ़लस्तीन राज्य	0.4[d]	..	4.0[d]	..	..	..	..	..	17.2	66.9	22.9	43.8	1.5	10.1
111	पराग्वे	4.5	27.8	10.0	61.6	1.5	9.2	0.7	4.4	88.5	10.7	8.1	79.4	7.4	20.1
112	मिस्र	26.3	12.9	53.0	26.0	..	..	..	..	19.5	41.7	22.4	59.9	8.4	18.1
113	माल्डोवा गणराज्य	0.9	16.6	3.9	68.5	..	..	..	..	73.0	22.6	16.2	62.4	8.2	15.6
114	फ़िलीपीन्स	51.5	28.0	58.5	31.8	13.2	7.2	11.3	6.1	8.0	85.1	11.7	66.8	72.8	58.4
114	उज़्बेकिस्तान	..	..	..	..	1.1	3.1	0.6	1.7	..	..	..	..	..	..
116	सीरियाई अरब गणराज्य	11.4	20.1	17.6	31.1	5.2	8.5	..	..	22.7	24.7	23.4	54.1	6.6	16.0
117	फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

	वस्तु व्यापार[a]				सेवाओं का व्यापार				वाणिज्यिक वस्तुओं की संरचना					
	वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात		वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात		सेवाओं का निर्यात		सेवाओं का आयात		वाणिज्यिक निर्यात की हिस्सेदारी (%)		वाणिज्यिक आयात की हिस्सेदारी (%)		अवयव और संघटक[b]	
	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	कृषि निर्यात	विनिर्मित निर्यात	कृषि आयात	विनिर्मित आयात	(विनिर्मित निर्यात का %)	(विनिर्मित आयात का %)
मा.वि.सू. श्रेणी	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
118 गुयाना	0.9	43.2	1.4	67.6	0.3	12.7	0.3	16.3	49.0	3.8	15.3	54.8	2.1	15.5
119 बोत्स्वाना	4.7	35.5	5.7	42.8	0.8	6.1	1.2	9.3	5.2	10.5	13.2	57.2	16.3	21.8
120 होण्डुरास	2.6[d]	17.8	6.0[d]	40.4	1.0	6.9	1.3	9.0	53.1	33.8	20.1	59.9	18.3	15.0
121 इण्डोनेशिया	157.8	25.3	135.5	21.7	16.8	2.7	26.1	4.2	22.8	37.0	11.5	63.4	18.8	32.9
121 किरिबाती	0.0	2.8	0.1	52.4	..	..	..	..	68.3	27.6	41.7	32.0	0.1	18.3
121 दक्षिण अफ्रीका	71.5	22.1	79.9	24.7	14.0	4.3	18.5	5.7	11.0	43.2	6.8	64.1	15.0	27.3
124 वनुआतू	..	..	..	..	0.2[d]	38.2	0.1[d]	16.8	..	..	..	..	..	..
125 किर्गिस्तान	1.3	27.4	3.2	68.0	..	..	..	..	17.1	18.6	18.1	53.9	14.6	12.8
125 ताजिकिस्तान	..	..	..	..	0.2	3.9	0.4	7.4	..	..	..	..	..	..
127 वियतनाम	72.2[d]	71.1	84.8[d]	83.5	..	..	..	..	23.3	64.0	12.1	71.9	19.0	23.6
128 नामीबिया	5.8	58.3	6.0	59.6	0.9	8.5	0.7	7.0	25.5	23.3	15.5	69.6	6.7	16.4
129 निकारागुआ	1.8	28.9	4.2	65.5	0.5	7.4	0.7	10.8	78.7	6.3	17.1	60.8	5.7	14.5
130 मोरक्को	17.8	19.6	35.4	38.9	12.5	13.8	7.4	8.2	20.6	63.4	13.6	59.9	28.2	21.5
131 इराक	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
132 केप वर्दे	0.0	2.9	0.7	44.8	0.5	31.3	0.4	23.2	81.6	17.5	29.1	57.8	0.0	18.2
133 ग्वाटेमाला	8.5	21.4	13.8	35.0	2.2	5.6	2.4	6.0	46.3	42.6	14.6	66.0	3.0	15.7
134 टिमोर लेस्ट	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
135 घाना	5.2	18.0	8.1	27.7	1.5	5.1	3.0	10.3	24.2	7.3	16.4	81.3	8.9	19.0
136 इक्वेटोरिअल गिनी	..	..	..	..	0.1	0.5	2.2	16.7	..	..	..	..	..	..
136 भारत	220.4	14.5	350.0	23.0	123.8	8.1	116.8	7.7	10.5	52.4	5.1	36.9	14.5	29.8
138 कम्बोडिया	5.6	51.7	4.9	45.3	1.8	17.0	1.2	10.8	3.7	96.1	8.6	79.4	0.2	7.3
138 लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
140 भूटान	0.4	29.7	0.9	61.4	0.1[d]	4.2	0.1[d]	5.3	7.4	69.5	13.7	60.8	0.0	19.1
141 स्वाज़ीलैण्ड	..	..	..	..	0.2	7.2	0.6	17.6	..	..	..	..	..	..
निम्न मानव विकास														
142 कौंगो	6.9	64.1	4.4	40.5	..	..	..	..	2.1	30.2	7.4	86.7	2.5	9.1
143 सॉलोमन द्वीपसमूह	0.2	32.9	0.4	65.6	0.1	14.7	0.2	28.8	29.2	0.1	18.7	20.1	14.5	21.6
144 साओ टोम एवं प्रिन्साइप	0.0	3.2	0.1	56.4	0.0[d]	5.3[d]	0.0[d]	9.6[d]	95.3	4.7	30.6	52.0	20.1	13.5
145 केन्या	5.2	16.5	12.1	38.5	3.7	11.7	2.0	6.4	57.6	33.9	13.6	62.8	6.3	16.1
146 बांग्लादेश	..	..	..	..	2.4	2.6	4.4	4.6	..	..	..	..	..	..
146 पाकिस्तान	21.0	12.4	37.5	22.1	6.4	3.8	7.1	4.2	18.8	74.0	18.0	48.4	0.6	17.1
148 अंगोला	..	..	..	..	0.6	0.8	17.3	22.0	..	..	..	..	..	..
149 म्यॉमार	7.6	..	4.2	..	0.3	..	0.7	..	30.2	5.5	8.7	67.9	2.3	14.3
150 कैमरून	3.9	17.4	5.1	22.9	1.2	5.2	1.7	7.8	39.2	6.9	19.3	51.3	18.6	17.5
151 मैडागास्कर	0.9	11.0	2.5	29.6	1.0[d]	9.9	1.2[d]	14.2	29.9	46.7	14.6	69.6	1.5	22.5
152 तंज़ानिया गणराज्य	3.9	17.7	8.0	36.2	..	..	..	..	29.6	17.2	10.8	60.5	8.0	15.0
153 नाइजीरिया	86.6	47.3	44.2	24.2	3.1	1.7	22.3	12.2	5.0	6.7	11.0	86.5	8.0	24.0
154 सेनेगल	2.2	16.9	4.8	37.3	1.1	8.9	1.1	8.9	27.2	36.4	23.9	44.4	3.2	15.9
155 मॉरिटानिया	0.7	21.9	1.7	52.0	0.2	4.8	0.8	23.2	38.4	0.0	19.9	52.8	0.0	30.7
156 पापुआ न्यू गिनी	..	..	..	..	0.2	2.4	2.8	32.7	..	..	..	..	..	..
157 नेपाल	0.8	5.8	5.1	35.5	0.7	4.7	0.9	6.0	23.0	72.3	13.4	56.5	3.0	15.5
158 लेसोथो	0.6	32.3	1.4	69.7	0.0	2.5	0.5	26.5	12.9	84.7	30.4	57.8	8.4	16.2
159 टोगो	0.4	13.9	1.0	31.3	0.3	8.6	0.3	11.0	18.8	70.2	17.0	67.2	0.3	12.1
160 यमन	6.2[d]	22.1	9.3[d]	33.0	..	..	..	..	6.8	1.1	31.6	46.7	5.3	13.7
161 हैती	..	..	..	..	0.4	5.8	0.9	13.6	..	..	..	..	..	..
161 युगाण्डा	1.2	7.0	4.7	28.3	1.3	7.9	1.8	11.1	74.0	22.8	13.5	65.3	2.7	18.0
163 ज़ाम्बिया	7.2	49.7	5.3	36.7	0.3	2.2	0.9	6.5	6.8	8.7	5.3	61.7	14.0	18.5
164 जिबूती	0.2[d]	15.0	0.6[d]	61.7	0.3[d]	30.7	0.1[d]	12.2	0.5	92.7	30.1	62.7	47.0	19.0
165 गैम्बिया	0.0	3.4	0.3	28.0	..	..	..	..	79.0	10.5	35.9	42.9	5.7	22.2
166 बेनिन	0.4	6.6	1.5	22.7	0.3	5.3	0.4	6.6	84.4	14.7	35.5	43.1	4.8	8.0
167 रवाण्डा	0.2[d]	4.4	1.1[d]	20.5	0.4	6.9	0.6	11.0	52.9	20.8	14.9	75.8	3.0	17.5
168 आइवरी कोस्ट	10.3	44.8	7.8	34.2	..	..	..	..	58.1	16.1	20.1	54.9	5.8	11.7
169 कोमोरॉस	..	..	..	..	0.1	11.3	0.1	17.9	..	..	..	..	..	..
170 मलावी	1.1	21.8	2.2	44.4	0.1	1.7	0.4	7.7	79.8	9.0	14.8	74.1	11.6	10.1
171 सूडान	9.0[d]	14.9	8.6[d]	14.1	0.3	0.4	2.9	4.8	6.2	0.4	16.1	78.9	4.4	16.8
172 ज़िम्बाब्वे	3.2	48.1	9.1	136.0	0.2	3.6	0.4	6.6	24.7	29.5	20.7	49.2	1.9	11.3
173 इथियोपिया	2.3	7.4	8.6	27.9	2.4	7.6	2.5	8.2	82.7	8.2	11.5	68.8	17.7	18.8
174 लाइबेरिया	..	..	..	..	0.2	16.9	1.1	115.7	..	..	..	..	..	..
175 अफ़गानिस्तान	0.4	2.5	5.2	32.8	..	..	..	..	50.8	19.6	13.7	19.1	0.0	27.1
176 गिनी बिसाउ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

		वस्तु व्यापार[a]				सेवाओं का व्यापार				वाणिज्यिक वस्तुओं की संरचना					
		वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात		वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात		सेवाओं का निर्यात		सेवाओं का आयात		वाणिज्यिक निर्यात की हिस्सेदारी (%)		वाणिज्यिक आयात की हिस्सेदारी (%)		अवयव और संघटक[b]	
		($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	($ बिलियन)	(स.घ.उ. का %)[c]	कृषि निर्यात	विनिर्मित निर्यात	कृषि आयात	विनिर्मित आयात	(विनिर्मित निर्यात का %)	(विनिर्मित आयात का %)
मा.वि.सू. श्रेणी		2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
177	सिएरा लिओन	..	..	..	..	0.1	3.2	0.1	7.6	..	..	..	..	..	..
178	बुरुण्डी	0.1	6.2	0.4	21.0	0.1	4.1	0.2	8.8	76.8	5.3	15.1	81.7	16.1	13.9
178	गिनी	..	..	..	..	0.1	1.4	0.4	8.9	..	..	..	..	..	..
180	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	0.1[d]	4.5	0.2[d]	10.6	0.1	3.3	0.2	8.7	37.4	3.1	30.2	67.2	13.2	18.4
181	इरिट्रिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
182	माली	1.9	21.0	4.7	51.2	0.4	3.8	0.9	9.8	14.2	3.7	12.1	61.3	11.0	21.3
183	बुर्किना फ़ासो	1.3	15.0	2.0	23.9	0.1	1.4	0.6	7.1	28.0	2.9	15.9	61.3	13.3	15.7
184	चाड	..	..	..	..	0.2	2.0	2.4	30.4	..	..	..	..	..	..
185	मोज़ाम्बीक	2.2	23.3	3.6	37.7	0.6	6.9	1.1	12.1	20.1	2.0	12.6	49.6	20.9	17.4
186	कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
186	नाइजर	0.5	9.1	2.3	43.0	0.1	2.5	1.1	19.8	20.7	11.9	17.3	69.3	2.6	18.3
अन्य देश अथवा अंचल															
	कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	मार्शल द्वीप समूह	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	मोनाको	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	नाउरू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	सैन मैरीनो	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	सोमालिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तुवालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह															
	अति उच्च मानव विकास	8,889.2	21.6	9,960.0	24.2	2,682.8	6.6	2,333.0	5.8	9.4	70.1	8.5	67.4	29.5	30.6
	उच्च मानव विकास	2,088.2	26.8	1,769.7	23.2	302.6	4.0	426.9	5.9	10.5	37.4	11.3	71.6	30.0	30.4
	मध्यम मानव विकास	2,475.3	27.0	2,409.2	26.2	418.1	4.7	446.8	5.1	7.9	79.9	8.7	59.0	28.5	38.8
	निम्न मानव विकास	188.8	24.9	210.0	27.9	29.1	3.3	82.6	9.8	18.0	19.4	14.1	66.9	3.8	18.9
क्षेत्र															
	अरब देश	546.6	38.9	367.5	..	86.4	5.8	..	..	4.4	17.8	16.7	70.5	12.5	21.0
	पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	यूरोप एवं मध्य एशिया	1,226.6	33.5	1,218.4	33.1	251.7	6.6	232.3	6.2	8.5	54.9	10.3	68.3	28.7	29.1
	लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	857.8	18.9	842.6	18.5	120.0	2.7	151.8	3.6	21.0	42.0	8.5	76.3	31.5	32.3
	दक्षिण एशिया	335.2	14.2	466.8	23.3	136.6	7.4	132.7	7.2	10.6	44.8	8.7	44.2	11.8	26.1
	सब-सहारा अफ्रीका	237.5	28.3	246.3	29.1	39.6	4.3	93.5	10.3	15.7	21.5	11.4	69.1	12.4	22.2
न्यूनतम विकसित देश		..	..	..	..	16.8	3.5	49.9	11.0	..	..	..	..	..	..
छोटे द्वीपीय विकासशील देश		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
विश्व		**..**	**23.2**	**..**	**24.5**	**3,432.6**	**5.9**	**3,289.3**	**5.7**	**9.4**	**66.5**	**9.0**	**66.6**	**29.2**	**31.6**

नोट

a वाणिज्यिक व्यापार के सभी आँकड़े 1996 संगत प्रणाली (एच.एस.) नामकरण के छह-अंकीय स्तर पर व्यक्त किए गए हैं। पारिभाषिक उद्देश्य से उन्हें मानक अंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (सी.आई.टी.सी.) के कॉन्कॉर्डेन्स टेबल के साथ सुसंगत बनाया गया है।

b अवयव और संघटक के वर्गीकरण की पद्धति के लिए ऑथुकोराला (2012) और उसमें उद्धृत उसके चर्चा पत्र को देखें।

c स.घ.उ. (चालू अमेरिकी डॉलर) के 2009 और 2010 का औसत है।

d आँकड़े 2009 के लिए संदर्भित।

परिभाषाएँ

वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यातः वस्तुएँ जो किसी देश की आर्थिक सीमा से बाहर निकलकर उसके भौतिक संसाधनों में से घट जाती है।

वाणिज्यिक वस्तुओं का आयातः वस्तुएँ जो किसी देश की आर्थिक सीमा में प्रवेश करके उसके भौतिक संसाधनों में जुड़ जाती है।

सेवाओं का निर्यातः अमूर्त उत्पादों और गतिविधियों का निर्यात, जो खपत ईकाई की दशाओं को बदलती है या उत्पादों अथवा वित्तीय सेवाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाती है।

सेवाओं का आयातः अमूर्त उत्पादों और गतिविधियों के विविध प्रकारों का आयात जो खपत ईकाई की दशाओं को बदलती है या उत्पादों अथवा वित्तीय सेवाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाती है।

कृषिक या विनिर्मित वस्तुओं की वाणिज्यिक आयात में हिस्सेदारीः कुल वाणिज्यिक आयात में कृषि या विनिर्मित वस्तुओं के आयात का प्रतिशत।

कृषिक या विनिर्मित वस्तुओं की वाणिज्यिक निर्यात में हिस्सेदारीः कुल वाणिज्यिक निर्यात में कृषि या विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात का प्रतिशत।

अवयव व संघटकः विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन या अंतिम खपत के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल में आने वाली मध्यवर्ती वस्तुएँ, कुल विनिर्मित निर्यात और आयात के प्रतिशत के रूप में व्यक्त।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1, 3 और 9-14: यू.एन.एस.डी. (2012b)।

कॉलम 2 और 4: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ यू.एन.एस.डी. (2012b) और विश्व बैंक (2012a) पर आधारित।

कॉलम 5 और 7: (UNCTAD) अंकटाड (2012)।

कॉलम 6 और 8: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ अंकटाड (2012) और विश्व बैंक (2012a) पर आधारित।

सारणी 11

अंतरराष्ट्रीय पूँजी प्रवाह और प्रवास

मा.वि.सू. श्रेणी	वित्तीय प्रवाह: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शुद्ध आतंरिक प्रवाह (सकल घरेलू उत्पाद का %) 2007–2011[c]	वित्तीय प्रवाह: प्राप्त शुद्ध आधिकारिक विकास सहायता (सकल राष्ट्रीय आय का %) 2010	वित्तीय प्रवाह: निजी पूँजी प्रवाह (सकल घरेलू उत्पाद का %) 2007–2011[c]	वित्तीय प्रवाह: भेजी गई रकम (स.घ.उ.के % के रूप में) अंतर्प्रवाह 2010	वित्तीय प्रवाह: भेजी गई रकम (स.घ.उ.के % के रूप में) बहिर्प्रवाह 2010	स्वर्ण को छोड़कर कुल भण्डार (सकल घरेलू उत्पाद का %) 2007–2011[c]	मानव गतिशीलता: प्रवास: प्रवासियों की संख्या (जनसँख्या का %) 2010	मानव गतिशीलता: प्रवास: आप्रवासियों की संख्या (जनसँख्या का %) 2010	मानव गतिशीलता: प्रवास: शुद्ध प्रवास दर (प्रति 1,000 लोग) 2005/2010[d]	मानव गतिशीलता: अंतरराष्ट्रीय अंतर्गामी पर्यटन (हज़ार में) 2010	मानव गतिशीलता: अंतरराष्ट्रीय टेलीफ़ोन ट्रैफ़िक (मिनट प्रति व्यक्ति) आने वाली कॉल 2005–2010[c]	मानव गतिशीलता: अंतरराष्ट्रीय टेलीफ़ोन ट्रैफ़िक (मिनट प्रति व्यक्ति) जाने वाली कॉल 2005–2010[c]
अति उच्च मानव विकास												
1 नार्वे	2.8	–1.1	–4.9	0.16	0.97	10.2	3.8	10.0	7.2	4,767	..	241.9
2 ऑस्ट्रेलिया	2.7	–0.3	6.5	0.43	0.33	3.1	2.1	25.7	10.5	5,885	..	..
3 यूनाइटेड स्टेट्स	1.5	–0.2	–0.2	0.04	0.36	0.9	0.8	13.5	3.3	59,791	82.5	237.1
4 नीदरलैंड	1.9	–0.8	1.1	0.50	1.67	2.4	6.0	10.5	0.6	10,883	..	96.5
5 जर्मनी	1.1	–0.4	1.2	0.35	0.49	1.9	4.3	13.1	1.3	26,875	..	182.5
6 न्यूज़ीलैंड	0.5	–0.3	1.7	0.59 [e]	0.82 [e]	11.7	14.5	22.4	3.1	2,492	..	173.3
7 आयरलैंड	6.4	–0.5	25.3	0.29	0.85	0.6	16.1	19.6	4.6	7,189	..	441.8
7 स्वीडन	2.3	–1.0	2.2	0.15	0.15	8.2	3.4	14.1	5.8	4,951	..	160.5
9 स्विटजरलैंड	0.4	–0.4	–9.0	0.49	4.09	44.0	5.4	23.2	4.8	8,628	..	409.3
10 जापान	0.0	–0.2	0.7	0.03	0.08	21.4	0.6	1.7	0.4	8,611	13.8	..
11 कनाडा	2.4	–0.3	4.1	..	..	3.8	3.5	21.3	6.6	16,097	..	..
12 कोरिआ गणराज्य	0.4	–0.1	–0.5	0.86	1.12	27.3	4.3	1.1	–0.1	8,798	22.2	47.7
13 हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	34.1	..	–0.8	0.15	0.19	117.1	10.2	38.8	5.1	20,085	524.3	1,446.9
13 आइसलैंड	7.2	–0.3	–55.2	0.20	0.10	60.1	13.0	11.3	6.8	1,213	233.1	148.0
15 डेनमार्क	4.6	–0.9	–1.6	0.20	1.02	24.6	4.7	8.8	3.3	8,744	183.9	190.6
16 इस्राइल	4.7	..	–0.2	0.65	1.72	30.8	14.0	40.4	7.8	2,803	..	..
17 बेल्जियम	18.0	–0.6	–0.2	2.18	0.87	3.5	4.2	13.7	3.8	7,186	..	255.0
18 ऑस्ट्रिया	3.3	–0.3	0.6	0.86	0.92	2.6	7.1	15.6	3.8	22,004	..	171.6
18 सिंगापुर	18.1	..	–1.4	..	..	99.1	6.1	40.7	30.9	9,161	447.5	1,525.2
20 फ्रांस	1.5	–0.5	10.8	0.61	0.21	1.8	2.8	10.7	1.6	77,148	182.1	192.1
21 फ़िनलैंड	0.0	–0.6	2.9	0.35	0.18	3.0	6.2	4.2	2.7	3,670	..	..
21 स्लोवेनिया	2.2	..	6.8	0.66	0.34	1.7	6.5	8.1	2.2	1,869 [f]	88.2	112.0
23 स्पेन	1.7	..	–3.2	0.76	0.88	2.2	3.0	15.2	10.1	52,677	..	118.9
24 लिख्टेन्स्टाइन	..	..	..	..	..	..	17.1	34.6	..	52	..	..
25 इटली	1.5	–0.2	–3.4	0.33	0.60	2.2	5.8	7.4	6.7	43,626	..	152.0
26 लक्ज़मबर्ग	542.9	–1.1	214.8	2.99	19.69	1.5	11.8	35.2	17.6	849	810.6	822.5
26 यूनाइटेड किंगडम	2.2	–0.6	–4.9	0.33	0.16	3.3	7.5	11.2	3.3	28,295	..	147.5
28 चेक गणराज्य	2.5	..	2.1	0.57	0.92	18.4	3.6	4.4	4.6	8,185	120.1	50.5
29 यूनान	0.6	..	–7.8	0.50	0.65	0.4	10.8	10.1	2.7	15,007 [g]	96.1	201.3
30 ब्रूनेई दारस्सलाम	4.0	..	4.3	..	3.60	12.6	6.0	36.4	1.8	157 [f]	..	..
31 साइप्रस	1.0	..	35.1	0.63	1.75	2.0	17.0	17.5	8.3	2,173	314.7	555.4
32 माल्टा	12.2	..	–42.2	0.58	0.56	5.6	26.2	3.8	2.4	1,332	..	144.0
33 अंडोरा	..	..	..	..	..	..	10.7	64.4	..	1,830	638.6	708.3
33 एस्टोनिआ	0.8	..	15.0	1.71	0.50	0.9	12.6	13.6	0.0	2,120	102.9	80.8
35 स्लोवाकिआ	0.6	..	1.4	1.83	0.08	0.9	9.6	2.4	1.3	1,298 [h]	137.2	140.6
36 कतर	4.3	..	..	..	..	9.4	0.7	86.5	132.9	1,866	422.7	484.8
37 हंगरी	17.1	..	6.5	1.76	0.98	34.8	4.6	3.7	1.5	9,510	116.2	48.2
38 बारबाडोस	16.3	0.3 [e]	10.4	2.99	0.97	22.1	41.0	10.9	0.0	532	..	..
39 पोलैण्ड	2.8	..	4.9	1.62	0.34	18.0	8.3	2.2	0.3	12,470	..	24.9
40 चिली	7.0	0.1	–0.3	0.00	0.00	16.9	3.7	1.9	0.4	2,766	26.2	12.2
41 लिथुएनिया	2.9	..	6.1	4.34	1.48	18.5	13.2	4.0	–2.1	1,507	75.1	34.4
41 संयुक्त अरब अमीरात	1.3	..	..	..	..	10.3	1.2	70.0	106.3	7,126	..	643.1
43 पुर्तगाल	4.3	–0.3	–3.8	1.56	0.62	0.8	20.8	8.6	2.8	6,756 [f]	173.9	111.2
44 लातीविया	5.5	..	2.9	2.56	0.18	21.2	12.3	15.0	–0.9	1,373	..	94.1
45 अर्जेंटीना	1.6	0.0	0.9	0.17	0.27	9.7	2.4	3.6	–1.0	5,325	..	18.4
46 सेशेल्स	17.4	6.3	19.3	1.13	2.72	25.1	14.6	12.8	..	175	64.7	111.3
47 क्रोएशिया	2.3	0.3	3.8	2.16	0.27	22.7	17.1	15.9	0.5	9,111	224.1	90.9
उच्च मानव विकास												
48 बहरीन	0.7	..	19.9	..	7.16 [e]	22.2	3.7	39.1	90.2	4,935	..	..
49 बहामास	7.6	..	7.1	..	1.18	13.7	12.8	9.7	3.9	1,370	..	..
50 बेलारूस	7.2	0.3	8.7	0.68	0.19	10.9	18.4	11.4	–1.0	119	69.6	52.2
51 उरुग्वे	4.1	0.1	9.0	0.26	0.02	22.0	10.5	2.4	–3.0	2,353	76.2	46.3
52 मॉन्टीनेग्रो	18.5	2.0	..	7.32	0.67	8.6	0.0	6.8	–0.8	1,088	..	..
52 पलाउ	1.4	19.5	..	..	..	..	38.8	28.1	..	84	179.9	205.1
54 कुवैत	0.1	..	–7.8	..	9.47 [e]	14.6	8.5	68.8	22.2	207	..	..
55 रूसी गणराज्य	2.8	..	–1.7	0.35	1.26	24.4	7.9	8.7	1.6	22,281	..	..
56 रोमानिया	1.5	..	3.0	2.40	0.22	23.9	13.1	0.6	–0.9	7,575	105.4	..
57 बुल्गारिया	3.4	..	2.2	2.91	0.05	28.5	16.0	1.4	–1.3	6,047	107.1	47.4

मा.वि.सू. श्रेणी	वित्तीय प्रवाह: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शुद्ध आतंरिक प्रवाह (सकल घरेलू उत्पाद का %) 2007–2011[c]	वित्तीय प्रवाह: प्राप्त शुद्ध आधिकारिक विकास सहायता (सकल राष्ट्रीय आय का %) 2010	वित्तीय प्रवाह: निजी पूँजी प्रवाह (सकल घरेलू उत्पाद का %) 2007–2011[c]	वित्तीय प्रवाह: भेजी गई रकम (स.घ.उ.के % के रूप में) अंतर्प्रवाह 2010	वित्तीय प्रवाह: भेजी गई रकम (स.घ.उ.के % के रूप में) बहिर्प्रवाह 2010	स्वर्ण को छोड़कर कुल भण्डार (सकल घरेलू उत्पाद का %) 2007–2011[c]	मानव गतिशीलता: प्रवास: प्रवासियों की संख्या (जनसँख्या का %) 2010	मानव गतिशीलता: प्रवास: आप्रवासियों की संख्या (जनसँख्या का %) 2010	मानव गतिशीलता: प्रवास: शुद्ध प्रवास दर (प्रति 1,000 लोग) 2005/2010[d]	अंतरराष्ट्रीय अंतर्गामी पर्यटन (हज़ार में) 2010	अंतरराष्ट्रीय टेलीफ़ोन ट्रैफ़िक (मिनट प्रति व्यक्ति) आने वाली कॉल 2005–2010[c]	अंतरराष्ट्रीय टेलीफ़ोन ट्रैफ़िक (मिनट प्रति व्यक्ति) जाने वाली कॉल 2005–2010[c]
57 सऊदी अरब	2.8	..	–0.5	0.05	6.00	93.7	0.7	27.8	8.2	10,850	..	..
59 क्यूबा	0.0	0.2	..	..	..	8.1	10.9	0.1	–3.4	2,507	32.7	2.5
59 पनामा	8.8	0.5	7.5	0.86	0.93	7.5	4.0	3.4	0.7	1,324	54.4	75.5
61 मैक्सिको	1.7	0.0	4.5	2.13	..	12.5	10.7	0.7	–3.3	22,260	..	..
62 कोस्टा रिका	5.1	0.3	5.8	1.52	0.75	11.6	2.7	10.5	3.4	2,100	85.7	43.1
63 ग्रेनाडा	7.7	4.6	6.0	6.96	0.47	14.8	65.5	12.1	–9.7	114	488.1	315.8
64 लीबिया	2.2	0.1[e]	–5.0	0.03[e]	..	..	1.7	10.4	–0.7	34[h]	..	..
64 मलेशिया	3.9	0.0	–1.4	0.55	2.75	47.3	5.3	8.4	0.6	24,577[e]	..	..
64 सर्बिया	6.0	1.8	10.6	8.72	0.18	33.0	2.0	5.3	0.0	683	104.4	32.1
67 एंटिगुआ और बरबूडा	8.4	1.7	5.2	2.15	0.19	13.1	47.6	23.6	..	230	487.3	247.8
67 त्रिनिडाड टोबैगो	2.6	0.0	2.6	0.57	..	46.3	26.7	2.6	–3.0	413	243.7	200.6
69 कज़ाकिस्तान	6.9	0.2	–2.7	0.20	2.04	13.5	23.6	19.5	0.1	3,393	40.1	38.9
70 अल्बानिआ	9.4	2.9	6.7	9.75	0.20	18.5	45.4	2.8	–3.0	2,417	224.3	23.6
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	1.7	0.0	2.4	0.04	0.20	3.1	1.8	3.5	0.3	615	..	20.1
72 डोमिनिका	5.2	7.0	6.6	5.56	0.04	16.8	104.8	8.3	..	77	140.8	172.6
72 जॉर्जिआ	6.8	5.5	6.7	6.93	0.43	19.6	25.1	4.0	–6.8	2,033	125.6	36.4
72 लेबनान	11.0	1.2	2.1	19.38	9.58	80.0	15.6	17.8	–0.6	2,168	318.4	87.3
72 सेंट किट्स एवं नेविस	17.9	1.8	14.4	6.52	0.85	34.5	61.1	9.6	..	92	820.6	629.7
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	0.9	0.0	..	0.32[e]	..	16.3	1.7	2.8	–0.5	2,034	3.5	10.9
77 पेरू	4.8	–0.2	7.8	1.65	0.08	26.7	3.7	0.1	–5.1	2,299	92.7	19.6
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	4.0	2.1	3.4	4.25	0.25	22.9	21.9	6.3	0.2	262	..	23.3
78 यूक्रेन	4.4	0.5	5.2	4.11	0.02	18.4	14.4	11.6	–0.2	21,203	..	..
80 मॉरिशस	4.4	1.3	19.9	2.33	0.14	22.8	10.9	3.3	0.0	935	140.8	108.5
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	2.4	3.0	2.4	11.44	0.33	22.9	38.9	0.7	–0.5	365	213.8	49.6
82 अजरबैजान	2.3	0.3	1.0	2.71	1.82	16.2	16.0	3.0	1.2	1,280	74.8	17.5
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	15.3	2.6	15.5	4.54	1.05	13.0	37.7	7.9	–9.2	72	..	..
84 ओमान	1.1	–0.1	–0.8	0.07[e]	9.86[e]	20.0	0.5	28.4	11.7	1,048[e]	223.1	206.9
85 ब्राज़ील	2.7	0.0	4.1	0.19	0.06	14.1	0.7	0.4	–0.5	5,161	..	2.3
85 जमैका	1.6	1.1	–1.5	14.50	2.26	15.1	36.1	1.1	–7.4	1,922	252.4	828.6
87 अर्मेनिआ	6.5	3.5	4.3	10.63	1.67	18.9	28.2	10.5	–4.9	575	174.9	243.8
88 सेंट लूसिआ	9.2	3.6	9.7	2.62	0.37	17.3	23.3	5.9	–1.2	306	292.7	203.6
89 इक्वाडोर	0.3	0.3	0.9	4.43	0.14	2.5	8.3	2.9	–1.7	1,047	62.7	11.7
90 तुर्की	2.1	0.1	4.6	0.12	0.02	10.1	5.6	1.9	–0.1	27,000	57.8	43.4
91 कोलम्बिया	4.0	0.3	3.7	1.41	0.04	9.5	4.6	0.2	–0.5	2,147	..	..
92 श्रीलंका	1.0	1.2	3.3	8.38	1.10	10.6	9.1	1.7	–2.5	654	28.6	..
93 अल्जीरिया	1.4	0.1	1.1	1.26	0.03	96.9	3.4	0.7	–0.8	1,912	36.5	17.1
94 ट्यूनीशिया	3.2	1.3	3.0	4.45	0.03	21.4	6.3	0.3	–0.4	6,903	58.0	16.1
मध्यम मानव विकास												
95 टोंगा	4.5	19.5	0.0	23.65	2.60	32.9	45.4	0.8	–16.0	45	..	..
96 बेलीज़	6.2	2.0	5.2	5.68	1.65	16.1	16.1	15.0	–0.7	239	135.8	178.5
96 डोमीनिकन गणराज्य	3.2	0.4	5.6	6.53	0.06	7.4	10.1	4.2	–2.9	4,125	309.4	52.2
96 फ़िजी	6.2	2.5	6.0	5.78	0.69	21.8	21.3	2.2	–6.8	632	..	..
96 सामोआ	0.1	25.5	1.8	24.11	1.21	25.7	67.3	5.0	–17.3	130	..	..
100 जॉर्डन	6.4	3.6	6.0	13.78	1.87	39.8	11.3	45.9	7.0	4,557	95.8	6.8
101 चीन	3.1	0.0	2.6	0.89	0.03	43.8	0.6	0.1	–0.3	55,664	9.2	2.9
102 तुर्कमेनिस्तान	10.4	0.2	..	..	..	..	5.0	4.0	–2.2	8	..	..
103 थाइलैंड	3.0	0.0	4.2	0.55	..	48.4	1.2	1.7	1.5	15,936	20.5	..
104 माल्दीव	7.9	5.6	7.9	0.20	5.31	17.0	0.6	1.0	0.0	792	..	428.6
105 सूरीनाम	–5.9	2.4	–6.2	0.10[e]	0.03[e]	13.8	39.0	7.5	–2.0	205	..	..
106 गैबन	1.3	0.9	..	..	..	12.7	1.7	18.9	0.7	358	..	..
107 अल सल्वाडोर	1.5	1.4	2.1	16.10	0.11	9.3	20.5	0.7	–9.5	1,150	223.3	175.7
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	3.2	3.6	4.2	5.54	0.53	40.6	6.8	1.5	–3.5	807	85.6	11.4
108 मंगोलिया	23.5	5.4	54.9	4.46	2.73	26.6	1.2	0.4	–1.1	457	35.2	17.2
110 फ़लस्तीन राज्य	..	..	..	..	..	..	68.4	43.6	–4.7	522	..	..
111 पराग्वे	2.1	0.6	2.0	3.67	..	20.7	7.9	2.5	–1.3	465	37.6	19.4
112 मिस्र	2.9	0.3	7.2	3.53	0.12	6.5	4.4	0.3	–0.9	14,051	55.4	7.8
113 माल्डोवा गणराज्य	3.9	7.5	3.7	23.57	2.01	28.1	21.5	11.4	–9.4	8	198.1	59.8
114 फ़िलीपीन्स	0.6	0.3	3.0	10.73	0.03	29.9	4.6	0.5	–2.8	3,520	..	..
114 उज़्बेकिस्तान	2.1	0.6	..	..	..	..	7.0	4.2	–3.9	975	..	..
116 सीरियाई अरब गणराज्य	2.5	0.2	2.2	2.78	0.36	32.9	4.2	9.8	–0.6	8,546	..	23.4

		वित्तीय प्रवाह						मानव गतिशीलता					
								प्रवास					
		प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शुद्ध आंतरिक प्रवाह	प्राप्त शुद्ध आधिकारिक विकास सहायता	निजी पूँजी प्रवाह	भेजी गई रकम (स.घ.उ.के % के रूप में)		स्वर्ण को छोड़कर कुल भण्डार	प्रवासियों की संख्या	आप्रवासियों की संख्या	शुद्ध प्रवास दर	अंतरराष्ट्रीय अंतर्गामी पर्यटन	अंतरराष्ट्रीय टेलीफ़ोन ट्रैफ़िक (मिनट प्रति व्यक्ति)	
		(सकल घरेलू उत्पाद का %)	(सकल राष्ट्रीय आय का %)	(सकल घरेलू उत्पाद का %)	अंतर्प्रवाह	बहिर्प्रवाह	(सकल घरेलू उत्पाद का %)	(जनसँख्या का %)		(प्रति 1,000 लोग)	(हज़ार में)	आने वाली कॉल	जाने वाली कॉल
मा.वि.सू. श्रेणी		2007–2011[c]	2010	2007–2011[c]	2010	2010	2007–2011[c]	2010	2010	2005/2010[d]	2010	2005–2010[c]	2005–2010[c]
117	फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	3.4	40.2	..	..	..	23.6	19.7	2.4	–16.3	26	..	..
118	गुयाना	11.9	6.7	11.8	13.65	3.41	34.6	56.9	1.5	–10.7	150	103.4	26.8
119	बोत्स्वाना	1.8	1.1	4.6	0.67	0.68	45.8	3.2	5.8	1.9	2,145	..	26.3
120	होण्डुरास	5.9	3.9	5.8	17.27	0.08	15.9	7.5	0.3	–2.8	896	96.0	139.9
121	इण्डोनेशिया	2.1	0.2	1.7	0.98	0.40	12.6	1.1	0.1	–1.1	7,003	..	..
121	किरिबाती	2.4	10.5	..	..	..	..	6.5	2.0	..	5[f]	..	..
121	दक्षिण अफ़्रीका	1.4	0.3	1.6	0.31	0.38	10.4	1.7	3.7	2.9	8,074	..	..
124	वनुआतू	5.6	16.2	7.1	0.93	0.38	21.2	1.6	0.3	0.0	97	..	..
125	किर्गिस्तान	6.6	8.5	3.9	26.60	6.19	28.8	11.2	4.0	–5.1	1,316	23.6	50.0
125	ताजिकिस्तान	0.3	7.8	0.4	39.96	15.17	4.4	11.2	4.0	–8.9	325	..	..
127	वियतनाम	7.5	2.9	6.4	7.76	..	10.9	2.5	0.1	–1.0	3,747	..	..
128	नामीबिया	7.1	2.4	4.5	0.13	0.14	14.5	0.7	6.3	–0.1	984	..	..
129	निकारागुआ	13.3	9.8	13.3	12.48	..	25.9	12.5	0.7	–7.1	1,011	..	..
130	मोरक्को	2.5	1.1	2.0	7.07	0.07	19.5	9.3	0.2	–4.3	9,288	114.1	14.5
131	इराक	1.8	2.8	–1.1	0.09	0.04	52.6	4.9	0.3	–1.0	1,518	..	..
132	केप वर्दे	6.7	20.7	4.8	8.36	0.71	17.8	37.6	2.4	–7.1	382	110.4	28.5
133	ग्वाटेमाला	2.2	1.0	1.5	10.23	0.05	12.4	6.1	0.4	–3.0	1,876	119.6	50.0
134	टिमोर लेस्ट	32.0	9.2	..	..	..	43.8	1.4	1.2	–9.4	40	6.9	11.4
135	घाना	7.9	5.3	9.8	0.42	..	14.0	3.4	7.6	–0.4	803	45.3	24.5
136	इक्वेटोरिअल गिनी	4.8	0.9	..	..	..	15.4	14.9	1.1	6.1	..	..	..
136	भारत	1.4	0.2	3.0	3.21	0.23	14.7	0.9	0.4	–0.5	5,776	20.1	7.5
138	कम्बोडिया	7.0	6.9	6.5	3.29	1.91	26.8	2.3	2.2	–3.7	2,399	..	..
138	लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	3.9	6.2	4.6	0.57	0.11	9.8	5.7	0.3	–2.5	1,670	..	..
140	भूटान	1.3	9.2	..	0.32	5.41	46.8	6.3	5.7	4.9	27	..	..
141	स्वाज़ीलैण्ड	3.7	2.6	5.0	2.95	0.30	15.1	13.4	3.4	–1.0	868	38.2	3.7
निम्न मानव विकास													
142	कौंगो	23.5	14.5	..	0.12	0.85	38.3	5.6	3.8	2.6	85	..	..
143	सॉलोमन द्वीपसमूह	35.1	61.4	34.3	0.43	0.65	49.2	1.0	1.3	0.0	21	..	..
144	साओ टोम एवं प्रिन्साइप	12.3	24.2	12.2	0.99	0.27	20.7	21.9	3.2	–8.2	8	40.7	14.6
145	केन्या	0.6	5.1	0.8	5.52	0.19	12.7	1.1	2.0	–1.0	1,469	16.5	7.6
146	बांग्लादेश	0.7	1.3	0.8	10.81	0.01	7.7	3.3	0.7	–4.0	267	..	..
146	पाकिस्तान	1.1	1.6	0.6	5.48	0.01	6.9	2.5	2.3	–2.4	855	24.8	13.1
148	अंगोला	–3.9	0.3	–5.9	0.10[h]	0.87	28.5	2.8	0.3	0.9	425	..	..
149	म्यॉमार	..	..	..	..	..	..	1.0	0.2	–2.1	311	2.9	0.2
150	कैमरून	0.0	2.4	0.5	0.87	0.24	12.6	1.4	1.0	–0.2	298	23.2	5.4
151	मैडागास्कर	9.9	5.4	..	..	..	12.9	0.4	0.2	–0.1	196	5.5	2.1
152	तंज़ानिया गणराज्य	1.9	13.0	4.6	0.11	0.55	15.7	0.7	1.5	–1.4	783	3.8	3.2
153	नाइजीरिया	3.1	1.2	4.9	5.10	0.02	14.9	0.6	0.7	–0.4	1,414	18.7	11.8
154	सेनेगल	1.8	7.3	3.1	10.47	1.12	13.6	5.0	1.6	–2.3	875	86.5	26.9
155	मॉरिटानिया	0.4	10.6	..	..	..	11.9	3.5	2.9	0.6	..	39.9	15.8
156	पापुआ न्यू गिनी	0.3	5.5	–0.8	0.16	3.41	32.9	0.9	0.4	0.0	114[h]	..	..
157	नेपाल	0.5	5.1	0.5	21.66	0.20	19.2	3.3	3.2	–0.7	603	12.9	..
158	लेसोथो	5.4	9.5	5.5	34.23	0.88	..	20.5	0.3	–1.9	414	..	..
159	टोगो	1.3	13.3	–0.6	10.49	2.27	21.5	5.4	2.7	–0.2	150	34.9	10.2
160	यमन	0.2	2.3	–1.8	3.99	1.09	13.2	4.7	2.1	–1.2	536	76.6	4.6
161	हैती	2.3	45.5	2.3	22.59	2.03	16.3	9.9	0.3	–5.0	423	..	..
161	युगाण्डा	4.7	10.2	6.3	5.32	3.50	15.6	2.2	1.9	–0.9	946	..	4.9
163	ज़ाम्बिया	10.3	6.4	4.6	0.27	0.42	12.1	1.4	1.8	–1.4	815	..	..
164	जिबूती	9.2	14.9[e]	9.2	3.09[e]	..	..	1.5	13.0	0.0	53	41.1	209.2
165	गैम्बिया	3.2	11.9	3.2	11.02	5.53	20.1	3.7	16.6	–1.7	91[h]	..	..
166	बेनिन	1.7	10.5	1.1	3.78	1.34	12.2	5.8	2.5	1.2	199[h]	40.8	23.9
167	रवाण्डा	0.8	18.5	1.1	1.63	1.27	16.5	2.6	4.5	0.3	666	9.2	3.0
168	आइवरी कोस्ट	1.8	3.9	1.4	0.78	3.29	17.9	5.4	11.2	–3.8	..	..	..
169	कोमोरॉस	1.7	12.5	..	..	..	25.4	5.6	2.0	–2.9	15	..	..
170	मलावी	2.8	20.8	1.4	..	..	3.5	1.4	1.8	–0.3	746	..	0.9
171	सूडान	3.1	3.4	3.1	2.95	0.00	0.3	2.2	1.7	0.7	420	10.4	16.0
172	ज़िम्बाब्वे	1.4	10.1	..	..	..	..	9.9	2.9	–14.3	2,239	16.0	21.8
173	इथियोपिया	1.0	11.9	2.0	0.76	0.09	..	0.7	0.6	–0.8	330	5.7	0.4
174	लाइबेरिया	45.8	175.5	45.8	2.71	0.10	..	10.5	2.3	16.7	..	24.5	28.0
175	अफ़गानिस्तान	0.4	42.4	..	..	..	25.9	8.1	0.3	–2.6	..	4.9	2.5

	वित्तीय प्रवाह						मानव गतिशीलता					
							प्रवास					
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शुद्ध आतंरिक प्रवाह	प्राप्त शुद्ध आधिकारिक विकास सहायता	निजी पूँजी प्रवाह	भेजी गई रकम (स.घ.उ.के % के रूप में)		स्वर्ण को छोड़कर कुल भण्डार	प्रवासियों की संख्या	आप्रवासियों की संख्या	शुद्ध प्रवास दर	अंतरराष्ट्रीय अंतर्गामी पर्यटन	अंतरराष्ट्रीय टेलीफ़ोन ट्रैफ़िक (मिनट प्रति व्यक्ति)	
	(सकल घरेलू उत्पाद का %)	(सकल राष्ट्रीय आय का %)	(सकल घरेलू उत्पाद का %)	अंतर्प्रवाह	बहिर्प्रवाह	(सकल घरेलू उत्पाद का %)	(जनसँख्या का %)		(प्रति 1,000 लोग)	(हज़ार में)	आने वाली कॉल	जाने वाली कॉल
मा.वि.सू. श्रेणी	2007–2011[c]	2010	2007–2011[c]	2010	2010	2007–2011[c]	2010	2010	2005/2010[d]	2010	2005–2010[c]	2005–2010[c]
176 गिनी बिसाउ	1.1	16.7	1.4	5.76	2.03	22.6	6.8	1.2	–1.4	30	..	..
177 सिएरा लिओन	4.5	24.4	36.9	3.01	0.31	19.6	4.6	1.8	2.2	39	..	..
178 बुरुण्डी	0.0	31.0	0.1	1.39	0.06	12.6	4.2	0.7	9.5	201	..	..
178 गिनी	2.1	5.1	22.7	1.28	0.92	..	5.2	3.8	–6.3	30[i]	..	..
180 मध्य अफ्रीकी गणराज्य	3.6	13.2	..	..	..	7.1	2.9	1.8	0.2	52	5.5	6.6
181 इरिट्रिया	2.6	7.7	..	..	..	4.4	18.0	0.3	2.3	84	22.9	1.7
182 माली	1.6	12.1	–0.6	4.63	1.77	13.0	7.6	1.2	–1.4	169	8.8	14.1
183 बुर्किना फ़ासो	0.4	12.0	0.4	1.08	1.13	9.4	9.7	6.4	–1.6	274	..	..
184 चाड	9.1	6.2	..	..	..	10.0	2.1	3.4	–1.4	31	..	..
185 मोज़ाम्बीक	8.6	21.4	16.1	1.43	0.87	19.3	5.0	1.9	–0.2	2,224	5.9	2.6
186 कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	22.4	29.0	..	..	..	8.1	1.3	0.7	–0.1	53	3.9	3.1
186 नाइजर	17.5	13.8	13.4	1.63	0.41	11.2	2.4	1.3	–0.4	66	..	..
अन्य देश अथवा अंचल												
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	..	..	..	..	..	..	1.3	0.2	0.0	..	..	..
मार्शल द्वीप समूह	5.3	45.9	..	..	..	..	16.6	2.7	..	5	..	..
मोनाको	..	..	..	..	..	..	56.3	71.6	..	279	..	..
नाउरू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
सैन मैरीनो	..	..	..	..	..	1.2	9.9	37.0	..	120	..	..
सोमालिया	..	..	..	..	..	20.7	8.7	0.2	–6.8	..	..	..
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
तुवालू	4.8	26.2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह												
अति उच्च मानव विकास	2.7	..	0.9	0.31	0.50	7.8	3.6	11.3	4.0	534,968	..	189.8
उच्च मानव विकास	2.7	0.2	2.2	0.99	1.25	23.2	6.7	4.5	–0.3	199,071	62.5	24.9
मध्यम मानव विकास	2.8	0.2	2.8	1.81	0.13	33.8	1.6	0.7	–0.6	163,618	..	..
निम्न मानव विकास	2.3	5.5	1.9	4.91	0.46	13.6	2.8	1.6	–1.5	19,020	..	..
क्षेत्र												
अरब देश	2.4	..	0.5	2.29	3.76	43.7	5.4	8.0	3.3	76,540	..	..
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	3.1	0.1	..	..	..	40.3	1.1	0.3	–0.5	116,484	..	..
यूरोप एवं मध्य एशिया	3.4	..	1.8	1.22	0.81	19.4	10.3	6.5	–0.1	149,901	90.3	49.2
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	2.7	0.2	3.7	1.15	0.12	13.1	5.3	1.1	–1.8	66,379	101.7	23.9
दक्षिण एशिया	1.3	0.7	2.6	3.60	0.23	14.0	1.6	0.8	–1.1	11,008	19.5	..
सब-सहारा अफ्रीका	2.7	3.8	2.8	1.99	0.52	15.0	2.5	2.1	–0.5	30,141	..	..
न्यूनतम विकसित देश	2.4	8.3	1.5	5.09	..	14.8	3.3	1.4	–1.4	16,915	..	..
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	2.7	3.4	5.0	6.13	1.05	16.7	12.5	1.8	–3.5	15,782	..	..
विश्व	**2.7**	**0.0**	**1.4**	**0.76**	**0.53**	**14.7**	**2.9**	**3.1**	**0.0**	**917,082**	**..**	**..**

नोट

a नकारात्मक मान दानदाता देशों की शुद्ध आधिकारिक विकास सहायता से संबद्ध है।

b कुछ मान 100% से अधिक हो सकते हैं (देखें परिभाषाएँ)।

c अँकडें दी गई अवधि के लिए सबसे हाल के वर्ष के लिए उपलब्ध आंकड़े हैं।

d 2005-2010 के लिए औसत वार्षिक प्राक्कलन के आँकडे।

e 2009 से सम्बद्ध।

f 2007 से सम्बद्ध।

g 2006 से सम्बद्ध।

h 2008 से सम्बद्ध।

परिभाषाएँ

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शुद्ध आतंरिक प्रवाह: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित इक्विटी पूँजी, आय के पुनर्निवेश, अन्य दीर्घ कालिक पूँजी तथा अल्प कालिक पूँजी का योग।

प्राप्त शुद्ध आधिकारिक सहायता: प्राप्तकर्ता देश की सकल घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित आधिकारिक संस्थाओं द्वारा विकास सहायता कमिटी की सूची 1 के सहायता पाने वाले देशों तथा क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती दरों पर दिया गया ऋण (मूल के भुगतान का शुद्ध) और अनुदान।

निजी पूँजी प्रवाह : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश।

प्रवासयों द्वारा भेजी रकम का अंतर्प्रवाह : अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों तथा शरणार्थियों द्वारा अपने पहले के निवास देश के या मूल देश के प्राप्तकर्ताओं को भेजी गई आय तथा भौतिक संसाधन।

घर भेजी गई रकम का बाह्य प्रवाह: प्रवासी कामगारों द्वारा किए गए अंतरण और आप्रवासी कामगारों द्वारा अर्जित किए गए मजदूरी और तनख्वाहें, घर भेजी गयी रकम (remittances) देश के भीतर एक साल से अधिक समय से रह रहे प्रवासी कामगारों के, चाहे उनकी प्रवास की अवस्थिति जो भी हो, अपने मूल देश को किए गए वर्तमान निजी अंतरण के रूप में परिभाषित की जाती है। प्रवासी अंतरण उन प्रवासियों के एक देश से दूसरे देश में उनकी कुल सम्पदा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनके मेजबान देश में एक वर्ष या अधिक रहने की संभावना हो। कर्मचारियों का मुआवजा उन प्रवासियों की आय है जो देश में एक साल से कम समय रहे हों। आँकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किये जाते हैं.

मुद्रा भंडार, स्वर्ण घटाकर : विशेष निकास अधिकारों, अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों द्वारा नियंत्रित निधि और मौद्रिक अधिकारियों के नियंत्रण में कुल विदेशी मुद्रा का योग जिसमें स्वर्ण निधि शामिल नहीं हैं, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

प्रवासियों की संख्या : किसी देश से आए प्रवासियों की संख्या का उसकी जनसंख्या से अनुपात (जनसंख्या और प्रवासियों की संख्या का योग का नहीं), देश की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित। प्रवासी की परिभाषा अलग-अलग देशों में अलग अलग है, लेकिन आमतौर पर यह निवासियों की उस संख्या को संदर्भित करती है जिन्होंने एक साल से अधिक समय तक विदेश में रहने के उद्देश्य से देश छोड़ा है।

आप्रवासियों की संख्या : देश के भीतर आप्रवासियों के स्टाक का अनुपात, देश की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित। आप्रवासी की परिभाषा अलग-अलग देशों में अलग-अलग है लेकिन आम तौर पर विदेशों में जन्मे लोगों की संख्या या विदेशी लोगों (नागरिकता के अनुसार) की संख्या या दोनों का मिश्रण इसमें शामिल होता है।

शुद्ध प्रवास दर : एक निश्चित समयावधि में देश के भीतर आने वाले तथा देश से बाहर जाने वाले कुल प्रवासियों के अंतर तथा उस अवधि की औसत जनसंख्या का अनुपात, प्रति 1000 लोगों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय अंतर्गामी पर्यटन : राष्ट्रीय सीमाओं में ग़ैर-नागरिक आगंतुकों का आगमन (रात भर के आगंतुक, पर्यटक, उसी दिन लौटने वाले आगंतुक, घुमक्कड़)।

अंतरराष्ट्रीय टेलीफ़ोन ट्रैफ़िक, आने वाली काल : प्रभावी (पूर्ण की गई) टेलीफोन कॉलें (फिक्स और मोबाइल) जो एक देश विशेष के बाहर से की जाती हैं और जिनका गंतव्य देश के भीतर होता है, प्रति व्यक्ति ट्रैफ़िक मिनट के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं।

अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन ट्रैफ़िक, की गई कॉल : प्रभावी (पूर्ण की गई) टेलीफोन कॉल (फिक्स और मोबाइल) जो एक देश विशेष के भीतर से की जाती हैं और जिनका गंतव्य देश के बाहर होता है, प्रति व्यक्ति ट्रैफ़िक मिनट के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1, 3-6: विश्व बैंक (2012**a**)।

कॉलम 2 : विश्व बैंक (2012**a**) और ओ.ई.सी.डी-डी.ए.सी (2012)।

कॉलम 7 : विश्व बैंक (2011) तथा एन.डी.ई.एस.ए. (2011) के आँकड़ों पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

कॉलम 8: विश्व बैंक (2011) के आंकड़ों और विश्व बैंक के जनसंख्या आँकड़ों (2012**a**) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

कॉलम 9: एन.डी.ई.एस.ए. (2011)।

कॉलम 10: संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन (2012)।

कॉलम 11 और 12: आई.टी.यू.(2012) की आने वाली तथा की गई कुल टेलीफोन कालों के आँकड़ों पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

सारणी 12 नवाचार और प्रौद्योगिकी

		शोध और विकास			नवाचार		प्रौद्योगिकी अंगीकरण				
		व्यय	शोधकर्ता	विज्ञान और अभियांत्रिकी में स्नातक[a]	निवासियों और अनिवासियों को मिले पेटेंट	रॉयल्टी और लायसेंस शुल्क प्राप्तियाँ	विद्युतीकरण दर	वैयक्तिक कम्प्यूटर	इंटरनेट उपयोगकर्ता	फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहक	फिक्स्ड और मोबाइल टेलीफोन ग्राहक
		(स.घ.उ. का %)	(प्रति मिलियन व्यक्ति)	(कुल का %)	(प्रति मिलियन व्यक्ति)	(डॉलर प्रति व्यक्ति)	(आबादी का %)	(प्रति 100 व्यक्ति)			
मा.वि.सू. श्रेणी		2005–2010[b]	2002–2010[b]	2002–2011[b]	2005–2010[b]	2005–2011[b]	2009	2002–2009[b]	2010	2010	2010
अति उच्च मानव विकास											
1	नार्वे	1.8	5,503.7	15.3	334.0	101.9	99.7[c]	62.9	93.3	35.3	149.3
2	ऑस्ट्रेलिया	2.3	4,258.5	18.1	653.7	32.7	99.7[c]	60.3	75.9	24.2	139.7
3	यूनाइटेड स्टेट्स	2.8	4,673.2	15.5	707.6	387.1	99.7[c]	80.6	74.2	27.6	139.0
4	नीदरलैंड	1.8	2,817.6	14.0	117.6	320.8	99.7[c]	91.2	90.7	38.1	158.9
5	जर्मनी	2.8	3,780.1	28.6	166.2	174.9	99.7[c]	65.6	82.5	31.7	183.7
6	न्यूज़ीलैंड	1.2	4,323.7	20.5	995.2	53.5	99.7[c]	52.6	83.0	24.9	157.7
7	आयरलैंड	1.8	3,372.5	21.6	54.4	574.2	99.7[c]	58.2	69.8	21.1	151.5
7	स्वीडन	3.6	5,017.6	25.0	147.1	619.4	99.7[c]	88.1	90.0	31.8	168.6
9	स्विटजरलैंड	3.0	3,319.8	21.6	96.7	..	99.7[c]	96.2	82.2	37.9	177.7
10	जापान	3.4	5,189.3	20.6	1,759.9	226.8	99.7[c]	40.7	77.6	26.9	126.4
11	कनाडा	2.0	4,334.7	21.1	562.1	114.4	99.7[c]	94.5	81.3	29.8	120.3
12	कोरिआ गणराज्य	3.4	4,946.9	31.5	1,428.8	86.8	99.7[c]	57.6	82.5	35.7	162.3
13	हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	0.8	2,759.5	34.7	758.9	56.6	99.7[c]	69.3	71.8	29.9	256.9
13	आइसलैंड	2.6	7,428.1	14.5	434.2	0.1	99.7[c]	52.7	95.6	34.1	168.1
15	डेनमार्क	3.0	6,390.3	19.6	27.9	..	99.7[c]	54.9	88.8	37.7	172.2
16	इस्राइल	4.3	..	..	502.0	137.3	99.7	24.2	65.4	25.1	172.5
17	बेल्जियम	2.0	3,490.7	16.3	49.7	232.1	99.7[c]	37.7	73.7	31.5	154.1
18	ऑस्ट्रिया	2.7	4,122.1	28.8	134.6	92.6	99.7[c]	60.7	72.7	23.9	184.6
18	सिंगापुर	2.7	5,834.0	..	873.3	367.7	100.0	74.3	71.1	24.9	184.8
20	फ्रांस	2.2	3,689.8	26.2	157.7	240.0	99.7[c]	63.1	77.5	34.0	151.8
21	फ़िनलैंड	3.8	7,647.4	29.4	172.1	556.5	99.7[c]	50.0	86.9	28.6	179.7
21	स्लोवेनिया	1.9	3,678.8	18.2	123.2	42.7	99.7[c]	42.5	69.3	24.2	148.0
23	स्पेन	1.4	2,931.8	25.3	60.2	23.0	99.7[c]	39.3	65.8	22.9	155.9
24	लिख्टेन्स्टाइन	..	..	19.8	..	..	99.7[c]	..	80.0	63.8	152.9
25	इटली	1.3	1,690.0	20.5	303.4	59.8	99.7[c]	36.7	53.7	21.9	185.3
26	लक्ज़मबर्ग	1.7	4,824.8	32.5	171.4	890.0	99.7[c]	67.3	90.1	33.2	197.1
26	यूनाइटेड किंगडम	1.8	3,794.2	21.7	90.2	226.3	99.7[c]	80.2	84.7	31.6	184.0
28	चेक गणराज्य	1.5	2,754.8	23.8	86.8	10.2	99.7[c]	27.4	68.6	14.5	159.7
29	यूनान	0.6	1,849.5	24.9	42.2	6.1	99.7[c]	9.4	44.6	19.9	154.6
30	ब्रूनेई दारस्सलाम	..	286.3	21.9	107.2	..	99.7[c]	9.1	50.0	5.4	129.1
31	साइप्रस	0.5	752.0	13.7	17.2	2.1	99.7[c]	30.9	53.0	17.6	131.2
32	माल्टा	0.6	1,168.1	15.0	9.6	81.0	..	..	63.1	28.0	169.2
33	अंडोरा	..	..	..	..	..	99.7[c]	..	81.0	28.9	122.2
33	एस्टोनिआ	1.4	3,210.3	19.4	89.5	16.9	99.7[c]	25.5	74.2	25.1	159.3
35	स्लोवाकिआ	0.5	2,437.7	20.6	68.8	0.7	99.7[c]	58.1	79.9	12.7	129.4
36	कतर	..	..	24.0	..	..	98.7	16.0	81.6	8.2	149.4
37	हंगरी	1.1	2,005.9	15.1	6.5	102.8	99.7[c]	25.6	65.2	19.6	149.9
38	बारबाडोस	..	..	8.7	..	12.6	99.7[c]	14.8	70.0	20.6	177.9
39	पोलैण्ड	0.7	1,597.5	15.7	78.5	7.1	99.7[c]	16.9	62.5	13.0	143.0
40	चिली	0.4	354.8	20.4	59.6	3.7	98.5	14.1	45.0	10.5	136.2
41	लिथुएनिया	0.8	2,541.1	21.0	25.3	0.2	99.7[c]	24.2	62.8	20.6	171.1
41	संयुक्त अरब अमीरात	..	..	27.3	..	..	100.0	30.0	78.0	10.5	165.1
43	पुर्तगाल	1.7	4,307.8	33.8	13.1	5.7	99.7[c]	18.2	51.3	19.2	185.0
44	लातीविया	0.5	1,601.2	14.3	81.7	4.5	99.7[c]	32.7	71.5	19.3	126.8
45	अर्जेंटीना	0.5	1,045.5	14.3	30.6	4.7	97.2	9.0	36.0	9.6	166.5
46	सेशेल्स	0.3	155.7	..	..	21.6	99.7[c]	21.2	40.8	7.3	160.5
47	क्रोएशिया	0.8	1,571.3	24.4	18.6	5.3	99.7[c]	18.0	60.1	18.3	186.2
उच्च मानव विकास											
48	बहरीन	..	..	..	..	..	99.4	55.0	55.0	5.4	142.2
49	बहामास	..	..	..	..	..	..	12.5	43.0	7.2	162.6
50	बेलारूस	0.6	..	26.6	127.4	2.1	..	..	32.1	17.4	152.5
51	उरुग्वे	0.7	346.1	13.6	8.6	0.1	98.3	13.6	47.9	10.9	160.8
52	मॉन्टीनेग्रो	1.1	..	..	418.1	..	..	..	52.0	8.3	211.9
52	पलाउ	..	..	..	..	..	..	..	..	1.2	105.0
54	कुवैत	0.1	151.9	..	..	..	100.0	26.5	38.3	1.7	181.5
55	रूसी गणराज्य	1.3	3,091.4	28.1	212.1	6.1	..	13.3	43.4	11.0	199.4
56	रोमानिया	0.5	894.8	21.7	20.8	13.7	..	19.2	40.0	13.9	135.9
57	बुल्गारिया	0.5	1,586.7	18.8	33.5	2.5	..	11.0	46.0	14.5	164.9
57	सऊदी अरब	0.1	..	35.8	7.1	..	99.0	65.7	41.0	5.5	203.0

	शोध और विकास			नवाचार		प्रौद्योगिकी अंगीकरण				
	व्यय	शोधकर्ता	विज्ञान और अभियांत्रिकी में स्नातक[a]	निवासियों और अनिवासियों को मिले पेटेंट	रॉयल्टी और लायसेंस शुल्क प्राप्तियाँ	विद्युतीकरण दर	वैयक्तिक कम्प्यूटर	इंटरनेट उपयोगकर्ता	फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहक	फिक्स्ड और मोबाइल टेलीफोन ग्राहक
	(स.घ.उ. का %)	(प्रति मिलियन व्यक्ति)	(कुल का %)	(प्रति मिलियन व्यक्ति)	(डॉलर प्रति व्यक्ति)	(आबादी का %)	(प्रति 100 व्यक्ति)			
मा.वि.सू. श्रेणी	2005–2010[b]	2002–2010[b]	2002–2011[b]	2005–2010[b]	2005–2011[b]	2009	2002–2009[b]	2010	2010	2010
59 क्यूबा	0.5	..	3.3	12.4	..	97.0	5.6	15.9	0.0	19.2
59 पनामा	0.2	111.3	19.2	107.5	..	88.1	6.3	42.7	7.8	200.4
61 मैक्सिको	0.4	347.3	25.6	82.9	..	..	13.9	31.1	10.0	98.1
62 कोस्टा रिका	0.4	257.4	11.9	9.7	0.9	99.3	23.2	36.5	6.2	96.9
63 ग्रेनाडा	..	..	..	..	0.7	..	15.6	33.6	13.8	144.5
64 लीबिया	..	..	..	..	..	99.8	2.3	14.0	1.1	190.8
64 मलेशिया	0.6	364.6	37.7	76.7	9.5	99.4	22.7	56.3	7.3	135.3
64 सर्बिया	0.9	1,060.1	23.7	43.3	7.8	..	17.6	43.1	11.2	178.7
67 एंटिगुआ और बरबूडा	..	..	..	104.7	..	..	20.6	80.6	8.0	232.2
67 त्रिनिडाड टोबैगो	0.0	..	30.4	67.6	..	99.0	13.2	48.5	10.8	163.1
69 कज़ाकिस्तान	0.2	..	..	10.9	0.0	..	..	33.4	8.9	143.7
70 अल्बानिआ	0.2	146.8	6.1	108.9	4.1	..	4.6	45.0	3.3	152.3
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	..	182.6	..	..	..	99.0	9.3	35.9	5.4	121.3
72 डोमिनिका	..	..	..	..	0.2	..	18.8	47.3	13.9	178.0
72 जॉर्जिआ	0.2	..	8.2	59.3	1.0	..	5.4	26.3	5.8	114.2
72 लेबनान	..	..	25.0	..	1.7	99.9	10.3	31.0	4.7	89.0
72 सेंट किट्स एवं नेविस	..	..	..	..	..	..	22.7	76.6	27.9	191.9
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	0.8	750.7	44.4	63.9	..	98.4	10.5	13.0	0.7	127.5
77 पेरु	..	..	..	12.6	0.1	85.7	10.2	34.3	3.1	111.0
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	0.2	471.6	21.4	163.7	4.7	..	36.6	51.9	12.5	124.6
78 यूक्रेन	0.9	1,353.1	26.3	85.2	2.3	..	4.5	44.6	6.5	145.8
80 मॉरिशस	0.4	..	..	6.2	1.7	99.4	17.6	28.7	6.1	123.2
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	0.0	197.2	..	46.0	3.4	..	6.4	52.0	8.2	109.3
82 अज़रबैजान	0.3	..	16.6	22.9	0.0	..	8.0	46.7	5.0	117.1
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	..	..	..	..	..	..	15.2	..	11.4	140.8
84 ओमान	..	..	38.9	..	..	98.0	18.0	62.0	1.6	175.6
85 ब्राज़ील	1.1	695.7	12.2	16.7	3.0	98.3	16.1	40.7	6.8	125.7
85 जमैका	..	..	..	15.9	1.8	92.0	6.8	26.5	4.3	127.5
87 अर्मेनिआ	0.3	..	15.9	40.1	..	..	9.7	44.0	2.8	144.2
88 सेंट लूसिआ	..	..	..	203.6	..	..	16.0	40.1	11.6	135.9
89 इक्वाडोर	0.3	106.1	12.8	1.9	..	92.2	12.5	29.0	1.4	116.6
90 तुर्की	0.8	803.9	20.9	9.0	..	..	6.4	39.8	9.7	107.2
91 कोलम्बिया	0.2	157.2	23.2	13.8	1.3	93.6	11.2	36.5	5.6	111.6
92 श्रीलंका	0.1	96.3	..	24.2	..	76.6	3.7	12.0	1.1	100.4
93 अल्जीरिया	0.1	170.1	28.0	6.3	0.1	99.3	1.1	12.5	2.5	100.7
94 ट्यूनीशिया	1.1	1,862.5	..	..	2.4	99.5	9.7	36.6	4.6	117.6
मध्यम मानव विकास										
95 टोंगा	..	..	..	..	..	..	5.9	12.0	1.0	82.0
96 बेलीज़	..	..	..	24.4	7.0	..	14.4	12.6	2.9	65.1
96 डोमीनिकन गणराज्य	..	..	..	..	..	95.9	2.2	39.5	3.6	99.8
96 फ़िजी	..	..	..	..	0.6	..	6.1	14.8	2.7	96.3
96 सामोआ	..	..	..	60.7	..	..	2.3	7.0	0.1	110.2
100 जॉर्डन	0.4	..	25.1	10.3	..	99.9	7.6	38.9	3.2	117.5
101 चीन	1.5	1,198.9	..	100.7	0.6	99.4	5.7	34.4	9.4	86.2
102 तुर्कमेनिस्तान	..	..	..	..	..	..	7.3	2.2	0.0	73.7
103 थाइलैंड	0.2	315.5	..	11.2	2.2	99.3	6.6	21.2	4.6	113.6
104 माल्दीव	..	..	..	..	26.5	..	20.0	28.3	4.8	171.6
105 सूरीनाम	..	..	..	..	1.3	..	4.0	31.6	3.0	185.7
106 गैबन	0.6	..	..	..	..	36.7	3.4	7.2	0.3	109.0
107 अल सल्वाडोर	0.1	..	26.4	..	0.0	86.4	5.8	15.9	2.8	140.5
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	..	120.3	..	..	0.7	77.5	2.4	20.0	1.0	80.8
108 मंगोलिया	0.2	..	17.1	34.8	0.8	67.0	25.8	12.9	2.6	98.1
110 फ़लस्तीन राज्य	..	144.3	16.5	..	1.4	..	5.5	36.4	..	..
111 पराग्वे	0.1	74.8	..	..	45.2	96.7	7.8	19.8	0.4	97.3
112 मिस्र	0.2	420.4	..	4.0	1.6	99.6	4.1	26.7	1.8	99.0
113 माल्डोवा गणराज्य	0.5	794.1	..	36.9	1.5	..	11.8	40.1	7.5	121.5
114 फ़िलीपीन्स	0.1	78.5	23.8	3.8	0.1	89.7	7.2	25.0	1.8	92.9
114 उज़्बेकिस्तान	..	..	21.1	7.0	..	..	3.1	19.4	0.3	80.8
116 सीरियाई अरब गणराज्य	..	..	..	2.4	0.1	92.7	9.4	20.7	0.3	77.6
117 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	..	..	..	..	..	..	5.5	20.0	0.9	32.4

	शोध और विकास			नवाचार		प्रौद्योगिकी अंगीकरण				
	व्यय	शोधकर्ता	विज्ञान और अभियांत्रिकी में स्नातक[a]	निवासियों और अनिवासियों को मिले पेटेंट	रॉयल्टी और लायसेंस शुल्क प्राप्तियाँ	विद्युतीकरण दर	वैयक्तिक कम्प्यूटर	इंटरनेट उपयोगकर्ता	फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहक	फिक्स्ड और मोबाइल टेलीफोन ग्राहक
	(स.घ.उ. का %)	(प्रति मिलियन व्यक्ति)	(कुल का %)	(प्रति मिलियन व्यक्ति)	(डॉलर प्रति व्यक्ति)	(आबादी का %)	(प्रति 100 व्यक्ति)			
मा.वि.सू. श्रेणी	2005–2010[b]	2002–2010[b]	2002–2011[b]	2005–2010[b]	2005–2011[b]	2009	2002–2009[b]	2010	2010	2010
118 गुयाना	..	..	14.4	..	62.2	..	3.6	29.9	1.5	93.4
119 बोत्स्वाना	0.5	..	13.0	..	0.1	45.4	6.1	6.0	0.6	124.6
120 होण्डुरास	..	..	6.8	..	..	70.3	2.5	11.1	1.0	133.9
121 इण्डोनेशिया	0.1	89.6	22.8	..	0.3	64.5	2.0	9.9	0.8	107.5
121 किरिबाती	..	..	..	..	..	..	1.1	9.0	0.9	14.1
121 दक्षिण अफ्रीका	0.9	395.6	..	106.3	1.3	75.0	8.4	12.3	1.5	109.2
124 वनुआतू	..	..	..	..	0.7	..	1.4	8.0	0.2	121.0
125 किर्गिस्तान	0.2	..	15.2	20.4	0.3	..	1.9	19.6	0.3	105.8
125 ताजिकिस्तान	0.1	..	26.0	0.4	0.1	..	1.3	11.5	0.1	91.7
127 वियतनाम	..	115.9	..	9.4	..	97.6	9.7	27.9	4.1	196.0
128 नामीबिया	..	..	2.6	..	0.0	34.0	23.2	6.5	0.4	73.9
129 निकारागुआ	..	..	..	..	..	72.1	4.1	10.0	0.8	69.6
130 मोरक्को	0.6	661.0	34.9	25.3	0.2	97.0	5.7	49.0	1.6	111.8
131 इराक	..	49.5	29.4	..	43.5	86.0	0.8	2.5	0.0	79.9
132 केप वर्दे	..	132.5	..	..	0.0	..	14.3	30.0	3.2	89.5
133 ग्वाटेमाला	0.1	39.4	16.8	7.2	1.0	80.5	2.1	10.5	1.8	136.0
134 टिमोर लेस्ट	..	..	..	..	..	22.0	..	0.2	0.0	53.7
135 घाना	0.2	17.3	16.7	..	..	60.5	1.1	9.5	0.2	72.6
136 इक्वेटोरिअल गिनी	..	..	..	..	..	..	1.5	6.0	0.2	59.0
136 भारत	0.8	135.8	..	5.1	0.1	75.0	3.2	7.5	0.9	64.3
138 कम्बोडिया	..	17.4	12.5	..	0.0	24.0	0.4	1.3	0.3	60.2
138 लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	..	15.8	12.8	..	..	55.0	1.7	7.0	0.2	66.2
140 भूटान	..	..	..	..	..	..	1.9	13.6	1.2	57.9
141 स्वाज़ीलैण्ड	..	..	2.7	..	0.2	..	4.1	9.0	0.1	73.6
निम्न मानव विकास										
142 काँगो	..	..	..	..	..	37.1	0.5	5.0	0.0	94.2
143 सॉलोमन द्वीपसमूह	..	..	..	..	0.0	..	4.7	5.0	0.4	7.1
144 साओ टोम एवं प्रिन्साइप	..	..	..	..	..	..	3.9	18.8	0.4	66.8
145 केन्या	0.4	56.2	..	0.5	1.3	16.1	1.4	25.9	0.0	62.6
146 बांग्लादेश	..	..	10.6	0.6	0.0	41.0	2.5	3.7	0.0	46.8
146 पाकिस्तान	0.5	161.9	..	1.0	0.0	62.4	0.5	16.8	0.3	59.1
148 अंगोला	..	..	11.9	..	0.7	26.2	0.7	10.0	0.1	48.3
149 म्याँमार	..	18.4	..	..	..	13.0	1.0	..	0.0	2.5
150 कैमरून	..	..	21.0	..	0.0	48.7	1.1	4.0	0.0	46.8
151 मैडागास्कर	0.1	46.2	18.2	2.7	0.1	19.0	0.6	1.7	0.0	37.9
152 तंज़ानिया गणराज्य	0.4	..	21.1	..	0.0	13.9	0.9	11.0	0.0	47.2
153 नाइजीरिया	0.2	38.6	..	..	..	50.6	0.9	28.4	0.1	55.8
154 सेनेगल	0.4	384.1	..	..	0.1	42.0	2.3	16.0	0.6	69.9
155 मॉरिटानिया	..	..	..	..	..	..	4.4	3.0	0.2	81.4
156 पापुआ न्यू गिनी	..	..	..	0.2	..	..	6.4	1.3	0.1	29.6
157 नेपाल	..	58.7	23.2	0.0	..	43.6	0.5	7.9	0.2	33.5
158 लेसोथो	0.0	21.3	..	..	..	16.0	0.2	3.9	0.0	47.3
159 टोगो	..	38.2	..	..	0.0	20.0	3.4	5.4	0.1	44.2
160 यमन	..	..	..	..	1.4	39.6	2.8	12.3	0.3	50.4
161 हैती	..	..	..	..	..	38.5	5.2	8.4	..	40.5
161 युगाण्डा	0.4	..	9.5	..	0.8	9.0	1.7	12.5	0.2	39.4
163 ज़ाम्बिया	0.3	43.3	..	..	..	18.8	1.1	10.1	0.1	42.8
164 जिबूती	..	..	46.5	..	..	..	4.2	6.5	0.9	20.7
165 गैम्बिया	0.0	..	..	4.4	..	..	3.6	9.2	0.0	88.3
166 बेनिन	..	..	..	..	0.0	24.8	0.7	3.1	0.0	81.5
167 रवाण्डा	..	11.9	..	2.1	0.0	..	0.3	13.0	0.0	33.8
168 आइवरी कोस्ट	..	70.4	..	..	0.0	47.3	1.8	2.6	0.0	77.6
169 कोमोरॉस	..	..	12.0	..	..	..	0.8	5.1	0.0	25.3
170 मलावी	..	29.9	..	..	..	9.0	0.2	2.3	0.0	21.5
171 सूडान	0.3	..	..	4.4	0.1	35.9	10.8	..	0.4	41.4
172 ज़िम्बाब्वे	..	..	24.8	..	..	41.5	7.6	11.5	0.3	64.3
173 इथियोपिया	0.2	20.8	20.9	0.2	0.0	17.0	0.7	0.7	0.0	9.4
174 लाइबेरिया	..	..	..	..	..	..	..	7.0	0.0	39.5
175 अफ़गानिस्तान	..	..	..	..	..	15.5	0.3	3.7	0.0	38.2
176 गिनी बिसाउ	..	..	..	..	..	..	0.2	2.5	..	39.5

	शोध और विकास			नवाचार		प्रौद्योगिकी अंगीकरण				
	व्यय	शोधकर्ता	विज्ञान और अभियांत्रिकी में स्नातक[a]	निवासियों और अनिवासियों को मिले पेटेंट	रॉयल्टी और लायसेंस शुल्क प्राप्तियाँ	विद्युतीकरण दर	वैयक्तिक कम्प्यूटर	इंटरनेट उपयोगकर्ता	फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहक	फिक्स्ड और मोबाइल टेलीफोन ग्राहक
	(स.घ.उ. का %)	(प्रति मिलियन व्यक्ति)	(कुल का %)	(प्रति मिलियन व्यक्ति)	(डॉलर प्रति व्यक्ति)	(आबादी का %)	(प्रति 100 व्यक्ति)			
मा.वि.सू. श्रेणी	2005–2010[b]	2002–2010[b]	2002–2011[b]	2005–2010[b]	2005–2011[b]	2009	2002–2009[b]	2010	2010	2010
177 सिएरा लिओन	..	..	..	..	0.2	..	..	..	..	34.3
178 बुरुण्डी	..	..	9.6	..	0.0	..	0.9	2.1	0.0	14.1
178 गिनी	..	..	..	..	0.0	..	0.5	1.0	0.0	40.3
180 मध्य अफ्रीकी गणराज्य	..	..	..	..	..	..	0.3	2.3	..	22.4
181 इरिट्रिया	..	..	7.9	..	..	32.0	1.0	5.4	0.0	4.6
182 माली	0.2	37.7	..	..	0.0	..	0.7	2.7	0.0	49.2
183 बुर्किना फ़ासो	0.2	45.1	23.3	..	0.0	14.6	0.6	1.4	0.1	35.5
184 चाड	..	..	..	..	..	..	0.2	1.7	0.0	24.3
185 मोज़ाम्बीक	0.2	15.8	12.1	1.8	0.0	11.7	1.4	4.2	0.1	31.3
186 कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	0.5	..	..	..	..	11.1	0.0	0.7	0.0	18.0
186 नाइजर	..	7.8	..	..	0.0	..	0.1	0.8	0.0	25.1
अन्य देश अथवा अंचल										
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	..	..	..	258.4	..	26.0	..	..	..	6.6
मार्शल द्वीप समूह	..	..	..	..	..	..	9.6	..	..	15.2
मोनाको	0.0	308.1	..	141.2	..	..	..	..	..	..
नाउरू	..	..	..	..	..	..	..	..	3.9	..
सैन मैरीनो	..	..	..	..	..	..	78.9	..	32.0	144.9
सोमालिया	..	..	..	..	..	..	0.9	..	..	8.0
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
तुवालू	..	..	..	..	..	..	8.7	25.0	3.3	41.9
मानव विकास सूचकांक समूह										
अति उच्च मानव विकास	2.5	3,854.0	20.3	566.2	210.9	99.6	58.3	72.8	26.5	153.2
उच्च मानव विकास	0.8	..	..	63.4	..	..	13.6	35.8	7.1	133.5
मध्यम मानव विकास	..	..	..	..	..	..	4.6	20.8	4.4	84.5
निम्न मानव विकास	..	..	..	..	..	..	1.5	10.7	0.1	42.7
क्षेत्र										
अरब देश	..	..	..	..	..	86.7	10.8	27.2	2.0	99.6
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	..	..	..	..	..	..	5.6	29.8	7.2	92.2
यूरोप एवं मध्य एशिया	1.0	1,948.2	23.9	93.8	8.2	..	12.3	43.4	10.0	150.0
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	..	..	..	..	..	93.4	12.2	34.1	6.6	116.7
दक्षिण एशिया	..	..	..	7.0	..	70.1	3.0	8.4	0.7	64.4
सब-सहारा अफ्रीका	..	..	..	..	..	..	1.6	11.3	0.2	47.1
न्यूनतम विकसित देश	..	..	..	..	..	..	1.7	4.8	0.1	34.5
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	..	..	..	..	..	..	5.6	18.7	2.2	62.7
विश्व	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**14.1**	**30.0**	**7.7**	**95.2**

नोट

a विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र के स्नातक शामिल।

b आँकड़े निर्दिष्ट अवधि में अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए हैं।

c विद्युतीकरण दर के आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण, इसे 99.7 प्रतिशत माना गया है।

परिभाषाएँ

शोध और विकास व्ययः ज्ञान को बढ़ाने और नए अनुप्रयोगों के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए व्यवस्थित रूप से किए गए रचनात्मक कार्यों पर चालू और पूँजीगत व्यय (सार्वजनिक और निजी, दोनों)। इसमें सामान्य शोध, अनुप्रयुक्त शोध और प्रायोगिक विकास शामिल हैं।

शोध और विकास में शोधकर्ताः नए ज्ञान, उत्पाद, प्रक्रियाओं, पद्धतियों या प्रणालियों की अवधारणा या सृजन में, और परियोजनाओं के प्रबंधन में लगे पेशेवर। शोध और विकास में संलग्न परास्नातक डॉक्टरेट छात्र (आई.सी.एस.ई.डी.97 स्तर 6) शामिल हैं।

विज्ञान और अभियांत्रिकी में स्नातक : जिन लोगों ने विज्ञान और अभियांत्रिकी में शिक्षा के किसी स्तर या उपस्तर के अंतिम वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

निवासियों और अनिवासियों को जारी पेटेंटः प्रति एक मिलियन लोगों में ऐसे नवाचार के लिए जारी विशेष अधिकारों की संख्या, जो एक उत्पाद या प्रक्रिया हों और जो किसी काम को नए ढंग से करने का तरीका मुहैया कराएँ या किसी समस्या के लिए नए प्रौद्योगिकी समाधान प्रस्तुत करें।

रॉयल्टी और लायसेंस शुल्क प्राप्तियाँ : निवासियों और अनिवासियों द्वारा अमूर्त, गैर उत्पादन, गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों और मालिकाना अधिकार के अधिकृत इस्तेमाल (जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक प्रक्रिया और फ़ैंचाइज़ी) और मूल उत्पादों के प्रतिमान (जैसे फ़िल्म और पांडुलिपि) तैयार करने के लिए लाइसेंस समझौते के मद में किया गया भुगतान और प्राप्तियाँ।

विद्युतीकरण दरः कुल जनसंख्या के मुकाबले बिजली तक पहुँच रखने वाले लोगों की संख्या, प्रतिशत में। इसमें वाणिज्यिक रूप से खरीदी गई बिजली (ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड, दोनों) और स्वयं उत्पादित बिजली शामिल है, लेकिन अनाधिकृत कनेक्शन शामिल नहीं।

वैयक्तिक कम्प्यूटरः प्रति 100 लोगों पर ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास अकेले व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल के लिए तैयार कंप्यूटर है।

इंटरनेट उपयोगकर्ताः प्रति 100 लोगों में उन लोगों की संख्या जिनके पास वर्ल्ड वाईड नेटवर्क तक पहुँच है।

फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकः प्रति 100 लोगों में ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास ब्रॉडबैंड उच्च-गति वाले सार्वजनिक इंटरनेट (टी.सी.पी./आई.पी. कनेक्शन) तक पहुँच है, जिसकी गति एक या दोनों दिशाओं में 256 किलोबाईट प्रति सेकेण्ड के बराबर या अधिक है।

फिक्स्ड और मोबाइल टेलिफ़ोन ग्राहकः कुल टेलिफ़ोन लाइन और मोबाइल उपभोगता प्रति 100 व्यक्ति पर।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1 और 3: विश्व बैंक (2012**a**)।

कॉलम 3: यूनेस्को साख्यिकी संस्थान (2012)।

कॉलम 4: एच.डी.आर.ओ. गणना डब्ल्यू.आई.पी.ओ. (2012) और यू.एन.डी.ई.एस.ए. के जनसंख्या आँकड़ों (2011) पर आधारित हैं।

कॉलम 5: एच.डी.आर.ओ .गणना विश्व बैंक (2012**b**) के रॉयल्टी और लॉयसेंस शुल्क प्राप्तियों के आँकड़ों पर आधारित।

कॉलम 6: आई.ई.ए. (2012)।

कॉलम 7: विश्व बैंक (2012**c**)।

कॉलम 8 और 9: आई.टी.यू. (2012)

कॉलम 10: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ आई.टी.यू. (2012) के सेल्युलर ग्राहकों और टेलीफोन लाइनों से संबंधित आँकड़ों पर आधारित और जनसंख्या आँकड़े यू.एन.डी.ई.एस.ए.(2011) से।

सारणी 13 पर्यावरण

मा.वि.सू. श्रेणी	प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति: जीवाश्म ईंधन	प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति: अक्षय ऊर्जा	उत्सर्जन: कार्बन डाईऑक्साइड: कुल	उत्सर्जन: कार्बन डाईऑक्साइड: प्रति व्यक्ति		उत्सर्जन: ग्रीनहाउस गैस: प्रति व्यक्ति	प्राकृतिक संसाधन: प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास	प्राकृतिक संसाधन: वन क्षेत्र		प्राकृतिक संसाधन: ताजे पानी की निकासी	प्राकृतिक संसाधन: लुप्तप्राय प्रजातियाँ	प्राकृतिक संसाधन: कृषि भूमि	प्रभाव: प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु	प्रभाव: पड़ती भूमि पर रहने वाली आबादी
	(कुल का %)	(कुल का %)	(मेगाटन)	(टन)	(औसत वार्षिक वृद्धि %)	(कार्बन डाई ऑक्साइड के टन के समतुल्य)	(स.रा.आ का %)	(भूमि क्षेत्र का %)	(बदलाव %)	(कुल अक्षय जल संसाधनों का %)	(सभी प्रजातियों का %)	(भूमि क्षेत्र का %)	(प्रति मिलियन लोगों पर वार्षिक औसत)	(%)
	2009	2009	2008	2008	1970/2008	2005	2010	2010	1990/2010	2003–2012[a]	2011	2009	2005/2011	2010
अति उच्च मानव विकास														
1 नार्वे	58.8	43.3	50	10.5	1.0	5.8	10.2	33.1	10.2	0.8	6.9	3.3	0	..
2 ऑस्ट्रेलिया	94.4	5.6	399	18.6	1.2	9.6	6.5	19.4	–3.4	4.6	18.5	53.2	3	9.0
3 यूनाइटेड स्टेट्स	84.1	5.4	5,461	18.0	–0.4	3.7	0.9	33.2	2.6	15.6	19.9	44.1	1	1.0
4 नीदरलैंड	93.1	4.0	174	10.6	–0.1	2.4	0.8	10.8	5.8	11.7	5.4	56.8	12	5.0
5 जर्मनी	79.5	8.7	787	9.6	..	1.9	0.1	31.8	3.1	21.0	10.5	48.4	12	8.0
6 न्यूज़ीलैंड	63.7	36.1	33	7.8	1.1	10.0	..	30.9	7.1	1.5	20.4	43.6	0	5.0
7 आयरलैंड	95.0	4.5	44	9.9	1.1	5.8	0.2	10.7	58.9	1.5	7.3	60.8	0	..
7 स्वीडन	32.7	34.8	49	5.3	–2.0	2.1	0.4	68.7	3.4	1.5	4.9	7.5	0	..
9 स्विटजरलैंड	53.3	17.7	40	5.3	–0.6	1.2	0.0	31.0	7.7	4.9	6.6	38.1	14	..
10 जापान	81.0	3.3	1,208	9.5	0.7	1.0	0.0	68.5	0.1	20.9	13.7	12.6	1	..
11 कनाडा	74.9	16.9	544	16.3	0.1	4.7	2.3	34.1	0.0	1.6	7.2	7.4	0	3.0
12 कोरिआ गणराज्य	..	..	509	10.5	4.9	1.2	0.0	63.0	–2.3	36.5	9.5	19.1	1	3.0
13 हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	95.1	0.4	39	5.5	2.6	0.5	0.0	..	..	..	8.3	..	0	..
13 आइसलैंड	15.7	84.2	2	7.0	0.1	3.3	0.0	0.3	243.7	0.1	8.4	22.8	..	..
15 डेनमार्क	80.4	17.4	46	8.4	–1.1	2.9	1.7	12.8	22.3	10.8	6.3	62.1	0	9.0
16 इस्राइल	96.5	5.0	38	5.2	–0.2	1.1	0.2	7.1	16.7	101.9	11.2	24.1	1	13.0
17 बेल्जियम	73.6	3.9	105	9.8	–0.7	1.8	0.0	22.4	0.1	34.0	5.5	45.0	20	10.0
18 ऑस्ट्रिया	70.2	27.8	68	8.1	0.5	1.9	0.2	47.1	2.9	4.7	11.6	38.4	4	3.0
18 सिंगापुर	99.8	0.1	32	6.7	–0.7	1.4	0.0	3.3	0.0	31.7	13.7	1.0	..	..
20 फ्रांस	51.0	7.7	377	5.9	–1.0	2.3	0.0	29.0	9.8	15.0	12.8	53.4	33	4.0
21 फ़िनलैंड	54.0	23.8	57	10.6	0.5	3.4	0.1	72.9	1.2	1.5	4.4	7.6	0	..
21 स्लोवेनिया	69.3	12.7	17	8.5	..	2.6	0.3	62.2	5.5	3.0	11.8	23.2	15	8.0
23 स्पेन	79.9	9.6	329	7.2	2.0	1.7	0.0	36.4	31.5	29.0	17.7	55.5	33	1.0
24 लिख्टेन्स्टाइन	..	..	..	..	..	..	..	43.1	6.2	..	1.1	40.6	..	..
25 इटली	87.5	9.7	445	7.4	0.8	1.4	0.1	31.1	20.5	23.7	13.5	47.3	33	2.0
26 लक्ज़मबर्ग	88.8	3.1	11	21.5	–1.7	3.5	0.0	33.5	1.1	1.9	2.8	50.6	33	..
26 यूनाइटेड किंगडम	87.3	3.2	523	8.5	–0.8	1.8	1.3	11.9	10.3	8.8	10.1	71.6	1	3.0
28 चेक गणराज्य	79.6	5.8	117	11.2	..	2.1	0.5	34.4	1.1	14.8	5.0	54.9	5	4.0
29 यूनान	92.4	6.4	98	8.7	3.1	1.4	0.3	30.3	18.3	12.7	16.3	63.6	1	1.0
30 ब्रूनेई दारस्सलाम	100.0	0.0	11	27.5	–2.3	17.9	..	72.1	–8.0	1.1	8.4	2.2	..	..
31 साइप्रस	95.7	3.9	9	7.9	2.8	1.3	0.0	18.7	7.5	19.3	7.7	13.5	0	11.0
32 माल्टा	99.9	0.1	3	6.2	2.8	0.9	..	1.1	0.0	71.3	6.8	29.1	..	..
33 अंडोरा	..	..	1	6.5	..	..	..	35.6	0.0	..	3.7	38.3	..	..
33 एस्टोनिआ	84.8	15.1	18	13.6	..	2.3	1.6	52.3	6.1	14.0	3.5	22.0	0	5.0
35 स्लोवाकिआ	69.5	7.3	38	6.9	..	1.4	0.4	40.2	0.6	1.4	5.2	40.1	2	9.0
36 कतर	100.0	0.0	68	49.1	–0.9	18.0	..	0.0	0.0	455.2	7.3	5.6	..	..
37 हंगरी	74.2	7.4	55	5.4	–0.6	1.6	0.5	22.6	12.7	5.4	8.0	63.9	7	17.0
38 बारबाडोस	..	..	1	5.0	2.7	..	..	19.4	0.0	76.1	8.7	44.2	0	..
39 पोलैण्ड	92.8	6.7	316	8.3	–0.3	2.7	1.4	30.5	5.1	19.4	5.7	53.0	3	13.0
40 चिली	74.5	25.1	73	4.4	1.4	1.6	12.4	21.7	6.3	1.2	9.9	21.2	1	1.0
41 लिथुएनिया	55.8	10.4	15	4.5	..	2.5	0.6	34.5	11.1	9.6	4.1	42.9	1	5.0
41 संयुक्त अरब अमीरात	100.0	0.0	155	25.0	–2.5	6.2	..	3.8	29.5	2,032.0	7.7	6.8	..	2.0
43 पुर्तगाल	78.0	19.7	56	5.3	2.9	1.8	0.1	38.1	3.9	12.3	17.0	40.3	26	2.0
44 लातीविया	59.5	37.1	8	3.3	..	2.3	0.5	53.8	5.7	1.2	4.6	29.5	4	2.0
45 अर्जेंटीना	89.4	7.0	192	4.8	0.9	3.9	4.9	10.7	–15.5	4.0	9.0	51.3	0	2.0
46 सेशेल्स	..	..	1	7.8	7.3	..	0.0	88.5	0.0	..	16.1	6.5	0	..
47 क्रोएशिया	83.4	10.9	23	5.3	..	1.5	0.9	34.3	3.8	0.6	14.3	23.2	18	18.0
उच्च मानव विकास														
48 बहरीन	99.9	0.0	22	21.4	1.5	4.3	..	0.7	143.5	219.8	7.2	10.3	..	..
49 बहामास	..	..	2	6.5	–2.2	..	..	51.5	0.0	..	10.0	1.4	3	..
50 बेलारूस	92.5	5.0	63	6.5	..	2.4	1.0	41.6	10.9	7.5	4.2	44.0	0	5.0
51 उरुग्वे	60.3	37.1	8	2.5	0.5	8.1	0.6	10.0	89.6	2.6	10.8	84.6	1	6.0
52 मॉन्टीनेग्रो	..	..	2	3.1	..	..	..	40.4	0.0	..	10.5	38.2	0	8.0
52 पलाउ	..	..	0	10.5	–0.3	..	..	87.6	5.6	..	11.4	10.9	..	..
54 कुवैत	100.0	0.0	77	30.1	–0.3	6.3	..	0.4	81.2	2,465.0	7.4	8.5	..	1.0
55 रूसी गणराज्य	90.2	2.8	1,709	12.0	..	4.9	14.3	49.4	0.0	1.5	10.2	13.2	40	3.0
56 रोमानिया	76.3	15.3	95	4.4	–0.8	1.7	1.6	28.6	3.2	3.2	9.4	58.8	3	13.0
57 बुल्गारिया	73.1	6.2	51	6.6	–0.2	2.0	2.0	36.1	18.0	28.7	9.3	46.3	1	8.0

		प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति		उत्सर्जन				प्राकृतिक संसाधन						प्रभाव	
				कार्बन डाईऑक्साइड			ग्रीनहाउस गैस								
		जीवाश्म ईंधन	अक्षय ऊर्जा	कुल	प्रति व्यक्ति		प्रति व्यक्ति	प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास	वन क्षेत्र		ताजे पानी की निकासी	लुप्तप्राय प्रजातियाँ	कृषि भूमि	प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु	पड़ती भूमि पर रहने वाली आबादी
		(कुल का %)		(मेगाटन)	(टन)	(औसत वार्षिक वृद्धि %)	(कार्बन डाई ऑक्साइड के टन के समतुल्य)	(स.रा.आ का %)	(भूमि क्षेत्र का %)	(बदलाव %)	(कुल अक्षय जल संसाधनों का %)	(सभी प्रजातियों का %)	(भूमि क्षेत्र का %)	(प्रति मिलियन लोगों पर वार्षिक औसत)	(%)
मा.वि.सू. श्रेणी		2009	2009	2008	2008	1970/2008	2005	2010	2010	1990/2010	2003–2012[a]	2011	2009	2005/2011	2010
57	सऊदी अरब	100.0	0.0	434	16.6	2.0	2.5	..	0.5	0.0	943.3	8.8	80.7	1	4.0
59	क्यूबा	84.1	15.9	31	2.8	0.7	1.4	..	26.1	39.5	19.8	18.1	62.5	0	17.0
59	पनामा	78.6	21.5	7	2.0	0.9	1.4	0.0	43.7	–14.3	0.3	7.2	30.0	2	4.0
61	मैक्सिको	88.9	9.6	476	4.3	1.8	1.7	5.7	33.3	–7.8	17.5	17.3	52.9	1	4.0
62	कोस्टा रिका	44.7	55.3	8	1.8	2.5	0.9	0.1	51.0	1.6	2.4	8.0	35.3	2	1.0
63	ग्रेनाडा	..	..	0	2.4	4.4	..	..	50.0	0.0	..	10.5	36.8	38	..
64	लीबिया	99.2	0.8	58	9.5	–1.4	2.7	..	0.1	0.0	718.0	8.7	8.8	..	8.0
64	मलेशिया	94.7	5.3	208	7.6	4.7	2.4	6.9	62.3	–8.6	2.3	15.4	24.0	0	1.0
64	सर्बिया	92.4	8.1	50	6.8	..	2.3	..	31.0	17.3	..	7.2	57.8	0	19.0
67	एंटिगुआ और बरबूडा	..	..	0	5.1	–0.8	..	..	22.3	–4.9	3.3	8.3	29.5	0	..
67	त्रिनिडाड टोबैगो	99.9	0.1	50	37.4	3.7	7.8	32.0	44.1	–5.9	6.0	6.8	10.5	0	..
69	कज़ाकिस्तान	99.0	1.1	237	15.1	..	4.3	23.4	1.2	–3.3	28.9	8.4	77.2	1	24.0
70	अल्बानिआ	54.0	38.8	4	1.3	–0.8	1.1	2.5	28.3	–1.6	4.4	12.7	44.0	1	6.0
71	वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	87.7	12.4	170	6.1	–0.4	3.0	12.4	52.5	–11.1	0.7	8.3	24.3	1	2.0
72	डोमिनिका	..	..	0	1.9	4.4	..	0.0	59.5	–10.7	..	8.6	32.7	15	..
72	जॉर्जिआ	68.0	33.3	5	1.2	..	1.4	0.6	39.5	–1.3	2.6	9.3	36.1	0	2.0
72	लेबनान	95.9	2.6	17	4.1	2.5	0.4	0.0	13.4	4.5	28.1	10.0	67.3	0	1.0
72	सेंट किट्स एवं नेविस	..	..	0	4.9	..	..	..	42.3	0.0	..	8.6	21.2	..	..
76	ईरान इस्लामिक गणराज्य	99.5	0.5	538	7.4	2.2	2.1	..	6.8	0.0	67.7	8.8	29.8	1	25.0
77	पेरु	73.5	26.5	41	1.4	0.1	0.9	8.1	53.1	–3.1	1.0	8.4	16.8	6	1.0
78	मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	84.3	11.3	12	5.8	..	1.0	5.9	39.2	9.4	16.1	13.3	40.2	1	7.0
78	यूक्रेन	80.0	1.6	324	7.0	..	2.1	3.7	16.8	4.7	27.6	8.2	71.2	2	6.0
80	मॉरिशस	..	..	4	3.1	4.4	..	0.0	17.3	–9.8	26.4	15.2	48.3	1	..
81	बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	92.2	12.1	31	8.3	..	1.2	..	42.7	–1.1	0.9	9.8	41.7	0	6.0
82	अजरबैजान	98.2	1.7	47	5.4	..	4.7	34.5	11.3	0.0	35.2	8.2	57.6	0	4.0
83	सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	..	..	0	1.8	4.7	..	0.0	68.5	5.5	..	9.0	25.6	0	..
84	ओमान	100.0	0.0	46	17.3	11.1	7.1	..	0.0	0.0	86.6	8.5	5.9	5	6.0
85	ब्राज़ील	51.3	45.8	393	2.1	2.0	4.0	3.4	62.4	–9.6	0.7	10.0	31.3	1	8.0
85	जमैका	83.7	16.3	12	4.5	1.4	0.7	0.6	31.1	–2.2	6.2	15.2	41.5	3	3.0
87	अर्मेनिआ	68.4	6.7	6	1.8	..	1.3	1.0	9.3	–24.5	36.4	7.9	61.6	0	10.0
88	सेंट लूसिआ	..	..	0	2.3	3.4	..	..	77.0	7.3	..	9.4	18.0	6	..
89	इक्वाडोर	86.7	12.4	27	1.9	2.6	1.7	12.9	35.6	–28.6	3.6	12.7	30.3	1	2.0
90	तुर्की	89.9	10.2	284	4.0	3.2	1.4	0.4	14.7	17.1	18.8	15.3	50.6	0	5.0
91	कोलम्बिया	75.2	25.1	68	1.5	0.3	1.8	7.8	54.5	–3.2	0.6	11.5	38.3	4	2.0
92	श्रीलंका	45.3	54.7	12	0.6	1.8	0.6	0.3	28.8	–20.9	24.5	17.8	41.6	2	21.0
93	अल्जीरिया	99.8	0.2	111	3.2	2.9	1.8	18.1	0.6	–10.5	52.7	12.2	17.4	4	29.0
94	ट्यूनीशिया	85.7	14.2	25	2.4	3.2	1.0	5.1	6.5	56.5	61.7	11.2	63.0	0	37.0
मध्यम मानव विकास															
95	टोंगा	..	..	0	1.7	4.6	..	0.0	12.5	0.0	..	8.5	43.1	0	..
96	बेलीज	..	..	0	1.3	0.7	..	0.0	61.1	–12.2	0.8	6.4	6.7	13	1.0
96	डोमीनिकन गणराज्य	76.6	23.4	22	2.2	3.1	0.9	0.2	40.8	0.0	16.6	16.1	51.1	9	7.0
96	फ़िजी	..	..	1	1.5	1.0	..	0.0	55.5	6.4	0.3	13.1	22.9	8	..
96	सामोआ	..	..	0	0.9	3.9	..	0.3	60.4	31.5	..	10.8	23.7	5	..
100	जॉर्डन	98.0	1.8	21	3.7	3.4	0.5	1.0	1.1	0.0	99.4	9.1	11.5	0	22.0
101	चीन	87.4	11.9	7,032	5.3	4.7	1.5	5.1	21.9	31.6	19.5	12.1	56.2	1	9.0
102	तुर्कमेनिस्तान	100.7	0.0	48	9.7	..	6.7	..	8.8	0.0	100.8	8.4	69.4	..	11.0
103	थाइलैंड	79.4	20.5	286	4.2	6.3	1.6	2.4	37.1	–3.0	13.1	12.5	38.7	2	17.0
104	माल्दीव	..	..	1	3.0	..	..	0.0	3.0	0.0	15.7	9.1	26.7	0	..
105	सूरीनाम	..	..	2	4.7	0.2	..	..	94.6	–0.1	0.5	3.5	0.5	2	..
106	गैबन	33.9	66.1	2	1.7	–2.2	6.4	33.1	85.4	0.0	0.1	5.9	19.9	0	..
107	अल सल्वाडोर	37.8	62.0	6	1.0	2.6	0.8	0.4	13.9	–23.9	5.5	3.8	74.5	7	6.0
108	प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	79.1	20.9	13	1.3	2.2	4.9	12.3	52.7	–8.9	0.3	4.7	34.1	5	2.0
108	मंगोलिया	96.4	3.2	11	4.1	1.6	3.7	32.3	7.0	–13.1	1.4	6.4	74.5	4	31.0
110	फ़लस्तीन राज्य	..	..	2	0.5	..	..	..	1.5	1.0	49.9	6.2	61.0	0	..
111	पराग्वे	28.5	153.2	4	0.7	2.1	4.1	0.0	44.3	–16.9	0.1	3.9	52.6	0	1.0
112	मिस्र	96.3	3.8	210	2.7	4.0	0.9	7.1	0.1	59.1	119.0	8.9	3.7	0	25.0
113	माल्डोवा गणराज्य	91.3	3.1	5	1.3	..	1.1	0.2	11.7	21.0	16.4	6.7	75.2	1	22.0
114	फ़िलीपीन्स	57.0	43.0	83	0.9	0.7	0.8	2.1	25.7	16.7	17.0	16.8	40.1	9	2.0
114	उज्बेकिस्तान	98.4	1.6	125	4.6	..	1.9	19.2	7.7	7.6	118.3	7.9	62.6	0	27.0

मा.वि.सू. श्रेणी	प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति		उत्सर्जन				प्राकृतिक संसाधन						प्रभाव	
	जीवाश्म ईंधन	अक्षय ऊर्जा	कार्बन डाईऑक्साइड			ग्रीनहाउस गैस	प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास	वन क्षेत्र		ताजे पानी की निकासी	लुप्तप्राय प्रजातियाँ	कृषि भूमि	प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु	पड़ती भूमि पर रहने वाली आबादी
			कुल	प्रति व्यक्ति		प्रति व्यक्ति								
	(कुल का %)		(मेगाटन)	(टन)	(औसत वार्षिक वृद्धि %)	(कार्बन डाई ऑक्साइड के टन के समतुल्य)	(स.रा.आ का %)	(भूमि क्षेत्र का %)	(बदलाव %)	(कुल अक्षय जल संसाधनों का %)	(सभी प्रजातियों का %)	(भूमि क्षेत्र का %)	(प्रति मिलियन लोगों पर वार्षिक औसत)	(%)
	2009	2009	2008	2008	1970/2008	2005	2010	2010	1990/2010	2003–2012[a]	2011	2009	2005/2011	2010
116 सीरियाई अरब गणराज्य	99.3	0.7	72	3.6	3.3	0.9	11.9	2.7	32.0	99.8	10.9	75.7	1	33.0
117 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	..	..	0	0.6	..	..	..	91.7	0.9	..	13.7	31.4	45	..
118 गुयाना	..	..	2	2.0	–0.2	..	6.0	77.2	0.0	0.7	3.8	8.5	4	..
119 बोत्स्वाना	64.3	23.6	5	2.5	..	4.1	3.4	20.0	–17.3	1.6	2.0	45.6	0	22.0
120 होण्डुरास	50.3	49.8	9	1.2	2.2	1.2	0.5	46.4	–36.2	1.2	8.3	28.5	4	15.0
121 इण्डोनेशिया	65.6	34.4	406	1.7	4.7	1.5	6.6	52.1	–20.3	5.6	14.3	29.6	2	3.0
121 किरिबाती	..	..	0	0.3	–1.0	..	..	15.0	0.0	..	12.4	42.0	0	..
121 दक्षिण अफ्रीका	87.8	10.0	436	8.9	0.7	1.9	6.1	7.6	0.0	25.0	14.1	81.7	1	17.0
124 वनुआतू	..	..	0	0.4	–0.4	..	0.0	36.1	0.0	..	12.0	15.3	0	..
125 किर्गिस्तान	72.5	28.4	6	1.2	..	1.0	6.9	5.0	14.0	43.7	5.9	55.4	2	10.0
125 ताजिकिस्तान	41.2	58.6	3	0.5	..	0.9	0.8	2.9	0.5	74.8	6.4	33.9	3	10.0
127 वियतनाम	56.2	43.3	127	1.5	2.2	1.3	9.4	44.5	47.4	9.3	12.1	33.1	3	8.0
128 नामीबिया	70.5	19.2	4	1.8	..	4.4	0.7	8.9	–16.8	1.7	5.6	47.1	7	28.0
129 निकारागुआ	44.7	55.3	4	0.8	0.7	1.7	1.6	25.7	–31.0	0.7	4.8	42.8	7	14.0
130 मोरक्को	92.5	4.9	48	1.5	3.1	0.5	1.6	11.5	1.6	43.4	15.2	67.3	1	39.0
131 इराक	97.6	0.9	103	3.4	0.9	0.7	45.7	1.9	2.6	87.3	8.2	20.1	0	5.0
132 केप वर्दे	..	..	0	0.6	4.2	..	0.1	21.1	47.3	6.8	12.5	21.8	0	..
133 ग्वाटेमाला	46.1	53.9	12	0.9	1.9	1.1	1.7	33.7	–23.0	2.6	9.3	41.0	14	9.0
134 टिमोर लेस्ट	..	..	0	0.2	..	..	..	49.9	–23.2	..	5.2	25.2	1	..
135 घाना	24.3	76.2	9	0.4	0.5	0.6	8.0	21.7	–33.7	1.8	5.7	68.1	1	1.0
136 इक्वेटोरिअल गिनी	..	..	5	7.3	11.3	..	49.4	58.0	–12.6	0.1	6.4	10.9	..	..
136 भारत	73.0	26.1	1,743	1.5	3.8	0.7	4.4	23.0	7.0	39.8	14.0	60.5	2	10.0
138 कम्बोडिया	27.8	70.8	5	0.3	1.8	1.9	0.1	57.2	–22.0	0.5	12.1	31.5	1	39.0
138 लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	..	..	2	0.3	0.5	..	8.3	68.2	–9.0	1.3	10.5	10.2	0	4.0
140 भूटान	..	..	1	1.0	12.4	..	3.6	69.1	7.1	0.4	6.8	13.2	1	..
141 स्वाज़ीलैण्ड	..	..	1	1.1	0.7	..	0.1	32.7	19.3	23.1	2.7	71.0	0	..
निम्न मानव विकास														
142 काँगो	44.2	53.1	2	0.5	0.4	2.7	59.6	65.6	–1.4	0.0	4.4	30.9	0	..
143 सॉलोमन द्वीपसमूह	..	..	0	0.4	1.1	..	15.6	79.1	–4.8	..	14.8	3.0	4	..
144 साओ टोम एवं प्रिन्साइप	..	..	0	0.8	3.7	..	0.8	28.1	0.0	0.3	14.9	58.3	..	..
145 केन्या	16.8	83.2	10	0.3	0.0	0.9	1.1	6.1	–6.5	8.9	8.4	48.1	2	31.0
146 बांग्लादेश	69.8	30.2	47	0.3	..	0.7	2.3	11.1	–3.5	2.9	8.6	70.3	6	11.0
146 पाकिस्तान	61.8	37.4	163	1.0	2.3	1.1	2.8	2.2	–33.2	79.5	8.6	34.1	3	4.0
148 अंगोला	37.6	62.4	24	1.4	2.1	5.1	35.1	46.9	–4.1	0.4	4.6	46.8	2	3.0
149 म्याँमार	27.7	72.3	13	0.3	1.1	2.2	..	48.3	–19.0	2.8	7.9	19.0	287	19.0
150 कैमरून	30.9	69.1	5	0.3	3.0	1.6	4.8	42.1	–18.1	0.3	10.9	19.8	0	15.0
151 मैडागास्कर	..	..	2	0.1	–1.1	..	1.0	21.6	–8.3	4.4	21.0	70.2	5	..
152 तंज़ानिया गणराज्य	11.1	88.9	6	0.2	0.4	1.4	3.2	37.7	–19.4	5.4	12.3	40.1	0	25.0
153 नाइजीरिया	14.7	85.3	96	0.6	1.4	1.1	22.0	9.9	–47.5	3.6	6.6	81.8	0	12.0
154 सेनेगल	57.8	41.8	5	0.4	0.7	1.0	0.8	44.0	–9.4	5.7	6.9	49.4	0	16.0
155 मॉरिटानिया	..	..	2	0.6	1.2	..	34.3	0.2	–41.7	14.0	8.1	38.5	1	24.0
156 पापुआ न्यू गिनी	..	..	2	0.3	0.3	..	22.2	63.4	–8.9	0.0	11.4	2.5	4	..
157 नेपाल	11.1	88.5	4	0.1	5.0	1.0	2.5	25.4	–24.5	4.7	6.1	29.6	6	2.0
158 लेसोथो	..	..	..	..	..	..	1.0	1.4	10.0	1.7	3.0	77.0	0	64.0
159 टोगो	14.4	83.4	1	0.2	1.7	0.8	3.4	5.3	–58.1	1.2	4.2	62.1	1	5.0
160 यमन	98.7	1.3	23	1.0	2.5	0.5	14.5	1.0	0.0	168.6	9.3	44.4	2	32.0
161 हैती	28.1	71.9	2	0.3	3.0	0.6	..	3.7	–12.9	8.6	19.4	66.8	65	15.0
161 युगाण्डा	..	..	4	0.1	–0.6	..	4.5	15.2	–37.1	0.5	7.6	69.9	2	23.0
163 ज़ाम्बिया	7.6	92.2	2	0.2	–4.6	3.8	18.9	66.5	–6.3	1.7	3.3	31.5	1	5.0
164 जिबूती	..	..	1	0.6	–0.9	..	..	0.2	0.0	6.3	8.2	73.4	6	8.0
165 गैम्बिया	..	..	0	0.3	2.3	..	0.8	48.0	8.6	0.9	4.9	66.5	1	18.0
166 बेनिन	40.4	57.4	4	0.5	4.3	0.9	0.3	41.2	–20.8	0.5	4.5	29.8	1	2.0
167 रवाण्डा	..	..	1	0.1	4.0	..	3.1	17.6	36.8	1.6	5.7	81.1	1	10.0
168 आइवरी कोस्ट	23.5	76.9	7	0.4	–0.5	1.0	3.9	32.7	1.8	1.7	6.7	63.8	0	1.0
169 कोमोरॉस	..	..	0	0.2	1.0	..	1.1	1.6	–75.0	0.8	11.7	83.3	0	..
170 मलावी	..	..	1	0.1	–0.4	..	1.8	34.4	–16.9	5.6	8.6	59.1	4	19.0
171 सूडान	30.2	69.8	14	0.3	0.1	3.0	12.9	29.4	–8.4	57.6	4.8	57.5	1	40.0
172 ज़िम्बाब्वे	25.7	69.4	9	0.7	–2.0	1.3	2.7	40.4	–29.5	21.0	3.3	42.4	0	29.0
173 इथियोपिया	7.1	92.9	7	0.1	1.2	1.1	4.2	11.2	–18.6	4.6	6.7	35.0	2	72.0
174 लाइबेरिया	..	..	1	0.2	–4.6	..	6.4	44.9	–12.2	0.1	8.4	27.1	0	..

	प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति		उत्सर्जन				प्राकृतिक संसाधन						प्रभाव	
	जीवाश्म ईंधन	अक्षय ऊर्जा	कार्बन डाईऑक्साइड: कुल	कार्बन डाईऑक्साइड: प्रति व्यक्ति		ग्रीनहाउस गैस: प्रति व्यक्ति	प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास	वन क्षेत्र		ताजे पानी की निकासी	लुप्तप्राय प्रजातियाँ	कृषि भूमि	प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु	पड़ती भूमि पर रहने वाली आबादी
	(कुल का %)	(कुल का %)	(मेगाटन)	(टन)	(औसत वार्षिक वृद्धि %)	(कार्बन डाई ऑक्साइड के टन के समतुल्य)	(स.रा.आ का %)	(भूमि क्षेत्र का %)	(बदलाव %)	(कुल अक्षय जल संसाधनों का %)	(सभी प्रजातियों का %)	(भूमि क्षेत्र का %)	(प्रति मिलियन लोगों पर वार्षिक औसत)	(%)
मा.वि.सू. श्रेणी	2009	2009	2008	2008	1970/2008	2005	2010	2010	1990/2010	2003–2012[a]	2011	2009	2005/2011	2010
175 अफ़गानिस्तान	..	..	1	0.0	–4.4	..	2.6	2.1	0.0	35.6	5.8	58.1	11	11.0
176 गिनी बिसाउ	..	..	0	0.2	1.4	..	0.5	71.9	–8.8	0.6	5.7	58.0	1	1.0
177 सिएरा लिओन	..	..	1	0.2	–0.9	..	2.1	38.1	–12.6	0.3	6.5	47.7	3	..
178 बुरुण्डी	..	..	0	0.0	0.6	..	12.7	6.7	–40.5	2.3	4.5	83.7	2	19.0
178 गिनी	..	..	1	0.1	–0.7	..	14.3	26.6	–9.9	0.7	7.3	58.0	0	1.0
180 मध्य अफ्रीकी गणराज्य	..	..	0	0.1	–1.6	..	0.0	36.3	–2.6	0.0	1.6	8.4	0	..
181 इरिट्रिया	22.6	77.4	0	0.1	..	0.8	0.0	15.2	–5.5	9.2	7.4	75.2	0	59.0
182 माली	..	..	1	0.0	0.5	..	9.8	10.2	–11.2	6.5	2.8	33.7	0	60.0
183 बुर्किना फ़ासो	..	..	2	0.1	4.2	..	4.3	20.6	–17.5	7.9	2.7	43.7	0	73.0
184 चाड	..	..	0	0.0	0.8	..	29.0	9.2	–12.1	0.9	3.7	39.2	2	45.0
185 मोज़ाम्बीक	7.7	96.7	2	0.1	–2.9	1.1	3.3	49.6	–10.0	0.3	7.0	62.7	1	2.0
186 कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	3.7	96.6	3	0.0	–2.8	1.9	13.7	68.0	–3.9	0.0	6.4	9.9	0	..
186 नाइजर	..	..	1	0.1	0.5	..	2.4	1.0	–38.1	7.0	3.6	34.6	0	25.0
अन्य देश अथवा अंचल														
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	81.7	0.7	78	3.2	..	1.0	..	47.1	–30.9	11.2	8.6	24.1	5	3.0
मार्शल द्वीप समूह	..	..	0	1.9	..	..	..	70.2	0.0	..	11.0	72.2	0	..
मोनाको	..	..	..	..	..	..	..	0.0	0.0	..	6.8	..	..	..
नाउरू	..	..	..	3.9	..	..	..	0.0	0.0	..	12.1	20.0	..	..
सैन मैरीनो	..	..	..	..	..	..	..	0.0	0.0	..	0.0	16.7	..	..
सोमालिया	..	..	1	0.1	0.5	..	..	10.8	–18.5	22.4	6.8	70.2	2	26.0
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
तुवालू	..	..	..	..	..	..	..	33.3	0.0	..	13.0	60.0	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह														
अति उच्च मानव विकास	81.0	7.5	12,643	11.4	–0.2	2.7	0.9	29.1	1.1	8.2	13.6	42.6	8	..
उच्च मानव विकास	86.7	9.5	5,765	5.8	1.0	2.8	..	38.0	–4.1	2.8	11.4	26.5	7	8.4
मध्यम मानव विकास	..	..	10,877	3.2	3.8	..	5.3	24.6	1.3	16.4	12.8	60.9	2	..
निम्न मानव विकास	..	..	473	0.4	0.5	..	9.5	28.8	–10.6	4.4	7.6	45.8	14	20.2
क्षेत्र														
अरब देश	96.7	3.1	1,509	4.6	1.1	1.5	..	7.1	–7.8	87.4	9.4	63.1	1	24.9
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	..	..	8,255	4.3	4.5	..	..	29.4	2.1	..	12.5	44.9	9	..
यूरोप एवं मध्य एशिया	88.3	4.7	3,723	7.9	..	3.0	7.3	38.5	0.7	5.8	9.6	20.5	13	8.5
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	72.6	26.3	1,637	2.9	1.2	2.7	5.7	47.2	–8.9	1.5	11.5	37.5	3	5.4
दक्षिण एशिया	76.7	22.6	2,509	1.5	3.2	0.8	4.0	14.5	2.4	28.6	12.5	33.9	2	10.1
सब-सहारा अफ्रीका	..	..	670	0.9	0.4	..	11.6	28.4	–10.2	1.6	7.5	54.7	1	25.0
न्यूनतम विकसित देश	..	..	191	0.2	–0.5	..	9.0	29.6	–9.4	2.8	7.6	47.1	20	26.0
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	..	..	137	2.7	1.4	..	..	63.1	–3.5	..	14.9	3.3	16	..
विश्व	**80.7**	**13.1**	**29,837**	**4.5**	**0.4**	**1.7**	**3.3**	**31.1**	**–3.3**	**7.3**	**11.7**	**38.6**	**6**	**10.6**

नोट

a आँकड़े निर्दिष्ट अवधि में अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए हैं।

परिभाषाएँ

जीवाश्म ईंधनः समस्त ऊर्जा आपूर्ति का वह प्रतिशत जो उन प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है, जो दीर्घकालिक भूगर्भीय अतीत के कारण बने थे (जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस)।

अक्षय ऊर्जाः समस्त ऊर्जा आपूर्ति का वह प्रतिशत जो लगातार नवीकृत किये जा सकने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होती है। इन स्रोतों में सौर, पवन, जैव-पदार्थ, जिओ-थर्मल, जल विद्युत और समुद्री, संसाधन व कुछ अपशिष्ट शामिल हैं। इसमें परमाणु ऊर्जा शामिल नहीं है।

कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जनः मानवीय गतिविधि के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन, जो जीवाश्म ईंधन के जलने, गैसों की ज्वालाओं से और सीमेंट के उत्पादन से पैदा होता है। वन क्षेत्र में कमी के जरिए वन जैव पदार्थों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाई ऑक्साइड शामिल।

प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनः कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन वर्ष मध्य की आबादी से विभाजित।

प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनः मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों, जिसमें हाइड्रोक्लोरो कार्बन, परफ्लूरोकार्बन और सल्फर हैक्सा क्लोराइड भी शामिल हैं, से होने वाला उत्सर्जन, वर्ष मध्य की जनसंख्या से विभाजित। इसमें कार्बन डाई ऑक्साइड शामिल नहीं है।

प्राकृतिक संसाधन क्षयः ऊर्जा, खानिजों और वनों के क्षय की मौद्रिक अभिव्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आय (स.रा.आ.) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त।

वन क्षेत्रः ऐसा भू क्षेत्र जो 0.5हेक्टेयर से अधिक है और जिसमें 5 मीटर से ऊँचे पेड़ लगे हैं और जिसका छाया क्षेत्र 10 प्रतिशत से अधिक है, या पेड़ जो इस स्तर तक बिना बाह्य हस्तक्षेप के पहुँचने में सक्षम हैं। इसमें मुख्य रूप से कृषि या शहरी भू उपयोग के अंतर्गत आने वाली जमीन, कृषि उत्पादन में शामिल पेड़ (उदाहरण के लिए, फल बागवानी और कृषि-वानिकी प्रणाली) और शहरी पार्कों तथा बागीचों के पेड़ शामिल नहीं है। पुनर्वनीकरण के तहत ऐसी भूमि जहाँ छाया क्षेत्र 10 प्रतिशत के स्तर तक न पहुँचा हो, लेकिन पहुँचने की उम्मीद हो और पेड़ की ऊँचाई 5 मीटर हो, और अस्थायी असंग्रहीत क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है, जिसके मानव हस्तक्षेप या प्राकृतिक कारणों से पुनर्जीवित होने की उमीद है।

ताजे पानी की निकासीः एक वर्ष में निकाला गया कुल ताज़ा पानी पुनर्पोषणीय जल संसाधन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त।

लुप्तप्राय प्रजातियाँः पशुजगत की प्रजातियों (स्तनपायी, पक्षी, सरीसर्प, उभयचर, मछली और रीढ़-विहीन शामिल) का वह प्रतिशत जिसे इंटरनेशनल यूनियन फ़ॉर द कन्जर्वेशन ऑफ़ नेचर द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय अथवा अरक्षित वर्गीकृत किया गया है।

कृषि भूमिः खेतिहर भूमि (अस्थायी कृषि फसलों के तहत भूमि; बहु-फसली क्षेत्रों को केवल एक बार ही गिना गया है), घास के अस्थायी चरागाह, बाजार और किचेन गार्डेन के अंतर्गत भूमि और अस्थायी रूप से पड़ती भूमि (पाँच साल से कम) के योग को कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त है। खेती स्थानांतरण के कारण छोड़ी गयी भूमि को शामिल नहीं किया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्युः उन लोगों की संख्या जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण मारे गये हैं या लापता होने के बाद मरे हुए मान लिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं को जलवायु संबंधी, पानी संबंधी और मौसम संबंधी आपदाओं के रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें अकाल, अत्यधिक तापमान, बाढ़, भू-गर्भीय परिवर्तन जलीय तूफान और जंगली आग शामिल है।

पड़ती जमीन पर रहने वाली आबादीः आबादी का वह प्रतिशत जो खराब या काफी ख़राब हो गई पड़ती भूमि पर रह रहा है। पड़त भूमि के आकलन में जैवपदार्थों की स्थिति, मिट्टी का स्वास्थ्य, जल की गुणवत्ता और जैव विविधता की तीव्रता को ध्यान में रखा गया है।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1 और 2: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ आई.ई.ए. (2012) द्वारा कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति के आँकड़ों पर आधारित।

कॉलम 3, 4 : विश्व बैंक (2012**a**)।

कॉलम 5 और 7: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ विश्व बैंक (2012**a**) के आँकड़ों पर आधारित।

कॉलम 6: एच.डी.आर.ओ .गणनाएँ विश्व बैंक (2012**a**) और यू.एन. डी.ई.एस.ए. (2011) के आँकड़ों पर आधारित।

कॉलम 8 और 9: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ एफ.ए.ओ. (2012) के वन तथा कुल भूमि क्षेत्र के आँकड़ों पर आधारित।

कॉलम 10: एफ.ए.ओ. (2011)।

कॉलम 11: आई.यू.सी.एन. (2012)।

कॉलम 12: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ एफ.ए.ओ (2012) के आँकड़ों पर निर्भर।

कॉलम 13: सी.आर.ई.डी. ई.एम.-डीएटी (2012) और यू.एन. डी.ई.एस.ए. 2011

कॉलम 14: एफ.ए.ओ. (2012)।

सारणी 14 जनसंख्या रुझान

		जनसंख्या													
		कुल[a] (मिलियन में)		वार्षिक वृद्धि (%)		शहरी (कुल का %)		माध्यिका उम्र (वर्ष)		कुल निर्भरता अनुपात (प्रति 100 लोगों पर 15-64 आयु)		कुल प्रजनन दर (जन्म प्रति महिला)		जन्म के समय लिंगानुपात[b] (बालिका के मुकाबले बालक जन्म)	
मा.वि.सू. श्रेणी		2012	2030	2000/2005	2010/2015[a,c]	2000	2012	2000	2010	2000	2012	2000	2012[a,c]	2000[d]	2012[c]
अति उच्च मानव विकास															
1	नार्वे	5.0 [e]	5.6 [e]	0.6 [e]	0.7 [e]	76.1	79.7	36.9	38.7	54.2	51.5	1.8	2.0	1.05	1.06
2	ऑस्ट्रेलिया	22.9 [f]	27.8 [f]	1.3 [f]	1.3 [f]	87.2	89.4	35.4	36.9	49.6	49.3	1.7	2.0	1.06	1.06
3	यूनाइटेड स्टेट्स	315.8	361.7	1.0	0.9	79.1	82.6	35.3	36.9	51.0	50.7	2.0	2.1	1.05	1.05
4	नीदरलैंड	16.7	17.3	0.6	0.3	76.8	83.6	37.3	40.7	47.3	50.6	1.7	1.8	1.06	1.06
5	जर्मनी	82.0	79.5	0.0	–0.2	73.1	74.1	39.9	44.3	47.0	51.7	1.3	1.4	1.06	1.06
6	न्यूजीलैंड	4.5	5.2	1.4	1.0	85.7	86.3	34.3	36.6	52.7	51.4	1.9	2.1	1.05	1.06
7	आयरलैंड	4.6	5.4	1.8	1.1	59.1	62.5	32.5	34.7	49.2	50.8	1.9	2.1	1.07	1.07
7	स्वीडन	9.5	10.4	0.4	0.6	84.0	85.4	39.4	40.7	55.3	55.5	1.6	1.9	1.06	1.06
9	स्विटजरलैंड	7.7	8.1	0.7	0.4	73.3	73.8	38.6	41.4	48.7	47.9	1.4	1.5	1.05	1.05
10	जापान	126.4	120.2	0.1	–0.1	78.6	91.9	41.3	44.7	46.6	59.6	1.3	1.4	1.06	1.06
11	कनाडा	34.7	39.8	1.0	0.9	79.5	80.8	36.8	39.9	46.3	45.1	1.5	1.7	1.05	1.06
12	कोरिआ गणराज्य	48.6	50.3	0.5	0.4	79.6	83.5	32.1	37.9	39.5	38.0	1.3	1.4	1.10	1.10
13	हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	7.2	8.5	0.1	1.0	100.0	100.0	36.5	41.8	39.3	32.3	0.8	1.1	1.07	1.07
13	आइसलैंड	0.3	0.4	1.1	1.2	92.4	93.8	32.8	34.8	53.5	49.6	2.0	2.1	1.04	1.05
15	डेनमार्क	5.6	5.9	0.3	0.3	85.1	87.1	38.4	40.6	50.0	54.1	1.8	1.9	1.06	1.06
16	इस्राइल	7.7	9.8	1.9	1.7	91.2	91.9	28.0	30.1	61.6	61.6	2.9	2.9	1.05	1.05
17	बेल्जियम	10.8	11.2	0.5	0.3	97.1	97.5	39.1	41.2	51.6	53.3	1.6	1.8	1.05	1.05
18	ऑस्ट्रिया	8.4	8.6	0.6	0.2	65.8	67.9	38.2	41.8	48.0	48.1	1.4	1.3	1.06	1.06
18	सिंगापुर	5.3	6.0	1.7	1.1	100.0	100.0	34.1	37.6	40.5	35.4	1.4	1.3	1.07	1.07
20	फ्रांस	63.5	68.5	0.6	0.5	76.9	86.4	37.7	39.9	53.6	55.7	1.8	2.0	1.05	1.05
21	फ़िनलैंड	5.4	5.6	0.3	0.3	82.2	83.8	39.3	42.0	49.3	53.5	1.7	1.9	1.05	1.05
21	स्लोवेनिया	2.0	2.1	0.2	0.2	50.8	49.8	38.0	41.7	42.7	45.0	1.2	1.5	1.05	1.05
23	स्पेन	46.8 [g]	50.0 [g]	1.5 [g]	0.6 [g]	76.3	77.6	37.6	40.1	46.3	48.4	1.2	1.5	1.06	1.06
24	लिख्टेन्स्टाइन	0.0	0.0	1.1	0.8	15.1	14.3	..	..	..	..	..	..	..	..
25	इटली	61.0	60.9	0.6	0.2	67.2	68.5	40.2	43.2	48.3	53.8	1.2	1.5	1.06	1.06
26	लक्ज़मबर्ग	0.5	0.6	1.0	1.4	83.8	85.7	37.3	38.9	49.1	46.1	1.7	1.7	1.06	1.06
26	यूनाइटेड किंगडम	62.8	69.3	0.4	0.6	78.7	79.7	37.7	39.8	53.4	52.7	1.7	1.9	1.05	1.05
28	चेक गणराज्य	10.6	10.8	0.0	0.3	74.0	73.4	37.4	39.4	43.7	42.9	1.1	1.5	1.06	1.06
29	यूनान	11.4	11.6	0.4	0.2	59.7	61.7	38.3	41.4	47.1	50.6	1.3	1.5	1.07	1.07
30	ब्रूनेई दारस्सलाम	0.4	0.5	2.1	1.7	71.2	76.4	25.8	28.9	49.8	41.6	2.4	2.0	1.06	1.06
31	साइप्रस	1.1	1.3	1.8	1.1	68.6	70.7	31.8	34.2	48.4	41.4	1.7	1.5	1.07	1.07
32	माल्टा	0.4	0.4	0.6	0.3	92.4	95.0	36.1	39.5	46.6	42.1	1.6	1.3	1.06	1.06
33	अंडोरा	0.1	0.1	3.7	1.5	92.4	86.7	..	..	..	..	..	..	..	..
33	एस्टोनिआ	1.3	1.3	–0.4	–0.1	69.4	69.5	37.9	39.7	49.8	50.0	1.3	1.7	1.06	1.06
35	स्लोवाकिआ	5.5	5.5	0.0	0.2	56.2	54.7	33.6	36.9	45.4	37.9	1.3	1.4	1.05	1.05
36	कतर	1.9	2.4	6.6	2.9	96.3	98.9	30.3	31.6	38.4	18.3	3.1	2.2	1.05	1.04
37	हंगरी	9.9	9.6	–0.2	–0.2	64.6	69.9	38.5	39.8	46.8	46.2	1.3	1.4	1.06	1.06
38	बारबाडोस	0.3	0.3	0.2	0.2	38.3	44.9	33.6	37.5	50.3	40.0	1.6	1.6	1.04	1.04
39	पोलैण्ड	38.3	37.8	–0.1	0.0	61.7	60.8	35.3	38.0	46.3	40.5	1.3	1.4	1.06	1.06
40	चिली	17.4	19.5	1.1	0.9	85.9	89.4	28.8	32.1	54.0	45.2	2.1	1.8	1.04	1.04
41	लिथुएनिया	3.3	3.1	–0.5	–0.4	67.0	67.2	35.9	39.3	51.2	44.9	1.3	1.5	1.06	1.05
41	संयुक्त अरब अमीरात	8.1	10.5	5.9	2.2	80.2	84.7	28.1	30.1	36.3	20.9	2.6	1.7	1.05	1.05
43	पुर्तगाल	10.7	10.3	0.4	0.0	54.4	61.6	37.7	41.0	47.8	50.0	1.5	1.3	1.06	1.06
44	लातीविया	2.2	2.1	–0.7	–0.4	68.1	67.7	38.1	40.2	49.9	47.3	1.2	1.5	1.05	1.06
45	अर्जेंटीना	41.1	46.8	0.9	0.9	90.1	92.7	27.9	30.4	60.7	54.4	2.5	2.2	1.04	1.04
46	सेशेल्स	0.1	0.1	1.2	0.3	50.4	54.0	..	..	..	..	..	..	..	..
47	क्रोएशिया	4.4	4.2	–0.3	–0.2	55.6	58.1	39.1	41.5	48.4	47.9	1.4	1.5	1.06	1.06
उच्च मानव विकास															
48	बहरीन	1.4	1.7	2.5	2.1	88.4	88.7	27.4	30.1	44.1	29.2	2.7	2.5	1.05	1.05
49	बहामास	0.4	0.4	1.4	1.1	82.0	84.5	27.0	30.9	52.9	40.9	2.1	1.9	1.06	1.06
50	बेलारूस	9.5	8.9	–0.5	–0.3	70.0	75.5	36.3	38.3	47.5	40.5	1.2	1.5	1.06	1.06
51	उरुग्वे	3.4	3.6	0.0	0.3	91.3	92.6	31.6	33.7	60.2	56.2	2.2	2.0	1.05	1.05
52	मॉन्टीनेग्रो	0.6	0.6	–0.2	0.1	58.5	63.5	33.5	35.9	47.1	46.5	1.8	1.6	1.08	1.08
52	पलाउ	0.0	0.0	0.8	0.8	70.0	85.1	..	..	..	..	..	..	..	..
54	कुवैत	2.9	4.0	3.1	2.4	98.1	98.3	28.3	28.2	42.3	41.1	2.6	2.3	1.03	1.03
55	रूसी गणराज्य	142.7	136.4	–0.4	–0.1	73.4	74.0	36.5	37.9	44.1	39.8	1.2	1.5	1.06	1.06
56	रोमानिया	21.4	20.3	–0.4	–0.2	53.0	52.8	34.7	38.5	46.7	43.6	1.3	1.4	1.06	1.06
57	बुल्गारिया	7.4	6.5	–0.7	–0.7	68.9	73.7	39.7	41.6	47.7	47.3	1.2	1.5	1.06	1.06
57	सऊदी अरब	28.7	38.5	3.6	2.1	79.8	82.5	20.9	25.9	72.5	49.0	4.0	2.7	1.03	1.03
59	क्यूबा	11.2	11.0	0.3	0.0	75.6	75.1	32.8	38.4	45.8	41.8	1.6	1.4	1.06	1.06
59	पनामा	3.6	4.5	1.8	1.5	65.8	75.9	24.8	27.3	59.6	54.3	2.7	2.4	1.05	1.05

	जनसंख्या													
	कुल[a]		वार्षिक वृद्धि		शहरी		माध्यिका उम्र		कुल निर्भरता अनुपात		कुल प्रजनन दर		जन्म के समय लिंगानुपात[b]	
	(मिलियन में)		(%)		(कुल का %)		(वर्ष)		(प्रति 100 लोगों पर 15-64 आयु)		(जन्म प्रति महिला)		(बालिका के मुकाबले बालक जन्म)	
मा.वि.सू. श्रेणी	2012	2030	2000/2005	2010/2015[a,c]	2000	2012	2000	2010	2000	2012	2000	2012[a,c]	2000[d]	2012[c]
61 मैक्सिको	116.1	135.4	1.3	1.1	74.7	78.4	23.4	26.6	62.5	53.5	2.6	2.2	1.05	1.05
62 कोस्टा रिका	4.8	5.7	1.9	1.4	59.0	65.1	24.8	28.4	58.5	44.5	2.4	1.8	1.05	1.05
63 ग्रेनाडा	0.1	0.1	0.2	0.4	35.9	39.5	21.8	25.0	74.9	51.9	2.6	2.2	1.05	1.05
64 लीबिया	6.5	7.8	2.0	0.8	76.3	77.9	21.9	25.9	55.6	55.0	3.1	2.4	1.06	1.06
64 मलेशिया	29.3	37.3	2.2	1.6	62.0	73.5	23.8	26.0	59.1	52.8	3.1	2.6	1.06	1.06
64 सर्बिया	9.8[h]	9.5[h]	–0.6[h]	–0.1[h]	53.0	56.7	35.7	37.6	50.5	46.7	1.7	1.6	1.08	1.08
67 एंटिगुआ और बरबूडा	0.1	0.1	1.6	1.0	32.1	29.8	..	..	..	..	..	..	..	..
67 त्रिनिडाड टोबैगो	1.4	1.4	0.4	0.3	10.8	14.0	26.9	30.8	47.3	38.6	1.6	1.6	1.04	1.04
69 कज़ाकिस्तान	16.4	18.9	0.3	1.0	55.7	53.5	27.7	29.0	52.6	47.2	1.9	2.5	1.07	1.07
70 अल्बानिआ	3.2	3.3	0.5	0.3	41.7	54.5	27.4	30.0	59.6	46.1	2.2	1.5	1.07	1.07
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	29.9	37.0	1.8	1.5	89.9	93.7	23.3	26.1	62.0	53.3	2.8	2.4	1.05	1.05
72 डोमिनिका	0.1	0.1	–0.2	0.0	67.2	67.2	..	..	..	..	..	..	..	..
72 जॉर्जिआ	4.3	3.8	–1.2	–0.6	52.6	52.9	34.4	37.3	52.5	44.8	1.6	1.5	1.11	1.11
72 लेबनान	4.3	4.7	1.6	0.7	86.0	87.4	25.6	29.1	59.4	45.1	2.4	1.8	1.05	1.05
72 सेंट किट्स एवं नेविस	0.1	0.1	1.3	1.2	32.8	32.0	..	..	..	..	..	..	..	..
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	75.6	84.4	1.3	1.0	64.0	69.2	20.8	27.1	65.2	38.7	2.2	1.6	1.05	1.05
77 पेरु	29.7	35.5	1.3	1.1	73.0	77.6	23.0	25.6	63.8	54.9	2.9	2.4	1.05	1.05
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	2.1	2.0	0.3	0.1	59.4	59.4	32.5	35.9	47.7	41.2	1.7	1.4	1.08	1.08
78 यूक्रेन	44.9	40.5	–0.8	–0.5	67.1	69.1	37.7	39.3	46.0	42.8	1.1	1.5	1.06	1.06
80 मॉरिशस	1.3	1.4	1.0	0.5	42.7	41.8	28.6	32.4	48.0	39.6	2.0	1.6	1.04	1.04
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	3.7	3.5	0.5	–0.2	43.0	48.8	35.1	39.4	44.5	40.5	1.4	1.1	1.07	1.07
82 अजरबैजान	9.4	10.8	1.1	1.2	51.4	53.9	25.6	29.5	58.1	38.3	2.0	2.2	1.17	1.15
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	0.1	0.1	0.2	0.0	45.2	49.7	24.2	27.9	62.3	48.3	2.4	2.0	1.03	1.03
84 ओमान	2.9	3.6	1.4	1.9	71.6	73.7	21.0	25.3	64.5	42.8	3.6	2.2	1.05	1.05
85 ब्राज़ील	198.4	220.5	1.3	0.8	81.2	84.9	25.4	29.1	54.0	46.8	2.4	1.8	1.05	1.05
85 जमैका	2.8	2.8	0.8	0.4	51.8	52.1	24.5	27.0	67.0	55.9	2.6	2.3	1.05	1.05
87 अर्मेनिआ	3.1	3.1	–0.1	0.3	64.7	64.1	30.3	32.1	55.9	45.3	1.7	1.7	1.18	1.14
88 सेंट लूसिआ	0.2	0.2	1.0	1.0	28.0	16.8	24.0	27.4	66.5	46.9	2.3	1.9	1.03	1.03
89 इक्वाडोर	14.9	17.9	1.7	1.3	60.3	68.0	22.6	25.5	65.1	56.3	3.0	2.4	1.05	1.05
90 तुर्की	74.5	86.7	1.4	1.1	64.7	72.5	24.5	28.3	56.0	46.8	2.4	2.0	1.05	1.05
91 कोलम्बिया	47.6	56.9	1.6	1.3	72.1	75.6	23.8	26.8	60.1	51.5	2.6	2.3	1.05	1.05
92 श्रीलंका	21.2	23.1	1.1	0.8	15.7	15.2	27.8	30.7	48.9	50.6	2.2	2.3	1.04	1.04
93 अल्जीरिया	36.5	43.5	1.5	1.4	60.8	73.8	21.7	26.2	62.2	45.6	2.6	2.2	1.05	1.05
94 ट्यूनीशिया	10.7	12.2	0.9	1.0	63.4	66.5	24.7	28.9	57.2	43.2	2.1	1.9	1.05	1.05
मध्यम मानव विकास														
95 टोंगा	0.1	0.1	0.6	0.4	23.0	23.5	19.9	21.3	78.9	76.1	4.3	3.8	1.05	1.05
96 बेलीज	0.3	0.4	2.3	2.0	47.7	44.5	18.8	21.8	83.4	60.8	3.6	2.7	1.03	1.03
96 डोमीनिकन गणराज्य	10.2	12.1	1.5	1.2	61.7	70.3	22.7	25.1	67.1	58.3	2.9	2.5	1.05	1.05
96 फ़िजी	0.9	1.0	0.3	0.8	47.9	52.6	22.1	26.4	62.6	51.7	3.1	2.6	1.06	1.06
96 सामोआ	0.2	0.2	0.4	0.5	22.0	19.6	19.7	20.9	81.6	72.7	4.6	3.8	1.08	1.08
100 जॉर्डन	6.5	8.4	2.0	1.9	79.8	83.0	19.4	20.7	75.8	66.9	3.9	2.9	1.05	1.05
101 चीन	1,353.6[i,j]	1,393.1[i,j]	0.6[i,j]	0.4[i,j]	35.9[j]	51.9	29.7	34.5	48.1	37.6	1.7	1.6	1.21	1.18
102 तुर्कमेनिस्तान	5.2	6.2	1.1	1.2	45.9	49.0	21.6	24.5	68.4	48.4	2.8	2.3	1.05	1.05
103 थाइलैंड	69.9	73.3	1.1	0.5	31.1	34.4	30.2	34.2	44.7	41.1	1.7	1.5	1.06	1.06
104 माल्दीव	0.3	0.4	1.5	1.3	27.7	42.3	18.8	24.6	79.2	43.6	2.9	1.7	1.06	1.06
105 सूरीनाम	0.5	0.6	1.3	0.9	64.9	70.1	25.7	27.6	57.1	52.3	2.7	2.3	1.08	1.08
106 गैबन	1.6	2.1	2.1	1.9	80.1	86.5	19.3	21.6	84.2	64.0	4.1	3.2	1.03	1.03
107 अल सल्वाडोर	6.3	7.1	0.4	0.6	58.9	65.3	20.7	23.2	78.2	60.6	2.9	2.2	1.05	1.05
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	10.2	13.4	1.9	1.6	61.8	67.2	20.0	21.7	78.1	66.9	4.1	3.2	1.05	1.05
108 मंगोलिया	2.8	3.5	1.1	1.5	57.1	69.5	21.8	25.4	63.9	46.8	2.2	2.5	1.03	1.03
110 फ़लस्तीन राज्य	4.3	6.8	2.1	2.8	72.0	74.6	16.2	18.1	98.7	79.5	5.4	4.3	1.05	1.05
111 पराग्वे	6.7	8.7	2.0	1.7	55.3	62.5	20.4	23.1	74.0	61.4	3.7	2.9	1.05	1.05
112 मिस्र	84.0	106.5	1.9	1.7	42.8	43.6	21.4	24.4	67.9	57.2	3.3	2.7	1.05	1.05
113 माल्डोवा गणराज्य	3.5	3.1	–1.7	–0.7	44.6	48.4	32.3	35.2	50.8	38.8	1.6	1.5	1.06	1.06
114 फ़िलीपीन्स	96.5	126.3	2.0	1.7	48.0	49.1	20.4	22.2	71.5	62.4	3.8	3.1	1.06	1.06
114 उज्बेकिस्तान	28.1	33.4	0.9	1.1	37.4	36.2	20.9	24.2	71.4	48.7	2.7	2.3	1.05	1.05
116 सीरियाई अरब गणराज्य	21.1	27.9	2.9	1.7	51.9	56.5	19.1	21.1	77.7	65.2	3.6	2.8	1.05	1.05
117 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	0.1	0.1	0.4	0.5	22.3	22.7	18.9	20.8	78.2	65.1	4.3	3.3	1.07	1.07
118 गुयाना	0.8	0.8	0.4	0.2	28.7	28.4	23.0	23.8	66.7	55.8	2.5	2.2	1.05	1.05
119 बोत्स्वाना	2.1	2.3	1.3	1.1	53.2	62.3	20.0	22.9	69.5	56.7	3.4	2.6	1.03	1.03
120 होण्डुरास	7.9	10.7	2.0	2.0	45.5	52.7	18.4	21.0	86.0	66.9	4.0	3.0	1.05	1.05
121 इण्डोनेशिया	244.8	279.7	1.3	1.0	42.0	51.5	24.4	27.8	54.7	47.3	2.5	2.1	1.05	1.05

		जनसंख्या													
		कुल[a] (मिलियन में)		वार्षिक वृद्धि (%)		शहरी (कुल का %)		माध्यिका उम्र (वर्ष)		कुल निर्भरता अनुपात (प्रति 100 लोगों पर 15-64 आयु)		कुल प्रजनन दर (जन्म प्रति महिला)		जन्म के समय लिंगानुपात[b] (बालिका के मुकाबले बालक जन्म)	
मा.वि.सू. श्रेणी		2012	2030	2000/2005	2010/2015[a,c]	2000	2012	2000	2010	2000	2012	2000	2012[a,c]	2000[d]	2012[c]
121	किरिबाती	0.1	0.1	1.8	1.5	43.0	44.0	..	..	..	..	..	..	..	..
121	दक्षिण अफ्रीका	50.7	54.7	1.3	0.5	56.9	62.4	22.9	24.9	59.6	52.9	2.9	2.4	1.03	1.03
124	वनुआतू	0.3	0.4	2.6	2.4	21.7	25.2	18.9	20.6	81.3	70.0	4.4	3.8	1.07	1.07
125	किर्गिस्तान	5.4	6.7	0.4	1.1	35.3	35.4	22.5	23.8	67.9	51.9	2.7	2.6	1.05	1.06
125	ताजिकिस्तान	7.1	9.0	0.9	1.5	26.5	26.5	18.5	20.4	84.9	65.3	4.0	3.2	1.05	1.05
127	वियतनाम	89.7	101.5	1.1	1.0	24.4	31.7	23.8	28.2	60.5	40.9	2.0	1.8	1.05	1.05
128	नामीबिया	2.4	3.0	1.9	1.7	32.4	39.0	19.5	21.2	77.6	64.8	4.0	3.1	1.03	1.03
129	निकारागुआ	6.0	7.2	1.3	1.4	54.7	57.8	18.9	22.1	80.4	61.2	3.3	2.5	1.05	1.05
130	मोरक्को	32.6	37.5	1.1	1.0	53.3	57.4	22.6	26.3	62.0	49.2	2.7	2.2	1.06	1.06
131	इराक	33.7	55.3	2.7	3.1	67.8	66.4	18.0	18.3	89.5	84.3	5.3	4.6	1.07	1.07
132	केप वर्दे	0.5	0.6	1.6	0.9	53.4	63.4	18.5	22.8	88.9	55.8	3.7	2.3	1.03	1.03
133	ग्वाटेमाला	15.1	22.7	2.5	2.5	45.1	50.2	17.7	18.9	92.4	82.4	4.8	3.9	1.05	1.05
134	टिमोर लेस्ट	1.2	2.0	3.9	2.9	24.3	28.7	15.3	16.6	106.8	93.0	7.1	6.0	1.05	1.05
135	घाना	25.5	36.5	2.4	2.3	44.0	52.6	19.1	20.5	79.9	73.0	4.7	4.0	1.06	1.06
136	इक्वेटोरिअल गिनी	0.7	1.1	3.1	2.7	38.8	39.6	19.5	20.3	85.9	72.0	5.8	5.0	1.03	1.03
136	भारत	1,258.4	1,523.5	1.6	1.3	27.7	31.6	22.7	25.1	63.8	53.8	3.1	2.6	1.08	1.08
138	कम्बोडिया	14.5	17.4	1.4	1.2	18.6	20.1	18.1	22.9	80.5	53.2	3.8	2.4	1.05	1.05
138	लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	6.4	7.8	1.6	1.3	22.0	35.4	18.6	21.5	85.0	58.4	4.2	2.6	1.05	1.05
140	भूटान	0.8	0.9	2.9	1.5	25.4	36.4	19.4	24.6	79.2	49.7	3.7	2.3	1.04	1.04
141	स्वाज़ीलैण्ड	1.2	1.5	0.8	1.4	22.6	21.2	17.2	19.5	90.8	69.4	4.2	3.2	1.03	1.03
निम्न मानव विकास															
142	कौंगो	4.2	6.2	2.4	2.2	58.7	64.1	18.9	19.6	82.7	79.3	4.9	4.5	1.03	1.03
143	सॉलोमन द्वीपसमूह	0.6	0.8	2.8	2.5	15.8	20.9	18.8	19.9	80.6	74.1	4.7	4.1	1.09	1.09
144	साओ टोम एवं प्रिन्साइप	0.2	0.2	1.6	2.0	53.4	63.4	17.8	19.3	88.3	75.8	4.6	3.5	1.03	1.03
145	केन्या	42.7	65.9	2.6	2.7	19.9	24.4	17.4	18.5	89.0	82.1	5.0	4.6	1.03	1.03
146	बांग्लादेश	152.4	181.9	1.6	1.3	23.6	28.9	20.8	24.2	70.4	53.0	3.1	2.2	1.05	1.05
146	पाकिस्तान	180.0	234.4	1.9	1.8	33.1	36.5	19.0	21.7	82.8	63.4	4.5	3.2	1.05	1.05
148	अंगोला	20.2	30.8	3.4	2.7	49.0	60.0	16.1	16.6	100.5	93.9	6.8	5.2	1.03	1.03
149	म्याँमार	48.7	54.3	0.6	0.8	27.2	33.2	24.7	28.2	55.2	43.0	2.4	2.0	1.03	1.03
150	कैमरून	20.5	28.8	2.3	2.1	45.5	52.7	18.2	19.3	86.3	78.3	5.0	4.3	1.03	1.03
151	मैडागास्कर	21.9	35.3	3.0	2.8	27.1	33.2	17.4	18.2	93.8	83.7	5.5	4.5	1.02	1.03
152	तंज़ानिया गणराज्य	47.7	81.9	2.6	3.1	22.3	27.2	17.4	17.5	91.0	92.6	5.7	5.5	1.03	1.03
153	नाइजीरिया	166.6	257.8	2.5	2.5	42.4	50.3	18.1	18.5	86.4	86.1	5.9	5.5	1.06	1.06
154	सेनेगल	13.1	20.0	2.7	2.6	40.3	42.8	17.0	17.8	92.1	84.3	5.5	4.7	1.03	1.03
155	मॉरिटानिया	3.6	5.2	2.8	2.2	40.0	41.7	18.4	19.8	83.0	73.1	5.2	4.4	1.05	1.05
156	पापुआ न्यू गिनी	7.2	10.2	2.5	2.2	13.2	12.5	19.6	20.4	74.7	70.3	4.5	3.8	1.08	1.08
157	नेपाल	31.0	39.9	2.2	1.7	13.4	17.3	19.2	21.4	80.5	64.1	4.1	2.6	1.05	1.05
158	लेसोथो	2.2	2.6	1.0	1.0	20.0	28.3	18.6	20.3	84.1	69.1	4.1	3.1	1.03	1.03
159	टोगो	6.3	8.7	2.4	2.0	32.9	38.5	18.0	19.7	86.4	73.6	5.1	3.9	1.02	1.02
160	यमन	25.6	41.3	3.1	3.0	26.3	32.9	15.5	17.4	105.6	86.4	6.5	5.0	1.05	1.05
161	हैती	10.3	12.5	1.6	1.3	35.6	54.8	19.1	21.5	79.2	65.5	4.3	3.2	1.05	1.05
161	युगाण्डा	35.6	59.8	3.2	3.1	12.1	16.0	15.6	15.7	106.0	103.1	6.9	6.0	1.03	1.03
163	ज़ाम्बिया	13.9	24.5	2.3	3.0	34.8	39.6	17.1	16.7	93.2	99.0	6.1	6.3	1.03	1.03
164	जिबूती	0.9	1.3	2.0	1.9	76.5	77.1	18.9	21.4	78.8	62.8	4.8	3.6	1.04	1.04
165	गैम्बिया	1.8	2.8	3.0	2.7	48.8	57.9	16.9	17.8	92.1	83.8	5.6	4.7	1.03	1.03
166	बेनिन	9.4	14.6	3.2	2.7	38.3	45.6	17.1	17.9	94.5	86.9	6.0	5.1	1.04	1.04
167	रवाण्डा	11.3	17.6	2.6	2.9	13.8	19.4	16.9	18.7	92.4	84.2	5.8	5.3	1.01	1.01
168	आइवरी कोस्ट	20.6	29.8	1.7	2.2	43.5	52.0	18.7	19.2	81.6	79.3	5.2	4.3	1.02	1.02
169	कोमोरॉस	0.8	1.2	2.7	2.5	28.1	28.1	18.5	18.9	79.2	82.8	5.3	4.8	1.05	1.05
170	मलावी	15.9	28.2	2.7	3.2	14.6	15.8	17.0	16.9	95.6	96.3	6.1	6.0	1.03	1.03
171	सूडान	35.0	50.8	2.3	2.4	32.5	33.3	18.6 [k]	19.7 [k]	83.7 [k]	76.0 [k]	5.5 [k]	..	1.05 [k]	1.05 [k]
172	ज़िम्बाब्वे	13.0	17.6	0.1	2.2	33.8	39.1	18.2	19.3	82.3	71.6	3.9	3.1	1.02	1.02
173	इथियोपिया	86.5	118.5	2.5	2.1	14.7	17.2	17.0	18.7	95.7	77.3	6.1	3.9	1.03	1.03
174	लाइबेरिया	4.2	6.5	2.2	2.6	44.3	48.5	17.9	18.2	85.9	86.0	5.8	5.1	1.06	1.06
175	अफ़गानिस्तान	33.4	53.3	3.8	3.1	20.6	23.8	15.9	16.6	101.3	92.6	7.7	6.0	1.06	1.06
176	गिनी बिसाउ	1.6	2.3	2.0	2.1	35.9	44.6	18.2	19.0	86.7	79.7	5.8	4.9	1.03	1.03
177	सिएरा लिओन	6.1	8.5	4.4	2.1	35.8	39.6	18.5	18.4	80.2	80.8	5.7	4.8	1.02	1.02
178	बुरुण्डी	8.7	11.4	2.6	1.9	8.2	11.2	16.7	20.2	96.5	67.7	5.8	4.1	1.03	1.03
178	गिनी	10.5	15.9	1.6	2.5	31.0	35.9	17.7	18.3	90.7	85.0	6.0	5.1	1.06	1.06
180	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	4.6	6.4	1.6	2.0	37.6	39.3	18.7	19.4	85.1	78.0	5.4	4.5	1.03	1.03
181	इरिट्रिया	5.6	8.4	4.0	2.9	17.6	21.8	17.1	19.0	89.7	78.9	5.4	4.3	1.03	1.03
182	माली	16.3	26.8	3.1	3.0	28.1	35.6	16.3	16.3	98.8	97.3	6.8	6.2	1.05	1.05

मा.वि.सू. श्रेणी	जनसंख्या: कुल[a] (मिलियन में) 2012	जनसंख्या: कुल[a] (मिलियन में) 2030	जनसंख्या: वार्षिक वृद्धि (%) 2000/2005	जनसंख्या: वार्षिक वृद्धि (%) 2010/2015[a,c]	जनसंख्या: शहरी (कुल का %) 2000	जनसंख्या: शहरी (कुल का %) 2012	माध्यिका उम्र (वर्ष) 2000	माध्यिका उम्र (वर्ष) 2010	कुल निर्भरता अनुपात (प्रति 100 लोगों पर 15-64 आयु) 2000	कुल निर्भरता अनुपात (प्रति 100 लोगों पर 15-64 आयु) 2012	कुल प्रजनन दर (जन्म प्रति महिला) 2000	कुल प्रजनन दर (जन्म प्रति महिला) 2012[a,c]	जन्म के समय लिंगानुपात[b] (बालिका के मुकाबले बालक जन्म) 2000[d]	जन्म के समय लिंगानुपात[b] (बालिका के मुकाबले बालक जन्म) 2012[c]
183 बुर्किना फ़ासो	17.5	29.1	2.9	3.0	17.8	27.4	16.5	17.1	95.3	90.5	6.3	5.8	1.05	1.05
184 चाड	11.8	18.4	3.5	2.6	21.5	21.9	16.9	17.1	96.2	92.6	6.6	5.8	1.03	1.03
185 मोज़ाम्बीक	24.5	35.9	2.6	2.2	29.1	31.4	17.9	17.8	88.8	89.1	5.7	4.8	1.03	1.03
186 कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	69.6	106.0	2.9	2.6	29.3	34.8	16.0	16.7	102.6	94.0	6.9	5.5	1.03	1.03
186 नाइजर	16.6	30.8	3.5	3.5	16.2	18.1	15.8	15.5	102.3	104.8	7.5	7.0	1.05	1.05
अन्य देश अथवा अंचल														
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	24.6	26.2	0.7	0.4	59.4	60.4	29.9	32.9	49.5	47.0	2.1	2.0	1.05	1.05
मार्शल द्वीप समूह	0.1	0.1	0.0	1.6	68.4	72.2	..	..	..	..	..	..	..	..
मोनाको	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	100.0	..	..	..	..	..	..	..	..
नाउरू	0.0	0.0	0.1	0.6	100.0	100.0	..	..	..	..	..	..	..	..
सैन मैरीनो	0.0	0.0	2.3	0.6	93.4	94.1	..	..	..	..	..	..	..	..
सोमालिया	9.8	16.4	2.4	2.6	33.2	38.2	18.0	17.5	88.3	91.0	6.5	6.3	1.03	1.03
दक्षिण सूडान	10.7	16.1	2.8[l]	3.2[l]	16.5	18.2	..	..	..	..	..	..	..	..
तुवालू	0.0	0.0	0.6	0.2	46.0	51.0	..	..	..	..	..	..	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह														
अति उच्च मानव विकास	1,134.3	1,216.9	0.7	0.5	77.0	81.2	36.8	39.3	49.1	50.3	1.6	1.8	1.05	1.06
उच्च मानव विकास	1,039.2	1,150.1	0.9	0.8	70.1	74.1	27.6	30.4	54.7	46.4	2.2	1.9	1.05	1.05
मध्यम मानव विकास	3,520.5	4,017.4	1.2	1.0	34.8	43.7	25.6	28.9	56.8	47.0	2.5	2.1	1.10	1.10
निम्न मानव विकास	1,280.7	1,845.3	2.3	2.2	28.6	33.6	18.4	19.8	85.2	75.5	5.1	4.2	1.04	1.04
क्षेत्र														
अरब देश	357.3	480.8	2.2	2.0	53.2	57.2	20.6	23.3	72.3	59.7	3.9	3.0	1.05	1.05
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	1,991.4	2,135.3	0.8	0.6	36.7	49.7	28.1	32.3	50.8	40.9	2.0	1.8	1.14	1.12
यूरोप एवं मध्य एशिया	481.6	491.3	0.0	0.2	63.2	64.8	32.9	34.9	49.5	43.4	1.6	1.7	1.06	1.06
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	597.7	696.0	1.3	1.1	75.3	79.3	24.4	27.5	60.3	52.1	2.6	2.2	1.05	1.05
दक्षिण एशिया	1,753.0	2,141.8	1.6	1.4	29.0	32.9	22.0	24.6	66.7	54.6	3.3	2.6	1.07	1.07
सब-सहारा अफ़्रीका	852.5	1,284.0	2.5	2.5	32.0	37.0	17.8	18.5	88.6	83.4	5.6	4.8	1.04	1.04
न्यूनतम विकसित देश	870.4 [T]	1,256.8 [T]	2.2 [T]	2.2 [T]	24.3 [T]	28.9 [T]	18.3 [T]	19.7 [T]	85.5 [T]	75.5 [T]	5.1 [T]	4.1 [T]	1.04 [T]	1.04 [T]
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	53.8	63.8	1.3	1.1	48.2	52.6	24.0	26.6	64.6	57.3	3.1	2.7	1.06	1.06
विश्व	**7,052.1**[T]	**8,321.3**[T]	**1.2**[T]	**1.2**[T]	**46.7**[T]	**52.6**[T]	**26.7**[T]	**29.2**[T]	**59.0**[T]	**52.0**[T]	**2.7**[T]	**2.5**[T]	**1.07**[T]	**1.07**[T]

नोट

a पूर्वानुमान मध्यम-प्रजनन भिन्नता पर आधारित।

b जन्म के समय प्राकृतिक लिंग अनुपात आमतौर पर कल्पित और अनुभवजन्य पुष्टि के अनुसार यह 100 महिला जन्म के मुकाबले 105 पुरुष जन्म है।

c आँकड़े 2010-2015 के लिए आनुमानित मान का वार्षिक औसत है।

d आँकड़े 2000-2005 के लिए औसत वार्षिक अनुमान हैं।

e स्वालबर्ड और जेन माईन द्वीप शामिल।

f क्रिसमस द्वीप, कोकोज (कीलिंग) द्वीप और नॉरफोल्क द्वीप शामिल।

g कैनरी द्वीप, सेउटा और मेलिला शामिल।

h कोसोवो शामिल।

i ताइवान, चीन शामिल लेकिन हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र तथा मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र शामिल नहीं।

j हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र तथा मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र शामिल नहीं।

k अनुमान केवल सूडान के लिए है, उनमें दक्षिण सूडान शामिल नहीं है।

l एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ यू.एन.डी.ई.एस.ए. (2012b) के जनसंख्या आँकड़ों पर आधारित है।

T मूल आँकड़ा स्रोत का संग्रह।

परिभाषाएँ

कुल जनसंख्या: किसी देश, इलाके अथवा क्षेत्र में रहने वाली वास्तविक जनसंख्या, 1 जुलाई को।

औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि: निर्दिष्ट अवधि के लिए औसत वार्षिक घातांक (exponential) वृद्धि दर।

शहरी जनसंख्या: प्रत्येक इलाके अथवा देश के मापदण्ड के अनुसार शहर के रूप में वर्गीकृत इलाकों में 1 जुलाई को वास्तविक रूप से रह रही जनसंख्या।

माध्यिका आयु: वह उम्र जो जनसंख्या वितरण को दो बराबर भागों में बाँटती है यानी 50 फ़ीसदी आबादी उस उम्र से बड़ी है और 50 प्रतिशत आबादी उससे छोटी।

कुल निर्भरता अनुपात: 15-64 वर्ग की जनसंख्या के मुकाबले आयु वर्ग 0-14 की जनसंख्या और 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों की जनसंख्या के योग का अनुपात

कुल प्रजनन दर: जन्म देने योग्य उम्र के अंतिम पड़ाव तक प्रत्येक महिला के हो सकने वाले बच्चों की वह संख्या जो उस महिला के द्वारा जन्मे जाते यदि वह महिला उम्र विशेष के लिए प्रचलित प्रजनन दर के अनुसार बच्चों को जन्म देती रहती।

जन्म के समय लिंगानुपात: प्रति बालिका जन्म के मुकाबले जन्मे बालक।

आँकड़ों के मुख्य स्रोत

कॉलम 1, 2, 13 और 14: यू.एन.डी.ई.एस.ए. (2012b)।

कॉलम 3, 4 और 7-12: यू.एन.डी.ई.एस.ए. (2011)।

कॉलम 5 और 6: यू.एन.डी.ई.एस.ए. (2012a)।

क्षेत्र

अरब राज्य (20 देश या क्षेत्रों)

अल्जीरिया, बहरीन, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, ओमान, फिलीस्तीनी राज्य, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरियाई अरब गणराज्य, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन

पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र (24 देश)

कम्बोडिया, चीन, फिजी, इण्डोनेशिया, किरिबाती, कोरियाई लोकतांत्रिक जन गणराज्य, लाओ लोकतांत्रिक जन गणराज्य, मलेशिया, मार्शल द्वीप समूह, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मंगोलिया, म्याँमार, नौरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, समोआ, सॉलोमन द्वीप, थाईलैण्ड, टिमोर लेस्ट, टोंगा, तुवालु, वनुआतू, वियतनाम

यूरोप और मध्य एशिया[1] (31 देश)

अल्बानिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कज़ाकिस्तान, किरगिस्तान, लात्विया, लिथुआनिया, माल्टा, मॉल्दोवा गणराज्य, मोंटेनेग्रो, पोलैण्ड, रोमानिया, रूसी संघ, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ताजिकिस्तान, पूर्व यूगोस्लावी गणराज्य मेसिडोनिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज़बेकिस्तान

लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र (33 देश)

एंटीगुआ और बारबूडा, अर्जेंटीना, बहामास, बारबाडोस, बेलीज़, प्लूरिनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनिकी गणराज्य, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गयाना, हैती, होण्डुरास, जमैका, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पराग्वे, पेरू, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विन्सेंट और ग्रेनाडाइन्स, सूरीनाम, ट्रिनिडाड और टोबैगो, उरुग्वे, बोलिवियाई गणराज्य वेनेज़ुएला

दक्षिण एशिया (9 देश)

अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान इस्लामिक गणराज्य, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका

सब सहारा अफ्रीका (46 देश)

अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुण्डी, कैमरून, केप वर्दे, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कॉमोरोस, कॉन्गो, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, आइवरी कोस्ट, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, इथियोपिया, गैबन, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, केन्या, लेसोथो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मॉरिटानिया, मॉरिशस, मोज़ाम्बीक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, रवाण्डा, साओ टोम और प्रिंसाइप, सेनेगल, सेशेल्स, सिएरा लियोन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, स्वाज़ीलैण्ड, तंज़ानिया संयुक्त गणराज्य, टोगो, युगाण्डा, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे

नोटः न्यूनतम विकसित देशों तथा छोटे द्विपीय विकासशील देशों के योग में शामिल देश संयुक्त राष्ट्र के वर्गीकरण का अनुसरण करते हैं जो कि http://www.unohrlls.org पर उपलब्ध है। एच.डी.आर.ओ. बहरीन, बारबाडोस अथवा सिंगापुर को छोटे द्विपीय विकासशील देशों के योग में शामिल नहीं करता।

1. यूरोप और मध्य एशिया के वे पूर्व समाजवादी देश जिनमें 1989-1991 के बाद व्यापक राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, साइप्रस, माल्टा और तुर्की भी शामिल।

सांख्यिकीय संदर्भ

ADB (Asian Development Bank). 2012. *Asian Development Outlook 2012: Confronting Rising Inequality in Asia*. www.adb.org/sites/default/files/pub/2012/ado2012.pdf. Accessed 30 April 2012.

Aguna, C., and M. Kovacevic 2011. "Uncertainty and Sensitivity Analysis of the Human Development Index." Human Development Research Paper 2010/11. UNDP–HDRO, New York. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/papers/HDRP_2010_47.pdf.

Alkire, S., A. Conconi, and J.M. Roche. 2012. "Multidimensional Poverty Index 2012: Brief Methodological Note and Results." University of Oxford, Department of International Development, Oxford Poverty and Human Development Initiative, Oxford, UK.

Alkire, S., J.M. Roche, M.E. Santos, and S. Seth. 2011. "Multidimensional Poverty Index 2011: Brief Methodological Note." University of Oxford, Department of International Development, Oxford Poverty and Human Development Initiative, Oxford, UK. www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index-2011-brief-methodological-note/. Accessed 15 February 2012.

Alkire, S., and J. Foster. 2010. "Designing the Inequality-Adjusted Human Development Index (HDI)." Human Development Research Paper 2010/28. UNDP–HDRO, New York. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/papers/HDRP_2010_28.pdf.

Anand, S., and A. Sen. 2000. "The Income Component of the Human Development Index." *Journal of Human Development and Capabilities* 1(1): 83–106.

Athukorala, Prema-chandra. 2012. "Asian Trade Flows: Trends, Patterns and Prospects." *Japan and the World Economy* 24: 150–62.

Barro, R. J., and J. W. Lee. 2010. *A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950–2010*. Working Paper 15902. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. www.nber.org/papers/w15902. Accessed 15 April 2012.

———. 2011. Dataset of educational attainment. www.barrolee.com. Accessed 15 April 2012.

CRED EM-DAT (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters). 2012. The International Disaster Database. www.emdat.be. Accessed 30 March 2012.

ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean). 2012. *Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean*. Santiago. www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/41974/P41974.xml&xsl=/. Accessed 30 April 2012.

Eurostat. 2012. "European Union Statistics on Income and Living Conditions (EUSILC)." Brussels. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc. Accessed 15 April 2012.

FAO (Food and Agriculture Organization). 2011. AQUASTAT database. www.fao.org/nr/water/aquastat/data. Accessed 15 April 2012.

———. 2012. Statistics Division Database. www.fao.org/corp/statistics/en/. Accessed 15 April 2012.

Gallup. 2012. Gallup World Poll database. https://worldview.gallup.com. Accessed 30 April 2012.

Høyland, B., K. Moene, and F. Willumsen. 2011. "The Tyranny of International Rankings." *Journal of Development Economics* 97(1): 1–14.

ICF Macro. 2012. Measure DHS (Demographic and Health Survey). www.measuredhs.com.

IEA (International Energy Agency). 2012. *World Energy Outlook 2011*. Paris. www.iea.org/weo/electricity.asp. Accessed 30 March 2012.

ILO (International Labour Organization). 2012. *Key Indicators of the Labour Market*. 7th edition. Geneva. www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/index.htm. Accessed 15 October 2012.

IMF (International Monetary Fund). 2012. World Economic Outlook database, October 2012. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx. Accessed 15 October 2012.

Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. 2012. Database on child mortality. www.childinfo.org/mortality_igme.html. Accessed 15 October 2012.

IPU (Inter-Parliamentary Union). 2012. PARLINE database. www.ipu.org/wmn-e/classif.htm. Accessed 15 May 2012.

ITU (International Telecommunication Union). 2012. World Telecommunication/ICT Indicators database. www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/. Accessed 15 October 2012.

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. www.iucnredlist.org. Accessed 15 April 2012.

LIS (Luxembourg Income Study). 2012. "Luxembourg Income Study Project." www.lisproject.org/techdoc.htm. Accessed 15 May 2012.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2010. Programme for International Student Assessment. www.oecd.org/edu/pisa/2009. Accessed 30 March 2012.

OECD-DAC (Organisation for Economic Co-operation and Development–Development Assistance Committee). 2012. Aid statistics database. www.oecd.org/dac/aidstatistics/. Accessed 15 October 2012.

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). 2012. SIPRI Military Expenditure Database. www.sipri.org. Accessed 30 March 2012.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 2012. Statistics. http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en. Accessed 1 May 2012.

UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). 2011. *World Population Prospects: The 2010 Revision*. New York. http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. Accessed 15 April 2012.

———. 2012a. *World Urbanization Prospects: The 2011 Revision*. New York. http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm. Accessed 30 April 2012.

———. 2012b. Population Division Database. Detailed Indicators. http://esa.un.org/undp/wpp/unpp/. Accessed 1 May 2012.

———. 2012c. *World Economic Situation and Prospects: Mid-2012 Update*. New York. www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/. Accessed 30 April 2012.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Institute for Statistics. 2012. Data Centre. http://stats.uis.unesco.org. Accessed 15 October 2012.

UNESCWA (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia). 2012. "Summary of the Survey of Economic and Social Developments in Western Asia, 2011–2012." Beirut. www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_EDGD_12_1_e.pdf. Accessed 30 April 2012.

UNICEF (United Nations Children's Fund). 2012. *The State of the World's Children 2012*. New York. www.unicef.org/sowc2012/. Accessed 30 March 2012.

———. Various years. Multiple Indicator Cluster Surveys. New York. www.unicef.org/statistics/index_24302.html. Accessed 15 October 2012.

UNODC (United Nations Office on Drug and Crime). 2012. *2011 Global Study on Homicide: Trends, Contexts, Data*. www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf. Accessed 30 May 2012.

UNSD (United Nations Statistics Division). 2012a. National Accounts Main Aggregate Database. http://unstats.un.org/unsd/snaama. Accessed 1 May 2012.

———. 2012b. International Merchandise Trade Statistics. Comtrade Database. http://comtrade.un.org/. Accessed 15 October 2012.

UN WTO (World Tourism Organization). 2012. Compendium of Tourism Statistics database. http://statistics.unwto.org/en/content/compendium-tourism-statistics. Accessed 30 April 2012.

WHO (World Health Organization). 2012a. *World Health Statistics 2011*. Geneva. www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2011_Full.pdf. Accessed 30 March 2012.

———. 2012b. Global Health Observatory. www.apps.who.int/ghodata. Accessed 30 March 2012.

———. 2012c. Mental Health. www.who.int/mental_health/en. Accessed 30 April 2012.

WHO (World Health Organization), UNICEF (United Nations Children's Fund), UNFPA (United Nations Population Fund) and World Bank. 2012. "Trends in Estimates of Maternal Mortality Ratio." www.childinfo.org/maternal_mortality_ratio.php. Accessed 15 May 2012.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2012. Intellectual Property Statistics. www.wipo.int/ipstats/en/. Accessed 22 March 2012.

World Bank. 2011. *Migration and Remittances Factbook*. 2nd Edition. Washington, DC. http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf. Accessed 15 April 2012.

———. 2012a. *World Development Indicators 2012*. Washington, DC. http://data.worldbank.org. Accessed 15 October 2012.

———. 2012b. International Income Distribution Database. [Not publicly available]. 15 April 2012.

———. 2012c. Correspondence on personal computers data. 15 April 2012.

तकनीकी परिशिष्टः
पूर्वानुमान जताने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

इस तकनीकी परिशिष्ट के अंतर्गत अध्याय 4 में वर्णित 2 पूर्वानुमान मॉडलों को संक्षेप में दिया गया है।

जनसांख्यिकी, शिक्षा और मानव विकास के लिए लत्ज़ और के.सी. (2013) मॉडल

वर्ष 2050 तक के जनसांख्यिकी रुझानों के बारे में पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए लत्ज़ और के.सी. (2013) मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। मॉडल इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि जनसंख्या वृद्धि के रुझान शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार से प्रभावित होते हैं। इस रिपोर्ट में 120 देशों के जनसंख्या के आँकड़ों को प्रयोग में लिया गया है, जो आयु, लिंग और शिक्षा के स्तर के रूप में बँटे हुए हैं।

लत्ज़ और के.सी. के बहुवर्गीय जनसंख्या मॉडल से जुड़ी पद्धति का विकास 1970 में आस्ट्रिया के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाईड सिस्टम अनैलिसिस में हुआ था और यह तकनीकी जनसांख्यिकी विशेषज्ञों के बीच सर्वमान्य है। पूर्वानुमान के पीछे का विचार सीधा सा हैः (वर्ष 2000 के बाद से ज्यादातर देशों का अंतरराष्ट्रीय रूप से तुलनात्मक आँकड़ा उपलब्ध है।) इसलिए 2000 को आधार रेखा बनाकर और यह मानकर कि एक निश्चित उम्र के बाद शिक्षा का स्तर अपरिवर्तित रहता है, 2000 में औपचारिक शिक्षा से वंचित 45-49 आयु वर्ग की महिलाओं के अनुपात के आधार पर सीधे 2005 में औपचारिक शिक्षा से वंचित 50-54 आयु वर्ग की महिलाओं का अनुपात जाना जा सकता है।

यह देखते हुए कि एक निश्चित कालावधि में जन्मे लोगों की संख्या केवल मृत्यु दर और विस्थापन की दशा में ही बदल सकती है, ये अनुपात उसी दशा में सही होंगे यदि कोई भी व्यक्ति 15 साल की उम्र के बाद प्राथमिक शिक्षा न हासिल करे और यदि मृत्यु दर तथा विस्थापन की दर शिक्षा के स्तर से अलग न हो। हालांकि, शिक्षा के स्तर और मृत्यु दर, जन्म दर तथा विस्थापन के बीच गहरे संबंध मौजूद हैं। ऐसे में इनके प्रभावों को सही करने के लिए समायोजन ज़रूरी होगा। निश्चित कालावधि में जन्मे लोगों की संख्या (birth cohort) प्रसव योग्य आयु की महिलाओं के शिक्षा स्तर पर निर्भर करती है, जहाँ परंपरागत रूप से नकारात्मक संबंध देखने को मिला है। इन विशेष आयु वर्गों के बारे में पूर्वानुमान जताने के दौरान शिक्षा समूहों के लिए अंतरीय जीवित रहने की दर (differential survival rates) को अपनाया गया है, जो पिछले आँकड़ों के इस्तेमाल से तैयार मॉडल और व्यापक साहित्यिक समीक्षा पर आधारित है।

वास्तव में, किसी व्यक्ति द्वारा एक शिक्षा स्तर से अगले स्तर में जाने की संभावना काफी हद तक उसके माता-पिता के शिक्षा स्तर पर निर्भर करती है। लेकिन इस वंशानुगत आधारित शैक्षिक व्यवस्था को यहाँ पूरी तरह से मॉडल नहीं माना गया है। इसके बजाय बदलाव की दरों और भविष्य में उनके विकासक्रम के बारे में अनुमान अतीत में शिक्षा प्रणाली के समग्र व्यवहार से प्राप्त किये गये हैं। चूँकि यह विस्तार आंशिक रूप से वंशानुगत तंत्र के कारण है, इसलिए एक तथ्य यह भी है कि ज्यादातर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके मुकाबले कहीं बेहतर शिक्षा हासिल करें। निश्चित रूप से वंशानुगत आधार को भी पूर्वानुमानों में जगह दी गयी है, जबकि इससे पहले यह मॉडल का हिस्सा नहीं था। इस तरह का प्रयास बेहतर लगता है क्योंकि शैक्षिक वंशानुगत व्यवस्था की सूक्ष्म प्रक्रियाओं से संबंधित भारी-भरकम आँकड़ों के मुकाबले शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास के आँकड़े, जिन पर भविष्य के पूर्वानुमान आधारित हो सकते हैं, अधिक आसानी से उपलब्ध हैं।

प्रत्येक देश के लिए प्रक्रिया को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः
- पाँच वर्षीय आयु वर्ग, लिंग और शिक्षा स्तर के आधार पर वर्ष 2000 के लिए आधारभूत जनसंख्या वितरण तैयार किया जाये।
- प्रत्येक पाँच साल बाद विशेष जन समूह अगले उच्च पाँच वर्षीय आयु वर्ग में चला जायेगा।
- प्रत्येक आयु, लिंग और शिक्षा समूह और प्रत्येक समयावधि से संबंधित मृत्यु दर लागू है।
- आयु और लिंग से संबंधित शैक्षिक उन्नयन दर लागू है।
- आयु, लिंग और शिक्षा विशेष के कुल में विस्थापितों की आबादी को घटा दिया गया है या जोड़ दिया गया है। यहाँ प्रस्तुत पूर्वानुमानों में विस्थापितों के बारे में धारणा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पूर्वानुमानों के अनुरूप हैं।
- नये 0-5 आयु वर्ग के आकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आयु, लिंग और शैक्षिक समूहों तथा प्रत्येक समयावधि में प्रजनन दर का इस्तेमाल किया गया है।

आयु, लिंग और शैक्षिक स्तर के अनुसार नये जनसंख्या वितरण का ख्याल रखा गया है और अगले पाँच वर्षों के लिए इन्हें दोहराया गया है।

इन पूर्वानुमानों का उद्देश्य पाँच वर्ष आयु वर्ग के आधार पर आबादी के आँकड़ों का संग्रह तैयार करना है। (इन आयु वर्गों को 15-20 वर्ष से शुरू करके 100 वर्ष उम्र और उसके आगे तक ले जाया जायेगा)। इन आँकड़ों को पाँच वर्ष के समयांतराल में 2000 (आधार वर्ष) से लेकर 2050 तक 50 वर्षों के लिए लिंग और चार शैक्षिक स्तरों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

मानव विकास और नीतिगत परिदृश्यों की संभावनाओं के लिए पार्डी सेंटर फॉर इन्टरनेशनल फ्यूचर्स (2013) मॉडल

इस रिपोर्ट में दीर्घावधि मानव विकास पूर्वानुमानों के लिए अंतरराष्ट्रीय भावी (Futures) मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जो आय, स्वास्थ्य, गरीबी, लिंग, सामाजिक बदलाव (अस्थिरता और जोखिम) और पर्यावरणीय संवहनीयता जैसे एक-दूसरे को प्रभावित करने वाले नीतिगत मसलों पर आधारित है। मॉडल को किस प्रकार विकसित किया गया है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए पार्डी सेंटर फॉर इन्टरनेशनल फ्यूचर्स (2013) और यूनीवर्सिटी ऑफ डेनवर कॉर्बेल स्कूल की वेबसाईट (www.ifs.du.edu/introduction) देखें।

अंतरराष्ट्रीय भावी मॉडल एक वृहद् स्तरीय और दीर्घावधि की एकीकृत वैश्विक प्रतिमान प्रणाली है, जिसमें 183 देशों के जनसांख्यिकी, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, सामाजिक-राजनीतिक, बुनियादी ढाँचा, तकनीकी और पर्यावरण संबंधी उप-मॉडल शामिल हैं,

जो वैश्विक प्रणाली में एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

दीर्घावधि पर्यावरणीय रुझानों को व्यक्त करने और मानव विकास पर उसके प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल 2011 की मानव विकास रिपोर्ट में किया गया था।

मानव विकास के विश्लेषण के उपयुक्त इस मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- उत्पादन कार्य जो चार प्रमुख श्रेणियों में उत्पादकता के मापदंड तय करता है। ये श्रेणियाँ मानव संसाधन, सामाजिक पूँजी, भौतिक पूँजी और ज्ञान शामिल हैं।
- एक जनसंख्या मॉडल जिसमें आयु और लिंग के आधार पर 22 विशेष आयु वर्ग इस तरह शामिल हैं जो प्रजनन दर में बदलावों को दर्शाता है। इसमें एक सघन स्वास्थ्य मॉडल भी है जो 13 मूल श्रेणियों में मृत्यु दर (और अस्वस्थ्ता) की गणना करना है।
- छह क्षेत्रों में संतुंलन स्थापित करने वाला आर्थिक मॉडल। ऐसा नहीं माना जाता है कि किसी दिये गये वर्ष में सटीक संतुलन स्थापित हो जायेगा, इसके बजाय यह वस्तु सूची को बफर स्टॉक के रूप में इस्तेमाल करता है और कीमतों के संकेत मुहैया कराता है ताकि समय के साथ मॉडल संतुलन की ओर बढ़ता जाये।
- प्राथमिक, माध्यमिक (अलग-अलग निन तथा उच्च माध्यमिक स्तर) और तृतीयक स्तर तक औपचारिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाला शैक्षिक मॉडल।
- एक ऐसा स्वास्थ्य मॉडल, जिसमें मृत्यु और विकलांगता की प्रमुख वज़हों का अनुमान लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिज़ीज़ कार्यक्रम के साथ ही कुपोषण, मोटापा तथा धूम्रपान जैसे स्वास्थ्य संबंधित खतरों को लेकर तुलनात्मक ज़ोखिम मूल्याँकन दृष्टिकोण, दोनों शामिल हैं।
- एक सामाजिक-राजनीतिक मॉडल जिसमें कराधान और व्यय संबंधी निर्णयों के जरिये राजकोषीय नीति और अन्य प्रशासनिक कारकों का प्रतिनिधित्व करता है। इन कारकों में भ्रष्टाचार का स्तर और शासन का प्रकार शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति (व्यापार, विदेशी निवेश, अंतर प्रशासनिक स्थानांतरण और तकनीकी उन्नयन पर केन्द्रित), बुनियादी ढाँचा (प्रमुख ढाँचागत प्रणालियों तक पहुँच के स्तर पर केन्द्रित) और पर्यावरण (जल और जमीन जैसे संसाधनों के इस्तेमाल और कार्बन उत्पादन पर केन्द्रित) संबंधी मॉडल भी हैं। कृषि और ऊर्जा मॉडल भौतिक स्तर पर आंशिक रूप से संतुलन प्रणाली हैं और उनकी गतिशीलता आर्थिक मॉडल में वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को आकार प्रदान करती है।

पूर्वानुमानों में त्वरित प्रगति परिदृश्य को तैयार करने के लिए आक्रामक लेकिन तार्किक नीतिगत हस्तक्षेपों की पहचान की गयी है। इसमें नीतिगत पहलों के एक दर्जन समूहों में हस्तक्षेप (तालिका क1 देखें) शामिल हैं और आधारभूत परिदृश्य के अनुमानों से संबंधित प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। निष्क्रियता का मूल्य दो परिदृश्यों के बीच अंतर के बराबर है। 'आक्रामक लेकिन तार्किक' की परिभाषा पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल यूचर्स की श्रृंखला 'संभावित मानव प्रगति के तौर-तरीके' के विश्लेषणों पर आधारित है और विकास स्तर के लक्ष्यित चरों से संबंधित पारस्परिक कार्यों पर निर्भर करता है।

सारणी A1

नीतिगत हस्तक्षेपों के बारह क्लस्टर, उत्प्रेरकों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए

मुख्य घरेलू उत्प्रेरक	मुख्य अंतरराष्ट्रीय उत्प्रेरक
1. जनसांख्यिकी	**7. सामाजिक पूँजी और अधिशासन**
प्रजनन दर महिला श्रम शक्ति की भागीदारी दर	आंतरिक टकराव की आशंका सरकारी राजस्व और भ्रष्टाचार लोकतंत्र और समावेश
2. बचत और निवेश	**8. व्यापार**
बचत और निवेश दर	व्यापार अवरोध निर्यात संवर्धन
3. घरेलू अंतरण	**9. विदेशी निवेश**
अकुशल परिवारों को अंतरण	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिभूति निवेश प्रवाह
4. मानव पूँजी	**10. पारिवारिक अंतरण**
शिक्षा भागीदारी लक्ष्य और शिक्षा व्यय स्वास्थ्य व्यय लक्ष्य और चुनिंदा स्वास्थ्य जोखिम कारकों के लक्ष्य	धन प्रेषण
5. ढाँचागत पूँजी	**11. अंतरशासकीय अंतरण**
बुनियादी ढाँचे तक पहुँच	विदेशी अनुदान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवाह
6. ज्ञान पूँजी	**12. प्रौद्योगिकी**
शोध और विकास	प्रौद्योगिकी उन्नयन

स्रोतः पार्डी सेंटर फ़ॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स (2013) से लिया गया है।

आधारिक परिदृश्य

आधारभूत परिदृश्य ऐतिहासिक तौर-तरीकों के साथ निरंतरता को बताता है। (इसमें हाल के दशकों के दौरान अपनायी गयीं विकासात्मक नीतियाँ शामिल हैं।) हालाँकि, मॉडल की जटिल गतिशीलता, जिसमें अरेखीय संबंधों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है, ऐसा ढाँचा उपलब्ध कराती है जो ऐतिहासिक वक्र रेखा से काफी अलग अरेखीय भावी तौर-तरीकों को उत्पन्न कर सकता है।

त्वरित प्रगति परिदृश्य

आधारभूत परिदृश्य की तुलना में त्वरित प्रगति परिदृश्य के तहत संसाधन और नीतिगत आकांक्षा काफी बढ़ जाती है। तालिका क 2 में दूसरी बातों के अलावा गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढाँचा और प्रशासन में हस्तक्षेप की उचित (आक्रामक लेकिन तार्किक) मात्रा के लिए विकल्पों और लक्ष्यों को बताया गया है। आधारभूत परिदृश्य में बदलाव प्रत्येक देश के लिए निहित मूल्यों से परस्पर संबंधित हैं और इसलिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रारंभिक बिन्दुओं और तौर-तरीकों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

सारणी A2

आधारिक परिदृश्य की तुलना में हस्तक्षेप की उचित मात्रा हेतु लक्ष्य

नीति क्षेत्र	10 वर्ष के दौरान	20 वर्ष के दौरान	30 वर्ष के दौरान	40 वर्ष के दौरान
वैश्विक स्तर				
गरीबी उन्मूलन	• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दोगुना कर्ज • विकसित देशों द्वारा विदेशी सहायता अनुदान में स.घ.उ. के मुकाबले कम से कम 0.5 प्रतिशत की वृद्धि	• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 30% वृद्धि • प्रतिभूति निवेश प्रवाह में 50 % वृद्धि • शोध और विकास की मद में 20 % वृद्धि • प्रवास में 50 प्रतिशत की वृद्धि		
बुनियादी ढाँचा[a]		• परिवहन मार्गों से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर रहने वाली ग्रामीण आबादी में आधे की कटौती या 10 प्रतिशत से कम (जो पहले हो) • बिजली की सार्वभौमिक उपलब्धता • घरों में खाना बनाने के मुख्य साधन के रूप में ठोस ईंधन का अन्त	• बुनियादी ढाँचे में 20 % सुधार • पानी और स्वच्छता के उन्नत स्रोत तक सार्वभौमिक पहुँच (1990 के स्तर से 2015 तक आधा होने के बाद) • मोबाइल टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच	• अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि
अभिशासन[b]	• दुनिया भर में भ्रष्टाचार में कमी और प्रभावी अभिशासन तथा नियामक गुणवत्ता में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति स.घ.उ. के लिए ठेठ मूल्यों से ऊपर एक मानक त्रुटि तक वृद्धि • लोकतंत्र और लैंगिक सशक्तीकरण के उपायों में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति स.घ.उ. के लिए ठेठ मूल्यों से ऊपर एक मानक त्रुटि तक वृद्धि	• आंतरिक टकराव की आशंका घटकर शून्य • गैर आर्थिक सहयोग एवं विकास देशों (OECD) के साथ सरकार के राजस्व में 10% वृद्धि (स.घ.उ. का लगभग 3 प्रतिशत अंक)		
क्षेत्रीय और घरेलू स्तर[c]	• विकासशील देशों के स्वास्थ्य व्यय में 20% वृद्धि, विश्व बैंक के मानकों के आधार पर सरकार की कार्यकुशलता में 20% सुधार, फ्रेसर इंस्टीट्यूट के मानकों के आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता में 20% वृद्धि और तकनीकी आधारित उत्पादकता वृद्धि में 0.2% बढ़ोतरी।	• ट्रान्सपेरेंसी इंटरनेशनल के मानकों के आधार पर भ्रष्टाचार में 30% की कमी		

a. परिवहन, ऊर्जा जल और स्वच्छता, और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी शामिल। वैश्विक लक्ष्य नियामक लक्ष्यों (सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों जैसी आकांक्षाएँ) का संयुक्त रूप है और सभी देशों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति की संभावनाओं पर विचार करते हुए वैश्विक लक्ष्य वास्तविक सार्वभौमिक लक्ष्यों का 97.5% है।

b. अभिशासन की अवधारणा त्रिआयामी है– सुरक्षा, क्षमता और समावेश। सुरक्षा आयाम का परिचालन आमतौर पर दो पूरक उपायों– घरेलू संघर्ष की आशंका और संघर्ष की संवेदनशीलता पर आधारित है। क्षमता आयाम का परिचालन राजस्व जुटाने (स.घ.उ. के 30%तक) और इसका प्रभावी इस्तेमाल (विशेष रूप से भ्रष्टाचार के निम्न स्तर पर जोर) करने की सरकार की योग्यता के आधार पर किया जाता है। समावेशी आयाम का परिचालन संस्थाओं के लोकतांत्रिक चरित्र और *मानव विकास रिपोर्ट* के लैंगिक सशक्तीकरण उपायों द्वारा प्रस्तुत व्यापक समावेश के आधार पर किया जाता है।

c. क्षेत्रवार लक्ष्य पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स (2013) में उपलब्ध हैं।

2012 की मा.वि.सू. श्रेणी और उसमें 2011 से 2012 में हुए बदलाव

अफ़गानिस्तान	175	
अल्बानिया	70	–1
अल्जीरिया	93	–1
अंडोरा	33	–1
अंगोला	148	
एंटिगुआ एवं बरबूडा	67	–1
अर्जेन्टीना	45	–1
आर्मेनिया	87	–1
ऑस्ट्रेलिया	2	
ऑस्ट्रिया	18	
अज़रबैजान	82	–1
बहामास	49	
बहरीन	48	
बांग्लादेश	146	1
बारबाडोस	38	
बेलारूस	50	1
बेल्जियम	17	
बेलीज़	96	
बेनिन	166	
भूटान	140	1
प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	108	
बॉस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	81	–1
बोत्स्वाना	119	–1
ब्राज़ील	85	
ब्रुनेई दारस्सलाम	30	
बुल्गारिया	57	
बुर्किना फ़ासो	183	
बुरुण्डी	178	–1
कंबोडिया	138	
कैमरून	150	
कनाडा	11	–1
केप वर्डे	132	–1
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य	180	–1
चाड	184	
चिली	40	
चीन	101	
कोलंबिया	91	
कॉमोरॉस	169	–1
कॉन्गो	142	
कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य	186	
कोस्टा रिका	62	
आइवरी कोस्ट	168	1
क्रोएशिया	47	–1
क्यूबा	59	
साइप्रस	31	
चेक गणराज्य	28	
डेनमार्क	15	
जिबूती	164	
डोमिनिका	72	
डोमिनिकन गणराज्य	96	2
इक्वाडोर	89	
इजिप्ट (मिस्र)	112	
अल सल्वाडोर	107	–1
इक्वेटोरियल गिनी	136	
एरिट्रिया	181	1
एस्टोनिया	33	1
इथियोपिया	173	–1
फ़िजी	96	2
फ़िनलैंड	21	
फ़्रांस	20	
गैबन	106	
गैंबिआ	165	

जॉर्जिआ	72	3
जर्मनी	5	
घाना	135	
यूनान	29	
ग्रेनाडा	63	–1
ग्वाटेमाला	133	
गिनी	178	–1
गिनी. बिसाउ	176	
गयाना	118	1
हैती	161	1
होण्डुरास	120	
हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	13	1
हंगरी	37	
आइसलैंड	13	
भारत	136	
इण्डोनेशिया	121	3
ईरान इस्लामिक गणराज्य	76	–2
इराक	131	1
आयरलैंड	7	
इस्राइल	16	
इटली	25	
जमैका	85	–2
जापान	10	
जॉर्डन	100	
कज़ाकिस्तान	69	–1
केन्या	145	
किरिबाती	121	
कोरिया गणराज्य	12	
कुवैत	54	–1
किर्गिस्तान	125	
लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	138	
लात्विया	44	1
लेबनान	72	
लेसोथो	158	1
लाइबेरिया	174	
लीबिया	64	23
लिक्टन्सटाइन	24	
लिथुआनिया	41	2
लक्ज़मबर्ग	26	
मैडागास्कर	151	
मलावी	170	1
मलेशिया	64	1
माल्दीव	104	–1
माली	182	–1
माल्टा	32	1
मॉरितानिया	155	
मॉरिशस	80	–1
मैक्सिको	61	
फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	117	
माल्डोवा गणराज्य	113	
मंगोलिया	108	2
मॉन्टीनेग्रो	52	–2
मोरक्को	130	
मोज़ाबीक	185	
म्याँमार	149	
नामीबिआ	128	
नेपाल	157	
नीदरलैंड	4	
न्यूजीलैंड	6	
निकारागुआ	129	
नाइज़र	186	1
नाइजीरिया	153	1

नॉर्वे	1	
ओमान	84	–1
पाकिस्तान	146	
पलाउ	52	2
अधिकृत फ़लीस्तीनी क्षेत्र	110	1
पनामा	59	1
पापुआ न्यू गिनी	156	
पराग्वे	111	–2
पेरू	77	–1
फ़िलीपीन्स	114	
पोलैण्ड	39	
पुर्तगाल	43	–3
कतर	36	
रोमानिआ	56	–1
रूसी संघ (फ़ेडरेशन)	55	
रवाण्डा	167	
सेंट किट्स एवं नेविस	72	–1
सेंट लूसिआ	88	
सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	83	–2
समोआ	96	
साओ टोमे एवं प्रिन्साइप	144	
सउदी अरब	57	
सेनेगल	154	–2
सर्बिआ	64	
सेशेल्स	46	
सिएरे लिओन	177	2
सिंगापुर	18	
स्लोवाकिया	35	
स्लोवेनिया	21	
सॉलोमन द्वीप समूह	143	
दक्षिण अफ़्रीका	121	1
स्पेन	23	
श्रीलंका	92	
सूडान	171	–1
सूरीनाम	105	
स्वाज़ीलैंड	141	–1
स्वीडन	7	
स्विटज़रलैण्ड	9	
सीरियाई अरब गणराज्य	116	
ताजिकिस्तान	125	1
तन्ज़ानिआ संयुक्त गणराज्य	152	1
थाइलैण्ड	103	1
मेसाडोनियाए पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	78	–2
टिमोर लेस्ट	134	
टोगो	159	1
टोन्गा	95	
ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	67	–1
ट्यूनीशिया	94	
टर्की	90	
तुर्कमेनिस्तान	102	
युगाण्डा	161	
यूक्रेन	78	
संयुक्त अरब अमीरात	41	–1
यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)	26	
यूनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्य अमेरिका)	3	–1
उरुग्वे	51	
उज़्बेकिस्तान	114	1
वनुआतू	124	–2
वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	71	–1
वियतनाम	127	
येमन	160	–2
ज़ाबिया	163	
ज़िबाब्वे	172	1

नोट : सबसे दाहिने के कॉलम में सकारात्मक और नकारात्मक मान 2011-2012 के बीच देशों की रैंकिंग के ऊपर या नीचे जाने की संख्या बताते हैं, सुसंगत आंकड़ों और कार्यविधि का प्रयोग करते हुए। शून्य दिखाता है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
1, यूनाइटेड नेशन्स प्लाज़ा
न्यू यॉर्क, एन.वाई. 10017

www.undp.org

ISBN 978-92-1-126340-4

इस 21वीं सदी में वैश्विक गतिकी में एक बेहद गहरा बदलाव आता दीख रहा है, जो विकासशील दुनिया में तेज़ी से उभर रहे सत्ता केन्द्रों से परिचालित है। चीन ने जापान से आगे आकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है, इसके फलस्वरूप सैकड़ों-लाखों लोगों को ग़रीबी के जाल से मुक्त करा लिया है। भारत एक नई उद्यमशील रचनात्मकता और सामाजिक नीति के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से अपने भविष्य को नए ढंग से गढ़ रहा है। ब्राज़ील अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विस्तार करके और ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के द्वारा जिस तरह अपना जीवन-स्तर उठाता जा रहा है, उसको आज दुनिया भर में अपनाया जा रहा है।

लेकिन 'दक्षिण का उदय' नाम की परिघटना इससे कहीं बड़ी है। इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ़्रीका, थाइलैंड, तुर्की और अन्य विकासशील देश विश्व मंच पर नायकों की भूमिका में नज़र आ रहे हैं। वर्ष 2013 की *मानव विकास रिपोर्ट* विकासशील दुनिया के 40 से भी अधिक ऐसे देशों को चिन्हित करती है, जिन्होंने हाल के दशकों में मानव विकास के संदर्भ में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और पिछले कोई एक दशक से त्वरित प्रगति में उल्लेखनीय काम किया है।

इनमें से प्रत्येक देश का अपना एक अनूठा इतिहास है और हर एक ने अपने विकास का विशिष्ट रास्ता खुद चुना है। लेकिन इन देशों की अनेक विशेषताएँ और चुनौतियाँ एक जैसी हैं । उनकी आपसी निर्भरता बढ़ ही रही है, साथ ही पारस्परिक जुड़ाव के सूत्र भी मज़बूत हो रहे हैं। और समूचे विकासशील जगत के लोग अपनी आवाज़ सुने जाने को लेकर आग्रहीऔर मुखर हो रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास विचारों के आदान-प्रदान के लिए संवाद-संप्रेषण के नए माध्यम हैं और वे सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अधिक जवाबदेही की माँग कर रहे हैं।

मानव विकास रिपोर्ट 2013 दक्षिण के उदय की इस लगातार जारी प्रक्रिया के कारणों और उसके परिणामों का विश्लेषण करती है और इस नई वास्तविकता के मूल में छिपी उन नीतियों की पहचान करती है जो आने वाले कई दशकों तक सारी दुनिया में और अधिक प्रगति की बयार बहाने में सहायक हो सकते हैं। यह रिपोर्ट वैश्विक अधिशासन व्यवस्थाओं में दक्षिण के बेहतर प्रतिनिधित्व का आह्वान करती है और अनिवार्य सार्वजनिक साधनों के लिए दक्षिण की ही परिधि के भीतर मौजूद संभावनायुक्त वित्तीयन स्रोतों की ओर इशारा करती है। ताज़ा और विश्लेषण-परक अंतर्दृष्टि से संपन्न और नीतिगत सुधारों के स्पष्ट प्रस्तावों से लैस यह रिपोर्ट प्रत्येक क्षेत्र के नागरिकों को मानव विकास की समान चुनौतियों का एकजुट होकर तथा पारदर्शी व प्रभावी तरीके से सामना करने का रास्ता तय करने में सहायता करती है।

''वैश्विक विकास की वर्तमान स्थिति की हमारी समझ को यह रिपोर्ट फिर ताज़ा करती है और दिखाती है कि दक्षिण के इतने सारे देशों की विकास की तेज़ प्रगति के अनुभवों से कितना कुछ सीखा जा सकता है।''

-यू.एन.डी.पी. प्रशासक हेलेन क्लार्क, आमुख में से

''मानव जीवन में आने वाली सफलताओं और वंचितताओं को ठीक से समझने, संवाद व चिंतन के मानव जीवन में महत्व की थाह पाने की दिक्कत से पार पाने के लिए मानव विकास का दृष्टिकोण एक अहम उपलब्धि है; साथ ही, यह दुनिया में पारदर्शिता और न्याय को बढ़ावा देने का ज़रिया भी है।''

-नोबल पुरस्कृत अमर्त्य सेन, पहले अध्याय से

''बेहतर विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, और इसीलिए न्यूयार्क दूसरे शहरों और देशों में हो रहे अच्छे कामों से सीखने का सिलसिला जारी रखेगा।''

-न्यूयॉर्क शहर के मेयर माइकेल ब्लूमबर्ग, तीसरे अध्याय से

''सफल रहे विकासशील देशों द्वारा अपनाए गए अलग-अलग विकास पथों को क़रीब से देखने-समझने से सभी देशों और क्षेत्रों के नीतिगत विकल्पों की सूची समृद्ध होती है।''

-रिपोर्ट के प्रमुख लेखक ख़ालिद मलिक, प्रस्तावना से